

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DATE	SIGNATURE

भारतीय अर्थशास्त्र

भारतीय अर्थशास्त्र

लेखको की विख्यात पुस्तक Indian Economics का हिन्दी रूपान्तर

[खण्ड २]

जे० बी० जथार, एम० ए०

तथा

एस० जी० बेरी, एम० ए०



राजकमल प्रकाशन

मूल पुस्तक Home University Library और Oxford University Press द्वारा प्रकाशित की गई है। प्रस्तुत संशोधित हिन्दी संस्करण में अद्यतन सूचनाएँ और ग्राँकडे संशोधनकर्ता द्वारा यथास्थान दे दिये गए हैं।

पूर्ववर्ती संस्करणों के रूपांतरकार तथा संशोधनकर्ता :
डी० एस० कुशवाहा, (इलाहाबाद विश्वविद्यालय)
पंचम संशोधित संस्करण के संशोधनकर्ता : डी० डी० मेहता
(के० एम० कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय)

प्रथम हिन्दी संस्करण, १९५५
द्वितीय संशोधित हिन्दी संस्करण, १९६०
तृतीय संशोधित हिन्दी संस्करण, १९६१
चतुर्थ संशोधित हिन्दी संस्करण, १९६२
पंचम संशोधित हिन्दी संस्करण, १९६६

मूल्य

खण्ड १ : ८ रुपये
खण्ड २ : ८ रुपये
सम्पूर्ण : १५ रुपये

प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली-६
मुद्रक : शाहदरा प्रिंटिंग प्रेस, नवीन शाहदरा, दिल्ली-३२

पंचम संशोधित संस्करण की भूमिका

स्वतन्त्रता-प्राप्ति व बाद भारत ने अनेक दिशाओं में प्रगति की है। आर्थिक समृद्धि किसी भी देश की शक्ति का प्रमुख आधार होता है। भारतीय अर्थ-व्यवस्था भी प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रही है। विविध योजनाओं द्वारा भारत अपने विस्तृत और मूलभूत साधनों के सतुलित विकास का मार्ग ढूँढ रहा है और अपने आर्थिक ढाँचे को शीघ्र ही बदलने का प्रयत्न कर रहा है। भारत की स्वतन्त्रता और उसका भविष्य पंचवर्षीय योजनाओं पर निर्भर है।

इस दिशा में परिवर्तनशील होते हुए भारतीय अर्थशास्त्र का अध्ययन अत्यधिक रोचक एवं महत्त्वपूर्ण है। आज का भारतीय अर्थशास्त्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देश की आर्थिक स्थिति के अध्ययन में लगा हुआ है। जयार और बेरी ने १९२८ में अपने ग्रंथ 'अर्थशास्त्र का अध्ययन' का प्रथम संस्करण प्रकाशित करके इस विषय के विस्तृत एवं गम्भीर अध्ययन में महत्त्वपूर्ण योग दिया था। तब से लेकर १९४६ तक उनकी पुस्तक के अनेक संस्करण प्रकाशित हुए, किन्तु दुर्भाग्य से सन् १९४६ में श्री बेरी के देहान्त के कारण इस पुस्तक के अन्य संस्करण न निकल सके।

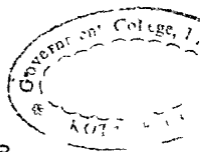
उनका ग्रंथ प्रथम प्रकाशन से आज तक भारतीय अर्थशास्त्र का विश्वकोश समझा जाता रहा है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन ग्रंथों को आधुनिकतम रूप देने तथा संशोधित करने का कार्य सौंपा गया है। मैंने १९६६-६७ के बजट, इण्डिया १९६५, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का संस्करण-पत्र और आर० वी० बुलेटिन इत्यादि से पर्याप्त सहायता ली है। इस कार्य में मुझे मेरे शिष्य आनन्द वी० चन्दन से बहूत सहायता प्राप्त हुई है। मैं आनन्द चन्दन का इसके लिए बहूत आभारी हूँ।

मुझे पूरी आशा है कि यह पुस्तक अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों दोनों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

किरोडीमल कॉलेज, दिल्ली-७

—डॉ० डॉ० मेहता

जून, १९६६



सूची : खण्ड २

१४ : औद्योगीकरण . साधन तथा विधि

३-२०

भारत में सरक्षण के पक्ष में प्रमुख तर्क—सरक्षण और राष्ट्रीय स्व-निर्भरता—भारत में सरक्षण के पक्ष में प्रबल भावना—विवेचनात्मक सरक्षण—विवेचनात्मक सरक्षण नीति में युद्धकालीन व्यवस्था की आवश्यकता—सरक्षण से सम्भावित हानियाँ—सरक्षण के अतिरिक्त अन्य आवश्यक तत्व—शिक्षा—भारत में औद्योगिक शिक्षा की स्थिति—एम्बट-ब्रुड रिपोर्ट—युद्ध-उद्योगों के लिए प्राविधिक व्यक्तियों की उपलब्धि—भण्डार-कय-नीति—औद्योगिक अनुसंधान—प्रान्तीय उद्योग विभागों का कार्य—आयोजन और औद्योगीकरण ।

१५ भारतीय उद्योग नवीन तथा पुरातन

२१-६७

अध्याय का क्षेत्र—सूती मिल उद्योग—सन् १९४७ के बाद सूती मिल-उद्योग—वस्त्र-उद्योग को सरक्षण—सूती मिल-उद्योग की कुछ कठिनाइयाँ—प्रमुख मण्डल द्वारा दूमरी जाँच (१९३२)—वस्त्र सम्बन्धी विशेष प्रमुख-मण्डल (१९३५)—भारत-ब्रिटेन व्यापारिक समझौते के अन्तर्गत प्रमुख-परिवर्तन (१९३९)—१९३९-४५ के युद्धकाल और बाद में सूती वस्त्र-उद्योग—जूट-उद्योग—अवसाद-काल और तदनन्तर जूट-उद्योग—जूट मिल उद्योग पर द्वितीय विश्व-युद्ध का प्रभाव—जूट-उद्योग की समस्याएँ—लोहा और इस्पात-उद्योग—लोहा और इस्पात का आयात—लोहा और इस्पात उद्योग को सरक्षण प्रदान करना—इस्पात-उद्योग की परिणियत जाँच (१९२६-२७)—लोहे और इस्पात के उद्योगों के विषय में सरक्षण के अन्य कदम—लोहा और इस्पात-उद्योग की वर्तमान स्थिति—सूक्ष्म नीति—योजना और इस्पात-उद्योग—सहायक उद्योग—उद्योग की समस्याएँ—चमड़ा सिम्हान और चमड़े का उद्योग—सिम्हाक उद्योग को सरक्षण—रासायनिक उद्योग—भारी रसायन-उद्योग तथा दवाइयाँ—तेल पेरने का उद्योग—कागज-निर्माण—कागज-उद्योग को सरक्षण—शीशा-निर्माण—जीशे का आयात और उत्पादन—शीशा उद्योग को सरक्षण—सीमेण्ट उद्योग—दियासलाई उद्योग—कुटीर-उद्योग—लघु प्रमाण उत्पादन के बने रहने के कारण—भारत में कुटीर उद्योग और उद्योगीकरण—सूती (हस्तचालित) करघा-उद्योग—उनी उद्योग—कच्चा रेशम और रेशम का निर्माण—अन्य कुटीर-उद्योग—कुटीर-उद्योगों को सहायता की विधियाँ—कुटीर-उद्योगों की राजकीय सहायता के हाल के उपाय—योजना एवं औद्योगिक उन्नति ।

श्रम-सम्बन्धी बढ़ती हुई समस्याएँ—औद्योगिक श्रम की पूर्ति और उसका देश-न्तर-गमनीय स्वभाव—देशान्तर-गमन के प्रभाव—औद्योगिक श्रम का प्रभाव—भरती करने का ढग—पारिश्रमिक देने की अवधि—मजदूरी में से कटौती—जुर्माना—काम के घटे और भ्रमणशील प्रवृत्ति—मिलों में काम करने की कठोर परिस्थिति—भारतीय कारखानों में अनुपस्थिति—औद्योगिक श्रम की कार्यक्षमता—भारतीय श्रम की अकुशलता के कारण—आवास (हाउसिंग) की परिस्थितियाँ—आवास की कठिनाइयों और स्वच्छता की कमी के दुष्परिणाम—सुधरे आवासों के लिए प्रयास—औद्योगिक आवास-सम्बन्धी आधुनिक प्रयत्न—मजदूरी की दर—रहन-सहन का निम्न स्तर—शराबखोरी पर व्यय—ऊँची मजदूरी का पक्ष—निम्नतम वेध मजदूरी—ऋणिता—भारत में श्रम-विधान—भारत में श्रम-विधान का उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ क्षेत्र—श्रम-विधान की एकरूपता की आवश्यकता—भारत में फँकट्टी-विधान का प्रारम्भ—१९११ का कारखाना अधिनियम (फँकट्टी एक्ट)—१९२२ का कारखाना अधिनियम—१९३४ का कारखाना अधिनियम, १९४६ का सशोधन तथा १९४८ का अधिनियम—बम्बई की दुकानों और वाणिज्यिक संस्थापन-सम्बन्धी अधिनियम (१९३६) (दि बॉम्बे शॉप्स एण्ड कर्माशयल एस्टेब्लिशमेन्ट्स एक्ट)—चाय के जिलों के प्रवासी श्रम अधिनियम १९३२ (दि टी डिस्ट्रिक्ट्स एमीग्रेट लेबर एक्ट)—खानों के लिए श्रम-विधान—रेलवे के श्रमिकों से सम्बन्धित अधिनियम—सन् १९२६ का श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून (सशोधित रूप में)—सामाजिक बीमा—भारत में औद्योगिक भगडों का इतिहास—१९३६ के पश्चात् औद्योगिक भगडे—औद्योगिक भगडों की रोकथाम—व्यापार विग्रह विधान (ट्रेड डिस्प्यूट्स सेजिस्लेशन)—सन् १९२३ का व्यापार विग्रह अधिनियम—जाँच किस प्रकार की होगी—जाँच-न्यायालय का निर्माण—समझौता बोर्ड—क्रिया-विधि—जनोपयोगी सेवाओं में हड़ताल—ग्रवेध हड़तालें—१९३४ का बम्बई व्यापार विग्रह समझौता अधिनियम (दि बॉम्बे ट्रेड डिस्प्यूट्स कन्सीलेशन एक्ट)—बम्बई औद्योगिक विग्रह अधिनियम (१९३८)—बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम (१९४६)—औद्योगिक विग्रह अधिनियम (१९४७)—भारत में श्रम-संघ ग्रान्दोलन—भारत में श्रम-ग्रान्दोलन की कठिनाइयाँ—१९२६ का श्रम-संघ अधिनियम—औद्योगिक कल्याण—कल्याण-कार्य की प्रकृति—कल्याण-कार्य का विभाजन—कल्याण-कार्य के मद—शिक्षा—ग्रोपधि सहायता—प्रसवकालीन लाभ—ग्रामोद-प्रमोद—आवास—सहकारी समितियाँ—ग्रन्न-बस्त्र की दूकानें—चाय की दूकानें और केण्टीन ।

राष्ट्रीय आय के अनुमान—दादाभाई नौरोजी का अनुमान—राष्ट्रीय आय १८७५ से १९११ तक—वाडिया और जोशी का अनुमान—शाह और खवाटा का

अनुमान—क्रिण्डले शिराज का अनुमान—वी० के० आर० वी० राव का अनुमान—
ईस्टर्न इकनामिस्ट का अनुमान—व्याख्या तथा तुलना की कठिनाइयाँ—अन्तर्राष्ट्रीय
तुलनाएँ—Tहन परीक्षण—क्या भारतीय दरिद्रता घट रही है—अधिक सही प्रांकडे
की आवश्यकता—बाउली-रावटसन जांच—प्रांकडे सकलित करने का सकलन—
राष्ट्रीय आय की माप—उत्पादन-गणना—ग्रामीण सर्वेक्षण—राष्ट्रीय आय-सम्बन्धी
आधुनिक अनुमान— भारतीय दरिद्रता की बटान वाली उपयोग-सम्बन्धी कुछ भूलें ।

१८ सवहन

१२७-१६५

परिवहन का महत्त्व—रेलवे—स्वतन्त्रता से पूर्व—रेलवे के विकास के प्रधान
काल—खण्ड—पुरानी गारण्टी प्रथा—सरकारी निर्माण और प्रबन्ध (१८६६-७६)—
नया गारण्टी सिस्टम (१८७६-१९००)—रेलो का शीघ्र विस्तार और लाभ का
प्रारम्भ (१९००-१९१४)—रेलो का विघटन (१९१४-१९२१)—प्राकट्य-समिति
(१९२१-२५)—भारत में सरकारी प्रबन्ध के पक्ष में मत—साधारण वित्त से रेलवे
वित्त का पृथक्करण (१९२४-२५ से १९२६-३०)—अवसाद-काल (१९३०-३१ से
१९३५-३६) तथा वेजबुड रेलवे-जांच-समिति (१९३६-३७)—द्वितीय विश्वयुद्ध-काल
और उसके बाद (१९३६-१९४७)—राज्य और रेलवे के बीच सम्बन्धों की विवि-
धता—स्वतन्त्रता के पदचात्—रेलवे के आर्थिक प्रभाव—रेलो के और अधिक विकास
की आवश्यकता—रेलवे प्रशासन की समस्याएँ—स्वतन्त्रता से पूर्व—रेलवे-दर-
नीति—प्रभावपूर्ण निरीक्षण का प्रभाव रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन—भारतीयकरण की
समस्या—रेलवे की समस्याएँ—स्वतन्त्रता के बाद—रेलवे में प्रगति तथा पंचवर्षीय
योजनाएँ—सड़क परिवहन—हाल का सड़क इतिहास—भारतीय सड़कों की विशेष-
ताएँ—अधिक सड़कों की आवश्यकता—सड़क बनाम रेलवे—सड़कों की प्रतिस्पर्धा
को कम करने के लिए अपनाय गए उपाय—परिवहन समय-नीति—रेल-सड़क-
संयोजन पर वेजबुड-समिति और उसके बाद—सड़क के मोटर यातायात (ट्रैफिक) का
नियमन—भारतीय सड़क-विकास-समिति और सड़क वित्त—नवीन सड़क नीति—
सड़क-खाते की आर्थिक दशा—सड़क-सम्बन्धी नवीन प्रस्ताव—नागपुर-योजना—
नयी सड़क योजना—पंचवर्षीय योजनाएँ और सड़क परिवहन—जल-परिवहन—
अन्तर्देशीय जल-यय—सामुद्रिक परिवहन—जलयान के सम्बन्ध में भारतीय साहस
की बाधाएँ—विलम्बित छूट व्यवस्था, दर-युद्ध इत्यादि—व्यापारिक जहाजरानी
समिति १९२३—तटीय यातायात को भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित करने का
विल—विलम्बित छूट-व्यवस्था की समाप्ति सम्बन्धी विल—जहाजरानी पुनर्निर्माण
नीति उप-समिति—भारतीय व्यापारिक बड़े की आवश्यकता—भारतीय
जलयान-निर्माण उद्योग की स्थिति—विजगापट्टम (अथ विशाखापटनम) का जल-
यान-निर्माण प्राण—वायु-परिवहन—नागरिक उड्डयन—बेंगलौर की वायुयान-
फैक्ट्री ।

१८ : भारत का व्यापार

१६६-१८६

बाह्य व्यापार—ऐतिहासिक सिंहावलोकन—१८६४-६५ से भारत का व्यापार—भारतीय बाजार के लिए संघर्ष—१९१४-१८ के युद्ध के पूर्व की स्थिति का सारांश—प्रथम विश्वयुद्ध का भारत के व्यापार पर प्रभाव—दोनों युद्धों के बीच के समय में व्यापार (१९१६-२० से १९३६-४०)—विश्व के आर्थिक अवसाद-काल में भारत का व्यापार—विश्व का आर्थिक समुत्थान और भारत का व्यापार—गिरावट (रिसेशन) के समय में भारत का व्यापार (१९३७-३८ से १९३८-३९ तक)—युद्ध-काल (१९३९-४५) में भारत का विदेशी व्यापार—ग्रेगरी-मीक मिशन—निर्यात-परामर्श-समिति तथा अन्य उपाय—राजकीय व्यापार-निगम और तदनन्तर—निर्यात-प्रोत्साहन—भारत के समुद्र-वाहित व्यापार की विशेषताओं में हुए परिवर्तन—१९५०-५१ के बाद—व्यापार की रचना में हाल में हुए परिवर्तन—भारत के व्यापार की दिशा—१९१४ से पहले भारत के व्यापार का वितरण—युद्धकाल (१९१४-१८) में भारत के व्यापार का वितरण—भारत के विदेशी व्यापार (१९१४-१८) की युद्धोत्तर प्रवृत्तियाँ—द्वितीय विश्वयुद्ध और उसके उपरान्त व्यापार की दिशा में परिवर्तन—भारत का मध्यागार (पुनर्निर्यात) व्यापार—व्यापारिक सतुलन—भारत के स्थिति-विवरणपत्रक (बैलेस शीट) में नामे और जमा की मदें—देश का (भौमिक) सीमान्त व्यापार—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक समृद्धि—अदायगी शेष तथा निर्यात उन्नति के साधन—आन्तरिक व्यापार—तटीय व्यापार—आन्तरिक व्यापार—भारत के प्रधान व्यापारिक केन्द्र—व्यावसायिक ज्ञान तथा व्यापार-संगठन—भारत के वाणिज्यिक संगठन ।

२० : व्यापारिक समझौते

१९०-२१०

साम्राज्य अधिमान (इम्पीरियल प्रेफरेंस) आन्दोलन का इतिहास—साम्राज्य अधिमान के प्रति भारत का रुख—ग्रीटावा-समझौता—ग्रीटावा-समझौता : पक्ष—ग्रीटावा-समझौता : विपक्ष—बम्बई-लकाशायर टेक्स्टाइल समझौता (मोदी लीज पेक्ट)—१९३५ का पूरक आंग्ल-भारतीय व्यापारिक समझौता—ग्रीटावा-समझौते पर धारासभा का विरोधी निर्णय—आंग्ल-भारतीय व्यापारिक समझौता (१९३६)—भारत-जापानी समझौते की उत्पत्ति (१९३४)—१९३४ के समझौते की धाराएँ—१९३४ के भारत-जापानी समझौते की कार्य-विधि—नवीन जापान-भारत व्यापारिक समझौता (१९३७)—१९४० का अस्थायी समझौता—१९४१ का नया बर्मा-भारत व्यापारिक समझौता—बर्मा द्वारा भारत को दी गई रियायतें—भारत द्वारा बर्मा को दी गई रियायतें—द्विपक्षी (बिलेटरल) व्यापारिक समझौतों की नयी रीति—जी० ए० टी० टी०—आधुनिक व्यापारिक समझौते ।

२१ : चलार्थ और विनिमय (भाग १)

२११-२४५

ब्रिटिश काल से पूर्व भारतीय चलार्थ (करेन्सी)—प्रथम युग (१८०१-१८३५)

—टिप्पणी—द्वितीय काल (१८३५-७४)—तृतीय काल (१८७४-९३)—चतुर्थ काल (१८९३-१९००)—भारत सरकार की वित्तीय कठिनाइयाँ—विनिमय-दर की गिरावट का भारतीय जनता पर प्रभाव—विनिमय और विदेशी पूंजी में गिरावट—यूरोपीय अधिकारियों की दशा—होमल समिति की सिफारिशें—फाउलर समिति (१८९८)—द्रव्य सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपनाये गए उपाय—स्वर्ण का प्रचलन—नोट और रुपये जारी करना—स्वर्ण प्रमाण सुरक्षित कोप—१९०७ और १९०८ का सफट—स्वर्ण प्रमाण अथवा स्वर्ण विनिमय प्रमाण—स्वर्ण विनिमय प्रमाण का स्वरूप—कौंसिल ड्राफ्ट प्रथा—चेम्बरलेन आयोग—१९१४-१८ के युद्ध का भारतीय करेन्सी पर प्रभाव—प्रथम युग (अगस्त, १९१४ से फरवरी, १९१५ तक)—द्वितीय काल (फरवरी, १९१५ से १९१९ से अन्त तक)—चाँदी व मूल्य में वृद्धि—सरकार द्वारा किये गए उपाय—सरकार का विनिमय पर नियन्त्रण—विनिमय-दर की वृद्धि—रजत-त्रय—चाँदी की सुरक्षा और उसकी मितव्ययता—पत्र-मुद्रा-प्रसार—आर्थिक उपाय—बैंकिंगन समिति—रिपोर्ट पर सरकार की कार्यवाही—विनिमय-नियन्त्रण—सावरेन के कानूनी मुद्रा मूल्य में परिवर्तन—युद्धकालीन प्रतिबन्धों की समाप्ति—रिर्वर्स कौंसिल की विक्री—सरकारी नीति की परीक्षा—नित्किप्रता की नीति (१९२१-२५)—भारतीय पत्र-मुद्रा—प्रारम्भिक इतिहास—नकद मुगलान और कानूनी मुद्रा-सम्बन्धी प्रतिबन्ध—पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप—पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप की आलोचना—१९१४-१८ के युद्ध का पत्र-मुद्रा पर प्रभाव—पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप का पुनर्निर्माण—स्थायी विधान—३१ मार्च १९२५ और १९३५ के बीच पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप की बनावट और स्थिति—नोट प्रचलन और करेन्सी की खपन—कुल और सक्रिय नोट प्रचलन—करेन्सी के विचित्र रूपों की सप्त ।

२२ चलार्थ और विनिमय (भाग २)

२४६-२७६

कारंरत हिल्टन यग कमीशन—स्वर्ण विनिमय प्रमाण के दोष—सुरक्षित कोप और शेप (बैलेन्सिज)—विप्रेषित धनराशियों (रिमेटेन्सिज) का प्रबन्ध—मुद्रास्फीति और मूल्यों की वृद्धि—अविचारित एवं व्ययशील पद्धति—आन्तरिक बनाव बाह्य स्थिरता—स्वर्ण पिण्ड प्रमाण—स्वर्ण की क्रय-विक्रय दरें—नोटों की परिवर्तनीयता—सुरक्षित कोप का एकीकरण और बनावट—स्वर्ण पिण्ड बनाव स्वर्ण करेन्सी प्रमाण—स्वर्ण पिण्ड प्रमाण की आलोचना—भारत में स्वर्ण करेन्सी प्रमाण का पक्ष—आयोग के प्रस्तावों के विरुद्ध अन्य आपत्तियाँ—रुपये का स्थायित्व—स्थायित्व का अनुपात—विमति टिप्पणी (मिनट ऑफ डिबेट)—विनिमय दर के विवाद का परीक्षण—बहुमत के तर्कों की आलोचना—१ सि० ४ पैस की दर के पक्ष का आलोचनात्मक परीक्षण—अनुपात (विनिमय-दर) के विवाद का तदनन्तर विकास (अप्रैल १९२० से सितम्बर १९३१ तक)—सरकार द्वारा हिल्टन यग आयोग की रिपोर्ट का स्वीकरण—मार्च, १९२७ का करेन्सी एक्ट—स्टैलिग और स्वर्ण का सम्बन्ध तथा भारत में इसकी प्रति

क्रियाएँ—रुपये को १० शि० ६ पैस से सम्बन्धित करना—भारत से स्वर्ण-निर्यात—
अनुपात का प्रश्न और रिजर्व बैंक बिल—नये करेन्सी अधिकारी के रूप में रिजर्व
बैंक ऑफ इण्डिया का विनिमय दायित्व—करेन्सी के सम्बन्ध में आधुनिक व्यवस्था
—अवमूल्यन का पक्ष और विपक्ष—अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्यात्मक कोष और रुपये का सम-
मूल्य—रुपये का अवमूल्यन (सितम्बर १९४६)—द्वितीय विश्व-युद्ध का भारतीय
चलार्थ (करेन्सी) और विनिमय पर प्रभाव—रुपये के सिक्के को प्रचलन से वापस
लेना और एक रुपये के नोट का प्रचलन—चाँदी के सिक्के के रजत तत्व में कमी
—दशमलव प्रणाली—विनिमय-नियन्त्रण—स्वर्ण के आयात निर्यात पर प्रतिबन्ध
—साम्राज्य का डालर सचय तथा युद्धोत्तर डालर कोष सम्पायर (डालर पूल एण्ड
पोस्ट वार डालर फण्ड) ।

२३ . भारतवर्ष में मूल्य

२७७-२६०

१८६१ से हुए मूल्य-परिवर्तनों पर एक विह्वल दृष्टि—१८६१ से १८६३
तक—मूल्य जाँच-समिति (१८६० से १९१२)—१९१४-१८ के युद्ध से पूर्व मूल्यों की
वृद्धि के कारण—विशेष रूप से भारतीय कारण—विश्वव्यापी कारण—पूर्व अवसाद-
काल तथा युद्ध-काल (१९१४-१८) में मूल्य—मुद्रास्फीति—ऊँची कीमतों का
प्रभाव—किसानों पर प्रभाव—उद्योगों पर प्रभाव—ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरों के
श्रमिक—स्थिर आमदनी वाले व्यक्तियों पर प्रभाव—अवसाद और उसके बाद के
समय में मूल्य—मूल्यों के घटने के कारण और प्रभाव—सितम्बर १९३६ के बाद
कीमते—द्वितीय महायुद्ध काल तथा युद्धोत्तर काल में मूल्य-परिवर्तनों का प्रभाव—
स्वतन्त्रता के उपरान्त मूल्य—मूल्य-नीति ।

२४ . अधिकोपण (बैंकिंग) और साख

२६१-३३७

भारतीय अधिकोपण का इतिहास—देशी अधिकोप—देशी अधिकोप की वर्त-
मान स्थिति—पुरानी तथा नई अधिकोप-प्रणाली के एकीकरण की आवश्यकता—
देशी साहूकारों से सम्बन्ध स्थापित करने की रिजर्व बैंक की योजना—आधुनिक
अधिकोप का उदय—प्रेसीडेन्सी बैंक—सुरक्षित कोष-पद्धति—प्रेसीडेन्सी बैंक के कारो-
बार तथा विकास—विनिमय बैंक (विदेशी बैंक)—विनिमय बैंकों के कारोबार तथा
उनकी वर्तमान स्थिति—विदेशी बैंकों पर प्रतिबन्ध—भारतीय विनिमय बैंक का
श्रीगणेश—मिश्रित पूँजी के बैंकों का इतिहास—बैंकों का दिवाला—बैंकों का दिवाला
निकलने के कारण—पर्याप्त नकद कोष का महत्व—बैंक-सम्बन्धी नियमन—सशो-
धित इण्डियन कम्पनीज एक्ट (१९३६) में बैंकिंग कम्पनियों से सम्बद्ध विशेष विधान—
बैंकिंग के नियमन हेतु हाल में की गई वैधानिक व्यवस्थाएँ—निकासी गृह—पोस्टल
सेविंग बैंक—भारतीय द्रव्य बाजार की विशेषताएँ तथा ऋटियाँ—द्रव्य की दरी में
भ्रामकता तथा गोलमाल—द्रव्य-सम्बन्धी मौसमी तर्गी—हुण्डी के बाजार का अभाव—

दृष्टी के बाजार की वृद्धि करने के उपाय—केन्द्रीय बैंक की उपयोगिता—इम्पीरियल बैंक की रचना—इम्पीरियल बैंक का विधान—इम्पीरियल बैंक के कार्य—सार्वजनिक सस्था के रूप में कार्य—इम्पीरियल बैंक की आलोचना के विषय—इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया सशोधन एक्ट, १९३४—स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया—रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट १९३४—रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया कार्यरूप में—रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (सार्वजनिक स्वामित्व का हस्तान्तरण) एक्ट १९४८—१९४९ के बाद भारतीय बैंकिंग—औद्योगिक वित्त—औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८—सचय करन की प्रवृत्ति—भारतीय बैंकरो की सस्था—बैंको की वर्तमान स्थिति ।

२५ : वित्त और कर

३३८-३८८

परिचयात्मक विचार—आय के केन्द्रीय शीर्षक—निराक्राम्य (कस्टम) प्रशुल्क का इतिहास—युद्धकालीन तथा उत्तर युद्ध-कालीन निराक्राम्य प्रशुल्क पद्धति—केन्द्रीय उत्पाद-कर—आय-कर का इतिहास—आय-कर में सुधार—कृषि-आय पर कर—उत्तराधिकार-कर—सम्पत्ति-कर—व्यय-कर—उपहार-कर—अफीम—माल-युजारी—आवकारी—आय के अन्य साधन—प्रान्तीय स्वायत्त-शासन के अन्तर्गत नये कर विक्री-कर—भारत में सार्वजनिक व्यय—नागरिक प्रशासन पर व्यय—कर-भार का वितरण—भारतीय वित्त का संक्षिप्त इतिहास—घाटे के बजट—भारत में लोक ऋण का सर्वेक्षण—पोण्ड-पावना—प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकारों के बीच वित्तीय सम्बन्ध—१९१९ के सुधारों के पूर्व के वित्तीय सबंध—१९१९ के सुधारों के अन्तर्गत पारस्परिक आर्थिक सम्बन्ध—मेस्टन परिनिर्णय—प्रान्तीय अशदान का अन्त—भारत में सघात्मक वित्त की समस्या—१९३५ के विधान के अनुसार केन्द्र और प्रान्तों के बीच आय-स्रोतों का बँटवारा—सर ऑटो निमेयर द्वारा वित्त सम्बन्धी जांच—प्रान्तों को सहायता—नमभौत के सिद्धान्त—प्रान्तों द्वारा आपत्ति—केन्द्र की आवश्यकताएँ—प्रान्तों को आय-कर का भाग अभिहस्ताकित करने में निमेयर सूत्र में सशोधन—देशमुख परिनिर्णय—वर्तमान प्रान्तीय अर्थ-प्रबन्ध—रेल वित्त—सेपरेशन कान्वेंशन के अन्तर्गत रेल विभाग के आर्थिक परिणाम—स्थानीय वित्त—स्थानीय (गाँव-सम्बन्धी) बोर्ड—नगरपालिका वित्त—स्थानीय सस्थाओं के अपयाप्त साधन—साधनों के अपवाप्त होने का कारण—साधनों की उन्नति ।

२६ बेरोजगारी

३८९-३९९

अध्ययन का क्षेत्र—ग्रामीण वृत्तिहीनता दुर्भिक्ष का वर्तमान रूप और उसका उपचार—दुर्भिक्ष का उत्तरदायित्व—मध्यवर्गीय बेरोजगारी समस्या का विस्तार क्षेत्र—मध्यवर्गीय बेरोजगारी की समस्या की गम्भीरता और प्रसार—विशेष रूप से प्रभावित वर्ग—वृत्तिहीनता के कारण—वृत्तिहीनता को दूर करने के उपचार वृत्ति व्यूरो—वृत्ति विनिमयालय—अन्य उपचार—सप्रू (वृत्तिहीनता) समिति—बेरोजगारी तथा योजनाएँ ।

२७ : भारतीय पंचवर्षीय योजनाएँ

४००-४०६

भूमिका—योजनाओं के लक्ष्य—पहली दो योजनाएँ—तीसरी पंचवर्षीय योजना—तीसरी योजना और रोजगारी—तीसरी योजना का मूल्यांक—चौथी पंचवर्षीय योजना—इस योजना में व्यय—विशेष उद्देश्य—भारतीय योजनाओं में कमी।

परिशिष्ट : रुपये का अद्यमूल्यन

४१०-४१४

द्वितीय भाग



अध्याय १

औद्योगीकरण : साधन तथा विधि

१. भारत में संरक्षण के पक्ष में प्रमुख तर्क—संरक्षण के लिए भारतीय उद्योगों की स्पष्ट उपयुक्तता को और सकेन करते हुए १९२४ के अर्थ-आयोग (फिस्कल कमीशन) ने प्रो० पीगू के निम्नलिखित शब्दों को उद्धृत किया—“उत्पादन के प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न किसी भी कृषि-प्रधान देश में उत्पादन-क्षमता बढ़ाने के लिए संरक्षण की नीति का दृढ़ता से समर्थन किया जा सकता है। ऐम देश में संरक्षण के फलस्वरूप देश के उत्पादन का विदेशी उत्पादन से कम विनिमय होने का कारण जो हानि होगी, अन्ततोगत्वा राष्ट्र को देश की उत्पादन-शक्ति के विकास की तीव्र गति द्वारा उसकी पूर्ति से अधिक लाभ होगा। संरक्षण-कर, जिन्हें कालवर्ट ने नये उद्योगों को चलना सिखाने वाली बैसाखी बताया है, उद्योगों के स्वतः चलना सीखने की अपेक्षा उन्हें इनकी जल्दी चलने की शक्ति प्रदान कर देती है कि बैसाखियों की लागत से वही अधिक लाभ प्राप्त होता है।”

२. संरक्षण और राष्ट्रीय स्व-निर्भरता—जो लोग संरक्षण के पक्षपाती होते हैं, वे हर सम्भव उपाय से निर्यात को भी प्रोत्साहन देने का समर्थन करते हैं। किन्तु यह स्पष्ट है कि यह आत्म-निर्भरता के आदर्शों के विपरीत है, क्योंकि निर्यात के साथ-साथ आयात अवश्यमेव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त यह प्रश्न भी किया जा सकता है कि क्या एक राष्ट्र की स्व-निर्भरता व्यक्ति की आत्म-निर्भरता से किसी भाँति अधिक वाछनीय है? डॉ० एडविन कैनन का कथन है कि “संरक्षण का कट्टर पक्षपाती उस साधु को भाँति है जिसे अपने पड़ोसी में कुछ भी खरीदना स्वीकार नहीं।” और एक साधु राष्ट्र एक साधु व्यक्ति से किसी भी भाँति अधिक प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। साधारणतया आत्म-निर्भरता के आदर्शों का पालन सापेक्षिक लागत के नियम द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही करना चाहिए और जहाँ उद्योगों के सम्बन्ध में नीति पर विचार करना चाहिए, जिनके सम्बन्ध में एक देश को निश्चित रूप से प्राकृतिक सुविधाएँ प्राप्त हो।

राष्ट्रीय स्व-निर्भरता के सिद्धान्त का समर्थन बहुधा राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टि-कोण से किया जाता है। भारत उत्पादन के विभिन्न साधनों से सम्पन्न एक विशाल देश है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए आत्मनिर्भरता ग्रेट

१. 'फिस्कल कमीशन रिपोर्ट (१९२४)', पृष्ठ ७४।

२. 'श्वेतनिष्ठ जनता', मार्च १९१९, पृष्ठ ७९।

ब्रिटेन की अपक्षा अधिक सुलभ है। किन्तु न तो यह सम्भव ही है और न वाछनीय ही, कि भारत अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य सारे देशों से सम्बन्ध विच्छेद कर ल।

३ भारत में सरक्षण के पक्ष में प्रबल भावना—ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनायी गई स्वतन्त्र व्यापार की नीति मुख्यतया इस सन्देश के कारण अलोकप्रिय रही कि मुक्त-द्वार की यह नीति भारत की अपक्षा ब्रिटेन के हितों की अधिक पोषक थी। यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी और यहाँ तक कि जापान जैसे अन्य देशों की समृद्धि भी सरक्षण के ही बल पर हुई थी। लोगों को इस तर्क पर विश्वास ही नहीं होता था कि उनके विकास के कारण बिल्कुल दूसरे ही थे तथा सरक्षण उनके औद्योगिक विकास में सहायक होने के बजाय गतिरोधक सिद्ध हुआ था। यह भी कहा जाता था कि ब्रिटेन न स्वयं भी सरक्षण की नीति का तभी परित्याग किया, जब उसकी औद्योगिक श्रेष्ठता का सिक्का निश्चित रूप से जम चुका था। यह बात भी सत्य थी कि ब्रिटेन में स्वतन्त्र व्यापार-काल का प्रारम्भ कृषि से सरक्षण हटाकर उद्योगों को सरक्षण देने के ध्येय से हुआ था। अन्त में, १९१५ से स्वयं ही सरक्षण की नीति का अनुसरण करने के कारण ग्रेट ब्रिटेन किस मुँह से भारत को स्वतन्त्र व्यापार की शिक्षा दे सकता था ?

प्रथम महायुद्ध (१९१४-१८) के बाद सार्वजनिक चर्चा में हुई अत्यधिक वृद्धि ने सरकार को आयात कर बढ़ाने के लिए बाध्य कर दिया। यह एक ऐसी पद्धति थी जो बहुत-से उद्योगों के लिए स्वतः सरक्षक सिद्ध हुई। अव्यवस्थित और अनियमित होने के कारण ऐसे सरक्षणों के कुछ परिणामों का अहितकर होना अवश्यम्भावी था। किसी स्थायी नीति के आश्वासन के बिना ही इन्होंने उद्योगों को प्रश्रय दिया, अतएव यह आवश्यक नहीं था कि सरक्षण उन्हीं उद्योगों को मिलेगा जो इस योग्य थे। आयात बढ़ाने के उद्देश्य से लगाये गए ऊँचे निराकाम्य कर (कस्टम ड्यूटीज), जो संयोग से सरक्षणात्मक भी थे, औद्योगिक विकास में सहायक सिद्ध होने के बजाय अधिक बाधक थे।

४ विवेचनात्मक सरक्षण—अर्थ आयोग द्वारा निर्धारित निम्नलिखित सामान्य नियमों को पथ प्रदर्शन के लिए अपनाया गया है—(१) उद्योगों को प्राकृतिक सुविधाओं से सम्पन्न होना चाहिए, उदाहरणार्थ कच्चे माल की पूर्ति की अधिकता, सस्ती शक्ति, श्रम की पर्याप्त पूर्ति और देश में विस्तृत बाजार की उपलब्धि। (२) सरक्षण उन उद्योगों को ही देना चाहिए जो या तो उसके बिना बिल्कुल पनप ही न सकते हों या इसके अभाव में जिनका विकास उस गति से न हो सकता हो, जो राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक है। (३) सरक्षण दिया जाने वाला उद्योग ऐसा होना चाहिए जो आगे चलकर बिना सरक्षण के ही विश्व-प्रतिस्पर्द्धा का सफलतापूर्वक सामना कर सके।

अन्य गौण सुझावों के अनुसार वे उद्योग जिनमें वृद्धिमान प्रत्युपलब्धि नियम लागू हों तथा वे उद्योग जिनसे निकट भविष्य में ही सारे देश की आवश्यकता-पूर्ति का आश्वासन मिलता हो, सरक्षण-योग्य हैं। ऐसे उद्योगों को सरक्षण कभी नहीं मिलना

चाहिए जिनसे देश की आवश्यकता की केवल आंशिक पूर्ति हो सकती हो ।

कभी कभी बाहरी देशों द्वारा राशिपातन (डम्पिंग) करने पर सरक्षण प्रपनाया जा सकता है या उमम वृद्धि की जा सकती है । जब यह स्पष्ट रूप से विदित हो जाए कि अन्य देश राशिपातन कर रहे हैं और इस कारण उम राष्ट्रीय उद्योग को हानि पहुँच रही है, जिसकी समृद्धि में राष्ट्र की समृद्धि सम्बद्ध है तो एक विशेष राशिपातन-कर आवश्यक हो सकता है । जिन देशों में मुद्रा का मूल्य बहुत कम हो गया हो जिसके फलस्वरूप वे अन्य सुदृढ़ मुद्रा वाले देशों के साथ नीचे भाव पर निर्यात करने के योग्य हो गए हो, तो उन देशों की वस्तुओं पर भी ऐसे कर लगाना उचित ठहराया जा सकता है । १८६६ के १४वें अधिनियम के अनुसार यदि कोई भी देश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्यात को आर्थिक सहायता देता है, तो गवर्नर जनरल को यह अधिकार है कि भारत गजट में अधिमूचित करके ऐसी सहायता की वास्तविक मात्रा के बराबर आपात पर अतिरिक्त कर लगा दे ।^१

अर्थ-आयोग के विचार में प्रायः नवीन उद्योगों को ही सरक्षण प्रदान करना चाहिए । फिर भी उनका मत है कि सुदृढ़ उद्योगों के साथ भी ऐसी आकस्मिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जब उन्हें सरक्षण देना उचित हो, ताकि वे उन कारणों में उत्पन्न संक्रमणकालीन मन्दी का सामना कर सकें, जिनका उपचार उनकी शक्ति के परे है । समय-समय पर मृती वस्त्र उद्योग को दिया गया सरक्षण इस कोटि में भली भाँति आता है क्योंकि यह उद्योग अब अपनी शैशवावस्था में नहीं है ।

पूर्ण रूप से नवीन उद्योगों के विषय में अर्थ-आयोग व सदस्यों का विचार था कि वास्तविक स्थिति का अध्ययन न कर नवीन उद्योगों के प्रवर्तकों को अनुमानों पर विश्वास करके सरक्षण प्रदान करना बहुत बड़ी जोखिम उठाना होगा । बिन्तु विद्यमान उद्योगों के सम्बन्ध में भी अनिश्चितता और अनुमान का सामना किये बिना नीति निर्धारित करना सम्भव नहीं है । परिकल्पना की मात्रा उन उद्योगों के सम्बन्ध में और भी अधिष्ठ होगी, जिनको अन्य शाखाएँ खोलने के लिए सरक्षण दिया जाएगा । फिर भी आयोग इस आधार पर सरक्षण देने का विरोधी नहीं था ।^२ अतएव यह स्पष्ट है कि उन सभी दशाओं में, जिनमें सरक्षण की मांग की जाती है, अनिश्चितता अवश्य विद्यमान रहनी । सरक्षण प्रदान किये जाने वाले एक नवीन उद्योग के विषय में यह सम्भव है कि बाहरी देशों में, जहाँ यह उद्योग पहले अस्तित्व में हुआ है, ऐसे विस्ववनीय तथ्य प्राप्त हो सकें जिनमें यहाँ इस उद्योग के विषय में कोई शक न रह जाए । अर्थ-आयोग का मत है कि आमतौर से नये उद्योगों के लिए सरक्षण आपत्तिजनक ही नहीं, बल्कि अनावश्यक सिद्ध होगा, क्योंकि सरकार की आर्थिक

१. अप्रैल, १९३३ में पास हुए उद्योग-सुरक्षा-अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल का यह अधिकार दिया गया था कि वह उन सभी दशाओं में अतिरिक्त कर लगा सकता है, जिनमें उसके अनुसार विदेशी माल का शतके कम मूल्य पर आयात हो रहा है कि उसमें एक तथा पत उद्योग की मकद है । ३१ मार्च, १९३५ को यह अधिनियम संशोधित हो गया ।

२. 'अर्थ-आयोग (विस्मय कमीशन) रिपोर्ट', पैरा १०० ।

आवश्यकताएँ आगम करो के स्तर को ऊँचा रखने के लिए बाध्य करेंगी। फलस्वरूप प्रारम्भ में आवश्यक सरक्षण स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। अतएव ऐसे उद्योग को, अन्यथा जिसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है, प्रारम्भ करने के पहले पर्याप्त सरकारी सहायता का आश्वासन प्राप्त होना चाहिए। सरकार द्वारा नया माहसोच्चमिथो को कुछ बैंकों की निम्नतम व्याज-दर की गारण्टी देने का सिद्धान्त, जिसका सभी क्षेत्रों में स्वागत हुआ है, मूलतः उन्हें सरक्षण देने की नीति के अलावा और कुछ नहीं है (नीचे सेक्शन १४ देखिए)। हर एक दशा में यह आवश्यक है कि उद्योग नीचे दी हुई शर्तें पूरी करे। भारतवर्ष के राष्ट्रीय महत्त्व के आधारोद्योगों में साधारणतया निम्न लिखित उद्योगों का नाम लिया जाता है—भारी रासायनिक उद्योग, रजक द्रव्य, यंत्र व औजार, रेल के डब्बे, इजन, हवाई जहाज, मोटरगाडिया, कागज, छुरी-काट, बरतन और बिजली के सामान।

किसी उद्योग को सरक्षण देना निश्चय कर लेने के बाद मुख्य समस्या सरक्षण की मात्रा निश्चित करना है। उद्योग को इतना अधिक सरक्षण नहीं देना चाहिए कि वह स्वतः प्रयत्न करना ही छोड़ दे। वास्तव में उद्योग को निष्क्रिय करने की अपेक्षा उस उत्तेजित करने की आवश्यकता है। कर की ऐसी यथोचित मात्रा, जो न कम हो न अधिक, निश्चित करना बहुत मुश्किल है। भारत और विदेशों की उत्पादन लागत की तुलना के लिए हम ऐसी औसत फर्मों का लेकर अध्ययन करना होगा, जो न तो असाधारण रूप से कुशल हैं और न अकुशल हैं।^१ सरक्षण की दर निर्धारित करते समय उपभोक्ताओं के हित का भी ध्यान रखना चाहिए। सरक्षण कर की दर ऊँची हानि में तीव्र औद्योगिक विकास हो सकता है, किन्तु मूल्य की अनुचित वृद्धि रोकने के लिए यह सम्भव है कि इस दर को कम रखना पड़े और विकास की अपेक्षाकृत मन्द गति को स्वीकार करना पड़े।

विवेचनात्मक सरक्षण की अनुचित रूप से कठोर और अनुदार व्याख्या करने की प्रवृत्ति को उस दूसरे शब्दों में रखकर कुछ सीमा तक ठीक किया जा सकता है। इंग्लैण्ड स्वयं कपास बाहर से मँगाता है, फिर भी सूती वस्त्रोद्योग में अब तक उसका स्थान वेजाड न सही, परन्तु उच्च कोटि का अवश्य है। फिर सूती वस्त्रोद्योग और अपने कई अन्य उद्योगों के लिए उसे बाहरी बाजारों पर निर्भर रहना पड़ता है, अतः अर्थ आयोग द्वारा सुभाषी गई पद्धति एक साधारण पथ प्रदर्शक के रूप में ही अपनायी जा सकती है। उसका शाब्दिक या कठोर पालन करना उचित नहीं। समय समय पर नियुक्त प्रमुख मण्डला (टैरिफ बोर्डों) और सरकार न भी इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया है। भारत में विवेचनात्मक सरक्षण की दूसरी आलोचना यह है कि

१. लागत विश्लेषण की जटिलता का अनुमान लगाने के लिए पाठक 'इंस्टिट्यूट फिस्कल प्रॉब्लम', (जे० सी० कोयानी द्वारा लिखित) पृ० ३६-३७ देखें वी० जी० काल 'इकनामिक्स आफ प्रोटेक्शन इन इण्डिया', सी० एन० वकील और एम० सी० भुगी, 'इण्टिड्यूशन टो इण्डियन विट्रिगल रफरेन्स टु कन्सुमर टैरिफ', पृ० ८२-८५, तथा टैरिफ बोर्ड की विवेचना रिपोर्टें देखें।

इसमें औद्योगीकरण की सम्पूर्ण समस्या को ध्यान में रखकर उद्योगों पर अलग-अलग विचार किया है। फलतः औद्योगिक विकास के पथ में अनावश्यक बाधाएँ उत्पन्न हो गई हैं और इसका स्वरूप अनियन्त्रित-या हो गया है।

भारतवर्ष में विवेचनात्मक संरक्षण की असफलता का प्रमुख कारण देश के शीघ्र औद्योगीकरण के प्रति ब्रिटिश सरकार की सहानुभूति का अभाव था। जैसा प्रो० वी० पी० अदरकर का कहना है, "पान्चाल्य देशों में सरकारों की सहायता से संरक्षण के अतिरिक्त और भी उपाय काम में लाये गए हैं, जैसे आर्थिक सहायता, राजकीय सहायता, औद्योगिक अनुसन्धान और औद्योगिक संस्थाओं का पथ-प्रदर्शन एवं नियन्त्रण। वास्तव में वहाँ विवेचनात्मक संरक्षण ने उद्योगों को उदासीन और अनमने भाव से नाम-मात्र की सहायता देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया है। तदनन्तर वे उद्योग अपने विकास के लिए स्वतन्त्र छोड़ दिये गए हैं। प्रमुख-मण्डल और सरकार की विलम्बकारी नीति के कारण प्राप्त संरक्षण बहुधा लाभकर नहीं होता।" इस भाँति भारतवर्ष में बहुत दिनों से औद्योगीकरण की समस्या का रूप आर्थिक की अपेक्षा राजनीतिक अधिक रहा है। अब स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई है, अतएव इसका हल सरल हो जाएगा।

५. विवेचनात्मक संरक्षण नीति में युद्धकालीन व्यवस्था की आवश्यकता—वास्तव में अत्र युद्ध-समाप्ति के बाहरी देशों की तीव्र स्पर्धा और संरक्षण को अकस्मात् समाप्त कर देने के फलस्वरूप उत्पन्न तीव्र असन्तुलन की स्थिति से अगले उद्योगों को बचाने के लिए एक सामान्य संरक्षण काल की आवश्यकता है। १९४७ ई० से प्रमुख-मण्डल विभिन्न उद्योगों के संरक्षण के लिए आये आवेदन-पत्रों पर विचार करने में लगा हुआ है और उनमें से बहुतों को संरक्षण मिल भी चुका है।

प्रत्येक उद्योग के सम्बन्ध में मण्डल निम्न बातों की जांच करता है (१) वह उद्योग कौन सी स्थापित और संचालित है या नहीं, (२) एक निश्चित समय में उसके विकास की सम्भावना है या नहीं, ताकि फिर संरक्षण अथवा किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता न रह जाए, (३) उस उद्योग को संरक्षण देना राष्ट्रीय हित में है अथवा नहीं और यह संरक्षण समाज को आर्थिक क्षति पहुँचाये बिना सम्भव है या नहीं। सरकार के आदेश पर मण्डल को निम्न कार्य भी करना पड़ते हैं—देश में पैदा होने वाली वस्तुओं के उत्पादन क्षमता की जाँच करना, अथक और कुटकर तथा अन्य मूल्यों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना, विदेशों की रनिपातन-नीति से उद्योग के लिए संरक्षण-सम्बन्धी सिफारिशें प्रस्तुत करना, आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न वस्तुओं पर

१. श्री पी० सी० जैन द्वारा संपादित, 'इण्टेस्ट्रियल प्रोब्लम्स ऑफ इण्डिया' में अदरकर का 'डिफेंस और वर्मगल पालिसी' नामक लेख देखिए।

२. लुह उद्योग, जिनमें मती बरतौद्योग, लोहा और इस्पात, कागज और लुगदी, मैग्नेशियम क्लोराइड और चीनी आदि के उद्योग भी सम्मिलित हैं, संरक्षित उद्योगों की कोटि से हटा दिये गए हैं।

मूल्यानुसार लगाये हुए तथा विजिष्ट करो के प्रभावों और प्रशुल्क-करो का मूल्यांकन करना तथा अन्य देशों को प्रशुल्क-कर में दी गई छूट के प्रभावों का अध्ययन करना, मूल्य को ऊँचा उठाने वाली, गिरने से रोकने वाली या प्रभावित करने वाली और इस भाँति व्यापार को रोकने वाली सस्थाओं, एकाधिकार, ट्रस्ट एव सयोजनों (कम्बिनेशन्स) के विषय में रिपोर्ट देना और उनकी गतिविधि को रोकने के लिए उपायों को सुझाना तथा संरक्षित उद्योगों पर निरन्तर दृष्टि रखना ।

अर्थ-आयोग द्वारा तैयार की गई प्रश्नावली में मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित थीं (१) आर्थिक पृष्ठभूमि में १९५२ से लेकर अब तक हुए परिवर्तन, (२) विवेचनात्मक संरक्षण की नीति और उसका प्रयोग, (३) गत प्रशुल्क-नीति के प्रभावों की समीक्षा, (४) संशोधित प्रशुल्क-नीति के सिद्धान्त, (५) व्यापार और उद्योग के लिए सम्भव गैर-आर्थिक उपाय, (६) व्यापार और नियोजन पर हवाना चार्टर के अनुसार निर्धारित अर्थ-व्यवस्था, (७) सहायता प्राप्त और संरक्षित उद्योग के अधिकार और कर्तव्य तथा (८) अर्थनीति और अधिमान । इस अर्थ आयोग (फिस्कल कमीशन) ने संरक्षण देने के लिए उद्योगों को तीन भागों में विभाजित किया—(१) सुरक्षा एव सैनिक महत्त्व के उद्योग, (२) आघारोद्योग, तथा (३) अन्य उद्योग । पहले प्रकार के उद्योगों को संरक्षण अनिवार्य रूप से देने की सिफारिश की गई, भले ही इससे समाज को कितना भी कष्ट क्यों न हो । दूसरे प्रकार के उद्योगों के संरक्षण के रूप और मात्रा का पूर्णतया निश्चय अर्थ आयोग के ऊपर था । इन उद्योगों को संरक्षण देने के लिए कोई सीमित शर्तें नहीं रखी गईं । तीसरे प्रकार के उद्योगों को संरक्षण देने के लिए दो शर्तें रखी गईं । प्रथम, उचित समय के भीतर ये उद्योग इतने विकसित हो सकें कि संरक्षण या किसी प्रकार की आर्थिक सहायता के बिना पनप सकें और द्वितीय, संरक्षण की सम्भाव्य लागत समाज के लिए अधिक न हो । अर्थ-आयोग ने एक स्थायी प्रशुल्क-आयोग (टैरिफ कमीशन) की नियुक्ति की सिफारिश की । प्रशुल्क-आयोग-अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत २१ जनवरी, १९५२ को सरकार ने प्रशुल्क-आयोग की स्थापना की, जिसके तीन सदस्य होते हैं (इनमें से एक सभापति होता है) । प्रशुल्क-आयोग को विस्तृत अधिकार दिये गए हैं, परन्तु इधर हाल में सरकार ने प्रशुल्क-आयोग की सिफारिशों में परिवर्तन करके उसके कार्य में हस्तक्षेप भी किया है जो अवाञ्छनीय है । सरकार ने मई १९६६ में डॉ० वी० क० ग्रार० वी० राव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो कि प्रशुल्क-आयोग के कार्य की जाच-पड़ताल करेगी तथा सुझाव देगी ।

६. संरक्षण से सम्भावित हानियाँ—जब एक उद्योग को संरक्षण प्राप्त हो जाता है, तो वह स्वभावतः उसका लाभ यथासम्भव समय तक उठाना चाहता है और वह जिन उपायों का बहुधा सहारा लेता है, उनमें से एक उपाय समृद्धि को छिपाना और प्रारम्भिक काल की असमर्थता का प्रदर्शन करना है । दूसरा उपाय आयात को कम करने वाली सस्था पर राजनीतिक प्रभाव डालना है । संरक्षण की अवधि को पहले से ही निश्चित कर लेना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि बीच में ही परिस्थितियों में

मौलिक परिवर्तन हो जाए तो संरक्षण की नीति पर पुनः विचार करना और सम्भवतः संरक्षण की अवधि बढ़ाना होगा ।

अर्थ-आयोग का मत है कि प्रशुल्क-मण्डल के लिए सन्तोपजनक नियन्त्रण बनाये रखने का एक ही रास्ता है कि वह संरक्षित उद्योगों की दशा की समय-समय पर जाँच करे और तर्कयुक्त निर्णय दे कि अमुक वस्तु पर कर बना रहने दिया जाए या हटा लिया जाए, और यदि बना रहने दिया जाए तो उसकी दर में परिवर्तन किया जाए या नहीं । प्रशुल्क-मण्डल के सदस्यों के चुनाव में सबसे अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है । संरक्षण के प्रयोग की सफलता इस सस्था की कार्य-प्रणाली पर निर्भर करती है ।^१ संरक्षण अपनाते वाले बहुत-से देशों में प्रशुल्क अधिनियम स्वार्थी गुटों में प्रभावित रहता है और समस्त देश के हित को ध्यान में रखकर निश्चित की गई योजना का शायद ही कभी अनुसरण करता है । अर्थ-आयोग का मत है कि विधानसभा में भिन्न-भिन्न स्वार्थों के प्रतिनिधित्व और विशेषकर कृषि तथा भूमि के मजदूर बने रहने वाले महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधित्व के कारण भारतवर्ष में अन्य देशों की भाँति अष्टाचार का भय नहीं है । किन्तु सम्भवतः यह परिस्थिति का अनावश्यक एवं अति आशावादी दृष्टिकोण से अध्ययन है तथा राजनीतिक अष्टाचार से उत्पन्न होने वाली हानियों को कम करके देखना है । संरक्षण द्वारा जो स्वार्थ फूलें-फलेंगे वे अपने विरोधियों की अपेक्षा अधिक साधनयुक्त तथा सुमगठित होंगे, क्योंकि विरोधी स्वार्थ भिन्न-भिन्न भाँति के होने के कारण प्रभाव-कारो ढग से युक्त नहीं हो सकते । विशेष व्यवहार की अपेक्षा रखने वाले उद्योगों की दशाओं में प्रशुल्क-मण्डल द्वारा की गई खोजों का अधिकाधिक प्रचार करने की आवश्यकता है ।

राजनीतिक अष्टाचार के अनिश्चित संरक्षण द्वारा प्रोत्साहित दूसरा दोष, जिससे बचने की आवश्यकता है, उत्पादकों का संयोजन है । किसी भाँति पैदा हुआ संयोजन वास्तव में देश के लिए हितकर है या नहीं, इसका उत्तरदायित्व प्रशुल्क-मण्डल पर ही है और यदि वह हानिकर है तो मण्डल को उस पर से संरक्षण उठा

१. सन् १९२६ के भारतीय आर्थिक सम्मेलन के सभापति-पद से भाषण करते हुए दिवंगत प्रोफेसर एम० एम० मुन्शाराव ने यह सुझाव रखा था कि यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल ट्रेड कमिशन और टैरिफ कमिशन की भाँति, जो अपनी विद्यार्थ-प्रणाली द्वारा सदैव नये-नये उपाय ढूँढते रहते हैं, भारत में भी एक राष्ट्रीय आर्थिक परिषद का निर्माण होना चाहिए । प्रशुल्क-मण्डल को उचित रूप से विस्तृत करना चाहिए और इसे उपममितियों तथा व्यक्तिगत सर्वेक्षकों की नियुक्ति की अनुमति देनी चाहिए । इसे स्वतः जांच और संवेक्षण करने तथा समय-समय पर अपने परामर्शों को सरकार के सम्मुख रखने का अधिकार देना चाहिए । यह शीघ्रता से की जाने वाली वर्तमानकालीन अव्यवस्थित राज्यों को दूर कर देगा, व्यवस्थित आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा और देश में आवश्यक औद्योगिक सन्तुलन को सुनिश्चित करेगा । साथ, १९३६ की विधानसभा में श्री एच० पी० मोदी ने सुझाव रखा कि ट्रेड-मिटेस की आयोजन-कर परामर्शदात्री समिति की तुलना में भारतीय प्रशुल्क-मण्डल को अधिक गतिशील और प्रभावशाली बनाने के लिए इसकी कार्यविधियों में संशोधन होना चाहिए ।

लेने या कम कर देने का सुझाव देना चाहिए ।

७ संरक्षण के अतिरिक्त अन्य आवश्यकतत्त्व — संरक्षण के बावजूद भी आधुनिक आर्थिक जीवन के अन्य अनिवार्य अंगों, जैसे एक कुशल बैंकिंग व्यवस्था, आवागमन के समुन्नत साधन, रेलों और जहाजों की दर-सम्बन्धी सहानुभूतिपूर्ण नीति, विक्रय के लिए सुगठित सप्लन, औद्योगिक और व्यापारिक सूचनाओं के लिए कुशल व्यवस्था, पूंजी-प्राप्ति के पर्याप्त साधनों आदि के अभाव में देश आर्थिक रूप से सदैव पिछड़ा रह सकता है ।

८ शिक्षा—भारतवर्ष में जिस बात की सर्वोपरि आवश्यकता है वह है प्रत्येक वर्ग के लोगों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन । 'आत्मविश्वास की बनी और माहस का अभाव, जो आज भारतीय चरित्र का अंग बन चुके हैं, हमारी दोषपूर्ण शिक्षा-व्यवस्था के परिणाम हैं । नीचे से लेकर ऊपर तक हमारी शिक्षा-पद्धति आवश्यकता से अधिक साहित्यिक और सस्थात्मक (एकेडेमिक) है । इसे और अधिक व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकता है । बुद्धिमानी से आयोजित शिक्षा-पद्धति अथवा प्रतिष्ठा के सिद्धान्तों पर जोर देने पर विशेष ध्यान देनी । हाथ से होन वाले कार्य अथवा भिन्न-भिन्न भाँति की रचनात्मक मानवीय क्रियाएँ प्रत्येक स्कूल के शिक्षा-क्रम

१. अपने एक पुराने शिष्य द्वारा पूछे जाने पर भारत के लिए मरक्षण के प्रश्न पर डॉ० माशल ने लिखा—“सिद्धान्त भारत में शौरव-वालीन उद्योगों को संरक्षण देने के विषय में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । किन्तु इन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निराक्राम्य कर एक बहुत महँगी विधि है । मेरे विचार से जब तक अन्य उपायों की परीक्षा न कर ली जाए इस्को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए । कम-से-कम उस समय तक इसे प्रयोग में नहीं लाना चाहिए जब तक कि वे उद्योग ह, जिन्हें माल पहुँचाने का लागत के लिए बहुत अधिक मरक्षण मिला है, (कुछ दशाओं में माल पहुँचाने की लागत का दूना संरक्षण मिला है) भारतीय साइस को प्रोत्साहित करने में सफल नहीं हो जाते । इस दृष्टिकोण से प्रमुख उद्योग चमड़ा, कागज और तिलहन के उद्योग हैं । यदि भारत के पास श्री टाटा के समान एक या दो कोठी व्यक्ति होते और जापानिया की भाँति वारतधिकता से सम्बन्ध रखने वाले, राजनीति और न्यायालयों में भाषण देने से घोर घृणा करने वाले और विचारों से भर मरिाधिक के साथ अन्य 'वस्तुओं' का काम करने से घृणा न रखने वाले कुछ व्यक्ति भी होते, तो भारत शीघ्र एक महान् राष्ट्र बन जाता । ऐसा होने पर कोई उसे रोक न सकेगा, न काइ निराक्राम्य कर ही वाधक सिद्ध हो सकेगा तथा अपनी परम्पराओं का वह शीघ्र प्राप्त कर लेगा । किन्तु जब तक उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीय सुनसृत विलास में अपना समय नष्ट करते रहेंगे या भारतीय न्यायालयों में धनोपार्जन करते रहेंगे—जा दोनों ही समुद्र के किनारे की रेत का भाँति ही दश के बहाराण के दृष्टिकोण से अनुपयोगी है—भारत के लिए कोई भी वस्तु लाभकर नहीं हो सकती । मैं २० वर्ष से मेम्ब्रिज में भारतीयों का जोर देकर बतला रहा हूँ कि वे दूसरों से पूछें कि हममें से कितने परिचम जाने समय अपने विकास के अतिरिक्त किसी अन्य विषय के बारे में सोचते हैं ? क्या जापानी सदैव अपने से नडा पूछा करते कि वे वापस लौटने पर किस भाँति अपने को अपने राष्ट्र के लिए अधिक-से-अधिक उपयोगी बना सकेंगे ? क्या उनको वास्तविक अध्ययन की लालसा नहीं रहता ? क्या परिचम की शक्ति के मूल पर वे दृष्टिपान नडा करते ? क्या वह जापान के शीघ्र विकास का प्रमुख कारण नहीं है ? क्या हम उसका अनुकरण नहीं कर सकते ? क्या हमें जापानियों का भाँति अपना देश के विषय में पहले और अपने विषय में बाद में सोचने का परिवर्तन लाने की आवश्यकता नहीं है ?”

(करीब्युलम) में रखी जानी चाहिए।^१ हाथ से होन वाले कार्यों के प्रति भारतवर्ष में पाई जान वाली ग्रहचि के कारण मुख्यतया सामाजिक है। किन्तु इस तथ्य का एक कारण यह भी रहा है कि अभी हाल तक भारतवर्ष के स्कूलों में बच्चों के लिए हाथ के कार्यों के लिए सन्तोपजनक प्रबन्ध का बिलकुल अभाव-सा रहा है। कुछ कलाश्रो या उत्पादक क्रियाश्रो के माध्यम से प्रारम्भिक स्कूला में शिक्षा देन के महात्मा गांधी के मौलिक विचारों पर आधारित वर्धा-शिक्षा-योजना का उद्देश्य हमारी शिक्षा-पद्धति के उपर्युक्त दायों को दूर करना है।^२ बहूत-स प्रान्तों एव राज्या में इसका उपयोग हो रहा है।^३ विद्यार्थी को अपनी आसों और हाथ का अधिकाधिक उपयोग निखलाना उचित शिक्षा पद्धति का एक उद्देश्य होना चाहिए। किसी भी भाँति की शिक्षा या उच्च शिक्षा के अभाव से भारतीय श्रमिक केवल अकुशल और अविश्वसनीय ही नहीं हो जाता, वरन उसकी आत्मोन्नति की सारी अभिलाषा ही मर जाती है। शिक्षा उमकी आवश्यकताश्रो को बढ़ा दगी, उनको पूर्ति के लिए अधिक श्रम श्रद्धों तरह से काम करन के लिए उम प्रेरित करेगी और इस प्रकार उसन जीवन को समुन्नत कर दगी। भारतीय उद्योगों की एक समस्या यह है कि कुशल कार्यक्षता, निरीक्षक एव यन्त्रा के चालक बाहर से मँगान पड़त हैं। ये मनुष्य स्वभावतः महँगे पटन हैं और उन्हें ऊँची दर से पारिश्रमिक देना पड़ता है। इस अलावा उनको उनक देश वापस करत समय भी भारी खर्च उठाना पड़ना है। अथ प्रायोग न मिफारिश की थी कि सरकार का चाहिए कि विदेशी फर्मों का आर्डर देन समय शिक्षार्थियों (अप्रेंटिसज) के प्रशिक्षण की गन भी टण्डर में रखे। कुशल कायकताश्रो, निरीक्षकों एव यन्त्र चालकों के अनिश्चित भारतीय प्रबन्धकों की भी आवश्यकता है। इस क्षेत्र में आवश्यक प्रशिक्षण के हेतु विदेश जान के लिए राज्य द्वारा दी गई प्राविधिक छात्रवृत्तियाँ बहुत सीमित मात्रा में ही आवश्यकता की पूर्ति कर सकती हैं। इन समस्या का एकमात्र वास्तविक हल यह है कि देश में ही हर श्रेणी के प्राविधिक विद्यालय खाल जाएँ ताकि भारतीय उद्योग प्रत्येक प्रकार के विदेशी श्रम न छुटकाय पा जाएँ। औद्योगिक समस्याश्रो में अनुसन्धान कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण श्रेणी का कार्य है। सरकार के नामन-सम्बन्धी आवश्यकताश्रो के उद्देश्य में बनायी गई अत्यधिक साहित्यिक ढग की शिक्षा कुछ असा में विद्यालयों तथा विन्विद्यालयों में आधुनिक विज्ञान के अध्यापन और उसकी बढ़ती महत्ता के कारण कम हो गई है। विनिष्ट मत्वा से व्यक्तिगत सम्पत्क एव प्रयागदानों में सम्भव प्रमाण-योग्य तर्क का अन्याय मनुष्यों के विचारा और क्रियाश्रो को लाभकारी दिशा प्रदान करते हैं। वाणिज्यिक एव प्राविधिक स्कूला तथा कॉलेजों के भी ऐसे ही वाछनीय फल होन चाहिए। जीवन-मध्य की बढ़ती तीव्रता पड़े लिये लागू को सरकारी नौकरियों की अपेक्षा व्यवसाय की ओर खीच रही है, क्योंकि सरकारी नौकरियाँ अमत्य

१. ए० एब्बट और एन० एब० बुल्, 'रिपोर्ट ऑन बकानाल एजुकेशन इन इण्डिया', पृ० ३० ।

२. 'रिपोर्ट ऑन द इन्विरहुमन कमिटी', मन्शन १ ।

३. सी० ले० बर्से, 'द बवान्कीन ऑफ एजुकेशन', दिल्लीय सुस्करण, अयाव ६ ।

स्नातको को प्राप्त नहीं हो सकती ।

६ भारत में औद्योगिक शिक्षा की स्थिति—विक्टोरिया जयन्ती प्राविधिक शिक्षालय (विक्टोरिया जुबिली टेक्निकल इस्टीट्यूट), जो बम्बई में मुख्यतया व्यक्तितगत प्रयत्नों द्वारा १८७७ में प्रारम्भ किया गया था, ही स्थानीय मिल-उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश में इस प्रकार की एकमात्र संस्था है । भारतीय शिक्षा-पद्धति के दोषों की जांच पड़ताल में, जो लॉर्ड कर्जन ने प्रारम्भ की थी और १९०१ में शिमला में शिक्षा-विशेषज्ञों का एक सम्मेलन बुलाया था, प्राविधिक शिक्षा व प्रश्न को अत्यधिक महत्व प्रदान किया ।

औद्योगिक आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशों की (१) कारीगर तथा श्रमिक वर्ग के लिए औद्योगिक विधि की समुचित प्रारम्भिक शिक्षा-व्यवस्था का स्थानीय सरकार एवं अधिकारियों द्वारा प्रबन्ध । उसके अन्तर्गत ऐसे नियोजताओं को आर्थिक सहायता देने की भी व्यवस्था हो, जो अपने श्रमिकों के लाभ के लिए शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान करें । (२) उद्योग-विभाग के नियन्त्रण में कुटीर उद्योगों के लिए उद्योग और कला के शिक्षालयों की व्यवस्था, और (३) संगठित उद्योगों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था । इनका विभाजन हस्तसाध्य उद्योग जैसे अभियान्त्रिक और ग्रहस्तसाध्य उद्योग जैसे रासायनिक पदार्थों के निर्माण में हुआ । पहले प्रकार के उद्योगों में शिक्षा कारखानों में ही देने और सैद्धान्तिक शिक्षा की कक्षाएँ इनसे संयुक्त कर देने की व्यवस्था बनायी गई । कुछ दशकों, जैसे वस्त्र-व्यापार के सम्बन्ध में, प्राविधिक स्कूलों के साथ उद्योगशालाएँ खोली गईं । दूसरे प्रकार के उद्योगों के सम्बन्ध में प्राविधिक स्कूल की शिक्षा कारखानों में प्राप्त व्यावहारिक अनुभव से पूर्ण होती थी । वर्तमान प्रांतीय शिक्षालयों के अतिरिक्त आयोग ने दो राजकीय विद्यालयों (इम्पीरियल कॉलेजों) की स्थापना की सिफारिश की—एक उच्चतम अभियान्त्रिक शिक्षा के लिए और दूसरा धात्विक एवं खनिज सम्बन्धी प्राविधिक शिक्षा के लिए ।^१

प्राविधिक शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण के प्रसार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बम्बई सरकार ने फरवरी, १९२१ में औद्योगिक और प्राविधिक शिक्षा के लिए एक समिति नियुक्त की । समिति ने दो रिपोर्टें तैयार की—एक यूरोपियन बहुमत की थी और दूसरी भारतीय अल्पमत की थी (अध्यक्ष एम० विश्वेश्वरया अल्पमत के समर्थक थे) । दोनों दलों के मतभेद के मुख्य विषय थे संस्थाओं का रूप, प्रशिक्षण पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या एवं लागत का अनुमान और संगठन तथा योजना कार्यान्वित करने के लिए संगठन एवं एजेंसियाँ ।

बहुमत वर्ग की सूचनाओं के आधार पर भी रक्ष-मात्र कार्यवाही नहीं की गई यद्यपि उद्योग-विभाग द्वारा संचालित बुनाई के शिक्षण केन्द्र अब भी वरधा-उद्योग को मदद दे रहे हैं । इस भाँति सामान्य प्राविधिक एवं वाणिज्यिक शिक्षा की दशाएँ

१. भू-भशास्त्रियों और खानों के अभियन्ताओं के लिए १९२६ के अन्त में धनवाद में इण्डियन स्कूल ऑफ़ माइन्स खोला गया ।

असन्तोषजनक ही रही और देश की विशालता तथा बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार या व्यक्तिगत प्रयत्नो द्वारा की गई व्यवस्थाएँ किसी भी भाँति पर्याप्त नहीं कही जा सकती। जैसा हारटोग-समिति ने कहा था कि व्यावसायिक एवं प्राविधिक प्रशिक्षण के प्रयत्न शिक्षा-पद्धति से विलकुल असम्बद्ध थे और इसलिए अधिकतर निष्फल सिद्ध हुए।

१०. एब्वट-बुड रिपोर्ट—भारत सरकार के निमन्त्रण पर इंग्लैंड से दो शिक्षा-विशेषज्ञ श्री ए० एब्वट और श्री एस० एच० बुड नवम्बर, १९३६ में शिक्षा के पुनर्संगठन और खासकर व्यावसायिक शिक्षा की समस्याओं पर परामर्श देन भारत आये। उन्होंने जून, १९३७ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उनकी कुछ सिफारिशें निम्नलिखित हैं

(१) प्रारम्भिक पाठशालाओं में छोटे बच्चों की शिक्षा पुस्तकों के ऊपर आधारित न होकर स्वाभाविक रूचि और क्रियाओं पर आधारित होनी चाहिए।

(२) उच्च (हाई) या उच्चतर माध्यमिक (हायर सैकण्डरी) स्कूलों में भारतीय भाषाओं को यथासम्भव रूप से शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, किन्तु इन स्कूलों में अंग्रेजी सारे विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य रखी जाए।

(३) व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार उद्योगों के विकास की तुलना में बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। यदि व्यावसायिक शिक्षा अधिक विशिष्ट न हो और यदि उमका लक्ष्य विचारों में सहनशीलता और कुछ ऐसी व्यक्तिगत गुणों को उत्पन्न करना हो जो समान रूप से बौद्धिक और नैतिक दोनों ही हों, तो उद्योग और वाणिज्य में वर्तमान आवश्यकताओं की अपेक्षा और अधिक अनुपात में प्रशिक्षित मनुष्यों को काम मिल सकता है।

(४) प्रत्येक प्रान्त को अपने उद्योग और वाणिज्य की शिक्षा-सम्बन्धी आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना चाहिए और इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा क रूप तथा प्रतिवर्ष भरती किये गए व्यक्तियों की खपत का अनुमान लगा लेना चाहिए।

(५) व्यावसायिक शिक्षा व उपयुक्त और पर्याप्त होने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग और वाणिज्य शिक्षा-संस्थाओं को सहयोग प्रदान करें। इस भाँति का सुसंगठित सहयोग भारत में अभी कहीं भी विद्यमान नहीं है।

(६) संगठित उद्योगों के विकास की इस स्थिति में देखरेख करने वाले व्यक्तियों, जैसे मिस्त्री (फोरमैन) इत्यादि के शिक्षण और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उत्पादन की कुशलता की कुंजी इन्हीं के पास है।

११. युद्ध उद्योगों के लिए प्राविधिक व्यक्तियों की उपलब्धि—देश की युद्ध-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति और औद्योगिक विकास के लिए प्रशिक्षित एवं प्राविधिक व्यक्तियों की उपलब्धि के उद्देश्य से भारत सरकार ने १९४० में एक प्राविधिक

प्रशिक्षण-योजना (टेक्निकल ट्रेनिंग स्कीम) चालू की।^१

गृह-उद्योग और युद्ध की फैक्ट्रियों के लिए औजार बनाने वाले तथा यन्त्रों के हिस्से तैयार करने वाले कुशल कारीगरों की प्राप्ति के लिए एक नयी योजना तैयार की गई। इसके अन्तर्गत सावधानी से चुने हुए प्रशिक्षित व्यक्ति और कारीगर गृह-उद्योगों में लगी हुई फर्में में लगाये गए, ताकि वे उच्चतम प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और बाद में युद्ध की फैक्ट्रियों या गृह-उद्योगों में लगाये जा सकें।^१

युद्ध के लिए इंग्लैण्ड में प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी को दूर करने तथा युद्ध-उद्योगों के लिए आवश्यक मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए आरम्भ की गई राजकीय प्रशिक्षण-योजना (गवर्नमेंट ट्रेनिंग स्कीम) से यह योजना सम्बद्ध थी। इस योजना में निहित दूसरा मन्तव्य यह था कि भारतीय मजदूरों को ब्रिटिश मजदूरों के निकट सम्पर्क में लाया जाए और इंग्लैण्ड की भाँति भारत में भी सुदृढ तथा सुसंगठित श्रम-आन्दोलन के विकास में सहायता दी जाए। यह भी आशा की जाती थी कि भारतीय श्रमिक प्रशिक्षण के बाद एक विस्तृत सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा समाजिक दृष्टिकोण के साथ वापस आयेगा। इस प्रशिक्षण के लिए सदस्यों का चुनाव कारखानों के मजदूरों में से हुआ और वे राजकीय धन पर प्रशिक्षण के लिए इंग्लैण्ड भेजे गये। इंग्लैण्ड में तीन महीने राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र में बिताने के बाद उन्हें ब्रिटेन के भिन्न-भिन्न युद्ध उद्योगों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कराने के उद्देश्य से और अभियानिकों की विशिष्ट शिक्षा प्राप्त कराने के लिए विभिन्न उद्योगों के कारखानों में भेजा गया। उनको ऐसे कारखानों में रखा गया, जो भारत लौटने पर उनके लिए सबसे अधिक लाभप्रद सिद्ध होते। प्रशिक्षण की कुल अवधि आठ महीने थी। भारत लौटने पर सभी प्रशिक्षितों की परीक्षा ली गई। इसके बाद उन्हें यथायोग्य काम दिये गए।

१२. भण्डार कय-नीति—लगभग ५० वर्ष पहले सरकार ने राजकीय उपयोग के लिए विदेशों में उत्पन्न या निर्मित वस्तुओं की अपेक्षा भारत में उत्पन्न या निर्मित भण्डारों को खरीदने की नीति की घोषणा की थी। भण्डार खरीदने के विषय में नियम भी बनाये गए, जिनमें समय-समय पर संशोधन किये जाते थे। इन नियमों के अन्तर्गत कोटि या गुण का ध्यान रखते हुए पूर्ण या आंशिक रूप से भारत में तैयार हुए माल को प्राथमिकता देना निश्चय किया गया। ऐसी दशाओं में जब विदेशी वस्तुओं की तुलना में भारत में बनी वस्तुएँ उतनी ही अच्छी और उस ही मूल्य की हों, तो यह स्पष्ट ही है कि भारतीय वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

१ १९३७-३८ के बाद बम्बई सरकार ने एक योजना बनायी, जिसके अनुसार प्राविधिक शिक्षा देने के उद्देश्य से विद्यार्थियों को भरती करके सरकार मिलों, कारखानों, प्रेस, रसायन या अन्य उद्योगों में काम या अहमदाबाद भेजती थी। ये नये प्रशिक्षित नवयुवक युद्ध के विभिन्न विभागों में निरीक्षक और उप-निरीक्षक के पद पर रख लिए गए।

२. 'इण्डियन लेबर मजदूर', अगस्त १९४३, पृ० २६।

कुछ लोग इस विचार के भी हैं कि यदि यहाँ की तैयार वस्तुओं की लागत कुछ अधिक हो तो उन्हीं को खरीदना चाहिए। उद्योग-आयोग की जाँच के अनुसार व्यवहार में बोटि एव मूल्य में समान होने पर भी भारतीय भण्डारों की तुलना में ब्रिटिश भण्डारों को प्राथमिकता दी जाती थी। विभिन्न सरकारी विभागों की माँगों की पूर्ति करने के लिए लन्दन-स्थित भारतीय कार्यालय के भण्डार विभाग द्वारा माँगे गए टण्डर के मन्वन्त्र में प्रतिस्पर्धा करने में भी भारतीय निर्माताओं को अनेक कठिनाइयों तथा बाधाओं का सामना करना पड़ता था। भण्डार-नय के नियम से लाभ उठाने तथा इस भाँति देश की निर्माण-शक्ति का पूर्ण विकास करने के प्रयत्न में असफल रहने के लिए सरकार ने यह सफाई दी कि खरीद करने वाले भारतीय अधिकारी को राय और सूचना देने के लिए कोई योग्य निरीक्षण-आत्मक एजेंसी नहीं है। इस कारण सारे उत्तरदायित्व और मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए वह सारे ग्रॉन्ड लन्दन-स्थित भारत-कार्यालय के भण्डार-विभाग को भेज देती थी। इस सफाई के विरुद्ध यह प्रश्न उठा कि विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने के लिए आवश्यक एजेंसी की नियुक्ति का प्रयत्न क्यों नहीं किया गया? भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए अर्थ-नीति को उपयुक्त रीति से नियोजित करने की नीति का भारतीय उद्योग मण्डल ने भी समर्थन किया था। यदि भारतीय उत्पादकों को नरक्षणात्मक अधिमान दिये बिना ही 'उचित अवसर और निष्पक्ष व्यवहार' की नीति अपनायी जाए तो सरकार के लिए अधिक मात्रा में कर-प्राप्ति स्वयमेव एक स्वस्थ और बहुमूल्य प्रोत्साहन का काम करेगी।

औद्योगिक विकास की प्रगति के साथ-साथ सरकारी माँग की अधिकाधिक पूर्ति स्थानीय उद्योगों द्वारा सम्भव होनी जा रही है—विशेषकर इसलिए कि निरीक्षण-आत्मक एजेंसियों तथा भारतीय भण्डारों की प्राप्ति के स्थान और मूल्य के विषय में सूचना के अभाव के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। औद्योगिक आयोग की सिफारिशों के अनुसार नियुक्त भण्डार-नय समिति १९२१ ने आयोग के इस मुद्दे का समर्थन किया कि राजकीय भण्डार के निरीक्षण के लिए एक केन्द्रीय विशेषज्ञ एजेंसी की स्थापना होनी चाहिए। फलस्वरूप भारतीय भण्डार-विभाग का संगठन हुआ, किन्तु प्रान्तीय सरकारों, नगरपालिकाओं, वन्दरगाह-अधिकारियों, कम्पनी द्वारा प्रवर्धित रेलवे, अन्य सार्वजनिक तथा अर्द्ध-सार्वजनिक संस्थाओं तथा भारतीय रिजासतों के लिए भी इसकी सेवाएँ प्राप्त हो सकती हैं। यह विभाग क्रय और निरीक्षक एजेंसी के रूप में परामर्शदाता की हैसियत से काम करता है। यह ग्रॉन्डों की जाँच इस दृष्टिकोण से करता है कि कोई भी ग्रॉन्डर व्यर्थ ही वाहर न भेजा जाए जबकि उस भाँति की वस्तुओं की उचित मूल्य पर पूर्ति भारतीय उत्पात्ति की वस्तुओं से सम्भव है। यह कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं का भारत में क्रय करता है और निरीक्षण करता है, भण्डार के क्रय और मूल्य से सम्बन्धित सारे मामलों पर सूचनाएँ एकत्र करने के केन्द्रीय कार्यालय के रूप में काम करता है और भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अन्य अनेक काम

करता है। कलकत्ता और बम्बई में स्थानीय क्रय-शाखाएँ स्थापित की गई हैं और मद्रास, कानपुर और दिल्ली में निरीक्षण एजेन्सियाँ स्थापित की गई हैं। विदेशी फर्मों से प्रतियोगिता करने वाली भारतीय फर्मों को सुविधा और प्रोत्साहन देने के लिए विभाग ने भारत में दिये जाने वाले टेण्डरों को रुपये में माँगने की नीति का अधिकाधिक अनुसरण प्रारम्भ किया।

१३. औद्योगिक अनुसन्धान—१९३५ में अलीपुर में औद्योगिक अनुसन्धान कार्यालय (इण्डस्ट्रियल रिसर्च ब्यूरो) की स्थापना एक अनुसन्धान-शाखा के साथ हुई। एक सलग्न परामर्श-दात्री सस्था—औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् (इण्डस्ट्रियल रिसर्च-कौंसिल) की सहायता से कार्य करने वाला यह कार्यालय भारतीय भण्डार-विभाग से मलम्न है। औद्योगिक सूचनाओं को एकत्र तथा प्रसारित करना, औद्योगिक अनुसन्धान में उद्योगों से सहयोग करना, औद्योगिक प्रमाण के विषय में परामर्श देने वाली उपयुक्त पत्रिकाओं का सम्पादन और औद्योगिक प्रदर्शन के सगठन में सहयोग देना इससे कार्य है। ऐसी केन्द्रीय सस्था की आवश्यकता और औद्योगिक अनुसन्धान के मूल्य के सम्बन्ध में अतिशयोक्ति नहीं की जा सकती। हाल ही में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् (साइण्टिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च कौंसिल) नामक एक नवीन सस्था स्थापित की गई है। विभिन्न प्रमुख उद्योगों के प्रतिनिधि इस परिषद् से सम्बद्ध हैं।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में तकनीकी तथा अनुसन्धान पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया, जिससे प्राविधिक व्यक्तियों की संख्या बढ़े, अनुसन्धान बढ़े तथा खोजन कम हो और औद्योगिक प्रगति हो। तीसरी योजना में शिक्षा के ५६० करोड़ रुपये में से १४२ करोड़ रुपये तकनीकी शिक्षा, इंजीनियरिंग की उन्नति के लिए रखे गए। इस प्रकार इस योजना में २५ प्रतिशत शिक्षा विभाग का खर्चा तकनीकी शिक्षा के लिए निर्धारित हुआ जबकि पहली और द्वितीय योजनाओं में १३ तथा १६ प्रतिशत था। चौथी पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिए १४७५ करोड़ रुपया रखा गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इंजीनियरिंग तथा तकनीकी सस्थाओं में प्रवेश की संख्या १३,८२० और २५,८०० (१९६०-६१) से बढ़कर १९,१३७ तथा ३७,३९१ (१९६५-६६) के अन्त तक हो गई है। यह आशा की जाती है कि १९७०-७१ में ३८,६०० तथा ८८,६०० हो जाएगी।

इस प्रकार वैज्ञानिक अनुसन्धान ने भी स्वतन्त्रता के पश्चात् बहुत उन्नति की है। पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं में इन कार्यों पर ८० करोड़ रुपया खर्च हुआ। तीसरी पंचवर्षीय योजना में १३० करोड़ रुपया निर्धारित हुआ तथा ७५ करोड़ रुपया दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्य पर, जो अभी चल रहा है, खर्चना था। इस प्रकार सरकार के यत्नों के कारण देश में ६२ विश्वविद्यालयों के अनुसन्धानों के अतिरिक्त २८ नेशनल लैबोरेटरीज, ८८ अनुसन्धान विभाग तथा केन्द्र और ५४ एसोसिएशन सस्थाएँ तकनीकी कार्य कर रही हैं। पहली अप्रैल १९५७ से औद्योगिक उन्नति के लिए डंसीमल सिक्को को चलाया गया और पहली अक्टूबर १९५८ में मीट्रिक नाप-तोल यन्त्र बनाए गये जो १९६६ में सारे राष्ट्र में लागू हो जाएँगे।

१४. प्रान्तीय उद्योग विभागों का कार्य—औद्योगिक आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रान्तीय उद्योग-विभागों की स्थापना की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। इन विभागों के मुख्य कार्य तीन प्रकार के हैं—(१) औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा का विकास, (२) औद्योगिक शिक्षा की पूर्ति, और (३) औद्योगिक प्रदर्शनियों, हस्तकला-मण्डलों एवं अर्थ (धन) द्वारा उद्योगों की सहायता। उनकी क्रियाएँ बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा कुटीर तथा ग्रामोद्योगों से अधिक सम्बद्ध हैं।^१ औद्योगिक आयोग के काल से आज की औद्योगिक दशा में महान् परिवर्तन तथा घनाभाव के कारण उद्योग-विभागों में औद्योगिक आयोग द्वारा अनुमानित मात्रा एवं दिशा में सफलता नहीं प्राप्त की। १९१९ और १९३५ के वैधानिक परिवर्तनों के कारण औद्योगिक विकास का उत्तरदायित्व बहुत अंश में प्रान्तों पर आ पड़ा। इससे भी एक व्यवस्थित और सम्यक् औद्योगिक नीति अपनायमान में बाधा पहुँची। अखिल भारतीय औद्योगिक सम्मेलन के वायिक अधिवेशनों द्वारा, जिनमें प्रान्तों के मन्त्रीमण्डल तथा उद्योग सचालक एवं कुछ भारतीय रियासतों के भी प्रतिनिधि उपस्थित रहते थे, कुछ अंश में उपयोगी संयोजन हो सका। बंगाल के उद्योग विभाग में अपेक्षाकृत अधिक सफलता प्राप्त की है। अपने पर्याप्त कर्मचारी-बल तथा कलकत्ता में अनुसन्धान प्रयोगशाला खुलाने के उपरान्त औद्योगिक आयोग की निर्धारित नीति का पालन करने के लिए बंगाल का उद्योग विभाग भली भाँति सुसज्जित समझा जा सकता है। उदाहरणार्थ मद्रास में स्थायी बनाने के कारखानों की चर्चा की जा सकती है। अन्य उद्योग असफल हो गए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में गिरों (बाबिन) बनाने का उद्योग।

१९३५ के राजकीय सहायता नियम के अधोर्धत्त हान के कारण छोट उद्योगों के लिए कम्बई विधानमण्डल में एक प्रस्ताव द्वारा कुछ नये नियम बनाये हैं। ये नियम कई प्रकार की राजकीय सहायता की व्यवस्था करते हैं, जिनमें ऋणपत्र या हिस्सों पर व्याज की गारण्टी, हिस्सा या ऋणपत्रों का लाना, ऋण प्रदान करना और अनुसन्धान-कार्य के लिए सहायता देना आदि सम्मिलित हैं। कुछ दिशाओं में उपर्युक्त नियमों के अनुसार नये उद्योग आरम्भ करने के लिए व्यक्तिगत साहाय्य-नियमों को ऋण भी दिया जा सकता है। वास्तव में ये नियम बृहद प्रमाण उद्योगों की अपेक्षा लघु-प्रमाण उद्योगों के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हुए हैं।^१ बड़ी-बड़ी मिलों, जैसे कार्नाटक पेपर मिल्स (मद्रास) और इण्डियन स्टील वायर प्राइवेट लिमिटेड (बिहार), को दिये गए बड़े-बड़े ऋणों की असफलता से यह सिद्ध है कि बड़े उद्योगों को अधिक सहायता की समस्या हल करने के लिए विशेष उपायों की आवश्यकता है।

उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय सर एस० एन० पोचखनवाला की अध्यक्षता में १९३४ में औद्योगिक वित्त समिति की स्थापना हुई। इसने प्रधान एवं अप्रधान

१. इन क्रियाओं का पुनरावलोकन अगले अध्याय में किया गया है।

२. देखिए, 'प्रोमीडिस्ट्स आब दि रिफ़र इण्डस्ट्रीयल कान्सेस' (१९०३) तथा सी० आर० गाडगिल, इरडिस्ट्रियल इन्वन्चुरान आब इन्डिया, चतुर्थ संस्करण, पृ० २२५।

उद्योगों को अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण देने के लिए २५ लाख की पूंजी तथा अधिक-से-अधिक २० वर्ष के लिए हिस्से पर ४% करमुक्त लाभांश पर सरकारी गारण्टी सहित 'दि यूनाइटेड प्राविसेज इण्डस्ट्रियल क्रेडिट बैंक लिमिटेड, की स्थापना के लिए सिफारिश की। इस समिति ने 'दि यूनाइटेड प्राविसेज फाइनेसिंग एण्ड मार्केटिंग कम्पनी लिमिटेड' नामक एक विपणन (मार्केटिंग) समूह प्रारम्भ करने की सिफारिश की, जिसकी पूंजी ५ लाख रुपये होती तथा जो सम्मिलित पूंजी वाली कम्पनियों की भाँति चलाई जाती। समिति के मतानुसार इस पूंजी के हिस्से के वितरण का उत्तरदायित्व औद्योगिक बैंक के ऊपर होगा।^१ जून, १९३६ में समिति की सिफारिशों के अनुसार निर्मित सरकारी योजना की उत्तर प्रदेश विधानमण्डल ने स्वीकार कर लिया।^२ दिसम्बर, १९३६ में बंगाल विधानमण्डल ने भी एक औद्योगिक साख-निगम सस्था की स्थापना स्वीकार की। इसका उद्देश्य कारागृह से मुक्त बन्धियों द्वारा लघु-प्रमाण उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण देना था। बंगाल के किसी ऐसे नागरिक को भी ऋण दिया जा सकता था जो व्यावहारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता।^३

१५. आयोजन और औद्योगीकरण—१९४४ में आठ प्रमुख भारतीय व्यापारियों ने भारत के औद्योगिक विकास की योजना का निरूपण करते हुए एक सक्षिप्त स्मृति-पत्र का पहला भाग प्रकाशित किया। सामान्यतः यह बम्बई योजना (बॉम्बे प्लान) के नाम के प्रसिद्ध है।^४

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य पन्द्रह वर्ष की अवधि के भीतर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय को दूना कर देना था। जनसंख्या की वृद्धि ५० लाख प्रति वर्ष अनुमान करने पर पन्द्रह वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दूना करने का अर्थ है वर्तमान सम्पूर्ण आय को तिगुना कर देना। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह प्रस्तावित किया गया कि कृषि की वास्तविक उत्पत्ति को दुगुने से कुछ अधिक और बड़े तथा छोटे उद्योगों के सम्मिलित उत्पादन को पाँच गुना कर दिया जाए।

उद्योगों को दो प्रधान वर्गों में विभाजित किया गया—(१) आधारीद्योग, (२) उपभोग-पदार्थों के उद्योग।

महत्वपूर्ण आधारीद्योगों में निम्नलिखित को योजना के आरम्भिक वर्षों में प्रधानता दी जाएगी : शक्ति—विद्युत्, खाने और घातुएँ—लोहा और इस्पात, अल्यूमिनियम, मैंगनीज, अभियांत्रिकी—सभी भाँति के यन्त्र, यान्त्रिक औजार;

१. 'स्टेट प्लान इन रीस्पेक्ट ऑफ इण्डस्ट्रीज', १९२८-३५, पृ० ४२।

२. इस योजना का विशेष विवरण 'बैंकिंग और साख' वाले अध्याय में 'औद्योगिक वित्त' शीर्षक के नीचे दिया गया है।

३. विशेष विवरण के लिए देखिए, एन० दास, 'इण्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज इन इण्डिया'।

४. इस योजना के नाम का कारण यह है कि एक-दो व्यक्तियों को छोड़कर इसके सभी लेखक बम्बई के हैं : सर पुरपोत्तमदास ठाकुरदास, जे० आर० डी० टाटा, जी० डी० निरला, सर आरदेशर दलाल, सर श्रीराम, कर्तारभाई लालभाई, ए० डी० अॉक और जॉन मथई।

रसायन—भारी रसायन, रासायनिक खादे, रंग, प्लास्टिक, दवाएँ, यातायात—रेल के इंजन और डिब्बे, जहाजों का निर्माण, मोटर-गाड़ियाँ, हवाई जहाज, सीमेंट ।

उत्प्रेोग-पदार्थों के प्रमुख उद्योग, जिनका और विकास करना है, निम्नलिखित हैं वस्त्र—सूती, ऊनी और रेशमी, सीने का उद्योग, चमड़े की वस्तुओं का उद्योग, कागज का उद्योग, तम्बाकू का उद्योग, तेल उद्योग ।

बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ ही छोट तथा कुटीर-उद्योगों के विकास का भी प्रवन्ध किया गया था, ताकि योजना की आरम्भिक अवस्था में पूँजी, विशेषकर बाहरी पूँजी की आवश्यकता कम हो सके और लोगों को काम मिल सके ।

बम्बई योजना का दूसरा भाग जनवरी, १९४५ में प्रकाशित हुआ । प्रधान योजना (मास्टर प्लान) के अधीन उद्योगों के विकीरण तथा प्रादेशिक वितरण के सम्बन्ध में भी सुझाव रखे गए । कुटीर एवं लघु-प्रमाण उद्योगों के प्रोत्साहन की आवश्यकता स्वीकार की गई और राजकीय तथा व्यक्तिगत साहस के उचित सहयोग पर जोर दिया गया । बम्बई योजना के निर्माताओं के तीन प्रमुख उद्देश्य थे (क) पूर्व-स्थित आर्थिक व्यवस्था के सुव्यवस्थित विकास की आवश्यकता, (ख) केन्द्रीय नियन्त्रण की अपेक्षित व्यवस्था, और अन्तिम (ग) समाज के सामाजिक और वितरणात्मक आदर्शों के अनुकूल कृषि और उद्योग तथा उत्पादन के साधनों और वास्तविक उत्पादन का अधिकाधिक विकीरण ।^१

१९२८ ई० की राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना के बाद सरकारी और गैर-सरकारी योजनाओं की भरमार-सी हो गई । १९३६ में युद्ध की घोषणा के पश्चात् शीघ्र ही कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के अलग भिन्न हो जाने के बाद राष्ट्रीय आयोजन समिति का कार्य बिलकुल बन्द हो गया । पाँच वर्षों के विराम के पश्चात् सितम्बर, १९४५ में समिति की पुनः बैठक हुई ।

मार्च, १९५० में भारत सरकार ने योजना-आयोग की नियुक्ति की । जुलाई, १९५१ में योजना-आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रस्तावित रूपरेखा सामने रखी । दिसम्बर १९५२ में योजना पार्लियामेण्ट के सामने अपने अन्तिम रूप में रखी गई । योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की ऐसी प्रक्रिया प्रारम्भ करना था जो रहन-सहन के स्तर को ऊपर उठाए तथा जनता को अधिक सम्पन्न और अनेक रूप में जीवन के नये अवसर प्रदान करे । इस योजना के अन्तर्गत १९५१-५६ में २,०६६ करोड़ रुपये व्यय करना निश्चित किया गया । बाद में यह राशि बढ़ाकर २,३५६ करोड़ ६० कर दी गई ।

यह योजना १९७७ तक प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय को दूना करने के उद्देश्य की प्राप्ति के प्रति पहला कदम है । बाद के अनुमानों के आधार पर यह पता लगा कि राष्ट्रीय आय १९६७-६८ तक दूनी हो सकती है तथा प्रति व्यक्ति आय १९७३-७४ में दूनी हो सकती है । प्रथम योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय आय में १८ ४ प्रतिशत

१. दी उन्नत इकनामिस्ट, २६ जनवरी १९४५, पृ० ६५-६६ ।

तथा प्रति व्यक्ति आय में १०८ प्रतिशत वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति उपभोग में ८ प्रतिशत की वृद्धि हुई। विनियोग का प्रतिशत १९५०-५१ के ५% से बढ़कर ७% हो गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना १५ मई, १९५६ के पार्लियामेंट के सम्मुख रखी गई। इस योजना के चार प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य भारी तथा आधारात्मकों के विकास पर जोर देते हुए तीव्र औद्योगीकरण करना था। इस योजना के अन्तर्गत ४,८०० करोड़ रु० का व्यय निश्चित किया गया। बाद में विदेशी विनिमय की कठिनाइयों के कारण योजना को दो भागों में बाँट दिया गया। योजना के प्रथम भाग—पार्ट ए—के ऊपर ४,५०० करोड़ रुपये का व्यय निर्धारित किया गया। इसके अन्तर्गत कृषि-उत्पादन की वृद्धि में प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित योजनाएँ, ऐसी योजनाएँ जिन पर काफी व्यय हो चुका है तथा आधारभूत योजनाएँ (Core projects) थी। इन आधारभूत योजनाओं में इस्पात के कारखाने, कोयला और लिमनाइट-सम्बन्धी योजनाएँ, रेलों तथा प्रमुख बन्दरगाहों से सम्बन्धित योजनाएँ, शक्ति-योजनाएँ आदि हैं।

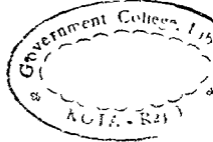
तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में विचार-विनिमय प्रारम्भ हो गया है। योजना के आरूप में ७,५०० करोड़ रु० सरकारी क्षेत्र में तथा ४,१०० करोड़ रुपये निजी क्षेत्र में व्यय करने की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में कुल २१,५००—२२५०० करोड़ रुपये व्यय करना निश्चित हुआ है, जिसमें से १४,५००—१५,५०० सरकारी क्षेत्र में खर्च होगा और शेष निजी क्षेत्र में होगा।

राष्ट्रीय आय १९५१-६१ में ४४% और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय १८.५ प्रतिशत बढ़ी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन सालों में ६.५ प्रतिशत तथा ०.५ प्रतिशत बढ़ी। १९६३-६४ में ४.५ प्रतिशत, जो कि वार्षिक आय के निर्धारित लक्ष्य ५ प्रतिशत से कम रही।

तृतीय योजना के पुनः निरीक्षण करने पर यह पता चला है कि राष्ट्रीय आय १९६५-६६ में १६,००० करोड़ के स्थान पर १७,४०० करोड़ रुपये (१९६०-६१ के मूल्य अनुसार) रह गई।

चौथी पंचवर्षीय योजना में इसे २५,००० करोड़ तक बढ़ाने की आशा है।



अध्याय २

भारतीय उद्योग : नवीन तथा पुरातन

१. अध्याय का क्षेत्र—भारतीय उद्योग दो वर्गों में विभाजित किये जा सकते हैं . (१) कारीगरों के घरों में हस्तचालित यन्त्रों से सम्पादित उद्योग, जिन्हें कुटीर-उद्योग कहा जा सकता है । यहाँ काम का प्रमाण छोटा, सगठन सीमित तथा उत्पादन मुख्यतया स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है । इस अध्याय के अन्त में हम इन कुटीर-उद्योगों का विवेचन करेंगे । (२) शक्ति-चालित यन्त्रों से सम्पादित सुगठित उद्योग जो कारखानों या उद्योगशालाओं में चलाए जाते हैं । इन सगठित उद्योगों का आकार साधारण ग्रामीण कारखानों से लेकर कपड़े की बड़ी-बड़ी मिलों एवं अभियांत्रिकी उद्योगशालाओं के समान होता है जहाँ हजारों मजदूर कार्य करते हैं और निर्माण एवं व्यापार के लिए पूर्ण सगठन होता है ।^१ कृषि से सम्बन्धित सगठित उद्योग, जैसे चाय, कढ़वा, नील और चीनी उद्योग का वर्णन कृषि के अध्याय में हो चुका है ।

२. सूती मिल-उद्योग—भारत के वृहद्-प्रमाण के कुछ उद्योगों का विवरण नीचे दिया जा रहा है । भारत में पहली सूती-बस्त्र मिल १८१८ में कलकत्ता में स्थापित हुई । बम्बई में, जो सूती-मिल उद्योग का गढ़ है, पहली मिल पागसी साहम के फलस्वरूप स्थापित हुई और इसने १८५४ में कार्य आरम्भ किया ।

वितरण के दृष्टिकोण से १८७७ का वर्ष उद्योग के विकास को एक नवीन दिशा प्रदान करता है । कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के ठीक मध्य में स्थित नगरों, जैसे नागपुर, घहमदाबाद और शोलापुर, में इस वर्ष बड़ी तेजी से मिलों की स्थापना

१. भारतीय उद्योगों के हाल के वर्गीकरण में सगठित उद्योगों को पुनः दो वर्गों में विभाजित किया गया है . लघु-प्रमाण उद्योग तथा वृहद्-प्रमाण उद्योग । उदाहरण के लिए बम्बई की औद्योगिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण समिति का कहना है कि “लघु-प्रमाण उद्योगों से हमारा तात्पर्य उन उद्योगों से है जहाँ शक्ति का प्रयोग होता है, परन्तु काम करने वालों की संख्या ५० से अधिक नहीं होती और न विनियोजित पंजी ही ३०,००० रुपये से अधिक होती है । मोटर की सम्मत, तेल, हाजरी, घड़ी-निर्माण, साधुन-निर्माण, चावल और आटे की चक्कियाँ इत्यादि उदाहरण हैं । वृहद्-प्रमाण उद्योग वे हैं जहाँ शक्ति का प्रयोग होता है परन्तु काम करने वालों की संख्या ५० से अधिक होती है तथा विनियोजित पंजी भी ३०,००० रुपये से अधिक होती है । इनका उदाहरण कपड़ा, कागज और शक्कर की मिलें हैं (रिपोर्ट-पैरा १५-१६) । आयोजन-समिति ने भी भारतीय उद्योगों को तीन वर्गों में विभाजित किया है : (१) कुटीर-उद्योग, (२) लघु-प्रमाण (अर्थात् आकार वाले) उद्योग, और (३) वृहद्-प्रमाण उद्योग ।”

२. देखिए, खण्ड १, अध्याय-६ ।

हुई। यह वितरण प्राकृतिक कारणों से हुआ, जैसे कच्चा माल, पर्याप्त थ्रम तथा बड़े-बड़े विपणन केन्द्रों की सन्निकटता। रेलों के विकास के कारण ही यह सम्भव हो सका। वर्तमान शताब्दी के आरम्भ में चीन से सूती व्यापार की कमी ने बम्बई के अद्वितीय महत्त्व को बहुत आघात पहुँचाया। स्वदेशी आन्दोलन ने भी बुनाई व्यवसाय को बम्बई के बाहर प्रोत्साहन दिया। ब्रिटिश भारत में कारखाना सम्बन्धी कानूनों (फैक्ट्री लेजिस्लेशन) के विकास ने उद्योग के देशों रियासतों में स्थापित होने की प्रवृत्ति को जन्म दिया, क्योंकि वहाँ कारखाना कानूनों का प्रशासन बहुत ढीला था।

१९१४-१८ के युद्ध-काल में सूती वस्त्र-उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिला। युद्ध के पूर्वी रणमंचों में सूती सामान की सैनिक आवश्यकताओं के कारण सरकार द्वारा मिलों को दिया गया प्रोत्साहन, जहाजों की कमी के कारण आयात की कमी तथा आयात किये हुए कपड़े के मूल्यों की बढ़ती से उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई, यद्यपि यन्त्रों के आयात की कठिनाई के कारण विकास उतनी अच्छी तरह नहीं हो सका जितना कि इस कठिनाई के न होने पर होता।

[३. सन् १९४७ के बाद सूती-मिल उद्योग—सन् १९४७ में अविभाजित भारत में ४२१ मिलें थीं। विभाजन के बाद भारत में ४०८ मिलें ही रह गईं। १९४६-५० में मिलों की संख्या बढ़कर ४२५ हो गई।

१९५१ और १९५६ के आँकड़े देखने से प्रतीत होता है कि मिल, तकली और करघा सभी की संख्या तथा सूत और कपड़े के उत्पादन में वृद्धि हुई है। सूती वस्त्र के प्रति व्यक्ति उपभोग के आँकड़े भी यही प्रदर्शित करते हैं। १९५०-५१ में सूती वस्त्र का प्रति व्यक्ति उपभोग ६ गज था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सूती वस्त्र के प्रति व्यक्ति उपभोग का लक्ष्य १५ गज था। यह लक्ष्य १९५४ ही में प्राप्त कर लिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उपभोग की मात्रा बढ़कर १८ ५ गज प्रति व्यक्ति हो जाएगी ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

नवम्बर १९५२ में कानूनगो समिति (Textile Enquiry Committee) मिलों, शक्तिचालित तथा हस्तचालित करघों के विभिन्न पहलुओं पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त की गई। १९५४ में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने अच्छे प्रकार के हस्तचालित तथा शक्तिचालित करघों द्वारा सूती वस्त्रों की मांग को सम्भालित वृद्धि को पूरा करने की सिफारिश की। अतएव समिति ने बुनने वाली मिलों के प्रसार का समर्थन नहीं किया। सादे करघों के स्थान पर स्वचालित करघों की स्थापना का भी सुझाव दिया है ताकि २० वर्ष में सादे करघों के बजाय केवल स्वचालित करघे ही प्रयोग में रहें। १२ लाख हाथ के करघों को शक्तिचालित करघों में बदलने के लिए समिति का सुझाव था कि प्रथम छ वर्ष में ३,००,००० हाथ के करघों को २,१३,००० अच्छे प्रकार के हस्तचालित तथा शक्तिचालित करघों में बदल दिया जाए तथा शेष करघों को दो या तीन पंचवर्षीय कालों में बदल दिया जाए। इस प्रकार २० वर्ष की अवधि में हाथ के करघों का सम्पूर्ण उद्योग अच्छे प्रकार के हाथ के करघों तथा शक्तिचालित करघा-उद्योग में बदल जाएगा। समिति के मतानुसार १९६० तक उत्पादन

को हाथ के करघे या घरेलू दक्कनचालित करघों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। इस सम्बन्ध में १९५५ में प्रस्तुत की गई कार्बे कमेटी की रिपोर्ट में भी हाथ के करघों के लिए उत्पादन सुरक्षित रखन की बात कही है।

१९५१ में प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में सूती वस्त्र उद्योग के इतिहास में एक नय युग का सूत्रपात किया। योजना में ग्रामीण और लघु प्रमाण उद्योगों की गहायना की घोषणा राजकीय नीति के रूप में की गई। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित नीति अपनायी गई—

- १ उत्पादन के क्षेत्रों का सुरक्षित करना।
- २ बड़े पैमाने के उद्योग के विस्तार की क्षमता पर रोक लगाना।
- ३ बड़े पैमाने के उद्योग पर उप-कर लगाना।
- ४ कच्चे माल की पूर्ति की व्यवस्था करना, तथा
- ५ अनुसन्धान, प्रशिक्षण इत्यादि का समन्वय करना।

इस नीति के अनुसार प्रथम पंचवर्षीय योजना में सूती मूल उद्योग की १९५६ के अन्त तक कपड़े की उत्पत्ति ४,७०,००,००० गज तथा सूत की उत्पत्ति १६,४०० लाख पौंड तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उद्योग ने यह लक्ष्य सन् १९५५ में ही पूरे कर दिए। पंचवर्षीय योजनाओं में सूती उद्योग ने काफी उन्नति कर ली है। सूत का उत्पादन १९६२-६३ में १८८५ मिलियन पौंड और कपड़ा ४९२१ मिलियन गज व्यवस्थित विभाग में था, १९६५-६६ में ५२५० मिलियन गज कपड़े का उत्पादन था। १९७०-७१ के अन्त तक ६,००० मिलियन गज तक उत्पादन होने की आशा की जाती है।

सन् १९५६ में ही सूती मिल-उद्योग के सामने एक संकट आ गया। मिलों के पास बिना विक्रय हुए कपड़ों के स्टॉक इकट्ठा होना लग। इस संकट के प्रमुख कारण तीन थे—

१ उद्योग के ऊपर अधिक उत्पादन-कर लगा हुआ था।

सम्भवतः सरकार दूमरी योजना के अर्थ-प्रबन्धन के लिए इस प्रकार अधिक धन इकट्ठा करना चाहती थी।

२ दशक के अन्दर कपड़े के उद्योग को हतोत्साहित भी किया गया। उदाहरण के लिए केन्द्रीय सरकार ने जनता द्वारा बड़े हुए उत्पादन-करों को न देने के लिए सूत्र प्रचार किया।

३ साद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक पदार्थों के मूल्य बढ़ जाने के कारण जनता की घटी हुई नय-शक्ति के फलस्वरूप भी सूती कपड़े का क्रय कम हो गया।

उपर्युक्त संकटों के कारण अनेक मिलें बन्द हो गईं। Textile Enquiry Committee, जिसने अपनी रिपोर्ट जुलाई १९५८ में प्रस्तुत की, के अनुसार २८ मिलें बन्द हो गईं जिसका अर्थ यह हुआ कि ५,००,००० तर्जुए और ६,००० करघे बन्द रहे।

वाणिज्य और उद्योग के कन्द्रीय मन्त्री ने ३० नवम्बर १९५६ को लोकसभा

मे यह कहा था कि १ अक्टूबर १९५८ को भी ४० मिले विलकुल बन्द थी तथा २७ मिले अशत बन्द थी। मिल बन्दी तथा पारियों (shift) को सख्या कम होने से हजागे मजदूर बेकार बैठ गए तथा उत्पादन की मात्रा में भी बहुत कमी हो गई।

परिस्थिति के अधिक विगडने के उपरान्त सरकार ने दिसम्बर १९५७ में मध्यम श्रेणी के कपडों पर लगे उत्पाद-कर को कम करने की घोषणा की। मार्च और जुलाई १९५८ में ममी प्रकार के कपडे के सम्बन्ध में दो रियायतें और दी गईं। अनुमान है कि इससे उद्योग को प्रतिवर्ष २० करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी।

अब हम सूती मिल-उद्योग की कुछ कठिनाइयों पर विचार करेंगे।]

मिलों की ओर से देश के बाजारों की उपेक्षा तथा उपभोग-केन्द्रों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करने की असफलता व असावा बम्बई की असमर्थता के और भी कई गम्भीर कारण थे, उदाहरणार्थ अपेक्षाकृत श्रम, ईंधन, जल-शक्ति की महँगाई तथा उच्च स्थानीय कर (१९३९ से लगे हुए १० प्रतिशत के सम्पत्ति-कर को मिलाकर जो मद्य-निषेध की लागत को वसूलने के लिए लगाया गया था), मुफसिल बाजारों तथा कच्चे पदार्थों के स्रोतों से दूरी आदि। उद्योग के इस सकट ने सरकार के प्रश्न को सामने ला दिया।

४ वस्त्र उद्योग की संरक्षण—यह स्पष्ट हो जान पर कि उद्योग विशेषकर बम्बई में सन्तोपजनक स्थिति में नहीं था, पहला सर्वेक्षण १९२५ में किया गया। प्रशुल्क-मण्डल ने १९२७ में रिपोर्ट प्रस्तुत की।

संरक्षण के सम्बन्ध में मण्डल की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं—आयात-कर ११ प्रतिशत के बजाय १५ प्रतिशत कर दिया जाए, उच्चकोटि (महीन) के सूत की कताई को अधिक सहायता दी जाए और वस्त्र-उद्योग के लिए आवश्यक यन्त्रों तथा मिलों के सामान को आयात-कर से मुक्त कर दिया जाए। भारत सरकार ने केवल अन्तिम सिफारिश स्वीकार की। इस निर्णय का मिल-मालिकों ने बहुत विरोध किया और फलस्वरूप कपास के सूत पर मूलानुसार ५ प्रतिशत या डेढ़ आना प्रति पौंड (जो भी अधिक हो) के संरक्षण-कर लगा दिये गए। ये कर ३१ मार्च, १९३० तक के लिए भारतीय प्रशुल्क अधिनियम (इण्डियन टैरिफ एक्ट, १९२७) के अनुसार लगाय गए। यन्त्रों और मिलों के सामानों पर लगे कर भी हटा दिये गए।

मण्डल की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने एक वाणिज्य शिष्टमण्डल (कमिश्नल मिशन) की भी नियुक्ति की। किन्तु ये सभी उपाय न तो मिल-उद्योग को ही सन्तुष्ट कर सक और न जनमत को ही। उद्योग में अवसाद बना रहा और सामान्य धारणा यह थी कि और अधिक सहायता अपेक्षित थी। अतएव कलकत्ता के कनक्टर आर कस्टम्स थी जी० एस० हार्डी को जुलाई १९२९ में बाह्य प्रतिस्पर्धा की उग्रता और विस्तार की जाच के लिए नियुक्त किया। श्री हार्डी की रिपोर्ट के आधार पर अप्रैल १९३० में सूती-वस्त्र-उद्योग संरक्षण-अधिनियम पास हुआ और

सरक्षणात्मक करो की मात्रा बढ़ा दी गई ।

५. सूती-मिल उद्योग की कुछ कठिनाइयाँ—इधर हाल में सूती वस्त्र के निर्यात-व्यापार की कठिनाइयाँ और बढ़ गई हैं । इसका एक कारण तो यह है कि विन्व बाजार में पहुँचने वाले कपड़े की मात्रा घटती रही है । द्वितीय विश्व युद्ध से पहले प्रतिवर्ष ६०,००० लाख गज कपड़ा विश्व-बाजार में खरीदा और बचा जाता था । अब यह मात्रा घटकर ५०,००० लाख गज प्रतिवर्ष हो गई है । इसका दूसरा कारण यह भी है कि देश में मानवीकृत रेशा का उपभोग तेजी से बढ़ रहा है । तीसरे अब अनेक देशों ने सूती कपड़े का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है । अतएव विश्व-बाजार में प्रतिस्पर्धा और कठिन हो गई है । भारत को पाकिस्तान की नई मशीनों से सुसज्जित मिलों के बने कपड़े की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है । इधर चीन न इस उद्योग में इतनी आश्चर्यजनक उन्नति की है कि वह विश्व के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अपना स्थान बनाने का हाँसला रखता है । दक्षिण-पूर्वी एशियाई बाजारों में जापान की तुलना में चीन १०-१५ प्रतिशत कम मूल्यों पर कपड़ा बच रहा है ।^१ जापान तो अपनी प्रतिस्पर्धा-शक्ति के लिए मशहूर ही है । पुराने देशों के अनिश्चित इन नये देशों की प्रतिस्पर्धा ने सूती कपड़े के निर्यात-व्यापार को चिन्ता का विषय बना दिया है ।

निर्यात-व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार भी चिन्तित है । सन् १९५४ में सूती वस्त्र-निर्यात प्रोत्साहन कौमिल की स्थापना की गई । सरकार न रियायतें तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान की । इनके फलस्वरूप ही १९५६ में अविद्य निर्यात सम्भव हो सका । यो तो उद्योग के सामने १०,००० लाख गज कपड़े के निर्यात का लक्ष्य है, किन्तु अभी तक यह लक्ष्य काफी दूर है । निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपाय किये गए हैं । पिछली जुलाई (१९५८) में 'क्वस्टाइन इन्व्वायरी कमेटी' ने यह सिफारिश की थी कि निर्यातकों को अपनी जरूरत के अनुसार मशीन व रासायनिक रजक पदार्थों की खरीदने की सुविधा दी जाए । निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए ३,००० स्वचालित करघों की स्थापना की स्वीकृति की सिफारिश भी कमेटी ने की । सूती कपड़े के निर्यात के आधार पर मशीन, कपाम व रासायनिक रजक पदार्थों के आयात के लिए उत्पादकों का छूट दान के सम्बन्ध में भी सरकार न यथासमय घोषणा की । जनवरी १९५६ में यह घोषणा की गई कि नवीकरण तथा पुनर्स्थापन के लिए अप्रक्षित विशिष्ट साज-सामान व आयात की मात्रा उन मिलों को दी जाएगी जो १९५४-५५-५६ के औसत निर्यात के ७५ प्रतिशत मूल्य से अधिक निर्यात करें या जिनका निर्यात १५०० रु० प्रति करघा प्रतिवर्ष के हिसाब में अधिक हो । इसी प्रकार की छूट सूत व निर्यात के लिए भी दी गई । फरवरी १९५६ में यह घोषणा की गई कि सूती कपड़े और सूत के निर्यातकों को निर्यात के ६६ २/३ प्रतिशत मूल्य के बराबर कपाम आयात करने

१ A Survey of the Indian Cotton Mill Industry, p 14

(1960) Indian Cotton Mills Federation, Bombay.

२ The Indian Cotton Mill Industry, pp 27-28—R A Peddar

का अनुमति दी जाएगी। इसी माह में सरकार ने यह घोषणा भी की कि अमेरिका और यूरोप (इंग्लिस्तान को छोड़कर) को कपड़ा और सूत का निर्यात करने वाली मिलों को कोलतार, रजक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ और गोद का आयात करने की अनुमति दी जाएगी। यह आयात उनके निर्यात के (F. O. B) मूल्य के ५ प्रतिशत के बराबर ही हो सकेगा। यह इंग्लिस्तान व अन्य देशों के निर्यात पर केवल ३ प्रतिशत के बराबर ही होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ७५ करोड़ रु० प्रतिवर्ष (१०,००० लाख गज कपड़ा) के निर्यात का लक्ष्य रखा गया। नवम्बर १९६५ में ही ६८७ लाख रुपये के मूल्य के कपड़े का निर्यात हुआ।

सूती मिल-उद्योग ऐसी स्पर्धा-शक्ति उसी समय प्राप्त कर सकेगा जबकि उद्योग का युवितकरण हो। इस उद्योग की यह दूसरी कठिनाई है कि मशीनों तथा अन्य साज-सामान पुराने और घिसे हुए हैं। सन् १९५२ में सूती वस्त्र-उद्योग की वकिंग पार्टी ने उद्योग की मशीनों का सर्वेक्षण किया। उद्योग के लगभग ५० प्रतिशत करघे १९१० के पहले के थे। २० प्रतिशत 'स्पिनिंग फ्रेम' भी १९१० से पहले के थे।

अनेक विशेषज्ञ निकायों ने, जिनमें टेक्स्टाइल इन्व्वायरी कमेटी १९५८ अद्यतन है, इस मत का समर्थन किया है। सरकार ने इस समिति के विचारों का समर्थन करते हुए यह भी स्वीकार किया है कि 'हमारे निर्यात तेजी से गिरते जाँगे जब तक कि हम स्वचालित करघों पर कपड़े का निर्यात नहीं करते।' सन् १९५७ में भारत में १४,१२८ स्वचालित करघे थे जबकि इसी वर्ष स्वचालित करघों की संख्या इटली में ७६,५६७, जर्मनी में ५८,१६७, जापान में ६७,५३६, यू० एस० ए० में ३५०,१०६ तथा यू० के० में ४४,८६३ थी। इन आँकड़ों से नवीकरण की समस्या का तुलनात्मक रूप पता चलता है। टेक्स्टाइल इन्व्वायरी कमेटी ने ३००० स्वचालित करघों की स्थापना का सुझाव दिया था जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। साथ ही वर्तमान करघों के स्थान पर प्रतिवर्ष २५०० स्वचालित करघों की दर से ७५०० स्वचालित करघों की स्थापना को स्वीकार करके सरकार ने व्यावहारिकता प्रदर्शित की है। नवीकरण के लिए उद्योग को लगभग ४०० करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इतनी बड़ी राशि के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम तथा ऐसी अन्य संस्थाओं को उद्योग की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए।

कपास इस उद्योग का प्रमुख आधार है। १९४७ में भारत के विभाजन के बाद भारत में कपास के उत्पादन को मात्रा काफी कम हो गई है। भारत में मध्यम और छोटी तूलिपट (staple) की कपास ही अधिकतर उगाई जाती है। अविभाजित भारत में १०६ लाख एकड़ भूमि में सुधरे प्रकार की कपास उगाई जाती थी। इसमें से ४७ प्रतिशत अर्थात् ५१ लाख एकड़ भूमि भारत के हिस्से में आई। इस प्रकार

अच्छी कपास की कमी है और भारत विश्व से औसतन ५२ लाख करोड़ रु० की कपास का आयात करता है।

६. प्रशुल्क-मण्डल द्वारा दूसरी जांच (१९३२)—चूंकि १९३० के अधिनियम में प्रस्तावित सरक्षण-करों की अवधि ३१ मार्च, १९३३ तक थी, अतएव प्रशुल्क-मण्डल को भारतीय सूती वस्त्र-उद्योग के सरक्षण के विषय में पुनः जांच करने की आज्ञा अप्रैल, १९३२ में दी गई। वस्त्र-उद्योग पर प्रशुल्क-मण्डल की रिपोर्ट के ऊपर सरकार को विचार करने का भोका देने के लिए १९३० में लगाये गए सरक्षणात्मक करों को २१ अक्टूबर, १९३३ तक बढ़ा दिया गया। अन्त में भारतीय विधानमण्डल ने २६ अप्रैल, १९३४ को १९३४ का भारतीय प्रशुल्क (वस्त्र-सरक्षण) सन्शोधन अधिनियम पास किया। यह अधिनियम १ मई से लागू हुआ। इसमें भारत-जापान के समझौते (१९३४) तथा भारत और इंग्लिस्तान के वस्त्र-उद्योग के गैर-सरकारी समझौते (जिसे 'मोदी ली पैक्ट' कहा जाता है) के आधार पर प्रशुल्क-मण्डल की वस्त्र-उद्योग को पर्याप्त सरक्षण देने की सिफारिश को कार्यान्वित किया। इस अधिनियम ने गैर-ब्रिटिश सूती वस्त्रों पर मूल्यानुसार ५०% आयात-कर निश्चित किया, जो कि सादे भूरे कपड़ों पर कम से-कम ५½ आना प्रति पौंड था।^१ इस अधिनियम की अवधि ३१ मार्च, १९३६ तक थी।

७. वस्त्र-सम्बन्धी विशेष प्रशुल्क-मण्डल (१९३५)—मण्डल ने अपनी जांच दिसम्बर, १९३५ में समाप्त की और जून, १९३६ में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित होने के लिए दी गई। साथ ही भारतीय प्रशुल्क अधिनियम की धारा ४ के अन्तर्गत एक अधि-सूचना द्वारा भारत सरकार ने प्रशुल्क-मण्डल के सुझावों के अनुकूल लकाशायर के वन कपड़ों पर कर की दर में २५ जून, १९३६ से तत्काल कमी की घोषणा की। प्रशुल्क-मण्डल की सिफारिशें निम्नलिखित थीं—

(१) सादे भूरे वस्त्रों पर मूल्यानुसार २५% या ४½ आना प्रति पौंड (जो भी दर ऊंची हो) से घटाकर, कर की दर मूल्यानुसार २०% या ३½ आना प्रति पौंड (जो भी ऊंची हो) कर दी जाए।

(२) छत्र कपड़ों के अतिरिक्त किनारेदार भूरे, कलफ किये या गीन वस्त्रों पर कर की दर २५ प्रतिशत से घटाकर मूल्यानुसार २० प्रतिशत कर दी जाए।

(३) कपास के सूत पर कर की दर पूर्ववत् रहे। लकाशायर में निराशा प्रकट की गई कि कर में उतनी कमी नहीं की गई जितनी होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ प्रमुख भारतीय व्यवसायियों ने सरकार की कर घटाने की नीति की कड़ी आलोचना की, क्योंकि यह भारतीय उद्योग, जिसके स्वभाविक विकास का क्षेत्र बहुत

१. देखिए, अध्याय १३।

२. = जनवरी, १९३४ से मिट्टेन के बाहर के आयात की वस्तुओं पर यही आयात की दर थी। भारत-जापान समझौते के फलस्वरूप कर की दर ७५ प्रतिशत से घटाकर ५० प्रतिशत कर दी गई।

३. रिपोर्ट ऑफ दि रैसल टैरिफ बोर्ड ऑन दि आइट ऑफ प्रोटेक्शन टु दि इंडियन कॉटन टैक्सडाल इ इस्ट्री (१९३६), पृ० १०६-१४।

सीमित था, के लिए घातक थी।

८ भारत-ब्रिटेन व्यापारिक समझौते के अन्तर्गत प्रशुल्क परिवर्तन (१९३६)—
ओटावा-समझौते के स्थान पर भारत और ब्रिटेन के बीच एक नये व्यापारिक समझौते के प्रश्न पर लम्बी कार्रवाइयो के दौरान में ब्रिटिश वस्त्रो पर लगाये गए प्रवेद्य करो में सशोधन का प्रश्न पुन प्रमुख हो उठा।^१ २० मार्च, १९३६ को हस्ताक्षरित इस नये व्यापारिक समझौते के अन्तर्गत भारत से ब्रिटेन को कच्ची कपास के निर्यात को ब्रिटिश वस्त्रो के आयात से सम्बद्ध कर दिया गया और इसके फलस्वरूप ब्रिटिश वस्तुओं पर आयात-कर में पुन कमी की गई। तदनुसार अप्रैल, १९३६ में पास हुए भारतीय प्रशुल्क (तृतीय सशोधन) अधिनियम के अनुसार ब्रिटेन के छपे कपडों पर मूल्यानुसार सरक्षारमक आयात-कर $17\frac{1}{2}\%$ हो गया, भूरे वस्त्रो पर मूल्यानुसार 15% या २ आना $7\frac{1}{2}$ पाई प्रति पीण्ड, जो भी ऊँचा हो, और शेप वस्त्रो पर मूल्यानुसार १५ प्रतिशत हो गया। ये आधारभूत कर थे। ब्रिटेन को ३,५०० लाख गज के निम्नतम कोटा के आयात की स्वीकृति दी गई और यदि किसी भी वर्ष मूती वस्त्रो का आयात ब्रिटेन से ३,५०० लाख गज से कम हुआ तो आधारभूत करो में $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत छूट देने की व्यवस्था थी। यदि किसी वर्ष ब्रिटिश आयात भारत में ५,००० लाख गज से अधिक हुआ तो आधारभूत करो में वृद्धि की भी व्यवस्था थी। यदि किसी भी वर्ष इंगलिस्तान का कुल आयात ४,२५० लाख गज न होता तो उस वर्ष के बाद ये बड़े हुए कर पुन घटाकर आधारभूत करो के बराबर कर दिए जाते। ब्रिटेन के वस्त्रो पर कर की दर-निर्धारण के समय भारत की कपास के निर्यात पर भी ध्यान देना आवश्यक था।

भारतीय सूती वस्त्र-उद्योग और विधान सभा ने करो के इस नये प्रबन्ध का बहुत विरोध किया, क्योंकि भारतीय कपास पैदा करने वालों के सापेक्षिक लाभ पर ध्यान न देकर इस अधिनियम में लकाशायर का अनुचित पक्षपात किया गया था और ऐसे समय में जबकि भारतीय सूती वस्त्र-उद्योग तनिक भी अच्छी अवस्था में नहीं था, सरक्षण की दरो में कमी करके इस अधिनियम ने उसके हितों की बलि दे दी।

उपरोक्त भारतीय प्रशुल्क (तृतीय सशोधन) अधिनियम (१९३६) ने मूती वस्त्र के लिए निश्चित सरक्षणात्मक करो की अवधि बढ़ाकर ३१ मार्च, १९४२ तक कर दी।^२

९ १९३६ ४५ के युद्ध-काल और बाद में सूती वस्त्र-उद्योग—महायुद्ध के प्रारम्भ के समय सूती वस्त्र उद्योग एक निष्क्रिय अवस्था में था।

१. देखिए, अध्याय १३।

२. जेन ब्रिटेन के साथ हुए व्यापारिक समझौते के अनुसार ब्रिटिश कपास पर आयात-कर में १७ अप्रैल, १९४० से कमी कर दी गई। भारतीय प्रशुल्क (सशोधन) अधिनियम, १९४७ के अनुसूची तत्कालीन सरक्षणात्मक करो को आगम करो में परिवर्तित कर दिया गया। १ जनवरी, १९४६ को मूल्यानुसार २५ प्रतिशत महीन वस्त्रों पर और ३ पाई प्रति गज मध्यम और मोटे कपडों पर एक उत्पादन-कर लगा दिया गया।

महायुद्ध के द्वितीय वर्ष से मुधार काल प्रारम्भ हुआ। वस्त्रों का आयात विशेषकर जुलाई, १९४१ में जापान के आयात समाप्त करने के वाद से नगण्य हो गया। सरकार और पूर्वी दल द्वारा युद्ध के लिए वस्त्रों की माँग में अपूर्व वृद्धि हुई तथा पश्चिमी और दक्षिणी अफ्रीका, मध्य-पूर्व, आस्ट्रेलिया, मलाया और डच पूर्वी द्वीप-समूह के लिए कपास से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में बहुत वृद्धि हुई। सूती वस्त्रों के मूल्य में इतनी वृद्धि हो गई कि सरकार को उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाने को बाध्य होना पड़ा। सरकार के सहयोग से मिलों द्वारा जनता के लिए सस्ते वस्त्रों के निर्माण की एक योजना चालू की गई और सरकार ने अपनी एजेन्सियों द्वारा निश्चित मूल्य पर इन्हे बचने का निश्चय किया। किन्तु यह योजना त्याग देनी पड़ी, क्योंकि यह 'उपयोगी' वस्त्र बिना न सके और उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकी। मई, १९४६ में भारत सरकार द्वारा सूती वस्त्र उद्योग के लिए मध्यान्तरकालीन योजना घोषित की गई। आगामी पाँच वर्षों में प्रतिवर्ष के लिए वस्त्र उत्पादन की सीमा ५५,००० लाख गज निश्चित की गई।

१०. जूट-उद्योग—१८६८ से १८७२ तक मिलों ने 'खूब पया बनाया' और १५ से २५ प्रतिशत तक लाभान्वित हुए। परिणामस्वरूप बहुत-सी नई मिलें खोली गईं और अति उत्पादन होने लगा। परन्तु यह हुआ कि लाभ शीघ्र ही घटने लग। उद्योग को एक मन्दकाल में गुजरना पड़ा और बहुत-सी मिल बन्द कर दी गईं। किन्तु जूट-उद्योग का आकार बहुत बड़ा हो चुका था, यहाँ तक कि १८८१ में वगल में ५,००० शक्तिचालित करघे चालू थे। १८८५ से उद्योग में टाट के बोरो की अपेक्षा जूट के कपडों के अधिक उत्पादन की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होने लगी। १८७७ और १९१५ के बीच जहाँ बोरो बनाने के करघे २,९५० से बढ़कर १७,७५० हो गए, जूट के कपडों के करघे ९१० से बढ़कर २०,६०३ हो गए, अर्थात् जूट के कपडा के करघों की वृद्धि २,४०० प्रतिशत हुई जबकि बोरो बनाने के करघों में ४३० प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रथम महायुद्ध में जूट-उद्योग में पर्याप्त प्रसार और समृद्धि हुई, क्योंकि विभिन्न युद्ध-क्षेत्रों की खाइयाँ के लिए बालू भरने के बोरो, तिरपाल, गाड़ियों को टक्कन के कपडे आदि युद्ध-सम्बन्धी माँग की पूर्ति उद्योग का करनी पड़ी। सन् १९१५-१६ में रूस पर जर्मनी के आक्रमण के कारण रूसी सन (पर्लैकम) की पूर्ति बन्द हो गई और उस स्थान पर भारतीय जूट का प्रयोग आवश्यक हो गया। इससे भी जूट-उद्योग को प्रोत्साहन मिला। १९१४-१८ के युद्धकाल के लाभ के फलस्वरूप अति उत्पादन होने लगा और युद्ध समाप्त होने पर उद्योग को बुरे दिन देखने पड़े। एक ओर माँग कम हो गई और दूसरी ओर जूट के मूल्य और मजदूरी बढ़ जाने के कारण उत्पादन-लागत बढ़ गई।'

११. अवसाद-काल और तदनन्तर जूट उद्योग—गिरते मूल्यों, प्रमुख उपभोग-केन्द्रों पर भण्डारों की उपस्थिति, श्रम अशान्ति आदि कारणों से जूट-उद्योग को भी हानि

पहुँची। इस सबके बावजूद भी इसन बम्बई के सूती मिल उद्योग की अपेक्षा युद्धोत्तर (१९२६) अवसाद की कठिनाइयों का सामना कहीं अच्छी तरह किया। यह पर्याप्त सुरक्षित कोष तथा समयानुसार बायाँवधि में कमी आदि उपायों का परिणाम था। मार्च, १९३६ में समाप्त होने वाले दस वर्षों में उत्पात्ति को कम करने की नीति का सदैव पालन किया गया था। जो मिलें सस्था की सदस्य थी वे प्रति सप्ताह ४० घण्टे काम कर रही थी और उनके करघों का एक निश्चित प्रतिदान बन्द रहता था। यह प्रतिशत १९३१ में १५ और १९३५ में १० था। बन्द करघों की प्रतिशत में वमी आने के कई कारण थे, यथा सीमीकरण-योजना के बाहर वाली मिलों की प्रतिस्पर्धा, व्यापारिक परिस्थितियों में सुधार तथा अन्य उत्पादन-केन्द्रों से प्रतिस्पर्धा। सस्था के बाहर की मिलों से समझौता न हो सका, अतः सस्था की सदस्य-मिलों को भी काम के घण्टों या यन्त्रों पर किसी प्रकार की रोक के बिना कार्य करने को स्वतन्त्र कर दिया गया।

सरकारी ऑर्डिनेन्स के स्थायी विधान में परिवर्तित हो जाने के डर से जनवरी, १९३६ में सस्था और बाहरी मिलों में कम घण्टे काम करने के लिए एक समझौता हो जाने से कानून द्वारा काम करने के घण्टे सीमित करने की आवश्यकता नहीं रही। जुलाई में एक पूरक समझौते के द्वारा मिलों ने २० प्रतिशत जूट के कपड़े और ७२ प्रतिशत बोरे बनाने के करघों को बन्द रखकर ४५ घण्टे प्रति सप्ताह काम करने का निश्चय किया। कच्चे जूट के मूल्य में कमी और बगाल के जूट-उत्पादकों पर इसके बुरे प्रभाव के कारण अगस्त, १९३६ में कच्चे जूट और टाट के निम्नतम मूल्य निश्चित करने के लिए प्रांतीय सरकार को दो ऑर्डिनेन्स जारी करने पड़े।

१२ जूट मिल उद्योग पर द्वितीय विश्वयुद्ध का प्रभाव—जहाजों द्वारा बाहर भेजी जाने वाली जूट-निर्मित वस्तुओं ने पूरे दशक के लिए एक रिकार्ड स्थापित कर दिया और १२,८०,४०० टन के वार्षिक उत्पादन में से १०,६८,७२५ टन का निर्यात हुआ। जूट और जूट-निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई जो मुख्यतया परिकल्पना का परिणाम थी। काम करने के घण्टों पर लगी रोक हटा ली गई और ६० घण्टे प्रति सप्ताह के अनुसार मिलें पूर्ण उत्पादन करने लगी तथा फैक्टरी-अधिनियम की कुछ धाराओं को भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेन्स द्वारा स्थगित कर दिया। बगाल सरकार ने भी जूट के कृषि-क्षेत्र को सीमित करने से सम्बन्धित एक बिल पर विचार करना स्थगित कर दिया।^१

जूट मिल सस्था ने अगस्त, १९४० में काम करने के घण्टों को कम करने ४५ घण्टे प्रति सप्ताह और मास में केवल ३ सप्ताह काम करना निश्चित किया। बाँधू भरने के बोरो व लिए नये गार्डरो के साथ काम करने के प्रति सप्ताह घण्टे

१. बाद में बगाल विधान सभा ने अगस्त, १९४० में बगाल जूट रेगुलेशन मिल जूट-उत्पादकों के हित में पास किया जो १९४१ में उत्पन्न होने वाली फसल पर लागू हुआ। इससे पहले मई, १९४० में सत्रा बानारों में कच्चे जूट और टाट के निम्नतम और अधिकतम मूल्य निश्चित करने के लिए बगाल सरकार ने दो ऑर्डिनेन्स जारी किये।

बढ़कर पुनः ६० हो गए, पर १८ मई, १९४० से कम होकर ये फिर ५४ घण्टे प्रति सप्ताह हो गए और १० प्रतिशत करके भी बन्द रहने लगे। विगत युद्ध में छद्मरीस मिलें सैनिक भण्डार और सामग्री के उत्पादन के लिए ले ली गईं। यद्यपि उद्योग इन भाँति अपनी उत्पादन-क्षमता के २५ प्रतिशत भाग से वञ्चित हो गया, परन्तु फिर भी यह युद्ध की माँग सहित सारी माँग की पूर्ति करने में समर्थ था।

सन् १९४७ और उसके उपरान्त विभाजन के फलस्वरूप जूट-उद्योग का (जो भारतीय गणराज्य में है) जूट-उत्पादक क्षेत्र (जो पाकिस्तान में है) से सम्बन्ध-विच्छेद हो गया है। भारतीय गणराज्य कच्चे जूट का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जबकि पाकिस्तान सबसे बड़ा विक्रेता है। विभाजन न, विशेषकर मुद्रा-प्रवृत्तयन (सितम्बर, १९४६) से, जूट-उद्योग को पूर्ण रूप से अश्वस्थित कर दिया। पाकिस्तान ने भारत को जूट निर्यात करना पूर्णतः बन्द कर दिया और प्रत्युत्तर में भारत ने (दिसम्बर, १९४६) पाकिस्तान को कोयले का निर्यात बन्द कर दिया। अविभाजित भारत के जूट उत्पादन करने वाले क्षेत्र का केवल २५१ ही भारत के भाग में आया था। भारत कच्चे जूट के विषय में आत्मनिर्भर होने के लिए अभी से प्रयत्नशील है।

१९४७-४८ की तुलना में क्षेत्रफल तीन गुना तथा उत्पादन टाई गुना हो गया है। जूट-उद्योग की समस्याओं के सम्बन्ध में सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए सरकार ने श्री के० आर० पी० आयोग की अध्यक्षता में जूट-जाँच आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने मई १९५४ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने कच्चे जूट के सम्बन्ध में सापक्षिक आत्मनिर्भरता की सिफारिश की। भारत को केवल उस कोटि का जूट बाहर से मँगाना चाहिए जो यहाँ पैदा न होना हो। दोष प्रकार के जूट की पर्याप्त मात्रा देना भी उगानी चाहिए। आयोग की अन्य प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थीं

(i) आयोग ने प्रति सप्ताह काम करने के घण्टों को सीमित करने तथा मशीनों के कुछ भाग को बन्द करने से सम्बन्धित (बकिंग टाइम एग्जीमेण्ट) कायावधि समझौते को समाप्त करने की सिफारिश की, क्योंकि इस समझौते के कारण अकुशल मिलों को अन्नतर मिलना है तथा विदेशी मिलें लाभ उठानी हैं।

(ii) कच्चे जूट के मूल्य के सम्बन्ध में आयोग का मत था कि उसे जूट के सामान के मूल्य-स्तर की तुलना में न्यायोचित सम होना चाहिए।

(iii) आयोग ने जूट उगाने वालों के दृष्टिकोण से सहकारी समितियों के नियमित बाजारों के संगठन-जैसे उपाय अधिक महत्त्वपूर्ण ठहराए।

प्रथम योजना के अन्तर्गत जूट के उत्पादन का लक्ष्य ५१ लाख गाँठें तथा जूट के सामान के उत्पादन का लक्ष्य १२ लाख टन था। किन्तु ये लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके। १९५५-५६ में कच्चे जूट का उत्पादन ४१.६७ लाख गाँठें तथा जूट के सामान का उत्पादन १०.६३ लाख टन (१९५६ के लिए) था। द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९६५-६६ के अन्त तक जूट के सामान के उत्पादन का १३ लाख टन तथा कच्चे जूट के उत्पादन का लक्ष्य ५० लाख गाँठें हुआ। जूट-निर्मित वस्तुओं

के उत्पादन के हाल के आँकड़े निम्न हैं
जूट-निर्मित वस्तुओं का उत्पादन^१

वर्ष	उत्पादन (लाख टन)
१९५५	१० २७
१९५६	१० ६३
१९५७	१० ३०
१९५८	१० ६२
१९५९	१० ५२
१९६५-६६	१३ ००

जूट-निर्मित वस्तुओं की माँग सप्ताह-भर की कृषि-सम्बन्धी उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है, क्योंकि आन्तरिक या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों ही में कृषि की उत्पाद्य वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए जूट-निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता होती है। भारत में कृषि के अच्छे साल में जूट-निर्मित वस्तुओं के निर्यात में कमी आ जाती है, क्योंकि फसलों की वृहद् राशि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाने के लिए जूट-निर्मित सामानों की आवश्यकता पड़ती है। इसी भाँति बाहरी माँग में कभी भी उदाहरणार्थ आधिक्य अवसाद के समय की कमी जूट-निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर बुरा प्रभाव डालती है।

१ मार्च १९५९ तक उद्योग के १२^१/_{१०} करघे बन्द थे। तदनन्तर बोरे के टाट का स्टाक बहुत मात्रा में एकत्रित हो जाना के कारण २ मार्च, १९५९ से २१ मार्च, १९५९ तक ११^०/_{१०} करघे और बन्द कर दिये गए। २२ जून के बाद इन १३^०/_{१०} करघों का चालू कर दिया गया। बाद में २४ अगस्त तक के लिए २३^०/_{१०} करघे चालू कर दिये गए। १९६३-६४ में जूट-उद्योग तथा व्यापार के लक्ष्यों को इस वर्ष में उत्पादन पार कर गया। उत्पादन १३ ५४ लाख टन और निर्यात ९.१३ लाख टन हुआ, जिसका मूल्य १५७ ४२ करोड़ रुपया था। जूट का निर्यात १९६४-६५ में और बढ़कर १७६ १४ करोड़ पहुँच गया। परन्तु जूट की विशेष प्रकार से कच्चे माल की समस्याओं तथा कीमतों इत्यादि का हल ढूँढने के लिए भारत सरकार ने सितम्बर १९६४ में जूट टेक्स्टाइल्स परामर्श बोर्ड (Jute Textiles Consultative Board) बनाया है और अर्ध १९६६ में जूट मिलों को उत्पादन से एक सप्ताह से अत्यन्त द्रिया गया।

१३. जूट-उद्योग की समस्याएँ—जूट-उद्योग की एक समस्या कच्चे माल की है। यह समस्या भारत के विभाजन के परिणामस्वरूप ही उत्पन्न हुई है। विभाजन के परिणामस्वरूप जूट उत्पन्न करने वाले क्षेत्र अधिकांशतः पाकिस्तान में चले गए।

१. वर्ष का अर्थ जुलाई से लेकर जून तक है। ये आँकड़े इण्डियन जूट मिल्स एसोसियेशन की सदस्य-मिलों व एक गैर-सदस्य मिल के हैं।
—इण्डिया १९६०, पृ० ३१२।

तब से सरकार जूट की किस्म और उत्पादन की वृद्धि के लिए बराबर प्रयत्नशील है। सन् १९५६-५७ में जूट (१,८८३ हजार एकड़) तथा मेस्टा (७३८ हजार एकड़) की खेती २,६११ हजार एकड़ भूमि में हुई थी। इस वर्ष जूट का उत्पादन ४,२२१ हजार गांठों तथा मेस्टा का उत्पादन १,४७४ हजार गांठों था। प्रारम्भ में कच्चे माल की समस्या के समाधान के लिए जूट की खेती पर लगे प्रतिबन्ध हटा लिये गए। कच्चे जूट के मूल्य पर लगा नियन्त्रण हटा लिया गया। बेकार भूमि को खेती-योग्य बनाया गया तथा घान के कुछ क्षेत्र जूट के उत्पादन के लिए प्रयुक्त होन लगे। इन सबका परिणाम यह हुआ कि अनेक ऐसे क्षेत्रों में जूट की खेती होन लगी जो जलवायु की दृष्टि से इस योग्य नहीं हैं। परिणाम यह हुआ कि उत्पादन में तो पर्याप्त वृद्धि हुई, किन्तु किस्म निम्न कोटि की ही रही। अतएव उच्च कोटि के जूट के आयात की समस्या ज्यों-की-त्यों बनी रही। फरवरी, सन् १९५३ में भारत सरकार ने जूट की किस्म में सुधार करने के हेतु सुभाव देने के लिए एक प्रवर समिति (एक्सपर्ट कमेटी) नियुक्त की। इस समिति की लगभग सभी सिफारिशें सरकार द्वारा मान ली गईं और जूट की किस्म सुधारन पर बहुत जोर दिया जाने लगा। जूट को मुलायम या नरम करने के लिए नये तालाबों के निर्माण तथा पुराने तालाबों को पुनः खोदकर तैयार करने का काम हाथ में लिया गया। बीज के कृषि क्षेत्र स्थापित किये गए ताकि उत्पादकों को अच्छा बीज मिल सके।

१९५८-५९ में कच्चे जूट के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। इस वर्ष जूट का उत्पादन ५१८ लाख गांठों तथा मेस्टा का उत्पादन १५८ लाख गांठों था। इस वर्ष ५७-५८ की तुलना में कृषि का क्षेत्रफल १७४ लाख एकड़ से बढ़कर १८३ लाख एकड़ हो गया। प्रति-एकड़ उपज भी १९५७-५८ की ०.३३ गांठों से बढ़कर २.८६ गांठों हो गई, किन्तु पाकिस्तान की प्रति एकड़ ३.६३ गांठों की उपज की तुलना में यह अब भी बहुत कम है। तत्पश्चात् मूल्यों के घटन के कारण १९५९-६० में कृषि के क्षेत्र में कमी आ गई। कच्चे माल की समस्या के हल के लिए सामान्यतः कृषि का विस्तार किया गया है। आवश्यकता इस बात की है कि गहन खेती, अच्छे बीज और औजारों की व्यवस्था तथा साख-सम्बन्धी सुविधाओं द्वारा अच्छे जूट के उत्पादन की मात्रा और प्रति-एकड़ उपज में वृद्धि की जाए। कच्चे माल की समस्या हल करने के लिए इन सभी बातों के सम्बन्ध में सुभाव दिये गए हैं, परन्तु कृषि-विस्तार की अपेक्षा इन पर कम ध्यान के कारण ही इस समस्या का समाधान नहीं हो सका है। केन्द्र और प्रान्तों के भिन्न मत होने के कारण भी कुछ कठिनाई उठती है।

पुनः इस समस्या को हल करते समय हमें जूट की किस्म के सुधार पर बराबर ध्यान देना चाहिए। यों तो १९५८-५९ में उत्पादन की मात्रा के दृष्टिकोण से भारत आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुका है, क्योंकि उस वर्ष अपेक्षित माँग ६५ लाख गांठों (जूट और मेस्टा) थी और उत्पादन लगभग ६७.६ लाख गांठों (जूट और मेस्टा) था, किन्तु

पाकिस्तान से जूट का आयात बराबर हो रहा है, क्योंकि उष्णकोटि के उत्पादन में हम अभी आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं।

जूट-उद्योग की दूसरी समस्या निर्यात से सम्बन्धित है। यह उद्योग विदेशी विनिमय अर्जित करने का प्रधान साधन रहा है।

निर्यात की कठिनाइयाँ बढ़ने के अनेक कारण हैं। भारत का एकाधिपत्य समाप्तप्राय है। अब अनेक एशियाई (जापान, थाईलैंड, बर्मा) और यूरोपीय देशों (फ्रांस, हालैंड, बेल्जियम) में जूट-मिलों की स्थापना हो रही है। भारत के पड़ोस में पाकिस्तान ही इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। कच्चे जूट की प्रचुरता तथा श्रेष्ठता और नई मशीनों से सुसज्जित मिलों के कारण पाकिस्तान का जूट उद्योग एक समय प्रतिद्वन्द्वी का रूप धारण करता जा रहा है। विदेशों में जूट के स्थानापन्न ढूँढ़ निकाले गए हैं। मुख्यतः परिवेष्टन के लिए कागज का प्रयोग होने लगा है। इससे जूट की माँग में कमी और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा की वृद्धि हो गई है। इधर वस्तुओं को अलग-अलग परिवेष्टित करने के बजाय सामूहिक परिवेष्टन (bulk handling) का प्रचलन होने के कारण जूट के बोरो की माँग प्रभावित हो रही है। निर्यात की समस्या का सन्तोषप्रद हल तभी हो सकता है जब कि जूट-उद्योग अपनी वस्तुओं को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर बेच। इसके लिए यह आवश्यक है कि सरकार कर-भार से उद्योग को मुक्ति प्रदान करे। जूट-आच आयोग ने भी ऐसी ही सिफारिश की थी। सरकार ने इस दिशा में कदम अवश्य उठाए हैं, किन्तु देर से उठाने के कारण उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा-शक्ति की हीनता के रूप में हानि उठानी पड़ी। जनवरी से सितम्बर, १९५६ तक ६७५,३६६ टन जून के सामान का निर्यात हुआ जिसे ८४६७ करोड़ रुपये का मूल्य का विदेशी विनिमय प्राप्त हुआ। इस अवधि में १९५८ में ६,१४,३३७ टन जूट के समान का निर्यात हुआ जिससे ८० करोड़ ६० के बराबर विदेशी विनिमय प्राप्त हुआ। बोरो के निर्यात में बहुत कमी आ गई, क्योंकि पाकिस्तान, बर्मा, थाईलैंड, फिलीपाइन, वियतनाम और मिस्र आदि देशों में जूट-मिलों की स्थापना से प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई। हमारा लक्ष्य १९५५-५६ के ६,७५,००० टन के निर्यात को बढ़ाकर १९६०-६१ तक ९,००,००० टन करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें ठोस कदम उठाने चाहिए। एक ओर हमें उत्पादित वस्तु की श्रेष्ठता पर जोर देना चाहिए (जो अशत कच्चे माल की श्रेष्ठता पर निर्भर है) तथा दूसरी ओर हमें उत्पादन में विविधता लानी चाहिए। इसके साथ ही हमें विदेशी बाजारों में बिक्री बढ़ाने के उपाय करने चाहिए तथा मूल्यों के सम्बन्ध में भी एक स्थिर नीति बरतनी चाहिए। भारत सरकार ने भारतीय जूट मिल संघ (इण्डियन जूट मिल्स एसोसियेशन) को जूट के सामान का प्रचार और प्रसार करने के लिए १९५६-६० में १२५ लाख रु० का अनुदान दिया है। इस सत्था ने यू० एस० ए०, कनाडा और यू० के०—इन देशों में एक शिष्टमण्डल भेजा है जो जूट-उद्योग के लिए बाजारों के विकास और नये बाजारों की तलाश करेगा।

३१ मार्च, १९५६ तक स्थिति यह थी कि ५५ प्रतिशत मिलों में नये ढग के

कनाई कतकुए लग चुके थे। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने २२ कम्पनियों (मिलों) को ४५५ करोड़ रु० का ऋण मजूर किया। इनमें से १६ कम्पनियों को ऋण मिल भी चुका है। युक्तीकरण के परिणामस्वरूप कुछ मिलें बन्द भी हो गईं, किन्तु सन्तोप की वान यह है कि इसमें बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि श्रमिकों को उन मिलों में काम मिल गया जो बन्द हुईं मिलों के उत्पादन के लिए उत्तरदायी थीं।

१४. लोहा और इस्पात-उद्योग—इंग्लैण्ड की नवीन औद्योगिक व्यवस्था की ठोस नींव लोहा और इस्पात उद्योग तथा सहायक यांत्रिक उद्योगों के सुदृढ आधार पर पड़ी थी, किन्तु भारतवर्ष में क्रान्ति का पथ ऐसे विकास से नहीं निश्चित हुआ है। हाल तक भारतीय उद्योग पूर्णरूपेण धायात किये गए यन्त्रों, यान्त्रिक वस्तुओं और घात्विक वस्तुओं पर साधारणतया निर्भर रहे हैं।

सिंहभूमि और मानभूमि जिलों की लोहे की खानों के नए स्रोतों के प्रयोग के साथ १९१० में बंगाल कम्पनी के इतिहास में एक नये युग का सूत्रपात हुआ। टाटा कम्पनी की स्थापना उद्योग के इतिहास में दूसरा महत्त्वपूर्ण चरण था। स्वर्गीय जे० एन० टाटा द्वारा १९०७ में कम्पनी सिंहभूमि जिले में सकची नामक स्थान पर स्थापित हुई और कारखाने का निर्माण १९०८ से आरम्भ हुआ। दिसम्बर, १९११ में पहली बार अशुद्ध लोहा तैयार किया गया और वर्तमान काल में भारतवर्ष में इस्पात का उत्पादन पहली बार १९१३ में हुआ। १९१६ तक युद्ध की माँगों से उत्तेजना पाकर समस्त यन्त्र पूर्ण उत्पादन कर रहे थे। इस भानि कुछ चिन्तापूर्ण समय के बाद कारखाना सुदृढ आधार पर स्थित हो गए तथा इन्होंने फिचस्तीन, पूर्वी अफ्रीका और मंगोलिका में मैनिक रेलों के लिए बृहद् मात्रा में रेल की पट्टी और स्लीपरों की पूर्ति करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की। १९१७ में विस्तार की एक बड़ी योजना सामने रखी गई जो १९२४ में पूरी हो गई। कारखानों में स्थित पहली मशीनें इस्पात का तैयार माल, जैसे रेल की पट्टी, निर्माण-सम्बन्धी भारी वस्तुएँ, छड़ें, निर्माण सम्बन्धी हल्की वस्तुएँ, हल्की रेल की पट्टियाँ और फिशप्लेटें आदि बनाती थीं। १९२६ से कारखानों में स्थित नये यन्त्रों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अन्य वस्तुएँ प्लेटें, चद्दर (काली और धातु चढ़ी हुई), चद्दरों की छड़ें और चद्दरों की स्लीपर आदि थीं। टाटा के साहस की सफलता ने कुछ नवीन कम्पनियों को जन्म दिया, जैसे कलकत्ता में मेसर्स वर्न एण्ड कम्पनी, १९०८ में आसनमोल के पास हीरापुर में स्थापित इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, १९२३ में भद्रावती में आरम्भ किये गए मैसूर स्टेट आयरन वर्क्स इत्यादि।

१५. लोहा और इस्पात का आयात—अपने बढ़ते उत्पादन के बावजूद भी भारत बाहरी लोहे और इस्पात पर बड़ी मात्रा में निर्भर रहा। १९१४ के पहले भारत ४ सौ और इस्पात का औसत आयात ८,०८,००० टन था और इसका मूल्य १२४८ करोड़ रुपये था। १९१४-१८ के युद्ध-काल में औसत आयात घटकर ४,२२,००० टन

रह गया जिसका मूल्य १० ११ करोड़ रुपये था । इसी काल में टाटा कम्पनी ने अपना उत्पादन बढ़ाया और सरकार की युद्ध-सामग्रियों की पूर्ति की । प्रथम महायुद्ध के बाद आयात बढ़ता गया । यह बढ़ता आयात रेलों, अन्य सार्वजनिक कार्यों तथा निर्माण-व्यापार के वर्द्धमान उपभोग का परिणाम बताया गया । इस बढ़ते आयात ने उद्योग की सुरक्षा प्रदान करने के विषय में एक और तर्क प्रस्तुत किया ।

१६. लोहा और इस्पात-उद्योग की सुरक्षा प्रदान करना—अर्थ-आयोग के सुझाव के अनुसार भारतवर्ष में विवेचनात्मक सुरक्षा की नीति पहले-पहल लोहा और इस्पात उद्योग में कार्यान्वित की गई । प्रचुल्क-मण्डल, जो जुलाई, १९२३ में स्थापित किया गया था, का निष्कर्ष था कि श्रम को छोड़कर उद्योग अर्थ-आयोग द्वारा दी गई सभी शर्तों की पूर्ति करता है । श्रम के सम्बन्ध में भारत की स्थिति लाभपूर्ण नहीं थी, परन्तु यह किसी भी कृपि-प्रधान देश में, जहाँ औद्योगिक अनुभव तथा प्रशिक्षण प्राप्त करना श्रेय है, अवश्यम्भावी है । इस कारण ही इस समय अमेरिका तथा यूरोप से कुशल निरीक्षकों का आयात आवश्यक है । किन्तु यह एक अस्थायी अनुविधा थी जो कालान्तर में दूर हो जाती । मण्डल की सम्मति थी कि सुरक्षा विधे बिना आगामी वर्षों में उद्योग के विकास की कोई आशा नहीं थी और भय अवश्य था कि वही उद्योग ही न ठप हो जाए ।

जून, १९२४ में मण्डल की सिफारिशों का समावेश करते हुए इस्पात सुरक्षा बिल (स्टील प्रोटेक्शन बिल) पास किया गया । इस्पात से तैयार कुछ वस्तुओं पर कर बढ़ा दिया गया । भारत में निर्मित इस्पात की भारी रेलों, फिशप्लेटों और रेल के डिब्बों को सहायता प्रदान की गई । १९२४-२७ तक का पूर्ण योग २४२ लाख रुपये था । अवधि के समाप्त होने पर कर और सहायता दोनों में संशोधन किया जा सकता था ।

इस्पात की सुरक्षा के इस पहलू के लिए प्रचुल्क-मण्डल ने कुछ सिफारिशों की जो सरकार और विधान सभा द्वारा स्वीकार कर ली गईं । कुछ अपवाद-सहित आयात विधे हुए इस्पात पर उच्चतर कर लगाकर अभियान्त्रिक उद्योग की सुरक्षा प्रदान किया गया ।

१७ इस्पात उद्योग की परिनियत जांच (१९२६-२७)—३१ मार्च, १९२७ की समाप्त होने वाले १९२४ के इस्पात-सुरक्षा अधिनियम के अनुसार १९२६ में प्रचुल्क मण्डल ने उद्योग की दशा की सावधानीपूर्वक जांच की और कुछ विशिष्ट दिशाओं में सुरक्षा की अवधि सात वर्ष के लिए और बढ़ा देने की सिफारिश की । अब सुरक्षा उत्पादन की सहायता के लिए न होकर बड़े हुए आयात-कर के रूप में हो गया । इसका कारण यह था कि सात वर्ष तक सहायता के रूप में सुरक्षा देना बहुत महंगा होता तथा इस अवधि के बाद पुन जांच करनी पड़ती कि कितना और कौसा सुरक्षा अभी और आवश्यक है । तदनुसार १९२७ के दिल्ली-अधिवेशन में एक बिल पेश किया गया जो १ अप्रैल, १९२७ से लागू हुआ । इसके अनुसार लोहे और इस्पात की विभिन्न वस्तुओं पर करों की विभिन्न दरें, निर्धारित की गईं, साथ ही ब्रिटिश उत्पादन की

वस्तुओं पर एक आधारभूत कर और ब्रिटेन से बाहर बनी वस्तुओं पर एक अनिश्चित कर भी लगाया गया ।

१८ लोहे और इस्पात के उद्योग के विषय में सरक्षण के अन्य कदम—भारतीय प्रशुल्क (ओटावा व्यापार समझौता) संशोधन अधिनियम, १९३२ ने, जो १ जनवरी, १९३३ से लागू हुआ, जुलाई और अगस्त, १९३२ में आटावा में भारत सरकार और इंग्लिस्तान की सरकार के बीच हुए समझौते तथा सितम्बर में लोह और इस्पात के पूरक समझौते के फलस्वरूप हुए प्रशुल्क-सम्बन्धी परिवर्तनों को कार्यान्वित किया । लोह और इस्पात की वस्तुओं की श्रेणी में केवल उन्हीं वस्तुओं को प्रायश्चित्त दी गई जो सरक्षण करों से मुक्त थीं । १९२७ के अधिनियम द्वारा लगाय गए सरक्षण करों की कार्यविधि बढ़ाकर ३१ अक्टूबर, १९३४ कर दी गई । इसी बीच इस्पात-उद्योग (सरक्षण) अधिनियम, १९२७ के अनुसार प्रशुल्क-मण्डल ने सरक्षण के नवीकरण का प्रश्न की पूर्ण समीक्षा की । लोहा और इस्पात-कर अधिनियम, १९३४ ने प्रशुल्क मण्डल द्वारा सुभाये गए सरक्षण क उपायों को १ नवम्बर से लागू किया । मण्डल को सिफारिशों के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के विषय में सरक्षण-कर के स्तर में कमी और उनके फलस्वरूप प्राप्त आय में कमी होने का कारण यह आवश्यक हो गया कि आय का लिए ब्रिटेन भारत में इस्पात के पिण्डों के उत्पादन पर ४ रु० प्रति टन का उत्पादन-कर और इस्पात के पिण्डों पर समप्रभावोत्पादक कर लगा दिया जाए । यह समप्रभावोत्पादक कर मण्डल द्वारा सुभाये गए सरक्षण-करों के अलावा है और जिन वस्तुओं को सरक्षण नहीं दिया गया उन पर मूल्यानुसार लगाय हुए आगम करों का विकल्प है । जैसा कि प्रशुल्क-मण्डल का सुभाव था, पूरक समझौता १९३४ में समाप्त कर दिया गया ।^१

सब वानों का ध्यान में रखकर यह कहा जा सकता है कि १९२४ के बाद भारत सरकार की नीति लोहा और इस्पात-उद्योग के विषय में सहायक रही । राज्य के सामयिक हस्तक्षेप के बिना उद्योग युद्धोत्तर-काल की प्रतिस्पर्धा का धक्के को सहन नहीं कर सकता था, फिर भी १९२४ और १९२७ के बीच प्राप्त सरक्षण पर्याप्त नहीं था और टाटा स्टील कम्पनी किसी भी भाँति अपना काम चलाती थी । इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी उद्योग ने प्रशंसनीय उन्नति की, जैसा उत्पादन की वृद्धि, श्रम की कुशलता में सुधार, विदेशी कर्मचारियों की संख्या में कमी, कार्यशाला की लागत में विचारणीय कमी और श्रमिकों की दशा में भी विचारणीय सुधार, विशेषकर मजदूरी, आवास तथा जीवन की अन्य विभिन्न सुविधाओं के सम्बन्ध में उन्नति से स्पष्ट है ।^२

उद्योग के स्थायी प्रसार की भाँती उत्पादन और धायान के आँकड़ों से मिल सकती है । शताब्दी के आरम्भ में अशुद्ध लोह का उत्पादन ३५,००० टन से बढ़कर

१. वी० एन० अदरकर, 'इस्टर्न एंड इण्डियन टैरिफ', पृ० २० ।

२. Engineering News of India, Sept, '60, p. 301

१९३८-३९ में १५,७६,००० टन हो गया, जिसमें से २५६ लाख रु० के मूल्य का ५,१४,००० टन निर्यात किया गया। जिसका ग्राहक जापान था। जापान के बाद इंग्लिस्तान और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भारतीय अशुद्ध लोहे के ग्राहक रहे हैं। भारत में उत्पादित अशुद्ध लोहा सब प्रकार से यूरोपीय अशुद्ध लोहे के समान है। वास्तव में अशुद्ध लोहे का आयात अब लगभग नगण्य है। इस्पात का उत्पादन १९१६-१७ के १,३९,४३३ टन से बढ़कर १९२७-२८ में ५,९९,५६५ टन हो गया और इसी अवधि में तैयार इस्पात का उत्पादन ९८,७२६ टन से बढ़कर ४,२८,६५४ टन हो गया। १९३८-३९ में इस्पात-पिण्डों का उत्पादन ९,७७,००० टन और तैयार इस्पात का उत्पादन ७,२६,००० टन था।

१९. लोहा और इस्पात-उद्योग की वर्तमान स्थिति—सितम्बर, १९३९ में युद्ध छिड़ जाने से भारत के लोहा और इस्पात उद्योग को एक नवीन प्रेरणा मिली। यह १९३९ और १९३८ के उत्पादन की तुलना से स्पष्ट हो जाता है जब दोनों वर्षों में अशुद्ध लोहे का कुल उत्पादन क्रमशः १८,३५,००० टन और १५,७५,००० टन था। इस्पात-पिण्डों और तैयार इस्पात का उत्पादन बढ़कर क्रमशः १०,६७,००० टन और १०,६२,९०० टन हो गया जो कि पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः ९२ प्रतिशत और १४१ प्रतिशत अधिक था। १९३९ का उत्पादन १९३२-३३ के उत्पादन का लगभग दूना था।

पहिले, टायर और धुरो इत्यादि के निर्माण के लिए जर्मिसेदपुर में इस्पात उत्पादन करने के नये मन्त्र स्थापित किये गए हैं, जिससे इञ्जनों और डिब्बों के बड़े पैमाने पर बनाने की सम्भावनाएँ हो गई हैं।

२०. मूल्य-नीति—मार्च, १९४६ में युद्ध के ठेके-सम्बन्धी मूल्य-नियन्त्रण समाप्त कर दिये गए तथा बाणिज्यिक मूल्य ही निश्चित किये गए। तब से दोहरे मूल्यों की प्रथा चली आ रही है। एक विनय-मूल्य निश्चित किया जाता है। इस मूल्य पर स्टील बाजार में बेचा जाता है। विनय से प्राप्त धनराशि एक कोष (equalisation fund) में जमा कर दी जाती है। इस कोष में से उत्पादकों को एक निश्चित मूल्य के अनुसार (जिसे retention price कहते हैं) अदायगी की जाती है तथा आयात करने वालों को आयात के भुगतान के लिए धनराशि दी जाती है।

२१. योजना और इस्पात-उद्योग—१९५१-५६ के औद्योगिक विकास के कार्यक्रम में टाटा बक्स के आधुनिकीकरण तथा १० लाख टन पिण्ड से उत्पादन १३ लाख टन पिण्ड करने का लक्ष्य रखा गया। इसी प्रकार बनेपुर के लिए भी उत्पादन-क्षमता की वृद्धि का लक्ष्य ३ लाख टन पिण्ड से बढ़ाकर ५ लाख टन पिण्ड था। योजना-आयोग ने उद्योग की आर्थिक कठिनाइयों को अनुभव करके उद्योग को आर्थिक सहायता दी। टाटा तथा इण्डियन आइरन, प्रत्येक को दस करोड़ रु० का व्याजरहित ऋण-मूल्य समानीकरण कोष (Price Equalisation Fund) में से दिया। इण्डियन आइरन को योजना प्रारम्भ होने से पहले १९५० में प्रारम्भ विस्तार-योजना के लिए ७९ करोड़ रु० का ऋण मिल चुका था। योजना-आयोग का अनुमान था कि १९५७ तक

तैयार स्टील की माँग २८ लाख टन हो जाएगी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में तीन प्रमुख उत्पादकों के तैयार स्टील का उत्पादन १०.७ लाख टन (१९५१) से बढ़कर १२.६ लाख टन (१९५५) हो गया। योजना-वधि में स्टील की खपत में वृद्धि हुई और आयात १,७८,००० टन (१९५१) से बढ़कर ६,००,००० टन (१९५५) हो गया।

सन् १९५४ में श्री टी० टी० कृष्णामाचारी ने स्टील की भावी माँग का अनुमान लगाने के लिए एक नये सर्वेक्षण का सूत्रपात किया। इस सर्वेक्षण के अनुसार १९६१ तक तैयार स्टील की माँग ४५ लाख टन अथवा ६० लाख टन पिण्ड होगी। अतएव मार्च १९५५ में स्टील के कारखानों की स्थापना में रूसी सहायता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। अगले महीने तीसरे कारखाने की स्थापना के लिए सरकार ने ब्रिटिश मिशन को आमन्त्रित किया। तीसरे कारखाने की स्थापना के लिए दुर्गापुर चुना गया। जुलाई १९५५ में एक पूरक समझौते द्वारा हरकेला के कारखाने को प्रारम्भ से ही दस लाख टन की क्षमता वाला कारखाना बनाना निश्चित किया गया।

१९५६ में सरकारी क्षेत्र के नौवें कारखानों में कार्य प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने ७,७०,००० टन पिग आइरन (भट्टी से निकला लोहा) तथा १,५०,००० टन स्टील (अर्द्धनिर्मित) का उत्पादन किया। १९५८ की तुलना में निजी क्षेत्र के दो कारखानों के उत्पादन में ४,५०,००० टन स्टील और ५,००,००० टन पिग आइरन (भट्टी से निकले लोह) की वृद्धि हुई।

लोहे और इस्पात के तीन प्रमुख उत्पादकों (टाटा आइरन एण्ड स्टील क०, इण्डियन आइरन एण्ड स्टील क०, जिसमें स्टील कारपोरेशन ऑफ बंगाल विलयित है तथा मैसूर आइरन एण्ड स्टील वर्क्स) की प्रसार-योजनाओं के बाद भी इस्पात के उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि सम्भव नहीं है। यदि सब कुछ ठीक रहे तो १९६३ तक ४५ लाख टन तैयार स्टील के उत्पादन का लक्ष्य पूरा हो सकता है।

लोहा तथा इस्पात बिजली की तरह औद्योगिक उन्नति के लिए एक बहुत आवश्यक चीज है। इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं में इसको बहुत महत्त्व का स्थान दिया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त तक तैयार इस्पात का उत्पादन १३ लाख टन था जो अधिकतर निजी क्षेत्र के कारखानों में हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को बड़ा करने के अतिरिक्त तीन नये इस्पात के कारखाने खोले गए (दस लाख टन क्षमता वाले)। तीसरी पंचवर्षीय योजना में तैयार इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य ६८ लाख टन रखा गया। १९६५-६६ में इस्पात का उत्पादन ५५ लाख टन तक रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना में इस्पात (अर्द्धनिर्मित) १.६५ करोड़ टन का लक्ष्य रखा गया है जो कि तीन सरकारी कारखानों के उत्पादन को बढ़ाने तथा एक चौथे कारखाने को बोकारो (Bokaro) में खोलने पर। चौथी पंचवर्षीय योजना में एक पाँचवें सरकारी स्टील कारखाने के खोलने का भी

विचार है। इसके अतिरिक्त टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी को अपनी उत्पादन शक्ति को २० लाख टन से ३० लाख टन और १० लाख टन से १३ लाख टन की अनुमति दे दी है।

सितम्बर १९६३ में जापान की ५ विशेष फर्मों की सहायता से दुर्गापुर में ६० हजार टन शक्ति के अलाय (Alloy) तथा अजगर स्टील को पैदा करने वाला कारखाना खोला गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में इस कारखाने की उत्पादन शक्ति तीन गुना बढ़ाई जायेगी। इसी प्रकार भद्रावती के स्टील कारखाने को भी अलाय के रूप में बदला जा रहा है। यूगोस्लाविया सरकार की सहायता से उदयपुर में भट्टी से निकलने वाले लोहे (Pig Iron) का कारखाना खोला गया है। महेन्द्रगढ़ (पंजाब) में भी इस प्रकार का कारखाना खोलने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने दो स्टेनलैस स्टील (Stainless Steel) के कारखाने खोलने का विचार है— एक मद्रास में और दूसरा बतवा (गुजरात) में।

अक्टूबर १९६३ की डॉ० के० एन० राज की रिपोर्ट के अनुसार इस बात पर जोर दिया गया कि अभाव प्रधानता इस्पात के मभरण पर सरकार का नियंत्रण हटा दिया जाय और प्रधानता इस्पात पर नियंत्रण रखा जाय। इसका विशेषतया सरकार की मूल्य नीति पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। फिर भी इन बातों के होते हुए भारत विश्व के अच्छे औद्योगिक देशों से पीछे है। (प्रति व्यक्ति इस्पात का उपभोग भारत में १६ पौंड है जबकि अमरीका में १२३७ पौंड है।)

लोहा और इस्पात उद्योग के युद्धकालीन विकास से अभियान्त्रिकी उद्योग का विकास घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है। इसके निम्नलिखित अति महत्वपूर्ण पहलू हैं—

(१) युद्ध सामग्री की फैक्ट्रियाँ—रक्षा-विभाग-योजना के अन्तर्गत युद्ध-सामग्री की फैक्ट्रियों का बहुत अधिक विकास और अभिनवीकरण हुआ है। इसकी सिफारिश चैंटफील्ड समिति ने भी की थी। बन्दूकों, गोलों और विस्फोटकों के उत्पादन की वृद्धि के साथ भारत पूर्व और मध्यपूर्व के देशों का आयुधागार बन गया।

१९६२ के चीनी आक्रमण तथा विशेषकर १९६५ के पाकिस्तानी आक्रमण के पश्चात् युद्ध-सामग्री की फैक्ट्रियों को बहुत सहायता दी जा रही है।

(२) अभियान्त्रिक तथा यान्त्रिक औजार (मशीन टूल) —युद्ध सामग्री के लिए अपेक्षित विशिष्ट मशीनों से लेकर धरमा (एक प्रकार का औजार) और खराद-जैमे साधारण औजारों और सभी यान्त्रिक औजारों के निर्माण में युद्ध-काल में कुछ-न-कुछ उन्नति हुई, फिन्नु मिल, जहाज, मोटरगाड़ियाँ, हवाईजहाज आदि के लिए आवश्यक भारी यन्त्रों के निर्माण में बहुत कम सफलता हुई।

युद्ध से अभियान्त्रिक सामग्रियों और भण्डारों के निर्माण को बहुत प्रोत्साहन मिला। इस सामग्री और भण्डार के कुछ उदाहरण निम्न हैं—स्टील पाइपे, छादन (शेड), क्रेन, पेट्रोल और पानी एकत्र करने की टर्कियाँ, लारियाँ, हथियारबन्द कारे रेल के डिब्बे, रेलवे भण्डार, बिजली का भण्डार, इस्पात के तारों के रस्ते, अग्नि से

खडने वाले औजार इत्यादि ।

यान्त्रिक औजार—स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत सरकार ने देश के यान्त्रिक औजारों के कारखानों को प्रोत्साहन दिया है, कई प्रकार की मशीनों तथा यन्त्रों के कारखान सरकारों क्षेत्र में खोले गए हैं और देश में दो-सौ करोड़ रुपये (२०० करोड़) का वार्षिक उत्पादन है । एक सेंट्रल मशीन टूल इन्स्टीट्यूट (Central Machine Tool Institute) बंगलौर में डीसाईन, ट्रेनिंग, अनुसंधान-कार्यों के लिए खोली गई है । इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान मशीन टूल और हैवी इलेक्ट्रिकल इण्डिया लिमिटेड (Heavy Electrical India Ltd) के खुल जाने के कारण इस प्रकार की चीजों का उत्पादन बढ़ जायेगा । उदाहरणतया १९६०-६१ में ७ करोड़ रुपये के मुकाबले में १९६५-६६ में ३० करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भारी बिजली के साज-सामान का उत्पादन १९६५-६६ के २० करोड़ के अन्तर में ३८ करोड़ रुपये वार्षिक हो जाएगा ।

२२. सहायक उद्योग—जमशेदपुर (पहले के सक्की) के पड़ोस में स्थापित गौण उद्योगों के विकास पर भी दृष्टिपात कर लेना उचित होगा । प्रसार-योजना के अन्तर्गत उत्पादित वस्तुओं में कुछ निम्नलिखित हैं—स्टील ट्यूब, टिन प्लेट, कलई का सामान, तार, कील, रैन के डिब्बे, ढले हुए लोहे के स्लीपर, चाय और जूट मिल के यन्त्र, कृषि के औजार, धातु चढ़ी हुई वस्तुएँ, लोहे और इस्पात की ढली वस्तुएँ, भारी रसायन, गन्धकीय अम्ल, क्षारीय अम्ल, रासायनिक खादें, जूना, अमोनियम सलफेट इत्यादि ।

सरकारी क्षेत्र में स्थापित इन कारखानों के लागत-सम्बन्धी अनुमानों की काफ़ी आलोचना हुई है । सच तो यह है कि १९५५ के अन्त में सविदाओं को जल्दी में तैयार किया गया और इसलिए पार्लियामेण्ट में पेश होने से पहले लागत-सम्बन्धी अनुमानों पर विस्तार से विचार नहीं हो सका । दूसरे, इन योजनाओं-सम्बन्धी विस्तृत रिपोर्टें प्राप्त होने पर अनेक भूलों तथा अपेक्षित समायोजनों की ओर ध्यान आकर्षित हुआ । इस कारण भी अधिक व्यय हुआ । तीसरे, द्वितीय योजना प्रारम्भ होने के समय इस आकार की योजनाओं के कुशल संचालन के लिए आवश्यक और उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध ही नहीं थे । अन्त में, जिस गति से द्वितीय योजना के इन कार्यक्रमों को चालू किया गया, उससे विदेशी परामर्श और ठेकों की निर्भरता अत्यधिक बढ़ गई । तृतीय पंचवर्षीय योजना में हर प्रकार से भारतीय प्रसाधनों के प्रयोग पर ही जोर दिया जाएगा ।

२३. उद्योग की समस्याएँ—उद्योग को एक समस्या कच्चे माल के सम्बन्ध में है । यद्यपि हमारे यहाँ कच्चे लोहे के निक्षेप बहुत हैं (लगभग २,१०,००० लाख टन प्रथम श्रेणी का लोहा), किन्तु कोकिंग कोयला के निक्षेप का अनुमान लगभग २०,००० लाख टन ही है । यदि इस बात को ध्यान में रखा जाए कि एक टन स्टील बनाने में १.५ टन कोकिंग कोयला की आवश्यकता होती है तो दीर्घकाल को ध्यान में रखते हुए भविष्य आवश्यक ही अन्वेषणपूर्ण है । अल्पकाल में भी इस्पात उद्योग तथा अन्य

उत्पादको क लिए पर्याप्त कोकिंग वोल्टा मिलना कठिन है। टाटा ने कोयले के प्रशालन (घुलाई) के लिए दो प्रशालनालय स्थापित किये हैं। ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद में इस दिशा में खोज-कार्य हो रहा है और आशा है कि समस्या का हल सम्भव हो सकेगा। अन्य देशों में भी इस दिशा में प्रयत्न हो रहे हैं कि अभिघमन भट्टी की आवश्यकता ही न रहे और इस प्रकार समस्या का अन्त ही हो जाए।

इस समय सभी इस्पात के कारखानों के लिए चूना-पत्थर एक ही क्षेत्र सुन्दरगढ़ (उड़ीसा) से आता है केवल मिलाई को पास में स्थित नन्दिनी की पत्थर की खान से कोयला मिलता है। दुर्गापुर-स्थित इस्पात के कारखाने को बिहार के साहाबाद जिले से चूना-पत्थर मिल सकता है।

भारतीय इस्पात उद्योग अब नई विधियों का प्रयोग भी कर रहा है। रूरकेला में इस्पात बनाने की नई विधि L—D विधि (Process) का प्रयोग कर रहा है। यह विधि आस्ट्रिया में १९४६ में विकसित की गई और पहला वाणिज्यिक कारखाना १९५२ में शुरू हुआ। इस विधि की विशेषता यह है कि पूंजी की लागत और चालू व्यय में बचत होती है।

एक दूसरी नवीनता अभिघमन भट्टी में जाने से पहले खनिज कूटने और उसके सरुंजन की है जिसे अंग्रेजी में *ove-crushing and sintering* कहते हैं। इससे अभिघमन भट्टी का काम हलका हो जाता है और उसकी कुशलता बढ़ जाती है। टाटा के यहाँ इसका प्रयोग होता है तथा सरकारी क्षेत्र के तीनों कारखानों में भी इस विधि का प्रयोग होगा।

२४ चमड़ा सिझाने और चमड़े का उद्योग—भारत में चमड़ा और खाल बहुतायत में मिलती है। गाय की खाल, जो 'ईस्ट इण्डिया क्विंस' का नाम से ज्ञात है, बकरी का चमड़ा, भैंस की खाल और भेड़ का चमड़ा इत्यादि भारत के कृषि-उद्योग के उपोत्पादन माने जा सकते हैं। १९१४-१८ के युद्ध के पूर्व भारत में कच्ची खाल का निर्यात बहुत मात्रा में, विशेषकर जर्मनी और आस्ट्रेलिया को किया, जिनका मूल्य १९१३ में ७ १७ करोड़ रुपये था। उसी वर्ष ३ ४ करोड़ रुपये के मूल्य का कच्चा चर्म विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात किया गया। बाहरी देशों में इसकी बड़ी माँग थी और ऊँचे दाम दिये जा रहे थे।

कानपुर में जब सरकारी साज और जूतों का कारखाना (हारनेस एण्ड सैंडलरी फैक्ट्री) १८६० में खोला गया तभी से उत्पादन की दिशा में एक नया कदम उठाया गया। कुछ ही दिन बाद श्रीयुत एलन और कूपर ने आर्मी बूट एण्ड इविंगप-मेण्ट फैक्ट्री खोली और सरकार से उन्हें पर्याप्त आर्थिक सहायता मिली। आदमजी

2

१. खाल उप-कर नाच समिति का अनुमान से भारत के लिए इस सम्पूर्ण उद्योग का कुल मूल्य ४० या ५० करोड़ रुपये के लगभग है। इससे अनेक व्यक्तियों को रोजी मिलती है तथा भारत के दलित वर्गों को आर्थिक उन्नति का वह एक साधन है।—रिपोर्ट आब दि इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रिन्सिपलरी कमिटी, १९३०, पैरा ५५८।

पीरभार्ड ने बम्बई में स्पोन नामक स्थान पर वेस्टर्न इण्डिया कार्मो एण्ड इविवपमेण्ट फैक्ट्री स्थापित की। कुछ और फैक्ट्रियाँ विभिन्न केन्द्रों पर खोली गईं जहाँ तैयार माल के उत्पादन का प्रयास किया गया। यद्यपि यूरोप की सिंभावशालाओं (टेनरीड) और चमड़े का काम करने वाली फैक्ट्रियों में यन्त्रों का पर्याप्त उपयोग होता है परन्तु भारतीय सिंभावशालाओं में यह अभी हाल तक उपयोग में नहीं लाया गया। १९१४ के पहले सिंभावे हुए चर्म और खालों का निर्यात-व्यापार मुख्यतः दक्षिणी भारत में सीमिन था, जहाँ दालचीनी के प्रकार के वृक्ष (कंसिया आरिबुलाटा) की छाल, जो मद्रास में अवेरम और बम्बई में तरवार नाम में ज्ञात है, मिलती है। मद्रास में सिंभावशालाओं की संख्या सबसे अधिक है।^१

१९१७-१८ में ४.८६ करोड़ रुपये के मूल्य की ३,६१,६७४ हण्ड्रेडवेट सिंभाई हुई खालों का निर्यात हुआ, जबकि १९१३ में १.७५ करोड़ रुपयों की १,६४,७६३ हण्ड्रेडवेट खालें ही बाहर भेजी गई थी। ईस्ट इण्डिया किंग्म क निर्यात-व्यापार के प्रतिरिक्त, युद्ध-काल में भारतीय सिंभावशालाओं में चमड़े के सभी तरह के सैनिक सामान तथा बूटों के उत्पादन में वृद्धि की। इस भाँति सस्त्रास्त्र-परिपद् के निर्देशानुसार सरकार ने सिंभाव-उद्योग को बहुत प्रोत्साहन दिया। निर्मित बूटों और जूतों का वार्षिक उत्पादन युद्ध-समाप्ति पर युद्ध के पहले के वर्षों से बीस गुना अधिक था।

१९१४ के बाद बहुत तीव्र प्रगति हुई और भारतीय क्रोम चमड़े की खालों को ग्रेट ब्रिटेन में लाभदायक बाजार प्राप्त हुआ। भारत में क्रोम सिंभाव उद्योग के विकास के सम्बन्ध में बहुत-सी कठिनाइयों का अनुभव हुआ है, जैसे रासायनिक ज्ञान और महीनगी यान्त्रिक सामग्रियों की अपेक्षा रखने वाली उच्च प्राविधिक विद्याएँ। भारतीय गायों की खाल और बकरियों के चर्म की एक पर्याप्त मात्रा इस श्रेणी के कार्य के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है और उद्योग के आशाजनक विकास का अनुमान किया जाता है। भारतीय सिंभाव उद्योग की एक औद्योगिक जाँच १९३६ में औद्योगिक अनुसंधान ब्यूरो (इण्डस्ट्रियल रिसर्च ब्यूरो) ने की। इसका उद्देश्य सिंभाव की प्रविधि के स्तर में सुधार करना और इस भाँति अच्छी किस्म के तैयार चमड़े के निर्यात-व्यापार को विकसित करना था।

२५. सिंभाव उद्योग की संरक्षण—१९१६ में १८६४ के भारतीय प्रशुल्क-प्रधिनियम का संशोधन हुआ और खाल तथा चर्म पर १५ प्रतिशत का निर्यात-कर लगाया गया। जो खालें और चर्म साम्राज्य के अन्य भागों को भेजी जाती थी और वहीं सिंभाई जाती थी, उन पर १० प्रतिशत की छूट दी गई। कर संरक्षणार्थ लगाया गया था, परन्तु भारतीय प्रयोगशालाएँ देश की कुल पूंति का अल्पांश ही प्रयोग कर सकती थी। अतएव छूट का समर्थन इस आधार पर किया गया कि वह भारतीय खालों के सिंभाव को जर्मनी से हटाकर ब्रिटिश साम्राज्य की ओर ले जाएँगी और इस प्रकार साम्राज्य के सिंभाव के लिए सहायक सिद्ध होगा। किन्तु यह प्रयोग किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति

१. माथेसन, पूर्व उद्धृत, भाग २, अध्याय ५, पृष्ठ ६४-५।

में असफल रहा। भारत सरकार ने १९२३ में कर को ५ प्रतिशत कर दिया और १० प्रतिशत छूट को समाप्त कर दिया। ५ प्रतिशत कर को वित्त-आवश्यकताओं के लिए आवश्यक बतलाकर न्यायोचित ठहराया गया। कर-जाँच समिति (टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी) के बहुमत ने अर्थ-आयोग से सहमत होकर इसकी शीघ्र समाप्ति की राय दी, किन्तु उन चर्चों पर कर के पूर्ववत् रहने का भी मत दिया जिनकी विश्व-बाजार में अच्युत साख थी और जिन पर कर से कोई हानिकारक प्रभाव पड़ने का भय नहीं था।

द्वितीय विश्व-युद्ध के अन्तर्गत बढ़ती हुई माँग की पूर्ति के लिए उद्योग का और अधिक विस्तार हुआ। युद्ध के आँदरों की पूर्ति के लिए यन्त्रों और अधिक श्रम का प्रयोग हुआ। जनवरी, १९४२ में सरकार ने मगठिन सिभावशालाओं के सारे उत्पादन को ले लिया।

खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के इस उद्योग-सम्बन्धी विकास कार्यक्रम का लक्ष्य मरे हुए जानवरों के उपोत्पाद का पूर्ण उपयोग तथा बड़े पैमाने पर लोगों को काम देना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्योग की छोटी-छोटी इकाइयों की प्राविधिक क्षमता के स्तर को ऊपर उठाने का लक्ष्य भी सम्मिलित है। अतएव कार्यक्रम के अन्तर्गत सिभाव-केन्द्र, निर्माण-केन्द्र, प्रशिक्षण-केन्द्र आदि स्थापित करने की व्यवस्था है। आयोग की सहायता करने के लिए इस उद्योग और व्यापार के प्रतिनिधियों से निर्मित एक परामर्श समिति भी है। १९५३-५४ से १९५५-५६ तक विभिन्न विकास-कार्यक्रमों पर ३१.७८ लाख रु० व्यय किया गया। इस अवधि में १५५ चर्मापनयन (चमड़ा उतारना) केन्द्र, ५६ आदर्श सिभावशालाएँ तथा ४० अस्थिचूर्ण (bone-crushing) केन्द्र स्थापित किये गए। १७९ व्यक्तियों को चर्मापनयन की सुधरी विधि का प्रशिक्षण दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत विस्तार की अपेक्षा सुधार पर अधिक जोर दिया गया। खादी आयोग ने द्वितीय योजना के अन्तर्गत इस उद्योग के विकास के लिए जो योजना बनाई है उसमें ३,५०० चर्मापनयन केन्द्र और ३५० सिभाव-केन्द्रों की स्थापना तथा ३५,००० मोचियों (जूता बनाने वाले) को सहकारी समितियों के अन्तर्गत लाने की व्यवस्था की गई है। योजनावधि उत्पादन-केन्द्रों पर निर्मित विभिन्न सामानों के विक्रय के लिए ५० विपणन-केन्द्र सगठित करने का लक्ष्य भी है।

सन् १९५४ में जब उद्योग की स्थिति का पुनर्वीक्षण किया गया था तो यह पाया गया कि सगठित (बड़े पैमाने) क्षेत्र की सिभावशालाओं की ५० प्रतिशत क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा था। सरकार न उद्योग की सहायता के लिए उन कच्ची खालों और चमड़ों का निर्यात बन्द कर दिया जिनकी पूर्ति कम थी तथा स्टॉकिंग क्षेत्र से इनका आयात सुलभ कर दिया। चमड़े और चमड़े के सामान के आयात पर सख्त प्रतिबन्ध लगा दिये गए। इस उद्योग की समस्या कच्चे माल के सम्बन्ध में चमड़ा, खाल और wattle bark से सम्बन्धित है। जहाँ तक चमड़े और खाल का सम्बन्ध है, वे पाकिस्तान से मँगाई जाती हैं। wattle bark के लिए मद्रास की सरकार ने

२१,००० एकड़ भूमि में *wattle* के राफण के लिए कदम उठाए है। अनुमान किया जाता है कि १९६०-६१ तक सिन्हाये हुए चमड़े की माँग २३० लाख तथा सिन्हाव हुई खाल की माँग २६० लाख होगी।

२६ रासायनिक उद्योग—एक आधुनिक राज्य में रासायनिक उद्योगों का ऐसे प्रमाण पर विकास करने के लिए कि वे राज्य के आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाएँ—जैसा कि इंग्लैंड, जर्मनी और अमरीका में है—यह आवश्यक है कि कुछ आवश्यक पदार्थ बहुत सस्ती दरों पर उपलब्ध हों। ये आवश्यक पदार्थ क्रमानुसार भारी रसायन, विशेषकर गंधकीय (सल्फ्यूरिक) और उद्नीरिक (हाइड्रोक्लोरिक) अम्ल, चूना, कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट, क्षारीय (नाइट्रिक) अम्ल इत्यादि हैं। देशी साधनों से उत्पन्न अन्य रसायनों के निर्माण में इनका उपयोग होता है। विभिन्न प्राकृतिक उत्पादनों या ऐसे उत्पादनों से बने पदार्थों के परिक्षोषण में भी इनका उपयोग होता है। अतएव स्थिर और खनिज तेलों का शोधन में गंधकीय (सल्फ्यूरिक) अम्ल और क्षारों की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। अन्य दो आवश्यक पदार्थ (१) गरम करने, घात्विक क्रियाओं और शक्ति के लिए इंधन तथा (२) रासायनिक स्थिर यंत्र हैं।^१

इम्पीरियल कैमिकल इण्डस्ट्रीज तथा टाटा एन्ड सन्स के प्रबन्ध के अन्तर्गत सोडा ऐश, कास्टिक सोडा और वाद में इसी प्रकार के अन्य रसायनों के उत्पादन के लिए दो कम्पनियों की स्थापना एक नवीन आकर्षक विकास है।^१ १९४८-४९ में सरकार द्वारा भारी मात्रा में सोडा ऐश और कास्टिक सोडा के आयात की अनुमति के कारण गृह-उद्योग को गहरा धक्का लगा।

यदि विभिन्न खनिज पदार्थों को केवल उचित रूप से प्रयोग में लाया जाए तो भारत में भारी रसायन के लिए कच्चे माल की कमी नहीं है। शुल्फेय (सल्फाइड) की खान, क्षोरा (यव क्षार—साल्ट पीटर), फिट्करी, चूने का पत्थर, मँगनसियम इत्यादि के रूप में उसकी सम्पत्ति का पहल ही सकेत किया जा चुका है। गंधकीय अम्ल के निर्माण में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हो चुकी है जो सभी रासायनिक उद्योगों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण पदार्थ है, यहाँ तक कि इसके उत्पादन को किसी देश की सम्पत्ति आँकने की कसौटी कहाँ जाया है। १९३६-४५ के युद्ध के पहले उद्योग को गवित्तमान यूरोपीय सिडीकेटो के साथ तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन सबसे बड़े प्रतिद्वन्द्वी थे।^१

रसायन उद्योग के अन्य आवश्यक पदार्थ इंधन और यन्त्र हैं। इंधन-सम्बन्धी परिस्थिति की समीक्षा पहले ही की जा चुकी है और यह दिखाया जा चुका है कि भारत को कोयले की खानें किसी भी अंतिम अंशमान रूप में वितरित हैं। विद्युत्-घातित

१. इम्पीरियल कैमिकल इण्डस्ट्रीज, पृ० ५८।

२. रिन्ग ऑव दि ट्रेड ऑव इण्डिया, १९३८-३९, पृ० १०५।

३. देखिए, रिपोर्ट ऑव दि टैरिफ बोर्ड आन दि हैवी कैमिकल इण्डस्ट्री (१९२९), पैरा ७२।

धात्विक उद्योग और विद्युत्-चालित रासायनिक उद्योग के विकास के लिए सस्ती विद्युत्-शक्ति की पूर्ति के विषय में प्रयत्न करना आवश्यक है ।

२७. रसायन-उद्योग पर युद्ध का प्रभाव—द्वितीय महायुद्ध ने रसायन-उद्योग को एक नवीन प्रोत्साहन दिया और आयात, जो बहुत कम किये जा चुके हैं, को स्थानापन्न करने के प्रश्न को इसने पुनः प्रमुखता प्रदान की । रासायनिक एवं औपधीय पदार्थों के निर्माता, जो नवम्बर १९३९ में कलकत्ता में हुए एक सम्मेलन में मिल चुके थे, रासायनिक पदार्थों को नई विधियों से उत्पादित करने की सम्भावनाओं का पता लगा रहे हैं । भारत सरकार ने हाल ही में भारी रसायनों के उत्पादन के लिए सरकारी यन्त्र स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है । पहले आयात होने वाली बहुत अधिक सख्या में विभिन्न दवाइयाँ अब देश में तैयार हो रही हैं । भारतीय कच्चे (रूड) तेलों से उड्डयन स्पिरिट (एविएशन स्प्रिट) का निर्माण हो रहा है, जबकि बाइक्रोमाइट का उत्पादन भी भली-भाँति हो रहा है । गन्धकीय अम्ल और अमोनियम सल्फेट का उत्पादन १५ प्रतिशत बढ़ गया है, जबकि सरकार ने श्वेतन-क्षोद (ब्लीचिंग पाउडर) के निर्माण की दिशा में कदम उठाया है । वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् वनस्पति एवं सस्लिष्ट (सिथेटिक) रजक द्रव्यों के निर्माण की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है । अन्य उद्योगों की भाँति इस उद्योग के लिए भी एक विकास-परिषद् संगठित की गई है । यह परिषद् उद्योग के विकास के लिए प्रयत्नशील रहेगी ।

विकास-परिषद् की दूसरी बैठक जुलाई, १९६० में मद्रास में हुई । इस बैठक में परिषद् ने निम्न सिफारिशें की—

कच्ची तथा नमक लगी हुई खालों और चमड़े के आयात को मुक्त एवं सामान्य अनुज्ञापद्धति (Open General license) के अन्तर्गत रखा जाए । यू० एस० ए०, जापान और स्वीडन—इन देशों के प्रति निर्यात की वृद्धि के लिए सिभाई हुई भारतीय खालों और चमड़ों पर से आयात-कर हटवाने के लिए भारत सरकार प्रयत्न करे । Wattle Bark and Wattle extract से आयात-कर हटाने के लिए सरकार से पुनः अनुरोध किया जाए ।

विकास परिषद् ने इस सम्बन्ध में भी अपनी सहमति प्रकट की कि प्रमुख केन्द्रों पर कच्चे चमड़े और खालों के सग्रह के लिए (Cold Storage) शीत सग्रहागारों की व्यवस्था की जाए ।

तीसरी योजना-सम्बन्धी कार्यक्रम पर अगली बैठक में विचार करने का निर्णय किया गया ।

२८. भारी रसायन-उद्योग तथा दवाइयाँ—भारी रसायन-उद्योग आघारोद्योग है जिसकी सामग्रियाँ लगभग सभी उद्योगों में प्रयुक्त होती हैं । राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह अनिवार्य है तथा उद्योग और कृषि-सम्बन्धी रासायनिक अनुसन्धान का आधार है । सात वर्ष की अवधि के संरक्षण के उपरान्त इस्पात-उद्योग की भाँति इस उद्योग को भी पुनः जाँच होने वाली थी । सुपरफासफेट के निर्माण के लिए एक सहायता की स्वीकृति मिलने वाली थी । इसका उपयोग कृत्रिम खाद के रूप में होता है । भारत में वृहद्

प्रमाण रासायनिक उद्योग की स्थापना के उद्देश्य से सरकार ने रेलवे किराये में कमी होने की स्वीकृति प्रदान की ।^१ काफी विलम्ब के बाद भारी रसायन-उद्योग (संरक्षण) अधिनियम १९३१ ने प्रशुल्क-मण्डल की कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित किया । कर-मुक्त वस्तुओं की सूची से मैंगनेशियम क्लोराइड को हटाकर इस पर तथा कुछ अन्य भारी रसायनों पर विभिन्न दर से संरक्षण-कर लगा दिये गए । केवल मैंगनेशियम क्लोराइड, जिसका संरक्षण मार्च, १९३६ तक था, तथा आवश्यकता पड़ने पर इस पर कर बढ़ भी सकता था, के अलावा अन्य वस्तुओं पर लगाये गए कर ३१ मार्च, १९३३ तक के लिए थे । अधिनियम द्वारा लगाये गए अन्य कर ३१ मार्च, १९३३ को समाप्त हो गए ।

सन् १९५५ में भारी रसायन उद्योग की विकास-परिषद् (Development Council) की स्थापना की गई । सन् १९५७ में इसे पुनर्गठित किया गया और इसका नाम क्षारीय तथा सम्बन्धित उद्योगों की विकास परिषद् रख दिया गया । परिषद् का एक महत्त्वपूर्ण कार्य क्षमता के मानदण्ड (Norms of Efficiency) प्रस्तावित करना है । इस निमित्त एक उपसमिति की स्थापना की गई । इस समिति ने परिषद् के समक्ष क्षमता-सम्बन्धी विस्तृत सुझाव प्रस्तुत किये । विद्युदधिक (electrolytic), कास्टिक, सोडा एंश उद्योग के क्षमता-सम्बन्धी मानदण्डों को इस समिति ने पुनर्वीक्षित किया, विशेषतः नमक तथा शक्ति और वाष्प की खपत के दृष्टिकोण से ।

योजनाओं के लक्ष्यों के अनुसार उत्पादन ठीक रूप से होता रहा । १९६५-६६ में लक्ष्य और उत्पादन में कुछ अन्तर रहा ।

भारत सरकार ने दिल्ली तथा अलवाई (Keral) में २ D.D T. के कारखाने खोले हैं, जिनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए ११० करोड़ रुपये और खर्चा जाएगा । इसके अतिरिक्त पीपरी (पूना) में पेन्थिलीन तथा स्ट्रैपटोमाईसीन इत्यादि बनाने के कारखाने खोले हैं ।

देश में रसायनों के उत्पादन की वृद्धि के परिणामस्वरूप आशा की जाती है कि निम्न रसायनों का आयात १९६० तक बन्द हो जाएगा (१) पोटेशियम क्लोरेट, (२) हाइड्रोजन पॉरॉक्साइड, (३) कास्टिक सोडा, (४) कैल्शियम कार्बाइड और प्रेमिपिटेटिड कैल्शियम कार्बोनेट ।

२६. तेल पेरने का उद्योग—वाष्प या अन्य यान्त्रिक शक्ति से काम करने वाली मिलों की सहाय्य में, सासकर सरसों, अरण्डों और मूँगफली के तेल के विषय में, गत वर्षों में काफी वृद्धि हुई है । तेल और खली के स्वतः निर्माण के स्थान पर तिलहन का निर्यात अनुचित और अनाधिक है, क्योंकि इससे वह निर्माताओं के लाभ, पशुओं के भोजन तथा अच्छी खाद से वञ्चित रह जाता है । इसके अतिरिक्त वनस्पति तेलों के और भी अनेक महत्त्वपूर्ण उपयोग हैं और सम्यक् समाज के आर्थिक जीवन में उनका बड़ा महत्त्वपूर्ण

१. रिपोर्ट ऑव दि टैरिफ बोर्ड ऑन हैवी कैमिकल इण्डस्ट्री (१९०६), पृष्ठा ७४ ।

स्नान है। वनस्पति तेल और चरबी साबुन और ग्लिसरीन बनाने, भोजन पकाने तथा मशीनों में तेल लगाने (लुब्रीकेटिंग) के लिए आवश्यक है। १९१४-१८ के युद्ध के बाद में भारतीय मिल-उद्योग को बड़े पैमाने पर विकसित करने की सम्भावना पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। द्वितीय विश्व-युद्ध ने इसे नवीन प्रोत्साहन दिया और निर्यात में कमी आ जाने के कारण विकास की आवश्यकता अब और अधिक बढ़ गई है। १९६०-६१ तक औद्योगिक तथा विविध उद्देश्यों के लिए वनस्पति तेलों की कुल माँग २,७८,००० टन होगी, ऐसा अनुमान किया जाता है।

३०. कागज-निर्माण—१८८५ में दकन पेपर मिल कम्पनी बनाई गई और उसने १८८७ से पूना में काम चालू किया। उत्तरी भागों में वर्तमान काल की सबसे महत्वपूर्ण कागज मिल रानीगज में है। यह १९८९ में बनाई गई तथा बंगाल पेपर मिल कम्पनी द्वारा १८९१ में चालू की गई थी। पंजाब पेपर मिल्स कम्पनी को सहारनपुर में निकट अपनी मिल के लिए भादर घास के सम्बन्ध में बहुत झूट (रियायत) प्राप्त है। आसाम में एक नई कम्पनी की स्थापना की गई है और चिटगांव में बांस से लुगदी बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री खोली गई। १९३८-३९ में भारत में कुल ११ कागज की मिलें थीं—बम्बई में चार, बंगाल में चार, उत्तर प्रदेश में एक, मद्रास में एक और त्रावनकोर में एक। कागज के निर्माण के लिए तब से नई-नई कितनी ही संस्थाएँ प्रारम्भ हुईं। इनमें मैसूर पेपर मिल्स, जिसने भद्रावती में १९३९ से कार्य प्रारम्भ किया तथा निजाम के राज्य में सिरपुर पेपर मिल्स (१९४२) विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गत युद्ध से कागज-उद्योग को बहुत लाभ हुआ है जैसा कि उसकी उत्पादन की वृद्धि से प्रकट है—१९३८ में कागज का उत्पादन ४८,५३१ टन था जबकि १९४४ में बढ़कर १,०३,८८४ टन हो गया। कागज के मूल्य में भी ३०० प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई।

अभी हाल के वर्षों तक कागज बनाने वालों का मुख्य कच्चा माल सबाई घास थी, जो उत्तर भारत में बहुतायत से उत्पन्न होती है। कागज बनाने में भारतीय लकड़ी का उपयोग अभी नहीं हुआ है और लुगदी का आयात यूरोप से होता है। सस्ते कोटि के कागज के लिए जूट की रद्दी और रद्दी कागज प्रयोग में आते हैं। बांस की लुगदी से कागज बनाने वाली पहली कम्पनी इण्डियन पेपर पल्प कम्पनी थी। सबाई घास अन्य वनस्पतियों के साथ यत्र-तत्र गुच्छों में उगती है और इस पर प्रतिकूल मौसम का कुप्रभाव भी पड़ता है। बांस की प्रति एकड़ उपज घासों से अधिक है और उत्पाद की लागत कम है। वन-अनुसंधान केन्द्र (फारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट) द्वारा किये गए अनुसंधानों में फलस्वरूप बांस के कागज की लुगदी के उद्योग से बहुत आशाएँ हो गई हैं। उद्योग अभी तक कुछ असुविधाओं, जैसे रसायनों की ऊँची लागत, कोयला होने की ऊँची दर, और स्कैंडिनेविया, जर्मनी, इंग्लैंड, आस्ट्रिया, जापान और समुक्त राज्य अमेरिका से कठोर प्रतिस्पर्धा आदि से ग्रस्त रहा है। १९३९ में युद्ध प्रारम्भ होने के

वाद—अस्थायी रूप ही में सही—यह प्रतिस्पर्धा अधिकांशतः समाप्त हो गई ।

३१ कागज उद्योग को सरक्षण—१९२५ में बांसी कागज-उद्योग (बैम्बू पपर इण्डस्ट्री) (सरक्षण) अधिनियम पास किया गया जिसमें उद्योग को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के हेतु ३१ मार्च, १९३२ तक सात वर्षों के लिए एक आना प्रति पौण्ड का सरक्षण कर लगाने की व्यवस्था थी । प्रसुल्क-मण्डल के सुभाव के अनुरूप बांसी कागज उद्योग (सरक्षण) अधिनियम (१९३२) ने ३१ मार्च, १९३६ तक के लिए सरक्षण-कर का पुनः नवीकरण कर दिया । बांस की लुगदी के उत्पादन और उपयोग को निश्चित रूप से प्रोत्साहन देने के लिए इसी अधिनियम में आयात की हुई लुगदी पर ४५ रु० प्रति टन के हिसाब से एक नया सरक्षण-कर लगा दिया । ३१ मार्च, १९३६ के बाद भी कागज-उद्योग को सरक्षण देने का प्रश्न १९३७-३८ में प्रसुल्क-मण्डल की जांच का विषय था । भारत सरकार ने मण्डल द्वारा प्रस्तावित दर से नीची दर पर उद्योग के लिए सरक्षण जारी रखने का निश्चय किया^१ और अपन निर्णय को भारतीय प्रसुल्क (द्वितीय सशोधन) अधिनियम, १९३६ पास करके कार्यान्वित किया । सरक्षण तीन वर्षों के लिए दिया गया, किन्तु बाद में इसकी अवधि मार्च, १९४७ के लिए बढ़ा दी गई तथा इसी वर्ष सरक्षण-कर समाप्त कर दिया गया ।^२ कागज की लुगदी पर ३० रु० प्रति टन या मूल्यानुसार २५ प्रतिशत का कर (जो भी अधिक हो) लगाया गया । कागज पर सरक्षण-कर ११ पाई प्रति पौण्ड के स्थान पर ९ पाई प्रति पौण्ड निश्चित किया गया ।

१९३६ से आयात के कम हो जाने तथा जहाजरानी की कठिन परिस्थितियों के कारण बड़ी कठिनाई अनुभव की जान लगी । देश में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के कागज १९४४ के पेपर कण्ट्रोल आर्डर के अन्तर्गत (मित-पय) कर दिए गए और उत्पादन का बड़ा प्रतिशत सरकारी उपभोग के लिए निश्चित कर दिया जाने लगा । इससे नागरिक उपभोग के लिए कागज की कमी, विशेषकर विद्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण-संस्थाओं के लिए, गम्भीर कठिनाई बन गई । देश में कागज के उपभोग के सम्बन्ध में पेपर पैनल (१९४७) का अनुमान (१९५१ के लिए) २,२०,००० टन था । १९५६ में उपभोग की मात्रा ३,२०,००० टन अनुमानित की गई है । इस अनुमान में ग्लूजप्रिण्ट शामिल नहीं है । योजना-आयोग के अनुसार १९५५-५६ तक उपभोग की मात्रा २,००,००० टन हो जाएगी । ग्लूजप्रिण्ट के सम्बन्ध में उपभोग का अनुमान १९५५-५६ के लिए १,००,००० टन था ।

सन् १९५६ में लुगदी और कागज-उद्योग की योजना बनाने तथा विभिन्न प्राविधिक पहलुओं पर सरकार को परामर्श देने के लिए एक पैनल (Panel) गठित किया गया । इस निकाय ने चार उप-समितियाँ बनाईं, जो क्रमशः (१) कागज मिल

१. कागज और कागज की लुगदी के उद्योगों पर प्रसुल्क-मण्डल की रिपोर्ट (१९३८), पैरा ७१ देखिए ।

२. मार्च, १९४७ में आयात किये हुए कागज पर मूल्यानुसार ३० प्रतिशत कर लगता है ।

की मशीनरी के निर्माण की योजना बनाने, (२) प्राविधिक सामग्री और मॉकडो के एकत्र एवं आदान-प्रदान करने, (३) कागज की माँग का अनुमान लगाने तथा (४) देश में कच्चे माल के स्रोतों का अनुमान लगाने के लिए है। कच्चे माल की उप-समिति ने देश में बाँस की उपलब्धि का सर्वेक्षण किया है तथा नयी मिलों की स्थापना के उपयुक्त अधिकता वाले क्षेत्रों की ओर सचेत किया है। मशीनरी उप-समिति के कार्यों के परिणामस्वरूप ५-१० टन प्रतिदिन कागज मिलों की मशीनरी की तीन योजनाएँ तथा ५०-६० टन प्रतिदिन लुगदी और कागज मिल की मशीनरी की दो योजनाएँ स्वीकृत कर ली गई हैं।

१९५८ के २,५३,००० टन की तुलना में १९५९-६० में कागज और पट्टे का उत्पादन बढ़कर ३,००,००० टन हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। यह वृद्धि उद्योग की उत्पादन-क्षमता की वृद्धि का परिणाम है।

कागज बनाने के उद्योग ने १९५० के पश्चात् तेजी से प्रगति की है। कागज तथा पट्टे का उत्पादन १०९ लाख टन (१९५०) से बढ़कर ४८० लाख टन (१९६४) हो गया। अब तक देश के उत्पादन की क्षमता ६८ लाख टन है जबकि तीसरी योजना का लक्ष्य था ७ लाख टन। इस प्रकार अखबारों कागज (न्यूजप्रिंट) का उत्पादन नीपा (मध्य प्रदेश) के कारखाने में आरम्भ किया गया (जनवरी १९५५)। अब इसकी उत्पादन शक्ति ३० हजार टन से ७५ हजार टन तक बढ़ाने का सुभाव है। इसके अतिरिक्त दो और निजी क्षेत्र में कारखाने खोले जा रहे हैं। तीसरी योजना में न्यूजप्रिंट का लक्ष्य १५० लाख टन रखा गया था, जो कि करीब-करीब पूर्ण हुआ। चौथी पंच-वर्षीय योजना में कागज तथा पट्टे का लक्ष्य १३५० लाख टन है और न्यूजप्रिंट का १६५ लाख टन है।

३२ शीशा-निर्माण—प्राचीन उद्योग के कोई चिह्न अवशिष्ट नहीं हैं और अब निश्चित रूप से केवल इतना ही कहा जा सकता है कि सोलहवीं शताब्दी में यह एक भलीभाँति स्थापित उद्योग के रूप में विद्यमान था। किन्तु उस समय भी यह उद्योग चूड़ियों तथा कुछ सीमा तक छोटी बोतलों और प्लास्को के निर्माण में प्रयुक्त निम्न कोटि की सामग्री के उत्पादन से अधिक विकसित नहीं हो सका था। आज की भाँति उस समय भी देश में चूड़ियों की बड़ी माँग थी। १८९२-९३ से बीच आधुनिक प्रकार की शीशे की पाँच फैक्ट्रियाँ खोली गईं।

ऐसा प्रतीत होता है कि शीशा-उद्योग के प्रति भारतीय विशेष रूप से आकृष्ट है, क्योंकि विछली असफलताओं के बावजूद भी १९०६-१३ के स्वदेशी काल में भारतीय साहसोद्यमियों द्वारा छोटे पैमाने पर सोलह फैक्ट्रियाँ खोली गईं। किन्तु मग १९१४ में उनमें से केवल तीन ही चालू थी और कोई भी व्यापारिक लाभ नहीं उठा रही थी। यद्यपि पूना जिले में पयसा कोष की सहायता से तलगाव फैक्ट्री विचित्र और व्यापारिक ढंग से अपना काम चला रही थी।

उद्योग की वर्तमान अवस्था में उसे दो स्पष्ट भागों में विभाजित किया जा सकता है (१) देशी कुटीर-उद्योग (चूड़ी बनाने का) और (२) आधुनिक फैक्ट्री

उद्योग । यो नो देशी उद्योग सम्पूर्ण भारत में बिखरा हुआ है, किन्तु यह उत्तर प्रदेश के फ़िरोज़ाबाद और दक्षिण के बेलगाँव में विशेष रूप से केन्द्रित है । फ़िरोज़ाबाद में चूड़ी बनाने वालों की एक बड़ी वस्ती है और चूड़ी की लगभग ६० फैक्ट्रियाँ हैं । किन्तु जापान से आयात की हुई 'रेशमी' चूड़ियाँ देश में तैयार वस्तुओं की गम्भीर प्रतिद्वन्द्वी रही हैं ।

युद्धकाल (१९१४-१८) में अस्त्र-सस्त्र-मण्डल द्वारा स्वीकृत विनिष्ट प्रकार के शीशों की माँग के कारण मिले प्रोत्साहन के फलस्वरूप बहुत-सी फैक्ट्रियाँ शीशे की नलियों, प्लास्को, बीकरो, पेट्री लश्तरियों और टैस्ट-ट्यूबों के उत्पादन में सफल रही और इण्डियन मेडिकल सर्विस द्वारा नियन्त्रित वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की माँग की पूर्ति के लिए भी कुछ फैक्ट्रियाँ आरम्भ की गईं ।

१९३६-४५ के युद्ध के दौरान उद्योग ने परिमाण तथा उत्पादन की विविधता दोनों ही दिशाओं में पर्याप्त उन्नति की ।

३३ शीशे का आयात और उत्पादन— १९१४-१८ के युद्ध-काल में चूड़ियों और लेंस के सामानों का आयात कम हो गया और उनका स्थान आंशिक रूप से भारतीय सामान ने ले लिया । १९२६-३० में आयात का मूल्य २५२ लाख रुपये था और ये मुटपतया जापान, इंग्लिस्तान, जर्मनी, बेल्जियम और चेकोस्लोवाकिया से आते थे । इससे प्रकट है कि भारतीय उद्योग उस समय भी अपनी शैशवावस्था में ही था । आयात का मूल्य १९२६-३० के २५२ लाख रुपये से घटकर १९३१-३२ में १२२ लाख रुपये रह गया । १९३७-३८ में वह बढ़कर १५२ लाख रुपये हो गया, किन्तु १९३८-३९ में घटकर पुनः १०५ लाख रुपये रह गया । आयात-आपार में जापान का स्थान अब भी सर्वप्रथम था ।

उद्योग की स्थापित सामर्थ्य ३,६२,२८४ टन प्रतिवर्ष है । यह १९५८ की तुलना में ११.५ प्रतिशत अधिक है । १९५६-६० और १९६०-६१ में क्रमशः १८,४४५ टन प्रतिवर्ष तथा १५,४८० टन प्रतिवर्ष की क्षमता और बढ़ जायेगी । उद्योग के उत्पादन में अब विविधता आ रही है । नई वस्तुओं में रंगी हुई शीशे की चादरें, मोटरो और हवाईजहाजों के लिए शीशा (safety glass), शीशे की पिचकारियाँ आदि हैं ।

इस समय शीशे के कारखानों (रजिस्टर्ड) की संख्या १३१ है । इन कारखानों की वार्षिक क्षमता २,८६,००० टन प्रतिवर्ष है । इस क्षमता में ३५,००० टन चूड़ी-उद्योग का उत्पादन सम्मिलित नहीं है । इन १३१ कारखानों में १२ करोड़ रु० की पूँजी लगी हुई है तथा ३०,००० श्रमिक काम करते हैं और १६-१८ करोड़ रु० के मूल्य का वार्षिक उत्पादन होता है । १९५८ में १३१ कारखानों में से ८४ कारखाने चालू थे, २५ अस्थायी रूप में तथा २२ स्थायी रूप से बन्द थे । इनके प्रधान केन्द्र, बम्बई, जवल्पुर, इलाहाबाद, नैनी, बड़ोई, अम्बाला, कलकत्ता थे । उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और नैनी को कच्चे पदार्थ और ईंधन की पूर्ति की सन्निकटता के कारण बम्बई-जैसे अन्य केन्द्रों की तुलना में रही अधिक सुविधाएँ प्राप्त हैं ।

इस उद्योग के सम्बन्ध में श्रम-सम्बन्धी कठिनाइयाँ बहुत गम्भीर हैं। तेलगाँव में पयसा फण्ड प्लास वक्स ने शीशा धोवने वालों को प्रशिक्षित करने की दिशा में उपयोगी काम किया है और युद्ध की परिस्थितियों में उद्योग का प्रसार केवल उन व्यक्तियों की उपलब्धि के कारण हो सका जो तेलगाँव के थे, यद्यपि वहाँ के प्रशिक्षण में बहुत-सी वाञ्छनीय बातों का अभाव है। रेल-सम्बन्धी सुविधाएँ भी आवश्यक हैं।

३४. शीशा-उद्योग को संरक्षण—भारत सरकार का निर्णय, जो अत्यधिक विलम्ब से जून, १९३५ में घोषित हुआ, प्रशुल्क-मण्डल की खोज के विरुद्ध था। उन्होंने संरक्षण के तर्कों को इस आधार पर अस्वीकार किया कि देश में कच्चे माल (सोडा ऐश) की पूर्ति का अभाव एक ऐसी कठिनाई है जो उद्योग के अन्य लाभों से पूरी नहीं की जा सकती। उन्होंने अपने अन्तिम निर्णय को उस समय तक के लिए स्थगित कर दिया जब तक कि सोडा ऐश के नवीन साधनों की पूरी खोज न हो जाए। इस बीच उन्होंने तीन वर्षों की अवधि के लिए आयात किये हुए सोडा ऐश पर कर में छूट देकर कुछ सहायता देने का निर्णय किया। भारत सरकार के इस निर्णय ने शीशा उत्पादकों में बहुत निराशा उत्पन्न की और यह निर्णय सामान्य रूप से आलोचना का विषय रहा। प्रशुल्क-मण्डल का मत यह था कि भारत में सोडा ऐश के पर्याप्त साधन न होते हुए भी इस आधार पर शीशा-उद्योग का संरक्षण पाने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाना। प्रशुल्क-मण्डल के अनुसार शीशे की चादर के उत्पादन में पर्याप्त सुधार की गुंजाइश है।

सन् १९५० में शीशे की चादर (sheet glass) को संरक्षण प्रदान किया गया जो बाद में दिसम्बर, १९६० के लिए बढ़ा दिया गया। सन् १९५० में संरक्षण-कर मूल्यानुसार ४५ प्रतिशत निश्चित किया गया, किन्तु जनवरी, १९५५ में इसे बढ़ाकर ७० प्रतिशत कर दिया गया। वह दर दिसम्बर, १९६० तक लागू रहेगी। ३५ सीमेण्ट-उद्योग—भारत में १९१४ के पूर्व भी सीमेण्ट की बहुत अधिक खपत थी और प्रतिवर्ष लगभग १,८०,००० टन का आयात होता था। १९१८ के बाद सीमेण्ट की माँग तीव्रता से बढ़ गई और यह माँग प्रतिवर्ष १०,००,००० टन से भी अधिक हो गई। पुलों तथा भारी भवन-निर्माण के सभी भाँति के कार्यों में लौह-ककड़ी का प्रयोग शीघ्रता से बढ़ रहा है। यह भी कहा जाता है कि अब इस्पात-युग के बजाय सीमेण्ट और लौह-ककड़ी का जमाना आ रहा है।

उद्योग मुख्यतः सरकार के संरक्षण से ही विकसित हुआ जो १९१४-१८ के युद्ध में उत्पादन का बहुत बड़ा भाग खरीदती थी। दोनों युद्धों के बीच के अभिवृद्धि-काल में अनेक कम्पनियों का प्रवर्तन हुआ। तीन पुरानी कम्पनियों का उत्पादन दूना हो गया और सात नई कम्पनियाँ खोली गईं, जिनमें से छह कम्पनियों ने १९२३ तक कार्य करना आरम्भ कर दिया। १९३०-३१ में आयात और वन हुआ तथा १,१२,००० टन रह गया, जिसमें से इंगलिस्तान ने ६३,२०० टन की पूर्ति की।

१. प्रशुल्क-मण्डल (शीशा-उद्योग) की रिपोर्टें, पैरा ३६।

अन्य प्रधान साधन जापान, जर्मनी, इटली और बेल्जियम थे। १९३८-३९ में सीमेण्ट के आयात में और कमी हुई और १० लाख ६० के मूल्य के २१,००० टन सीमेण्ट का आयात हुआ। १९४०-४१ में ६ लाख रुपये का ४२०० टन आयात हुआ। इस सम्बन्ध में देश अब लगभग आत्मनिर्भर हो गया। १९३२-३३ में भारत में ५,६३,००० टन सीमेण्ट का उत्पादन हुआ जो १९३७-३८ में लगभग दूना हो गया। भारतीय सीमेण्ट ब्रिटिश सीमेण्ट से खराब नहीं और यूरोप के सस्ते सीमेण्ट से भली भाँति स्पर्धा करता है। भारत के एसोसिएटेड सीमेण्ट कम्पनीज अॉव इण्डिया लिमिटेड नामक एक प्रभावशाली संयोजन का निर्माण प्रगति की दिशा में एक बड़ा कदम था। दस प्रधान कम्पनियों के इस आश्चर्यजनक संयोग ने उद्योग के प्रौद्योगिक और वाणिज्यिक सगठन में सुधार ला दिया है।^१ जहाँ एक ओर १९३९-४५ के युद्ध ने उत्पादन-जागत बड़ा दी वहाँ दूसरी ओर निर्यात के लिए पर्याप्त माँग के द्वार भी खोल दिए। सीमेण्ट-उद्योग पर उत्पादकों के दो समूहों का प्रभुत्व है—असोसिएटेड कम्पनी और डालमिया, जिनके उत्पादन का योग कुल उत्पादन का ८५ प्रतिशत है। गन वर्षों में सीमेण्ट की माँग बहुत बढ़ गई है और उद्योग की उत्पादन-क्षमता बढ़ाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

इस समय देश में सीमेण्ट की ३२ फैक्ट्रियाँ हैं। १९५८ के अन्त में उद्योग की उत्पादन-क्षमता ७० ५ लाख टन थी तथा १९५९ के अन्त में ८३ ५ लाख टन थी। १९५८ और १९५९ में सीमेण्ट का उत्पादन क्रमशः ६० ६ लाख टन और ६८ २ लाख टन था।

मनु १९५८ में ४०,६०२ टन सीमेण्ट का निर्यात किया गया तथा १९५९ में १,७६,६०२ टन सीमेण्ट का निर्यात किया गया।

प्रशुल्क-मण्डल ने देखा कि उद्योग को कच्चे माल की सुविधाएँ प्राप्त थीं, किन्तु कोयले की खानों से दूर होने के कारण ईरन के सम्बन्ध में बड़ी कठिनाई थी। बाजार के विषय में मण्डल का कहना है कि काठियावाड़ की फैक्ट्रियों को छोड़कर भारतीय सीमेण्ट फैक्ट्रियों के लिए देश के अन्दर के बाजार स्वभावतः सुरक्षित बाजार हैं, क्योंकि वे किसी भी वन्दरगाह से ३०० मील से अधिक दूरी पर स्थित हैं। अन्यत्र भारतीय सीमेण्ट को विदेशी सीमेण्ट से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। किन्तु, भारत की सीमेण्ट का प्रधान बाजार सुदूरवर्ती आन्तरिक भाग में न होकर बम्बई और कलकत्ता के वन्दरगाहों के समीप है, अतएव भारतीय फैक्ट्रियों को वन्दरगाहों से दूर होने के कारण यहाँ असुविधा है।^२

१९०४ में मण्डल ने इस आधार पर सरकार को सूचित कर दिया कि उद्योग अति-उत्पादन में ग्रस्त था और मूल्य आयात के बजाय भारतीय उत्पादकों की

१. तब से एक इकाई (कच्ची सीमेण्ट कम्पनी) बन्द हो गई है, परन्तु दो नए कम्पनियों ने काम करना आरम्भ कर दिया है।

२. प्रशुल्क-मण्डल की (सीमेण्ट-उद्योग) १९५५ की रिपोर्ट देखिए, पैरा ८-१२।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धा से निश्चित होता था। किन्तु उनका विचार था कि शीघ्र ही स्थिरता आ जाएगी। सीमेण्ट की फैक्ट्रियों के कोयले के क्षेत्रों और बन्दरगाहों से अधिक दूर होने के कारण उत्पन्न हुई कठिनाई को दूर करने के लिए मण्डल ने एक विधान बनाने की सिफारिश की, जिससे सरकार बन्दरगाहों के निश्चित अर्द्धव्यास की परिधि के अन्दर भारतीय फैक्ट्रियों द्वारा भेजे जाने वाले सीमेण्ट को सहायता प्रदान कर सके।

डालमिया, भारत और रोहतास के लिए ५४.५० रु० प्रति टन, एस० सी० सी० के लिए ५८.०० प्रति टन तथा यू० पी० की चुर्क सीमेण्ट फैक्ट्री के लिए ५७.०० रु० प्रति टन तथा इसी प्रकार अन्य फैक्ट्रियों के लिए विभिन्न मूल्य निर्धारित किये। सरकार ने इन सिफारिशों को पहली जुलाई, १९५८ से लागू करने का निश्चय किया क्योंकि ३० जून, १९५८ तक सीमेण्ट कन्ट्रोल आर्डर के अन्तर्गत निश्चित मूल्य लागू थे। यह भी निश्चय किया गया कि ये मूल्य जून, १९६१ तक लागू रहेंगे। यद्यपि प्रत्येक उत्पादक को मिलने वाले मूल्यों में कुछ-न-कुछ वृद्धि हुई है किन्तु उपभोक्ताओं के रेल-केन्द्रों पर सीमेण्ट ११७.५० रु० प्रति टन के भाव से ही मिलता रहेगा। पिछले दो वर्षों से सीमेण्ट के सम्पूर्ण उत्पादन के विक्रय को राज्तीय व्यापार निगम ही सम्हाल रहा है तथा उपभोक्ताओं को उपर्युक्त एक ही मूल्य पर सीमेण्ट देना, निगम द्वारा अपने पारिथमिक को $\frac{2}{3}$ प्रतिशत से घटाकर $\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर देने के कारण ही सम्भव हुआ है।

सीमेण्ट का उत्पादन १९५०-५१ में २७ लाख टन से बढ़कर ६४ लाख टन (१९६३-६४) में हो गया। १९६५-६६ में १ करोड़ १० लाख टन उत्पादन हुआ जबकि तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य १ ३२ करोड़ टन था। १९७०-७१ तक उत्पादन ३ करोड़ टन तक बढ़ा देने का लक्ष्य है। भारत सरकार ने सीमेण्ट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के नाम को एक कम्पनी बनाई है जो सीमेण्ट के अनुसन्धान सर्वेक्षण तथा उत्पादन को बढ़ाने की चेष्टा करेगी।

३६ **दियासलाई-उद्योग**—१८९५ में स्थापित अहमदाबाद की गुजरात इस्लाम मंच फैक्ट्री को छोड़कर, १९२१ तक दियासलाईयों का निर्माण व्यावसायिक स्तर पर सफलतापूर्वक नहीं होता था। वित्त के उद्देश्य से १९२२ में एक रपया आठ आना प्रति आंस (आंस=बारह दर्जन) या मूल्यानुसार, १०० प्रतिशत से भी अधिक आयात-कर लगा देने से गत वर्षों में उद्योग का पर्याप्त विस्तार हुआ है। प्रतिवर्ष सात करोड़ आंस खपत के होने के कारण उद्योग को एक विशाल धरेलू बाजार प्राप्त है। श्रम सस्ता है और सरल यन्त्रों के संचालन में भली भाँति पटु है। आयात-कर लग जाने के कारण स्वीडन के विशाल संयोजन (कम्बाइन) द्वारा, जो सत्तार की ७० प्रतिशत भाँग का नियन्त्रण करता है, भारत में दियासलाई की फैक्ट्रियों की

१. कोयला और नमक-उद्योग का विवरण प्रथम खण्ड के दूसरे अध्याय में दिया गया है और चूनी तथा चाय-उद्योग उसी भाग के छठे अध्याय में दिये गए हैं।

स्थापना उद्योग का महत्त्वपूर्ण विकास है। इस विदेशी व्यापारिक सस्था का भारतीय उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पटने के कारण दियासलाई के भारतीय निर्माताओं ने इसका पर्याप्त विरोध किया। १९२८ में प्रशुल्क-मण्डल ने सरक्षण के सम्बन्ध में रिपोर्ट देते हुए कहा कि दियासलाई के मूल्य का नियमन आन्तरिक स्पर्धा द्वारा होता है तथा उपभोक्ता को वे यथासम्भव सस्ती मिल जाती हैं और इसलिए उद्योग बिना सहायता कही अन्य देशों की प्रतिस्पर्धा का सामना करने में समर्थ है। किन्तु उन्होंने सिफारिश की कि एक रुपया आठ आना प्रति ग्रॉस का चासू आयात-कर अनिश्चिन काल के लिए एक सरक्षण-कर में बदल दिया जाए, ताकि उद्योग को आश्वासन प्राप्त हो सके कि अब तक प्राप्त सुरक्षा से वह एकाएक ही वञ्चित नहीं कर दिया जाएगा। इनका मन था कि स्वीडिश मैच कम्पनी भारत में उद्योग के प्रकार के सम्बन्ध में उपयोगी काम करती रही है। परन्तु उन्होंने कम्पनी को रुपये की पूंजी और भारतीय संचालकों की नियुक्ति द्वारा भारत की राष्ट्रीय एवं राजनीतिक चेतना के अनुसूच पुनर्निर्माण करने की राय दी। उन्होंने कम्पनी की देख रेख करने की आवश्यकता भी स्वीकार की ताकि वह अपने बृहद् साधनों द्वारा एकाधिकार न स्थापित कर ले।^१

प्रशुल्क-मण्डल के सुभाव के अनुरूप विधान सभा ने दियासलाई उद्योग (सरक्षण) अधिनियम (बिल) सितम्बर, १९२८ में पास किया, जिसके अनुसार एक ग्राम डिब्बियों पर (जिनमें एक दियासलाई में १०० सलाइयाँ होती थी) १ रु० ८ आ० का कर निर्धारित किया गया।^२

इस समय भारत में दियासलाई के उत्पादन की इकाइयाँ २४२ के लगभग हैं। इनमें से वेस्टर्न इण्डिया मैच कम्पनी द्वारा प्रवन्धित पाँच इकाइयाँ यन्त्रीकृत हैं, २५ इकाइयाँ अज्ञान यन्त्रीकृत हैं। इस समय (१९५६-६०) उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत (regd) दियासलाई की ६१ फैक्ट्रियाँ हैं तथा इस वर्ष इनका उत्पादन ५० ग्रॉस डिब्बियों के ६३७ हजार बक्के होंगे। गत वर्ष ऐसा ६२६ हजार बक्को का उत्पादन हुआ। शेष कुटीर-उद्योग की इकाइयाँ हैं। रामनद जिले में सतुर, सिक्कासी तथा तिनेवेती जिले में कोविलपट्टी कुटीर-उत्पादन के प्रधान केन्द्र हैं। देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त उद्योग घोडा-सा निर्यात करने में भी समर्थ हो गया है।

दियासलाई-उद्योग एक कुटीर-उद्योग की तरह भगठित किया जा सकता है और इससे गाँववालों, विशेषकर महिलाओं को बड़ी सरलता से रोजी मिल सकती है।

१ मण्डल का मन था कि फैक्ट्रिया के बृहद् उत्पादन को दृष्टि में रखते हुए कुटीर-उद्योग आधार पर दियासलाई का उत्पादन विलुक्त असम्भव है। प्रशुल्क-मण्डल (दियासलाई-उद्योग) की रिपोर्ट (१९०८), पैरा १३१-२ देखिए।

२. १९३४ में दियासलाई पर उत्पादन-कर लगाने तथा आयात-कर के परिवर्तन का विवरण १२वें अध्याय में देखिए।

दियामलाई-उद्योग आकार और उत्पादन के अनुसार ए०, बी० और सी० वर्गों में विभाजित है। कुटीर-उद्योग के रूप में खादी और ग्राम उद्योग आयोग एक नये वर्ग—'डी' वर्ग की फैक्ट्रियों के विकास की ओर अग्रसर है। इस प्रकार की फैक्ट्रियों के उत्पादन की अधिकतम मात्रा २५ ग्रॉस डिब्बियाँ प्रतिदिन हैं तथा इनमें ४० व्यक्ति काम पर लगाये जा सकते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दियामलाई के कुटीर-उद्योग के विकास के लिए १००० 'डी' वर्ग की फैक्ट्रियाँ स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इनकी उत्पादन-क्षमता २६२.५ लाख ग्रॉस डिब्बियाँ है तथा लागत का अनुमान १.१ करोड़ रु० है।

कुटीर-उद्योग

३७. लघु प्रमाप उत्पादन के बने रहने के कारण—मुख्य आन्तरिक तथा बाह्य मितव्ययताओं के त्याग के बिना ही वाष्प के स्थान पर विद्युत् के बढ़ते हुए प्रयोग ने उत्पादन की इकाइयों को छोटा करने की प्रवृत्ति को जन्म दिया है। पुनः प्रत्येक उन्नतिशील समाज में बहुते-सी कलापूर्ण तथा विश्वास की सामग्रियाँ होती हैं जिनका प्रमाणीकृत उत्पादन नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त सम्पत्ता के भौतिक उपकरणों के अनेक सुधार छोटे-छोटे कारखानों की जन्म देते हैं और इस प्रकार लघु प्रमाप उद्योग चलते रहते हैं। अन्तिम नये उद्योग जब तक वे प्रयोग-रूप में होते हैं, पहले छोटे पैमानों पर ही आज़माए जाते हैं और सफल होने पर ही बड़े पैमाने पर सगठित किये जाते हैं।^१ इस भाँति पश्चिम के अत्युन्नत देशों में भी बृहद् प्रमाप उद्योगों के साथ-ही-साथ बहुत से लघु प्रमाप उद्योग भी फूलते-फलते हैं। जापान की आर्थिक व्यवस्था में लघु-प्रमाप और कुटीर-उद्योगों का महत्त्वपूर्ण योग सर्वविदित है।

३८. भारत में कुटीर-उद्योग और औद्योगीकरण—भारत में विशेषकर वर्तमान परिस्थितियों में, निरूढ़ भविष्य के औद्योगिक विस्तार की विशेषता से देश-भर में लघु प्रमाप उद्योगों की वृद्धि होगी। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत की औद्योगीकरण-सम्बन्धी प्रगति प्राचीन प्रणाली के सभी उद्योगों को यथास्थित रहने देगी और उनकी शक्ति में कमी न आएगी। नवीन उद्योगों के पालनों के पास सदब ही कुछ प्राचीन प्राणहीन उद्योग पड़े रहेंगे और यह अवश्य होगा कि वेगमान औद्योगीकरण आज भी विद्यमान कुछ दस्तकारियों के लिए हानिकर होगा। आर्थिक सन्नति ने किस भाँति देश के विभिन्न उद्योगों को प्रभावित किया है, इसका संक्षिप्त विवरण पहले ही दिया जा चुका है।^२ भारत की वर्तमान परिस्थितियों में केवल इसी उपाय से अधिकतम उत्पादन, पूर्ण रोजगार और सम्पत्ति के न्यायोचित वितरण के आदर्श की उपलब्धि हो सकती है। बृहद् प्रमाप उत्पादन के बिना अधिकतम उत्पादन सम्भव

१. श्री राधाकमल मुकर्जी, 'दि फाउण्डेशन्स ऑव इंडियन इकनॉमि-स', पृ० १६०।

२. खण्ड १, अध्याय ५, पैरा २१, २२, २५ तथा रिपोर्ट ऑन दि सर्वे ऑव कॉटेज इण्डस्ट्री, मद्रास प्रेसीडेंसी, १९२६ भी देखिए।

नहीं, किन्तु आधुनिक उद्योगों की प्रगति कितनी भी तीव्र क्यों न हो, सम्भवतः भारत की विशाल जनसंख्या को यह पूर्ण रोजगार नहीं दे सकती। अतएव छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। बड़े उद्योगों के विपरीत, जो धन को कुछ हाथों में ही केन्द्रित करते हैं, छोटे उद्योग धन के समान वितरण का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

भारत के कुटीर-उद्योग निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किये जा सकते हैं—

(१) हाथ की कतारों जैसे कुछ पुराने उद्योग लुप्तप्राय हो गए हैं, किन्तु जैसा हम पहले ही देख चुके हैं, कृषि के सहायक उद्योग के रूप में अब भी हाथ की कतारों व उद्योग के विकास की सम्भावना है। (२) कुछ अन्य उद्योग हैं जिनके उत्पादन यन्त्रोत्पादित वस्तुओं से स्पर्धा कर रहे हैं और इनकी दशा त्रिशकु-जैसी है। जो इन उद्योगों में लगे हुए हैं वे अपने पंतक पेशे को छोड़ने की अनिच्छा या फैक्ट्रियों में काम की कठोर दशाओं के कारण उन्हें नहीं छोड़ते। यह भी हो सकता है कि उनमें लगे रहने व लिए कारीगर अर्थ-प्रबन्धक सोदागर द्वारा वाध्य किये जाते हों, ताकि वह अनिश्चित काल तक उनका शोषण करता रहे और अपना धन प्राप्त कर ले।^१ (३) तीसरी श्रेणी उन कुटीर-उद्योगों की है जो आन्तरिक और निवारणीय त्रुटियों से मुक्त हैं तथा वर्तमान दशाओं में भी जीवित रहने योग्य हैं। उदाहरण के लिए, वे उद्योग जो खेती से सम्बन्ध रखते हैं और जिनमें सरल औजारों की आवश्यकता पड़ती है इसी प्रकार के हैं। उन्हें फैक्ट्री में उत्पादित वस्तुओं से डरने का कोई कारण नहीं है। ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ कारीगरों ने नवीन दशाओं के अनुरूप अपने को सफलतापूर्वक ढाल लिया है और उत्तम कोटि के कच्चे पदार्थ तथा अच्छे औजारों का प्रयोग सीधे लिया है। बुनकर मिल के सूत का रंगरेज कृत्रिम रंगों का, पीतल और ताँबे के कारीगर घातू की चादरों का तथा लुहार सुविधाजनक भागों में पतं किये हुए लोहे का उपयोग करने लगें हैं। प्रत्येक दशा में उत्पादन की लागत कम हो जान से कारीगरों को सुविधा हो गई है और उनका वाजार बहुत बड़ा गया है। निचले बंगाल में कुछ जिलों में बुनकर फ्लाइंग शटिल का उपयोग करने लग गए हैं और हाल ही में मद्रास के तटवर्ती जिलों में बड़ी अधिक संख्या में बुनकरों ने इसे अपनाया है। साथ ही अन्य स्थानों पर भी यह धीरे-धीरे प्रयोग में आ रहा है। दर्जी आवश्यक रूप से सिलाई की मशीनों का प्रयोग करते हैं और शहरों के कारीगर शीघ्र ही यूरोप या अमेरिका में बने औजारों को अपना लेते हैं।^२ फलस्वरूप गाँव के सामुदायिक सभठन में कारीगरों में से कुछ अब भी अपना प्राचीन रपात स्थान अक्षुण्ण बनाये हुए हैं तथा पहले ही

१. भाग १, अध्याय ८, पैरा १६ देखिए।

२. कुटीर-उद्योगों के आर्थिक और अन्य कठिनाइयों-सम्बन्धी विस्तृत विवरण के लिए बॉम्बे इकॉनॉमिक एण्ड इण्डस्ट्रियल सर्वे कमेटी की रिपोर्ट देखिए, पैरा १०६-४२।

३. औद्योगिक आयोग रिपोर्ट, पैरा २५५।

बतलायी गई विधि से अपना पारिश्रमिक प्राप्त करते हुए गाँव के लोगों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति प्राचीन काल की भाँति ही कर रहे हैं।^१ किन्तु गाँव की आत्मनिर्भरता पर अधिकाधिक आक्रमण होता जा रहा है और जब यह लुप्त हो जाएगी तो इन कारीगरों की दशा के प्रतिस्थापन की आवश्यकता होगी।

अब तक इस देश में आधुनिक उद्योग की प्रगति मन्द रही है। लगभग सभी शहरो या गाँवों की जनसंख्या का बड़ा शतांश विभिन्न कुटीर-उद्योगों में लग मजदूरों का है। उनकी संख्या अब भी सगठित उद्योगों में लगे मजदूरों से बहुत अधिक है।^२ सूती सूती (हस्तचालित) करघा-उद्योग—सामान्यतया करघा उद्योग के महत्त्व और व्यापकता पर ध्यान नहीं दिया जाता। सूती वस्त्र प्रशुल्क-मण्डल ने १९५२ में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में १९,८४ ९५० करघों की संख्या का अनुमान लगाया था, जबकि १९३१ की गणना के अनुसार सूत और रेशम कातने और बुनने के काम में लगे लोगों की संख्या २५,७५,००० थी।^३ यद्यपि पिराडें का यह कथन है कि 'उत्तमांशा अन्तरीप (केप ऑव गुड होप) से लेकर चीन तक स्त्री और पुरुष सिर से पाँव तक भारतीय करघों से उत्पन्न वस्त्र पहनते हैं,' अब सत्य नहीं है और उद्योग की वर्तमान दशा सन्तोषजनक होने से अत्यन्त दूर है, परन्तु फिर भी यदि इसको समुचित ढंग से सगठित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएँ तो इसके सम्मुख अब भी एक महान् भविष्य है। इस समय देश के विभिन्न भागों में २७५८ लाख हस्तचालित करघे रजिस्टर्ड हैं।

गरीब लोग, विशेषकर ग्रामीण, करघे के कपड़े को इस कारण पसन्द करते हैं कि ये मिल के बने हुए कपड़ों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और टिकाऊ होते हैं। अनेक विशिष्ट प्रकार के वस्त्रों का उत्पादन, जिनका उपयोग मन्दगामी भारतीय रिवाजों द्वारा अनुमोदित है, मिले नहीं कर सकती। यद्यपि उनकी कुल माँग बहुत अधिक है, किन्तु प्रत्येक प्रकार के लिए माँग इतनी कम है कि उनका पंक्ती में उत्पादन आर्थिक दृष्टिकोण से विचारणीय ही नहीं है। १९१४-१८ के युद्ध-काल में आयात किये गए कपड़ों के ह्रास को पूरा करने में भारतीय मिलों की असमर्थता तथा युद्ध-समाप्ति के बाद के मिल के बने कपड़ों के बहुत ऊँचे मूल्य ऐसे कारण थे जिन्होंने बुनकरों को बहुत मदद दी। १९२२ के बाद विदेशी (विशेषकर जापान से) और भारतीय मिलों की बड़ी हुई प्रतिस्पर्धा से बुनकरों को अधिक हानि हुई, यद्यपि अधिक कुशल और साहसी व्यक्तियों ने रेशम की बुनाई तथा गोटे की कढ़ाई का काम अपना

१. खण्ड १, अध्याय ५, पैरा १४ देखिए।

२. औद्योगिक आयोग रिपोर्ट, पैरा २५५ देखिए।

३. विभिन्न राज्यों में सूती करघा उद्योग की तत्कालीन दशा के उष्कृष्ट विवरण के लिए सैण्डल वैकिंग इन्व्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का पैरा २९९ देखिए। स्टेट पब्लिशर इन रिसीक ऑव इण्डस्ट्रीज, १९२८-३५, अध्याय ३ भी देखिए। बम्बई राज्य के हाल के सर्वेक्षण के लिए (१९४०) देखिए, बम्बई की आर्थिक और औद्योगिक सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट, पैरा ७०-३।

लिया । करघे के बुनाई-उद्योग ने अद्भुत जीवन-शक्ति और ग्रहणशीलता का प्रदर्शन किया है ।

अपन घरो में काम करने वाला बुनकर फँवट्टी के मजदूर से अधिक घण्टे काम करता है और उसे कोई पारिश्रमिक दिए बिना ही घर के कामकाज से फुरसत होने पर परिवार को स्त्रियों से सहायता मिल जाती है । १९४१ के आरम्भ में ही भारत सरकार ने हाथ के करघे की बुनाई के उद्योग को मदद देने के लिए आवश्यक उपायों को निश्चित करने के उद्देश्य से आँकड़ों के सङ्कलन हेतु एक तथ्य-निर्देशक समिति (फैब्रि-फाइण्डिंग कमेटी) (करघे और मिलो की) नियुक्त की । इस समिति की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि मध्यस्थों की एक शृङ्खला द्वारा लाभ के बड़े भ्रश को हथिया लेने के कारण उद्योग की उत्पादन-नागत ऊँची और बुनकर की आमदनी अनुचित रूप से कम है ।

महात्मा गांधी की प्रेरणा से अखिल भारतीय वर्तक सस्था (ऑल इण्डिया म्पिनर्स एसोसिएशन) ने करघा-उद्योग के उत्थान के लिए बहुमूल्य काम किया । इस सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकारों के कार्यों को आधिक सहायता देकर भारत सरकार ने भी १९३४ से सक्षिप प्रोत्साहन की नीति अपनायी ।

उद्योग की दशा को सुधारने के उद्देश्य से अखिल भारतीय (हस्तचालित) करघा परिषद् की हाल ही में स्थापना हुई है जिसमें बुनकरो, प्रान्तीय सरकारों तथा उद्योग में रुचि रखने वाले राज्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है । परिषद् के इस सुभाव को सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि उद्योग को सूत की पूर्ति का आश्वासन मिलना चाहिए और युद्धोत्तरकालीन विकास योजना के पहले पाँच वर्ष में लगाय गए त्रकुओं के उत्पादन में से आधा सुरक्षित रखकर इसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए । द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत कपड़े के उत्पादन में १७,००० लाख गज की वृद्धि होगी । वृद्धि को इस मात्रा में १०,००० लाख गज कपड़े के उत्पादन का उत्तरदायित्व हस्तचालित करघा-उद्योग पर है । इसमें से ७००० लाख गज कपड़ा मिल के सूत से तथा ३००० लाख गज अन्तर चरखा के सूत से बनाने की व्यवस्था है ।

अखिल भारतीय (हस्तचालित) करघा परिषद् के अध्यक्ष ने एक निर्यात-अभिवर्द्धन समिति की स्थापना की । इस समिति में १४ सदस्य हैं । १९५६ के पहले ३५ सड़ियों में १५११ करोड़ गज कपड़े का निर्यात किया गया जिसका मूल्य २५६ करोड़ ६० था, जबकि १९५६ में इतने समय में १६५६ लाख गज कपड़ा बाहर भेजा गया जिसका मूल्य २३७६ लाख रुपया था । निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सहकारी क्षेत्र के भीतर और बाहर के सभी निर्यातकों को बस्त्र-रसायन, सूती सूत, रजक पदार्थ (coal tar dyes) के आयात के लिए निम्न दर पर अनुज्ञा देने की व्यवस्था की गई है ।

(१) गजों में निर्यात किये जाने वाले कपड़े पर प्रति १०० गज पर दस रुपये ।

(२) बजन से निर्यात किये जाने वाले कपड़े पर प्रति २५ पाँड पर ७ ५० रुपये ।

इस योजना के अन्तर्गत कोलम्बो, अदन, सिंगापुर, बवालालाम्पुर तथा बंकाक में इम्पोरियम खोले गए हैं। १९५८-५९ में इस योजना के अन्तर्गत २४.४८ लाख रु० की बिक्री हुई। सूती खादी हाथ करधे को प्रोत्साहन मिला और खादी १९६२-६३ में ६.७ करोड़ रुपया थी। तीसरी योजना के अन्त तक खादी का कुल उत्पादन १०० से ११० मिलियन गज हो गया। चौथी योजना का लक्ष्य ५००० मिलियन गज सब प्रकार के खादी के कपड़े का लक्ष्य है।

४०. ऊनी उद्योग—किसी-न-किसी रूप में ऊनी वस्तुओं का उत्पादन देश के सब भागों में पाया जाता है, क्योंकि भेड़ हर स्थान पर पाया जाने वाला जानवर है। उनकी किस्म प्रत्येक स्थान पर भिन्न है। मैदानी भेड़ों की तुलना में पहाड़ी भेड़ों का ऊन सामान्यतया अच्छी किस्म का होता है। ऊनी करघा-उद्योग ४०,००० लोगों को आशिक समय के लिए काम देता है।

मुगल काल में ऊनी कालीनों का निर्माण उत्कृष्टता के उच्चतम शिखर पर पहुँच चुका था। कालीनों की माँग, विशेषकर शाही दरबारों और अमीरों के पहारों से होती थी। अतएव उद्योग के स्वाभाविक स्थान राजधानी के प्रमुख नगर थे, यद्यपि मुगल साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होने के बाद यह अन्य केन्द्रों में स्थापित हो गया। साम्राज्य के पतन ने व्यवहारतः कालीनों की स्थानीय माँग को समाप्त कर दिया, किन्तु ब्रिटिश शासन के स्थापित हो जाने के बाद इसका स्थान बाहरी माँग ने ले लिया। यद्यपि बाहरी माँग ने कारीगरों के आर्थिक विनाश को रोकने में मदद की, परन्तु वस्तुओं की उत्कृष्टता के ह्रास के लिए यही उत्तरदायी थी। इसने बाहर से भेजे गए नमूनों के आधार पर सस्ती वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। वर्तमान काल में भारत में कालीनों की बुनाई लगभग पूर्णतया विदेशी माँग पर निर्भर है, जिसमें पूर्ण उत्पादन के ९० प्रतिशत भाग की खपत होती है।

ब्रिटिश काल के पूर्व शॉलों के निर्माण में भारत ने, विशेषकर काश्मीर और पंजाब ने, बड़ी ख्याति प्राप्त की थी और मुगल विशेष रूप से इसका विकास में रुचि लेते थे। १८३० के अकाल से उद्योग को ऐसा गम्भीर धक्का पहुँचा जिससे यह पुनः पनप न सका तथा काश्मीर राज्य में लगाये गए अनेक करों से इसकी कठिनाइयाँ और बढ़ गईं। यूरोप से निर्यात व्यापार का विकास, जो उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में शुरू हुआ, उद्योग के पतन को रोकने में सहायक सिद्ध हुआ और अनुमान किया जाता है कि किसी समय इसमें १५,००० मजदूर काम करते थे। किन्तु १८७१ के फ्रांस-जर्मन युद्ध के कारण इसकी यूरोपीय माँग एकदम बरम हो गई। यह आकस्मिक रोक अस्थायी प्रकृति की भी नहीं थी, क्योंकि यूरोप में शॉल शीघ्र ही फैशन से बाहर हो गए और युद्ध के बाद भी व्यापार में पुनरुत्थान का अनुभव नहीं हुआ। इस परिणाम में योग देने वाला अन्य कारण स्कॉटलैण्ड में पैसले नामक स्थान पर शॉलों के निर्माण का आरम्भ था।

१९३९-४५ के युद्धकाल में सेना के लिए कम्बलों की विशाल माँग ने कारण ऊनी (हस्तचालित) करघा-उद्योग को बहुत लाभ हुआ, चूँकि इंग्लैंड द्वारा दिये गए

ग्राइंडरो को पूरा करने के लिए ऊनी मिलें अपनी पूर्ण क्षमता तक कार्य कर रही थी, अनएव (हस्तचालिन) करघे की वस्तुओं का स्थानीय बाजार बहुत बढ गया। युद्ध-काल की यह समृद्धि अल्पकालीन सिद्ध हुई, किन्तु उद्योग के लिए सहकारी उत्पादन और विगएन अब भी नवीन सगठन और क्रियाओं की आशा दिलाते हैं।

४१. कच्चा रेशम और रेशम का निर्माण—भारत में कच्चे रेशम के उत्पादन में जो भी सफलता मिली है वह देश के उन भागों—जैसे बंगाल, काश्मीर और मंसूर—तक ही सीमित है जहाँ शहतूत के पेड़ और श्रम प्रचुरता से उपलब्ध है।

मोटे तौर पर सत्रहवीं शताब्दी के प्रथम तीन-चतुर्थांश में ईस्ट इण्डिया कम्पनी प्रमुख रूप से कच्चे रेशम के व्यापार की ओर आकृष्ट थी। बाद में कम्पनी ने अनुभव किया कि भारत-निर्मित रेशमी वस्तुओं को इंग्लैण्ड भेजना अधिक लाभ सम्भव था। उन्होंने इस नीति को ऐसी सफलता से अपनाया कि इंग्लैण्ड के बुनकर भयभीत हो उठे। ब्रिटिश बुनकरों के विरोध तथा अन्य कारणों से ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने पुनः कच्चे रेशम के व्यापार की नीति अपना ली। कच्चे रेशम के उत्पादन को प्रथम देने और रेशमी उत्पादन को हतोत्साहित करने की नीति का देशी बुनाई-उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।^१

संक्षेप में, अभी हाल के वर्षों में कच्चे रेशम और रेशम की बुनाई के उद्योग ह्रासोन्मुख रह हैं। भारत के कच्चे माल का निर्यात केवल घट ही नहीं गया है वरन् उसका ह्रास भी बदल गया है। वर्तमान समय में अधिकतर रेशम का कोबा बाहर भेजा जाता है। भारत में रेशम लपेटने (रीलिंग) का काम इतनी बुरी तरह किया जाता है कि अन्य देश भारत से कोबे लेकर सूत लपेटने का काम स्वयं करना पसन्द करते हैं। भारत में आयात किये गए रेशम की बढ़ती लोकप्रियता का भी यही कारण है। भारतीय बुनकर स्वयं देशी माल की अपेक्षा जापान या चीन के एक-ममान लपेटे सूतों को अधिक पसन्द करते हैं। भारतीय रेशम की किस्म को उन्नत करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। बंगाल का कृषि-विभाग रेशम पैदा करने की शिक्षा देने के लिए दो विद्यालय चला रहा है। आसाम, काश्मीर और मंसूर के भारतीय राज्यों में भी रेशम-उत्पादन को प्रोत्साहन देने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। १९३५ में भारत सरकार ने राजकीय रेशम-उत्पादन समिति (इम्पीरियल सेरीकल्चरल कमेटी) की स्थापना की और उसकी सिफारिश के अनुसार ९३,००० रुपये की मदद विभिन्न प्रदेशों को प्रदान की गई, ताकि वे रेशम-उत्पादन के लाभ के लिए बंगाल, आसाम, मद्रास, बिहार और उड़ीसा तथा वर्मा में योजनाएँ कार्यान्वित करने में समर्थ हो सकें।^२ योजनाओं का लक्ष्य रोगमुक्त बीजों से उत्पादन बढ़ाना और रेशम के कीड़ों के रोग के विषय के प्रश्नों के अनुमन्वान में सहायता देना है। भारत सरकार ने १ अप्रैल, १९३५ से ३१

१. निर्यात व्यापार के आँकड़ों द्वारा रेशम-उद्योग का हास विलुल स्पष्ट हो जाता है। १८८६ में निर्यात हुए रेशमी-उत्पादन का मूल्य ३२,९६,००० रु० था, १९४१-४२ में केवल २,९६,००० रु०।
२. देखिए, 'इण्डिया इन १९३४-३५,' पृ० २५।

मार्च, १९४० तक पाँच वर्ष के लिए १००,००० रुपये की वार्षिक सहायता देना स्वीकार किया। गत वर्षों में कृत्रिम रेशम के सूत का आयात बढ़ता रहा। आयात व्यापार की सभी शाखाओं में जापान का प्रभुत्व था, किन्तु उन देश में कृत्रिम रेशम-उद्योग में अवसाद और चीन-जापान युद्ध के आरम्भ होने के बाद कच्चे माल की प्राप्ति की कठनाइयों के फलस्वरूप इटली ने १९४० में युद्ध में उतरने से पहले ही जापान को प्रथम स्थान से च्युत कर दिया।

१९४८ में केन्द्रीय रेशम परिषद् अधिनियम पास किया गया। इसके अन्तर्गत १९४९ में भारत सरकार ने केन्द्रीय रेशम परिषद् की स्थापना की। इस परिषद् पर भारत में रेशम-उद्योग को विकसित करने का उत्तरदायित्व है। उद्योग के विकास की सही नींव डालने के लिए परिषद् ने रेशम की दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण राज्यों में अनुसन्धान पर जोर दिया। विदेशों से विशेषज्ञ भी बुलाये गए। उदाहरणार्थ, १९५७-५८ में श्री शोहूइ कारासबा, जो एशिया की रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग समिति के प्रमुख मंत्री हैं, को आमन्त्रित किया गया। इन्होंने रेशम के कीड़ों को पालने के सम्बन्ध में प्रयोग किये।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत परिषद् के नार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने का है। द्वितीय योजना में रेशम-उत्पादन और रेशम उद्योग के लिए ६५ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई। बाद में राशि घटाकर ४४८ करोड़ रु० कर दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना की १३ करोड़ रु० की नगण्य राशि की तुलना में द्वितीय योजना के अन्तर्गत उद्योग पर काफी ध्यान दिया गया है। जनवरी से लेकर जून, १९५९ तक कच्चे रेशम का उत्पादन १२,७७,३२१ पौंड था, जबकि इसी अवधि में १९५८ में १२,७१,८७४ पौंड का उत्पादन हुआ था। राज्यीय व्यापार निगम ने अप्रैल से दिसम्बर १९५९ तक ५९,८३,१९१ रु० के मूल्य के ३,३२,८६० पौंड कच्चे रेशम का आयात किया। कते हुए रेशमी सूत का भी आयात किया गया और १५० लाख रु० की अनुज्ञाएँ (licences) प्रदान की गईं।

अप्रैल, १९४० में रेशम और रेशम से बनी वस्तुओं पर लगाये हुए सरक्षण-करों को दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। भारतीय रेशम-उद्योग के पांच वर्षों के संरक्षण और आयात-कर में सर्वत्र वृद्धि के लिए १९३८ के प्रशुल्क-मण्डल द्वारा की गई सिफारिशों को १९४२ में अपनाया गया और सरक्षण-कर पाँच वर्षों के लिए बढ़ाकर २५ प्रतिशत + १४ आना प्रति पौंड + कुल कर का $\frac{1}{2}$ कर दिये गए।

इस हाल में रेशम-उत्पादन उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क-आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट १९५२ में दी। १९५३-५४ में प्रशुल्क आयोग ने १ जनवरी १९५४ से पाँच वर्षों के लिए सरक्षण बढ़ा देने की सिफारिश की। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया, किन्तु करों की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में २३ लाख किलोग्राम मलबरी सिल्क तथा अन्-मलबरी सिल्क (Non-Mulberry) सिल्क का लक्ष्य था। सरकार ने मार्च १९६४ में राँची तथा लख्खा (मध्य प्रदेश) में टस्तर सिल्क सर्वेक्षण स्टेशन बनाये हैं।

४२. ग्रन्थ कुटीर-उद्योग—पहले भाग के पाँचवें अध्याय में विभिन्न कुटीर-उद्योगों की वर्तमान दशा का संकेत पहले ही किया जा चुका है (खण्ड १, अध्याय ५), जबकि तेल पेरने, चमटा सिझाने, शीशा बनाने और दियासलाई बनाने के उद्योग के विवरण में हमें इनकी कुटीर-शाखाओं पर विचार किया है। कृषि के गौण उद्योगों की दशा और उनके भविष्य पर भी कृषि-संगठन के अन्तर्गत (खण्ड १, अध्याय १) विचार हो चुका है। अन्य अनेक कुटीर-उद्योग भी हैं, उदाहरणार्थ कढ़ाई का काम, सड़की का सामान, घातु और छुरी कांटा, सोने और चांदी के तारों का उद्योग, बरतन, साबुन बनाना, टोपी बनाना, खिलौन और मूर्ति-निर्माण, गुटके बनाना आदि को लिया जा सकता है।

४३ कुटीर-उद्योगों की सहायता की विधियाँ—कारीगरों की अज्ञानता और निर्धनता के कारण यह आवश्यक है कि उनको मदद देने की एक सर्वाङ्गीण योजना बनाई और कार्यान्वित की जाए। इस दिशा में प्रकट रूप से पहला कदम अधिक अच्छी सामान्य शिक्षा देना है जिसके द्वारा कुछ दस्तकारी और औद्योगिक कारीगरी की शिक्षा देने का प्रयास किया जाए। बम्बई आर्थिक और औद्योगिक सर्वेक्षण समिति ने सिफारिश की कि प्रारम्भिक शिक्षा, विशेषकर गाँवों में दस्तकारी के माध्यम से दी जाए। इसके अतिरिक्त विशेष औद्योगिक स्कूलों में, विशेषकर उद्योग-संचालक द्वारा नियन्त्रित स्कूलों में, भी कारीगरों की शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक है। प्रौद्योगिक आयोग ने भी सिफारिश की थी कि अधिक तीव्र वृद्धि के कारीगरों के प्रशिक्षण के लिए सरकार की सहायता में प्रदर्शनार्थ हस्तचालित करघे के कारखाने खोल जाएँ और बुनाई के स्कूलों से एक वाणिज्य विभाग सम्बन्धित कर दिया जाए, ताकि इस भाँति प्रशिक्षित साहसी कारीगर स्वयं अपनी छोटी करघा-फँवट्टी खोल सकें। जेल और सुधारार्थक स्कूलों की विशेषता उनमें रहने वाले को काष्ठशिल्प, वेत और बाँग के काम—जैसी प्रौद्योगिक दस्तकारियों की शिक्षा देना है, ताकि छूटने पर श्रद्धी कारीगरों की तरह जीवन प्रारम्भ कर सकें। बिहार और उड़ीसा में प्रदर्शक उन्नत श्रोजारों का धूम-धूमकर प्रदर्शन करते हैं। ये प्रदर्शन कुटीर-उद्योग विद्यालय (कॉटेज इंडस्ट्रीज इस्टीट्यूट) पर निर्भर हैं जो अपने विभिन्न विभागों में प्रयोगात्मक कार्य चलाते रहते हैं और करघों, रग, अन्य सामान इत्यादि की पूर्ति का प्रयत्न करते हैं तथा बुनकरों को नये कपड़ों तथा नये नमूनों से परिचित कराते हैं। भागलपुर रेशम विद्यालय द्वारा ऐसी ही सेवाएँ रेशम-उद्योग के लिए की जाती हैं और पटना प्रदेश के दक्षिण में गया की प्रयोगात्मक कम्बल फँवट्टी प्राचीन कम्बल-उद्योग के लिए ऐसी ही प्रयत्न कर रही है। मध्य प्रदेश में उद्योग विभाग बुनकरों में अच्छे प्रकार की स्लेज के प्रयोग का प्रचार कर रहा है। प्रौद्योगिक प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिक परामर्श और सुविधाएँ प्रदान करने तथा कारीगरों को नवीन तर्ज और उन पर काम करने के लिए नमूने देकर उन्हें बहुत मदद दी जा सकती है तथा उनकी बिनी बटाई जा सकती है। बम्बई आर्थिक और औद्योगिक सर्वेक्षण समिति ने कुटीर-उद्योगों से सम्बन्धित समस्याओं के अध्ययन के लिए कुटीर-उद्योग उपासचालक व अर्धन एक राजकीय कुटीर-

उद्योग अनुसन्धान विद्यालय की स्थापना की सिफारिश की। यह विद्यालय केवल औजारों तथा उत्पादन की विद्यमान विधियों में सुधार का ही प्रयत्न नहीं करेगा, वरन् नवीन कुटीरोद्योगों के आरम्भ करने की सम्भावनाओं की भी खोज करेगा।

दस्तकारी में लगे मनुष्यों की आवश्यक पूँजी प्रदान करने के उद्देश्य से औद्योगिक आयोग ने सिफारिश की कि उद्योगों के सञ्चालक द्वारा कुछ दशकों में छोटे ऋण दिये जाने चाहिएँ या यत्र और औजार 'किराये पर खरीद की पद्धति' पर प्रदान करने चाहिएँ ताकि अन्त में वे कारीगर की सम्पत्ति हो जाएँ। जर्मनी के खिलौने के उद्योग और जापान के कुटीर-उद्योग अपनी सफलता के लिए उन व्यावसायिक सगठनों के अस्तित्व के ऋणी थे जो उनकी उत्पादित वस्तुओं को खरीदकर देश-विदेश में विक्रय करते थे। इस समय भारत में विदेशी बाजार तो उपेक्षित हैं ही, परन्तु घरेलू बाजार का भी भलीभाँति विकास नहीं किया जा रहा है। बम्बई के स्वदेशी-भण्डार 'देश में बनी वस्तुओं को देश के भीतर वितरित करने वाली सत्रिय और सफल एजेसी' के उत्तम तथा अनुकरणीय उदाहरण हैं। बम्बई के उद्योग विभाग न कुटीर-उद्योगों के उत्पादनों को लोकप्रिय बनाने व उद्देश्य से बम्बई में एक विक्रय-गोदाम (सेल्स डिपो) खोल रहा है। इसी लक्ष्य से बम्बई आर्थिक और औद्योगिक सर्वेक्षण समिति न सामयिक प्रदर्शनियों व प्रबन्ध तथा स्थायी सग्रहालयों व निर्माण की सिफारिश की थी।^१

१९३४ के छठे औद्योगिक सम्मेलन में कर्घे से बनायी हुई वस्तुओं के विक्रय व प्रश्न पर विचार किया गया और उसका बाद मद्रास, बम्बई, मध्य प्रान्त और बरार, बिहार और उड़ीसा आदि की प्रान्तीय सरकारों ने सहकारी प्रयत्नों के आधार पर अनेक आशाप्रद योजनाएँ अपनायीं। बम्बई में मुख्य-मुख्य केन्द्रों पर आठ जिला सहकारी सस्थाएँ बनायी गई हैं। प्रत्येक सस्था की अपनी दुकान है जो सामान भेजने के लिए कुछ अग्रिम लती है और करघा-बुनकरों की बनायी हुई वस्तुएँ कमीशन के आधार पर बचती है। एक विक्रय-अधिकारी और एक बरन-डिजाइनर की भी नियुक्ति की गई है।^२ बम्बई की आर्थिक और औद्योगिक सर्वेक्षण समिति ने भी सिफारिश की थी कि प्रत्येक जिले में एक स्थानीय परामर्शदात्री समिति की सहायता से जिला उद्योग-अधिकारी व आधीन एक जिला औद्योगिक सस्था होनी चाहिए।^३

४४ कुटीर-उद्योगों की राजकीय सहायता के हाल के उपाय—भारत सरकार कुछ वर्षों से कुटीर-उद्योगों, विशेषकर सूती (हस्तचालित) करघा-उद्योग रेशम पैदा करने के उद्योग के उत्पादन में मनीयोग से लगी हुई है। जुलाई, १९३४ में हुए छठे अन्तर्प्रान्तीय उद्योग सम्मेलन ने देश के प्रधान कुटीर उद्योग—करघा-उद्योग—के

१. रिपोर्ट, पैरा २०८।

२. विभिन्न विक्रय-आयोजनाओं के सम्बन्ध में अन्य विवरण के लिए देखिए, 'स्टेट एक्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज' १९२८-३५, पृ० २६-२७; और बम्बई आर्थिक और औद्योगिक सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट, पैरा १५६।

३. रिपोर्ट, पैरा २०६ और २१२।

विकास के लिए विभिन्न प्रान्तीय सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं पर विचार किया। सरकार ने सम्मेलन में हस्तचालित करघा-उद्योग के विकास के लिए पाँच वर्ष तक ५ लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च करने की घोषणा की।^१ इस भाँति विभिन्न प्रान्तों में चालू की गई योजनाएँ विभिन्न प्रकार की हैं। इन योजनाओं में उन्नत उत्पादन-विधियों में बुनकरों का प्रशिक्षण, हाथ के करघे की वस्तुओं को बेचन के लिए विक्रय-गोदाम और बुनकरों की सहकारी समितियों की स्थापना, तथा नवीन तर्जों, नय नमूनों और उन्नत योजारों का प्रचलन भी शामिल है। प्रान्तों को अनुदान उनके व्यय और सूत की खपत के आधार पर दिया जाता है। सातवें उद्योग सम्मेलन ने भी करघे के यन्त्रों तथा वस्त्रों के प्रदर्शन के पक्ष में निश्चय किया है।^२ हम रेशम उत्पन्न करने के उद्योग को संरक्षण और प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाये गए उपायों की समीक्षा कर चुके हैं।

१९३७ में स्थापित कांग्रेसी मन्निमण्डलों के अन्तर्गत प्रान्तीय सरकारों ने कुटीर-उद्योगों को पुनरुज्जीवित करने की ओर विशेष ध्यान दिया। इण्डियन नेशनल कांग्रेस के तत्वावधान में १९३५ में स्थापित अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघ (ग्रॉल इण्डिया विलेज इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन) ने भी देश की आर्थिक योजना में कुटीर-उद्योग के महत्त्व की ओर ध्यान आकृष्ट किया। कुटीर और लघु प्रमाण उद्योगों को प्रभाव-पूर्ण ढंग से विकसित करने के लिए १९४८ में अखिल भारतीय कुटीर-उद्योग परिषद् की स्थापना की गई। बाद में इसके स्थान पर अखिल भारतीय दस्तकारी परिषद् (१९५२ में) तथा अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग परिषद् (१९५३ में) की स्थापना की गई। १९५७ में एक अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने 'खादी ग्रामोद्योग आयोग' की स्थापना की। पहले की इन नाम की परिषद् पुन गठित कर आयोग के लिए परामर्श-निकाय के रूप में परिवर्तित कर दी गई। मुख्यतः हस्तचालित करघा-उद्योग की समस्याओं को हल करने के लिए अखिल भारतीय (हस्तचालित) करघा-परिषद् की स्थापना भी १९५२ में की गई।

नवम्बर १९५३ में आय फाउण्डेशन आयोजन दल ने छोटे पैमाने के उद्योगों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्टें मार्च, १९५४ में प्रस्तुत की। सरकार ने निम्न सिफारिशों को यथाशीघ्र कार्यान्वित करने का निश्चय किया।

(१) चार प्रादेशिक प्राविधिक संस्थाएँ (रीजनल टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टीट्यूट्स) की स्थापना,

(२) विपणन-निगम (मार्केटिंग सर्विस कॉरपोरेशन) की स्थापना, तथा

(३) लघु-प्रमाण उद्योग निगम की स्थापना।

फोर्ड फाउण्डेशन दल की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज बोर्ड, ऑफिस ऑफ दी डेवलपमेण्ट कमिश्नर फॉर स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज, नेशनल स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन आदि की स्थापना की, ताकि मध्यम-प्रमाण

१. स्टेट पब्लिशर इन रिपब्लिक ऑफ इण्डिया, १९२०-३५, पृष्ठ २०।

२. अक्टूबर १९३५ में दिल्ली में हुए उद्योग सम्मेलन के सातवें अधिवेशन की कार्यवाही।

उद्योग द्वारा औद्योगीकरण की योजना कार्यान्वित की जा सके। उद्योग के प्रकार-आकार, विपणन आदि के सम्बन्ध में सरकार ने डॉ० यूजीन स्टेली को एक परामर्श-दाता के रूप में आमन्त्रित किया। विपणन-निगम की स्थापना तथा अन्य सम्बन्धित समस्याओं के लिए न्यूयार्क यूनीवर्सिटी के प्रोफेसर लिंकन क्लार्क को भी आमन्त्रित किया गया था।

११ जून, १९५५ को सरकार ने लघु प्रमाण उद्योगों को 'प्रसार सेवा' प्रदान करने के लिए चार प्रादेशिक संस्थाओं की स्थापना के निर्णय की घोषणा की। ये संस्थाएँ कलकत्ता, बम्बई, फरीदाबाद और मडुराई में स्थापित की जाएँगी। प्रत्येक संस्था में ३० से अधिक अधिकारी होंगे, जो अधिकतर प्राविधिक विशेषज्ञ होंगे। प्रत्येक संस्था सादी मशीनों और अच्छे औजारों का प्रयोग दिखाने के लिए आदर्श कार्यशाखाएँ स्थापित करेगी तथा उनका प्रचार करेगी।

उदाहरणार्थ, केन्द्रीय सरकार यन्त्र-सम्बन्धी व्यय का ७५% तथा भूमि और जमीन-सम्बन्धी व्यय का ५०% अनुदान के रूप में देती है, यदि आदर्श कार्यशालाओं आदि के लिए राज्य सरकार इनकी सिफारिश कर दे।

पचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कुटीर-उद्योगों को औद्योगिक सहकारी समितियों के संगठन द्वारा विकसित करने की नीति अपनायी गई है। जैसे कुटीर-उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग में प्रतिस्पर्धा हो, वहाँ एक सामान्य उत्पादन योजना (common production programme) अपनाने की सिफारिश की गई है।

पहली और दूसरी पचवर्षीय योजना में २१८ करोड़ रुपया ग्राम तथा कुटीर-उद्योगों पर व्यय किया गया। तीसरी पचवर्षीय योजना में २६४ करोड़ रुपया इसके लिए निर्धारित किया गया। इस प्रकार कुटीर-उद्योगों का अनुदान राष्ट्रीय आय में १९५०-५१ में ६१० करोड़ से बढ़कर १९६२-६३ में १२१० करोड़ रुपया हो गया।

चौथी पचवर्षीय योजना में मूल आधार इन कुटीर-उद्योगों के लिए इस प्रकार है कि प्रत्येक थर्मिक (Artisan) को उत्पादन के बढ़ाने में उसका हाथ हो तथा स्वामित्व में उनका स्थान बढ़े। इस विकेन्द्रीकरण की नीति को बढ़ाने के लिए १० सुझावों की एक आर्थिक नीति बनाई गई है। चौथी पचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में ४५० करोड़ रुपया तथा ४०० करोड़ रुपया निजी क्षेत्र में खर्चा जाएगा।

४४ योजना एव औद्योगिक उन्नति—पहली दोनों पचवर्षीय योजनाओं में, विशेष रूप से दूसरी योजना में उद्योगों की भिन्न-भिन्न शाखाओं में बहुत उन्नति हुई। तीन नये लोहे तथा इस्पात के कारखाने सरकारी क्षेत्र में खोले गए तथा निजी क्षेत्र के कारखानों की उत्पत्ति का दुगुना कर दिया गया। इसके अतिरिक्त बिजली, भारी मशीनों, इंजीनियरिंग तथा सीमेंट बनाने की मशीनों का राष्ट्र में पहली बार उत्पादन आरम्भ हुआ। रासायनिक तथा उसकी शाखाओं में बहुत उन्नति हुई। यूरिया, अमोनियम फास्फेट, पेंसिलीन का उत्पादन शुरू हुआ। साइकिल, कपड़े सीने की मशीनें तथा टेलीफोन इत्यादि उद्योगों का उत्पादन तेजी से बढ़ा। इन दस वर्षों में

मगठिन औद्योगिक उत्पादन दुगुना हो गया (औद्योगिक सूचांक १०० जो कि १९५१ में या १९६१ में १९४ हो गया) यह ठीक है कि कुछ क्षेत्रों में कमियाँ भी रह गईं (लोहे और इस्पात में, रासायनिक खाद उद्योग, भारी मशीनों के कारखानों में)। दूसरी पंचवर्षीय योजना से यह सुभाव मिलना है कि विशेष रूप से प्रारम्भिक तथा आधार-मन्त्रन्त्री उद्योगों पर जोर दिया जाए तथा तकनीकी क्षमता इस प्रकार बढ़े कि आने वाली योजनाओं में आर्थिक व्यवस्था आत्मनिर्भर हो जाए। इस प्रकार तीसरी योजना में ये प्रधानताएँ रखी गईं—

(१) जो कार्य दूसरी योजना में कार्यान्वित नहीं हुए उन्हें पूर्ण रूप से किया जाए।

(२) मशीनों, तकनीकी, रासायनिक खाद के उद्योगों को बढ़ा दिया जाए तथा विरोध स्थान दिया जाए (*Diversify*)।

(३) औद्योगिक उन्नति के लिए बच्चे माल तथा मध्यम किस्म की सामग्री तथा खनिज तेलों की उत्पादन-शक्ति बढ़ाई जाए।

(४) उन उद्योगों को अच्छा स्थान दिया जाए जो प्रतिदिन प्रयोग होने वाली वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे कि दवाइयाँ, कपडा, तेल, कागज तथा चीनी आदि।

इस प्रकार तीसरी पंचवर्षीय योजना में खनिज तथा उद्योगों की उन्नति के लिए २,९९३ करोड़ रुपया निर्धारित हुआ। यह आशा की गई कि वार्षिक औद्योगिक प्रगति ११ प्रतिशत बढ़ेगी। तीसरी योजना के मध्य मूल्यांक (*Mid Term Appraisal*) से यह पता चला है कि निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं हो सके।

चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रगति का कार्य एक प्रधानता के रूप में सुचारु रूप से हो। जो उद्योगों की वर्तमान स्थायी शक्ति है उसका ठीक प्रकार से प्रयोग हो। निजी क्षेत्र में विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं तथा मध्यम वर्ग की वस्तुओं के उत्पादन पर जोर दिया जाए। चौथी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उन्नति पर ५,६०० करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा जिसमें से निजी क्षेत्र में २,४०० करोड़ रुपया होगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि प्रोजेक्ट्स को ठीक प्रकार से चलाया जाए और समयानुसार पूर्ण कर लिये जाएँ। और जो त्रुटि डिजाइन बनाने तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में है, उसे दूर किया जाए जिससे राष्ट्र आत्म-निर्भर हो सके।



औद्योगिक श्रम

१. श्रम सम्बन्धी बढ़ती हुई समस्याएँ—हमारे औद्योगीकरण की गति धीमी होने के कारण यद्यपि यहाँ श्रम-समस्या यूरोपीय देशों के समान कठिन नहीं है, परन्तु उनके जैसी होने में अब देर भी नहीं है। १९१४-१८ के महायुद्ध के साथ आए नव-जागरण ने श्रमिक-वर्ग को उनके महत्त्व तथा अधिकारों के प्रति अधिक सजग बना दिया है। लीग ऑफ नेशन्स भी स्वीकार कर चुकी है कि भारतवर्ष सप्ताह के आठ प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों में एक है। अब सरकार और जनता दोनों ही राष्ट्रहित में, कुशल और सन्तुष्ट श्रम के महत्त्व को अनुभव करने लगी हैं। मई, १९२६ में माननीय जे० एच० विल्डले की अध्यक्षता में 'राजकीय श्रम-आयोग' (रॉयल कमिशन ऑन लेबर) की नियुक्ति इस बात की पुष्टि थी। आयोग की सिफारिशों सरकार की श्रमनीति का आधार मानी जा चुकी है और हाल के श्रम-सम्बन्धी कानूनों को उन्होंने काफी प्रभावित किया है। बम्बई सरकार का यह कार्यक्रम अखिल भारतीय श्रमनीति के आधार-रूप में स्वीकृत हो चुका है। कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने श्रम-सम्बन्धी कानूनों के क्षेत्र में बहुत ही क्रियाशीलता दिखाई है। नवम्बर, १९३६ में उनके पद-त्याग के बाद इस दिशा में क्षिणिलता आना अवश्यम्भावी था। पर इधर द्वितीय महायुद्ध ने श्रम-समस्या को पुनः प्रमुखता प्रदान की, क्योंकि श्रमिक-वर्ग ने इस बार प्रथम महायुद्ध की अपेक्षा अधिक मुचासुरूप में संगठित होकर मँहगाई तथा अन्य रियायतों की सफल मांग की है।

२. औद्योगिक श्रम की पूर्ति और उसका देशान्तर-गमनीय स्वभाव—कारखानों के क्षेत्र का लालन-पालन पश्चिमी देशों के श्रमिकों की श्रेष्ठता के लिए बहुत-कुछ उत्तरदायी है, पर इस देश के कारखानों का श्रमिक तो प्रायः प्रवासी होता है और शायद ही कभी गाँव से सम्बन्ध-विच्छेद करता हो। पर यह भी कहना ठीक नहीं कि भारतीय कारखानों का प्रतिनिधि श्रमिक असल में खेतिहर है जो अस्थायी रूप से कृषि-कार्य छोड़कर अपनी आय बढ़ाने के लिए शहर में आता है। अधिकांश मजदूरों का शीघ्र ही गाँव को लौटना तथा एक कारखाने में अधिक दिन न टिकना अवश्य ही इस बात का द्योतक है कि वे कृषि कार्य अल्पकाल के लिए ही छोड़ते हैं। खेती से अधिक

१. १९३१ में प्रकाशित विल्डले-आयोग के प्रतिवेदन का निर्देश इस परिच्छेद में 'श्र० आ० प्र०' के द्वारा तथा उसके पृष्ठों का निर्देश अत्रों द्वारा किया गया है। इस प्रकार 'श्र० आ० प्र० ४' का अर्थ श्रम आयोग प्रतिवेदन पृष्ठ ४ है।

लाम प्राप्त करने वाले श्रमिकों की सख्या का प्रायः जो अनुमान किया जाता है वास्तव में वह उतनी नहीं है। बहुतेको का कृषि में प्रायः अप्रत्यक्ष सम्बन्ध ही होता है, उदाहरणार्थ, वे या तो किसी मयुक्त कृषक-परिवार के सदस्य होते हैं या उनका कोई घनिष्ठ सम्बन्धी कृषि-कार्य करता है। अधिकांश श्रीशौचिक श्रमिक गाँवों में ही पैदा होते हैं तथा उनका पालन-पोषण भी वहीं होता है। अब तो कारखानों में काम करने वाले बच्चों की उम्र की निम्नतम सीमा बढ जान से यह प्रवृत्ति और भी बढ रही है। बहुत-से श्रमिक अपना परिवार गाँवों में ही रखते हैं। नहर में अपने पति के साथ आने वाली पत्नी भी प्रसव के समय प्रायः गाँव ही चली जाती है। हमारे उद्योगों के विकास के साथ ही गाव में आने वाले मजदूरों की सख्या तेजी से बढती ही जा रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से उपयुक्त होने पर ही वे गाव जाते हैं।

श्रमिकों के गाँव से शहर आन व कारखानों पर दृष्टिपान करन पर हम देखेंगे कि कृषि पर पडन वाली विभक्ति का पहला अमर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों पर ही पडता है, अत उन्हें गाँव छोडकर कारखानों, नौका-निर्माण स्थानों वगीचो तथा रेल, मिचार्ड आदि मरकारी निर्माण-कार्य वाल स्थानों में अधिक वनन के लिय काम हूँटने-तनु जाना पडता है। उनके इन प्रवास-कार्य में मयुक्त परिवार-प्रणाली इस अर्थ में महायक होनी है कि परिवार के कुछ सदस्य अन्न घर तथा खेत स सम्बन्ध विच्छेद किए बिना ही उने परिवार के अन्य व्यक्तियों की दल-रेख में छोडकर गाँव में चले जाते हैं। कभी कभी कृषक गाँव क साहूकार स बचन या भूमि और पशु खरीदने के लिए पयाप्त धन कमन व उद्देश्य स शहरों में तौकरी तलाश करते हैं। फिर कभी अपनी जीविका और भावी जीवन को उत्तम बनाने की आशा स निम्न श्रेणी के ग्रामीण श्रमिक (जो कि दलिन-वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं) शहरों और कस्बों को चले जान हैं। चूंकि उनके नगर जाने का प्रधान कारण कष्ट है न कि महत्वाकांक्षा, अत हम यह कह सकते हैं कि गाँवों से नगरों का प्रवास करने वाले लोग सबसे कम कुशल और अत्यन्त निर्याय ग्रामीण होते हैं।

३. देशान्तर-गमन के प्रभाव—देशान्तर-गमन व पण्ड्यामस्वरूप कारखानों में काम करन वाली व कितन ही वर्ग अपन को एकदम अपरिचित रीति-रिवाजों और परम्पराओं के मध्य पाते हैं। यह भी हा सकता है कि वहाँ पापा भी दूसरी हो। पुरानी प्रथाओं और मान्यताओं के बन्धन टोले पड जात हैं। “वे सब बन्धन, जो ग्रामीण जीवन को समुष्ट रूप प्रदान करते हैं, टोले पड जात हैं नवीन सम्बन्ध शीघ्रता से नहीं स्थापित हा पात। फलत जीवन अधिकाधिक वैयक्तिक हो जाता है।” जलवायु के अत्यधिक परिवर्तन, दापपूर्ण भोजन, स्थानाभाव के कारण अत्यधिक भीड-भाड, मर्यादा का अभाव तथा परिवारिक जीवन से विच्छेद हान क बाद पुन मिलने का प्रलोभन, इन सबका मयुक्त प्रभाव श्रमिक व स्वास्थ्य पर बहुत बुरा पडता है। कुछ दुर्घ्य-मनों व कारण श्रमिक क नैतिक जीवन का और भी पतन होता है। जराब और जुआ इन दुर्घटना व उदाहरण हैं जो कि गाँवों में अपक्षाहृत अज्ञात हैं। ग्रामीण श्रमिक का काम कभी-कभी होना है और काम के बीच उने सम्बन्ध विधाम लेने

की आदत रहती है। इसके विपरीत औद्योगिक श्रमिक होने पर अनुशासित जीवन में उसे नियमित रूप से लगातार कई घंटे काम करना पड़ता है, इससे उसके स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके बार-बार गाँव लौटने तथा अन्य कारणों से मालिक और श्रमिक के बीच सम्पर्क की घनिष्ठता नष्ट हो जाती है और उनमें प्रभावपूर्ण संगठन का भी अभाव हो जाता है। श्रमिक जब लम्बी अनुपस्थिति के बाद लौटता है तो यह निश्चित नहीं होता कि उसे काम मिलेगा ही। पुनः काम मिलने की कठिनाइयाँ उसे साहूकार, मजदूरों के ठेकेदार, शराब बेचने वाले आदि की दया पर आश्रित कर देती हैं।^१

जिस प्रकार गाँवों के आर्थिक भार को नगर-प्रवास हल्का कर देता है, उसी प्रकार गाँव नगरों की वृत्तिहीनता के प्रति एक प्रकार की सुरक्षा (वीमा) प्रदान करते हैं। ग्रामीण और नागरिक जीवन का संयोग दोनों (नगरों और गाँवों) के लिए हितकर होना है। इससे ग्रामीण जीवन में बाहरी दुनिया का थोड़ा-सा ज्ञान आ जाता है तथा पुरानी जर्जर प्रथाओं की शृंखला तोड़ने में सहायता मिलनी है। इसी प्रकार नागरिकों को भारतीय जीवन की वास्तविकताओं का सूक्ष्म ज्ञान होना है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर श्रम-आयोग का सुविचारित मत यह था कि इस समय गाँवों से सम्बन्ध की कड़ी को बनाए रखना लाभदायक है और उद्देश्य यह होना चाहिए कि समाप्त करने के बजाय इसे सुनियमित और प्रोत्साहित किया जाए। (देखिए अ० आ० प्र० १७-२०)

४. औद्योगिक श्रम का प्रभाव—हम भारतीय औद्योगिक श्रम की कमी और महंगेपन की ओर संकेत कर चुके हैं।^२ इस अभाव के वास्तविक कारण बम्बई-जैसे नगरों में गृह और निवास की भयंकर परिस्थिति, कम मजदूरों और रहन-सहन का ऊँचा ध्येय तथा मजदूरों को भरती करने के लिए सुव्यवस्थित संगठन का अभाव है। इन सबक अतिरिक्त समय-समय पर प्लेग और इनफ्लुएन्जा तथा अकाल से होने वाली अधिक सख्या में मृत्यु भी श्रम की कमी को और बढ़ा देती है। श्रम का देशान्तर गमनीय स्वभाव इस कमी का अनुभव और तीव्र कर देता है। कुशल श्रम का एक प्रकार से अभाव ही है। इसका कारण यह है कि यहाँ आधुनिक उद्योगों के लिए श्रमिकों के प्रशिक्षण की सुविधाओं का अभाव है। प्राविधिक एवं व्यापारिक अनुभव से युक्त मिस्त्री अथवा फोरमैन-वर्ग के अभाव का कारण साधारण शिक्षित-वर्ग की हर प्रकार के हाथ के काम के प्रति अरुचि भी है।

५. भरती करने का ढंग—अब भी अधिकांश मिलों के प्रबन्धक सीधे सीधे ही आवश्यक श्रम की भरती नहीं करते। कुछ हालतों में ठेकेदारों द्वारा गाँवों में घूम घूमकर भरती करना आवश्यक हो सकता है। उदाहरणार्थ, आसाम के चाय के बगीचों में ऐसा ही होता है, परन्तु अब साधारणतया ऐसा नहीं होता। लेकिन अब भी सामान्यतः

१. देखिए वी० हर्ट्ज, 'लेबर एण्ड हाउसिंग इन बाम्बे', आमुल-लेखक श्री स्टैनली रीड, पृ० ५-६।

२. देखिए सख्त १, अध्याय ३, संश्लेषण २४।

मध्यस्थो (जाँवर) या फोरमैन के माध्यम से ही श्रमिकों की भरती होती है। जहाँ पर विभागाध्यक्ष यूरोपियन हैं वहाँ उनके और मजदूरों के बीच भारतीय मध्यस्थ (जाँवर) एक अनिवार्य कड़ी है। उसकी महत्ता का एक कारण यह भी है कि नियोजता श्रम-सघों से दूर रहते हैं। यह कभी-कभी हड़ताल के नेता का भी काम करता है।^१ उसके कुछ कार्य पाश्चात्य श्रम-सघ के अधिकारियों की भाँति हैं। वह अनेक प्रकार से श्रमिकों के लिए अनिवार्य बन जाता है। वह उन्हें घन देता है, भगडो में मध्यस्थ का काम करता है और कुटुम्ब-सम्बन्धी मामलों में राय देता है। चूंकि सभी श्रमिक उसी के द्वारा भरती किये जाते हैं, अतः नवीन श्रमिक स्थायी अथवा अस्थायी किसी भी प्रकार का काम पाने का एक-मात्र उपाय उसे घूम देना समझते हैं। कलकत्ता की जूट-मिलों में दम्तूरी के नाम पर घूमवोरी खूब फैली हुई है और सरदार द्वारा इधर-उधर से बमूल की गई रकमों से उसकी आय कभी-कभी मासिक मजदूरों की पाँचगुना तक हो जाती है, यहाँ तक कि तनरवाह देने वाले छोट-छोट क्लर्क भी इन प्रकार की आमदनी करते हैं। भरती करन वाला एजेण्ट प्रायः ऐसा प्रवन्ध करता है कि श्रमिक काम छूटने के भय से उसे कुछ-न-कुछ देने पर सदैव मजबूर होता है। स्त्रियों को भी, विशेषकर विधवा होने पर, श्रोवरसियरों द्वारा मजदूरों पर लगाये गए भार में भाग बंटाना पड़ता है।^२

श्रम-आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में कितने ही बड़े बड़े सगठनों, जैसे ई० डी० सासन एण्ड कम्पनी तथा बर्मा शील कम्पनी आदि, ने मजदूरों की भरती और कल्याण के लिए 'विशेष श्रम-कल्याण अधिकारी' नियुक्त किए हैं। बम्बई के मिल-मालिक सघ ने 'बदली-नियन्त्रण-पद्धति' जारी की है जिसमें केवल कार्ड रखने वालों को ही रिक्त स्थान पर रखा जाता है। कितने ही जूट-मिलों ने श्रम-नियोजनालय (ब्यूरो) स्थापित किए हैं जिनका एक प्रधान काम श्रमिकों की भरती है।

कानपुर श्रम-जाँच समिति (कानपुर लेबर इन्क्वायरी कमेटी) ने श्रमिकों की नियुक्ति से मिस्त्रियों को बिलकुल अलग करन का सुझाव रखा और सरकारी नियन्त्रण में श्रम-विनिमय की स्थापना पर जोर दिया जो कि फेक्टोरिया की माँग पर प्रार्थियों को नौकरी देगे।^३ उत्तर भारत नियात्रा सघ, कानपुर ने इन्हीं आधारों पर एक वृत्ति-विनिमयालय (एम्प्लायमेण्ट एक्सचेंज) स्थापित किया है। यह वाञ्छनीय होगा कि नियमित छुट्टियाँ मिले और छुट्टियों में भत्ता देना भी शुरू किया जाए, ताकि मध्यस्थों (जाँवर) को दक्षिण क्षीण हो जाए और एक सन्तुष्ट एवम् दुःखाल श्रम-शक्ति का निर्माण हो।^४

जनवरी, १९४० में हुए श्रम-मन्त्री सम्मेलन में भारतीय श्रमिकों को सवेतन

१. भारत के विभिन्न भागों में 'जाँवर' के भिन्न-भिन्न नाम हैं, यथा मरदार, मुकरम, निरत्री आदि।
२. देरिड, जे० एन्ड० केन्सलैन्, लेबर इन इण्डिया, पृ० १०८-९।
३. रिपोर्ट, पैरा १३६-६०।
४. ध० घा० प्र०, ०३-०७।

छुट्टी देने के प्रश्न पर भी विवाद हुआ। सम्मेलन ने इस प्रश्न पर केन्द्रीय अधिनियम का पक्ष लिया।

भरती करने के ढंग को अधिक युक्तियुक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों पर रोजगार-सेवा (Employment Service) की स्थापना द्वारा नियोक्ताओं के लिए अपनी आवश्यकतानुसार श्रमिकों को भरती करने का अवसर दिया है। अनेक राज्यों में Decasualization Schemes चालू हैं। उत्तर प्रदेश में इनके अन्तर्गत १९५८ में ९,८९१ व्यक्ति रोजगार के लिए रजिस्टर किये गए तथा ८,५९२ को रोजी मिली। अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की योजनाएँ चालू हैं।

६ पारिश्रमिक देने की अवधि—बम्बई की प्रायः सभी मिलों में वेतन माहवारी दिया जाता है। यह अगल महीने की ८ तारीख को दिया जाता है। इस प्रकार भरती होने के बाद नये मजदूर को वेतन के लिए छह सप्ताह तक प्रतीक्षा करना पड़ती है। मासिक वेतन देने से काम छोड़ने वाले श्रमिक को यह आवश्यक हो जाता है कि वह एक महीने पहले सूचना दे। कितने ही श्रमिक इस नियम की अज्ञानता में बिना सूचना दिए ही काम छोड़ देते हैं और इस प्रकार एक महीने के वेतन से हाथ धो बैठते हैं। माथारण रूप से यह कहा जा सकता है कि श्रम की अवधि जितनी ही लम्बी होगी, पारिश्रमिक मिलन में उतनी ही देर भी होगी। क्लकत्ता की जूट-मिलों में साप्ताहिक पारिश्रमिक मिलता है, अतः केवल एक सप्ताह की ही मजदूरी रकी रहती है। ग्रहमदाबाद में मजदूरी दो सप्ताह बाद मिलती है अर्थात् १४ या १६ दिन बाद।

१९३६ में पास किये गए पारिश्रमिक देने के अधिनियम के अनुसार (१) मजदूरी की अवधि एक महीने से अधिक न रखी जाए, (२) सब मजदूरी तिथि को या करंसी नोटों में दी जाए, (३) १००० से अधिक कमचारियों के रेलवे या अन्य किसी भी औद्योगिक कारखाने में प्रत्येक व्यक्ति की मजदूरी ७वें दिन के समाप्त होने के पूर्व मिल जानी चाहिए और अन्य रेलवे तथा औद्योगिक कारखानों में मजदूरी की अवधि के अन्तिम दिन से दसवें दिन तक अवश्य मिल जानी चाहिए।

पारिश्रमिक भुगतान (सशोधन) अधिनियम १९५७ में पास किया गया और पहली अप्रैल १९५८ से यह अधिनियम लागू किया गया। सशोधित नियम के अन्तर्गत ४०० रु० प्रतिमाह तक पाने वाले व्यक्ति हैं, जबकि १९३६ के अधिनियम के अन्तर्गत २०० प्रतिमाह तक पाने वाले व्यक्ति ही थे।

७ मजदूरी में से कटौती—१९५७ के सशोधित अधिनियम के अनुसार नियोजित,

१. श्रम सदस्यों द्वारा प्रस्तावित उपर्युक्त अधिनियम का संशोधन, जिसमें १५ दिन से ७ दिन पर पारिश्रमिक देने की व्यवस्था थी, बहुमत न प्राप्त कर सका। इसका प्रधान कारण मासिक वेतन पाने वालों का विरोध था। उनका कहना था कि भ्रमण का किराया और रात के बिल महीने पर आने और उन्हें तन्खाह सप्ताह पर मिलेगा, तब तक वह समाप्त हो जायेगी—'इण्डियन इन्टर लुक' १९४४-४५, पृ० ५१५।

सरकार, परिणियत आवास परिपद् इत्यादि द्वारा दिये गए रहने के मजान के लिए कटौती, बीमा चुकाने के लिए कटौती, तथा सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदने के लिए कटौती । १९५७ के संशोधित अधिनियम के अनुसार सेवा-नियम (Service Rules) के अन्तर्गत किये गए जुर्माने कटौती में सम्मिलित नहीं होंगे ।

जुर्माना—किसी भी वृत्ति-प्राप्त व्यक्ति पर जुर्माना उसी दशा में किया जा सकता है जबकि हानि या भूख केवल भली प्रकार अधिसूचित कार्यों के सम्बन्ध में उस स्थान पर हो, जहाँ काम होता है । पन्द्रह वर्ष से नीचे के किसी भी व्यक्ति पर जुर्माना नहीं किया जा सकेगा ।

इस अधिनियम के परिणामस्वरूप जुर्माना करभा प्रायः बन्द-सा हो गया है, परन्तु नियोक्ताओं ने अधिनियम से बचने के कितने ही तरीके निकाल लिए हैं । उदाहरण के लिए, वे मजदूरों को जिना वेतन के छुट्टी पर जाने के लिए विवश करते हैं तथा मजदूरों की भेदात्मक दरें प्रारम्भ करते हैं ।

८. काम के घंटे और भ्रमणशील प्रवृत्ति—भारत के नियोक्ता की हमेशा से यह शिकायत रही है कि भारतीय श्रमिक लगातार स्थिर रूप से काम नहीं करता । वह अनेक वहाँ बसाकर इधर-उधर समय बिताया करता है । काम करने वाले अपनी मशीनों से अनुपस्थित रहते हैं जिनके बदले दूसरे आदमियों को लगाना पड़ता है । १९०८ के भारतीय फँवट्री आयोग (इण्डियन फँवट्री कमिशन) के अनुसार “यद्यपि भारतीय श्रमिक थोड़ी देर तक काफी शक्ति और कुशलता से काम कर सकता है, परन्तु स्वभावतः वह काम को काफी देर तक फँलाए रहना चाहता है तथा उसकी प्रवृत्ति आराम के साथ काम करने और परिश्रम करने की अनिच्छा होने पर विश्राम लेने की होती है ।” काम के घंटों में कमी, सफाई की दशा में सुधार, कारखानों में हवादानों का प्रबन्ध, उचित निरीक्षण आदि से घूमने की आदत कम हो जाएगी और श्रम की कुशलता बढ जाएगी । उदाहरण के लिए, कलकत्ता की जूट-मिल्सों में भ्रमण की आदत कम है क्योंकि वहाँ श्रमिकों के काम करने की पारी (शिफ्ट) कम घंटों की है । यही हालत अभियन्त्रण की दूकानों की है जहाँ काम के घण्टे आठ से अधिक नहीं हैं ।

१९४८ के कारखाना-अधिनियम के अन्तर्गत काम करने के घण्टे ४८ प्रति सप्ताह तथा ९ घण्टा प्रतिदिन निश्चित किये गए हैं । काम का अधिकतम फँलाव किसी दिन १०^१/_२ घण्टे तक हो सकता है किन्तु इसमें बीच में आराम के लिए दिया गया मध्याह्न भी शामिल है । बच्चों के लिए कार्यावधि ४^१/_२ घण्टा प्रतिदिन रखी गई है और कार्यावधि का अधिकतम फँलाव ५ घण्टे तक हो सकता है । जहाँ कार्यावधि की उपर्युक्त सीमाओं का उल्लंघन किया जाता है, वहाँ अधिनियम में यह व्यवस्था है कि (अ) प्रत्येक श्रमिक के काम के घण्टे प्रतिदिन १० घण्टे से अधिक नहीं और प्रति सप्ताह ५० घण्टे से अधिक नहीं होना चाहिए तथा (ब) किसी भी दिन काम का फँलाव १२ घण्टे से अधिक नहीं होना चाहिए । जो व्यक्ति निश्चित अवधि से अधिक काम करने उन्हे उस समय के लिए सामान्य मजदूरों की दूनी दर में पारिश्रमिक दिया

जाएगा ।

६ मिलों में काम करने की कठोर परिस्थिति—हवा और प्रकाश का प्रबंध कपड़े की मिलों में पर्याप्त कठिनता प्रस्तुत करता है । बम्बई जैसे शहरों में मिलें कई मजिलों में होती हैं । अन्तिम मजिल को छोड़कर शेष मजिलों में छत स प्रकाश नहीं आसकता । जितने भी प्रयोग किये गए हैं उनसे मालूम हुआ है कि गरमी में पर्याप्त रूप से हवादान न होने से कुशलता में २० प्रतिशत तक कमी हो जाती है । नमीकरण एक अन्य कठिन समस्या है । भारत की जलवायु स्वतः नम नहीं है । कपड़े की बुनाई के लिए इसी प्रकार की जलवायु आवश्यक है । कपड़े के धागे को टूटने से बचाने के लिए कारखानों में कृत्रिम उपायों से नमी रखना आवश्यक हो जाता है । जब इस प्रकार का नमीकरण अन्दर भाग पहुँचाकर तथा गर्दे पानी का प्रयोग से किया जाता है तो यह काम करने वालों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है । भारत सरकार ने इस विषय के एक विशेषज्ञ की नियुक्ति की है जिसका काम नमीकरण की सर्वोत्तम विधि बताना है ।

जलपान गृहों की अत्यन्त आवश्यकता है जिनमें स्त्री पुरुष दोनों वर्गों के लोग जा सकें । पीने के लिए शुद्ध जल की पूर्ति, स्नान-सम्बन्धी व्यवस्था—जो कि एक गरम देश में अत्यन्त आवश्यक है—स्वच्छ शौचालय आदि अन्य बातें हैं जिन पर श्रमिकों की सुविधा और कुशलता बढ़ाने के दृष्टिकोण से अभी तक नियोजताओं ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है । विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए अधिनियमों द्वारा भी काम करने की परिस्थितियों में सुधार करने का प्रयत्न किया गया है । उदाहरण के लिए, भारतीय डॉक श्रमिक अधिनियम १९३४ (Indian Dock Labourers Act, 1934), जो १० फरवरी १९४८ से लागू हो सका, के अन्तर्गत कार्य के स्थान पर मेडबन्दी और उचित प्रकाश, तथा उन स्थानों की पहुँच को सुरक्षित करने की व्यवस्था है । १९५३ में इस अधिनियम में पुनः संशोधन किया गया ।

१०. भारतीय कारखानों में अनुपस्थिति—भारतीय श्रमिकों के एक बड़े भाग (प्रतिशत) की अनुपस्थिति कारखानों के काम को अत्यन्त ही कठिन बना देती है । मिल मालिकों का कथन है कि वानस तथा मजदूरी बढ़न या मिलन से अनुपस्थिति बहुत बढ़ जाती है । भारतीय श्रमिक जीवन-यापन के लिए पर्याप्त घन मिल जाने पर सन्तुष्ट हो जाता है । अनुपस्थिति की मात्रा (जो बम्बई में ८ से १२ प्रतिशत तक है) मौसम के अनुसार भी बदलती रहती है । यह मानसून के समय तथा विवाहदि अवसरों पर अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है अर्थात् मार्च से जून तक बहुत अधिक होती है तथा दिसम्बर और जनवरी में सबसे कम रहती है ।

उपस्थिति के लिए भत्ते (ग्रलाउन्स) देकर कुछ सफलता प्राप्त की गई है । टैंक्सटाइल टैरिफ बोर्ड (वस्त्र प्रशुल्क-मण्डल) ने श्रम सचय के निर्माण पर जोर दिया है । इससे अस्थायी 'बदली वालों' की आवश्यकता न पड़ेगी और छुट्टी देने के काम में भी सरलता होगी (रिपोर्ट, पृ. ६०) ।

एक कारखाने से दूसरे कारखाने में श्रम के आने-जाने से भी अनुपस्थिति अधिक

होती है।^१ दम्बई, मद्रास और नागपुर जैसे औद्योगिक केन्द्रों में श्रमिकों में मिल-कर्मचारी ११ वर्ष में प्रायः सब-से-सब बदल जाते हैं। इस प्रकार कर्मचारियों की कुशलता घटने के साथ ही-साथ उत्पादन-लागत भी बढ़ जाती है।

११ औद्योगिक श्रम की कार्यक्षमता—सर वलीमेट सिम्पसन व अनुमान के अनुसार, लकाशायर की मिल का एक श्रमिक २ ६७ भारतीय श्रमिकों के बराबर काम करता है। डॉ० गिलवर्ट स्पेटर के मतानुसार, इन गणनाओं में भारतीय श्रमिक की कुशलता अधिक बढ़ा-चड़ाकर प्रदर्शित की गई है। भारत और इंग्लैंड में एक वर्ष (लूम) का चलाने के लिए लगाए गए श्रमिकों की संख्या से परिस्थिति का यहाँ अर्थ नहीं होता। भारत में अधिक व्यक्ति लगाए जाने का कारण यह है कि इनके उत्पादन का मूल्य दिया गए पारिश्रमिक की अपेक्षा अधिक होता है। इंग्लैंड में पारिश्रमिक अधिक होने के कारण श्रमिकों की मरना में मिनटव्ययता बरनी पड़ती

डॉ० स्पेटर भी यह स्वीकार करते हैं कि यद्यपि भारतीय श्रमिक की कुशलता अधिक बढ़ा चड़ाकर प्रदर्शित की जाती है परन्तु इसका अस्तित्व असंदिग्ध है। इंग्लैंड के श्रमिकों की अपेक्षा कहीं अधिक शारीरिक गठन, लगातार काम करने की शक्ति, अनुशासनबद्धता के कारण इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे भारतीय श्रमिकों की अपेक्षा अधिक कुशल हैं। उपरोक्त प्रकार के गणितों पर अनुमानों को अपमान में सावधानी से काम लेना चाहिए। भारतीय मिलों के कम उत्पादन का उत्तरदायित्व बस भारतीय श्रमिक पर ही नहीं रखा जा सकता। इसका आंशिक कारण प्रवृत्त की कुशलता भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त कपास की खराबी के कारण भी सूत बराबर दटा करता है परिणामस्वरूप अधिक आदमी काम में लगाने पड़ते हैं। यह भी शिकायत है कि लकाशायर व मिल मालिकों की तरह भारत के मिल मालिक अचानक मशीनों का उपयोग नहीं करते।

उद्योग-आयोग के मतानुसार निम्नतम मजदूरी के बावजूद भारतीय श्रमिकों का उत्पादन पाश्चात्य श्रमिकों से कम होता है। १९०८ में डॉ० नॉयर ने कहा कि "यदि लकाशायर का एक श्रमिक भारत के २ ६७ के बराबर होता तो लकाशायर में काम करने वाले की मजदूरी ४ पनी या ६० र० है, जबकि मद्रास के एक मजदूर की मजदूरी १५ र० है। इस प्रकार स्पष्ट है कि समान व्यय करने पर अंग्रेज मिल-मालिकों की तुलना में भारतीय मिल-मालिकों लगभग दूना काम करा लेते हैं।" इसका अभिप्राय यह हुआ कि वस्तुतः भारतीय श्रमिक अधिक कुशल हैं। किन्तु अ

१. काम के घण्टों और पारिश्रमिक-सम्बन्धी अनुशासन के कारण एक कारखाने से दूसरे कारखाने में बदली जानी रहती है। प्रायोगिक मजदूरी के अभाव में कारखाना छोड़ने की भावना और प्रवृत्त होती है—(आर० व० दास 'वैक्य' लेकर इन इंडिया, पृ० ४४-५)। मजदूर (नावर) के कारण भी इन काम में काफी कुशलता पैदा हो गई है। इन दूर करने के लिए सरकारी श्रम शिष्टाचार को काम में लाया जाता है।

तो यह सर्वमान्य है कि पाश्चात्य श्रमिक की तुलना में भारतीय श्रमिक अकुशल है।^१ १२ भारतीय श्रम की अकुशलता के कारण—अकुशलता के कुछ स्थायी कारण हैं, परन्तु कुछ अस्थायी और उपचार-योग्य कारण भी हैं। प्रथम प्रकार के कारणों में भारत की जलवायु का नाम लिया जा सकता है जो कि अधिक ऊँची कार्यक्षमता के प्रतिकूल है। उदाहरण के लिए, यदि हम कपास के उद्योग के बारे में सोचें तो भारत की मिलों की अपक्षा लकाशायर की ठण्डी और प्राणदायी जलवायु बहुत ही अनुकूल है। इस प्रकार लकाशायर अधिक लाभप्रद स्थान पर स्थित है। भारत की उष्ण जलवायु को ध्यान में रखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि काम के घण्टे अब भी काफी लम्बे हैं और इस कथन में पर्याप्त सत्य है कि भारतीय श्रमिक की ढील डालने और विश्राम लन की आदत स्वास्थ्य-रक्षा का एक उपाय है जिसे वह अचेतन रूप से अधिक कठोर परिश्रम से अपनी शारीरिक रक्षा के लिए अपनाता है। यह निर्विवाद है कि भारतीय श्रमिक की शारीरिक शक्ति एक अग्रज की अपेक्षा कम है। इसके दो प्रधान कारण हैं—(१) बीमारी के कारण होने वाली हानियाँ, (२) भोजन में कमी। जैसा कि स्पष्ट है भारत के गावों में भी मलेरिया, प्लेग, हैजा, काला अजार, टुक वम जैसी बीमारियाँ होती हैं, परन्तु घनी आवादी वाले औद्योगिक क्षेत्रों में उनका प्रभाव कहीं अधिक है। अंधेरी और घनी बसी कोठरियों (स्लम) में बीमारियाँ पलती हैं। इन स्थानों में उनके प्रसार की आदर्श दशाएँ होती हैं।

जहाँ तक भोजन की कमी का सवाल है, वह समस्त भारत से सम्बन्धित है और इसका विस्तृत विवरण अध्याय ४ में किया जाएगा।

१३ आवास (हाउसिंग) की परिस्थितियाँ—अधिकांश औद्योगिक नगरों में ऐसी घनी आवादी और सफाई की दुर्व्यवस्था है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बहुत अंश में यह श्रम की अकुशलता के कारण है। उन औद्योगिक क्षेत्रों में, जहाँ कारखाने नगर से कुछ दूर स्थित हैं, मजदूरों की आवास सम्बन्धी समस्या अपेक्षाकृत सरल है। यही स्थिति कलकत्ता के औद्योगिक क्षेत्रों में भी है। इन स्थानों में बम्बई की अपक्षा कम दाम पर भूमि मिल जाती है। यहाँ मजदूरों के घर भोपड़ियों की कतारें हैं जिन्हें बस्ती कहा जाता है। ये भोपड़े मिल-मालिकों द्वारा नहीं बनाये गए हैं और मिलों में काम करने वालों को उचित किराये पर दिये जाते हैं। कुछ स्थानों, जैसे बानपुर कलकत्ता और अहमदाबाद, में बुद्धिमान् नियोक्ताओं ने स्वयं श्रमिकों के लिए रहने के स्थान बनवाए हैं ताकि वे श्रम-बाजार पर प्रभाव स्थापित कर सकें

१. श्री (अब हिन एमिलेन्मी सर) एच० पी० भादी ने, जो कि बम्बई मिल-मालिक संघ के चैयरमैन थे, अपनी मौखिक गवाही में अम-आयोग के समक्ष अम-कुशलता के निम्न आँकड़े दिये 'जापान में एक बुनने वाला ४ करघे देखता है, उसकी कुशलता ६५% है। चीन में एक बुनने वाला ४ करघे देखता है, उसकी कुशलता ८०% है। रूस में एक बुनने वाला २ करघे देखता है, उसकी कुशलता ८०% है। चिन और जापान की गणना के आधार पर एक बुनने वाला बम्बई में चीन, जापान की अपेक्षा २००% और ३००% अधिक पाता है।'

और उम प्रकार के श्रम को प्राप्त कर सके जिम पर प्रधान रूप से कपास की मिले चलती है।^१ अन्य औद्योगिक केन्द्रों की अपक्षा अहमदावाद में मजदूरों के रहने की व्यवस्था अधिक खराब है। प्राय सभी औद्योगिक केन्द्रों में घनी आबादी की समस्या बढ़ती गई है, क्योंकि औद्योगिक विकास के लिए स्थान चुनने पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं रखा जाता। इस दुर्घटना का यही कारण है। श्रमिक वर्ग में से अधिकांश चाली में रहते हैं जोकि प्राय एक कमरे की होनी है, लेकिन इनमें दा से अधिक कमरे नहीं होते। इन चाली का प्रधान उद्देश्य सस्ते-से-सस्ते में अधिक-से-अधिक श्रमिकों को निवास-स्थान देना है।^२

१४ आवास की कठिनाइयों और स्वच्छता की कमी के दुष्परिणाम—“अच्छे घरों का अर्थ है, गृह-जीवन की सम्भावना, सुख और स्वास्थ्य, बुरे घरों का अर्थ है, गन्दगी, शराबखोरी, बीमारी, आचारहीनता, ध्वभिचार और अपराध। इनके लिए अस्पताल, जेल और पागलखानों की आवश्यकता होती है, जहाँ समाज का भ्रष्ट और पतित लोगों को छिपाया जाता है जो स्वयं समाज की लापरवाही के ही परिणाम हैं।” अपूर्ण और गन्दे मकान भी औद्योगिक अशान्ति का कारण है। ये सब बुराईयाँ न्यूनाधिक मात्रा में बम्बई में पाई जाती हैं। इनमें से एक सबसे बड़ी बुराई अधिक सख्या में शिशु मृत्यु है जो बम्बई की गन्दी बस्तियों (स्लम्स) में पाई जाती है। मृत्यु-सख्या निवास के कमरों के विपरीत अनुपात में है। उदाहरण के लिए, १९३६ में एक कमरे वाले निवास स्थानों में मृत्यु सख्या ७८३ प्रतिशत थी।^३ सबसे गन्दे स्थानों में मृत्यु-दर २६८ प्रति-हज़ार थी जबकि साधारण दर २०० से २५० प्रति हज़ार ही थी।^४ अन्त में चाल के जीवन की भयकर दशाएँ तथा गोपनीयता के अभाव के कारण लोग अपने कुटुम्ब को नहीं ला पाने, जिससे श्रम की कुशलता और स्थिरता पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। श्रम जाँच समिति (लेबर इनवेस्टीगेशन कमेटी) इस परिणाम पर पहुँची कि शिक्षा और औपधि-सम्बन्धी सहायता की भाँति सरकार को औद्योगिक आवास का भी उत्तरदायित्व सँभालना चाहिए।

१५ सुधरे आवासों के लिए प्रयास—१९२० तक नगरपालिका (म्युनिसिपैलिटी) ने भी अपने कर्मचारियों के लिए २,६०० मकान बनवाए और २,२०० के लिए स्वीकृति दी। पोर्ट ट्रस्ट ने ५,००० व्यक्तियों के लिए मकान बनवाए। इधर नगर की जन-सख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, परन्तु मिल-मालिकों ने अपने मजदूरों के आवास के लिए कोई प्रयास नहीं किया। घनी आबादी से बचने के लिए तथा अच्छी आवास-

१. श्रमिक नियोजनाओं द्वारा दी गई आवास-सुविधाओं से पूरा-पूरा लाभ नहीं उठाते। कारण यह है कि इनमें उनकी स्वच्छता में बाधा पहुँचती है, क्योंकि हस्तान्तरण और मिल-बन्दी के समय वे उन आवासों से निकाल दिये जाते हैं। उनके अन्य कार्यों की, जिन्हें नियोजना अनुचित समझना है, निगरानी भी अवश्य होगी। वी० गिबराव, 'इण्डस्ट्रियल वर्कर इन इण्डिया'।

२. हर्ट—नूवादधृत, पृ० २०, अन्-आयोग १, रिपोर्ट, पैरा - ४१ भी देखिए।

३. रिपोर्ट आफ दि रेण्ट इन्वेंचर कमेटी, बम्बई, १९३६, पैरा २६।

४. अ० आ० प्र०, २७१।

व्यवस्था के लिए उद्योग आयोग ने कुछ अपवादसहित नई फर्मों की स्थापना के लिए स्वीकृति देना बन्द करने की सिफारिश की ।^१ औद्योगिक विकास के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र चुनने, रेलवे के कारखाने नगर से उचित दूरी पर स्थापित करने, रेलवे, सरकार और सार्वजनिक सस्थाओं द्वारा अपने नौकरों को निवास-स्थान देने, उपनगर-निर्माण के लिए संचार-साधन के आयोजन तथा नगर में स्थित आवासों में रहने की सन्या का निश्चित प्रमाण तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा निर्माण योजना बनाने और कार्यान्वित करने की सिफारिशें भी की । १९१४-१८ के युद्ध के उपरान्त बम्बई सरकार द्वारा इस समस्या को सुलझाने के लिए सुविस्तृत योजना तैयार की गई । इसके लिए ६ करोड़ के विकास-ऋण तथा बम्बई आने वाली सभी कपास पर १ ६० प्रति गाँठ के हिसाब से नगर-कर (टाउन ड्यूटी) लगाकर आवश्यक धन इकट्ठा किया गया । किन्तु इस प्रकार बनी कितनी ही चाले, विशेषकर 'बोरली' की चाले, लगभग दस साल तक खाली पड़ी रही । इनमें रहने के लिए मजदूरों के अर्कपित न होने के निम्न कारण थे—वहा तक पहुँचने की कठिनाइयाँ, बाजार-सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव, उनका सीमेण्ट से बना होना—जिमके कारण वे गरमी में अधिक गरम तथा जाड़े में अत्यन्त ठण्डी रहती है—किराये की ऊँची दर तथा प्रकाश-सम्बन्धी व्यवस्था और पुलिस-सुरक्षा का अभाव । इन दोषों को दूर करने के लिए कुछ प्रयास किये गए हैं ।

कानपुर, नागपुर, अहमदाबाद, मद्रास इत्यादि स्थानों में अधिक सुविधाजनक परिस्थितियाँ हैं । यहाँ पर मिल-मालिकों ने कर्मचारियों के हित पर अधिक ध्यान दिया है । इससे दोनों दलों को लाभ हुआ है । इस सम्बन्ध में एम्प्रेस मिल्स, नागपुर और टाटा के जमशेदपुर के लोहे और इस्पात के कारखानों के प्रबन्धकों द्वारा किये गए आवास-सम्बन्धी स्तुत्य प्रयत्नों की चर्चा करना उचित है । इस समय कर्मचारियों के मकान की समस्या को हल करने में प्रधान कठिनाइयाँ निर्माण के लिए उचित स्थलों का अभाव, श्रम तथा भवन-निर्माण सामग्री की ऊँची कीमतें और अभाव हैं ।

श्रम आयोग ने अनेक प्रकार के सुझाव पेश किये—(१) भूमि प्राप्त करने के अधिनियम को इस प्रकार संशोधित किया जाए ताकि मिल-मालिक कर्मचारियों के हेतु मकान बनवाने के लिए भूमि प्राप्त कर सकें । अतएव १९३३ में स्वयं भारत सरकार ने इस अधिनियम को संशोधित किया । (२) प्रांतीय सरकारें उद्योग और नगर-क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर आवास-सम्बन्धी आवश्यकताओं का पता लगाएँ और सब दलों के सहयोग के लिए व्यावहारिक योजनाओं पर परस्पर-परामर्श का प्रबन्ध करें । (३) सरकार को एक निम्नतम मानदण्ड स्थापित करना चाहिए जिसमें घनफल, स्थान, हवादारी, प्रकाश आदि की उचित व्यवस्था हो । (४) जहाँ आवश्यक हो नगर आयोजन अधिनियम पास किये जाएँ । (५) प्रत्येक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट पर बैंध-रूप से थ्रिफिक-वर्ग के लिए भवन-निर्माण का उत्तरदायित्व रखा जाए । (६) सरकारी आवास-समितियों को प्रोत्साहन दिया जाए । (७) स्वास्थ्य, सफाई और आवास से सम्बन्धित उपनियमों को संशोधित एवं अद्यतन बनाया जाए और उन्हें कठोरता के

१. यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया और बम्बई खास में नई भिल्लें नहीं बनायी जाती ।

साथ लागू किया जाए। (श्रम आयोग रिपोर्ट, अध्याय १५)^१

कानपुर श्रम जाँच समिति ने अपनी रिपोर्ट (पैरा २११-२२) में सिफारिश की कि प्रान्तीय सरकार को ५० लाख ऋण लेना चाहिए और ५ वर्ष तक १० लाख प्रतिवर्ष इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को श्रमिकों के लिए १२,००० मकान बनवाने के लिए दें। १९३८ में बम्बई सरकार द्वारा नियुक्त किराया जाँच समिति (रेण्ट इन्व्वायरी कमेटी) ने एक दस वर्षीय आवास-योजना अपनाने की सिफारिश की, जिसमें राज्य की सहायता से नगरपालिकाओं द्वारा छोटे-छोटे और सस्ते मकानों के निर्माण का सुभाज रखा गया था। समिति ने यह भी मुझाव रखा कि १०,००० या इससे अधिक श्रमिकों को रखने वाला नियोजना कम-से-कम २५ प्रतिशत श्रमिकों के लिए आवास की व्यवस्था करे।^२

तीसरी पंचवर्षीय योजना में मकानों तथा शहरों की उन्नति पर २२७ करोड़ रुपया रखा गया, चौथी योजना में ६८० करोड़ रुपया। निजी क्षेत्र में १३५० करोड़ रुपया रखा गया और चौथी योजना में १८७० करोड़ रुपया रखा जाएगा।^३

श्रीद्योगिक आवास सम्बन्धी आधुनिक प्रयत्न—श्रमिकों के आवास के लिए इधर हाल में कुछ महत्त्वपूर्ण प्रयत्न किये गए हैं। अप्रैल १९४८ में केन्द्रीय सरकार ने १० वर्ष में श्रमिकों के लिए १० लाख मकान बनाने का निर्णय किया। अप्रैल १९४९ में श्रमिकों के आवास के लिए अपक्षित पूंजी के आधार पर एक नई योजना बनायी गई। इसके अन्तर्गत $\frac{३}{५}$ पूंजी केन्द्रीय सरकार तथा $\frac{२}{५}$ पूंजी प्रान्तीय सरकार या उसके द्वारा प्रस्तावित नियोजना देता। यह योजना भी सफल नहीं हुई क्योंकि राज्य सरकारों से उचित सहयोग नहीं मिल सका।

राज्यीय सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों के प्रतिनिधियों से परामर्श करने के बाद भारत सरकार ने मिनम्बर, १९५२ में आर्थिक सहायता प्राप्त श्रीद्योगिक आवास-योजना (सन्सिडाइज्ड इण्डस्ट्रियल हाउसिंग) को अन्तिम रूप दिया। यह १९४९ की योजना का संशोधित रूप था।

१९६६ के अन्त तक इस योजना के अन्तर्गत ६४,५४९ मकान बन चायेगे। इसके लिए तीसरी योजना में २९८ करोड़ रुपया रखा गया था।

१,०५,२७७ घरों में से ७९,००० घर अर्थात् ७५% १९५८ के अन्त तक बन चुके थे। स्वीकृत राशि में से १९७१ ४७ लाख रुपये की रकम १९५८ के अन्त तक दी जा चुकी थी। १९५७ में आवास-मन्त्रियों के दूसरे सम्मेलन की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सहकारी समितियों को दिये जाने वाले ऋण की मात्रा ५० प्रतिशत से बढ़ाकर ६५ प्रतिशत तथा निजी नियोक्ताओं को दी जान वाली ऋण की मात्रा ३७ $\frac{३}{४}$ प्रतिशत

१. नगरपालिकाओं द्वारा आवास-सुधार में एक कठिनाई यह है कि वे विशेष रूप से स्लम के मालिकों द्वारा प्रभाविन और परिवारित होते हैं।

२. रिपोर्ट ऑफ दि रेण्ट इन्व्वायरी कमेटी (बम्बई), १९३६, पैरा ८५-७।

३. रिजर्व बैंक रिपोर्ट।

से बढ़ाकर ५० प्रतिशत कर दी गई। अक्टूबर, १९५८ में आवास-मन्त्रियों का तीसरा सम्मेलन दार्जिलिंग में हुआ। इसकी सिफारिशों सरकार के विचाराधीन हैं।

सभी राज्यीय सरकारें औद्योगिक आवास के कार्यक्रम में आगे बढ़ रही हैं। विभिन्न राज्यों में इस सम्बन्ध में आवश्यक विधान भी पास किये जा चुके हैं, उदाहरणार्थ, वाम्बे हाउसिंग एक्ट, मैसूर लेबर हाउसिंग एक्ट, १९४६, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड एक्ट, १९५० तथा यू० पी० शुगर एण्ड पावर अलकोहल इण्डस्ट्रीज लेबर वेल्फेयर एण्ड डेवलपमेंट एक्ट, १९५१। इसके लिए आवश्यक धन केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के अनुदान, नियोक्ताओं के अशदान तथा काम करने वालों से प्राप्त किराये द्वारा मिलना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के १३ लाख घरों की तुलना में द्वितीय योजना के अन्तर्गत १६ लाख घर बनाने की व्यवस्था है। १९५८ में योजना के प्रारम्भ में प्रस्तावित १२० करोड़ रुपये की राशि घटाकर ८४ करोड़ रुपये कर दी गई। द्वितीय योजना के अन्तर्गत आवास-सम्बन्धी निम्न योजनाएँ चालू हैं।

(क) आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास-योजना, (ख) गन्दी बस्तियों (स्लम्स) को हटाने की योजना, (ग) निम्न आय वाले वर्ग की आवास-योजना, (घ) रोपण-उद्योग के श्रमिकों की आवास-योजना, (च) ग्रामीण आवास-योजना तथा (ङ) मध्यम आय वाले वर्ग की आवास-योजना। इनमें से (क), (ख) और (ग) औद्योगिक श्रमिकों से सीधे-साधे सम्बन्धित हैं।

पहली योजना की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना के अन्तर्गत केंद्रीय सरकार राज्यीय सरकारों को सहायता देती है। राज्यीय सरकार म्युनिसिपल या अन्य स्थानीय निकायों को गन्दी बस्तियों के हटाने तथा उनमें रहने वालों को पुनः बसाने के लिए सहायता देती है।

नवम्बर, १९५८ तक २०.५५ करोड़ रुपये की लागत की १६१ ऐसी योजनाएँ आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बम्बई, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल से प्राप्त हुईं। दिसम्बर, १९५८ तक १०३ योजनाएँ मजूर हो चुकी थीं, जिनके अन्तर्गत १८,८४८ घर बनाने तथा ६,७४३ खुले हुए प्लाट का विकास सम्मिलित था।

१६. मजदूरी की दर—कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की प्रतिव्यक्ति दैनिक (ग्रीसत) मजदूरी-सम्बन्धी आंकड़े विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों से पारिश्रमिक भुगतान अधिनियम १९३६ के अन्तर्गत एकत्रित किये जाते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। १९३६ के पारिश्रमिक भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरी से अभिप्राय द्रव्य में प्रदर्शित करने योग्य उस सभी राशि में है जो काम के बदले में पूर्व-निर्धारित शर्तों के अनुसार मिले। इस राशि में निम्न सम्मिलित नहीं है—(क) मकान, प्रकाश, पानी इत्यादि का मूल्य, (ख) नियोक्ता द्वारा पेन्शन कोष अथवा पूर्वोपाय कोष के लिए दिया गया अशदान, (ग) सफर का भत्ता या इस हेतु दी गई रियायतें, (घ) विशेष व्यय पूरा करने के लिए दी गई राशि, और (च) निकाले जाने पर प्राप्त राशि (gratuity)।

यह कहना बड़ा कठिन है कि अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत पारिश्रमिक-सम्बन्धी पाँकड़े कहीं तक एकरूप होते हैं। कारखानों को निम्न पाँच मदों के अन्तर्गत सूचना देनी होती है।

(१) आधार मजदूरी (Basic wages), (२) नरुद भत्ते, जिनम महगाई का भत्ता भी शामिल है, (३) रियायत या छूट या द्राव्यिक मूल्य, (४) वोनस तथा (५) बकाया (arrear)। तीसरी मद में भिन्नता की पर्याप्त गुजाइश है क्योंकि द्राव्यिक मूल्य निकालने के लिए कोई सर्वमान्य आधार नहीं है। इसके अलावा सभी कारखाने यह सूचना प्रस्तुत नहीं करते। सूचना देने वाले कारखानों की सख्या प्रतिवर्ष अलग-अलग होती है। अतएव इनके आधार पर प्रतिव्यक्ति वार्षिक पारिश्रमिक पूर्णतः तुलना योग्य नहीं होता।

सरकार की उदार धर्म नीति के कारण पारिश्रमिक में बढ़ने की स्पष्ट प्रवृत्ति है। सन् १९५८ के विभिन्न निर्णयों और समझौतों का परिणाम सम्बन्धित उद्योगों में किसी-न-किसी रूप में पारिश्रमिक की वृद्धि ही रहा है। उदाहरणार्थ पश्चिमी बंगाल के सूती वस्त्र उद्योग में जून १९५८ के निर्णय के अनुसार बेसिक मजदूरी २८ १७ रुपये तथा महंगाई भत्ता ३२ ५० रुपये और इस प्रकार कुल मासिक मजदूरी ६० ६७ रुपये हो गई, जबकि १९४८ के औद्योगिक ट्रिब्यूनल ने २० ६० २ आ० ५ पा० की बेसिक मजदूरी तथा ३० ६० का महंगाई भत्ता निश्चित कर कुल मासिक मजदूरी ५० ६० २ आ० ५ पा० निर्धारित की थी। बढ़ते हुए मूल्यों को दृष्टि में रखने पर मजदूरी की वृद्धि पर आश्चर्य नहीं किया जा सकता।

वास्तविक वेतन में बढोत्तरी हुई, यद्यपि कीमतें बढ़ी हैं, इसका पता हम निम्न तालिका से चलता है—

	१९५७	१९६३
(१) आम सूचाक वेतन का	१७०	१९५
(२) भारतीय श्रमिक संघ उपभोक्ता कीमतों का सूचाक	१२८	१५४
(३) वास्तविक वेतन का सूचाक	—	—
	१३४	१२६

१७. रहन-सहन का निम्न स्तर—भारतीय कृषक की अकुशलता का एक प्रधान कारण उसके रहन-सहन के स्तर की निम्नता भी है। पूर्ण कुशलता के लिए आवश्यक जीवन यापन स्तर से भारतीय श्रमिक का स्तर बहुत नीचा है। इस आमदनी से सन्तोष-जनक जीवन-स्तर कायम रखना प्रायः असम्भव सा ही है। काम करने वाला स्वास्थ्य-वर्धक भोजन नहीं खरीद सकता, चाहे वह अपनी आय कितनी ही बुद्धिमानी से खर्च करे। हम रहने के मकानों के सम्बन्ध में दयनीय अवस्था का विवरण पहले ही कर आए हैं। देश की गरम आवाहवा को ध्यान में रखते हुए उसका कपड़े बहुत ही कम हैं। शिक्षा पर होने वाला व्यय प्रायः नहीं के बराबर है। उसके फर्नीचर है कुछ

लकड़ी के हूटे सन्दूक, लोहे की चद्दर के बक्स, बांस के डडे, देशी कम्बल और कागजों पर बने कुछ पौराणिक चित्र ।

भारत सरकार श्रमिक-परिवारों के रहन-सहन-सम्बन्धी सर्वेक्षण ५० प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों में कर रही है । सर्वेक्षण-कार्य अगस्त-सितम्बर, १९५८ में प्रारम्भ किया गया । अनेक राज्य भी पारिवारिक बजट-सम्बन्धी जाँच कर रहे हैं ।

१९६१ की जनगणना के अनुसार १.६ करोड़ मकान शहरों में हैं और प्रति गृह के हिस्से में १.६३ कमरे आते हैं । प्रति कमरा घर के सदस्य २.६ हैं । खाद्य के उपभोग पर ६१.४ प्रतिशत आय-भाग खर्चा जाता है । कोयले और बिजली पर ६.३ प्रतिशत, कपड़े पर ६.२ प्रतिशत ।

१८. शराबखोरी पर व्यय—कारखानों में काम करने वालों में शराबखोरी बड़ी ही तीव्र गति से फैल रही है । लगभग कुल आय का ४ प्रतिशत शराब पर खर्च होना है । यह सख्या परिवार-बजट की साक्षी पर दी जा रही है । भगी जैसे निम्न श्रेणी के श्रमिकों के मामले में यह सख्या १० प्रतिशत तक पहुँच जाती है । पुरुष श्रमिक (स्त्रियाँ शायद ही कभी पीती हैं) अपने दिन के कठोर श्रम को भूलने के लिए शराब की शरण लेता है । शराब पीने की अभिलाषा और गन्दे निवास-स्थान, काम करने की अस्वास्थ्यकर परिस्थिति, दरिद्रता तथा भोजन की कमी में कुछ अनिवार्य-सा सम्बन्ध है । यदि शराब पर खर्च किया जाने वाला धन अच्छा भोजन खरीदने में व्यय किया जाए तो भोजन की कमी कुछ अंश में घट जाए । श्रमिक न केवल दरिद्र है वरन् वह अपनी आय को अच्छी तरह व्यय करने में भी अयोग्य है । शराबखोरी पर होने वाला व्यय उसकी दरिद्रता को और बढ़ाता है तथा दरिद्रताजन्य परिस्थितियाँ शराबखोरी को और बढ़ाती हैं ।

स्वतन्त्र भारत के संविधान में शराबखोरी को पूर्णतया समाप्त करने के लिए कहा गया है । दिसम्बर, १९५४ में नियुक्त मद्य-निषेध जाँच-समिति की यह महत्त्व-पूर्ण सिफारिश कि मद्य-निषेध की योजनाओं को विकास-योजनाओं का अंग बना देना चाहिए, ३१ मार्च १९५६ को सदन का समर्थन प्राप्त कर चुकी है । सभी राज्य इस दिशा में प्रयत्नशील हैं । बम्बई मद्य-निषेध अधिनियम, १९४९ के १९५६ के संशोधन ने सम्पूर्ण बम्बई राज्य में (चन्द्रा ज़िले के विशेष रूप से उल्लिखित स्थानों को छोड़कर) मद्य-निषेध की घोषणा कर दी ।

१९. ऊँची मजदूरी का पक्ष—नियोक्ताओं का कथन है कि यदि मजदूरी अधिक दी जाती है तो उसका अधिकांश शराबखोरी में खर्च हो जाता है और श्रमिकों की तुल्यता बढ जाती है । श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि नहीं होती और न उनका जीवन-यापन का स्तर ही ऊँचा उठता है । प्रो० पीगू इस आक्षेप का निवारण निम्न शब्दों में करते हैं—

“इसमें सन्देह नहीं कि गरीबों की मनोवृत्ति अपने वातावरण के अनुकूल ढल जाती है और अचानक आमदनी बढ जाने से अवश्य ही अनेक बेवकूफों के खर्च किये जाएँगे, जिनसे स्वभावतः आर्थिक सुख की अधिक वृद्धि या कुछ भी वृद्धि नहीं होती ।

किन्तु यह वृद्धि कुछ अधिक दिन तक कायम रहे तो यह दशा समाप्त हो जाएगी। और यदि यह वृद्धि क्रमिक होगी तो यह वेवकूफी की दशा शायद आए ही नहीं। लेकिन यह कहना कि गरीब आदिमियों की फिजूलखर्ची और वेवकूफी इतनी अधिक है कि उसकी आय में वृद्धि ही अवाञ्छनीय है, क्योंकि उससे आर्थिक सुख-समृद्धि की वृद्धि ही नहीं होगी, नितान्त भ्रामक है।”

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की दशा भी पारिश्रमिक को समता की ओर ले जाने में भयानक बाधा डाल रही है। यह तो मानना पड़ेगा कि कम-से-कम अल्पकाल के ही लिए कोई भी देश अपने श्रमिकों से भरपूर परिश्रम लेकर काफी लाभ उठा सकता है। लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सभी देश इसी नीति का अनुसरण करेंगे। यह कहा जा सकता है कि अत्यन्त घोर परिश्रम से अर्जित व्यापार में स्थायी लाभ नहीं होगा, क्योंकि अन्त में इस प्रकार के श्रम का परिणाम यह होगा कि कार्यक्षमता घट जाएगी। इसके विपरीत कोई भी सम्यक् देश यह नहीं भूल सकता कि उत्पादन-वृद्धि के आर्थिक आदर्श के समान ही महत्त्वपूर्ण आदर्श मानव-जीवन को उच्चतर बनाना है।

२० निम्नतम बंध मजदूरी—जनेवा में हुए १९२८ के ११वें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में एक ऐसे यन्त्र के निर्माण और कायम रखने पर जोर दिया, जिसके द्वारा विशिष्ट व्यापार और उद्योग में लगे कर्मचारियों के लिए एक न्यूनतम वेतन का मानदण्ड निश्चित किया जाए। यह ऐसे उद्योगों, विशेषकर गृह-उद्योगों, से सम्बन्ध रखता है जिनमें वेतन का कोई निश्चित मानदण्ड नहीं है और जिनमें पारिश्रमिक काफी नीचा है। श्रम आयोग का सुझाव है कि न्यूनतम पारिश्रमिक-निर्धारक यन्त्र की स्थापना से पहले ऐसे उद्योगों को चुनना होगा जिनके सम्बन्ध में यह निश्चित धारणा है कि उनमें वेतन की दशा शोचनीय है और विस्तृत गवेषणा वाञ्छनीय है। इन गवेषणाओं के आधार पर यह निश्चित किया जाए कि क्या न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण व्यवहार्य और वाञ्छनीय है? इस प्रकार के निर्णय के पश्चात् व्यय पर विशिष्ट रूप से ध्यान रखनी होगी, क्योंकि नियोजकों की उदासीनता और कर्मचारियों के अज्ञान के कारण इन नियमों के पालन में बड़ी असुविधा और शिथिलता होती है। यदि बिना भयंकर परिणामों के वाञ्छनीय उद्देश्य प्राप्त करना है तो गति को धीमा करना होगा।^१

१९३८ में नियुक्त बिहार श्रम जाच-समिति ने जून, १९४० में रिपोर्ट दी तथा अन्त में श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए १५० सिफारिशों की। १९४७ के केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट ने ऊंची श्रेणी से लेकर नीची श्रेणी के सरकारी

१ ८० सी० पी०, 'इकनामिक्स आफ वेल्फेयर'।

२. देखिए, रजिस्ट्रेशन जनरल आफ इकनामिक्स, डॉ० फ्रेडरिक्स नूबर्गर १९३०, माद्री विधान तथा भारतीय दशाओं से इनका सम्बन्ध, वी० चार० सेठ और एम० पी० सक्सेना।

३. श्र० आ० प्र०, २१०-१४।

कर्मचारियों के लिए वेतन का एक नया ढाँचा स्वीकार करने की सिफारिश की है। इसके प्रस्ताव के अनुसार न्यूनतम वेतन ३० रुपये माहवार से कम न होना चाहिए और अधिकतम वेतन २००० रुपये माहवार से अधिक नहीं होना चाहिए।

१९४८ में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पास किया गया। यह अधिनियम केन्द्रीय और राज्याय सरकारों से अनुसूचित उद्योगों में नियत अवधि के भीतर कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने की अपेक्षा रखता है। अधिनियम कर्न्तर्गत कर्मचारी (employee) से अभिप्राय किसी भी किराये या पुरस्कार के बदले काम पर लगाये कुशल या अकुशल, हाथ के या दफ्तर आदि के काम में लगे व्यक्तियों से है। १००० से कम सख्या में कर्मचारियों को रखने वाले रोजगारों को न्यूनतम मजदूरी निश्चित करना आवश्यक नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत पुरुष, बयस्क, बच्चा और प्रशिक्षार्थी, सभी के लिए विभिन्न पेशों, स्थानों अथवा काम की प्रकृति के अनुसार (क) न्यूनतम समय दर, (ख) न्यूनतम कार्यानुसार दर, (ग) गारण्टी की हुई समय दर तथा (घ) निश्चित समय से अधिक काम की दर अर्थात् अधिसमय दर निर्धारित करने की व्यवस्था है। न्यूनतम मजदूरी (सशोधन) अधिनियम, १९५७ ने अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की तिथि बढ़ाकर दिसम्बर १९५६ कर दी। सशोधन अधिनियम ने यह व्यवस्था भी की है कि जिन अनुसूचित उद्योगों में निर्धारण के ५ वर्ष बाद तक मजदूरी का पुनर्वीक्षण (रिव्यू) नहीं हुआ है, वहाँ मजदूरी का पुनर्वीक्षण किया जाए। १९६१ में इसमें थोड़ा और परिवर्तन लाया गया।

२१ ऋणिता—भारत के अधिकांश श्रमिक अपने क्रियाशील जीवन में ऋणी रहते हैं। ऐसा अनुमान किया गया है कि कितने ही उद्योग-केन्द्रों में लगभग दो-तिहाई श्रमजीवी ऋणी हैं और उनका ऋण तीन महीने में मिलने वाले पारिश्रमिक के बराबर है। श्रम आयोग ने सुझाव रखा था कि ३०० रु० प्रति मास से कम पाने वाले सब श्रमजीवियों के वेतन को कुर्की से मुक्त कर देना चाहिए और पूर्वोपाय कोष (प्रॉविडेंट फण्ड) के प्रति अक्षदान से भी श्रमिकों को मुक्त कर देना चाहिए। भारत सरकार ने इसी आधार पर व्यवहार-विधि-संहिता (सिविल प्रोसीजर कोड) को संशोधित किया, ताकि एक निश्चित सीमा के नीचे के वेतन कुर्की से मुक्त रहे। यह भी सुझाव रखा गया है कि ऋण के सम्बन्ध में औद्योगिक श्रमिकों की गिरफ्तारी और जेल की सजा बन्द कर दी जाए। गिरफ्तारी और जेल की सजा केवल उन हालतों में दी

१. अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित उद्योग इस प्रकार हैं - ऊनी कारखाने, शाल बुनने के कारखाने, चावल, आटा या दाल की चक्कियाँ, तम्बाकू (बीड़ी बनाना सम्मिलित है) बनाने के कारखाने, रोषण, तेल मिल, स्थानीय अधिकारी, सड़क बनाना या निर्माण-कार्य, पर्यटन-घरना या पीसना, लघु-निर्माण, अन्नक के कारखाने, सरकारी मोटर परिवहन, सिमावशाळाएँ और चर्म-निर्माण के कारखाने तथा कृषि। सरकार को यह अधिकार है कि वह अधिनियम को अथ उद्योगों पर भी लागू कर सकती है। पलत* अनेक राज्यों में यह अधिनियम अथ उद्योगों पर भी लागू किया गया है।

जाए जबकि श्रमिक कर्ज चुकाने योग्य होकर भी उसे अदा नहीं करता। श्रमिकों के अप्राप्य कर्ज को समाप्त करने में सरकारी विधि का उपयोग करना चाहिए और कर्ज की अदायगी को श्रमिक के वेतन के साथ इस प्रकार सन्तुलित करना चाहिए ताकि उसे चुकाने में अधिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। कर्जदार श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कानपुर श्रम जांच मजिनि ने मध्य प्रदेश के कर्जदार सुरक्षा नियम (१९३७) के आधार पर उपाय अपनाए का प्रस्ताव किया।^१ इस अधिनियम के अनुसार किमी कर्जदार के साथ बुरी तरह से व्यवहार करना दण्डनीय अपराध है। बंगाल में अधिक सीमित अधिनियम प्रचलित है। सरकारी ऋण इस समस्या का अधिक स्थायी समाधान है।^१

भारत में श्रम-विधान

२२ भारत में श्रम-विधान का उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ क्षेत्र—भारत में श्रम विधान इंग्लैण्ड-जैसे औद्योगिक देश के समान महत्वपूर्ण नहीं है। कारण यह है कि यहाँ यान्त्रिक शक्ति का प्रचार और प्रभाव-क्षेत्र सीमित है। उद्योगीकरण के दुर्गुणों को दूर करने के लिए दृष्टापूर्वक सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है, चाहे इसमें उद्योगीकरण में थोड़ी बाधा हो पहुँचे। अब तक हम यूरोपीय देशों के अनुभव से लाभ उठाने में अमफल रहे हैं। अज्ञानता का बहाना किये बिना ही हमने अपने बीच अनेक दुर्गुण ही रहन दिए हैं, जैसे स्वामि वाले शहरों का बनना, शिशु-श्रम का शोषण, काम के अधिक लम्बे घण्टे, सफाई की कमी, सुरक्षा का अभाव इत्यादि। इन्हें दूर करने का हम अब प्रयास कर रहे हैं।

२३ श्रम विधान की एकत्पता की आवश्यकता—१९३५ के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार स्थापित प्रान्तीय स्वतन्त्रता के साथ ही प्रान्तों में लोकप्रिय मन्त्रिमण्डलों का शासन प्रारम्भ हुआ। इन्होंने श्रम की स्थिति के सुधार पर जोर दिया। इससे अनेक प्रान्तीय सरकारों के श्रम अधिनियम में एकत्पता का अभाव भी स्पष्ट रूप से लक्षित होना लगा। एकत्पता का अभाव निश्चित रूप से औद्योगिक प्रगति के लिए घातक है, विशेषकर उन प्रान्तों के लिए जो औद्योगिक विकास में आगे बढ़े हुए हैं। इस प्रश्न पर श्रम-मन्त्रियों और राज्य-प्रशासकों (स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर्स) के प्रथम सम्मेलन में विचार किया गया। सम्मेलन ने निश्चय किया कि केन्द्रीय सरकार चार प्रमुख विषयों पर कानून बनाए (औद्योगिक भण्डे, संवेतन छुट्टियाँ, श्रम और उद्योग-सम्बन्धी आकों का सक्शन और पारिश्रमिक देने के अधिनियम का सशोधन), जिन पर प्रान्तों और श्रम मन्त्रियों के दूसरे सम्मेलन द्वारा विचार किया जाए।

२४. भारत में फँकड़ी विधान का प्रारम्भ—अम्बई में काम-उद्योग की प्रगति से लकानायर के निमाण करन वालों की ईव्या जाग उठी। इन्होंने आन्दोलन खड़ा किया,

१. दलित, रिप, १० २३७।

२. दलित, भाग १, अन्वय १०, मेम्बरन ११।

जिसका दिखावटी उद्देश्य तो भारत के श्रमिकों को लाभ पहुँचाना था, किन्तु अन्तिम उद्देश्य भारत के उद्योगपतियों के मार्ग में बाधाएँ खड़ी करना था। इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप १८७५ में बम्बई सरकार ने कारखाना आयोग की नियुक्ति की। फलस्वरूप १८८१ में प्रथम फँवट्री अधिनियम पास हुआ।

प्रथम कारखाना अधिनियम के पास होते ही उसमें परिवर्तन करने के लिए आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। किन्तु लकाशायर के हितों के दबाव के कारण राज्य-सचिव (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) ने हस्तक्षेप किया और १८९१ में एक और भी कठोर अधिनियम पास किया गया। यह कानून कम से-कम पचास व्यक्तियों द्वारा शक्ति-परिचालित कारखानों तक लागू होता था। परन्तु स्थानीय सरकारों को इसे बीस व्यक्तियों वाले कारखानों पर भी लागू करने का अधिकार था। बच्चों के लिए निम्न और ऊर्ध्व-आयु की सीमाएँ क्रमशः ९ और १४ हो गईं। उनके काम के घण्टे किसी भी दिन ७ से ज्यादा नहीं हो सकते और वह भी ५ बजे प्रातः से ८ बजे सायंकाल के बीच में ही हो सकते थे। औरतें किसी भी कारखाने में ८ बजे के बाद और ५ बजे से पहले काम नहीं कर सकती थी।

२५. १९११ का कारखाना अधिनियम (फँवट्री एक्ट)— १९११ का फँवट्री एक्ट पास हुआ। इसके अन्तर्गत ४ महीने से कम समय तक काम करने वाले मौसमी कारखाने भी आ गए। इसमें आयु प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया और सूत की मिलों में काम करने वाले बाल श्रमिकों की कार्यावधि ६ घण्टे कर दी गई। इस अधिनियम द्वारा कपास से बिनोला निकालने और उसे दवाने के काम को छोड़कर औरतों का रात में काम करना बन्द कर दिया गया। प्रथम बार प्रौढ पुरुषों के घंटे बँध रूप से नियमित किये गए, जिसके अनुसार कपास की मिलों में १२ घंटे दैनिक काम करने की व्यवस्था की गई। जिन कारखानों में पारी-प्रथा (शिफ्ट सिस्टम) है उन्हें छोड़कर कपास के कारखानों में कोई भी व्यक्ति प्रातः ५ बजे से पहले और रात्रि में ७ बजे के बाद काम पर नहीं लगाया जा सकता—ये सीमाएँ विशेष रूप से औरतों और बच्चों के लिए थी। अन्त में स्वास्थ्य और सुरक्षा की व्यापक व्यवस्थाएँ की गईं तथा फँवट्री का निरीक्षण और अधिक प्रभावपूर्ण बना दिया गया।

२६. १९२२ का कारखाना अधिनियम— १९१९ में वाशिंगटन में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की मान्यताओं को स्वीकार करने के कारण भारत में श्रम-विधान सम्बन्धी अन्य परिवर्तन आवश्यक हुए। १९२२ के कारखाना अधिनियम (फँवट्री एक्ट) के अनुसार २० से अधिक व्यक्तियों द्वारा शक्ति से परिचालित सभी कारखाने अधिनियम की परिधि में आ गए। स्थानीय सरकारों को स्वतन्त्रता दी गई कि वे इसे दस से अधिक व्यक्तियों वाले कारखानों पर भी लागू कर सकती थी, चाहे उनमें विद्युत्-शक्ति का उपयोग होता हो या नहीं। काम करने वाले बच्चों की निम्नतम आयु १२ और उच्चतम १५ वर्ष कर दी गई। इनके काम के घंटे छह तक सीमित कर दिए गए। बच्चे और औरतें सुबह ५^३/_४ बजे से पहले और शाम के ७ बजे के बाद काम पर नहीं लगाये जा सकते थे। प्रौढ पुरुषों के काम के घंटे ६० घंटे प्रति सप्ताह और ११ घंटे

प्रतिदिन से अधिक नहीं हो सकते थे। सप्ताह ६ दिन से अधिक का नहीं हो सकता था। सभी वर्ग के श्रमिकों के लिए मध्याह्न और विश्राम का आयोजन किया गया। ६ घंटे के बाद १ घंटे का विश्राम आवश्यक घोषित किया गया। इसे श्रमिकों की प्रार्थना पर $\frac{1}{2}$ घंटे के दो विश्रामों में विभाजित किया जा सकता है, यदि लगातार ५ घंटे से अधिक काम न किया जाता हो। निरीक्षण की पद्धति में और सुधार कर दिया गया। पूरे समय तक काम करने वाले निरीक्षकों की नियुक्ति की गई। सुरक्षा और स्वास्थ्य से सम्बन्धित धाराएँ और व्यापक बना दी गईं। स्थानीय सरकारों को प्रकाश और कृत्रिम नमीकरण के मानदण्ड स्थिर करने के अधिकार दिये गए।

२७. १९३४ का कारखाना अधिनियम, १९४६ का सशोधन तथा १९४८ का अधिनियम—१९२२ के अधिनियम में १९२३, १९२६ और १९३१ में सशोधन करके कितनी ही प्रशासकीय कठिनाइयाँ दूर कर दी गईं। कुछ मामूली सुधार भी किये गए। १९३४ में एक नवीन अधिनियम पास किया गया। श्रम-आयोग की सिफारिश पर पास किया गया यह अधिनियम १ जनवरी, १९३५ में लागू किया गया। यह अधिनियम

(१) वर्ष-भर चालू रहने वाले और मौसमी कारखानों में भेद स्थापित करता है।

(२) १५ और १७ वर्ष की आयु वाले के एक तृतीय किशोर-वर्ग को स्थापना करता है, जिन्हें बच्चों के काम के उपयुक्त न समझा जान पर बच्चा समझा जाएगा।

(३) मौसमी कारखानों में काम करने वाले के लिए ११ घण्टे प्रतिदिन और ६० घण्टे प्रति सप्ताह की सीमाएँ अब भी लागू हैं। किन्तु वर्ष-भर चालू रहने वाले कारखानों के श्रमिकों के सम्बन्ध में सीमाएँ १० घण्टे प्रतिदिन और ५४ घण्टे प्रति सप्ताह कर दी गईं। बच्चों के लिए सर्वत्र ५ घण्टे प्रतिदिन की व्यवस्था है।

(४) प्रथम बार प्रसार का सिद्धान्त व्यवहार में लाया गया, अर्थात् लगातार काम करने की सीमा पुरुषों के सम्बन्ध में १३ और बच्चों के सम्बन्ध में ७ $\frac{1}{2}$ घण्टे कर दी गई।

(५) कृत्रिम नमीकरण की वर्तमान धाराएँ और व्यापक बना दी गईं। इस अधिनियम द्वारा स्थानीय सरकारों को एक निरीक्षक नियुक्त करने का अधिकार दिया गया, जिसका कार्य सब कारखानों के प्रबन्धकों को हवा में ठण्डक बढ़ाने का प्रबन्ध करने का निर्देश देना और पालन कराना था।

(६) भलाई के लिए भी कुछ व्यवस्थाएँ की गई हैं। उदाहरण के लिए कारखानों में विश्राम के लिए समुचित व्यवस्था, जिनमें स्त्री और बच्चों के लिए कमरे सुरक्षित रहे और प्राथमिक सहायता की व्यवस्था आदि।

(७) स्थानीय सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे कार्य-समयों के सम्बन्ध में नियम बनाएँ और उन बच्चों को कारखानों में काम न करने दें जो काम करने के अयोग्य प्रमाणित किये गए हैं।

(८) निरीक्षकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे प्रबन्धकों से कारखानों

के निर्माण के ऐसे दोष दूर करने के लिए कहे जिनसे काम करने वालों को खतरा पहुंचता हो।

(६) निर्धारित समय से अधिक समय तक काम करने की सीमाएँ निर्धारित कर दी गई हैं। उसका वेतन भी नियमित है। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत में वर्ष-भर चासूरहने वाले कारखानों में ४८ घण्टे का सप्ताह होता है। प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वे चाहे तो जनता के हित में इस सीमा को बढ़ा सकती हैं।

१९४८ का फ़ैक्ट्रीज़ एक्ट १ अप्रैल १९४९ में लागू किया गया। इसके अन्तर्गत दस या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा परिचालित शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा बीस या बीस से अधिक व्यक्तियों द्वारा चालित परन्तु शक्ति का प्रयोग न करने वाले सभी कारखाने आ जाते हैं। राज्यों की सरकारों व्यक्तियों की संख्या तथा शक्ति के प्रयोग के प्रति निरपेक्ष होकर इस कानून की धाराओं को जहाँ उचित समझे लागू कर सकती हैं। ये नियम केवल वही लागू न होंगे जहाँ एक व्यक्ति बाहरी मजदूरों को लगाए बिना केवल अपने परिवार की सहायता से काम कर रहा हो। अब मौसमी और वर्ष भर चलने वाले कारखानों वाला भेद हट गया है।

राज्य की सरकारों को कारखानों की रजिस्ट्री और अनुज्ञा देने के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। इस नियम के अनुसार कारखाने के मालिक को कारखाना लेते समय कारखानों के प्रधान निरीक्षक के पास उसका पूर्ण विवरण भेजना चाहिए।

२८ बम्बई की दुकानों और वाणिज्यिक संस्थापन-सम्बन्धी अधिनियम (१९३६) (द्वि बॉम्बे शॉप्स एण्ड कर्माशयल एस्टाब्लिशमेण्ट्स एक्ट)—बम्बई की कांग्रेस सरकार ने एक नया श्रम-विधान प्रारम्भ किया। इस विषय में इतने अन्य प्रान्तों की अनु-आई की। वाणिज्य और उपभोक्ताओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसका उद्देश्य दुकानों, रेस्तराँ, थियेट्रो और अन्य संस्थानों में काम के घण्टों का नियन्त्रण करना है। इसका उद्देश्य काम के लम्बे घण्टों—११ से १५ घण्टों तक—और छुट्टियों की अपर्याप्त व्यवस्था तथा विश्राम की कमी का निराकरण करना है। जहाँ तक दुकानों का सम्बन्ध है, काम के अधिकतम घण्टे ६½ हैं। ५ घण्टे के काम के बाद ३ घण्टे का विश्राम और सप्ताह में १ दिन की छुट्टी आवश्यक है। बम्बई के कानून में १९४६ में संशोधन किया गया।

१९५८ में विभिन्न राज्यों में निम्न अधिनियम पास किये गए—राजस्थान का दुकान और वाणिज्यिक संस्थापन अधिनियम, मध्य प्रदेश का दुकान और वाणिज्यिक संस्थापन अधिनियम, पंजाब का दुकान और वाणिज्यिक संस्थापन अधिनियम। इनके अलावा केरल और मंसूर में दुकानों और वाणिज्यिक संस्थापनों में कार्य की दशाओं को सुधारने तथा तत्सम्बन्धी विधान को समोचित करने के लिए विल प्रकाशित किये गए ताकि जनमत का संग्रह हो सके। उड़ीसा की सरकार ने १९५६ में पास किये गए उड़ीसा के दुकान और वाणिज्यिक संस्थापन अधिनियम की धारा १२ और १४

को सशोधित किया। इनका सम्बन्ध कटौती तथा हटाने से पूर्व कर्मचारी को नोटिस देने से था। १९५८ में मद्रास आहार-प्रदान (केटरिंग) संस्थापन अधिनियम पास हुआ। इस नियम के लागू होने के पश्चात् आहार-प्रदान संस्थापन साप्ताहिक छुट्टी अधिनियम १९४२, कारखाना अधिनियम १९४८ तथा मद्रास के दुकान और वाणिज्यिक संस्थापन अधिनियम १९४७ से मुक्त हो गए।

२६. चाय के तिलो के प्रवासी श्रम अधिनियम १९३२ (दि टी डिस्ट्रिक्ट्स एम्प्लेंट लेबर एक्ट)—वाग लगाना औद्योगिक श्रम से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है, परन्तु इसकी कुछ अपनी समस्याएँ हैं जो विशेष रूप से आसाम के चाय के बगीचों के लिए श्रमिकों को भरती से सम्बन्धित हैं। चाय के बगीचे लगाने वाले श्रमिकों की नियुक्ति-सम्बन्धी मामले उपर्युक्त अधिनियम द्वारा नियन्त्रित होते हैं। १९३२ का अधिनियम श्रम-प्रायोग की सिफारिशों पर आधारित है। यह सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत (जिसमें म्यांमार परगना भी शामिल है) में लागू होता है। १९३२ के नियम का प्रथम उद्देश्य नियुक्ति पर नियन्त्रण करना, सहायता-प्राप्त प्रवासियों को आसाम के चाय बगीचों की ओर भेजना तथा यह देखना या कि उनके ऊपर अनुचित प्रतिबन्ध न लगाए जाएँ। भारत सरकार के नियन्त्रण में स्थानीय सरकारों को यह अधिकार दिया गया कि वे सहायता-प्राप्त प्रवासियों के ऊपर नियन्त्रण रखें। नियुक्तियों को प्रमाण-प्राप्त बगीचों के सरदार अथवा अनुज्ञा-प्राप्त भरती करने वालों के अलावा अन्य किसी माध्यम द्वारा भरती करने से रोका गया। १६ साल से नीचे के व्यक्तियों को प्रवास में सहायता देना अवैध घोषित किया गया, जब तक कि वे अपने माता-पिता या अग्नि-भावकों के साथ न हों। जहाँ तक फिर से लौटने का सम्बन्ध है, प्रत्येक प्रवासी श्रमिक आसाम में आने के तीन वर्ष बाद लौटने का अधिकारी है, भले ही किसी नियुक्ताने उसे पुनः नौकर रख लिया हो। तीन साल के पहले भी लौटना सम्भव था, परन्तु यह ऐसी दशा में ही हो सकता था जबकि प्रवासी का स्वास्थ्य खराब हो रहा हो, या उसे नमुचित काम न मिला हो, या उसकी मजदूरी रोक ली गई हो, या और कोई पर्याप्त कारण हो।

फलतः केन्द्रीय सरकार ने १९३३ में चाय के बगीचों के प्रवासी श्रम नियम बनाए। सन् १९५५ में एक अधिसूचना द्वारा इन्हें सशोधित किया गया। इन मसौघों में श्रम का पूर्णतया भारतीय रेल मार्ग द्वारा आनाम भेजना, भरती करने वालों को दण्ड देने की व्यवस्था, श्रमिकों के वापस जाने के अधिकारों की रक्षा आदि वाते सम्मिलित थी। १९५१ के लेबर एक्ट के अनुसार चाय कट्टे के बगीचों में काम करने वाले मजदूरों की मकानों तथा वस्त्रों की देख-रेख, शिक्षा तथा मनोरंजन का साधन बनाया गया। इस अधिनियम को १९६१ में सशोधित किया गया जिससे मानिक देयता से छुटकारा न पा सके।

३०. लानों के लिए श्रम-विधान—जपान के उद्योग की अपेक्षा खानों ने श्रमिकों के सम्बन्ध में श्रम-विधान काफी धीरे-धीरे प्रारम्भ हुआ। १९०१ में पहला भागतीय खान अधिनियम (इण्डियन माइन्स एक्ट) पास हुआ और निरीक्षकों की नियुक्ति हुई।

१९०१ के अधिनियम (जो कि १९२३ में संशोधित किया गया था) के अनुसार भारत सरकार को जो अधिकार मिले थे उनका उपयोग करते हुए उसने १९२६ में नियम बनाए, जिनका उद्देश्य उसी समय से खान के अन्दर औरतो का काम करना बन्द कर देना था। वे केवल इन अधिनियमों से मुक्त खानों, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा मध्यप्रान्त की कोयले की खानों और पंजाब की नमक की खानों, में काम कर सकती थी। उपर्युक्त खानों को भी धीरे-धीरे इन नियमों की मुक्ति से अलग करने की व्यवस्था थी, ताकि १ जुलाई १९३६ तक औरतो का खानों के अन्दर काम करना एकदम बन्द हो जाए। युद्धकालीन उत्पादन की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खान के अन्दर औरतो के काम करने पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया था वह १९४३ में कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया, परन्तु फरवरी, १९४६ में फिर से लागू कर दिया गया। १९२३ के अधिनियम में काम के दैनिक घण्टों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। १९२८ (मार्च) में एक संशोधन-नियम पास किया गया। इसके अनुसार किसी भी खान के कर्मचारियों के एक ही समूह द्वारा किसी भी खान में १२ घण्टे से अधिक काम नहीं कराया जा सकता था। यह व्यवस्था भी की गई कि मालिक कार्यालयों के सामने काम के घण्टों को निर्धारित करने वाले नोटिस लगाएँ। १९३५ के संशोधन अधिनियम द्वारा निम्न परिवर्तन हुए।

कोई भी व्यक्ति खान में एक हफ्ते में ६ दिन से अधिक काम नहीं कर सकता। खान के ऊपर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हफ्ते में ५४ घण्टे से अधिक काम नहीं कर सकता। एक दिन में १० घण्टे से अधिक कोई भी व्यक्ति काम नहीं करेगा। कार्य काल इस प्रकार होगा कि विश्राम काल को लेकर वह एक दिन में १२ घण्टे से अधिक नहीं होगा। उसे ६ घण्टे लगातार काम करने के बाद १ घण्टे का विश्राम अवश्य मिलेगा। खान के अन्दर काम करने वाले व्यक्ति को एक दिन में ६ घण्टे से अधिक काम नहीं करना होगा। खान के अन्दर एक ही प्रकार का काम ६ घण्टे से अधिक नहीं किया जाएगा। यदि बारी-बारी से काम करने की पद्धति हो तो उसे अपवाद माना जा सकता है, किन्तु इसमें भी एक वार में ६ घण्टे से अधिक काम नहीं होगा। खान के अन्दर १५ साल से कम उम्र के बच्चों को काम करने की मनाही है।

१९३७ में एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति हुई जिसका काम दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करना था। समिति का कोयलो की खानों का विवरण उद्धृत करने योग्य है—“संक्षेप में एक खेल के रूपक का उपयोग करने पर यह कहा जा सकता है कि कोयले की खान का काम भारतवर्ष में एक दौड़ के समान है, जिसमें लाभ हमेशा प्रथम रहा है। बेचारी सुरक्षा ‘द्वितीय’, अच्छी पद्धतियाँ ‘नाम के लिए दौड़ने वाली’ तथा राष्ट्रीय हित एक ‘मृत अश्व’ के समान रहा है, जिसका नाम तो दर्ज कर लिया गया किन्तु जो दौड़ न सका।”

१९४८ में नये फ्रैंचूटी कानून पास हो जाने के बाद खानों में काम करने वाले श्रमिकों से सम्बन्धित विधान को संशोधित करना आवश्यक हो गया। इस उद्देश्य से ८ दिसम्बर, १९४६ को खानों में काम करने वाले श्रमिकों के विधान

में संशोधन करने के लिए एक विल पेश किया गया जो १५ मार्च, १९५२ को पास होकर १ जुलाई, १९५२ से लागू किया गया। जम्मू और काश्मीर को छोड़कर यह कानून सारे भारत पर लागू है। इस कानून के अन्दर खानों की परिभाषा और विशद रूप से दी गई। मजदूरों की सुरक्षा तथा भलाई के विषय में भी विशद व्यवस्थाएँ की गईं। इस कानून के अनुसार खान के ऊपर काम करने वाले श्रमिकों का काम ६ घण्टे प्रतिदिन तथा ४८ घण्टे प्रति सप्ताह कर दिया गया। खान के भीतर काम करने वाले श्रमिकों की अवधि ८ घण्टे प्रतिदिन तथा ४८ घण्टे प्रति सप्ताह कर दी गई। स्त्रियाँ खानों के ऊपर शाम के ७ बजे से प्रातः ६ बजे तक काम नहीं करेगी। केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में योडा-वट्टन परिवर्तन कर सकती है, परन्तु वह रात्रि के १० बजे और प्रातः ५ बजे के बीच स्त्रियों और वयस्कों का काम करना बंध नहीं कर सकती। इस कानून में सेवेतन छट्टियों की भी व्यवस्था है।

खानों में काम करने वाले मजदूरों की भलाई के लिए एक प्रकार का कोष खोला गया है जो ५६ सस्यामों, ६१ वयस्कों की शिक्षा के लिए तथा ५६ स्त्रियों की भलाई के लिए बुद्ध आराम-गृह चला रहा है। इसकी वार्षिक आमदनी ३५ करोड़ है। इसी प्रकार १९६१ के एक्ट के अनुसार (Iron Ore Mines Labour Welfare Cess) इनमें काम करने वालों की हालत को बचले और मायका जैसा बनाया गया। ३१. रेलवे के श्रमिकों से सम्बन्धित अधिनियम—रेलवे के सभी कारखाने १९२२ के कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। भारत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सभा के प्रति अपने परिणियत कर्तव्यों को पूरा कर सका। इसके अनुसार कोई भी रेलवे कर्मचारी, एक सप्ताह में ६० घण्टे से अधिक काम न करेगा। ऐसा रेलवे कर्मचारी, जिसका काम स्यायी नहीं है, ८४ घण्टे से अधिक काम नहीं करेगा। उपर्युक्त व्यवस्थाओं से असुविधाएँ दूर हो सकती हैं (१) ऐसी कठिन परिस्थिति में जबकि रेलवे के काम में कोई भयकर बाधा उपस्थित हो गई हो, (२) या कार्यभार अत्यन्त अधिक हो। परन्तु ऐसी दशा में अधिक समय तक काम करने का वेतन मिलेगा। सप्ताह में लगभग २४ घण्टे का विश्राम आवश्यक था। इसमें कभी-कभी, उदाहरणार्थ उपर्युक्त परिस्थितियाँ आने पर, व्यक्तिगत हो सकता है। गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल को रेलवे श्रम के निरीक्षकों की नियुक्ति का अधिकार था, ताकि वह इस बात का पता लगा सके कि कानून की धाराओं का पालन हो रहा है या नहीं।

३२ सन् १९२३ का श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून (संशोधित रूप में)—प्रायः सभी पाश्चात्य देशों में इस बात को बंध स्वरूप प्राप्त हो गया है कि यदि श्रमिक नियमित घण्टों के बीच किसी कर्मचारी को काम करते समय किसी प्रकार की शारीरिक हानि पहुँचे तो उसे क्षतिपूर्ति दी जाए। भारत में क्षतिपूर्ति देने के विचार की प्रगति धीमी रही है। १९२३ के अधिनियम के पूर्व दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर १८८५ के धानक दुर्घटना अधिनियम (फेटल एक्सीडेंट्स एक्ट) के अन्तर्गत निधोचना पर मुकदमा दायर किया जा सकता था, परन्तु इस अधिनियम का शाब्द ही कभी प्रयोग किया गया हो। इसके अतिरिक्त नियोजना का उत्तरदायित्व भी अनिश्चित था।

१९२३ के अधिनियम का सिद्धान्त यह था कि दुर्घटना से घायल हुए कर्मचारियों को मुआवजा दिया जाएगा, यदि दुर्घटना काम करते समय हुई हो। कुछ हालतों में बीमारियों के लिए भी मुआवजा (क्षतिपूर्ति) दिया जाता था।

१९३३ के अधिनियम के अन्तर्गत रेलवे, ट्रामवे, कारखाने, खानों, सामुद्रिक व्यक्ति, बन्दरगाह, सड़को या इमारतों, सुरंगों और पुलों की भरम्भन या निर्माण या उन्हें गिराने के काम में लगे व्यक्ति, सामुद्रिक कार्य, तार, टेलीफोन से सम्बन्धित काम या विजली के तार उखाड़ना या खोदना, नौ-सेना, प्रकाश-स्तम्भ, चाय, कॉफी, रबर या सिनकोना के बगीचे, विद्युत् या गैस बनाने के स्टेशन, सिनेमा कर्मचारी, वेतन-प्राप्त मोटरों के ड्राइवर तथा जमीन को नीचे बहने वाली नालियों की सफाई करने वाले कर्मचारी आदि सभी आते हैं। इन सभी कामों में लगे हुए प्रशासकीय या वावूगीरी (क्लेरीकल) ढग के काम करने वाले तथा ३०० रुपये से अधिक वेतन पाने वाले लोग इसमें शामिल नहीं हैं।

वास्तविक आश्रितों को ही मुआवजा मिलेगा, जैसे पत्नी या अबधस्क (नाबालिग) पुत्र। दूसरे वे लोग, जो इस परिस्थिति में नहीं हैं, जैसे पति या माता-पिता आदि। ऐसी व्यवस्था की गई है कि घातक दुर्घटनाओं से आश्रितों का हित अच्छी तरह सुरक्षित रहे। यह भी प्रबन्ध है कि ये दुर्घटनाएँ आयुक्तों के सामने भी लाई जाएँ, जो प्रान्तीय सरकारों द्वारा कानून के अन्दर नियुक्त किये जाते हैं।

इस अधिनियम का प्रशासन और भगडों का निर्णय इन्हीं आयुक्तों को सौंपा गया है जिन्हें बहुत अधिकार दिये गए हैं। क्रिया-पद्धति सीधी है और अपील करने के अवसर सीमित हैं। इस प्रकार के विधान की सफलता के लिए कुशल डॉक्टरों द्वारा चोट की ठीक-ठीक जांच और रिपोर्टों की आवश्यकता है, साथ ही सरकार द्वारा निष्पक्ष जजों की नियुक्ति भी आवश्यक है ताकि श्रमिक अपना उचित प्राप्य (लाभ) पा सकें। भारतीय श्रमिक की प्रवासी प्रवृत्ति, कानून के अन्दर प्राप्य आर्थिक सहायताओं के विषय में अज्ञान तथा श्रमिकों के पक्ष की मुआवजे के लिए प्रस्तुत कर सकने वाले व्यक्तियों का अभाव—इन सब कारणों से यह विधान कठिनता से लागू हो पाता है। १९४६ के मुआवजा (सशोधन) विधान ने मुआवजा पाने वालों की वेतन की सीमा ३०० रु० से बढ़ाकर ४०० रु० कर दी है और इनके बीच की घामदनी के लिए मुआवजे की दर भी निर्धारित कर दी है।

यह कहा जा सकता है कि नियोजकों के भय के विपरीत इस मुआवजा अधिनियम से उत्पादन लगत में कृद्धि नहीं हुई है, परन्तु सुरक्षा का स्तर काफी ऊँचा हो गया है। इस अधिनियम में पुनः सशोधन करने के लिए २४ सितम्बर १९५८ को राज्यसभा में एक बिल पेश किया गया। इस बिल में निम्न सशोधनों की व्यवस्था है (क) क्षतिपूर्ति के लिए बयस्क और अल्पवयस्क का भेद मिटाना, (ख) सात दिन के प्रतीभा काल को घटाकर तीन दिन करना तथा जहाँ कार्य-योग्य न रहने का समय अट्टहास या और अधिक दिन हो, अयोग्य होने के दिन से क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था करना तथा (ग) अनुमूची 1, II, III के क्षेत्र का विस्तार करना।

३. सामाजिक बीमा—औद्योगिक श्रमिक की सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा का अद्वान्न औद्योगिक दृष्टि से विकसित जर्मनी और ब्रिटेन-जैसे सभी देशों में स्वीकार किया गया है। इसमें श्रमिकों को होने वाली कठिनाइयों, जैसे बीमारी, वृत्तिहीनता, दवावस्था आदि, से बचाने की व्यवस्था है। बम्बई की कांग्रेस सरकार ने सामाजिक बीमा के विकास की एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की तथा इस बात पर भी विचार किया कि बीमारी के समय में भी वेतन दिया जाए। यह इस आशा से किया गया कि इससे बीमारी के बीमों का मार्ग प्रशस्त होगा।^१

गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल ने १९४४ में एक श्रम जांच समिति (लबर इन-वेस्टिगेशन कमेटी) नियुक्त की। इसने ३६ उद्योगों की विस्तृत तथ्य स्यापक जांच की। इस समिति द्वारा प्राप्त तथ्यों ने नीति-निर्धारण को पुष्टि आधार प्रदान किया। सामाजिक बीमा की योजनाओं के सम्बन्ध में विचारणीय महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उद्योग इस प्रकार से पड़े हुए भार को कहां तक सह सकता है? यह वाञ्छनीय है कि सामाजिक बीमा की योजनाएँ अन्य देशों की योजनाओं के समान अशदायी हों और श्रमिक, नियोक्ता तथा सरकार तीनों ही अपना-अपना न्यायोचित भार वहन करें।

श्रमिक राज्तीय बीमा अधिनियम (एम्प्लॉईड स्टेट इश्योरेंस एक्ट), जोकि अप्रैल, १९४८ में पार किया गया, में इस बात की व्यवस्था है कि बीमारी और काम के समय लगी चोट आदि के सम्बन्ध में अनिवार्य राज्तीय बीमा हो तथा ४०० रु० माहवार से कम पाने वाली स्त्रियों को प्रसूति-सहायता प्राप्त हो, चाहे वे हाथ का काम करती हों या बाबूगिरी (ब्लर्की)। राज्य सरकारों को अस्पताल द्वारा देख-रेख और दवा का व्यय संभालना होगा। बीमारी के लिए नकद सहायता एक वर्ष में अधिक-से-अधिक आठ सप्ताह मिलेगी। काम में लगने वाली चोट से उत्पन्न अयोग्यता के समय अयोग्यता-सहायता (डिसेबलमेण्ट बेनीफिट) प्राप्त होगी। कुछ दशाओं में विधवाओं, पुत्रों और पुत्रियों को 'आश्रितों की सहायता' देने की भी व्यवस्था की गई है।

१९५१ के सशोधन के अनुसार नियोक्ताओं का अशदान उनके द्वारा दी जाने वाली कुल मजदूरी का ३/१० निश्चित कर दिया तथा १/२० इसके अलावा निश्चित किया। इस प्रकार नियोक्ताओं का अशदान अब ११/१० है।

इस स्कीम को १०० से अधिक केन्द्रों में लागू किया गया है और १७ लाख मजदूरों को बीमा से लाभ पहुँचाया गया है। तीसरी योजना में ३० लाख मजदूरों को लाभ पहुँचेगा।

३४ भारत में औद्योगिक श्रमिकों का इतिहास—१९१७ से पहले भारत में हड़तालें प्रायः नहीं होती थीं। १९०५ में बम्बई में कई हड़तालें हुईं, जिनका कारण बिजली का प्रचार था, जिससे काम बहुत अधिक समय तक सम्भव था। १९१९-२० में जब

१. लैबर गजट (बम्बई), अगस्त १९३७, पृ० ६१ ।

बम्बई में कपास की मिलों के १,५०,००० श्रमिकों की बड़ी हड़ताल हुई, तब से स्थिति विशेष रूप से सकटापन्न हुई। इन हड़तालों के सहायक कारणों में काम के लम्बे घण्टे, आवास की बुरी परिस्थितियाँ, चोट के खिलाफ मुआवजों की अव्यवस्था, सरदारों (फोरमन) द्वारा श्रमिकों के साथ होने वाला दुर्व्यवहार तथा एक वर्ग की हड़ताल की अन्य वर्ग की हड़तालों के साथ सहानुभूति आदि का नाम लिया जा सकता है।

१९१६-२१ में हड़ताल की स्थिति अधिक भयंकर हो गई। परिणाम यह हुआ कि औद्योगिक केन्द्रों में हड़तालों की एक लहर आ गई। १९२६-२७ अपेक्षाकृत शान्त वर्ष थे। १९२८ में औद्योगिक अशांति पुनः उत्पन्न हो गई और त्रितनी ही बड़ी-बड़ी हड़तालों हुई। उदाहरण के लिए, बम्बई की कपास की मिलों की बड़ी हड़ताल (अक्टूबर, १९२८) का नाम लिया जा सकता है। १९२९ में पूर्ण वर्ष की औद्योगिक हलचल जारी रही तथा साम्यवादी प्रभाव स्पष्टतः लक्षित हुए। बम्बई में फिर एक सम्पूर्ण हड़ताल रही। इन तूफानी वर्षों के बाद कुछ समय तक देश-भर में शान्ति रही। १९२९-३३ के आर्थिक अवसाद में मजदूरी में कटौती हुई और कुछ हड़तालों भी हुई। बम्बई की सरकार ने प्रान्त में मजदूरी में कटौती के प्रश्न पर वैभाषिक जांच प्रारम्भ की। १९३४ में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसी समय अर्ध-साधारण हड़ताल, जो बम्बई की मिलों में चालू थी, समाप्त कर दी गई। इस जांच का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम बम्बई सरकार द्वारा ट्रेड डिसप्लूट्स कमीशन एक्ट पास किया जाना था। इसकी समीक्षा आगे सेक्शन ३७ में की गई है। इस अधिनियम के पास होने के तीन वर्ष बाद तक बम्बई नगर की कपास की मिलों में हलचल न रही। १९३७ में बम्बई, अहमदाबाद, कानपुर और मद्रास-जैसे औद्योगिक केन्द्रों में फिर श्रम-अशांति प्रारम्भ हो गई। इसका कारण औद्योगिक एवं व्यापारिक समुत्थान के आधार पर ऊँचे वेतन की माँग तथा कटौती की पूर्ति और अशत साम्यवादियों द्वारा भड़काया जाना था। श्रमिक वर्ग में फैला हुआ भीषण असन्तोष, यद्यपि पहले वर्ष में ही उनकी दशा सुधारने के नियम पास हो चुके थे, १९३७-३८ में हुई बड़ी हड़तालों के रूप में प्रकट हुआ।

३५. १९३६ के पश्चात् औद्योगिक अगड़ें— १९३६ में ऋगडों की औसत संख्या ४०६ थी। यह उस समय तक की उच्चतम संख्या थी।^१ बम्बई में ऋगडों की संख्या १९४२ में और भी अधिक अर्थात् ६९४^२ थी। युद्ध के उपरान्त श्रम-अशांति का प्रधान कारण मूल्यों तथा जीवन-स्तर में वृद्धि थी जो कि प्रधानतया मुद्रास्फीति के कारण थी। मजदूरी और कीमतों के बीच होने वाली दौड़ में मजदूरी सदैव पीछे रह गई। इस स्थिति पर तभी काबू पाया जा सकता है जबकि कीमतें नियन्त्रित और स्थिर

१. बम्बई का श्रम गजट, जून १९४०, पृ० ८६६।

२. सन् १९४६ में अगस्त के महीने तक केवल बम्बई नगर में ही ३०० से अधिक हड़तालों हुईं। अन्य श्रम-केन्द्रों में इसी प्रकार प्रभावित थे।

कर दी जाएं। यद्यपि अनेक उद्योगों में अभूतपूर्व लाभ हुए परन्तु सामान्य रूप से श्रमिकों की दशा गिरती ही गई। हड़तालों का भूत सवार हो गया और देश में श्रम-असन्तोष की लहर सी आ गई। इसका कारण राजनीतिक एवं सामाजिक भी है और अशत साम्यवादियों की क्रियाएँ भी हैं, लेकिन प्रधान कारण कीमतों और मजदूरी के बीच की गहरी खाई ही है।^१

३६. औद्योगिक झगड़ों की रोक-थाम—औद्योगिक झगड़ों को निपटाने के लिए स्थापित यन्त्र की विवेचना करने से पूर्व उन्हें रोकने के सम्बन्ध में दो शब्द कह देना उचित होगा। इन्हें रोकने के लिए नियोक्ताओं और श्रमिकों का दृढ़ संगठन पहली आवश्यक वस्तु है। भारत में नियोक्ता प्रायः अचञ्ची तरह संगठित हैं, लेकिन श्रमिकों की दशा ऐसी नहीं है, अतः मजदूर श्रम-सघों की आवश्यकता है। दोनों पक्षों के सुदृढ़ सघों (जो अपने-अपने पक्ष के लिए अचञ्ची तरह श्रेय सक्त हैं) के निर्माण से यन्त्र-तन्त्र होने वाली हड़तालों और काम-बन्दी रुक जाएगी। साथ ही हड़ताल करने के पहले ही माँगों की रूपरेखा तैयार हो जाएगी न कि हड़ताल करने के बाद, जो भारतीय हड़ताल की प्रधान विशेषता है। अहमदाबाद की कपड़े की मिलों के झगड़ों में मध्यस्थता करने के लिए एक स्थायी मध्यस्थ परिषद् (आरबीट्रेशन बोर्ड) की स्थापना की गई है।

अब हम झगड़ों को तय करने के लिए मध्यस्थता और समझौते के तरीकों की विवेचना करेंगे। १९१४-१८ के बाद हुए अनेक झगड़ों से उन्हें मुलभाने और जाँच करने के लिए उचित साधन की आवश्यकता स्पष्ट हो गई। इस ओर सबसे पहला कदम मद्रास सरकार ने उठाया। १९२१ में बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त तथा १९२२ में बम्बई सरकार द्वारा नियुक्त समितियों ने बहुत अच्छा प्रारम्भिक काम किया और झगड़ों के निवारण और मध्यस्थता के सम्बन्ध में विस्तृत सिफारिशें पेश कीं। भारत सरकार ने समस्या की ग्रन्थि भारतीयता पर जोर दिया। लेकिन श्रम सघ विल (ट्रेड यूनियन विल) पास होने से पूर्व इस अपरिपक्व माना गया। श्रम सघ विल १९२६ में कानून बन गया और अगले वर्ष चलायू कर दिया गया। व्यापार विग्रह अधिनियम (ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट), जो १९२६ में पास किया गया था और प्रारम्भ में केवल आगामी ५ वर्ष तक लागू रहता, १९२४ में स्थायी बना दिया गया।

सन् १९४० से भारत सरकार ने एक नवीन परामर्शदात्री सस्था को जन्म दिया और उसे पूर्णता प्रदान की। इसका नाम भारतीय श्रम सम्मेलन (त्रिदलीय श्रम सम्मेलन)^२ था।

१. १९५८ में १९५७ की तुलना में औद्योगिक झगड़ों की संख्या में कमी हुई। १९५७ में औद्योगिक झगड़ों की संख्या १६३० थी, जबकि १९५८ में १५२४ थी। इसके बावजूद भी मशीनों से संचालित व्यक्तियों की संख्या तथा काम के दिनों में काम से अलग रहने वालों की संख्या में ४.४ प्रतिशत तथा २१.३ प्रतिशत की वृद्धि हुई। १९५८ के प्रधान अर्द्ध-वर्ष की तुलना में दूसरे अर्द्ध-वर्ष में औद्योगिक अशांति का जोर बन रहा। इनका कारण नियोक्ताओं तथा श्रमिकों के संगठनों द्वारा अनुशासन-सम्बन्धी नयाँदावतों (कोड ऑफ डिस्प्लिन) की स्वीकार करना था।

२. ट्रिपार्टाइट लेबर कॉन्फरेन्स।

३७. व्यापार विग्रह विधान (ट्रेड डिस्प्यूट्स लेजिस्लेशन)—(१) सन् १९२६ का व्यापार विग्रह अधिनियम—यह अधिनियम अंग्रेजी कानून के अनुसार है। इसमें अनिवार्य मध्यस्थता की व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन की तरह भगडो के निर्णय में जनमत को एक निश्चित साधन माना गया है और निहित विचार यह है कि निश्चित प्रश्नों पर विवाद हो और निष्पक्ष (मध्यस्थ) न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) द्वारा उन पर मत प्रकट किया जाए, ताकि भली प्रकार सूचित जनमत का निर्माण हो सके। इस विधान में जाँच-न्यायालय (इनक्वायरी कोर्ट्स) और समझौता परिषदों (कंसोलिडेशन बोर्ड्स) के निर्माण की व्यवस्था है।

(क) जाँच किस प्रकार की होगी—प्रांतीय सरकार या गवर्नर-जनरल तथा जहाँ नियोजित गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल के अधीन किसी विभाग या रेलवे कम्पनी का अध्यक्ष है, वहाँ गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल को भगडो को तय करने के लिए एक जाँच-न्यायालय या समझौता बोर्ड (कंसोलिडेशन बोर्ड) स्थापित करने का अधिकार है। श्रावण देने वाले व्यक्ति दोनों दलों के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। (ख) जाँच न्यायालय का निर्माण—इसमें एक निष्पक्ष सभापति, अन्य ऐसे स्वतन्त्र व्यक्ति जिन्हें नियुक्ति-अधिकारी योग्य समझे अथवा एक स्वतन्त्र व्यक्ति हो सकता है। (ग) समझौता बोर्ड का विधान अलग है। इसमें एक सभापति, दो या चार अन्य सदस्य जिन्हें नियुक्ति-अधिकारी योग्य समझे या एक ही स्वतन्त्र व्यक्ति होगा। सभापति एक स्वतन्त्र व्यक्ति होगा तथा अन्य व्यक्ति भी स्वतन्त्र होंगे या बराबर सह्या में नियुक्त ऐसे व्यक्ति होंगे जो दोनों पक्षों की सिफारिशों पर उनका प्रतिनिधित्व करते होंगे। (घ) क्रियाविधि—ऐसे बोर्ड का काम भगडो के गुण-दोषों का विवेचन तथा वे सब काम करना होता है जिनसे दोनों दलों के भगडो शान्तिपूर्वक तथा न्यायोचित ढंग से तय हो जाएँ और उन्हें (दलों को) इसके लिए पर्याप्त समय मिल जाए। असफल होने पर इसे अपनी कार्यवाही का पूर्ण विवरण नियुक्ति-अधिकारी के पास भेजना पड़ता है जिसमें बोर्ड द्वारा उठाये गए कदम, उसकी जाँच के परिणाम और सिफारिशें भी होती हैं। नियुक्ति-अधिकारी को इसकी मध्यवर्ती (इंटरिम) या अन्तिम रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रकाशित करनी पड़ती है। (च) जनोपयोगी सेवाओं में हड़ताल—जनोपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित अधिनियम का द्वितीय भाग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जनोपयोगी सेवा का अर्थ यह है—(१) गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल द्वारा जनोपयोगी घोषित कोई भी रेलवे सेवा। (२) कोई भी तार, टेलीफोन और डाक की सेवाएँ। (३) कोई भी व्यापार या व्यवसाय जो जनता के लिए प्रकाश और पानी की व्यवस्था करता है। (४) जन-स्वास्थ्य और स्वच्छता की कोई भी सेवा। इन सेवाओं में मासिक वेतन पर नियुक्त श्रमिक यदि अपने नियोजता को हड़ताल करने से पहले एक महीने के अन्दर कम-से-कम १४ दिन की अग्रिम सूचना न दे तो उन्हें विशेष दण्ड दिया जाता है। इसी प्रकार यदि

१. श्रम आयोग ने अधिनियम के अन्तर्गत तदर्थ न्यायालयों के स्थान पर स्थायी न्यायालयों की स्थापना सम्बन्धी सम्भावना की जाँच करने की सिफारिश की। (श्र० आ० प्र०, १० १४६)

जनापयोगी सेवाओं के नियोजिता पूर्व-सूचना दिय बिना ही उन्हें स्वयं वन्द करते है तो उन्हें विशेष दण्ड दिया जाता है (इनका दण्ड अधिक होता है) । अपराध को प्रोत्साहन देने वाली वा साधारण अपराधी सशोधन अधिनियम (क्रिमिनल अमेण्डमेण्ट लाँ) के अनुसार सजा मिलगी । (छ) अर्बेध हडतालें—१९२७ के ब्रिटिश व्यापार विग्रह अधिनियम (ब्रिटिश ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट) के अनुसार अर्बेध हडतालों के सम्बन्ध म और भी व्यवस्थाएँ है । ऐसी हडताल या मिल-बन्दी को अर्बेध करार दिया जाता है ।

इस विधान के अनुसार नियोजिता और श्रमिकों के सगठन का अस्तित्व पहले से ही मान लिया जाता है । इसका उद्देश्य इस प्रकार व सगठन का विकास करना, यत्र-तत्र होने वाली हडतालों को रोकना तथा इस बात में सहायता करना है कि माँगे हडताल होने से पहले ही व्यवस्थित रूप धारण कर लें (न कि हडताल होने के बाद) । अधिनियम के अन्तर्गत सहानुभूति में की गई हडतालों अर्बेध होगी । इसके विपक्ष म कहा गया है कि सरकार इस आधार पर किमी भी हडताल को अर्बेध घोषित कर सकती है । लेकिन इसके प्रत्युत्तर में कहा जा सकता है कि इंग्लैण्ड की त्रिगुट हडताल (ट्रिपल स्ट्राइक) (१९२६) जैसी हडताले देश के लिए घातक मिद्ध हो सकती हैं । कानून की अन्य धाराओं के समान इस धारा का भी केवल इसी आधार पर विरोध नहीं किया जा सकता है कि इसका दुरुपयोग हा सकता है । यह भी कहा गया है कि हडतालों को अर्बेध घोषित करने वाली धाराएँ श्रमिकों के आधारभूत अधि-कारों में हस्तक्षेप करती हैं और श्रम-सध अन्दोलन का अंशव-काल में ही गला घोट देंगी तथा मजदूरों के मन म अविश्वास उत्पन्न करेगी । यह भी कहा जाता है कि अधिनियम में जनोपयोगी सेवाओं और अर्बेध हडतालों से सम्बन्धित भाग अनावश्यक हैं । समाज-सुरक्षा, जैसे पानी की पूर्ति, प्रकाश तथा सफाई आदि, में एकाएक की गई हडतालों पहले से ही दण्ड-विधान (पीनल कोड) के अन्तर्गत दण्डनीय हैं । साधारण जनोपयोगी सेवाओं में होन वाली हडतालों (उदाहरण के लिए, डाक, तार टेलीफोन या रेलवे) के सम्बन्ध में इतनी सख्ती न बरतनी चाहिए ।

अगस्त, १९३७ से लोकप्रिय मन्त्रिमण्डलों की स्थापना के बाद अधिनियम का प्रायः उपयोग किया जा रहा है, विशेष रूप से मद्रास प्रान्त में । जौच न्यायालय और समझौता परिषद् की नियुक्ति-सम्बन्धी कार्यविधि भाराक्रान्त प्रतीत हुई । परि-णामस्वरूप बम्बई की सरकार ने १९३४ में नवीन अधिनियम पास किया ।

(२) श्रम-आयोजन सिफारिश की थी कि अत्येक प्रान्तीय सरकार समझौते के लिए एक या एकाधिक अफसर रखे । मद्रास के श्रमायुक्त, पजाब के उद्योग-संचालक-मध्य प्रान्त के सांख्यिकीय संचालक, सहायुक्त और उद्योग-संचालक को समझौता अफ-सर के अधिकार दिये गए हैं ।

(३) १९३४ का बम्बई व्यापार विग्रह समझौता अधिनियम (दि बॉन्डे ट्रेड डिस्प्यूट्स कसीलियेशन एक्ट)—इसमें एक श्रम-आयुक्त की नियुक्ति की व्यवस्था भी की गई जो पदेन प्रधान समझौताकार होता है । इसमें धर्माधिकारी और सह समझौता-कार की भी व्यवस्था थ श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए १९३४ म एक श्रम-

अधिकारी की नियुक्ति हुई। मिल-मालिक सघ ने भी सरकारी अमाधिकारी और प्रमुख समझौताकार की कार्यवाहियों में अपनी मिलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अमाधिकारियों की नियुक्ति की।^१

(४) बम्बई औद्योगिक विग्रह अधिनियम (१९३८)—१९३४ के अधिनियम के स्थान पर बने १९३८ के इस नियम का उद्देश्य हड़ताल या मिल-बन्दी से पहले समझौते और मध्यस्थता के सभी अस्त्रों का पूरा उपयोग करना है।

इस अधिनियम में उन सघों की रजिस्ट्री की व्यवस्था है जो नियोक्ताओं द्वारा स्वीकार किये जा चुके हैं या सदस्यता की कुछ शर्तों को पूरा करते हैं। रजिस्ट्री सघों को मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने के अनेक अधिकार मिल जाते हैं। अमाधिकारी और समझौताकार (कसीलियेटर) प्रान्त के विभिन्न क्षेत्रों या उद्योगों के लिए नियुक्त किये जा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था की जाएगी ताकि मजदूरों की माँगों, शिकायतों या उनकी सेवा की शर्तों में किये गए परिवर्तनों पर पूरा विचार किया जा सके। हड़ताल और मिल-बन्दी उस समय तक अर्बन्ध मानी जाएगी जब तक कि बाद-विवाद और विचार-विनिमय के सभी साधनों का प्रयोग न कर लिया जाए। समझौते की कार्रवाई के दो महीने बाद हड़ताल या मिल-बन्दी के अधिकार का उपयोग करना चाहिए।

यदि दोनों पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुँचते तो समझा जाएगा कि व्यापार-विग्रह प्रारम्भ हो गया है और सरकारी समझौताकार भगडे को शान्त करने का प्रयास करेगा। यदि समझौताकार भी असफल रहता है अथवा सरकार आज्ञा देती है तो समझौता-परिषद् नियुक्त की जाती है।

ऐसे उद्योगों और केंद्रों में, जहाँ नियोजता और श्रम-सघों में भगडे का फंसला मध्यस्थों को सौंप दिया गया है, सरकारी कार्यवाही प्रारम्भिक दशा में और हो सका तो अन्त तक नहीं की जाएगी। फिर भी सभी समझौतों और परिनिर्णयों (अर्बाइंस) की रजिस्ट्री अर्बन्ध होगी।

अधिनियम के अन्तर्गत एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति हुई है जिसका काम सघों की रजिस्ट्री, उनकी ग्राह्यता का निर्णय, समझौतों, परिनिर्णयों, सूचनाओं तथा अन्य रिपोर्टों का लेखा रखना है।

एक महत्वपूर्ण विषय में अधिनियम एकदम नवीन है। इसमें हाईकोर्ट के जज या जज होने योग्य वकील की अध्यक्षता में एक औद्योगिक न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था है। यह न्यायालय स्वेच्छिक मध्यस्था में निर्णायक का काम करेगा और इस अधिनियम के अन्तर्गत उठ खड़े होने वाले अन्य भगडों के लिए भी न्यायालय का काम करेगा। यह मिल-बन्दी और हड़तालों की अर्बन्धता का निर्णय करेगा तथा समझौतों और परिनिर्णयों की व्यवस्था करेगा। ऐसे न्यायालय की स्थापना हो चुकी है।

सन् १९३८ का बम्बई उद्योग-विग्रह अधिनियम देश में श्रम-सम्बन्धी महत्वपूर्ण और सर्वांग अधिनियम है। इस विधान की आलोचना में कहा जाता है कि यह

१ ऐसे ही अमाधिकारी-बंगाल, उत्तर प्रदेश, मद्रास और बिहार में भी नियुक्त हुए हैं।

आवश्यकता से अधिक मस्तन और कामगरो के हडताल घोषित करने के स्वतन्त्र अधिकार का विरोधी है। इसके विपरीत यह भी कहा जाना है कि यह हडताल करने के अधिकार को समाप्त नहीं करना बल्कि इसके उपयोग को तब तक टालता रहता है जब तक कि मभी शान्तिपूर्ण तरीके, जिनसे व्यापारिक विग्रह का समझौता किया जा सकता है, समाप्त न हो जाएँ।

इस अधिनियम की दूसरी आलोचना यह है कि आन्तरिक मगठन के मूल्य को अंकित करने के लिए कुछ भी नहीं करता, जिससे श्रमिकों के सहयोग में वाद्यक मनो-वैज्ञानिक अन्तर दूर किये जा सकते हैं। इसका आधारभूत विचार सामूहिक सौदे (क्लेक्टिव बार्गेनिंग) का प्रचलन है, जिसमें एक और नियोक्ता और दूसरी और सगठित श्रमिक-समाज होता है।^१

मन् १९३६-४५ के युद्ध-काल में और भी कानूनी व्यवस्थाओं की आवश्यकता प्रतीत हुई, जो न केवल पर्याप्त रूप से लचीली ही हों बल्कि भगडो के समझौते के निश्चित उनाय भी प्रस्तुत करें। १९४२ में भारत सरकार द्वारा पास किये गए भारत-सुरक्षा नियम ८१ 'अ' का यही मूल सिद्धान्त था। इससे श्रमिकों की हडताल करने की स्वतन्त्रता बहुत सीमित हो गई। १९४१ का आवश्यक सेवा (स्थापन) अध्यादेश (असेशियल सर्विसेज रेगुलेशन एक्ट) भी इसी प्रकार का था। इसका उद्देश्य श्रमिकों को सरकार द्वारा आवश्यक घोषित की गई सेवाओं को छोड़ने से रोकना था।

(५) बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम (१९४६) का उद्देश्य १९३८ के औद्योगिक विग्रह अधिनियम को स्वानान्तरित करना है, जिसकी प्राय सभी धाराएँ पूर्ववत् रखी गई हैं तथा कुछ नई धाराएँ भी जोड़ी गई हैं। अनुभव से सिद्ध हुआ है कि मध्यस्थता तथा समझौते और निर्णयों से पर्याप्त सफलता मिली है तथा श्रमिकों को भी लाभ हुआ है।

औद्योगिक विग्रह अधिनियम (१९४७)—यदि समझौताकार मंत्रीपूर्ण ढंग से समझौता नहीं करा सकता तो मामला समझौता-परिपद् के हाथ में चला जाना है, जिसमें एक स्वतन्त्र सभापति और दो से चार तक अन्य सदस्य होते हैं। यह आशा की जाती है कि परिपद् अपना काम दो महीने में समाप्त करेगी। यदि परिपद् समझौता कराने में सफल होती है तो यह समझौता छ महीने या दोनो दलों द्वारा स्वीकृत अवधि में से उस समय तक के लिए लागू किया जाता है जो अधिक लम्बा हो। इसमें एक जांच न्यायालय की नियुक्ति की भी व्यवस्था है जो कि सौंपे गए विवादास्पद प्रश्न की छानबीन करता है। न्यायालय में एक या अधिक स्वतन्त्र व्यक्ति होते हैं। इसे उचित सरकार को अपनी जांच छ महीने के अन्दर देनी होनी है। उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) के न्यायाधीशों द्वारा निर्मित एक औद्योगिक मध्यस्थ न्यायालय (इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल) का निर्णय छ महीने या दोनो पक्षों को मजूर किनी अन्य अवधि—

१. देखिए, इण्डियन वर्कर्स आक श्वर्नोन्सिन, कॉन्फरेन्स अक, १९४०, में श्री पी० एन० लोकनानन का 'इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल' रिपोर्ट्स एंड लेटिजेस' नामक लेख।

इन दोनों में जो भी अधिक हो—तक मान्य होगा। समझौते की कार्रवाई के समय हड़ताल या मिल-बन्दी की इजाजत नहीं है।

सौ या सौ से अधिक व्यक्तियों को काम में लगाने वाले औद्योगिक कारखानों या संस्थापनों (एस्टाब्लिशमेंट) में श्रम-समितियों (वर्क्स कमिटी) को स्थापित करने की व्यवस्था है। इनमें नियोक्ताओं और श्रमिकों के प्रतिनिधि होंगे। श्रमिकों के प्रतिनिधियों की संख्या (जोकि रजिस्ट्रीयुद्धा श्रम-संधों की सलाह से चुने जाएँगे) कम-से-कम नियोक्ताओं की संख्या के बराबर होगी। इन समितियों का काम श्रमिकों और मालिकों के बीच अच्छे सम्बन्ध बनाये रखना और उन्हें ऐसे अनौपचारिक ढंग से मिलने-जुलने देना है कि वे एक-दूसरे से मिलकर रोज़मर्रा के झगड़े तय कर सकें। अधिनियम में अनिवार्य मध्यस्थता के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। इससे विरुद्ध यह कहा गया है कि यह श्रमिकों की सामूहिक सौदा करने की शक्ति को नष्ट करता है और इस प्रकार नियोक्ताओं के विरुद्ध प्रयोग में लाए जाने वाले सबसे शक्तिशाली अस्त्र अर्थात् हड़ताल को छीन लेता है। प्रत्युत्तर में कहा जाता है कि समस्त राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा अनिवार्य मध्यस्थता लागू करना उचित है। यह भी कहा जाता है कि व्यवहार में उसूलन समझौते के प्रयोग और ऐच्छिक मध्यस्थता की भी व्यवस्था है। सरकार के अनिवार्य मध्यस्थता पर हठ करने की नीति से दोनों दल अधिक विवेकपूर्ण ढंग तथा सरलता से समझौता कर सकेंगे।

सन् १९४७ की धाराओं को पूरा करने के लिए दिसम्बर, १९४६ में इण्डस्ट्रियल डिसप्यूट्स (बैंकिंग एण्ड इन्वयोरेंस कम्पनीज) एक्ट पास किया गया। सन् १९४७ के केन्द्रीय कानून को कुछ राज्य सरकारों ने भी संशोधित किया है, उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश (१९५१), मैसूर (१९५३)। केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के कानूनों के अन्तर्गत किये गए निर्णयों की अपील की व्यवस्था करने के लिए २० मई, १९५० में इण्डस्ट्रियल डिसप्यूट्स (एपीलेट ट्रिब्यूनल) एक्ट पास किया गया। जम्मू और काश्मीर को छोड़कर यह कानून सारे भारत में लागू है। अपील सुनने के लिए एक न्यायालय (अपील ट्रिब्यूनल) की स्थापना हो चुकी है। इस न्यायालय के तीन स्थान हैं—बम्बई, कलकत्ता और लखनऊ। १९४६ के इण्डस्ट्रियल अधिनियम का १९६१ तथा १९६३ में संशोधन किया गया। चीनी आक्रमण के बाद नवम्बर १९६२ में इण्डस्ट्रियल अस्थायी विराम रेजोल्यूशन (Industrial Truce Resolution) द्वारा इन झगड़ों को मिटाने की कोशिश की गई। फिर भी १९६३ में १४७१ औद्योगिक झगड़े हुए जिसमें ३२,६८,५२४ श्रमिक दिनों की हानि हुई।

३८. भारत में श्रम-संध आन्दोलन—श्री बी० पी० वाडिया के नेतृत्व में मद्रास में १९१८ में ही श्रम-संधों का संगठन किया गया था। मद्रास से श्रम-संध आन्दोलन बम्बई पहुँचा। १९१७ में प्रारम्भ होने वाली औद्योगिक अशांति के परिणामस्वरूप कितने ही श्रम-संध स्थापित किये गए। ये सब अस्थायी थे और उद्देश्य पूरा होते ही—चाहे वह मजदूरी की वृद्धि हो या कुछ और—विनष्ट हो गए। ये हड़ताल-

समितियाँ-सी थी जिनमें कुछ अफसर और कुछ चन्दा देने वाले सदस्य थे।^१ परिस्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। आन्दोलन की प्रारम्भिक दशा में आर्थिक कष्ट के एकमात्र सूत्र से श्रमिक बँधे रहते थे। यह बन्धन आर्थिक स्थिति के सुधार के साथ ही कमजोर होता जाता था। बाद में आन्दोलन में शक्ति आती गई। इसे १९२६ के श्रम-संघ अधिनियम द्वारा काफी बल मिला। भारत के व्यापार-संघ आन्दोलन की प्रारम्भ से ही एक अखिल भारतीय संस्था—अखिल भारतीय श्रम संघ कांग्रेस (ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस)—का सहयोग प्राप्त हुआ, जिसके अधिवेशन १९२० से होते आ रहे हैं।

१९४८ के अन्तिम तथा १९४९ के प्रारम्भिक महीनों में ट्रेड यूनियन कांग्रेस से कितने ही संघ अलग हो गए। ट्रेड यूनियन कांग्रेस अब कम्युनिस्टों के अधिकार में है। इधर हाल में कांग्रेस के सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुए ग्रहमदावाद में भी एक संघ बनाया गया। इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय श्रम-संघ कांग्रेस (इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस) है और यह धीरे-धीरे शक्ति संग्रह कर रही है। श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समाजवादियों ने हिन्दू मजदूर पचायत नाम का एक शक्तिशाली संगठन बनाया है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय की स्थापना से भारत में केन्द्रीय श्रम संघ स्थापित होने में शीघ्रता हुई। जेनेवा सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति से भारतीय श्रम आन्दोलन पश्चिमी दुनिया के सम्पर्क में आ गया।

१९४० में अखिल भारतीय श्रम संघ कांग्रेस में कुल १९१ संघ थे तथा इससे सम्बद्ध सदस्यों की संख्या ३५४,५४१ थी। १९४६-४७ में रजिस्ट्रीगुदा श्रम-संघों की संख्या १,७२५ थी जिनमें से ९९८ ने अपना लेखा पेश किया। उनकी सदस्यता १,३३१,९६२ थी। स्त्रियों की सदस्यता कुल सदस्यता के ४ प्रतिशत से भी कम थी। १९५७-५८ में (जम्मू और कश्मीर, मैसूर और मनीपुर को छोड़कर) भारत में ९,६४४ श्रम-संघ थे। इनमें से ५,३१९ श्रम-संघों ने अपना लेखा प्रस्तुत किया। इनकी सदस्यता २५,९५,५१९ पुरुषों तथा ३,१०,५९४ स्त्रियों की है। ये सब संघ शक्ति और मामर्थ्य में समान नहीं हैं। लगभग आधे संघ तो सरकारी नौकरियों से सम्बद्ध व्यक्तियों के थे।

३९. भारत में श्रम-आन्दोलन की कठिनाइयाँ—सबसे प्रधान कठिनाई भारतीय श्रमिकों की परिवर्तनशीलता है (देखिए, सेक्शन ३)। द्वितीय, बम्बई तथा कलकत्ता-जैसे उद्योग केन्द्रों में काम करने वाले व्यक्तियों में इतनी विभिन्नता है कि वे अलग-अलग भागएँ बोलते हैं और इसलिए एक-दूसरे के प्रति आकृष्ट नहीं होते। जहाँ पर प्रवासी श्रमिकों की संख्या कम है, जैसे ग्रहमदावाद में, वहाँ व्यापार-संघ काफी सुदृढ़ हैं। तीसरे, बहुत-से श्रमिक नियमित चंदा तथा संघ अनुदान से भी घबराले हैं।

यही वजह है कि सघो में नाम लिखे गए व्यक्तियों का प्रतिशत बहुत कम है। साधारण मजदूर इतना गरीब होता है कि थोड़ा-सा भी चन्दा देना उसे भारी मालूम होता है। चीथे, अधिकार मजदूर निरक्षर होते हैं। परिणाम यह होता है कि उन्हें अपने वर्ग से नेता नहीं मिल पाते। इसी वजह से भारतीय श्रम सघ आन्दोलन की यह विशेषता है कि इसके नेता अधिकतर मध्य वर्ग के व्यक्ति रहे हैं, जैसे पेशेवर वकील या अन्य ऐसे व्यक्ति जिन्हें राजनीतिक या आर्थिक क्षेत्र में कोई विशिष्टता प्राप्त नहीं हुई है।^१ इससे अतिरिक्त उनके हित कितने ही सघो में विभक्त होते हैं और उनका कानूनी पेशेदगी-सम्बन्धी ज्ञान भी अत्यन्त सीमित होता है। अन्य बाधा वास्तविक जनतन्त्रीय आदर्श का अभाव है जो कि श्रम सघो के लिए अत्यन्त आवश्यक है। अन्त में, सफल श्रम-सघ वर्तमान सामाजिक व्यवस्था की स्वीकृति पर भी निर्भर करते हैं ताकि श्रमिकों के लिए अधिक-से-अधिक लाभ उठाया जा सके।^२ यदि श्रमिक वर्ग के नेता वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था को विनष्ट करने पर तुले होंगे तो उनका प्रभाव इस आन्दोलन को कमजोर ही बनाएगा।

४०. १९२६ का श्रम-सघ अधिनियम—१९२० में मद्रास उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया, जिसमें श्रम-सघ के कर्मचारियों तथा सगठनकर्ताओं को श्रमिकों को नियोजकों के साथ अधिक मजदूरी के लिए समझौते को हड़ताल करके तोड़ने के लिए प्रभावित करने से रोका गया। इससे भारतीय श्रम-सघो की रजिस्ट्री और सुरक्षा के लिए विधान की आवश्यकता प्रतीत हुई। रजिस्ट्रीशुदा सघो को अपना नाम और उद्देश्य निश्चित करना होता है। इन्हें सदस्यों की सूची रखनी पड़ती है और अपने धन कोप की जाँच करानी होती है। यह धन कुछ निश्चित विषयों पर सदस्यों के हित के लिए व्यय किया जाता है। रजिस्ट्रीशुदा श्रम सघ के कम-से-कम आधे पदाधिकारी उसी उद्योग के होने चाहिएँ। इन प्रतिबन्धों के साथ ही कानून ने सभी श्रम-सघो के कर्मचारियों को श्रम-सघ के वैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये गए कामों में अपराध की जिम्मेदारी से छूट दे दी है। उनका ऊपर पड़्यन्त्र का दोष नहीं लगाया जा सकता है। अधिनियम में ऐसी व्यवस्था है कि (१) किसी रजिस्ट्री-शुदा सघ कर्मचारी के खिलाफ व्यापारिक भगडे को अग्रसर करने के लिए किये गए किसी काम का मुकदमा दीवानी कचहरी में इस आधार पर दायर नहीं किया जा सकता कि वह नौकरी के खिलाफ भड़काता है या व्यापार अथवा व्यवसाय या दूसरे की नौकरी या अपनी सम्पत्ति को प्रयोग करने के अधिकार में हस्तक्षेप करता है। दीवानी

१. ऐसा कि ब्रिटिश श्रम-सघ आन्दोलन के प्रारम्भिक दिनों में हुआ था जब श्रम-सघ अपने नेतृत्व के लिए राबर्ट ओवेन, फ्रांसिस ग्लेस, किंगले, लडलो और फ्रेडरिक हेरिस्टन आदि चर्चों पर निर्भर थे। इसी प्रकार भारतीय आन्दोलन अपने प्रारम्भिक दिनों में प्रायः संपूर्णतया चर्चों के उद्देश्यों से निर्भर था। इसी वर्ग से अध्यक्ष और सचिव मिलते थे। इस विषय पर रोचक आलोचनाओं के लिए देखिए, अ० आ० प्र०, पृष्ठ ३२४-२५ और ३०८-२६।

२. अहमद सुल्तान, ट्रेड यूनियनियम एण्ड लेबर डिमण्ड्स इन इण्डिया।

कचहंगी में (२) किली भी रजिस्ट्रीयुद्ध श्रम-संघ के खिलाफ इस आधार पर भी कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता कि कोई कर्मचारी व्यापारिक विग्रह को अग्रसर कर रहा है, जब तक कि यह न साबित हो जाए कि वह संघ की कार्यकारिणी को बिना बताए या उसके प्रकट आदेशों के विरुद्ध काम कर रहा है। रजिस्ट्रीयुद्ध श्रम-संघ सदस्यों के नागरिक एवं राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए कोप इकट्ठा कर सकता है किन्तु इसके लिए बन्दा पूर्णतया ऐच्छिक होता है। १९६३ में श्रम संघों की संख्या २,६२५ थी और सदस्यों की संख्या २२,०८,२१६ थी।

औद्योगिक कल्याण^१

४१. कल्याण-कार्य की प्रकृति—सरकार, श्रमिकों, नियोक्ताओं या सामाजिक संस्थाओं द्वारा ऐसे प्रयत्न किए जा सकने हैं। एक दृष्टिकोण से ऐसे प्रयत्नों की मानवता का कार्य कहा जा सकता है जिसका उद्देश्य औद्योगिक जनता का हित होता है। सकुचित और केवल उपधोगितावादी अर्थ में तथाकथित कल्याण-कार्यों को कुशलता-कार्य भी कहा जा सकता है। इसका श्रमिकों के शारीरिक स्वास्थ्य और कुशलता पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

४२. कल्याण कार्य का विभाजन—कल्याण-कार्य के दो प्रधान भाग हैं (१) कारखाने के अन्दर के कल्याण कार्य तथा (२) कारखाने के बाहर के कल्याण-कार्य। जहाँ तक कारखाने के अन्दर काम की दशाओं के सुधारने का सवाल है इसके विषय में सरकार, नियोक्ताओं तथा अन्य साधनों द्वारा किये गए प्रयत्नों का विवेचन अध्याय में पहले ही किया जा चुका है।

बीते युग के नियोक्ताओं की ओर से श्रमिकों के अदकाश का सदुपयोग करने के प्रयत्न पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। जो प्रयत्न किये गए वे औपधि-सम्बन्धी सहायता या शिक्षा और आवास की सहायता के रूप में थे। वर्तमान समय में बढ़ती हुई औद्योगिक अशान्ति के कारण इस पर अधिकधिक ध्यान दिया जा रहा है। मई, १९२६ में भारत सरकार ने सभी प्रान्तीय सरकारों से काम पर न होने के समय श्रमिकों की रहने की दशा सुधारने के लिए किये गए प्रयत्नों के प्रांकडे एकत्रित करने के लिए कहा। यह जांच अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन के छठे सम्मेलन की सिफारिश पर की गई। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन ने विभिन्न सरकारों से इस बात की प्रार्थना की कि वे श्रमिकों के खाली समय के उपयोग से सम्बन्धित अद्यतन सूचना दें।

बम्बई के कुछ उदार नियोक्ताओं द्वारा प्रदर्शित रुचि के अतिरिक्त कितने ही नियोक्ताओं ने अन्य औद्योगिक केन्द्रों, विशेषकर नागपुर, मद्रास, जमशेदपुर और कानपुर, में श्रम-कल्याण-कार्य की योजनाएँ प्रारम्भ की हैं। बर्किंगहम कर्नाटक मिलों

१. इन विषय पर श्रम-आयोग की रिपोर्ट का चौदहवां अध्याय देखिए।

द्वारा भूतकाल में किया गया कल्याण-कार्य सभी को ज्ञात है। नागपुर की इम्प्रेस मिल ने श्रमिकों के हित की देख-भाल का काम वाई० एम० सी० ए० (नवयुवक ईसाई सघ) को सौंप दिया है। जमशेदपुर के टाटा आइरन और स्टील कम्पनी के सचालको का कहना है कि कम्पनी के प्रारम्भ से ही श्रम के प्रति उनका रुख तथा श्रमिकों के लिए सफाई, सुरक्षा, शिक्षा, जल-वितरण, आवास, जल-निकासी, अस्पताल तथा अन्य सार्व-जनिक सेवाओं की व्यवस्था भारत में बेजोड़ है और भारतीय जनता के सभी मतों के व्यक्तियों ने उसे सहर्ष स्वीकार किया है। कानपुर में ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन ने कल्याण कार्य अधीक्षक की व्यवस्था की है जो कि श्रमिकों के रहने के लिए बनाई गई दो बस्तियों की देख-रेख करता है। बम्बई कारपोरेशन, पोर्ट ट्रस्ट-जैसी नगर-पालिकाओं और रेलो-जैसी जनोपयोगी सेवाओं ने भी अपने कर्मचारियों के हित के लिए काम किया है।

प्रान्तीय स्वशासन के अन्तर्गत कितनी ही सरकारों ने नियोक्ताओं द्वारा किये गए कल्याण और आमोद-प्रमोद की क्रियाओं को पूरा करने के लिए स्वयं कल्याण-योजनाएँ प्रारम्भ की हैं। उदाहरणार्थ, बम्बई की सरकार ने बम्बई के औद्योगिक क्षेत्रों तथा राज्य के अन्य नगरों में कल्याण-केन्द्र खोले हैं।^१

४३ कल्याण-कार्य के मद—(१) शिक्षा—औद्योगिक श्रमिकों की शिक्षा से सम्बन्धित दयनीय दशा की चर्चा की जा चुकी है।^२ टाटा-जैसे कुछ उदात्त नियोक्ताओं ने श्रमिकों की शिक्षा का भी प्रबन्ध किया है। उनके और उनके बच्चों के लिए दिन और रात्रि की पाठशालाएँ खोली गई हैं। बम्बई के समाज सेवा सघ और ईसाई नवयुवक सघ ने भी औद्योगिक श्रमिकों की शिक्षा के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण काम किया है। इन्होंने स्कूल और रात्रि पाठशालाओं के अतिरिक्त पाठ गृहों और पुस्तकालयों की भी व्यवस्था की है। (२) औषधि सहायता—भारत के बड़े कारखानों में औषधि-सहायता की सुविधाएँ सामान्यतः प्राप्त हैं, किन्तु लेडी डॉक्टरों द्वारा स्त्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत कम पाई जाती है। (३) प्रसवकालीन लाभ—स्त्रियों और उनके बच्चों के हित के लिए पाश्चात्य देशों में प्रसवकालीन लाभ और बच्चा होने के कुछ दिन पूर्व और पश्चात् तक काम न करने देने की प्रथा है। चूँकि भारत में स्त्रियाँ गृह-सेवक का भी काम करती हैं, अतः यहाँ भी यह व्यवस्था अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण हो जाती है। १९१६ के वाशिंगटन अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने औरतो को काम में लगाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया। इसमें प्रसवकालीन लाभ के प्रश्न पर भी विचार किया। यह आशा नहीं की जाती थी कि भारत इस प्रस्ताव को तुरन्त स्वीकार कर लेगा, फिर भी भारत सरकार को इस प्रश्न की छानबीन करने के लिए आमन्त्रित किया गया ताकि वह दूसरे सम्मेलन को अपनी रिपोर्ट दे सके। प्रस्तुत की गई जाँचों से यह सिद्ध हुआ कि बहुत थोड़े-से ही नियोक्ताओं ने इस प्रकार

१. इण्डियन इन्धर बुक, १९४०-४१, पृ० ५५६।

२. देखिए, अध्याय १, सेक्शन ६।

का काम प्रारम्भ किया है। प्रान्तीय सरकारों ने ऐसी ऐच्छिक योजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की। जून, १९२४ में भारत सरकार द्वारा की गई अन्य जांचों से भी स्पष्ट हो गया कि वगाध के तीन प्रवान और सगठित उद्योगों—जूट, चाय और कोयला—में प्रसवकालीन लाभ की निश्चित योजनाएँ चांसी थीं। आसाम के चाय के वगीचों, आसाम-रेलवे तथा व्यापार कम्पनी, बिहार और उड़ीसा की खानों और बम्बई के कारखानों में भी इस प्रकार की योजनाएँ चल रही थीं। इनमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त हैं, जैसे गर्भावस्था में कुछ समय की छुट्टी, दूध तथा दूध पिलाने वाली धोतलो का निर्मूल्य वितरण। इन सबके अतिरिक्त बम्बई में प्रसूति-ग्रह भी हैं। बम्बई सरकार द्वारा नियुक्त लेडी डॉक्टर वेन्स ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में टाटा मिल-समूह द्वारा दी गई प्रसवकालीन सुविधाओं का रोचक विवरण दिया है। कम-से कम ११ महीने काम कर चुकने वाली स्त्री को बच्चा पैदा होने के एक महीने पहले और एक महीने बाद की तनखाह भत्ते के रूप में दी जाती है, यदि वह किसी लेडी डॉक्टर द्वारा गर्भावस्था का आठ महीने पूरे होना का प्रमाणपत्र पेश करे और यह आश्वासन दे कि वह मजदूरी पर अन्यत्र काम न करेगी।

१९३४ में सम्बोधित अधिनियम द्वारा बच्चा पैदा होने के चार सप्ताह तक काम करना अवैध घोषित किया गया। आठ मात प्रतिदिन के हिसाब से प्रसवकालीन लाभ बच्चा पैदा होने के चार सप्ताह पहले और बाद तक मिलेगा, बसंत कि वह नियोजित को इस बात की सूचना देने की तिथि के नौ महीने पहले से काम कर रही हो और सूचना देने के एक महीने बाद ही बच्चा पैदा होने को हो। यदि इस छुट्टी की अवधि में वह कहीं और काम करेगी तो उसे यह लाभ नहीं मिलेगा। १९३८ में यह अधिनियम सभी औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाली स्त्रियों पर लागू कर दिया गया। १९५८ में प्रसवकालीन लाभ अधिनियम मध्य प्रदेश में तथा १९५७ में केरल में भी पास किया गया। १९३५ में मद्रास में भी बम्बई-जैसा एक अधिनियम पास किया गया, जिसमें १९५८ में मसोधन किया गया। आसाम का अधिनियम ही कारखानों और चाय के वगीचा, दोनों में लागू होता है। शेष सभी अधिनियम केवल कारखानों पर ही लागू होते हैं। सभी प्रसवकालीन लाभ विधानों के आधारभूत सिद्धान्त एक ही हैं, अर्थात् बच्चा पैदा होने के कुछ समय पूर्व और पश्चात् स्त्रियों का नकद आर्थिक सहायता दी जाए, प्रसव के बाद उन्हें अनिवार्य रूप से कुछ समय तक विश्राम करने दिया जाए और यदि वह बच्चा पैदा होने की सूचना देती है तो पहले भी करने दिया जाए। सभी अधिनियमों में लाभ मिलने के लिए एक निश्चित अवधि की नौकरी या काम आवश्यक है।

(४) आमोद-प्रमोद—आमोद प्रमोद का महत्व स्वयं इतना स्पष्ट है कि उस पर विशेष बल देने की आवश्यकता नहीं है। श्रमिका के नीरस जीवन में थोड़ी भी हुरियाली लाने वाली कोई भी चीज स्वागत योग्य है। श्रमिक को ऐसे काम में लगाना आवश्यक है ताकि उसका फालतू समय शराबखारी और नशे में व्यतीत न हो तथा औद्योगिक कन्दो में औद्योगिक काम के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाए और

वह बिना हिचक के वहाँ बस जाए। बम्बई सरकार के कल्याण-केन्द्र की स्थापना के प्रयत्न भी स्तुत्य है। इन त्रियाग्रो के फलस्वरूप सिनेमा, मेजिक लेण्टर्न की सहायता से भाषण, संगीत-सम्मेलन, नाटक, प्रखाडे, दगल आदि के आयोजन का नाम लिया जा सकता है। (५) आवास—इस समस्या का विवेचन इस अध्याय में पहले ही हो चुका है। (६) सहकारी समितियाँ—सहकारी आन्दोलन के विवरण में इसका पूरा वर्णन हो चुका है। (७) अन्न-वस्त्र की दूकानें—कुछ मिलों में श्रमिकों को सस्ती दर पर अन्न-वस्त्र बेचने के लिए दूकानें भी खोली गई हैं, जिससे वे धोखेबाज बनिशों के चमूल से बच सकें। इस समस्या का सन्तोपजनक निदान सहकारी स्टोर खोलने से ही हो सकता है। (८) चाय की दूकानें और केण्टीन—चाय और स्वास्थ्यजनक खाद्य की आवश्यकता प्रतीत होने पर भी हमारी मिलों में इनका प्रबन्ध नहीं के बराबर है।

ऊपर बताया गए फैक्ट्री एक्ट के आधुनिकतम संशोधन में कल्याण-कार्य के लिए अनेक धाराएँ हैं, जिनमें विश्राम के लिए सुन्दर विश्राम-गृहों का निर्माण, ५० से अधिक स्त्रियों को नौकर रखने वाली फैक्ट्रियों में उनके बच्चों के लिए कमरों की व्यवस्था तथा प्राथमिक सहायता के उपस्कर की व्यवस्था आदि का नाम गिनाया जा सकता है। श्रमिकों को वृद्धावस्था में काम आने के लिए १९५२ में श्रमिक प्रोवीडेंड फण्ड पास हुआ जो जनवरी १९६५ के अन्त तक ९६ इन्डस्ट्रीज और अन्य संस्थाओं में लागू हुआ। इसकी सदस्य-संख्या ३६ लाख हो चुकी है और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मजदूरों को लाभ पहुँचायेगी। इस योजना के अन्त तक इस सघ के पास ७०० करोड़ रुपये की साख हो अयेगी।

१. देखिए, सेवरान १३-१५।

२. देखिए, खण्ड १, अध्याय १०, सेवरान ११।

अध्याय १७ राष्ट्रीय आय

१ राष्ट्रीय आय के अनुमान : दादाभाई नौरोजी का अनुमान—दादाभाई नौरोजी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'पॉवर्टी एण्ड दी ब्रिटिश रूल इन इण्डिया' में पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय अंकित करने का गम्भीर प्रयास किया। यह अनुमान १८६७-७० के सरकारी अंकड़ों पर आधारित है। डॉ० नौरोजी ने जिन सिद्धान्तों का अनुसरण किया, उनकी व्याख्या वह निम्न शब्दों में करते हैं—“मैंने प्रान्त की एक या दो मुख्य उत्पत्तियों को उस प्रान्त की कुल उत्पत्ति का प्रतिनिधि मान लिया है। मैंने प्रत्येक जिले की जोती जाने वाली सम्पूर्ण भूमि, प्रति एकड़ उत्पादन एवं उसके मूल्य को लिया है, अब साधारण गुणा और जोड़ स कुल उत्पादन की मात्रा और मूल्य मालूम हो जाता है। इससे प्रति एकड़ औसत उत्पादन और सम्पूर्ण उत्पादन का मूल्य भी सही-सही मालूम हो जाता है।” इस आधार पर काम करते हुए वह इस परिणाम पर पहुँचे कि कृषि-उत्पादन का कुल मूल्य २७७,०००,००० पौंड है। इसमें से ६% वह बीज के लिए घटा देते हैं। इसके बाद २६०,०००,००० पौंड बचा। नमक, अफीम, कोयला और व्यापार में होने वाले लाभ का मूल्य प्रायः १७,०००,००० पौंड, निर्मित वस्तुओं का मूल्य १५,०००,००० पौंड, लगभग इतना ही मछली, दूध, गोदत इत्यादि का मूल्य तथा ३०,०००,००० पौंड अन्य बातों के लिए रख लेने पर इन सबका योग ३४०,०००,००० पौंड होता है। जनसंख्या को १७०,०००,००० मानने पर ब्रिटिश भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय ४० शिलिंग या २० रुपये हुई। जेल में दी जाने वाली खुराक और प्रवासी कुलियों को दिये जाने वाले राशन के आधार पर वह इस नतीजे पर पहुँचे कि यह केवल जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक आय—३४ रु०—से भी कम है। “बूँकि राष्ट्रीय आय दैनिक आवश्यकताओं को पूरित करने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी, अतएव देश की उत्पादक पूँजी धीरे-धीरे प्रतिवर्ष व्यय होती गई और देश की बढ़ती गरीबी के साथ उत्पादन-शक्ति का ह्रास होता गया।”

डॉ० वी० के० आर० वी० राव का मत है कि दूध, मछलियाँ तथा मांस के सम्बन्ध में दादाभाई नौरोजी का अनुमान कम है। दूध, मांस और मछलियों का उत्पादन कृषि का चतुर्थांश है। इस प्रकार इन साधनों से प्राप्त आय ६५० लाख पौंड होगी न कि १५० लाख पौंड। उद्योगों पर अवलम्बित जनसंख्या कृषि-जनसंख्या का ६% से अधिक है तथा कृषि-जनसंख्या की तुलना में औद्योगिक श्रमिकों की आय भी अपेक्षाकृत अधिक है। अतएव निर्माणों से प्राप्त आय १५० लाख पौंड के बजाय ६०० लाख पौंड होनी चाहिए। इसी प्रकार प्रशासन, परिवहन, पेशे और गृह-सेवकों

के लिए भी कुछ जोड़ना होगा। इन संतोचनों के बाद राष्ट्रीय आय २० ह० प्रति व्यक्ति से बढ़कर २३ या २४ ह० प्रति व्यक्ति हो जाएगी।'

२. राष्ट्रीय आय १८७५ से १९११ तक—दादाभाई नौरोजी के बाद, १८८२ में दूसरी जांच अर्ल क्रोमर (उस समय, मेजर ईवलिन बेरिंग) तथा सर (उस समय मिस्टर) डेविड वारवर ने की और उनके परिणाम इस प्रकार थे—

कृषि-आय	ह० ३५०,००,००,०००
गैर-कृषि-आय	ह० १७५,००,००,०००
योग	ह० ५२५,००,००,०००

१९४,५३६,००० व्यक्तियों में बाँट देने पर, जो तत्कालीन जनसंख्या थी, प्रति व्यक्ति औसत आय २७ रुपये हुई।

१९०१ की जनगणना के अनुसार जनसंख्या २३,१०,००,००० थी। इस आधार पर एक अर्द्धे वर्ष में प्रति व्यक्ति आय १८ ह० ८ आना ११ पाई होती। दुर्भिक्ष वर्ष १८९६-१९०० के लिए डिम्बी द्वारा अनुमानित आय १२ ह० ६ आने थी।

दुर्भिक्ष आयोग के लिए आकलित आँकड़ों के आधार पर कृषि-आय को ४५०,००,००,००० ह० मानकर लार्ड कर्जन ने उपर्युक्त कथनों के उत्तर में अपना अनुमान प्रस्तुत किया। १८८० की गणना के अनुसार कृषि-आय १८ ह० प्रति व्यक्ति थी। उसी क्षेत्र की अद्यतन जनगणना की सख्याओं को लेकर यह अनुमान लगाया गया कि कृषि-आय १८ ह० से बढ़कर २० ह० हो गई। यह मानने पर कि गैर-कृषि-आय भी उसी अनुपात में बढ़ी होगी, १९०० में भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय १८८० के २७ ह० के बजाय ३० ह० हुई। लार्ड कर्जन ने स्वीकार किया कि आँकड़े निर्विवाद नहीं थे। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि १८८० की सख्याएँ भी अनुमानित ही थी और यदि एक तर्क के समर्थन के लिए एक सख्या प्रयुक्त की जा सकती है तो उसी प्रकार दूसरी सख्या का प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि गणना के आधार पर निर्दिष्ट आर्थिक दशा की प्रगति न तो महत्त्वपूर्ण ही थी और न सतोपजनक ही। लेकिन इससे यह बात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं लौट रहे हैं।

१९०२ में एफ० जे० अटकिंसन ने एक लेख 'स्टेटिस्टिकल रिव्यू ऑफ दि इनकम एण्ड वेल्थ ऑफ ब्रिटिश इण्डिया' लिखा जो लन्दन में रॉयल स्टेटिस्टिकल सोसाइटी के सामने पढ़ा गया। उन्होंने सम्पूर्ण जनसंख्या को तीन वर्गों में विभाजित किया—(१) कृषि जनसंख्या, (२) गैर-वृषीय जनसंख्या (गरीब), (३) गैर-वृषीय जनसंख्या (धनी)। पहले वर्ग की आय क्षेत्रफल, उत्पादन और कीमतों के आँकड़ों पर निर्धारित की गई। दूसरे वर्ग की आय प्रत्येक वर्ग के श्रमिकों की सख्या को

उनकी पारिश्रमिक दर से गुणा करके प्राप्त की गई। तृतीय वर्ग में सरकारी नौकरो के लिए सरकारी अनुमान (सिविल एस्टिमेट्स) और पेशेवर लोगो के लिए आय-कर को प्रयोग में लाया गया। इस आधार पर अर्टकिसन न अनुमान लगाया कि १८७५ में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय ३० ५ रु० तथा १८९५ में ३६ ५ रु० थी। इनमें से धोज, धिसाव आदि के लिए कुछ नहीं घटाया गया। इस प्रकार अन्तिम परिणाम में अनिरजन का दोष आ गया और डॉ० राव ने इसमें सुधार करना आवश्यक समझा तथा अनुमान को ३६ रु० ८ आने से घटाकर ३१ रु० ८ आ० कर दिया।^१

३. वाडिया और जोशी का अनुमान—१९१३-१४ की राष्ट्रीय आय का अनुमान श्री पी० ए० वाडिया और श्री जी० एन० जोशी न लगाया है।^२ हम उनकी जाच का परिणाम संक्षेप में नीचे दे रहे हैं। कृषि-उत्पादन का मूल्य १०,७२,६६,६३,२८२ रु० रखा गया। इसमें से बीज और खाद के लिए प्रतिशत घटाया गया। अतएव वास्तविक कृषि-आय ८,५८,३६,६४,६२६ रु० हुई। खनिज पदार्थों का मूल्य १४,४०,६५,००० रु० अनुमान किया गया। इसमें २० प्रतिशत धिसाव और मजदूरो से सम्बन्धित खनन का व्यय घटाया गया। (गणना में आगे खनिज-उत्पादन निर्माण (मिन्नेक्वचर्स) में जोड़ लिया गया है।) इस तरह वास्तविक मूल्यांकन ११,५२,७६,००० रु० हुआ। जहाँ तक निर्मित वस्तुओ (मिन्नेक्वचर्स) के मूल्य-निर्धारण का प्रश्न है, इसे कच्चे माल का $\frac{१}{३}$ अर्थात् २० प्रतिशत माना गया। इसका मूल्य (२०४,७६,६५,०००—५) = ४०, ६५, ३३, ००० रु० हुआ। लेखकगण ऊपर बताया गई पद्धतियो से इस कुल आय में से कई चीजे घटाकर निम्न आलेख प्रस्तुत करते है जो कि १९१३-१४ की कुल राष्ट्रीय आय में से घटाई गई राशि प्रदर्शित करता है—

(१) गृह-व्यय	२००,००,००० पौण्ड
(२) सरकार की ओर से विदेशी पूंजी का विनियोग	८०,००,००० पौण्ड
(३) भारत में लगी विदेशी पूंजी पर लाभ	३६०,००,००० पौण्ड
(४) भारत में नई विदेशी पूंजी का विनियोग	५०,००,००० ^३ पौण्ड
(५) सरकारी अफसरो, यूरोपीय नौकरो आदि द्वारा भारत से बाहर भेजा जान वाला द्रव्य	१००,००,००० पौण्ड
	८२०,००,००० पौण्ड

= १२३,००,००,००० रु०

इस आय को ब्रिटिश भारत की जनसंख्या में विभाजित करने पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय ४४ रु० ५ आ० ६ पा० आनी है। १९११ की जनगणना के अनुसार ब्रिटिश भारत की जनसंख्या २४,४१,८६,७१६ थी। इसमें तीन वर्ष की सम्भावित वृद्धि

१. पूर्व उद्धृत, पृ० ८-३६।

२. 'दि वेल्थ ऑफ इण्डिया', पृ० ६७-११२।

३. वाडली रावर्त्स की रिपोर्ट के लेखकों का कहना है कि इस मद का मूल्य दो बार घटाया गया है।

के लिए १०,००,००० जोड़ दिया गया है।

४. शाह और खवाटा का अनुमान—जे० टी० शाह और जे० खम्बाटा के अनुमान का सारांश इस प्रकार है—

मदें	युद्ध-पूर्व काल	युद्ध-युद्धोत्तर काल	कुल अवधि	वष
	१९००-१४	१९१४-२२	१९००-२२	१९२१-२२
	करोड़ रुपयो मे			
कृषि-उत्पादन	१०१४.८	१६८६.५	१२५७.१	२१५५.८
बीजो के लिए घटाया गया	२०	३५	२५	५८
वास्तविक कृषि उत्पादन	९९४.८	१६५१.५	१२३२.१	२०९७.८
वन-धन	१०	२०	१४	२८
मछलियाँ	१२	२५	१९	३२
निर्मित वस्तुएँ	८०	१५०	१०६	१८६
खनिज पदार्थ	१०	२१.६	१४	२८.७
मकान इत्यादि	१०	१६.४	१२	२०.३
योग	११०६	१८६२	१३८०	२३६४

इस प्रकार प्रति व्यक्ति कुल आय

—१९००-१४—	३६ रु०
—१९१४-२२—	५८ ^३ / _४ रु०
—१९००-२२—	४४ ^३ / _४ रु०
—१९२१-२२—	७४ रु०

५. फिण्डले शिराज का अनुमान—१९२०-२१ और १९२१-२२ के लिए फिण्डले शिराज के अनुमान में कृषि-उत्पादन क्रमशः १,७१,४९४ लाख रु० तथा १,९८,३४१ लाख रु० तथा गैर-कृषि-उत्पादन क्रमशः ८८३ करोड़ रु० रखा गया। इस आधार पर १९२१ और १९२२ के लिए प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय क्रमशः १०७ रु० तथा ११६ रु० हुई। शिराज ने बताया कि १८८१ से १९११ तक की अवधि में किये गए सब अनुमानों में यह मान लिया गया था कि कृषीय और गैर-कृषीय आय दोनों वर्गों में उनकी संख्या के अनुपात से विभाजित है। यह गणना तब तक ठीक थी जब तक देश का औद्योगिक विकास अपनी शैशवावस्था में था। लेकिन इधर हाल में कुछ शीघ्रता से परिवर्तन हुए हैं, अतएव कुल गैर-कृषीय उत्पादन पर पहुँचने के लिए कुछ और जोड़ना आवश्यक हो गया है। इसके लिए ७५ करोड़ रु० जोड़ना उपयुक्त होगा और इसे जोड़ने पर कुल ८८३ करोड़ रुपये हुए। शिराज के अनुमान के विरुद्ध एक स्पष्ट आलोचना यह है कि कृषि-उत्पादन-गणना में उन्होंने बीज इत्यादि को घटाने की आवश्यकता समझी।

६ ची० के० आर० वी० राव का अनुमान—डॉ० राव ने १९३१-३२ के लिए राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया है। उनके अनुसार वास्तविक आय (ब्रिटिश भारत की) १,६०,००० लाख और १,८०,००० लाख रु० के बीच है और प्रति व्यक्ति आय ६५ रु०। इसमें मूल संचोधन के लिए ६% जोड़ा या घटाया जा सकता है। नीचे की सारणी में विस्तृत वर्णन दिया गया है—

	मूल्य दस लाख रुपयों में	भूल की सीमा, प्रतिशत
कृषि-उत्पादन का मूल्य	५,९२७	—
पशु " "	२,६८३	= १०
मछली और शिकार "	१२०	= २०
जंगल के उत्पादन "	६२	—
खनिज " "	१८०	—
आय वर पर लगी हुई आय	२,१६१	—
" से मुक्त आय (उद्योगों में लगे श्रमिकों की)	२,१००	= १७
" " " " रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ	५६०	—
व्यापार में लगे लोगों की आयकर से मुक्त आय	१,२३३	= १५
शिक्षा इत्यादि में " " " " "	४१६	= १५
रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ को छाड़कर परिवहन में लगे लोगों की आयकर से मुक्त आय	०८३	= २०
गृह-सेवास्यों में लगे श्रमिकों का आय-कर	३२५	= २०
विविध मदों से मुक्त आय	७८०	= १०
योग	१६,८६०	= ६

डॉ० राव अपने अनुमान को इस आधार पर अधिक सही बताते हैं कि उन्होंने प्राप्य आंकड़ों को मास, दूध की उत्पत्ति, उद्योग में लगे हुए लोगों की आय, स्थानीय अधिकारियों की सेवाओं इत्यादि के सम्बन्ध में की गई तदर्थ (एड हॉक) जांचों द्वारा पूर्ण किया है।^१

७ ईस्टर्न इकनामिस्ट का अनुमान—ईस्टर्न इकनामिस्ट ने अपने वार्षिक अंक (३१ दिसम्बर, १९४८) में १९३९-४० से १९४७-४८ के लिए राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में निम्न मस्याएँ दी—

१. ब्रिटिश भारत की राष्ट्रीय आय (१९३१-३२), पृ० ४ और १८५-६।

ब्रिटिश भारत की आय (१९३६-४० से १९४७-४८ तक)
(दस लाख रुपये में)

	१९३६-४०	४०-४१	४१-४२	४२-४३	४३-४४	४४-४५	४५-४६	४६-४७	१९४७-४८
कृषि तथा अन्य सम्बन्धित पेशों से आय	६५२७	१०३६५	११०४८	१७४०२	२१२२८	२२६३८	३०३४५	२५६६३	२१२६३
उद्योगों से आय	३७६०	४०६२	६०२०	६५६०	१२४००	१११२०	१०३३८	६३८२	६८००
अन्य स्रोतों से	६०२६	६१२६	६२६०	६७७२	८६५१	८६५१	६७६६	६७६८	८३२८
कुल आय	१६३१३	२०५८३	२३३६०	३३७३४	४०३३८	४२७०९	४०३३०	४४८७२	३६४२१

जीवन-निर्वाह-व्यय देशनाक की सहायता से व्यवस्थित (द्रव्य आय से भिन्न) वास्तविक आय के परिवर्तन निम्न तालिका में प्रदर्शित किये गए हैं—

वास्तविक आय १९३६-४० में ६७ रु० प्रति व्यक्ति थी, १९४७-४८ में घट कर ६२ रु० हो गई। इसके अतिरिक्त इस आय का कुछ भाग उपभोग पर नहीं व्यय किया गया, बरन् पौण्ड पावना के निर्माण में खर्च हुआ। वह बात निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाएगी जो कि उपभोग (खाना और कपड़े) की कमी प्रदर्शित करती है।

खाना और कपड़ा प्रति व्यक्ति उपभोग

	१९३६-४०	१९४०-१	१९४१-२	१९४२-३	१९४३-४	१९४४-५	१९४५-६	१९४६-७	१९४७-८
प्रति व्यक्ति भोजन का उपभोग	३८८	३६६	३४८	३७८	३७६	३७०	३४०	३५८	३५७
प्रति व्यक्ति कपड़े का उपभोग (गजों में)	१६	१६	१४	१०	१४	१४	१२	१२	११

८. व्याख्या तथा तुलना की कठिनाइयाँ—इन परिणामों की तुलना करते समय पाठक को बहुत-सी बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात तो यह है कि वे विभिन्न तिथियाँ और वर्षों की हैं, अतएव इस बीच हुए मूल्यों के अन्तर का खयाल रखना होगा। मूल्यों में ८०% वृद्धि की मान्यता पर १९१३-१४ का ४५ रु० १९२१-२२ के ८१ रु० के बराबर होगा। दूसरी बात यह है कि गणना में लिया गया क्षेत्र हर गणना में एक ही नहीं है। उदाहरणार्थ शाह और खवाटा ने केवल ब्रिटिश भारत ही नहीं, अपितु भारतीय रियासतों का भी शामिल कर लिया है। अतएव इस गणना और उस गणना के बीच, जोकि केवल ब्रिटिश भारत तक सीमित है, तुलना करते

समय हमे शाह-खवाटा की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिश भारत रियासतों की अपेक्षा थोड़ा अधिक धनी और आर्थिक दृष्टि से विकसित है। हमें अपनायी गई पद्धतियों से उत्पन्न अन्तर भी ध्यान में रखना होगा। जैसा कि हम देख चुके हैं, शिराज कुछ भी नहीं घटाते जबकि अन्य गणनाओं में थोड़ा बहुत घटाया गया है। राष्ट्रीय आय के तत्त्वों के सम्बन्ध में भी मतभेद है, जबकि शिराज पक्षों में हुई आमदनी को जोड़ता है अन्य गणनाएँ ऐसा नहीं करती।^१ अतएव विभिन्न अनुमानों की तुलना करते समय हमें दी गई वास्तविक समस्याओं को ध्यान में न रखकर उन समस्याओं को ध्यान में रखना चाहिए जो सबके द्वारा एक ही पद्धति अपनाने पर होती। एक और ध्यान देने की बात यह है कि बाद की गणनाएँ अधिक वैज्ञानिक आधार पर हैं। जैसा कि शिराज ने कहा है, यदि उसके विस्तृत तरीके के ध्यान पर पुरानी पद्धति का अनुसरण किया जाए तो कृषि और अन्य पक्षों से होने वाली आय का मूल्य काफी कम होगा।

इन गणनाओं से आर्थिक समृद्धि के सम्बन्ध में परिणाम निकालते समय भी काफी सावधानी से काम लेना होगा। यहाँ केवल प्रति व्यक्ति औसत आय को ही ध्यान में नहीं रखना होगा बल्कि राष्ट्रीय आय वित्त अंगों से मिलकर बनी है इसका भी ध्यान रखना होगा। भारत-जैसे देश के लिए यह महत्त्वपूर्ण होगा कि आय का कितना भाग खाद्य-सामग्री के रूप में है, क्योंकि यदि खाद्य-सामग्री जैसी जीवन की आवश्यकताओं में बनी है तो अन्य प्रकार की आय में वृद्धि उतने महत्त्व की नहीं होगी। यदि सेवाओं को राष्ट्रीय आय के अन्तर्गत लेना है तो यह ध्यान रखना होगा कि क्या हमारी परतन्त्रता के युग में कुछ सेवाओं का बहुत बड़ा-चढ़ाकर मूल्य बन नहीं किया जाता या ?

कभी-कभी तो दरिद्रता की तस्वीर इसलिए बड़ा चढ़ाकर खींच दी जाती है कि वे समझते हैं कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय एक औसत कुटुम्ब की आय का प्रति-निधित्व करती है। यदि हम जनता को ज़रूरत से ज्यादा खुशहाल समझते हैं तो हम दूसरी दिशा में गलती करते हैं, क्योंकि ऐसा करने में हम यह भूल जाते हैं कि आय का वितरण असमान है। कुछ लोगों की आय औसत से बहुत ज्यादा और बहुतों की औसत से बहुत कम है। विद्वत्तापूर्ण पक्षों और जमींदारियों में अपेक्षाकृत अधिक आय है। छोटे-मोटे व्यापारियों की आय मध्यम श्रेणी की है। नगरों में आधी आय आबादी के दशमांश लोगों के हाथ में है। पड़े-लिखे, पक्षे वाले तथा बड़े-बड़े जमींदारों की आमदनी काफी ज्यादा है। ऐसे लोगों का ३८%, जिनकी आय २,००० रु० से ज्यादा है, कुल आय के १७% का अधिकारी है, जबकि १% व्यक्तियों के पास कुल आय का १०% है।

शाह और खम्वाटा की गणना के अनुसार १ प्रतिशत या आश्रितों को

१. शिराज अपने खाम अनुमान में कुल रूप से सेवाओं को शामिल नहीं करता, लेकिन अपनी गैर-कृषीय आय की नीच एक तालिका द्वारा करता है जिसमें सेवाएँ सम्मिलित हैं।

सम्मिलित करने पर अधिक-से-अधिक ५% व्यक्ति देश की एक-तिहाई सम्पत्ति का उपभोग करते हैं और देश की सम्पत्ति के एक-तिहाई से कुछ अधिक लगभग ३५% आय का उपभोग एक-तिहाई जनसंख्या (आश्रितों को मिलाकर) करती है और तत्कालीन ब्रिटिश भारत के शेष लगभग ६०% व्यक्ति देश में उत्पन्न सम्पत्ति के ३०% का उपभोग करते हैं। हमारे पास ये विश्वास करने के आधार हैं कि दूसरे और तीसरे वर्गों से प्राथमिक वर्ग की (कृषि की) धोर प्रवाह हो रहा है, साथ ही श्रमिकों की द्राव्यिक एवं वास्तविक आय में भी वृद्धि हुई है। यह भी सच है कि कुछ उद्योगों में श्रम की उत्पादकता घट जाने से उनकी वास्तविक आय १३% कम हो गई है। उत्पादकता के ह्रास का कारण अशत तो मशीनों की दुरवस्था तथा अशत काम के घण्टों का घट जाना भी है। १९४३ के बाद से वास्तविक मुनाफा भी घट रहा है।^१

यह भी ध्यान देने की बात है कि एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में भी प्रति व्यक्ति आय में अन्तर पड़ता है।^२ व्यावसायिक फसले बोनो वाले तथा अधिक उद्योगीकृत प्रान्तों में आय अधिक है, जैसे बम्बई, बिहार, मध्यप्रान्त और बरार, जबकि उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मद्रास अपेक्षाकृत गरीब हैं।

६. अन्तर्राष्ट्रीय तुलनाएँ—सर जोशिया स्टॉम्प का कथन है कि 'जिन देशों की तुलना करनी है उनके निवासियों का निश्चित वस्तु के प्रति एकसा ही दृष्टिकोण होना चाहिए तथा उनके पारस्परिक मूल्यों का मानदण्ड भी समान होना चाहिए। इस बात में जहाँ तक देशों में विभिन्नता होगी, तुलना सारहीन होगी।'^३ भारत और इंग्लैण्ड-जैसे देशों की एक ही संख्याओं के मूल्य में बड़ा अन्तर होगा। कारण यह है कि न केवल इन देशों के मूल्य का मानदण्ड विभिन्न है, अपितु भिन्न बाह्य परिस्थितियाँ भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को जन्म देती हैं।

१०. गहन परीक्षण—व्यक्तिगत रूप में की गई जाँचों, जैसे बम्बई में डॉ० मैन द्वारा की गई जाँच तथा मद्रास में डॉ० स्टेलर द्वारा की गई जाँचों, के अतिरिक्त ग्रामीण और नागरिक विभाग, पञ्जाब आर्थिक जाँच परिषद् (पञ्जाब बोर्ड ऑफ इकनामिक इन्व्वायरी) के तत्वावधान में कई सर्वेक्षण किये गए। भारतीय केन्द्रीय कपास समिति न भी कुछ वर्ष हुए, कपास उगाने वालों की आर्थिक और विपणन परिस्थितियों के सम्बन्ध में आठ जाँचें कीं। भारतीय आर्थिक जाँच समिति द्वारा प्रस्तावित नमूने

१. इंस्टीट्यूट इकनामिस्ट, वार्षिक अंक १९४८, पृ० ११२३-६।

२. वकील और मुरजन, पूवाद्घृण, ३५६-७।

३. तुलना कालिप, "दो देशों की आर्थिक तुलना बड़ा ही सुदृग्ध विषय है। मकान, वपड़े और खान-पान में भी तुलना नहीं की जा सकती, अन्-पारिश्रमिक आय का महत्व भी घटना-बदला है। एक दर में कुछ ऐसी चीजें खरीदी जाती हैं जो दूसरे देश में देकार होगी या उन्मुक्त रूप से प्रकृति के दान के रूप में मिलती होगी। हमें औद्योगिक वर्गों की तुलना नहीं करनी चाहिए—जैसे इन्जीनियरिंग, छपाई, मकान-निर्माण इत्यादि में लगे लोगों की, क्योंकि काम के तरीके और परिस्थितियों में बड़ा अन्तर होता है। इन बातों को ध्यान में रखे बिना तुलना अर्थहीन है।—ए० एल० बाउली, 'नेचर एण्ड परपज ऑफ दि मेजरमेण्ट ऑव सोशल पेनामेन्स', इकनामिक इन्व्वायरी रिपोर्ट में उद्धृत, पृ० ११७।

की यह पहली गहन जांच थी तथा इसमें अत्यन्त महत्वपूर्ण ज्ञान भरा है।^१ इन सब जांचों से भारतीयों की आर्थिक दशा के सम्बन्ध में उपर्युक्त निष्कर्षों की पुष्टि होती है।

११. क्या भारतीय दरिद्रता घट रही है?—घोर निर्बन्धता को एक निर्बिबाद सत्य के रूप में स्वीकार करने पर प्रश्न यह उठता है कि यह घट रही है या बढ़ रही है या स्थिर है। अब दरिद्रता केवल कुछ प्रारम्भिक आवश्यकताओं की अतृप्ति ही नहीं बल्कि इस युग की नवीनतम वस्तुओं में भाग न पा सकने का नाम हो गया है। हालाँकि आज पाश्चात्य देशों में पचास साल पहले की अपेक्षा जनता को अच्छा भोजन, कपड़े और मकान प्राप्त है, किन्तु उसका असतोष पहले से कहीं तीव्र है। कुछ लोगों के मतानुसार भारत में भी वैसे ही परिवर्तन हो रहा है और असन्तोष आर्थिक अवस्था में सुधार का परिणाम है। ऊपर दिये गए विविध अनुमान अपनी अपूर्णता के बावजूद इतनी बात तो स्पष्ट करते ही हैं कि भारत की आर्थिक अवस्था की गति सुधार की ओर है। इस बात की पुष्टि इससे भी हो जाती है कि भारतीय औद्योगिक तथा कृषि श्रमिक की भावना में एक प्रकार की स्वच्छन्दता व दर्शन होते हैं। १९३६-४५ के युद्ध-काल के पूर्व इस पर भी विश्वास किया जा सकता था कि भारत में प्रति व्यक्ति भोजन और कपड़े के उपयोग की मात्रा बढ़ रही है। सरकारी अधिकारियों का निश्चित मत था कि देश की आर्थिक दशा सुधर रही है, जैसा कि निम्न उद्धरण से स्पष्ट हो जाएगा—“जहाँ तक साधारण वसोटी का उपयोग किया जा सकता है यह कहा जा सकता है कि भारतीय भू-धारक, व्यापारी, रैथत और दस्तकार की दशा आज से पचास वर्ष पूर्व की अपेक्षा सुधरी हुई है। वह चीनी, नमक, लम्बाकू तथा आयात-विलासिताओं (इम्पोर्टेड लक्जरीज) का पहल की पीढ़ी की तुलना में अधिक मात्रा में उपयोग कर रहा है। जहाँ घर-घर जाँच की गई है वहाँ पना चला है कि साधारण ग्रामीण अपने पिता की अपेक्षा अच्छा खाना खाता और अच्छे कपड़े पहनता है। पीतल या अन्य धातु के बरतनों न पुराने मिट्टी के बरतनों का स्थान ले लिया है और उसके घर में पहल की अपेक्षा अधिक कपड़े हैं।”^२ इस प्रकार की तसवीर की सत्यता पर गैर-सरकारी लोगों ने मतभेद और कुछ छोटी छोटी बातों पर तो खुले आम सन्देह प्रकट किया। उदाहरण के लिए, ग्रामीणों का अधिक भोजन सर्वमन से स्वीकृति न पा सका। अन्य बातों के साथ यह बताया गया कि विशेषकर कस्बों के समीप के गाँवों का आहार-स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। दूध का, जो कि एक शाकाहार-प्रधान देश में प्रधान खाद्य है, नितान्त अभाव होता जा रहा है और उसी उपयोगिता के आहार-रूप में और कोई

१. देखिए, कप्तान उगान बार्ना का आर्थिक एवं वित्त में की गई जाँचों पर साधारण रिपोर्ट, १९२८।

२. 'रिचल्ट्स ऑफ इण्डियन स्टैटिस्टिकल इन दि पास्ट सिफ्टी इअर्स', १९०६, पृ० २६। एल० सी० ए० वाउलन द्वारा 'इकनामिक डेवलपमेण्ट ऑफ दि ब्रिटिश ओवरसीज एम्पायर' में उद्धृत (१७६३-१९१४) भाग १, पृ० २७५।

पदार्थ उसका स्थान नहीं ले पाया है। यह मान लेने पर भी कि थोड़ा-बहुत सुधार हुआ है यह तो सच ही है कि भारत पाश्चान्य देशों, विशेषकर इंग्लैंड, की तुलना में एक क्षण भी खड़ा नहीं हो सकता, जब कि हम वहाँ की दरिद्रता में कभी, मृत्यु की दर तथा गरीबी से उत्पन्न बीमारियों में घटती, शिक्षा का प्रसार, आमोद-प्रमोद के साधनों में वृद्धि, अधिक अच्छी सफाई और मकान की दशाओं को देखते हैं। पश्चिम में भी धन के वितरण में बड़ी असमानता है, किन्तु आर्थिक समृद्धि का भी विस्तृत प्रसार है, यह निस्सन्देह कहा जा सकता है। जीवन की अच्छी वस्तुओं की अधिकता और आमदनी में साधारण रूप से वृद्धि ने सर्वसाधारण की त्रयशक्ति की क्षमता के अन्तर्गत अनेक ऐसी वस्तुएँ ला दी हैं जो पहले बहुत थोड़े-से धनी लोगों का एकाधिकार थीं।

१२. अधिक सही आँकड़ों की आवश्यकता—भारत की आर्थिक दशा से सम्बन्धित समस्याओं के सुलभाने या निर्धारित करने के लिए जो त्रुटियाँ और अव्यवस्थाएँ आ जाती हैं उनका प्रधान कारण है सही आँकड़ों का अभाव। धीरे निर्धनता को छोड़कर और सब विषयों से हम लोग प्रायः अन्वकार में हैं। ठीक आँकड़ों के प्राप्त हो जाने पर अनेक अनुमानित मान्यताओं का सहारा न लेना होगा और हमारी गणना अधिक सही और विश्वसनीय होगी। इससे देश की अनेक दुरवस्थाओं के कारणों का ठीक-ठीक पता लगेगा तथा उन्हें सुलभाने में बड़ी सहायता मिलेगी। प्रशासन की कितनी ही कठिनाइयाँ दूर हो जाएँगी। १९२५ की भारतीय आर्थिक जाँच समिति ने इस सम्बन्ध में (लन्दन) 'टाइम्स' का उपयुक्त मत उद्धृत किया है। १९२१ में हुए साम्राज्य आँकड़ा सम्मेलन (एम्पायर स्टेटिस्टिकल कॉन्फ्रेंस) के सम्बन्ध में 'टाइम्स' का मत है कि "युद्ध से पूर्व जर्मनी में स्टेटिस्टिकल ब्यूरो अविश्वसनीय गति से उन आँकड़ों का सकलन करने में सफल था जिनसे देश के भविष्य-निर्माण में किंचित भी सहायता मिल सकती थी। अब जो युग प्रारम्भ हो गया है उसमें जो राष्ट्र आँकड़ों के द्वारा की गई व्याख्या से सुसज्जित हैं वे उनसे प्रस्तुत किये गए लाभों का पूरा उपयोग कर सकते हैं तथा उस राष्ट्र की अपेक्षा निश्चित ही अच्छे हैं जो केवल अनुभवजन्य ज्ञान पर निर्भर हैं।" इस समय एकत्रित आँकड़े विशेषज्ञों के निर्देशन से रहित एवं असम्बद्ध हैं। वस्तुतः वे सरकारी वैभागिक कार्रवाई के उपोत्पाद हैं, उनका उद्देश्य जनता को सामाजिक और आर्थिक महत्त्व की बातों की जानकारी कराना नहीं होता।

यह बात सच है कि भारत में आँकड़ों के एकत्र करने के मार्ग में अनेक बाधाएँ हैं। पहले तो देश का विशाल आकार ही काम को व्ययशील और कठिन बना देता है। दूसरे, जनता कस्बों और नगरों में केन्द्रित न होकर गाँवों में बिखरी पड़ी है। तीसरे, जनता की अशिक्षा और अज्ञान के कारण आँकड़े एकत्र करने के काम में उससे

जरा भी सहायता नहीं मिलती, इससे यह प्रायः व्यावहारिक असम्भावना का रूप धारण कर लेता है। इंग्लैण्ड या अन्य देशों में उत्पादन, पारिश्रमिक एवं कीमती के आँकड़े व्यक्तियों को अनुसूचियाँ बाँटकर एकत्र किये जाते हैं जो भरकर निश्चित समय में लौटा देते हैं। वृत्तिक कर्मचारियों की अपेक्षा यह अधिक सतह और कम व्ययसाध्य होता है। व्यक्तिगत सस्थाओं में भी बड़ी सहायता मिल जाती है। इस प्रकार की सस्थाएँ भारत में नहीं हैं।

१३. बाउली-राबटंसन जाँच—नवम्बर, १९३३ में भारत सरकार ने प्रो० ए० एल० बाउली (लन्दन स्कूल ऑफ इकनामिक्स) और मि० डी० एच० राबटंसन (केम्ब्रिज में इकनामिक्स के प्राध्यापक) को अधिक सही और व्यापक आँकड़े इकट्ठा करने तथा उत्पादन-गणना करने की व्यावहारिकता पर परामर्श देने के लिए नियुक्त किया। इनके साथ ही तीन भारतीय अर्थशास्त्रियों ने भी काम किया और इन लोगों के सम्मिलित प्रयत्न के फलस्वरूप १९३४ में एक महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसका नाम था 'भारत की आर्थिक गणना की योजना' (ए स्कीम फॉर एन इकनामिक्स सेन्सस ऑफ इण्डिया)। संक्षेप में उसको नीचे दिया जाना है—

१४. (१) आँकड़े सकलित करने का संकल्पन—केन्द्रीय कार्यकारिणी की आर्थिक समिति से सलग्न एक स्थायी आर्थिक कर्मचारी-वर्ग नियुक्त किया जाए, जिसमें चार सदस्य हों। पुराना सदस्य कार्यकारिणी की आर्थिक समिति के सचिव का काम करेगा और यह आर्थिक समिति व प्रति सम्पूर्ण आर्थिक सूचना के संगठन कार्य के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रकार वह अत्यावश्यक प्रश्नों पर, जैसे-जैसे वे सामने आएँगे, रिपोर्ट करेगा। सांख्यिकी मंचालक को सूचना का प्रमुख अंग तथा सदस्य होने के अतिरिक्त और भी कार्य करने पड़ने थे—(१) जनगणना कराना, (२) उत्पादन गणना कराना (३) केन्द्रीय आँकड़ों का संयोजन और (४) प्रान्तीय आँकड़ों का संयोजन। इस कार्य में उसकी सहायता करने के लिए वाणिज्य सूचना विभाग की सांख्यिकीय शाखा उसके अधीन कर दी जाएगी और उसके कुछ स्थायी सदस्य भी बढ़ा दिए जाएँगे। 'वाणिज्य सूचना विभाग', जो केवल व्यावसायिक दुनिया की जाँच-पटताल का जवाब में लगा रहता है, वाणिज्य-विभाग का एक अंग हो जाएगा।

उत्पादन-गणना हर पाँचवें वर्ष होनी चाहिए। एक स्थायी सांख्यिकीय विभाग गणना की तैयारी तथा उसके परिणामों का विश्लेषण करेगा और उसे प्रायः सदैव कार्य लगन रहना पड़ेगा तथा दसवर्षीय जनगणना की अवस्था पर उसे थोड़ा-सा और बढ़ा दिया जाएगा। वर्गीकरण में एकता लाने के लिए सांख्यिकीय मंचालक को अन्य विभागों में आँकड़े प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से सलाह ले सकने का अधिकार होना चाहिए। इससे साधारण उपयोग के लिए आँकड़े प्राप्त होंगे और विभाग के कार्य के लिए भी आवश्यक आँकड़े एवत्र रहेंगे। उसे सांख्यिकीय सारांश (स्टैटिस्टिकल एग्मट्रेक्ट) प्रकाशित करने के लिए भी उत्तरदायी होना चाहिए। हर प्रान्त में पूरे समय तक काम करने वाले सांख्यिकीय होंगे। प्रशासनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें यथासम्भव स्वतन्त्रता मिलेगी तथा उसकी सेवाएँ हर

विभाग को प्राप्य होगी। वह उन सबके आँकड़ों का पुनर्विलोकन करेगा। वह केन्द्रीय सांख्यिकीय सचालक से हर प्रकार से सहयोग करेगा और उसके निर्देशानुसार जन-गणना कराएगा।

१५. (२) राष्ट्रीय आय की माप—रिपोर्टों के लेखकों के मतानुसार वर्तमान समय में प्राप्य सामग्री भारत की आय और धन की माप करने के लिए अत्यन्त दोषपूर्ण है। अब तक किये गए विभिन्न अनुमान पुराने पड़ गए हैं और समस्या को फिर शुरु से जाँच करनी आवश्यक है।

जैसा कि सभी जानते हैं, गणना की दो विधियाँ हैं—पहली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यांकन की है और दूसरी व्यक्तिगत आयों के योग की। ये दोनों पद्धतियाँ एक-दूसरे की सत्यता सिद्ध करने में हर जगह सहायक नहीं होती—उदाहरण के लिए, मन्त्रिमण्डल के मन्त्रियों की सेवाएँ उनको मिलने वाले वेतन के बराबर हैं क्योंकि उनको नापने का और कोई तरीका ही नहीं है। भारत के विषय में तो ऐसा असम्भव दीखता है कि पूरे क्षेत्र या केवल उद्योगों के सम्पूर्ण क्षेत्र में भी प्रथम (उत्पादन-गणना) विधि पूरी तरह से लागू होगी। दोनों विधियों का परिष्कार को मिलाते में भी विशेष सावधानी आवश्यक हो सकती है। प्रथम (उत्पादन गणना) विधि में निम्न बातें हैं

(१) खेती, खनिज, उद्योग इत्यादि उत्पादन की विभिन्न शाखाओं के वास्तविक उत्पादन को उत्पादन होते ही आँक लिया जाए ताकि दुबारा गणना करने की गलती से बच जाएँ।

(२) गृह-उत्पादित वस्तुओं एवं आयातों में परिवहन और व्ययसयियों की सेवाओं द्वारा हुई मूल्य-वृद्धि को जोड़ा जाए।

(३) गृह-उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जान वाला उत्पाद कर जोड़ा जाए।

(४) निर्यात (जिसमें सोना चाँदी भी शामिल है) का मूल्य घटाया जाए।

(५) आयात (जिसमें सोना चाँदी भी शामिल है) का मूल्य जोड़ा जाए।

(६) आयात पर लगे आयात-कर (कस्टम्स ड्यूटीज) को जोड़ा जाए।

(७) उन वस्तुओं के मूल्य को—चाहे वे देश में उत्पन्न की जाती हों या विदेश से मँगामी जाती हों, जो स्थिर पूँजी को कायम रखने में प्रयोग में लायी जाती हैं—घटा दिया जाए।

(८) सब प्रकार की वैयक्तिक सेवाओं को जोड़ा जाए।

(९) मकानों का सालाना किराया जोड़ा जाए—चाहे वे किराये पर उठे हों या मालिक-मकान द्वारा उपयोग किए जाते हों।

(१०) धन-राशि में (चाहे सरकारी हो या व्यक्तिगत) विदेशी प्रतिभूतियों द्वारा हुई अन्निवृद्धि को जोड़ा जाए, या इस प्रकार की धन-राशि में से देश में विदेशियों की प्रतिभूतियों की वृद्धि को घटाया जाए मगर इनकी कमी को जोड़ा जाए।

इतने से कुछ पर टिप्पणियों की आवश्यकता है—

(१) कृषि का वह भाग जो उत्पादकों द्वारा उपयुक्त होता है—भारत में यह

हिस्सा बहुत अधिक है—और वह हिस्सा जोकि स्थानीय सेवाओं से बढ़ता जाता है, इनका भी मूल्यांकन होना चाहिए। यह मूल्यांकन स्थानीय मूल्य में ही होना चाहिए, न कि दर के बाजारों के फुटकर मूल्य पर, जिसमें उठाने, ल जान आदि की मजदूरी भी शामिल रहती है जोकि स्थानीय मूल्य में नहीं होती।

(३, ६) यह आवश्यक है क्योंकि जिस योग की हम खोज है वह उपभोक्ताओं के विनिमय-मूल्य का कुल जोड़ है।

(४, ५, १०) यह आसानी से देखा जा सकता है कि जब भारत सरकार रेलवे निमाण के लिए इंग्लैण्ड से ऋण लेती है तो जिन प्रतिभूतियों का आयात होता है वे इंग्लैण्ड के विनियोजकों की वास्तविक आय का एक भाग होती है, ठीक उसी प्रकार जैसे भारतीय चाय का आयात वास्तविक आय का भाग है।

(६) (१) सरलता के लिए यह मान लिया जाता है कि सरकारी नौकरों की मबाएँ जनता को सीधा लाभ पहुँचानी हैं और उपयोगी हैं। अतएव वे वास्तविक राष्ट्रीय आय का एक अंग हैं। इनक मूल्यांकन में पेंशन-अधिकारों को भी शामिल करना चाहिए।

राष्ट्रीय आय निकालन के लिए उत्पादन गणना विधि दोनों विधियों में अधिक आधारभूत है। दूसरी विधि (आय-गणना) के परिणाम उपयुक्त विधि के परिणामों से मिल सक इसक लिए कुछ सावधानियाँ बतानी पड़गी।

(१) स्वयं उपयुक्त वस्तुओं तथा वस्तु रूप में प्राप्त आय को गणना में शामिल करना होगा। इसकी वीमत उत्पादन के स्थान की वीमत के अनुसार लगानी होगी। इसी प्रकार जिन घरों में लागू रहते हैं—चाह वे उसक मजान मालिक ही क्या न हों—उसका भी वास्तविक मूल्य लगाना होगा।

(२) सब प्रकार के यात्रा खर्च व उपभोग के लिए लिय गए ऋण पर भी बंधों न दिय गए हों, व्यक्ति की आय में से घटाने होगे।

(३) इसक अतिरिक्त हर एक व्यक्ति की आय, जिसमें सरकारी नौकरों की पेंशन और सरकारी ऋण पर व्याज जवा की-त्यो शामिल करनी होगी अर्थात् इन्हें बर देन से पूर्व शामिल करना होगा। कर में मालगुजारी भी शामिल है। सरकारी नौकरों की आय में उस वष के पेंशन के अधिकार भी जाड़ लन चाहिए। इस प्रकार के योग में कर्मचारियों के अविभाजित मुनाफे और सरकारी कामों से होने वाले लाभों को भी जाचना होगा। इस प्रकार प्राप्त योग में से उत्पादक ऋणों के अतिरिक्त ग्रेप सरकारी ऋण के व्याज की राशि तथा पहले के सरकारी नौकरों की पेंशने—चाह वे देश में दी जाएँ या विदेश में—भी घटानी होगी।

(४) इस प्रकार प्राप्त योग में आयात-कर, उपाद-कर, स्टाम्प-कर और स्थानीय कर (लाकल टैक्स) भी जोड़ने होंगे, क्योंकि यह उत्पादकों को मिलने वाले विनिमय मूल्य का कुल योग है, जबकि उत्पादन गणना-विधि से आकलित वास्तविक राष्ट्रीय आय उपभोक्ताओं को मिलने वाले विनिमय-मूल्यों का समूह है। अत जब तक यह नहीं जोड़ा जाता, गलतियाँ होने की सम्भावना है।

नीचे जो सुझाव दिये गए हैं वे राष्ट्रीय आय के बड़े भागों से सम्बद्ध हैं। ऊपर निर्देश की गई विभिन्न व्यवस्थाएँ अन्तिम गणना में अपना स्थान रखेंगी।

यद्यपि ठीक-ठीक राष्ट्रीय धन का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है, फिर भी स्थायी कामों में सरकारी खर्च, नयी पूँजी के विनियोग तथा पूँजी के विनियोग की तरह के व्ययों के अनुमानों से राष्ट्रीय आय के परिवर्तनों का निर्देश तो किया ही जा सकता है।

राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए प्रस्तावित गवेषणा प्रधानतया उत्पादन के आधार पर है, लेकिन जैसा सभी देशों में होता है कुछ भाग वैयक्तिक आय पर निर्भर रहता है। भारत में इस प्रकार की आय नगरों में ज्यादा है, परन्तु पारिवाहिक देशों की तुलना में बहुत ही कम है। कुछ तो उत्पादन के स्वभाव और कुछ इसलिए क्योंकि गवेषणा के विभिन्न तरीके आवश्यक हैं, ग्रामीण आय नागरिक आय से भिन्न रखी जाती है।

ग्रामीण आय के लिए उन्होंने सुझाव रखा कि कुछ चुने हुए गाँवों का घना सर्वेक्षण करके भूमि से उत्पादित सब वस्तुओं और गाँवों में की जाने वाली सब सेवाओं का पता लगाया जाए।

नागरिक आय के लिए उन्होंने अन्यत्र सफलतापूर्वक काम में लयी गई विधियों पर बड़े नगरों के सर्वेक्षण की सिफारिश की। यह कुटुम्बों की जीविका की जाँच द्वारा किया जा सकता है, जिनमें नमूने के कुछ कुटुम्ब लेकर कुछ तो उनके स्वयं के विवरणों द्वारा और कुछ प्रचलित वेतन और पारिश्रमिक की दर के अनुसार उनकी आय का पता लगाया जाए। कर-मुक्त आयों से ऊपर की आयों के लिए आय-कर के आँकड़ों बड़े ही लाभदायक सिद्ध होंगे।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि एक माध्यमिक शहरी गणना कर ली जाए। इन तीनों जाँचों की पूर्ति विद्युत्-शक्ति का उपयोग करने वाली फॅक्ट्रियों, खानों तथा अन्य कुछ उद्योगों की उत्पादन-गणना से की जाएगी। यह बहुत अंशों में नागरिक सर्वेक्षण तथा कुछ अंशों में ग्रामीण सर्वेक्षण की पुनरावृत्ति होगी। लेकिन यह स्वतः बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है और अन्य सर्वेक्षणों की तुलना में सम्पूर्ण जाँच के कुछ भाग का बहुत सही विवरण प्रस्तुत करेगा। ऐसा विश्वास है कि जब सब प्रकार की सामग्री सामने होगी तो शहरी या ग्रामीण उत्पादन-गणना या अन्य विधियों में सम्मिलित आय का अनुमान लगाकर दोहरी गणना के दोष से बचने के तरीके निकाले जा सकेंगे।

१६ (३) उत्पादन-गणना—इंग्लैण्ड की तरह उत्पादन-गणना की व्यवस्था धारा-सभा के अधिनियम द्वारा कर देनी चाहिए, जिसके अन्तर्गत माँगे गए तथ्यों के सम्बन्ध में सूचना देना अनिवार्य हो। कुछ छोटे कारखाने ऐसे हो सकते हैं जिनमें उत्पादन-गणना सरलता से लागू हो सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे काम जो बड़े पैमाने पर चल रहे हों और जिनमें किसी प्रकार की यांत्रिक शक्ति का उपयोग न किया जाता हो—उदाहरण के लिए ईंटें बनाना, मकान बनाना और दूरी बुनना—उत्पादन-गणना-विधि के अन्तर्गत लाने चाहिए। इसी प्रकार 'ज्वान-अधिनियम' के अन्तर्गत

कारखानों और रेलों को भी इसी विधि के अन्तर्गत लाना होगा ।

यद्यपि फ़ैक्ट्रियों में लगे व्यक्ति उद्योगों में लगे व्यक्तियों से अनुपात में बहुत कम हैं, फिर भी निर्यात की दृष्टि से विशेष महत्त्व होने के कारण इस पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है । यह ध्यान में रखना होगा कि फ़ैक्ट्री उद्योग कुछ अंशों में कुटीर उद्योगों को नष्ट करके आगे बढ़ रहा है और इन दोनों को सांख्यिकीय दृष्टि से सम्बद्ध करना होगा । इन उद्योगों की गणना सामग्री की इस प्रकार भी तानिका बनायी जा सकती है कि जब वे फ़ैक्ट्री के आँकड़ों के साथ उपयोग में लायी जाएँ तो इन दोनों संगठनों (उद्योगों) के आर्थिक महत्त्व का भी पता चल जाए ।

ग्रामीण सर्वेक्षण—भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण में यह आवश्यक है कि अन्य आयों के साथ भूमि से प्राप्त आय (चाहे रुपये के रूप में हो या अन्न इत्यादि के रूप में) की जानकारी प्राप्त की जाए और यह देखा जाए कि वह किस तरह मालिकों और मजदूरों के बीच वितरित होती है ।

यह तो सम्भव नहीं है कि भारत के लाखों गावों में सबका विस्तृत सर्वेक्षण किया जा सके । वर्ष बरदास्त होने और इतनी सख्या में जाँच करने वाले व्यक्ति मिलने पर भी यह काम शीघ्र ही नहीं हो सकता ।

राष्ट्रीय आय-सम्बन्धी आधुनिक अनुमान—राष्ट्रीय आय-सम्बन्धी जितने अनुमानों की चर्चा अभी तक की गई है, वे सभी अविभाजित भारत से सम्बन्धित हैं । स्वतन्त्रता के बाद भारत सघ की राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में अनुमान करने की आवश्यकता हुई । अतएव अगस्त, १९४६ में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति (नेशनल इनकम कमेटी) नियुक्त की, जिसके अध्यक्ष प्रो० पी० सी० महालनोबिस थे । फरवरी, १९५४ में समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई । समिति ने उत्पादन-गणना तथा आय-गणना दोनों विधियों के समन्वय से काम किया । कृषि, वन, पशु-पालन, खनन आदि के सम्बन्ध में उत्पादन-गणना-विधि अपनायी गई, जबकि व्यापार, परिवहन, प्रशासन आदि के सम्बन्ध में आय-गणना-विधि अपनायी गई । समिति ने चालू मूल्यों तथा १९४८-४९ के मूल्यों के आधार पर राष्ट्रीय आय के अनुमान प्रस्तुत किए हैं । इन दोनों मूल्यों के आधार पर १९४८-४९, १९४९-५० तथा १९५०-५१ के लिए समिति ने राष्ट्रीय आय के निम्न अनुमान प्रस्तुत किए हैं—

	वास्तविक उत्पत्ति	प्रति व्यक्ति वास्तविक उत्पत्ति
	₹ करोड़ ६० में	₹ करोड़ ६० में
चालू मूल्य	१९४८-४९ के मूल्य	चालू मूल्य १९४८-४९ के मूल्य
१९४८-४९	८,६५०	२४६.९
१९४९-५०	९,०१०	२५३.९
१९५०-५१	९,५३०	२६५.३

चालू मूल्यों तथा १९४८-४९ के मूल्यों पर अनुमानित राष्ट्रीय आय की तुलना से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि १९४८-४९ से १९५०-५१ तक राष्ट्रीय आय में द्रव्य के रूप में तो वृद्धि हुई है, परन्तु वास्तविक आय की वृद्धि नहीं के बराबर है,

जैसा कि १९४८-४९ के मूल्य पर अनुमानित राष्ट्रीय आय के अंकड़ों में स्पष्ट है।

यद्यपि राष्ट्रीय आय के अनुमान के सम्बन्ध में समिति ने डॉ० वी० के० आर० वी० राव की तरह ही उत्पादन-गणना तथा आय-गणना के समन्वय से काम किया है किन्तु समिति के अनुमान अधिक सही हैं। इसका कारण सांख्यिकीय सामग्री का अधिक मात्रा में उपलब्ध होना था। इन विधि से राष्ट्रीय आय का अनुमान करने से एक लाभ यह भी है कि विभाजन के फलस्वरूप हुए प्रादेशिक परिवर्तनों तथा मूल्य-परिवर्तनों के लिए मसौदा कर लेने पर इन अनुमानों की तुलना पुराने अनुमानों में की जा सकती है।^१

१९५१ से भारतवर्ष में राष्ट्रीय आय की वृद्धि के लिए नियोजित विकास द्वारा प्रयत्न हो रहे हैं। प्रथम योजना के अन्त में राष्ट्रीय आय में (चासू मूल्यों पर) १८ प्रतिशत वृद्धि हुई। द्वितीय योजना के अन्त तक २० प्रतिशत वृद्धि की आशा है। १९५१-६१ के बीच राष्ट्रीय आय की वृद्धि का अनुमान ४२ प्रतिशत तथा प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की वृद्धि का अनुमान २० प्रतिशत है।^२

१७ भारतीय दरिद्रता को बढ़ाने वाली उपभोग-सम्बन्धी कुछ भूलें—जा भी वान देश की उत्पादन शक्ति को घटाने में सहायक होती है उसे अवश्य ही भारतीय दरिद्रता का कारण मानना पड़ेगा। निम्न उत्पादन के अनिश्चित बुद्धिहीन उपभोग भी आर्थिक विकास के मार्ग में एक भारी स्कावट है। बुद्धिसंगत उपभोग या 'उपयोगिताओं के नाश' के लिए 'विचारशीलता, बुद्धि और कल्पना' की आवश्यकता है।^३ धन का अपव्यय धनवान को तो बरबाद कर ही सकता है किन्तु साथ ही ऐसी विलासिताओं पर किया गया निरर्थक व्यय, जो जीवन को अधिक समृद्ध और पूर्ण नहीं बनाना, समाज के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। कारण यह है कि इससे इतनी पूंजी और थम आवश्यकताओं के उत्पादन से हटकर विनासिताओं के उत्पादन में लग जाता है। यह कहना गलत होगा कि केवल धनी लोग ही अपव्यय में दोषी हैं। प्रायः सभी दग्ध देशों में गरीब अपनी गरीबी के ही कारण अनेक प्रकार की फिजूलखर्चियाँ करते हैं। इनके विपरीत कुछ वर्गों के व्यक्ति जैसे मध्यवर्गीय लोग और भारवाडी, भित्त-व्यथिता के नाम पर इतने कजूस होते हैं कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति न करके कौड़ी-कौड़ी की दाँत से पकड़ते हैं और जहाँ उन्हें स्वच्छन्दता से खर्च करना चाहिए वहाँ भी कजूसी बरतने से बाज नहीं आते। ऐसा देखा गया है कि पुरानी पद्धति में सन्तानों के लिए धन का एकत्रीकरण किया जाता था ताकि जीवन प्रारम्भ करने में उन्हें अच्छे साधन प्राप्त हों, परन्तु अब इसका स्थान नवीन विचारधारा ले रही है

१. देविप्र राष्ट्रीय आय समिति (अन्तिम रिपोर्ट) फरवरी १९५४, पृ० १, पैरा २, ४।

२. देविप्र तृतीय पंचवर्षीय योजना का आरूप (अध्यायी), पृ० १७।

३. तुलना की लिए, "रूपों को अच्छी तरह पैदा करने की अपेक्षा उसका अनुपयोग करना कठिन काम है। रूपों पैदा करने के तरीके निश्चित हैं, काम निश्चित है, किन्तु व्यर्च करने के लिए व्यय-कला सम्बन्ध है। अब केवल निष्प्रिय आशाकारिता के स्थान पर सदबुद्धि की आवश्यकता है।"—जे० एम० निवल्सन, 'प्रिन्सिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकनॉमी', खण्ड ३, पृ० ४३६।

जिममे अर्जन करने वाले के वर्तमान जीवन को अधिक पूर्ण बनाने का प्रयास किया जाता है और अपनी सुख-समृद्धि के लिए सन्तान स्वयं अपने ऊपर ही निर्भर होती है। सन्तान को निजी पूंजी से युक्त अर्थात् भली भाँति प्रशिक्षित अवश्य करा दिया जाता है।^१

यहाँ भारत की उपभोग-समस्या के सब पहलुओं का विवेचन सम्भव नहीं है। परन्तु इतना तो सच ही है कि यद्यपि भारतीय दरिद्रता बहुत अंश में कम उत्पादन का परिणाम है, फिर भी बुद्धिशील और अग्रवस्थित उपभोग ने भी समस्या को और जटिल बना दिया है। यहाँ हम केवल एक प्रकार के बुद्धिहीन उपभोग का, जिस पर इधर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है वर्णन करेंगे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि शारीरिक स्वास्थ्य, कुशलता तथा भोजन के बीच बड़ा ही गहरा सम्बन्ध है। जर्मन कहावत 'मनुष्य जो खाता है वही बनता है' में बहुत सत्य है। भारतीयों का भोजन स्थानीय परिस्थितियों और प्रथाओं पर निर्भर है। प्रायः जो वस्तुएँ एक स्थान पर उत्पन्न होती हैं वे ही वहाँ के भोजन में सम्मिलित होती हैं। इसको सीमित करने में अनेक धार्मिक एवं सामाजिक बन्धनों ने भी सहायता पहुँचायी है। परिणामतः कुछ प्रान्तों के भोजन में आवश्यकीय पोषिक पदार्थों का अभाव रहता है। भारत की विभिन्न जातियों, यथा मद्रासी, पंजाबी, बंगाली, मराठा आदि, की शारीरिक क्षमता के विभेद को उनके भोजन की विभिन्नता द्वारा समझा जा सकता है और "अब तो इन निश्चित रूप से भोजन के जीव सम्बन्धी मूल्यों में सम्बद्ध कर दिया गया है।" शारीरिक असमता के कारण के रूप में आहार की अपोषित्वता व सम्बन्ध में लफिटनष्ट कर्नल मैक केमिगन द्वारा किये गए अनुसन्धान बड़े शिक्षात्मक हैं तथा उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय आहारों की सापेक्षिक पोषणता को ही अच्छे ढंग से प्रदर्शित किया है। इन अनुसन्धानों से पता चलता है कि चावल, जो भारत में बहुत लोगों का, विशेषकर बंगालियों और मद्रासियों का भोजन है, अनिम्न कोटि का आहार है। इसमें कितने ही महत्वपूर्ण कार्बनिक (आर्गनिक) नमक नहीं हैं तथा अत्यन्त आवश्यक विटामिनो का अभाव है। इनकी तुलना में गेहूँ और मसूर आदि का भोजन करने वाले मूख, पठान और गोरखे अधिक शक्तिशाली होते हैं। चावल के साथ गेहूँ, दूध, मास इत्यादि का सेवन करने से चावल का आहार बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसा कि कृषि आयोग ने कहा था, 'अपोषिक आहार और भुचमरी एक ही बात नहीं है।' ऐसा सम्भव है कि अपोषणता से ग्रस्त एक व्यक्ति शरीर द्वारा प्राप्तानों से पचाए जा सकने की तुलना में अधिक भोजन कर रहा हो, जब कि उसका भोजन भली प्रकार सन्तुलित होने पर कम होता। भोजन में किसी खास पोषक तत्त्व के अभाव में

१. 'रिपोर्ट ऑफ दि कमेटी ऑन नेशनल डेट एण्ड टेकमेशन' पर एन्वू० एन्वू० कोल्न के कथन क लिए देखिए 'जर्नल ऑफ रायल स्टैटिस्टिकल सोसायटी', '१९२७, खण्ड XC, भाग २, पृ० २५६।

बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। उनका होना दरिद्रता^१ का परिचायक नहीं है, और न खाद्यान्न की कमी का ही। अपोपक तत्वों से युक्त भोजन, ऐसा सम्भव है, स्वास्थ्यवर्द्धक एवं भली प्रकार सन्तुलित भोजन से अधिक व्ययशील भी हो सकता है।

१९१५ में कर्नल मेके द्वारा बंगाल और सयुक्त प्रान्त के जेलों के भोजन के सम्बन्ध में की गई खोजों से पता चला कि भोजन जनता के शारीरिक विकास और साधारण सुख का एक महत्त्वपूर्ण कारण है। उन्होंने बताया कि बंगाली की शारीरिक अशक्तता के मूल में उसके भोजन में प्रोटीन-जैसे तत्वों की कमी है। परिवहन के साधनों में सुधार के साथ एक प्रान्त के खाद्यान्नो को उन प्रान्तों में, जहाँ उनकी कमी है, पहुँचाया जा सकता है और इस प्रकार असन्तुलित भोजन की समस्या को हल किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि लोग अपने भोजन में परिवर्तन करने के लिए तैयार हों और उस प्रकार के पौष्टिक आहार की माँग करें जिसकी उनके प्रान्त में कमी है। भोजन के विषय में शिक्षा और जागरूकी से यह काम सरल हो सकता है। कृषि आयोग ने जनता के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए जो सुझाव रखे उनमें एक यह भी है कि देश के मछली के मत्स्य-साधनों का संरक्षण किया जाए। यह एक ऐसा काम है जिसे सरकार, स्थानीय बोर्ड और साधारण रूप से ग्रामीण समुदाय अपने सक्रिय सहयोग से सफल बना सकते हैं। यह इसलिए आवश्यक है कि मछली चावल खाने वाले लोगों के लिए अधिक आहार-मूल्य प्रस्तुत करेगी।^२ जनता के एक विशाल भाग में मछली खाने के प्रति किसी प्रकार का धार्मिक विरोध नहीं है और इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए।

एक जमाना था जब कि इंग्लैण्ड में लेखकों और सुधारकों का यह फंशान था कि वे 'चाय पीने के दुर्गुणों' को बहुत बड़ा-बड़ाकर सामने रखने दें,^३ लेकिन इंग्लिश धार्मिक इसका प्रयोग करते आ रहे हैं और अब तो इसका उपयोग इतना बढ़ गया है कि यह जीवन की आवश्यकताओं में से एक हो गई है। जनमत भी धीरे धीरे बदल गया है और चाय पीने को दुर्गुण बताने के बजाय जल-पान में एक प्रकार की

^१ डाक्टर स्लेटर इन बात की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं कि रहन-सहन के दरजे की वृद्धि से कुछ अर्थ में शारीरिक हानि हुई है। उदाहरण के लिए चावल की मिलों ने रित्रियों को परिश्रम से तो बचाया किन्तु वह परिश्रम शरीर में लिए लाभदायक था। साथ ही चावल की बहुत-कुछ पौष्टिकता भी नष्ट हो गई। एकदम बाहरी मतलब पर जो विटामिन रहता था वह मिलों में नष्ट हो जाता है।—इकनॉमिक क्वार्टरली, 'दिस इन्डिया', पिल्लर की भूमिका से उद्धृत, पृष्ठ २६।

^२ वही, पृष्ठ ४११-१७। आयोग ने यह भी सुझाव रखा कि एक सेण्ट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन की स्थापना की जाए तथा प्रान्तीय सरकारों द्वारा मंगठित अनुसन्धानों का भी उससे नियोजन के दिशा में किया जाए। उन्होंने यह भी सिफारिश की कि पशु-आहार एवं मानवीय आहार में निकट सहयोग स्थापित किया जाए तथा भारत में का गड़ इस प्रकार की खोजों को विदेशों में होने वाली ऐसी ही खोजों से समुक्त किया जाए। समरयाणें इतनी महान् हैं कि समस्त कर्मचारियों (स्टाफ) और प्रायः सामान्य जनता को समस्या के समाधान के लिए काम में लगाना होगा।

^३ हेलेन क्लॉव्हेट, 'दि स्टैण्डर्ड ऑफ लाइफ', पृष्ठ ३०।

शालीनता का चिह्न समझा जाने लगा है। चाय पीना अधिक शराब पीने के दुर्गुणों को दूर करने का एक साधन माना जाने लगा है। डॉ० स्लेटर का मत है कि भारतीय किसान एक बात में बड़ा गरीब है और वह है पेय पदार्थ तथा वह इसके मूल्य को भी नहीं समझता। "जनता का बड़ा भाग गन्दे स्थिर तालाबों, सिंचाई की नालियों या नदियों से प्राप्त गन्दा पानी पीता है जिसमें हर प्रकार की अशुद्धता और गन्दगी मिली रहती है।" डॉ० स्लेटर का मत है कि वर्तमान समय में उबाले हुए पानी के पेय पदार्थों में सबसे सस्ते पेय अर्थात् चाय का प्रचार करने से बहुत लाभ होगा। यह सच है कि जब तक भी पानी पिया जाता है तब तक गन्दा पानी पीने से होने वाली हानियाँ पूरी तरह से दूर नहीं की जा सकती। अर्थात् तो यह होगा कि किसी प्रकार शुद्ध पानी की व्यवस्था की जाए। शराब के स्थान पर तो चाय एक वरदान ही है। हाँ, अधिक चाय पीना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, विशेषकर जब निम्न कोटि की चाय का प्रयोग किया जाता है, जैसी कि भारत की अधिकतर चाय की दुकानों पर मिलती है। अर्थात् चाय की व्यवस्था करने के लिए कुछ कदम उठाना आवश्यक प्रतीत होता है, ताकि गन्दी चाय पीने को न मिले, यद्यपि सबसे अधिक प्रभावपूर्ण कदम तो यह होगा कि जनता की रुचि में ही सुधार किया जाए।

उपभोग के स्वरूप में परिवर्तन तो धीरे-धीरे ही होगा। सामाजिक और धार्मिक भावनाओं से निर्मित उपयोग का स्वरूप सहज ही परिवर्तित नहीं हो सकता। उसके लिए सतुलित आहार और पौष्टिकता के विषय में जनमत को शिक्षित करना होगा।

स्वतन्त्रता के पश्चात् योजनाओं के कारण, देश की अर्थव्यवस्था अर्थात् तीसरी योजना के पहले तीन सालों में राष्ट्रीय आय ६५ प्रतिशत बढ़ गई। तीसरी योजना के पहले तीन सालों में राष्ट्रीय आय ६५ प्रतिशत और प्रति व्यक्ति आय २५ प्रतिशत बढ़ी। इस प्रकार १९६१-६४ में तीसरी पंचवर्षीय योजना के ५ प्रतिशत वार्षिक आय के बढ़ने के मुकाबले में कम रही। निवेश दर १९५१-६१ में लगभग दुगुना हो गया। घरेलू बचत का दर इस समय में ५ प्रतिशत से बढ़कर ८५ प्रतिशत हो गया।

तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाने के समय यह आशा की गई थी कि राष्ट्रीय आय १६ हजार करोड़ रुपया १९६५-६६ से बढ़कर १९७०-७१ में २५ हजार करोड़

१. मम साउथ इण्डियन वित्तोजेउ, पृ० २३२।

२. दक्षिण भारत में प्रचलित कॉफी पीने पर भी इसी प्रकार के आक्षेप किये जाते हैं। शराब पीने पर व्यय और उसके सन्बन्ध में बरती जाने वाली नीति का अन्यत्र विवरण दिया जाएगा (देखिए अध्याय १२)। और भी इसी प्रकार के गलत उपयोग भारतीय अर्थशास्त्र के विचारार्थियों के दिनाग में आर्थो, जैसे शादी और मृत्यु के अपव्यय, सोने-चांदी के गहने बनाने की आदत आदि (अध्याय ११ में आनुचयन स्वभाव का सेचरान देखिए)। आहार की पौष्टिकता के सम्बन्ध में पाठक बंगाल फेरीन इन्वार्थरी कमीशन रिपोर्ट, भाग २, पृ० १०६-४० देखें।

हो जाएगी और पाचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ३३ ३४ हजार करोड़ हो जाएगी। परन्तु तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्य मूल्यांकन को देखकर यह लगता है कि राष्ट्रीय आय १९६५-६६ में १७,४०० करोड़ तक रह जाएगी। इस प्रकार १९६५-६६ में कुल निवेश (Net Investment) राष्ट्रीय आय का १६ प्रतिशत और घरेलू बचत राष्ट्रीय आय का १३ प्रतिशत।

चौथी पंचवर्षीय योजना के उत्पादन लक्ष्य इस प्रकार हैं कि उत्पत्ति दर ६ ५ प्रतिशत रह। उदाहरण के रूप में वार्षिक आय खेती-बाड़ी का ५ प्रतिशत, संगठित उद्योग में ११ प्रतिशत से, लघु उद्योग ८ प्रतिशत से, रेलवे, यातायात तथा संचार ८ प्रतिशत से, बैंको का तथा बीमा ८ प्रतिशत से, वणिज्य (Commerce) तथा नौकरी क्षेत्र में ६ ५ प्रतिशत से।

अध्याय १८

संवहन

१ परिवहन का महत्त्व—उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक भारत में परिवहन के माधन अत्यन्त ही अविकसित थे। उनकी तुलना इंग्लैण्ड की अठारहवीं सदी की परिस्थिति से की जा सकती थी। हाँ, कुछ अच्छी जलवायु की परिस्थितियों के कारण भारत में मड़कों की हानत इंग्लैण्ड की अपेक्षा कुछ अच्छी थी। देश में उस समय तक रेलें नहीं चली थीं तथा उत्तर भारत में मुगल शासकों द्वारा बनाई गई थोड़ी-सी मुख्य सड़कें भी काम देने लायक नहीं रह गई थी।^१ कितनी ही तथाकथित सड़कें भूमि पर गाड़ियों और छकड़ों द्वारा बनाई गई थीं, जिन पर बरसान में किसी भी पहियदार गाड़ी का चलना अनम्भव था। भारवाही पशु ही देश के अन्दर जान के एकमात्र साधन थे। सड़कें मुरझिन नहीं थीं। उन पर ठगों और पिण्डारियों का बोलबाला था। नौगम्य नहर नहीं थी। कुछ स्थान जैसे गंगा और सिन्धु के किनारे के स्थान, अन्य स्थानों की अज्ञात इन दृष्टि में अधिक भाग्यशाली थे। कुल मिलाकर सुखे भीमम में सफर योग्य मैदान, कुछ नौगम्य नदियाँ और थोड़ी सी उनाड हुई सड़कों के कारण उत्तरी भारत में संचार की दशा दक्षिण प्रायद्वीप की अपेक्षा अधिक मनोपजनक थी। दक्षिण में थोड़े पहाड़ों और तल नदियों के कारण परिवहन की स्थिति बड़ी ही असतोपजनक थी। बवल दोनों समुद्री किनारों पर थोड़ी-सी सुविधा थी।

इस अध्याय में हम उस सम्बन्ध में किये गए विभिन्न प्रयासों का संक्षिप्त विवरण देंगे।

विवरण की सुविधा के लिए हम इस चार उप-विभागों में विभाजित करेंगे—

(१) रेलवे, (२) सड़कें, (३) जल-मार्ग, और (४) वायु परिवहन।

रेलवे

भारतीय रेलवे के इतिहास को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—(१) स्वतन्त्रता से पूर्व और (२) स्वतन्त्रता के पश्चात्।

(१) स्वतन्त्रता से पूर्व

२. रेलवे के विकास के प्रधान काल-खण्ड—भारतीय रेलों के इस अवधि के इतिहास

१. 'ड्रासपोर्ट' के लिए परिदहन और 'कन्वूनिवेशन' के लिए संचार शब्द का प्रयोग किया गया है।

२. देखिए, डब्ल्यू० एच० मोरलैण्ड, 'इण्डिया एट दि टैथ ऑफ अकबर', पृष्ठ १६६-६७।

में १० काल-खण्ड स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं—(१) १८४४-६६ पुराना गारण्टी सिस्टम, (२) १८६६-७६ सरकारी निर्माण और प्रबन्ध, (३) १८७६-१९०० नई गारण्टी पद्धति, (४) १९००-१४ तीव्र प्रगति और विकास, (५) १९१४-२१, १९१४-१८ की युद्ध-जनित परिस्थितियों के परिणामस्वरूप रेलवे का विघटन, (६) १९२१-२५ आक्वर्थ कमेटी की रिपोर्ट तथा सरकारी प्रबन्ध और नियन्त्रण, (७) १९२४-२५ से १९२६-३० तक संपरेशन कन्वेंशन और तत्कालीन प्रगति, (८) १९३०-३१ से १९३५-३६ तक अवसाद, १९३६-३६ आंशिक पुनरुत्थान तथा रेलवे जाँच और (९) १९३६ से १९४७ तक ।

३. पुरानी गारण्टी प्रथा—१८४४ में पहली बार रेलवे बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें इंग्लैंड में स्थापित कम्पनियों को ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा निश्चित लाभ के आश्वासन पर भारत में रेलें बनाने देने के प्रश्न पर विचार किया गया । कलकत्ता और बम्बई के पास दो छोटी-छोटी रेलवे बनाने के ठेके दिये गए । ये ठेके क्रमशः ईस्ट इण्डियन रेलवे कम्पनी और ग्रेट इण्डियन पेनिनसुला रेलवे कम्पनी को दिये गए । १८५३ में लार्ड डलहौजी की प्रसिद्ध टिप्पणी ने नीति को निश्चित दिशा प्रदान की । इस टिप्पणी में लार्ड डलहौजी ने रेलों का निर्माण टूक सिस्टम पर करने का प्रस्ताव रखा, ताकि प्रेसीडेसी प्रान्तों में आन्तरिक भाग को उसके प्रधान नगरों एवं बन्दरगाहों में जोड़ दिया जाए तथा एक प्रेसीडेसी का दूसरी प्रेसीडेसी से जोड़ दिया जाए । उन्होंने रेलों के निर्माण से भारत तथा इंग्लैंड को होने वाले सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक लाभों की ओर सकेत किया । रेलों के शीघ्र निर्माण और प्रसार के लाभों में लार्ड डलहौजी ने यह भी देखा कि इससे इंग्लैंड को पूंजी और साहस का भारतीय वस्तु-निर्माण (मेनूफैक्चर्स) और व्यापार में उपयोग होगा । उन्होंने राज्य के नियन्त्रण और निरीक्षण में कम्पनियों द्वारा रेलों के प्रबन्ध और निर्माण को सरकारी निर्माण से अधिक प्राथमिकता दी, क्योंकि उनके विचार में ध्यावसायिक कार्य सरकारी कार्य-क्षेत्र से बाहर थे विशेषकर भारत में, जहाँ हर बात के लिए जनता की सरकार पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति को घटाने की अत्यन्त आवश्यकता है ।

१८५४-६० के बीच डलहौजी की योजना के अनुसार ८ कम्पनियों के साथ भारत के विभिन्न भागों में रेलों के निर्माण और नियन्त्रण का ठेका किया गया ।

लेकिन यह पद्धति सरकार के लिए बड़ी व्ययशील और करदाता के लिए बड़ी भारस्वरूप सिद्ध हुई । कम्पनियाँ अपना व्याज पैदा न कर सकी और सरकार से व्याज अदायगी की माँग करने लगी । १८६६ में रेलवे बजट में १,६६,५०,००० रु० का घाटा हुआ । लार्ड लारेस, जिन्होंने १८६७ में गारण्टी सिस्टम की बड़ी निन्दा की थी तथा ऐसे अन्य आलोचकों ने इस गारण्टी सिस्टम की भी कड़ी आलोचना की और घाटे को कम्पनियों के अपव्यय का परिणाम बताया जिन्हे निर्माण में धन की मितव्ययता का कोई ध्यान ही न था । आक्वर्थ रेलवे समिति ने राय दी कि

१. देखिए, आर० सी० दत्त, 'दि इकनामिक हिस्ट्री ऑफ इण्डिया इन दि विक्टोरियन एज', पृ० ३५५-५६ ।

तात्कालीन परिस्थिति में इंग्लैंड में बने हुए लोगों की कम्पनियों का निर्माण ही उचित था, क्योंकि रेलों का निर्माण अत्यन्त आवश्यक था और भारतीय पूंजी के लज्जशीलता को दखते हुए अंग्रेजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए कुछ सुविधाएँ और आश्वासन देना अत्यन्त आवश्यक था। उनके विपरीत (१८७२ में) विलियम थार्नटन ने ससदीय (पार्लियामेण्टरी) समिति के सामने यह गवाही पेश की कि यदि गारण्टी न दी गई होती तो भी अंग्रेजी पूंजी भारत में रेलों के निर्माण में विनियोजित की जाती, क्योंकि इंग्लैंड की अपार धन-शक्ति दक्षिणी अमेरिका तथा अन्य देशों में विनियोग के साधन ढूँढ रही थी और कोई कारण नहीं दिखाई देना था कि वह लगातार भारत की उपेक्षा करती।^१

४. सरकारी निर्माण और प्रबन्ध (१८६६-७६)—भारत सरकार पुराने गारण्टी सिस्टम पर अधिक दिनों तक चलने के लिए तैयार नहीं थी। इसके विशेष कारण ये—प्रथम, कम्पनियाँ अव्यवस्थी थीं। दूसरे, सरकार का उन पर नियन्त्रण अधूरा था। तीसरे, व्याज-दर और उसे चुकाने का आश्वासन सरकार के लिए काफी खर्चीला सिद्ध हुआ। चौथे, सरकार को कम्पनियों को होने वाले लाभ की भी निकट भविष्य में कोई आशा नहीं दिखाई पड़ी। इसलिए दो परिवर्तन किये गए। कुछ कम्पनियों के सम्बन्ध में, जैसे जी० आई० पी०, सरकार ने मुनाफे के विवरण की व्यवस्था बदल दी। सरकार ने २५ साल के बाद रेलों को खरीदने का अधिकार छोड़ दिया और प्रति छमाही में होने वाले लाभ का आधा हिस्सा माँगने लगी। इससे भी महत्वपूर्ण परिवर्तन—उस समय जब कि राज्य-निर्वाहता का व्यक्तिवादी सिद्धान्त अपने चरम सीमा पर था—तब हुआ जबकि भारत-सचिव (सक्रेटरी ऑफ स्टेट) ने यह निश्चय किया कि सरकार को अपनी साल का पूरा लाभ उठाकर स्वयं मसत में रेलों का निर्माण करना चाहिए। अब १८६६ के बाद कई वर्षों तक सरकार ने स्वयं पूंजी लगाई और नये ठेके नहीं दिये गए। यह निश्चय किया गया कि सरकार द्वारा प्रबन्धित और अधिकृत रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए प्रति वर्ष २० लाख पौण्ड खर्च किया जाएगा तथा सस्ते अर्थात् मीटर गेज पर रेलों का निर्माण होगा। पलने रेलों के निर्माण का कार्य बड़े जोर-शोर से और रुस्ले दाम पर होना लगा, लेकिन लगानार धन की व्यवस्था सवने कठिन समस्या थी। पहले तो सैनिक एवं यौद्धिक कारणों से पंजाब और सिन्ध की लाइनें (जो बाद में नार्थ-वेस्टर्न रेलवे के नाम से प्रतिष्ठित हुईं) मीटर गेज से ब्राड गेज में बदलनी पड़ीं। दूसरे, १८७४ और ७६ के दुर्भिक्ष तथा सीमाप्रान्त और अफगान युद्धों के कारण सरकारी खजाने पर काफी भार पड़ा। इसके अतिरिक्त १८८० के दुर्भिक्ष आयोग ने ५००० मील रेलों का निर्माण अनिवार्य बनाया ताकि देश को दुर्भिक्ष के जगुल से बचाया जा सके। यह तभी सम्भव था जब इतने निर्माण (५००० मील) को मिलाने के लिये रेलवे लाइनें १०,००० मील ही जानी।

१. अलि, भारत सी० दर, 'दि हिन्दा आन् इण्डिया इन दि विन्टरेयन ६-१, पृ० २००।

५ नया गारण्टी सिस्टम (१८७६-१९००)—इस प्रकार सरकारी प्रबन्ध में रेलों के निर्माण की विचारधारा की शक्ति क्षीण होने लगी और रेलवे के इतिहास का एक नया अध्याय प्रारम्भ हुआ। पुरानी प्रथा से भिन्न नई प्रथा की विशेषताएँ निम्न-लिखित हैं—(१) नई कम्पनियों द्वारा बनाई गई लाइनें भारत-सचिव की सम्पत्ति घोषित की गई। भारत-सचिव को २५ वर्ष के बाद, या हर दस वर्ष के बाद दी गई पूंजी को कम्पनियों द्वारा दे देने के बाद पुन ठेका निश्चित करने का अधिकार था, (२) कम्पनियों द्वारा एकत्र धन पर गारण्टी की हुई व्याज-दर पहले की अपेक्षा कम थी। प्रायः यह ३½% थी और (३) सरकार ने लाभ का अधिकार (३) अपने हित के लिए सुरक्षित रखा।

इस प्रकार, नई पद्धति पर निर्मित रेलवे लाइनें प्रारम्भ से ही सरकारी सम्पत्ति थी, यद्यपि कम्पनियों को व्याज-दर की गारण्टी दी गई थी और रेलों बन जाने पर प्रबन्ध भी उन्हीं के हाथ में दिया गया था। इसी प्रकार जब कम्पनियों को पुरानी पद्धति पर दिये गए ठेके समाप्त हो गए तो सरकार ने उन्हें खतम करने का तरीका अपनाया, हालांकि यह तरीका लागू करने में काफी भेद-भाव बरता गया। कई कम्पनियों के ठेके समाप्त होने पर, हालांकि प्रबन्ध कम्पनियों के हाथ में ही रहने दिया गया, सरकार ने विभिन्न तरीकों से अपने लिए लाभदायक शर्तें तय की, जैसे कम्पनी के हिस्से की पूंजी और गारण्टी की हुई व्याज-दर घटा दी तथा लाभ के बटवारे से सम्बन्धित शर्तों में भी परिवर्तन किया।

इस प्रकार सरकार प्रायः सभी टुक लाइनों की मालिक हो गई। रेलों की पूंजी भी सरकारी हो गई, चाहे वह प्रारम्भ में लगाई गई सरकारी पूंजी का परिणाम हो या पुराने ठेकों के समाप्त होने पर सरकार द्वारा प्राप्त कर ली गई हो। घोड़े-से अपवादों को छोड़कर प्रबन्ध प्रायः कम्पनियों के हाथ में ही रखा गया, परन्तु सरकार ने निरीक्षण और कम्पनियों की परिपक्व में एक संचालक की नियुक्ति का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। १९०५ से इजन, डिब्बे (रोलिंग स्टॉक), जन-सुरक्षा, रेल-संयोजन, रेल-सेवाएँ, निराये की दर इत्यादि विषयों के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के द्वारा सरकार उपयुक्त अधिकार का प्रयोग (अर्थात् निरीक्षण) करने लगी। एक कम्पनी को छोड़कर, जिसका ठेका २५ साल के लिए था, शेष कम्पनियों के ठेके भारत सचिव की इच्छानुसार कम्पनियों को बराबर पूंजी देकर समाप्त किये जा सकते थे। बंगाल, नागपुर का ठेका सन् १९५० में समाप्त हुआ और यह आखिरी था। लेकिन सरकार ने लाइन को १ अक्टूबर, १९४४ में ही ले लिया था।

६ रेलों का शीघ्र विस्तार और लाभ का प्रारम्भ (१९००-१९१४)—इस काल की विशिष्टता थी राष्ट्र विकास की जोरदार नीति, जिसने सम्पूर्ण आर्थिक जीवन को प्रभावित किया। १९०८ में जन मैके-समिति ने रेलों के लिए १२,५००,००० पौण्ड वापिक पूंजी व्यय करने का सुझाव रखा—यद्यपि यह सचय समय पर सशोधन के अधीन थे—तो एक नवीन प्रेरणा मिली। यद्यपि सरकार मैके-समिति द्वारा रखे गए सुझावों को कार्यान्वित न कर सकी और न उतना धन ही व्यय कर पाई, किन्तु यह

मानना पडेगा कि पहले की अपेक्षा उमन काफी अधिक धन व्यय किया। इस कालावधि में रेलों की मीलो में दूरी १६०० में २४,७५२ मील से बढ़कर १६१३-१४ में ३४,६५६ मील हो गई और विनियोजित पूंजी ३२६ ५३ करोड़ रुपये से बढ़कर ४६५ ०६ करोड़ रुपये हो गई।

इस कालावधि की दूसरी विशेषता १६०० से रेलों को लाभ होना है। इससे पहले रेलवे से लाभ न होने का कारण अशतः तो कम्पनियों का मितव्ययितारहित निर्माण और पुरानी गारण्टी-कम्पनियों का प्रबन्ध था और अशत यौद्धिक लाइनो, जैसे नार्थ वेस्टर्न रेलवे तथा दुर्भिक्ष में सहायता पहुँचाने के लिए बनाई गई रेलवे लाइनो, का निर्माण था। प्रारम्भिक अवस्था में यातायात की कठिनाइयों के कारण भी लाभ नहीं हुआ। रेलवे के प्रथम ४० वर्षों में सरकार का रेलो द्वारा हुमा घाटा ५८ करोड़ ६० था। इसके बाद सरकार को विनियोजित पूंजी पर लाभ होना प्रारम्भ हो गया। इससे देश के आर्थिक विकास, विशेषकर सिंचाई के विकास, के फलस्वरूप पंजाब और सिन्ध के आर्थिक विकास ने भी सहायता पहुँचाई, जिसके फलस्वरूप फ्रिंटर रेलवे भी सुचारु रूप से संचालित होने लगी। लाभ होने का अन्य कारण पुराने ठेको को बन्द कर अपने लिए लाभदायक शर्तों पर फिर से नया करना था। १६००-१० तक सरकार को लाभ कम ही हुआ, लेकिन १६२४ तक कुल लाभ १०३ करोड़ रुपये था। रेलवे से होने वाला मुनाफा प्रतिवर्ष बढ़ता रहता है, क्योंकि यह देश की कृषि एवं आन्तरिक व्यवसाय और वाणिज्य की अवस्था पर निर्भर करता है। आक्वर्थ-समिति के सुझावों को अपनाने तथा (१६२२-२३) इक्वेप समिति द्वारा सुभाई गई छँटनी (रिट्रैचमेन्ट) के परिणामस्वरूप रेलवे एक सुदृढ़तर आर्थिक आधार पर स्थित हो गई। वास्तविक आय का प्रतिशत (कुल प्राप्त में से चालू खर्च घटाने पर) पूंजी पर लगने वाले व्याज को बिना घटाए, १६१८-१९ में ७ ५ प्रतिशत और १६२१-२२ में २ ६ प्रतिशत था। १६१२ और १६३६ के बीच औसत दर ४ प्रतिशत से थोड़ी अधिक ही थी।

छँटनी समिति (रिट्रैचमेन्ट कमेटी) ने निर्धारित किया कि रेलों का उद्देश्य विनियोजित पूंजी से ५ १/२ प्रतिशत लाभ प्राप्त करना होना चाहिए। सरकार द्वारा घोषित रेल के लाभ के सम्बन्ध में चन्द्रिकाप्रसाद का मत है कि "रेलो से लाभ की घोषणा करते समय स्टॉक के घिसने की व्यवस्था के साधारण व्यावसायिक सिद्धान्त को ध्यान में नहीं रखा गया।" उनके मतानुसार इस प्रकार घोषित मुनाफे में से इस मद के लिए काफी घटाना चाहिए। आक्वर्थ समिति ने भी इस बात को स्वीकार किया है और जोरदार सिफारिश की कि हर रेलवे को अपने स्थायी मार्ग और रोलिंग स्टॉक को फिर से नया करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। रेलों की कार्य-वाही के आर्थिक परिणामों की १२वें अध्याय में विवेचना की गई है।

१. व्यापारिक मन्दी व परिणामस्वरूप १६३०-३१ से १६३६-३७ तक व्याज-दर चुकाने के बाद रेलों को बन्धा धान ठठाना पडा।

७. रेलों का विघटन (१९१४-२१)—आकवर्थ-समिति ने युद्ध के भार से रेलों के विघटन का चित्र निम्न शब्दों में प्रस्तुत किया है, "बीसियों ऐसे पुल हैं जिन पर से आधुनिक भारी बोम्बों से लदी गाड़ियाँ नहीं चल सकती और कितने मील ऐसी रेलें, सैकड़ों ऐसे इंजन और हजारों ऐसे डिब्बे हैं जिनकी बदलने की सही तारीख बहुत दिन पहले बात चुकी है।" ऐसी स्थिति में यदि जनता तथा व्यापारी वर्ग ने वस्तुओं और मनुष्यों के परिवहन में होने वाली असुविधाओं के विरुद्ध शिकायतें की तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। विदेशी कम्पनियों द्वारा रेलों के प्रबन्ध के प्रति जनता अधिकाधिक विरोध कर रही थी और चाहती थी कि जहाँ तक सम्भव हो इनका प्रबन्ध सरकार अपने हाथों में ले।

८. आकवर्थ-समिति (१९२१-२५)—यह भी अनुभव किया जाने लगा कि तत्कालीन रेलवे-बोर्ड रेलवे की नीति-निर्धारण में असफल रहा और रेलवे प्रशासन, विशेषकर किराये और दरों के सम्बन्ध में, प्रभावपूर्ण नियन्त्रण नहीं कर सका। आवश्यकता से अधिक प्रतिबन्ध, कामों का निश्चित क्रम, स्थानीय दशाओं की अज्ञानता और प्राविधिक (टेक्निशियन) एवं विशेषज्ञ कर्मचारियों की कमी इसका कारण थी। रेलवे की भावी आर्थिक नीति को नवीन ढंग से संचालित करने की आवश्यकता भी प्रतीत हो रही थी। ये सब प्रश्न नवम्बर, १९२० में नियुक्त एक विशेष समिति को सौंप दिए गए, जिसके सभापति इंग्लैण्ड के (भूतपूर्व) सर विलियम आकवर्थ थे। इस समिति की नियुक्ति का तात्कालिक कारण ईस्ट इण्डियन रेलवे के सम्बन्धों में कार्यवाही निरूपण करने का प्रश्न था, जो कम्पनी द्वारा प्रबन्धित सरकार की सम्पत्ति थी और जिसका ठेका दिसम्बर, १९१९ को समाप्त होने वाला था। अस्थायी उपचार के रूप में पुराना ठेका १९२६ तक बढ़ा दिया गया और प्रबन्ध के विकल्पों के गुण-दोषों के परीक्षण का काम आकवर्थ जांच-समिति को सौंप दिया गया। विस्तृत जांच के बाद समिति ने १९२१ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर समिति के निष्कर्ष निहित थे। किन्तु इसका सारांश देने के पहले हम सरकारी प्रबन्ध बनाम कम्पनी-प्रबन्ध के विवाद की विवेचना करेंगे।

९. भारत में सरकारी प्रबन्ध के पक्ष में मत—सैद्धान्तिक स्तर पर राज्य-प्रबन्ध का विरोधी मत काफी शक्तिशाली है।^१ लेकिन जब हम किसी खास देश के सम्बन्ध में इसकी विवेचना करते हैं तो सैद्धान्तिक मत अधिक उपयोगी नहीं सिद्ध होता। वस्तुतः किसी भी देश में प्रचलित पद्धति का निर्धारण सैद्धान्तिक कारणों से नहीं बरन् ऐतिहासिक कारणों से किया है। यही कारण है कि भिन्न-भिन्न देश भिन्न-भिन्न प्रकार की पद्धतियों का अनुसरण करके फल-फूल रहे हैं। सरकार अनेक कारण-वशात् रेल-व्यापार अपने हाथ में लेती है, यथा राजनीतिक अथवा व्यक्तिगत साहस की कमी को पूरा करने के लिए, जनता को अधिक सस्ती दर का लाभ देने के लिए अथवा सुविधा प्रदान करने के लिए तथा विभिन्न हितों के प्रति निष्पक्ष व्यवहार करने

१. इस सम्बन्ध में देखिए, डब्ल्यू० एम० आकवर्थ, 'स्टेट रेलवे ऑनरशिप'।

के लिए। ये सब कारण किसी-न-किसी हद तक भारत में सरकार द्वारा रेलों के प्रबन्ध को पुष्टि करते हैं। इसके अतिरिक्त इस देश में यथायंत्त कम्पनी द्वारा प्रबन्ध असम्भव और असुवहाय्य है।

हालांकि कम्पनियाँ, जो अपना रूपया लगाती, अपनी सम्पत्ति का स्वयं प्रबन्ध करती और लाभांश के रूप में परिणाम के आधार पर अपने अधिकारियों की नियुक्ति करती हैं, निश्चय ही सरकार द्वारा प्रबन्धित साहसिक कार्यों की अपेक्षा अधिक कार्य-कुशल होंगी। परन्तु भारत में रेलों का प्रबन्ध करने वाली अंग्रेजी कम्पनियाँ इस अर्थ में कम्पनियाँ नहीं थीं। उनको प्रबन्ध के लिए सौंपी गई सम्पत्ति उनकी अपनी नहीं थी और उनके द्वारा विनियोजित पूँजी भी अपेक्षाकृत कम थी।^१ इस प्रकार की योजना भूतकाल में कभी सफल नहीं हुई और न भविष्य में ही सफल हो सकती है। प्रबन्ध केवल नाम-मात्र के लिए ही कम्पनियों के हाथ में था क्योंकि सरकार अपने को मालिक समझती थी और कम्पनियों को प्रेरक शक्ति के कार्य के लिए कोई स्थान न था। सभी महत्त्वपूर्ण बातें, जैसे नये स्थानों और पदों का निर्माण सरकार के हाथ में था। जहाँ तक अल्पमत रिपोर्ट के इस प्रस्ताव का प्रश्न है कि प्रबन्ध अंग्रेजी कम्पनियों से भारतीय कम्पनियों के हाथ में सौंप दिया जाए, इसके सम्बन्ध में पहला विरोध यह है कि इस काम में भारतीय कम्पनियों का अल्पहित होगा और सरकार प्रभावशाली सांभालदार बनकर आधे से अधिक संचालकों की नियुक्ति करेगी तथा अपना नियन्त्रण यथावत् बनाए रखेगी। सरकार और संचालक-मण्डल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) के बीच कार्य का विभाजन अब भी रहेगा। अधिकारियों की भक्ति नियुक्त करने और तनत्वाह देन वाले संचालक-मण्डल और सरकार के बीच विभाजित रहेंगे और वे पूर्ण समता तथा ध्यान से काम न कर पाएँगे। योग्य व्यापारी संचालक-मण्डल में आने में इन्कार कर देंगे, क्योंकि यहाँ उनकी प्रतिभा को पूरा अवसर न मिलेगा, सरकारी नियन्त्रण और नियमन से उनका हाथ बँधा रहेगा। अतएव कम्पनियों को भारतीय कर देने से ही मामला हल नहीं हो सकता। भारत में सरकारी नियन्त्रण से पूर्णतया मुक्त कम्पनियाँ बनाना भी आसान न था, क्योंकि ऐसी स्थिति में आवश्यक धन मिलना बहुत कठिन होगा। सरकार को हमेशा इस काम में अधिक हिंसा बँटाना पड़ेगा और सरकारी प्रबन्ध कम्पनियों के प्रबन्ध से कहीं अच्छा रहेगा। कम्पनी-प्रबन्ध भारत में कभी भी लोकप्रिय न होगा।

१. इस सम्बन्ध में निम्न मस्यार मजोरवक हैं—मार्च १९४० के अन्त में कुल लगी पूँजी, जिनमें बनती हुई रेलों भी शामिल हैं, ८२५.५६ करोड़ ६० थी। इसमें ७५८.६० करोड़ २० सरकारी रेलवे का था, ६३ ६७ करोड़ भारतीय रियामन, लिमिटेड और कम्पनियों का था। इनमें अधिकारा प्रायः ७२६.७० करोड़ रुपये सरकारी पूँजी थी और केवल १/२५ भाग, अर्थात् २८.८६ करोड़ रुपये कम्पनियों की पूँजी थी। इन मस्यारों में मार्च के अन्त तक का व्यय (३८ ८० करोड़) भी शामिल है जो कि बौद्धिक महत्त्व की लाहना के लिए व्यय किया गया था। देखिए, 'रिपोर्ट ऑन इण्डियन रेलवे' (१९३६-४०), पृष्ठ १, पैरा ३३।

राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह आवश्यक है कि जहाँ तक सम्भव हो रेलवे-निर्माण के लिए जनता धन दे और यह शीघ्रता से तभी सम्भव हो सकता है जबकि प्रबन्ध सरकार के हाथ में हो। फिर भी यदि बाहरी कर्ज लेना ज़रूरी ही हुआ तो ऋण देने वालों की निगाहों में भारत सरकार की प्रतिष्ठा अधिक मूल्यवान् वस्तु होगी। सरकारी प्रबन्ध के पक्ष में एक सबसे बड़ा तर्क यह भी था कि विदेशी कम्पनियों ने जान-बूझकर राष्ट्रीय हितों की चिन्ता नहीं की, बल्कि विरोधी बनी रही। ये सब बुराईयाँ राष्ट्रीय प्रबन्ध से दूर हो जाएँगी। सरकार द्वारा किये गए प्रबन्ध से प्राप्त अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया था कि सरकारी प्रबन्ध किसी भी अंश में कम्पनियों की तुलना में बुरा नहीं है। इन पूँजीपतियों ने न केवल देश के विभिन्न भागों में सामग्री और मनुष्यों के परिवहन पर ही नियन्त्रण रखा, बल्कि प्रधान (ट्रक) और सहायक नई लाइनों तथा दो या अधिक लाइनों के सम्बन्ध को भी नियन्त्रित किया। प्रभाव-क्षेत्र उत्पन्न हो गए थे, जिनसे रेलवे के उचित प्रसार में बाधा उत्पन्न हो रही थी। सरकारी प्रबन्ध में यह दोष दूर हो जाएगा और लाइनों देश के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाएँगी। व्यापारियों और यात्रियों की सुविधाओं का भी अधिक अच्छी तरह ध्यान रखा जाएगा।¹

१९२४-२५ में ईस्ट इण्डिया रेलवे और जी० आई० पी० रेलवे के ठेके खत्म होत के समय यह विवाद और तीव्र हो गया। फरवरी, १९२३ में विषय धारासभा के सामने रखा गया। गैर-सरकारी भारतीयों का मत निश्चित रूप से सरकारी प्रबन्ध के पक्ष में था। परिणामतः इन दोनों रेलवे को सरकार द्वारा खे लिये जान का प्रस्ताव पास हो गया। ये दोनों प्रत्यक्ष सरकारी प्रबन्ध के अन्तर्गत आ गईं। (जनवरी, १९२६ में बर्मा रेलवे भी सरकारी प्रबन्ध में आ गई)। १९३० में सरकार ने दक्षिण पंजाब रेलवे खरीद ली। यह सरकार द्वारा अधिकृत और प्रबन्धित पश्चिमोत्तर रेलवे के अन्तर्गत कर दी गई। बी० बी० एण्ड सी० आई० तथा आसाम बंगाल रेलवे १ जनवरी, १९४२ से सरकार के प्रबन्ध में आ गईं।

१०. साधारण वित्त से रेलवे वित्त का पृथक्करण (१९२४-२५ से १९२६-३०) — आकवर्थ-समिति ने अनेक आधारों पर रेलवे वित्त को साधारण वित्त से अलग करने के लिए जोर दिया। प्रथम, वार्षिक आय व्ययक (बजट) से रेलवे के लाभ व कारण होने वाली सदिग्धता दूर हो जाएगी। रेलों का मुनाफा मौसम और व्यापार के साथ बदलता रहता है, फलतः बजट के अनुमान कई करोड़ रुपये से भी गलत हो सकते हैं। रेलवे के दृष्टिकोण से भी दोनों को अलग करने की आवश्यकता और भी अधिक प्रतीत होती है। केन्द्रीय सरकारी बजट पर निर्भर होने से रेलों को व्यावसायिक रूप से चलाने में बाधा पहुँचती है। ऐसी व्यवस्था, जिसमें यह मान लिया जाता है कि हर

१. जैसा कि श्री एन० बी० मेहता का कहना है अन्तर रेलवे-प्रतिस्पर्धा के अभाव और जायज़ जन-मत्त के प्रभाव ने रेलों के सरकारी नियन्त्रण को एक नैतिक आवश्यकता में परिवर्तित कर दिया है। देखिए, इण्डियन रेलवेज रेवेन्यू रेगुलेशन, पृ० ८१।

वर्ष की ३१ मार्च को काम समाप्त हो जाता है और नय सरकारी वर्ष के साथ फिर प्रारम्भ होता है, रेलवे के विकाम के लिए धातव थी। अतएव केवल व्यावसायिक आधार पर रेलों के सुचारु सञ्चालन की दृष्टि से ही नहीं, वरन् पुरानी पद्धति की अनेक सदिग्धताओं और बुराइयों से सरकार को स्वतन्त्र करने के लिए भी रेलवे वित्त को पृथक् करने का निश्चय किया गया। विषय के महत्त्व को ध्यान में रखकर वित्तम्बर १९२१ में धारासभा में एक प्रस्ताव रखा गया और इन प्रश्न पर विचार करने के लिए दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति की नियुक्ति हुई। समिति ने यह निर्णय किया कि तुरन्त अलग करना व्यावहारिक राजनीति के बाहर की बात होगी। किन्तु उन्हें इस बात की आवश्यकता प्रतीत हुई कि वर्तमान रेलवे लाइनें, जो युद्ध के कारण विगड़ गई थी या उपेक्षित थी, उनको फिर से चालू किया जाए। इस काम के लिए उन्होंने १५० करोड़ रुपये व्यय करने की सिफारिश की जो कि पांच वर्षों में रेलों के सुधार और तृतीय श्रेणी के यात्रियों को अधिक सुविधाएं देने के लिए व्यय किये जाएं। १९२४ में धारासभा ने इसे स्वीकार किया और रेलवे वित्त को अलग करने की योजना को भी मानने के लिए तैयार हो गई। शर्त यह थी कि रेलवे के मुनाफे से प्रति वर्ष एक निश्चित धनराशि सरकारी बजट के लिए दी जाए। यह हिस्सा इस आधार पर तय किया गया कि वर्ष के अन्त में वारिण्ड-सम्बन्धी लाइनों पर लगी पूंजी पर १% (कम्पनियों और रियासतों द्वारा दी गई पूंजी को छोड़कर) तथा लाभ का $\frac{1}{2}$ भाग उसी वर्ष के घाट तथा यौद्धिक लाइनों पर लगी पूंजी के ब्याज को घटाकर सरकार को दिया गया। धारासभा ने यह तय किया कि इस प्रकार निश्चित धनराशि का देन के पश्चात् यदि रेलवे सुरक्षित कोष (रिजर्व) को हस्तान्तरित किया जान वाला मुनाफा ३ करोड़ से अधिक हो तो इस अधिक धन का $\frac{1}{3}$ साधारण आगम (रेवेन्यू) में दे दिया जाए। रेलवे सुरक्षित कोष (रिजर्व) का उपयोग वार्षिक अशदान, बकाया अपकर्ष (डिप्रेसिजेशन) पूरा करने और साधारण रूप से रेलवे की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए था।

११ अक्टूबर काल (१९३०-३१ से १९३५-३६) तथा वेजवुड रेलवे जांच-समिति (१९३६-३७) — १९३०-३१ से १९३५-३६ तक का समय रेलवे के इतिहास में अक्टूबर का समय है। रेलवे को वार्षिक आय घटनी चली गई। परिणाम यह हुआ कि बजट को संतुलित करने के लिए सुरक्षित कोष और अपकर्ष कोष (डिप्रेसिजेशन फण्ड) को महारा लेना पड़ा तथा सामान्य बजट के प्रति अशदान भी बन्द करना पड़ा। इस अवधि में रेलवे की आर्थिक दशा में होने वाले भयंकर ह्रास न विषय की जांच-पड़ताल अनिवार्य कर दी। सर ऑटो नेमियर (एक द्वितीय विशेषज्ञ, जो १९३६ में भारत आये) ने रेलवे के खर्च में सम्पूर्ण परिवर्तन की राय दी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट, '१९३५ के मविधान के अन्तर्गत प्राप्ति और केन्द्र में वित्तीय व्यवस्था' में परिवर्तन के विभिन्न साधनों के संयोजन पर जोर दिया।^१

१. इण्डियन फाइनेंशियल इन्वेंचरी (नेमियर) रिपोर्ट, पैरा ३१-३३ में प्रकाशित (पृष्ठ १०१)।

जून, १९३७ में प्रकाशित समिति की रिपोर्ट में रेलवे के हर पटलू को स्पष्ट करने वाले ऐसे सुझाव हैं जिनसे उसकी कार्यकुशलता और आर्थिक परिस्थिति दोनों ही सुधारी जा सकती हैं। इसने पोप-समिति, जिसने १९३२-३४ में मितव्ययिता और कुशलता बढ़ाने की दृष्टि से रेलवे के हर महत्वपूर्ण कार्य का विस्तृत विश्लेषण किया था, के सब सुझावों का समर्थन किया तथा एक पर्याप्त अपकर्ष-कोष (डिप्रेसियेशन फण्ड) की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके विचार में ३० करोड़ रुपये की वचत साधारणतः ज्यादा नहीं कही जा सकती। इसने रेलवे व साधारण सुरक्षित कोष के निर्माण की सिफारिश की, इससे ऋण ली हुई पूंजी और व्याज को चुकता किया जा सकेगा।^१

समिति ने रेलों की अपनी लोकप्रियता बढ़ाने और जनता से अपने सम्बन्ध अच्छे करने के सुझाव रखे। इस काम के लिए समाचारपत्रों से घनिष्ठता बढ़ाने पर जोर दिया। समिति ने अनेक रेलों की एक में मिलाने पर अधिक जोर नहीं दिया, क्योंकि इससे प्रबन्ध और प्रशासन में अशुविधा उत्पन्न होती।^२ वेजबुड-समिति की रेल-सड़क संयोजन, तथा किराये की दर में सशोधन की सिफारिशों की चर्चा अन्य भागों में की गई है।

१२ द्वितीय विश्व-युद्ध-काल और उसके बाद (१९३९ से १९४७)—द्वितीय विश्व युद्ध का एक परिणाम यह हुआ कि यातायात में काफी वृद्धि हो गई। फलतः परिवहन-क्षमता पर असाधारण भार पड़ा। समृद्धि काल के कारण रेलवे इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए थोड़ी-बहुत सुसज्जित थी। रेलवे के निर्माण में बड़ा रुपया खर्च किया गया था। कार्य विधि में सुधार भी किया गया तथा अच्छे शक्तिशाली इंजन भी मंगाए गए थे। १९४१ के अपने बजट भाषण में सर गुथरी रसेल, रेलवे चीफ कमिश्नर न अनुमान लगाया कि आवश्यकता पड़ने पर अपनी वर्तमान कार्य-क्षमता से रेलवे बौयला को छोड़कर समुद्र-तट के तमाम यातायात को संभाल सकती है।^३

१५ अगस्त, १९४७ को स्वतन्त्रता प्राप्ति और विभाजन ने समस्याओं के प्रकार और रूप को ही बदल दिया। देश के विभाजन के साथ ही रेलवे और तत्सम्बन्धी अन्य सम्पत्ति का भी विभाजन हुआ।

१३ राज्य और रेलवे के बीच सम्बन्धों की विविधता—नियन्त्रण और स्वामित्व की दृष्टि से राज्य और रेलों के बीच विभिन्न सम्बन्ध रहे हैं। मुख्य लाइनों में से चार लाइनों सरकार के स्वामित्व में थी (नार्थ-वेस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न बंगाल रेलवे, ईस्ट इन्डियन रेलवे जिसमें १ जुलाई, १९२९ को अवध और रुहेलखण्ड रेलवे मिला दी गई थी और चौथी जी० आई० पी० रेलवे)। अन्य पांच का स्वामित्व तो सरकार के

१ रिपोर्ट, पैरा २०६, २१०-११।

२ इन्डियन रेलवे इन्क्वायरी रिपोर्ट, अध्याय १२-२३।

३ देखिए, रेलवे बजट १९४०-४१, पैरा २।

४ देखिए, रिपोर्ट ऑन इन्डियन रेलवेज (१९३८-३९) भाग १, अनुसूची बी।

पास था किन्तु वे सरकार की तरफ से वैयक्तिक कम्पनियों द्वारा प्रवर्धित थी जिन्हें सरकार व्याज की सुरक्षा दे चुकी थी (बी० वी० एण्ड सी० आई० रेलवे और एम० एण्ड एस० एम०, आसाम-बंगाल रेलवे, बंगाल-नागपुर रेलवे और एल० आई० रेलवे) । दो महत्वपूर्ण लाइनें (बंगाल एण्ड नार्थ वेस्टर्न रेलवे तथा हटेलखण्ड-कूमायूं रेलवे) तथा कम महत्व की अनेक लाइनें व्यक्तिगत कम्पनियों की सम्पत्ति थी । इनमें से कुछ तो स्वयं कम्पनियों द्वारा तथा कुछ सरकार द्वारा शासित होती थी । कुछ लाइनें देशी रियासतों के अधीन थी जैसे वाड़ी से हैदराबाद (हैदराबाद राज्य), खण्डवा से इन्दौर (होल्कर राज्य) तथा इन्दौर से नीमच-उज्जैन होते हुए (ग्वालियर राज्य) कितनी ही छोटी-छोटी लाइनें तो जिला बोर्डों के स्वामित्व में थी या उन्हें इन बोर्डों द्वारा व्याज की गारन्टी प्राप्त थी ।

अब लगभग सभी रेलें सरकारी अधिकार और प्रबन्ध के अन्तर्गत हैं ।^१

(२) स्वतन्त्रता के पश्चात्

१९४७ में विभाजन के फलस्वरूप रेलवे की पूंजी, रोलिंग स्टॉक, कारखाने आदि का बँटवारा रेडक्लिफ-निर्णय के अनुसार रेलवे भण्डार उपसमिति (रेलवे स्टोर्स सब-कमिटी) ने तय किया । कुल रेलमार्ग का लगभग १६ प्रतिशत पाकिस्तान के हिस्से में आया । वित्तीय देयता में भी पाकिस्तान का भाग लगभग १६ प्रतिशत ही रहा । पाकिस्तान की देयता लगभग १५० करोड़ २० तथा भारत की देयता ६६० करोड़ ६० थी (१९४७-४८ के बजट के आधार पर) ।

१९४६ में भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से रेलों के पुनर्स्थापन के लिए, ३४ करोड़ डालर का ऋण प्राप्त किया । इस ऋण की सहायता से ४१० इञ्च, २६ वायलर तथा अन्य भागों की खरीद के लिए आर्डर दिये गए । इसके अलावा भारत सरकार ने अपने साधनों से भी इञ्च, डिब्बे तथा अन्य रोलिंग स्टॉक पर्याप्त मात्रा में खरीदे । दिसम्बर, १९५२ में भारत सरकार ने यू० स० टेक्नीकल मिशन के साथ रेलों के पुनर्स्थापन के लिए एक और समझौता किया ।

अगस्त १९४६ में भारत में ३७ रेल-व्यवस्थाएँ (रेलवे सिस्टम) थीं । रेलवे सगठनों की अखिलता व्यवधानित और अकुशल प्रबन्ध को जन्म देती है । अतएव भारतीय रेल व्यवस्था को पुनः नये ढंगों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता प्रतीत हुई । रेल-व्यवस्था के पुनर्गठन के मूल में यही सत्य निहित था । इसके अतिरिक्त पुनर्गठन के अन्तर्गत अत्यन्त हेतुमूर्त उच्चतम क्षमता से सम्पन्न हो सकेगा तथा रेलवे की अद्यतन प्रविधियों के अनुसरण में समर्थ होगा । अन्तिम पुनर्गठन से कोई गतिरोध और अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होगी ।^२ इन सिद्धान्तों के आधार पर रेलवे को विभिन्न वर्गों में विभाजित करने की योजना १५ अप्रैल, १९५२ को तैयार हो गई थी । प्रारम्भ में

१. सरकारी रेलवे की लम्बाई ३४,१८१.०५ मील तथा गैर-सरकारी रेलवे की लम्बाई ७०२.८० मील है । देखिए, टाइम्स ऑफ इण्डिया हाइरेकॉर्टी एण्ड इअर बुक, १९६०, पृ० २६० ।

२. देखिए, सेकण्ड फाईव ईअर प्लान, पृ० ४६० ।

रेलो को ६ वर्गों में विभाजित करने की योजना थी, किन्तु बाद में दो वर्ग और बनाए गए। इस समय रेलवे साठ वर्गों में विभाजित है। ये वर्ग निम्नलिखित हैं तथा बोधक में इनके सगठन की तिथि और हेडक्वार्टर का नाम दिया हुआ है - (१) दक्षिण-क्षेत्र (१४ अप्रैल, १९५१, मद्रास), (२) मध्य-क्षेत्र (५ नवम्बर, १९५१, बम्बई), (३) पश्चिमी क्षेत्र (५ नवम्बर, १९५१, बम्बई), (४) उत्तरी क्षेत्र (१४ अप्रैल, १९५२, दिल्ली), (५) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (१४ अप्रैल, १९५२, गोरखपुर), (६) उत्तर-पूर्वी सीमा-क्षेत्र (१५ जनवरी, १९५८, पंहु), (७) पूर्वी-क्षेत्र (१ अगस्त, १९५५, कलकत्ता), (८) दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र (१ अगस्त, १९५५, कलकत्ता)। रेलों के इस वर्गीकरण के विरुद्ध मुख्यतः दो आपत्तियाँ की गईं। एक तो यह कि कुछ क्षेत्रों के अन्तर्गत रेल की लम्बाई इतनी अधिक है कि प्रशासकीय कठिनाइयाँ घटने के बजाय बढ़ जाएँगी, ऐसी आशा थी। दूसरे यह कि रेल-परिचालन में रकावटें पैदा हो जाएँगी। वर्गीकरण के पश्चात् वैजवाड़ा और मुगलसराय तथा अन्य स्थानों में टिकावटों का अनुभव भी किया गया, किन्तु सरकारी दृष्टिकोण यह रहा कि ऐसी कठिनाइयाँ वर्गीकरण का परिणाम नहीं थीं। इन आपत्तियों के विरुद्ध सरकार ने यही कहा कि वर्गीकरण की योजना से (१) प्रशासन और वित्तीय नियन्त्रण में सुधार, (२) प्रबन्ध में मितव्ययिता और कार्यक्षमता में वृद्धि, तथा (३) परिचालन-व्यवस्थाओं और कर्मशाला (वर्कशाप, का युक्तीकरण होगा। वर्गीकरण विवादास्पद विषय नहीं था। अनेक समितियों ने, यथा एकवर्ध-समिति, बेजबुड-समिति, सभी ने सिफारिश की थी। वर्गीकरण के विरुद्ध केवल यही कहा जा सकता था कि यदि यह योजना कुछ समय बाद लागू की जाती तो अधिक अचढ़ा होना। कृंजूरू समिति (१९४७-४८)^१ का यही मत था। वर्गीकरण हो जाने के बाद अब यह विवाद का विषय नहीं रहा है।

१९५१ में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हुई। इन योजना में रेलवे के पुन-स्थापन और विस्तार के ऊपर ४०३ ७३ करोड़ ६० व्यय किये गए। प्रथम योजना का व्यय मुख्यतः चल स्टाक तथा स्थिर सम्पत्ति का पुनस्थापन और नवीकरण, उत्पादन और विकास-सम्बन्धी योजनाओं से उत्पन्न नई आवश्यकताओं की पूर्ति तथा यात्रा करने वाली जनता तथा रेलवे कर्मचारियों को सुविधाएँ प्रदान करना था। योजनावधि में द्वितीय महायुद्ध में उखाड़ी गई लाइनों में से ४३० मील लाइन फिर से बिछा दी गई तथा ३०० मील लम्बी लाइनों का निर्माण हुआ। योजना के प्रारम्भ में भारतीय रेलवे के पास ८,२०६ इजन, १६,२२५ कोचिंग डिब्बे तथा २२२,४४१ माल के डिब्बे थे। इनमें से २,११२ इजन, ७,०११ कोचिंग डिब्बे तथा तथा ३६,५८४ मालगाड़ी के डिब्बे अपनी आयु पूरी कर चुके थे और उन्हें बदलना आवश्यक था। प्रथम योजना के अन्त तक प्राप्त इजन, कोचिंग के डिब्बे तथा माल के डिब्बों की संख्या क्रमशः १,५८६, ४,८३७

१. कृंजूरू-समिति का मत था कि रेलवे का पुनर्गठन गतिरोध और अव्यवस्था को जन्म देगा। समिति ने सिफारिश की थी कि पुनर्गठन की योजना कुछ वर्षों के लिए कार्यान्वित न की जाए। किन्तु ईना ऊपर कहा गया है, सरकारान्त इसे मानने को तैयार नहीं था।

तथा ६१, ७१३ रही होगी ।

द्वितीय योजना में प्रधानतः रेल-व्यवस्था के विस्तार पर जोर दिया गया ताकि व्यापार और उद्योग की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके । १९५८ में रेलवे को विद्द वैक से ४०.५ करोड़ रु० का ऋण प्राप्त हुआ । ३१ मार्च १९५९ तक इस ऋण का उपयोग चल-स्टाक तथा रेलवे सम्बन्धी अन्य साज-सामान खरीदने के लिए किया जा चुका था । १९५८-५९ में रेलवे ने ३६९ इञ्च (जिनमें ७१ डीजेल के इञ्च भी शामिल हैं), १६४३ कोचिंग के डिब्बे तथा १३,४२२ माल-गाड़ी के डिब्बे प्राप्त किए ।

द्वितीय योजना में १४४२ मील लम्बी रेल की लाइन का विद्युतीकरण प्रस्तावित था । बाद में इस लक्ष्य में परिवर्तन किया गया । परिवर्तन का कारण शक्ति की कमी तथा विदेशी विनिमय की कठिमाइयाँ थीं । हावडा-वर्दवान की मुख्य लाइन व शोरापुली-तारकेश्वर ब्रान्च लाइन पर ८८ मील की दूरी के लिए विद्युतीकरण हो चुका है । १९५८-५९ तक इस क्षेत्र में ११२ विजली से चलने वाली रेलें चलने लगी थीं । पूर्वी तथा दक्षिणी-पूर्वी रेलवे की मुख्य लाइन पर विद्युतीकरण का काम चालू था ।

१४. रेलवे के आर्थिक प्रभाव—रेलवे या अन्य दूरी को नष्ट करने वाले साधनों के लाभ इतने स्पष्ट हैं कि उन्हें गिनाने की आवश्यकता नहीं । राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इनका बड़ा ही महत्त्व है । कुशल प्रशासन, सुरक्षा, दुर्भिक्ष-सहायता, व्यापार और उद्योग का विकास, प्राकृतिक साधनों का अधिक अच्छा उपयोग, जनमख्या का सम-विभाजन, ये सब रेलों पर निर्भर हैं । कस्बों और बन्दरगाहों का विकास भी बहुत हद तक रेलवे के कारण ही सम्भव हुआ । रेलों द्वारा सफाई और कृषि-मुवार में भी बड़ी सहायता पहुँच सकती है । अन्त में सरकारी धाय प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से बढ़ती है । प्रत्यक्ष रूप से सरकार रेलवे के मुनाफे में हिस्सेदार है । परोक्ष रूप से रेलों से देश की सम्पत्ति में वृद्धि होने से जनता की कर देन की शक्ति बढ़ जाती है ।

१५. रेलों के और अधिक विकास की आवश्यकता—प्रारम्भ में रेलों से होने वाली अनेक हानियों का कारण देश में रेलों का निर्माण न होकर निर्माण की पद्धति और उसके सम्बन्ध में दिखाई गई अनुचित जल्दबाजी है । यह बात बहुत जल्द ही है कि कुछ प्रविन्धों के अन्तर्गत देश में रेलों का विकास यथासम्भव शीघ्रता से हो । इससे देश का व्यावसायिक और औद्योगिक विकास सरलता से होगा । यह बात तो स्पष्ट है कि देश में अभी रेलवे का पूर्ण प्रसार नहीं हो पाया है । प्रमाण के लिए हम यूरोप को ले सकते हैं । यूरोप का क्षेत्रफल (रूस को निकाल देने पर) १,६९०,००० वर्गमील है, जिसमें १९०,००० मील रेल है । भारत का क्षेत्रफल १२,५९,७९७ वर्ग मील है, लेकिन इनमें केवल ३५,०८१ मील रेलवे लाइन है ।

रेलवे प्रशासन की समस्याएँ

१. स्वतन्त्रता से पूर्व—हम पहले रेलवे प्रशासन की उन समस्याओं की चर्चा

करेंगे जो १८४४-१९४७ के काल में विचारणीय थी।

१६. रेलवे दर-नीति—एक बड़ी पुरानी शिकायत थी कि रेलवे की दर मूलतः आर्थिक लाभ के सिद्धान्त पर आधारित है और यूरोपीय सौदागरों को फायदा तथा भारतीय उद्योग और साहस के विकास को बाधा पहुँचाती है। १९१५ में सर इब्राहीम रहीम-तुल्ला ने धारासभा (इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल) में इसका जिक्र किया। उद्योग और वित्त-आयोग के सामने भी कितने लोगों ने इस बात की गवाही दी। आकवर्ध-समिति ने भी इस ओर ध्यान आकृष्ट किया। एक खास शिकायत यह थी कि दरें इस प्रकार रखी गई थी कि वे आन्तरिक यातायात की अपेक्षा अन्दर ने बन्दरगाहों तक आने वाले और बन्दरगाहों से अन्दर जाने वाले यातायात को प्रोत्साहन देने वाली थी। इससे बच्चे माल के निर्यात और विदेशी निर्मित वस्तुओं के आयात को प्रोत्साहन मिलता था।^१ भारतीय व्यापारियों की शिकायत थी कि उन्हें देश के विभिन्न भागों से बच्चा माल भंगाने और विभिन्न बाजारों में तैयार माल भेजने में काफी ऊँची दर देनी पड़ती थी। अवरोधक दर प्रथा (ब्लॉक रेट सिस्टम)^२ से भी काफी असन्तोष था क्योंकि इससे यातायात का कृत्रिम विकीरण होता था जिससे उद्योग और व्यापार दोनों को असुविधा होती थी। रेलवे-दर का एक प्रभाव यह भी था कि भूतकाल में प्रायः उद्योग बन्दरगाहों के पास केन्द्रित होने लगे थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें भी कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

जैसा कि अर्थ-आयोग (फिस्कल कमीशन) ने स्वीकार किया था, भारतीय उद्योगों के साथ किये गए अनुचित व्यवहार की बात निराधार नहीं थी। व्यवहार में रेलों को अपने ढंग से दर निश्चित करने की स्वतन्त्रता थी। यद्यपि यह स्वतन्त्रता रेलवे बोर्ड द्वारा दी गई स्वीकृतियों के अन्तर्गत ही थी, किन्तु उन्हें विशिष्ट मामलों विशेषतः बर्ग में रखने की स्वतन्त्रता थी। प्रश्न का गम्भीर अध्ययन करने के उपरान्त उद्योग-आयोग ने यह निष्कर्ष की कि एक प्रकार की सामग्री को उतनी ही दूरी पर ले जाने का किराया बराबर होना चाहिए, नाकि बच्चा माल जहाँ तक सम्भव हो सके निर्यात के पूर्व निम्न सामग्री की दशा में हो जाए। उन्होंने यह भी सुझाव रखा कि एक से अधिक लाइनों पर चलने वाली वस्तु की पूरी दूरी का किराया एक ही दर से एक ही बार ले लिया जाए। अर्थ आयोग ने इन सुझावों को स्वीकार किया और यह भी सुझाव रखा कि नये उद्योगों के लिए कुछ वर्षों तक विशेष रूप से रिआयती दर देनी चाहिए और अन्य उद्योगों को भी विशेष रिआयत दी जाए, यदि वे अपने को इस योग्य सिद्ध कर सकें। कृषि-आयोग, जिसने रेलवे दर से कृषि-विक्रम पर पड़ने वाले प्रभाव की जाँच की, ने यह सुझाव रखा कि कृषि विभाग और

१. फिस्कल कमीशन रिपोर्ट, पैरा १२७।

२. 'ब्लॉक रेट' का मतलब है कि थोड़ी दूरी के लिए अधिक दर से किराया लेना। यह अकरण के निकट किसी स्टेशन से उम अकरण तक और वहाँ से दूसरी रेलवे पर अधिक दूर तक जाने वाले यातायात पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य यातायात को प्रतिद्वन्दी लाइनों पर जाने से रोकना तथा एक लाइन तक ही सीमित रखना है।

रेलवे-विभाग के बीच अधिक सम्पर्क स्थापित किया जाए तथा कृत्रिम खादों, ईंधन, चारा और दूध देने वाले पशुओं के यातायात को विशेष सुविधा दी जाए। उन्होंने कृषि के श्रीजारों के कच्चे मान और श्रीजारों के परिवहन की दर को फिग से जांच कराने की सिफारिश की।^१

१९२२ में आकवर्थ-समिति के सुझाव के अनुसार एक अध्यक्ष, एक व्यवसायी हितो का प्रतिनिधि सदस्य, दूसरा रेलवे का प्रतिनिधि सदस्य, इनकी एक दर परामर्शदात्री समिति (रेट्स एडावइजरी कमेटी) का निर्माण किया गया। इसे जांच करके निम्न विषयों पर सुझाव देने के लिए कहा गया

(१) अनुचित अधिमान की शिकायतों को जांच। (२) यह शिकायत की कि रेलवे कम्पनिया व्यापार को पूरी सुविधा देने का कार्य नहीं कर रही हैं तथा अन्तिम स्थान-सम्बन्धी (टर्मिनल्स) भंगडे। (३) य शिकायतें कि दरें उचित नहीं हैं। (४) मुकसान पहुँचाने या पहुँचाने वाली सामग्री के परिवेष्टन (पैकिंग) से सम्बन्धित शर्तों के औचित्य सम्बन्धी शिकायतें। (५) किसी दर से सम्बन्धित परिवेष्टन-सम्बन्धी शिकायतें। जैसी कि वेजवुड जांच समिति ने सिफारिश की थी, १९४० में समिति की कार्य-विधि अधिक सरल कर दी गई।

१७ प्रभावपूर्ण निरीक्षण का प्रभाव—रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन आकवर्थ-समिति ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन पर जोर दिया था ताकि इसे एक सन्तोषजनक माध्यम बनाया जा सके जिससे भारत सरकार सम्पूर्ण रेल व्यवस्था के ऊपर प्रभावपूर्ण निरीक्षण सरलता से कर सके। पुनर्गठित रेलवे बोर्ड की संरचना एक प्रधानायुक्त (चौफ कमिश्नर), एक वित्तायुक्त और तीन सदस्यों से मिलकर हुई।^२ आकवर्थ-समिति की सिफारिश थी कि रेलों तीन क्षेत्रों में विभाजित हो, जिनमें से प्रत्येक क्षेत्र एक कमिश्नर के अधीन हो। इसके स्थान पर विषय के आधार पर काम को विभाजित करने का ढंग अपनाया गया। एक सदस्य प्राविधिक (टेकनिकल) विषयों का काम देखता है, दूसरा साधारण प्रशासन कर्मचारी और यातायात-सम्बन्धी विषयों का काम देखता है और तीसरा वित्तायुक्त, जो कि वित्त विभाग का प्रतिनिधि होता है, सभी आर्थिक पहलुओं की दखल-रेख करता है। बोर्ड की सहायता के लिए पांच सचालक होते हैं। (सिविल इंजीनियरिंग, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, यातायात, वित्त और संस्थापन—एस्टैब्लिशमेंट) जो कि प्रधानायुक्त और सदस्यों के दिन-प्रतिदिन के काम में सहायता पहुँचाते हैं ताकि वे अपना ध्यान रेलवे-नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कन्द्रित कर सकें और विभिन्न रेलों पर यात्रा करके स्थानीय सरकारों से पहले की अपेक्षा कहीं अधिक उपविनयत सम्पर्क स्थापित कर सकें।

१८ भारतीयकरण की समस्या—आकवर्थ-समिति और ली आयोग (१९२३) दोनों ने उच्च रेलवे सेवाओं के लिए भारतीयों को प्रशिक्षित करने की सुविधाओं के प्रसार की सिफारिश की थी। ली-आयोग ने ऐसे ७५ प्रतिशत पदों के लिए प्रशिक्षण की

१ कृषि-आयोग-रिपोर्ट, पृ० ३७७-६।

२ अतिरिक्त सुझावों के लिए देखिए, शाइड्यन रेलवे इनक्वायरी रिपोर्ट (१९३७), पैरा ७८-६०

भिकारिश की। सरकार ने यह बात स्वीकार कर ली और प्रशिक्षण-सुविधाओं के प्रसार के लिए कदम उठाया। बेजबुड-समिति की रिपोर्ट पर विवाद होते समय भारत सरकार ने रेलवे-सेवाओं के भारतीयकरण की बात को पुनः दुहराया। अब यूरोपीयों को नौकरियाँ मिलना बन्द हो गया है और भारतीयकरण का प्रश्न भी राज-सत्ता भारतीय हाथों में हस्तान्तरित हो जाने से समाप्त हो गया है।

रेलवे की समस्याएँ

२ स्वतन्त्रता के बाद—स्वतन्त्रता के बाद रेलवे की समस्याओं का रूप ही बदल गया। कुछ समस्याएँ जैसे, भारतीयकरण की समस्या, अप्रासंगिक हो गईं तथा कुछ अन्य समस्याएँ अधिक महत्वपूर्ण ही उठीं। इस समय भारतीय रेलवे के समक्ष निम्न मुख्य समस्याएँ हैं

१ रेल चलाने के लिए शक्ति-उत्पादन के हेतु अधिकांशतः कोयला प्रयुक्त होता है। भारत में अच्छी कोटि के कोयले के कुल निक्षेप सीमित हैं तथा दीर्घकालीन प्रयोग की दृष्टि से वे लोहा और इस्पात जैसे आधारभूत उद्योग के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। इन उद्योगों का भविष्य निम्नकोटि के कोयले के सुधार और तदनन्तर इनके उपयोग पर ही आधारित है। अतएव रेलवे में कोयले का प्रयोग निम्नतम करना आवश्यक है। इस दृष्टि से भारत में बिजली और डीजेल से चलने वाली रेलों की व्यवस्था करना आवश्यक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस दिशा में प्रयत्न किये गए हैं जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं।

२ रेलवे की दुर्घटनाओं से सम्बन्धित दूसरी महत्वपूर्ण समस्या है। ये दुर्घटनाएँ अनेक प्रकार की होती हैं, यथा टक्कर, पटरी से उतरना, गाड़ी से जानवरो का कटना, सम-पार पर गाड़ी का सड़क यातायात से टकराना, गाड़ी का दूसरी स्कावटो से टकरा जाना आदि। १९५७-५८, १९५८-५९ तथा १९५९-६० में दुर्घटनाओं की संख्या क्रमशः ९,०११, ९,०७१ तथा ८,९१६ थीं। १९५९-६० में इस प्रकार कुल दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आ गई। किन्तु इस वर्ष रेल-पथ से उतरने और रेल-पथ की खराबी के कारण हुई दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गई। टक्कर, गाड़ी का पटरी से उतरना, गाड़ी का सम-पार पर सड़क यातायात से टकराना, गाड़ी में आग लगना—इस प्रकार की कुल १,१२४ दुर्घटनाएँ रेलवे कर्मचारियों की असावधानी से हुईं जबकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की कुल संख्या (१९५९-६०) में २,११९ थीं। अतएव उपर्युक्त प्रकार की लगभग ५०% घटनाओं के लिए रेलवे कर्मचारी ही उत्तरदायी थे। यह कहा जा सकता है कि इन घटनाओं को कम करना तो सरकार के ही हाथ में है। उपाय के रूप में सरकार दुर्घटना की कारण रूपा भूलों के सम्बन्ध में रेलवे कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए जनरल मैनेजरों तथा परिचालन अधीक्षकों की प्रावधिक बैठक में बराबर जोर देती रही है। दुर्घटना के सरकारी निरीक्षकों ने १९५९-६० में जिन दुर्घटनाओं की जाँच की, उस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उन्होंने बहुत-से सुझाव दिये। तदनुसार रेल प्रशासनो को हिदायतें भी दी गईं। दुर्घटनाओं को कम करने की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण

चात तो इन हिदायतो का पालन है । सम-वार के पाटको की दुर्घटनाओं, रेल पथ म खराबी के कारण होने वाली घटनाओं तथा ममाज विग्रेधी तत्त्वो व तोड फोड के कार्यों को रोकन के लिए भी सरकार प्रयत्नशील है और आशा की जा सकती है कि आगामी वर्षों में रेल-यात्रा और अधिक सुरक्षित हा जाएगी ।^१

रेलवे की तीसरी महत्त्वपूर्ण समस्या यात्रियों को सुविधा पहुँचान की है । रेलवे प्रशासन के विरुद्ध यह धालोचना प्रस्तुत की जा रही है कि तीसरे दर्जे के यात्री-जिनसे अन्य यात्रियों की अपेक्षा सबसे अधिक आय प्राप्त होती है—सुविधा की दृष्टि से सबसे अधिक उपक्षित है । लडाईं क बाद भारतीय रेलो में यात्री-यातायात बराबर बटता रहा है, उसकी वजह से गाडियो म भीड रहती है । वुंकि रेलवे के उपलब्ध साधनो से भीड में कोई खास कमी नहीं की जा सकती, इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि इन साधनो का उपयोग इस तरह से किया जाए कि भीड कुछ खास क्षेत्रा और गाडियो में अधिक न होकर समान रूप से सब गाडियो और क्षेत्रो में बँट जाए । फिर भी इस बात की कोशिश की जा रही है कि बडी और मीटर दोनो लाइन म सवारो गाडियो की मील-सख्या बडे ।

द्वितीय योजना में रेल-उपभोगकर्ताओं की सुविधा के लिए १५ करोड रु० मजूर किये गए थे । अनुमानित व्यय १५ १५ करोड रु० है । तीसरी योजना के प्रथम वर्ष में ३०२ करोड रु० व्यय करन का विचार है ।^१ उपर्युक्त विवरण स इतना तो स्पष्ट है कि सरकार यात्रियों को अधिक सुविधा प्रदान करने क प्रति जागरूक है । यात्री-सुविधा की दिशा में अभी बहुत-कुछ करना जेप है । रेल क डिब्बो में बँटन की आरामदायक सीट, पखा चौचादि की स्थिति म सुधार आदि । साधारण जनता यात्री-सुविधा से तभी प्रभावित होगी जबकि उपयुक्त सुविधाएँ हर गाडी में प्रस्तुत की जाएँ । १६ रेलवे में प्रगति तथा पंचवर्षीय योजनाएँ— क्योंकि रेलव यातायात की सबसे बडी अभिकरण (Agency) है, इसलिए इसकी प्रगति सारी आर्थिक व्यवस्था पर बहुत प्रभाव डालती है । इसका पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष महत्व है । इसका विवरण निम्नलिखित तालिकाओं से मिलता है—

तालिका—१

व्यय तथा रेलवे का अशदान (करोड रुपयो में)

	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना
१ योजना म रेलव पर व्यय	४२३ २३	१ ०४३ ६६	१,५८१ ००
२ रेलव का अशदान योजना के कार्य	२८० ००	४६५ ००	५३१ ००
३ विदेशी मुद्रा की रेलवे के लिए आवश्यकता	—	३१६ ४५	२८३ ५०

१. देखिए, भारत की सरकारी रेलों में दुर्घटनाओं की समीक्षा (१९५६-६०) रेलवे मन्त्रालय परवरी १९६१ में प्रकाशित ।

२. देखिए, वानी सुविधा के प्रति—रेलवे मन्त्रालय (१९६१-६२) ।

तालिका—२
योजनाओं के अर्न्तगत प्रगति

	पहली योजना (वास्तविक)	द्वितीय योजना (वास्तविक)	तृतीय योजना का लक्ष्य
नई लाइनें खोली गईं (किलोमीटर)	१,०३४	१,३११	२,६४०
दुगुनी लाइनें की गईं (किलोमीटर)	३७०	१,५१२	३,८६४
रेलो में विजली का प्रयोग	—	३६१.५	२,४६८
रेलवे इंजन	१,५८६	२,२१६	२,०७०
रेल के डिब्बे	४,७५८	७,७१८	८,६०१
मालगाडी के डिब्बे	६१,२५४	६७,६५६	१,५७,२२७

पहली पंचवर्षीय योजना में यातायात, जिस पर लडाईं तथा विभाजन का गहरा असर पडा था, को फिर से अर्च्छी दशा में लाने का कार्य था। उसने साथ-साथ यातायात को औद्योगिक उन्नति के लिए भी आवश्यकताओं को पूर्ण करना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसमें भारी उद्योग तथा यातायात संचार पर खूब जोर दिया गया था, में रेलवे प्रगति पर अर्च्छा ध्यान दिया गया। दूसरी योजना में १३४० करोड़ रुपया यातायात पर लगाया गया। तीसरी योजना में इन क्षेत्र में १४८६ करोड़ रुपया रखा गया। इसमें रेलवे पर ८६० करोड़ रुपया था, इसके अतिरिक्त ३५० करोड़ रुपया टूट-फूट के फण्ड (Depreciation) से ३५ करोड़ रुपया स्टोर सस्पेन्स-खाते से (Suspense)।

चौथी पंचवर्षीय योजना में संचार तथा यातायात पर ३,००० करोड़ रुपया सरकारी क्षेत्र में और ६५० करोड़ रुपया निजी क्षेत्र में खर्च होगा, जिसमें से रेलवे पर १,४०० करोड़ रुपया खर्च होगा और ६५० करोड़ रुपया रेलवे टूट-फूट फण्ड में से लगाया जाएगा। इस प्रकार रेलवे में कुल ब्यवसाय २२५ मिलियन टन से (१६६५ ६६) से बढ़कर (१६७० ७१) में ३५५ मिलियन टन हो जाएगा।

सडक परिवहन

२०. हाल का सडक इतिहास—लाई डलहौजी के समय में भारत की सडकों के निर्माण का नया युग प्रारम्भ हुआ। डलहौजी ने रेलों के निर्माण के अतिरिक्त सडकों के निर्माण के लिए भी कुछ शक्तिशाली नीति का अनुसरण किया। इस काम के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक कार्य-विभाग के अतिरिक्त (१८५५ में) प्रत्येक प्रान्त में सैनिक बोर्ड (मिलिटरी बोर्ड) के स्थान पर सार्वजनिक कार्य-विभाग (पी० डब्ल्यू० डी०) की स्थापना की गई (१८५५)। प्राय. ६० वर्षों से रेलों के प्रभाव से भी सडकों के निर्माण में सहायता मिलती आ रही है। ज्यों-ज्यों रेलों का प्रसार होता गया, रेलों की सामग्री, माल और जनता की मांग पूरी करने के लिए एक सहायक क रूप में न कि प्रतिद्वन्दी के रूप में) सडकों का निर्माण आवश्यक हो गया। रेलवम पक्की सडकों की—जो कि रेलवे से समकोण पर देश के आन्तरिक भाग से साल-भर सतारी और माल लाने में सहायता पहुँचाएँ—आवश्यकता की और भी तीव्र कर

दिया और यह माँग आज भी पूरी तरह से सतुष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन रेलों के प्रसार से होने वाले लाभ ने सरकार का ध्यान सड़कों की ओर कम जाने दिया, खासतौर से उन सड़कों की ओर जो रेलवे के समानान्तर चलती हैं।^१

२१ भारतीय सड़कों की विशेषताएँ—इस समय देश के एक छोर से दूसरे छोर तक फैली हुई चार टुक सड़कें हैं। इनके साथ अनेक सहायक सड़कें जुड़ी हुई हैं। सबसे प्रसिद्ध टुक रोड, जो पुराने जमाने में सेनाओं के आवागमन के लिए बनाई गई थी, ब्राड टुक रोड है। यह खँवर से कलकत्ता तक जाती है। अन्य तीन सड़कों में से, एक कलकत्ता और मद्रास को मिलाती है, दूसरी मद्रास को बम्बई से मिलाती है और तीसरी बम्बई को दिल्ली से मिलाती है। इन चारों प्रधान सड़कों की लम्बाई ५,००० मील है जब कि कुल पक्की सड़कें १२१,६१७ मील हैं। दक्षिण भाग में सहायक सड़कें अच्छी दशा में हैं, उनकी सतह भी अधिक है। पक्की सड़कों के अतिरिक्त काफी कच्ची सड़कें भी हैं (१६५०-५१ मील)। ३८,१३६ मील लम्बी कच्ची सड़कों का निर्माण तो प्रथम याज्ञना-काल में १६५६ तक सामुदायिक विकास-योजना तथा राष्ट्रीय प्रसार-सेवा के अन्तर्गत हुआ। इनमें से कुछ तो सूखे मौसम में मोटर इत्यादि के लिए भी काफी अच्छी हैं। मोटरों के आविष्कार और प्रचलन के पहले भी देश की आवश्यकता के लिए भारतीय सड़कें प्रयुक्त थीं।^२

जिस अन्तर्घर्षजनक शीघ्रता से मोटर परिवहन—दस और निजी कारें—का दश में विकास हुआ है उससे सड़कों का निर्माण और सुरक्षा से सम्बन्धित वितनी ही नहीं समस्याएँ उठ खड़ी हुई हैं। यह बात सच है कि मोटर-लारों ने कृषि-उत्पादन और तैयार माल को (ले जाने) ढोने में बँलगाड़ियों के काम को कम ही प्रभावित किया है। सड़कों की यह दुर्दशा बिना पुलवाली नदियों और रेलगाड़ी की प्रतिद्वन्द्विता के कारण है। जब ये सब कठिनाइयाँ दूर हो जाएँगी तो हमें आशा है कि यन्त्र-सज्जित परिवहन (मेकनाइज्ड ट्रांसपोर्ट) यातायात के अधिकांश भाग को अपने अधिकार में कर लेगा। यह विकास खासकर पहाड़ी इलाकों में अधिक प्रभावशाली होगा, क्योंकि वहाँ रेलवे निर्माण की अपेक्षा सड़कें बनाना सस्ता पड़ेगा और सम्भव भी होगा। इसके अतिरिक्त बड़े नगरों के समीप नष्ट होने वाली वस्तुओं के लिए भी

१. देखिए, रोड डिवेलपमेण्ट कमेटी रिपोर्ट, पैरा १७।

२. कृषि-आयोग (१९२८) ने बताया कि जबकि प्रति १०० वर्गमील क्षेत्र में संयुक्तराज्य में ८० मील सड़कें हैं, भारत में केवल २० मील (प्रतिवर्ग वर्गमील) हैं (रिपोर्ट, पैरा १६६)। भारत अब मा केनेथ मिचेल द्वारा रखे गए आदर्श में काफी दूर है। अब मिचेल भारत सरकार के सबक परिवहन के नियन्त्रक थे, उन्होंने कहा था कि १००० जनसंख्या का कोई भी गाँव सड़क से अपने माल से अधिक दूर न जाना चाहिए। भारतीय सड़क और परिवहन-विकास-संस्था (इंस्टीटयन रोड्स एण्ड ट्रांसपोर्ट डिवेलपमेण्ट एनीमिशन) ने सुझाव रखा कि प्रत्येक ३०० निवासियों के गाँवों से अधिक-से-अधिक १ मील की दूरी पर १० फीट चौड़ी सड़क होनी चाहिए। यदि भारत के ७००,००० गाँवों का निर्यात के वाजारों, मालों और रेलवे स्टेशनों से जोड़ने के लिए औसतन १ मील सड़क भी मिलता तो कुल ७००,००० मील सड़क की आवश्यकता होगी, जबकि इन समय केवल ३००,००० मील सड़क हैं।

मोटर परिवहन के लिए पर्याप्त अवसर है ।

२२ अधिक सड़कों की आवश्यकता—जैसा कि कृषि-आयोग न कहा है, 'परिवहन विज्ञय का आवश्यक अंग है । आधुनिक व्यावसायिक विकास ने अच्छी सड़कों के संचार-महत्त्व को बहुत बड़ा दिया है ।' अच्छी परिवहन-व्यवस्था से कृषि-उत्पादन को निश्चय ही प्रेरणा मिलेगी और जीवन-निर्वाह कृषि का स्थान व्यवसायिक कृषि ले लेगी जिसे ग्रामीणों का जीवन स्तर भी ऊँचा उठेगा । इससे खींचने वाले और भारवाही पशुओं की शक्ति और प्राणवत्ता पर भी कम भार पड़ेगा और उनकी कार्य-क्षमता बढ़ेगी । इससे सवारियों का घिसना भी कम हो जाएगा, समय की भी बचत होगी । निर्यात या आन्तरिक उपभोग वाले कृषि-उत्पादन से सम्बन्धित उद्योगों को भी कृषि से पर्याप्त सहायता पहुँचेगी । वे (सड़कों) उद्योगों के विवेन्द्रीकरण में भी सहायक होगी । इस प्रकार अनुचित स्थानीयकरण से उत्पन्न श्रम और मकानों की जटिल समस्याएँ भी कम होंगी, ग्रामीण वातावरण में उद्यान-फँटिद्रियों का स्वप्न सत्य होने लगेगा । अन्त में, उपयुक्त सड़क-परिवहन वी सहायता से भारत की अपार धन-राशि का भी पूरा-पूरा उपयोग किया जा सकेगा ।

२३ सड़क बनाम रेलवे—सड़क-परिवहन रेल-परिवहन में इस अर्थ में अच्छा है कि इसके लिए स्टेशनों, सिगनलों, द्वाड़कों आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती । न तो इसमें समाप्ति (टरमिनी) पर समय का ही नुकसान होता है, न खाली डिब्बे ही ढोने पड़ते हैं और न रोलिंग स्टॉक ही बेकार रहता है । सड़कों का स्पष्ट सस्तापन इसलिए भी है क्योंकि रेलवे को अपनी लाइनें बनाने और उन्हें सुरक्षित रखने का सब खर्च स्वयं बरदास्त करना पड़ता है, इसके विपरीत, सड़कों का निर्माण और सुरक्षा साधारण कर देन वालों के धन से होती है । यदि मोटरों को ही सड़कों की सुरक्षा का खर्च भी बरदास्त करना पड़े तो भी सड़क-परिवहन सस्ता ही पड़ेगा । यह बात थोड़ी दूर की यात्रा और हल्के यातायात के विषय में ही लागू होगी । इसके विपरीत दूर की यात्रा और भारी बोझ ढोने का काम रेलवे द्वारा अधिक सस्ते में होगा, क्योंकि उनके चलाने का खर्च कम पड़ता है । कुछ जगहों पर रेलवे और सड़कों में प्रतिद्वन्द्विता भी रहती है । कुछ स्थानों पर वे एक-दूसरे को सहायता पहुँचाती और पूरक का काम करती हैं । इसे निम्न शब्दों में भली प्रकार प्रकट किया गया है, "सड़कें किसानों की जोतों को बाजारों और पास के स्टेशनों से संयुक्त करती हैं । इसके विपरीत रेलवे उत्पादन-क्षेत्र और दूर के उपभोक्तृओं के बीच सम्बन्ध स्थापित करती हैं तथा नगर के उत्पादकों और हल, कृत्रिम खाद और वपड़ा खरीदने वाले किसानों को मिलाती हैं । अच्छी और पर्याप्त सड़कों के बिना कोई भी रेलवे परिवहन के लिए पर्याप्त सामग्री इकट्ठी नहीं कर सकती । इसके विपरीत सबसे अच्छी सड़कें भी फसल का उत्पादन करने वालों को उपभोक्तृओं के सम्पर्क में नहीं ला सकती ।" इसलिए यह सोचना कि रेलवे में लगी लगभग १२२६ करोड़ रुपये की पूँजी को सड़कों के प्रसार

से हानि पहुँचेगी, विलकुल भ्रामक है। यह ठीक है कि रेलवे और सड़को के बीच थोड़ी-सी प्रतिद्वन्द्विता रहेगी, इसे विलकुल समाप्त नहीं किया जा सकता। यह बात बड़े नगरो के समीप और उपनगरो के लिए भी उतनी ही सच है, जितनी देश के अन्य भागो के लिए जहाँ रेलवे और मोटरो समानान्तर पर चलती हैं, जैसे अहमदनगर और पूना के बीच। रेलवे की सामान्य नीति सड़क-परिवहन से अधिक सुविधा देना तथा मोटरो द्वारा ढोये गए माल और व्यापार का भी पूरा लाभ उठाना है। स्पष्टतः सभी चालू की जाती है जब किसी-न-किसी प्रकार जनता की माँग रेलो द्वारा पूरी नहीं हो पाती। जनता के दृष्टिकोण से यह प्रतिस्पर्धा लाभदायक ही सिद्ध हुई है, क्योंकि इसने रेलवे को जनता की सुविधाओ का अधिक ध्यान रखने के लिए बाध्य किया है।

२४. सड़कों की प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए अपनाये गए उपाय—सड़क की प्रतिस्पर्धा कम करने के लिए रेलवे ने निम्नलिखित तरीके अपनाए हैं—रेलवे आम्नी-बस सेवाएँ, सन्तरी कोचेज, शटल ट्रेनें, टाइम टेबल में परिवर्तन, मस्ते वापसी टिकट, नृतीय श्रेणी के मौसमी और जून टिकट, पारतों के लिए रिमायती दर, कम दर पर स्पेशल ट्रेने, रेलवे की सेवाओ का प्रचार तथा अन्य सुविधाएँ।^१ वेजबुड-समिति ने इस प्रकार के अनेक तरीके बताए जिनसे सड़को की प्रतिद्वन्द्विता को कम किया जा सकता है।^२ जहाँ तक पैसेंजर ट्रेनो का सवाल है, सरकार न तब चलने वाली पैसेंजर ट्रेनें, ट्रेनो वा एक-दूसरे में मेल, अधिक अच्छी सेवाएँ और नीचे दर्जे के यात्रियों को अधिक सुविधाएँ देना पसन्द किया। उन्होंने सड़को की प्रतिस्पर्धा कम करने के लिए किराये को एक साथ कम करने का विरोध किया। किन्तु किसी स्थान-विशेष पर जनता को रेल का प्रति आकर्षित करने के लिए कम किये जा सकते हैं या वहाँ कम किये जा सकते हैं जहाँ यह भय है कि अन्य सवारियाँ रेलो से विमुख होकर किसी अन्य परिवहन की ओर चली जायेंगी। भारतीय रेलो को बुकिंग एजेंसी द्वारा याता-यात के विकास का प्रयास करना चाहिए। यह ध्यान देने की बात है कि इधर वेजबुड-समिति की सिफारिशो के फलस्वरूप रेलवे प्रशासन का व्यावसायिक पक्ष पर्याप्त सुदृढ़ कर दिया गया है। जहाँ तक माल के यातायान का सवाल है, इस समिति ने तेज मालगाडियाँ, माल का जल्दी उतारना-चढाना, लिफ्ट पढी की विधि को सरल बनाना, एकत्र करने और छोड़ने की सेवाओ में विकास, कन्टेनर और रेलवे रेफ्रिजरेटर ट्रको का प्रयोग आदि के सुझाव दिये।

२५. परिवहन सघोजन-नीति—१९३०-३३ में रेलवे और सड़को की प्रतिद्वन्द्विता की जाँच करने के लिए नियुक्त अफसरों की एक छोटी-सी समिति की जाँच का फल था। व दोनों अफसर भारत सरकार के सड़क इंजीनियर सर वे० जी० मिचेल और ए०

१. रिपोर्ट ऑफ दि रेलवे बोर्ड ऑन इन्टिग्रेशन रेलवेन (१९३६-४०), पैरा ६०-४।

२. भारत सरकार द्वारा वेजबुड-रिपोर्ट की सिफारिशों पर किये गए काम के विशेष विवरण के लिए देखिए, रेलवे इज० (१९३८-३९), पैरा ८-१० और (१९३९-४०), पैरा ९-१७।

एच० कर्कनेस रेलवे बोर्ड में विशेष अधिकारी थे। इसमें प्रतिद्वन्द्विता को उचित बनाने के लिए मोटर परिवहन पर और अधिक नियन्त्रण करने का सुभाव दिया गया।^१ १९३३ में हुए रेल-सड़क सम्मेलन में विभिन्न प्रकार के परिवहन के संयोजन से सम्बन्धित कई प्रस्ताव पास किये गए ताकि इनकी प्रतिद्वन्द्विता घट जाए। अन्य तरीकों में सम्मेलन ने रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली बस-सर्विस पर से कानूनी प्रतिबन्ध हटाने का सुभाव दिया। सड़क परिवहन सेवाओं को, ग्रामीण सेवाओं के विकास की दृष्टि में रखकर, एकाधिकार दे दिया जाए तथा केन्द्र और प्रान्तों में संयोजन का काम सरल करने के लिए संस्थाएँ स्थापित की जाएँ। परिवहन-मन्त्री की अध्यक्षता में एक परिवहन परामर्शदात्री समिति की स्थापना हुई (१९३५)। इसका काम रेल, सड़क तथा परिवहन के अन्य माध्यमों को संयोजित कर सड़कों के सम्बन्ध में ऐसी नीति प्रस्तुत करना था जो रेल, सड़क तथा अन्य परिवहन-साधनों के विकास के लिए प्रान्तों द्वारा अपनाई जाए। यह उद्देश्य देश के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था।^२ संयोजन नीति का अनुसरण १९३७ में संचार-विभाग की स्थापना द्वारा सरल हो गया। इस नये विभाग ने १९४७ से रेलवे, पोस्टर, तार, वायुयान, सूचना-प्रसार आदि का काम संभाला।

२६ रेल-सड़क-संयोजन पर वेजवुड-समिति और उसके बाद—वेजवुड-समिति ने बताया कि प्रान्तीय सरकारों का सड़क-परिवहन का नियमन अपर्याप्त और अस्त-व्यस्त था। प्रान्तीय सरकारों द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीति में एक असंगठित और अकुशल सड़क-परिवहन को जन्म दिया, जिसने रेलवे को कमजोर बनाने में सहायता दी पर स्वयं विश्वसनीय सेवाएँ न दे सका। इसके विपरीत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रान्तीय सरकारों को सड़कों के निर्माण के लिए दिए गए धन को देने में देर करके ही केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण को प्रभावशाली बनाया जा सकता था जो (सड़क-निर्माण) स्वयं जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं में से है। अतएव इस नीति से भारत में रेलवे—अवनत रेली—और सड़कें अपर्याप्त रहेंगी।^३ प्रभावपूर्ण संयोजन तो रेलवे और सड़क दोनों को जन-सेवाओं के रूप में चलाने पर ही हो सकता है। समिति इससे सहमत नहीं थी कि सड़कों का नियमन केवल रेलवे की सुरक्षा की दृष्टि से ही किया जा रहा था। सड़कों का उचित नियमन केवल सुरक्षा की दृष्टि से ही आवश्यक नहीं था, अपितु वह उन (सड़कों) के विकास को पुष्ट आर्थिक आधारा पर लाने के लिए भी आवश्यक था। रेलवे को एक नये प्रतिद्वन्द्वी की अनुचित और अनाधिक प्रतिद्वन्द्विता से बचना भी वाञ्छनीय है। केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित सिद्धान्तों के अनुसार प्रान्तीय सरकारों को सड़कों का नियमन करना चाहिए, किन्तु सड़कों के परिवहन पर इस प्रकार के कोई प्रतिबन्ध न लगाने चाहिए जिनसे उनके

१. देखिए, मिचेल कर्कनेस रिपोर्ट, पृ० २४।

२. संयोजन के विषय पर शिक्षाप्रद विकास के लिए देखिए, एम० के० रुक्षा, 'प्रोब्लम्स आफ़ ट्रांसपोर्ट को-ऑर्डिनेशन इन इण्डिया'।

३. रिपोर्ट, पैरा १३८।

विकास में बाधा पड़े। जन-सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक ही प्रकार के नियम बसो-लारियों दोनों के लिए लागू किये जाने चाहिए। परिवहन की अनावश्यक (अधिक) व्यवस्था और दुर्घटनाएँ से बचने के लिए जनता की आवश्यकताओं के अनुसार लाइसेंस दिए जाने चाहिए। टाइम-टेबल और किराया निश्चित होना चाहिए तथा यात्रियों को ले जाने वाली मेवाओं का मार्ग अनुज्ञा (लाइसेंस) द्वारा नियमित होना चाहिए। समिति ने माल टोने वाली गाड़ियों की प्रादेशिक अनुज्ञा-प्रणाली (रीजनल लाइसेंसिंग) की सिफारिश की और भविष्य में बस्तुओं के भाड़े को नियंत्रित करने के लिए वैधानिक व्यवस्था का सुझाव रखा। व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों ही लारियों के लिए एक-से ही नियम लागू किये जाने चाहिए। प्रान्तीय नियन्त्रण को कार्यान्वित करने के लिए पुलिस की शक्ति और नियन्त्रण को सुदृढ़ बनाना होगा। प्रान्तों की मोटरगाड़ियों की कर-सम्बन्धी नीति में एकता लानी चाहिए।

अप्रैल, १९४५ में भारत सरकार ने एक पूरक माँग पेश की ताकि रेलवे समानान्तर सड़कों पर बस कम्पनियों में पूंजी लगा सके, लेकिन यह माँग स्वीकार करने के पहले धारासभा ने सरकार से सड़क और रेलवे के संयोजन के सम्बन्ध में एक स्पष्ट नीति के कथन की माँग की। अतएव सरकार ने जनवरी, १९४६ में एक ब्रूइड पेंपर प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया कि सरकार का उद्देश्य दोनों प्रकार के परिवहनों का विकास इस प्रकार करना है कि ये प्रतिद्वन्द्वी न होकर पूरक रहे। जहाँ रेलवे और सड़कें सामानान्तर थी और भीषण होड़ की सम्भावना थी, वहाँ सबसे सन्तोषजनक समाधान दोनों पक्षों के आर्थिक हितों का एकीकरण था। इसलिए एक मधुक्त मोटर बस सेवा प्रारम्भ करने का विचार किया गया जिसमें बसों के वर्तमान मालिक, रेलवे और प्रान्तीय सरकार तीनों का हिस्सा रहे। ये सधुक्त कम्पनियाँ एक मंचालक-मण्डल द्वारा प्रशासित होने की थी। इसके लिए प्रबन्धकारक एजेण्ट (मेनेजिंग एजेण्ट) रखने की आवश्यकता नहीं थी। अनेक प्रान्तीय सरकारों ने योजना को कार्यान्वित करने का प्रयास किया, किन्तु ऐसा करने में बहुतांश ने निर्दिष्ट साधारण नीति का उल्लंघन किया। केन्द्रीय धारासभा द्वारा सड़क रेल-संयोजन की जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने योजना कार्यान्वित करने में अनेक गलतियाँ देखीं और इस निष्कर्ष पर पहुँची कि जब तक प्रान्तों में लोकप्रिय सरकार न बन जाए तब तक इस प्रकार की कम्पनियाँ बनाने का काम स्थगित कर देना चाहिए।

भारत-सरकार ट्थर कुछ दिनों से पुनः परिवहन के सभी साधनों बल्कि मुख्यतः रेल और सड़क के संयोजन तथा भावी विकास पर विचार कर रही है। परिवहन के क्षेत्र में नियोजित विकास की दृष्टि से इन समस्याओं का विस्तृत परीक्षण सहायक सिद्ध होगा। इस दृष्टि से भारत सरकार ने श्री वे० भी० नियोगी की अध्यक्षता में मई, १९५६ में एक उच्च-स्तरीय समिति की स्थापना की जो निहित समस्याओं का अध्ययन करके राष्ट्रीय परिवहन-नीति निश्चित करने के लिए सुझाव प्रस्तुत करेगी।

२७. सड़क के मोटर यातायात (ट्रेफिक) का नियमन—१९१४ के अधिनियम के

याद १९३६ का मोटर विहिकल्स अधिनियम पास हुआ, जिसमें पुराने अधिनियम की त्रुटियों को दूर करने और मोटर-प्रयोग के प्रसार के कारण उत्पन्न नई परिस्थितियों को पूर्ति करने का प्रयास किया गया था।

अधिनियम के दो खास पहलू हैं—(१) नियमन करने वाला, (२) संयोजन करने वाला। इसकी साधारण योजना थी कि किराये पर या किसी भी प्रकार माल और यात्रियों को ढोने वाली सभी सवारियों का नियन्त्रण रोजनल ट्रांसपोर्ट प्राधिकारियों के हाथ में रहेगा, जोकि प्रान्त के निश्चित भागों के लिए नियुक्त किये जाएंगे तथा अपील सुनने और संयोजन के काम के लिए सारे प्रान्त के लिए एक प्रान्तीय परिवहन-प्राधिकारी होगा। कोई भी व्यक्ति जिसका किसी भी परिवहन कम्पनी से ज़रा सा भी आर्थिक सम्बन्ध होगा प्राधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा और सदस्य की तरह ही रह सकेगा। प्रत्येक गाड़ी के पास परमिट का होना अनिवार्य है जो कि उस क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा दिया जाएगा। परमिट पाने वाले को कुछ शर्तें स्वीकार करनी होंगी, जैसे गाड़ी को अच्छी दशा में रखना, गति की सीमा को पार न करना, अधिक भीड़ न करना और ड्राइवरी से बहुत अधिक काम न लेना।

मोटर बसों और टैक्सियों को अनुज्ञा (परमिट) देते समय परिवहन अधिकारी निम्न बातों का ध्यान रखते हैं—जनता की आवश्यकता और सुविधा, आर्थिक दृष्टि से हानिकारक प्रतिद्वन्द्विता को रोकना तथा उन परिवहनियों को बरदाश्त करने के लिए सड़कों की उपयुक्तता। जनता के माल के यातायात के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त है कि शीघ्रता से नष्ट होने वाले पदार्थों का थोड़ी दूर तक का यातायात सड़क से बहन के लिए छोड़ दिया जाता है, किन्तु लम्बी दूरी का यातायात प्रधानतया रेलवे के लिए रखा जाता है। सड़क के परिवहन का आवश्यक नियन्त्रण प्रान्तीय सरकारों के हाथ में रहता है। यह व्यवस्था की गई है कि मार्ग-सम्बन्धी अनुज्ञा (रूट परमिट) प्राप्त व्यक्ति अनावश्यक होड़ से सुरक्षा करने के बदले में नियमित सेवाएँ दें अर्थात् अपना उत्तरदायित्व एक अन सेवा कम्पनी के समान समझे। नियमन प्राधिकारी को सड़क यातायात के सम्बन्ध में उच्चतम और निम्नतम दरें निश्चित करने का अधिकार है।

यह भी व्यवस्था की गई है कि मोटर लाइसेंस समस्त भारत में वैध होगा। प्रत्येक राज्य अपना कर निश्चित करने के लिए स्वतन्त्र है। नये प्राधिकारों को लाइसेंस लेते समय कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं।

यद्यपि नवीन अधिनियम की कुछ धाराओं में विवाद को जन्म दिया है, परन्तु सिद्धान्ततः यह विवादहीन है और इसे 'सड़क संहिता' (हाईवेज कोड) का नाम ठीक ही दिया गया है। अराजकता से व्यवस्था की ओर बढ़ने, सुरक्षा की विधियों को अपनाने, जनता की सुविधाओं का ध्यान रखने तथा परिवहन की संयोजित पद्धति को अपनाने की आवश्यकता सबको प्रतीत हो रही है।

मद्रास और केरल राज्य में तीसरे पक्ष के जोखिम की बीमा के सम्बन्ध में

१. ड्राइवरों के काम के ६ घण्टे प्रतिदिन और ५४ घण्टे प्रति सप्ताह ई तथा ५ घण्टे के काम के बाद आधा घण्टा विश्राम मिलना चाहिए।

एकरूपता लान के लिए १९३६ के मोटर वहीकिलत अधिनियम मे अपेक्षित सशोधन कर्न के लिए २ मार्च, १९६० मे ससद ने एक बिल पान किया ।

२८ भारतीय सडक-विकास-समिति और सडक वित्त—जैसा कि भारतीय सडक-विकास (जपकर) समिति ने कहा—“भारत का सडक-निर्माण और विकास स्थानीय बोर्डों और स्थानीय सरकारो की आर्थिक क्षमता के बाहर होता जा रहा है और एक ऐसा काम होना जा रहा है जिसमे राष्ट्र को दिलचस्पी लेनी चाहिए । अन्त वेन्द्रीय वित्त से उसका काम करना उचिन होगा । केन्द्रीय वित्त को सडको के विकास से केवल रेलवे की प्राप्ति म वृद्धि द्वारा ही लाभ नही होता, बल्कि सडको पर चलने वाली मोटरो, मोटर स्परिट स प्राप्त चुगी इत्यादि स भी लाभ होता है, जो (मोटर-यातायात) इस समय शीघ्रता स बड रहा है । एवं सुसंयुक्त मोटर-कर योजना मे, पट्रोल कर, गाडियो का कर, किराये पर चलन वाली गाडियो की लाइसेंस-फीस इत्यादि शामिल होन चाहिए । इन सबम होन वाली आमदनी को सडको के विकास पर खर्च करना चाहिए । सडको का पुनर्विभाजन इस प्रकार होना चाहिए कि कुछ स्थानीय सडको को प्रधान (आरटीयल) सडको के बगं मे कर दिया जाए ताकि स्थानीय सस्थाएँ उनक भार स मुक्त हो जाएँ और अपना ध्यान नहायक और स्थानीय महत्त्व की सडको के निर्माण और सुरक्षा की ओर लगा सके । सडक-समिति ने बताया कि तमाम दुनिया म यह बात स्पष्ट रूप मे स्वीकार की गई है कि स्थानीय छोटी-छोटी सस्थाओ पर प्रधान सडको के निर्माण और सुरक्षा का भार छोडना न्यायसगत नही है । स्थानीय सस्थाओ का प्रान्तो स और अधिक आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए । यदि सडक-समिति की सिफारिसो अपनाई जाती है तो उससे गांवो म सडके बनाने के काम मे परोक्ष रूप से सहायता मिलेगी, क्योंकि इस प्रकार स्थानीय और प्रान्तीय धन जो बडी-बडी सडको की देखरेख और निर्माण म प्रयुक्त होना है, इस काम से बच जाएगा । सडक-समिति न यह भी सुभाव रखा कि रेलवे को भी अपनी सहायक सडको के निर्माण और देखरेख की जिम्मेदारी ग्रहण करनी चाहिए । समिति न सडको पर किसी प्रकार की चुगी (सिवाय पुलो व जहाँ नदियो को पार करन के लिए नावो के स्थान पर विशेष सेवा की जाती है) का सडको के निर्माण की प्रगति म बाधक और तेज परिवहन व विकास म अनुचित र्कावट माना ।

कृषि-प्रायाग व मन मे प्रचलित वित्त पर निर्भर न रहकर यदि सडको के विकास के लिए ऋण लिया जाए तो उनक विकाम म सरलता और शीघ्रता होगी । सडको और उनसे सम्बन्धित काम व अर्ध-स्थायी स्वभाव को देखत हुए उनका विचार था कि ऋण को चुकाना करन के लिए वार्षिक धन प्रान्त के साधनो की सीमा व बाहर न होगा ।^१ सडक समिति का यह मत था कि ऋण किसी योजना के स्थायी भागो, जैसे पुलो व निर्माण, के लिए खर्च करना चाहिए, क्योंकि पुल का जीवन निश्चित रूप से मासूम किया जा सकता है तथा ऋण चुकाने के लिए आवश्यक कोष की

^१ इति-प्रायाग-रिपोर्ट, पैरा २०६ ।

गणना सरलता से की जा सकती है तथा पुल की सुरक्षा का व्यय भी अधिक नहीं होता। १९३३ के रेल-सड़क-सम्मेलन में सुरक्षा के सधनो के अन्दर ऋण लिये धन से प्रधान और सहायक सड़कों के विकास की सम्भावनाओं की परीक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाने की सिफारिश की। भारतीय सड़क और परिवहन-विकास-संस्था लि० की बारहवीं बैठक (१९४०) में सड़कों के निर्माण और रक्षा के लिए उर्वर आर्थिक व्यवस्था से युक्त एक नयी सड़क नीति का समर्थन किया, जबकि रेलें ऋण लिये गए धन से बनायी गई थीं और सड़कों का निर्माण आगम (रेवेन्यू) से हुआ था, अतएव ऋण लिये हुए धन का प्रयोग किये बिना सड़कों के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था अव्यवहार्य है।

२६ नवीन सड़क-नीति—सड़क समिति की खास सिफारिशों के आधार पर मार्च, १९२६ में भारतीय वित्त अधिनियम में मोटर स्पिरिट पर ४ आने के स्थान पर ६ आने प्रति गेलन उत्पादन-कर लगा दिया (इससे १९२६-३० में ६४ लाख रुपये मिले)। सर बी० एन० मिश्रा ने धारासभा में एक प्रस्ताव रखा (११ सितम्बर, १९२६), जिसका आधार सड़क समिति के पैरा ७०-७६ में की गई सिफारिशों के विवाद थे। इसकी प्रधान बातें ये थीं—(१) सड़क के कार्यक्रम को जारी रखने का प्रयत्न किया जाए। मोटर स्पिरिट पर कम-से-कम पाँच वर्ष तक कर होना चाहिए, (२) पाँच वर्ष तक इस अधिक कर की आय को सड़कों के विकास पर खर्च किया जाए। एक अलग रोड-विकास-खाता खोल दिया जाए और उसका बाकी रुपया वित्तीय वर्ष के अन्त में बालातीत न माना जाए, (३) वार्षिक अनुदान को इस प्रकार विभाजित किया जाए—(क) भारत सरकार दो वर्ष तक १० प्रतिशत अपने पास सुरक्षित रखती, उसके बाद फिर विचार किया जाता। इस सुरक्षित धन में से आवश्यकता पड़ने पर विशेष अनुदान दिये जाते। ये विशेष अनुदान उन परिस्थितियों में दिये जाते जबकि कोई योजना स्थानीय संस्थाओं की आर्थिक शक्ति के बाहर होती या दो प्रान्तों की सीमाओं पर पड़ने के कारण किसी विशेष प्रान्त का काम न होती या प्रान्तीय या केन्द्रीय सीमाओं पर पुलों के निर्माण से सम्बन्धित होती। (ख) शेष में से (१) विद्यमान वर्ष में भारत में उपभोग किये गए कुल पेट्रोल का जितना हिस्सा प्रान्तों में उपयुक्त होता उसी हिस्सा से उसे धन दिया जाता, (२) बाकी जो छोटे प्रान्तों, रियासतों या प्रशासनों के उपभोग का प्रतिनिधित्व करता, वह भारत सरकार को दे दिया जाता। (३) सड़कों की स्थायी समिति की सलाह पर गवर्नर जनरल कौंसिल द्वारा स्वीकृत इन योजनाओं पर खर्च करने के लिए प्रान्तों को अनुदान दिया जाता। (४) प्रतिवर्ष सड़कों के लिए एक स्थायी समिति (स्टैंडिंग कमेटी) का निर्माण किया जाए, जिसमें भारतीय विधान-मण्डल के दोनों सदनो के कुछ निर्वाचित और कुछ मनोनीत सदस्य होते। इसका सभापति गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति का सड़कों से सम्बन्ध रखने वाला सदस्य होता। इसका काम गवर्नर जनरल को सड़कों से सम्बन्धित हर एक मामले पर परामर्श देना था, जिसमें केन्द्रीय सड़क अनुसंधान और सामयिक सड़क सम्मेलनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही भी

शामिल है। (५) वार्षिक अनुदान में किये जाने वाले सब न्यय या एकत्रित धन घन स्वीकृति के लिए वित्त-उप-मिति के नमश रखना होता था, जिनमें (वित्त-उप-मिति) स्थायी समिति का सभापति और वे सदस्य होते थे जो पारामभा के भी सदस्य थे।

१९२० के दिल्ली के अधिवेशन में ५ वर्षों के लिए इसे स्वीकार कर लिया गया।

३०. सड़क-खाते की आर्थिक दशा—पेट्रोल पर लगाये गए अधिभार के साथ ही सड़क के लिए प्राप्य पेट्रोल-कर का भाग १ अक्टूबर, १९३१ में ७ आना प्रति गेलन से २½ आना प्रति गेलन हो गया।

३१ सड़क-सम्बन्धी नवीन प्रस्ताव—(१) सड़क-खाने का ५ वर्ष का परीक्षण-काल १९३३-३४ में बीत गया। १९३४ में केन्द्रीय विधानमण्डल ने एक नया प्रस्ताव अपनाया जिससे सड़क-खाता स्थायी हो गया। इससे भारत सरकार का मुश्किल धनकोष १०% से १५% हो गया ताकि वह अपेक्षाकृत अधिकमिन् प्रान्तों को उदारता से धन दे सके। इससे न सड़को का विकास, निर्माण एवं मरुक्षित रखने के लिए धरण भी दिया जा सकता था।

(२) परिवहन परामर्शदात्री समिति के मुभाव पर सड़क कोष से अनुदान के वितरण पर केन्द्रीय सभा द्वारा एक नया प्रस्ताव पास किया गया (फरवरी, १९३७)। इसके द्वारा निम्न परिवर्तन किये गए—(क) गवर्नरों के प्रान्तों को दिये जाने वाले धन को गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल तब तक अपने पाम रख सकता था जब तक कि प्रान्तों द्वारा उम धन का सुरक्षित उपयोग करने के लिए उसकी मांग न की जाती। (ख) यदि कोई प्रान्त बिना समुचित कारण के अपने धन का उपयोग सड़क-विकास के लिए समय से न कर पाता तो केन्द्र को अधिकार होना कि वह सम्पूर्ण धनराशि या उनका एक अग्न देने से इन्कार कर दे। (ग) लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह था कि गवर्नर जनरल-इन-कौंसिल को यह अधिकार था कि यदि कोई प्रान्त उसके द्वारा बनाया गए मोटरों के नियमन और नियन्त्रण से सम्बन्धित नियमों को कार्यान्वित करने में चूकता तो वह उनका भाग न दे। प्रान्तों ने इसे अनुचित हस्तक्षेप माना और कहा कि यह रेलवे की आय-व्ययक स्थिति को दृढ़ रखने का एक तरीका था। केन्द्रीय सरकार ने कहा कि इसका उद्देश्य एक मनुलित मचार व्यवस्था स्थापित करना था। (घ) गौघ्र ही मिलने वाली प्रान्तीय म्बन्धना को हटि म रक्क सड़क-कोष में सड़को का कर्ज चुकाए जान की नीति बन्द कर दी गई।

मार्च, १९५६ के अन्त तक केन्द्रीय सड़क कोष की कुल प्राप्ति ५७ ४३ कराड ६० तथा मरुक्षित कोष की कुल प्राप्ति ११ करोड २० थी। १९५६ के प्रारम्भ में कोष में प्राप्त होनेवाला वार्षिक आगम ५½ करोड ६० था। इसमें एक करोड ६० का वार्षिक विशेष मरुक्षित कोष भी सम्मिलित था। केन्द्रीय सड़क-कोष स्थापना के १५ वर्ष बाद तक यही कोष नयी सड़को के निर्माण तथा विद्यमान सड़कों के सुधार और नवीकरण के लिए पर्याप्त था, किन्तु अब स्थिति में बहुत परिवर्तन हा गया है। १९५६ में यह कोष मोटर-परिवहन पर लगे कर में प्राप्त कुल आय का केवल ६ प्रतिशत तथा द्वितीय

योजना में नयी सड़कों के कुल व्यय का १० प्रतिशत था ।

नागपुर योजना—दिसम्बर, १९४३ में विभिन्न राज्यों के मुख्य अभियन्ताओं (चीफ इंजीनियर) का सम्मेलन नागपुर में हुआ । इस सम्मेलन ने देश की न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर एक सड़क-योजना बनाई । इस योजना का लक्ष्य यह था कि सुविकसित कृषि क्षेत्रों का कोई गाँव पक्की सड़क से पाँच मील से अधिक दूर न हो । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सड़कों की मील दूरी में ५० प्रतिशत वृद्धि अपेक्षित थी ।

नयी सड़क योजना—१९४७ में विभाजन के पश्चात् नागपुर-योजना के लक्ष्यों में कुछ परिवर्तन करना पड़ा । अब नागपुर योजना लगभग पूरी हो चुकी है । भारत सरकार के कहने से मुख्य अभियन्ताओं ने २० वर्षीय नयी योजना बनाई । मोटे तौर पर योजना की रूपरेखा के अनुसार सड़कों की लम्बाई (१९६१ की) ३७९ लाख मील से बढ़कर १९८१ में ६५७ लाख मील हो जाएगी । योजना के अनुसार प्रति वर्गमील में ०.५२ मील सड़क हो जाएगी जबकि इस समय प्रति वर्ग मील में ०.२६ मील सड़क है । योजना के पूरे होने पर कृषि क्षेत्र के किसी गाँव की पक्की सड़क से दूरी ५ मील से घटकर ३ मील और कच्ची सड़क से दूरी ११ मील हो जाएगी । अर्ध विकसित क्षेत्र में यह दूरी पक्की सड़क से ८ मील तथा किसी भी सड़क से ३ मील हो जाएगी । अर्धविकसित और कृषि के अयोग्य क्षेत्र में स्थित किसी भी गाँव की दूरी पक्की सड़क से १२ मील तथा किसी भी सड़क से ५ मील होगी । इस योजना की अनुमानित लागत ४७०० करोड़ रु० है तथा इसे चार पंचवर्षीय योजनाओं में बाँटा गया है । इन चार योजनाओं के बीच लागत का विवरण इस प्रकार है

१९६१-६२ से १९६५-६६	४७० करोड़ रु०
१९६६-६७ से १९७०-७१	६४० , ,
१९७१-७२ से १९७५-७६	१,४१० ,, ,,
१९७६-७७ से १९८०-८१	१,८८० ,, ,,

पंचवर्षीय योजनाएँ और सड़क परिचालन—प्रथम पंचवर्षीय योजना में १५६ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई थी । पाँच वर्ष की अवधि में कुल ६८,१५९ मील की नयी सड़कें बनाई गईं, जिनमें २४,०७१ मील की पक्की (मेटल) तथा ४४,०८८ मील की कच्ची सड़कें थी । इसके अतिरिक्त १७,३११ मील की वर्तमान सड़कों में सुधार करके उन्हें अच्छे स्तर की सड़कें बनाया गया ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सड़क विकास के लिए २६९ करोड़ रुपये निर्धारित किये गए । मार्च, १९५९ तक सड़क विकास की प्रगति आसाम, बम्बई, केरल, उ० प्र० और बंगाल को छोड़कर अन्य स्थानों में धीमी रही है । १९५६-५९ की अवधि में कुल १४० करोड़ रु० व्यय हुआ है । मार्च, १९६१ तक लगभग २५० करोड़ रु० व्यय होने का अनुमान है । तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित व्यय भी २५० करोड़ रु० है ।^१

^१ विविध, धर्म पाठ्य दफ्तर प्लान, इन्फ्रस्ट्रक्चर डिवीजन, १० १४८ ।

परिवहन के सुनियोजित विकास तथा विभिन्न प्रकार के परिवहन-साधनों तथा केन्द्र और राज्य की परिवहन-नीतियों में समन्वय स्थापित करने के लिए तीन परिवहन निकायों की स्थापना का निर्णय किया है। परिवहन-विकास-परिषद (ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट काउन्सिल) व सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन परामर्श समिति (द रोड एण्ड इनलैंड ट्रान्सपोर्ट एडवाइजरी कमेटी) तथा केन्द्रीय परिवहन सयोजन समिति (सेन्ट्रल ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी) प्रथम एक उच्च स्तरीय निकाय होगा, जिसके सदस्य राज्य के परिवहन मन्त्री, संघीय क्षेत्र (यूनियन टेरिटरी) के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर और मुख्य आयुक्त (चीफ कमिश्नर) तथा सम्बन्धित मन्त्रालयों के केन्द्रीय मन्त्री आदि होंगे। इसका कार्य सरकार को सड़क, सड़क-परिवहन तथा अन्तर्देशीय जिला परिवहन के समन्वय में परामर्श देना होगा।

राष्ट्र की उन्नति के लिए सड़क बनाने का कार्य एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। १९५०-५१ में देश में १,५६,००० किलोमीटर पक्की सड़कें तथा २,४२,००० किलोमीटर सड़कें थीं। पहली पंचवर्षीय योजना में सड़कों के बनाने में १३५ करोड़ रुपया व्यय हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना में देश की प्रगति तथा रेल के यातायात के बोझ को कम करने के लिए २४५ करोड़ रुपया सड़कों इत्यादि बनाने के लिए खर्चा गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस कार्य पर और भी जोर दिया गया और यह आशा की गई कि १९६५-६६ में पक्की सड़कें २,७०,००० किलोमीटर तक पहुँच जाएँगी। इसी प्रकार बसें तथा ट्रकों की संख्या को भी बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। १९५०-५१ में व्यापार के उपयोग में आने वाली गाड़ियों की संख्या १,१५,००० (बसें तथा ट्रक) थी (१९६५-६६) में २,५५,००० तथा (१९६०-७१) में ४,७०,००० हो जाएगी तथा बसों की संख्या १९६५-६६ में ८०,००० से बढ़कर १,२६,००० हो जाएगी। तीसरी योजना में यातायात के राष्ट्रीयकरण करने के लिए २६ करोड़ रुपया रखा गया है, तथा इसके अतिरिक्त १० करोड़ रुपया रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन (Road Transport Corporation), बनाने के लिए रेलवे भी लगायेगी। इस प्रकार चौथी पंचवर्षीय योजना में यात्रियों की सेवाओं का ५० प्रतिशत भाग राष्ट्रीयकरण किये हुए परिवहन के हिस्से में आयेगा जबकि तीसरी योजना में ३३ प्रतिशत है।

जल-परिवहन

२२. (१) अन्तर्देशीय जल-पथ—जल परिवहन का विकरण स्वभावतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—(१) अन्तर्देशीय परिवहन, (२) सामुद्रिक परिवहन।

भारत में इंग्लैण्ड-जैसी नदियाँ, जो स्वाभाविक जल-पथ का काम देती हैं, नहीं हैं। उत्तर भारतीय और प्रायद्वीप की नदियों का जिन बरसे समय हम इस विषयता की ओर सन्तक कर चुके हैं।

प्रायद्वीप की नदियाँ इस प्रकार नौगम्य नहीं हैं। मौसम के अनुसार कभी तो वे

तूफानी हो जाती हैं और कभी केवल जल की पतली रेखा मात्र रह जाती है और इस प्रकार इनमें नावे चलाना प्रायः असम्भव-सा हो जाता है। नर्मदा और ताप्ती-जैती कुछ नदियों की पथरीली सतह और तेज धार नौगम्यता के लिए जटिल समस्या बन जाती है। महानदी, गोदावरी और कृष्णा अथर्व ऊपर तक नौगम्य हैं, किन्तु उनसे यातायात कम ही है।

जल-पथ की इन सकुचित सुविधाओं के अतिरिक्त किनारे-किनारे कुछ छोटी-छोटी नदियाँ और खाडियाँ हैं, जिनका छोटी-मोटी नावों द्वारा उपयोग किया जाता है। लेकिन इस प्रकार के क्षेत्र के बाहर नौका-गमन प्रायः डेल्टा और घाटियों तक ही सीमित है।

एक समय नौगम्य नहरों के पक्ष में बड़ा आन्दोलन चला था। अन्ध कावेरी और गोदावरी नहरों के निर्माता सर आर्थर कॉटन ने नौगम्य नहरों की एक महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की, जो १८७२ में संसदीय समिति के समक्ष रखी गई। उनके मतानुसार रेलवे की अपेक्षा जल-परिवहन की सुविधाएँ भारत के लिए अधिक उपयुक्त तथा कम खर्चीली हैं। इसके अतिरिक्त उनसे यह भी लाभ होगा कि इनको सिंचाई के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। खर्च की अधिकता (३०० लाख पौण्ड, के कारण योजना को त्याग देना पड़ा। इसका एक कारण यह भी था कि अंग्रेज अपने देश के अनुभव के आधार पर भारत में नहरों की उपयोगिता भली भाँति नहीं समझ सके, क्योंकि उनके यहाँ रेलवे ही अधिक लाभप्रद सिद्ध हुई थी। रेलवे द्वारा किया गया विरोध भी एक और कारण था।

जब रेलवे से घाटा हो रहा था तो नहरों का निर्माण चाहे सिंचाई के काम के लिए या केवल नौगम्य के लिए ही आकर्षक प्रतीत होता था। औद्योगिक आयोग ने सिफारिश की थी कि भारत सरकार को इस प्रश्न पर ध्यान देना चाहिए और जो भाग रेल और जल-पथ दोनों ही द्वारा सेवित हो वहाँ इनके प्रशासन समन्वय से काम करें तथा जल-पथ ट्रस्ट के निर्माण के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाए। समुचित रीति से विकसित जल-पथों से रेलों की भीड़ कम हो जाएगी और छोटे पैमाने के परिवहन का कार्य भी इनके द्वारा पूरा हो सकेगा। कुछ सिंचाई की नहरों को परिवहन की नहरों में भी परिवर्तित किया जा सकेगा। लेकिन जब हवा का रख बदला और रेलवे में लाभ होने लगा तो उत्साह कुछ ठंडा पड़न लगा। इस समय नौगम्य नहरें केवल थोड़ी सी हैं—उदाहरण के लिए पूर्वी तट के समानान्तर मद्रास की धर्किषम नहर। अनेक सिंचाई की नहरें नौगम्य जल-पथ का काम नहीं दे सकती। दोनों प्रकार की नहरें सरलता से एक में संयुक्त भी नहीं की जा सकती।

अन्तर्राज्यीय तथा राष्ट्रीय जल-पथों के गमन पर केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण है तथा केन्द्रीय जल और शक्ति-आयोग जल साधनों के बहु-उद्देश्यीय विकास में सहायता करता है। श्री बी० के० गोखले की अध्यक्षता में नियुक्त अन्तर्देशीय जल परिवहन-समिति ने अन्ध बाताँ के अतिरिक्त ये सिफारिशें की हैं कि केन्द्रीय प्राविधिक संगठन तथा एक प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की जाए तथा देशी नाव चाली की सहकारी

समितियों को बढावा व नदी-घाटी-योजनाओं में नौवागमन की सुविधाओं का विकास किया जाए। इस समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए तृतीय पंचवर्षीय योजना में अन्तर्देशीय जल-मयों के विकास के लिए ७६० करोड़ रु० का व्यय प्रस्तावित है जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अनुमानित व्यय ७५ लाख रु० है। तृतीय योजना में अन्तर्देशीय जल-मयों के सम्बन्ध में कुछ मुख्य बातें अधिक महत्त्वपूर्ण नदियों के सम्बन्ध में जलवर्षानात्मक सर्वेक्षण (हाइड्रोग्राफिक सर्वे) तथा ब्रह्मपुत्र नदी और सुन्दरदल क्षेत्र के लिए निकपंको (ड्रेजर) की खरीद आदि है। गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों पर जल-परिवहन के विकास को सञ्चालित करने व लिए गंगा ब्रह्मपुत्र जल-परिवहन परिषद (गंगा ब्रह्मपुत्र वाटर ट्रांसपोर्ट बोर्ड) की स्थापना राज्तीय और केन्द्रीय सरकारों व ऐच्छिक सहयोग से १९५० में हुई। गंगा-ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में प्रमुख जल-मयों का निकपंको (ड्रेजिंग) तथा चुने हुए स्थानों में अन्तर्देशीय बन्दरगाहों का विकास आदि गाने नियोजित कार्यक्रम में सम्मिलित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रादेशिक सरकारों ने भी जल परिवहन परिषद पर १४८ करोड़ रुपया खर्चना निश्चित किया। उस समय देश में ८ हजार किलोमीटर दरियाई जहाज या किश्तियाँ चलाई जा सकती हैं। इनमें से ३ हजार मशीनों से चलनेवाले हैं और ५ हजार किश्तियाँ हैं।

३३ (२) सामुद्रिक परिवहन—जहाँ तक बाह्य जल परिवहन का प्रश्न है यद्यपि भारत की इंग्लैण्ड से तुलना न हो सकेगी क्योंकि यहाँ पर न तो इंग्लैण्ड जैसा कटाफटा समुद्र-तट है और न प्राकृतिक बन्दरगाह ही हैं, फिर भी उसकी सामुद्रिक स्थिति काफी महत्त्वपूर्ण है। जैसा एम० एन० टाजी ने कहा है कि “एक दल, जो कि प्राचीन विश्व व महाद्वीपों में भूमिकों की भाँति जडा है, जिसका समुद्र-तट ४००० मील लम्बा है और जो अनेक प्रकार की वस्तुओं के निर्माण की खान है जिन्हे अन्यत्र नहीं पंदा किया जा सकता, प्रकृति द्वारा एक नाविक देश होने के लिए ही बना है। इसके बन्दरगाह सख्या और आकार में इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं।”

शायद यहाँ अनिरजित चित्र खींचा गया है। यह चित्र भारत में प्राकृतिक बन्दरगाहों की कमी को उचित रूप से हमारे सामने नहीं रखता, फिर भी अपनी भौगोलिक स्थिति और विस्तृत समुद्र व कारण वह दुनिया का एक मुख्य जल-परिवाहक देश हो सकता है। १९वीं सताब्दी के प्रारम्भ तक भारत को एक नवीन देश कहा जा सकता था। “जलयानों का निर्माण ऐसी अच्छी दना में था कि भारत के बन्दरगाहों में जहाजों के सरक्षण में और उनके साथ टेम्स तक जाने थे।” १८०० में गवर्नर जनरल ने लीडेनहाल स्ट्रीट में अपने स्वामियों का सूचना देते हुए कहा कि ‘कलकत्ता के बन्दरगाह में भारत-निर्मित १०,००० टन के जहाज हैं जो इंग्लैण्ड तक माल ले जान योग्य हैं। सागवान की लकड़ी के बने बम्बई के जहाज इंग्लैण्ड के

१. देविंग, घट फाइव इन्टर प्लान—ए शान्ट आउट लाइन, १० २५१।

२. देखिए, इकनॉमिक्स ऑफ़ इण्डिया, १० ३६५-६।

चीशम की लकड़ी के जहाज से कहीं अच्छे थे।”

अप्रैल की मृत्यु के समय की दशा का वर्णन करते हुए मोरलैण्ड का कहना है कि भारतीय समुद्र का प्रधिकार धारिण्य भारत में बने जहाजों द्वारा होता था। भारत के यात्री-जहाज पुर्तगालियों द्वारा बनाये गए जहाजों को छोड़कर तत्कालीन सभी यूरोपीय देशों से बड़े थे।

३४. जलयान के सम्बन्ध में भारतीय साहस की बाधाएँ—ब्रिटिश इण्डिया स्टीम नविवेशन कम्पनी न, जो कि एक ब्रिटिश कम्पनी है, प्रायः १०० वर्ष से अधिक से देश का तटीय एवं समुद्र-पार व्यापार अपने कब्जे में कर रहा है। भारतीय और अंग्रेजी कम्पनियों ने दर-युद्ध (रेट वार) से बचने के लिए और व्यापार को अपने बीच बाँट रखने की दृष्टि से अपने को एक सम्मेलन में संगठित कर लिया है। चूँकि यह सम्मेलन विदेशी हितों से अनुशासित है, इसका उद्देश्य देशी जलयानों को दबान का ही रहता है। जहाजों के भारतीय मालिकों की दो शिकायतें थी—(१) बिलम्बित छूट-प्रथा (डेफर्ड रिवेट सिस्टम),^१ (२) दर-युद्ध (रेट वार)।^२

३५. बिलम्बित छूट-व्यवस्था, दर-युद्ध इत्यादि—इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है, ‘परिवहन कम्पनियाँ जहाज से मान भेजने वालों के लिए एक परिपत्र जारी करती है कि यदि उन्होंने एक निश्चित समय के अन्त तक (प्रायः ४ या ६ महीने तक) कम्पनी के अतिरिक्त किसी अन्य जहाज से सामान नहीं भेजा है तो कम्पनी उन्हें इसके बदले में उनके इस अवधि में कुल भाड़े में कुल का कुछ हिस्सा (प्रायः १०%) रियायत के तौर पर उनके नाम लिख देगी और यदि इसके बाद कुछ और समय तक (प्रायः ४ या ६ महीने तक) वे सम्मेलन (कान्फ्रेंस) के जहाजों से ही सामान भेजते रहें, तो छूट की यह रकम उन्हें दे दी जाएगी। इस प्रकार दी गई धन-राशि को बिलम्बित छूट कहते हैं।’

इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि विगत ४० वर्षों से भारतीयों द्वारा इस उद्योग में प्रवेश पाने के प्रायः सभी प्रयत्न विफल रहे। जितनी भी कम्पनियाँ बनीं प्रायः सब बिलीन हो गईं। इसके मार्ग में दूसरी बाधा यह थी कि यूरोपीय बीमा-कम्पनियों ने भारतीय कम्पनियों के साथ भेदपूर्ण व्यवहार किया और जो जहाज लन्दन में भी प्रथम श्रेणी के समझे जाते थे उनको भी वे द्वितीय श्रेणी में इसलिए रख देते थे क्योंकि

१. इन्ड्यू० डिग्री, प्रास्पेरेस ब्रिटिश इण्डिया, पृ० ८५-६।

२. जे० ए० वेस्टेलीनी का लेख, प्लानिंग इन ट्रांसपोर्ट, इटर्नल इकनामिस्ट, “भारतवासियों ने नये समुद्रों का अन्वेषण चाहे भले ही न किया हो किन्तु उनका सामुद्रिक ज्ञान, दिशा-निर्देशक यन्त्रों की महत्प्रता एवं जलयान-रक्षण बरकोटिगामा को चर्चित करने वाली थी।”

३. इसके विगृह्य विवरण के लिए देखिए, एम्प० एन० हाजी, ‘इकनामिक्स ऑफ शिपिंग’, अध्याय ५।

४. १९३८-३९ में बम्बई स्टीम नेविगेशन कम्पनी और भारतीय कम्पनियों (जो कि सिन्धिया स्टैम नेविगेशन कम्पनी द्वारा नियोजित थी) के बीच दर-युद्ध चला था।

५. हाजी, पूरे उद्धृत, पृ० १०३।

उनके मालिक भारतीय थे ।

विदेशी जहाजी कम्पनियों के विरुद्ध अन्य शिकायतें निम्न हैं—याचियों की सुविधाओं का कम ध्यान रखना, ऊँचे पदों पर केवल यूरोपियनों की नियुक्ति और उच्च पदों, जैसे इंजीनियर आदि, के लिए भारतीयों को काम न सिखाना आदि ।

३६. व्यापारिक जहाजरानी समिति (१९२३)—इस समिति की नियुक्ति फरवरी, १९२३ में हुई । इसका कार्य भारतीय जहाजरानी और जलयान-निर्माण उद्योग के विकास के प्रश्न पर विचार करना था । समिति के विशेष सुझाव निम्न हैं—

(१) भारतीय व्यापारिक जहाजरानी के लिए अनिवार्य अफसरों की प्रशिक्षण-हेतु सरकार द्वारा बम्बई में जलयान-प्रशिक्षण की स्थापना । (२) सामुद्रिक इंजीनियरों की ट्रेनिंग के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में सुविधाएँ देना तथा सामुद्रिक अनुभवों की सुविधाएँ देना । (३) तटीय व्यापार लाइसेंस-प्राप्त जहाजों के लिए सुरक्षित रखना । (४) भारतीय अधिकारी और कर्मचारी वर्ग द्वारा तटीय व्यापार में पर्याप्त दक्षता दिखाने पर विदेशी समुद्र-पार व्यापार के लिए भारतीय कम्पनियों को अनुदान देने व प्रश्न पर विचार करना । (५) कलकत्ता की स्वतः चालित जलयानों के निर्माण का केन्द्र बनाना, (६) भारतीय कम्पनियों द्वारा जलयान निर्माण प्राण (शिप बिल्डिंग वार्ड) की स्थापना में सरकार का सहायता देना तथा (७) प्रारम्भ करने के लिए विदेशों से विशेषज्ञों की सहायता लाना ।

३७. तटीय यातायात को भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित करने का बिल—उपर्युक्त पहली सिफारिश का फलस्वरूप प्रशिक्षण जलयान 'डफरिन' की स्थापना के अनिमित्त सरकार समिति के अन्य किसी भी सुझाव को कार्यान्वित न कर सकी, अतः नितम्बर, १९२८ में मि० हाजी ने धारासभा में तटीय यातायात सुरक्षण के लिए एक बिल पेश किया । इसमें कुल हिस्से का ७५% भारतीयों के हाथ में निहित करने की व्यवस्था थी ।

गत कई वर्षों से जनता द्वारा की गई माँग के फलस्वरूप १९५० में भारत का तटीय व्यापार भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित कर दिया गया । १ जनवरी, १९५१ को नये (भारतीय) तटीय सम्मेलन ने कार्य प्रारम्भ कर दिया । इस सम्मेलन में अधिकांशतः भारतीय जहाजरानी कम्पनियाँ हैं । दो ब्रिटिश जहाजरानी कम्पनियाँ भी इस सम्मेलन की सदस्य हैं ।

३८. बिलम्बित छूट-व्यवस्था की समाप्ति-सम्बन्धी बिल—मि० हाजी ने बिलम्बित छूट-व्यवस्था के उन्मूलन के लिए फरवरी, १९२६ में एक बिल पेश किया, जिसका उद्देश्य तटीय सुरक्षा बिल का पूरा करना था । जबकि सुरक्षा बिल जहाजरानी से होने वाली आय को भारत में रखना चाहता था बिलम्बित छूट बिल का उद्देश्य तटीय व्यापार व सुरक्षित हो जान पर व्यापार का भारतीय जहाजों के बीच समुचित वितरण करना था । इस बिल का उद्देश्य था भारतीय-अभारतीय किसी प्रकार की कम्पनियों के एकाधिकार को समाप्त करना तथा एक नवीन युग का प्रारम्भ करना, जिसमें एकाधिकार का अन्त करके नवीन कम्पनियों के प्रागमन के पथ को प्रोत्साहित कर दिया

जाएगा।

१९५१ से नये तटीय सम्मेलन के कार्याारम्भ के बाद अब यह प्रश्न समाप्त हो गया है।

३६. जहाजरानी पुनर्निर्माण नीति उप-समिति—द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर भारत सरकार के योजना-विभाग ने जहाजरानी-नीति-समिति (पोलिसी कमेटी ऑफ शिपिंग) की नियुक्ति की। समिति ने कहा, "द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ होने के समय भारत के पास गहरे समुद्रों में जाने योग्य १,५०,००० टन (ग्रास) के ३० जहाज थे। युद्धोत्तर-काल में इस स्थिति को तुरन्त सुधारना चाहिए।" तदनन्तर भारत सरकार द्वारा जहाजरानी (शिपिंग) के लिए एक पुनर्निर्माण-नीति-समिति की नियुक्ति हुई। इसने अपनी रिपोर्ट १९४७ (अप्रैल) में प्रस्तुत की। समिति ने जहाजरानी के लिए एक सबल राष्ट्रीय नीति का अनुमोदन किया। इसने १९५४ तक प्राप्त करने के लिए २० लाख टन भारवाहिकता का लक्ष्य रखा, ताकि भारतीय जहाजरानी को (१) सम्पूर्ण तटीय व्यापार, (२) भारत के बर्मा और सीलोन के व्यापार का ७५%, (३) भारत के दूरवर्ती व्यापार का ५०% और (४) पूर्व में घुरी शक्तियों द्वारा लोये गए व्यापार में ३०% प्राप्त हो जाए।^१

बहुमत रिपोर्ट ने भारतीय जहाजरानी उसे कहा है जो 'भारतीयों द्वारा अधिभूत, नियंत्रित एवं प्रबन्धित' हो। सर ए० एच० गज्जनकी के मतानुसार भारतीय जहाजरानी का अभिप्राय उन कम्पनियों से भी है जिनमें कम-से-कम ७०% हिस्से भारतीयों के हैं। इस मत का आधार यह था कि वर्तमान परिस्थिति में अल्प सख्या में विदेशियों का भाग लेना हानिकारक तो है ही नहीं, प्रत्युत लाभदायक ही है।

भारत सरकार ने अपने १२ जुलाई, १९४७ के प्रस्ताव में समिति के विचारों से पूर्ण सहमति व्यक्त की है।

जनवरी, १९४७ में १० करोड़ रु० की अधिकृत पूंजी से तीन निगमों की स्थापना के निर्णय की घोषणा की गई। ३० मार्च, १९५० को अधिकृत ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन की रजिस्ट्री १० करोड़ की पूंजी सहित हुई। १५ अगस्त, १९५६ को यह पूर्णतः सरकार के नियन्त्रण में आ गई। अगस्त, १९५६ के वेस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन की स्थापना १० करोड़ रु० की अधिकृत पूंजी के साथ की गई। १९५७ में सरकार ने भारतीय जहाजरानी की प्रगति-हेतु रुपये के अर्थ-प्रबन्धन का निश्चित साधन उपलब्ध कराने के लिए जहाजरानी-विकास-कोष (शिपिंग डिवेलपमेंट फण्ड) की स्थापना के निर्णय की घोषणा की। इस कोष का निर्माण भारत की सचिव निधि (कन्सोलिडेटेड फण्ड ऑफ इण्डिया) के अनुदानों से होगा। १९५८-५९ के बजट में इस कोष के प्रति १ करोड़ रु० अनुदान की व्यवस्था थी। जहाजरानी के क्षेत्र

१. भारतीय जहाजरानी कम्पनियों का एक प्रतिनिधिमण्डल मई, १९४७ को इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार और जहाजरानी के क्षेत्रों से भारतीय जहाजरानी के विकास के सम्बन्ध में वार्तालाप करना था। यह सितम्बर, १९४७ में विल किसी परिषद पर पहुँचे लौट आया।

में एक अन्य महत्वपूर्ण घटना परिवहन विभाग में जहाजरानी-संयोजन-समिति (शिपिंग को-ऑर्डिनेशन कमेटी) की स्थापना है। यह समिति उपलब्ध भारतीय भारवाहिता (टनेज) के अधिकतम उपयोग की दृष्टि से विभिन्न मन्त्रालयों तथा अन्य सरकारी सगठनों के बीच अधिक अच्छा सम्पर्क स्थापित करेगी। सरकार को जहाजरानी नीति से सम्बन्धित बातों पर परामर्श देने के लिए राष्ट्रीय जहाजरानी परिषद् (नेशनल शिपिंग बोर्ड) की स्थापना की गई (मार्च, १९५६)।

जहाजरानी पर प्रथम योजना में १८७ करोड़ २० व्यय किये गए तथा द्वितीय योजना में उसके अन्त तक ५४ करोड़ २० के व्यय का अनुमान है। तृतीय योजना में प्रस्तावित व्यय ५५ करोड़ २० है।^१

राष्ट्रीय जहाजरानी परिषद् ने १९६५-६६ तक १४२ लाख टन की क्षमता का लक्ष्य रखा है।

अनुमान है कि इस समय भारत के समुद्र-पार व्यापार का ८ या ९ प्रतिशत भारतीय जहाज ही ले जाते हैं।

४०. भारतीय व्यापारिक बेड़े की आवश्यकता—जहाजरानी और जहाज बनाने के सम्बन्ध में भारत के पास पर्याप्त सुविधाएँ हैं। ऐसा कहा जाता है कि जापान, संयुक्त राज्य अमरीका और जर्मनी की भाँति सरकारी हस्तक्षेप से थोड़े ही दिनों में एक पर्याप्त व्यापारिक बेड़े का निर्माण हो सकता है। इंग्लैण्ड की भी सामुद्रिक महत्ता और शक्ति का श्रेय बहुत अंश में नौका-गमन अधिनियमों को है। ये अधिनियम प्रायः दो शताब्दियों तक लागू रहे और उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में समाप्त कर दिये गए। एक बड़ा राज्य-हस्तक्षेप के अभाव में भारतीय नाविकता यूरोपीय प्रतिद्वन्द्वियों से होड़ लेने में असफल रही।

१७ सितम्बर, १९५८ को लोकसभा ने मर्चेंट शिपिंग एक्ट, १९५८ पास किया। ३० अक्टूबर, १९५८ को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस अधिनियम के अन्तर्गत ही राष्ट्रीय जहाजरानी परिषद् तथा जहाजरानी-विकास-कोष की स्थापना हुई है। इनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को किसी भारतीय जहाज को किराये पर लेने की दरें निश्चित करने तथा तटीय व्यापार में सलग्न जहाजों के लिए यात्रियों और व्यापारिक माल लाने-लेजाने की दरें भी निश्चित करने का अधिकार है। केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति जहाज-सम्बन्धी अपने हिस्से या हित को न हस्तांतरित कर सकता है, और न प्राप्त ही कर सकता है। अधिनियम में यात्रियों के किराये पर अधिकार लगाने की भी व्यवस्था है। इससे प्राप्त आय यात्रियों के कल्याण पर ही व्यय की जाएगी। व्यापारिक बेड़ा प्रशिक्षण समिति ने १९४९ में सिफारिश की थी कि एक प्रशिक्षण-परिषद् की स्थापना की जाए। अब व्यापारिक बेड़ा-प्रशिक्षण-परिषद् (मर्चेंट नेवी ट्रेनिंग बोर्ड) की स्थापना हो गई है। इसकी उद्घाटन बैठक ४ फरवरी, १९६० को हुई।

१ देखिए, धर्मेन्द्र काश्यप इमर प्लान—ए इण्डिया टाइम्स, पृ० २५०।

४१. भारतीय जलयान-निर्माण-उद्योग की स्थिति—भारतीय जहाज बनाने का उद्योग भारतीय जहाजरानी से कोई खास अच्छी परिस्थिति में नहीं है। गैर-भारतीय जहाज-निर्माताओं से केवल छोटे जहाजों के सम्बन्ध में प्रतिस्पर्धा की जा सकती है क्योंकि उन्हें यहाँ लाने की लागत उनके मूल्य के अनुपात से अधिक है, अन्यथा विदेशी जहाज बनाने वाले कारखानों का स्वच्छन्द एकाधिपत्य है। अभी हाल तक भारत में बड़े जहाज बनाने के लिए उपयुक्त इस्पात कारखाने नहीं थे। थोड़े-से मरम्मत करने वाले कारखाने थे परन्तु वे भी गैर-भारतीयों के हाथ में थे।

४२. बिजगापट्टम (अब विशालापटनम) का जलयान-निर्माण-प्रागण—कम्पनी द्वारा बना पहला जहाज एस० एस० जलउपा जनवरी, १९४८ में पानी में उतारा गया। कुल मिलाकर (जिसमें जलपत्नी दिसम्बर, १९४६, जलपद्मा सितम्बर, १९५० भी शामिल हैं) ८००० टन वाले ५ जहाज (बिजगापट्टम में) तीन वर्ष में बनाये गए। जलयान-प्रागण को बन्द होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने जलपद्मा को खरीद लिया। १९४६ में सिन्धिया कम्पनी ने भारत सरकार से प्रागण अपने हाथ में ले लेने की प्रार्थना की।

मार्च, १९५२ में सरकार ने सिन्धिया से विशालापटनम-जलयान-निर्माण-प्रागण खरीद लिया और उसका प्रबन्ध हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० को सौंप दिया। इसमें दो-तिहाई पूंजी सरकार की है। अब तक जलयान-प्रागण ने समुद्र में जाने योग्य २३ जहाज तथा दो छोटे जहाज बनाये।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत इंग्लिस्तान की सरकार ने एक प्राविधिक शिष्ट-मण्डल इस उद्देश्य से भेजा था कि वह दूसरे जलयान-प्रागण की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान का सर्वेक्षण और आवश्यक जानकारी एकत्रित करे। शिष्ट-मण्डल ने अप्रैल, १९५८ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके अनुसार किसी भी स्थान को आदर्श स्थान नहीं कहा जा सकता, किन्तु उपयुक्तता की दृष्टि से उन्होंने कोचीन (इर्नाकुलम), मजगाँव डॉक, काँडला, ट्राम्बे तथा ज्योखली का नाम गिनाया। भारत सरकार ने एक अन्तर्बिभागीय समिति की नियुक्ति की जिसने दूसरे जलयान-प्रागण की स्थापना के लिए कोचीन को चुनने की सिफारिश की। तीसरी पंचवर्षीय योजना में नये जहाजों की जलपत्नी के लिए ५५ करोड़ रुपये रसे गए और इस प्रकार योजना के पहले दो सालों में जलपत्नी ८,५७,००० GRT अप्रैल १९६१ से बढ़कर १०,५७,००० GRT (अप्रैल १९६३) और यह आशा की जाती है कि १९६५-६६ के अन्त तक इसको सन्ध्या १५ लाख GRT तक पहुँच जाएगी। १९६३ में जल परिपद् बनाई गई जो सरकार को शिपिंग की नीति के बारे में समय-समय पर सुझाव देती है। इस प्रकार योजनाओं में पोतालय तथा बन्दर-गाहों को नवीन तथा उन्नत बनाने के लिए बड़ा जोर दिया गया है। पहली दो योजनाओं में ५८ करोड़ रुपये निर्धारित हुआ। १९६५ के अन्त तक बड़ी बन्दर-गाहों पर माल तथा और वस्तुओं के स्वीकार करने की क्षमता को ६२,००,००० तक

पहुँचाया गया है। कोचीन, मद्रास इत्यादि बन्दरगाहों को बड़ा करने के लिए ७५ करोड़ रुपया रखा गया है। उड़ीसा सरकार परादीप नाम की बन्दरगाह को भी उन्नत कर रही है। इस प्रकार छोटी-छोटी बन्दरगाहों को उन्नत करने के लिए भी कोशिश की जा रही है और इस कार्य पर तीसरी योजना में १५ ६८ करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा और यह बन्दरगाह तीसरी योजना के अन्त तक ६० लाख टन को व्यापार तथा व्यवसाय को ठीक स्थान दे सकेगी।

चौथी योजना में जहाजों की जलपखी १९६५-६६ के अन्त तक १५ लाख से बढ़ाकर १९७०-७१ तक ३० लाख टन (GRT) की जाएगी। बड़ी बन्दरगाहों की शक्ति को लगभग ६ करोड़ तक बढ़ाया जाएगा और यह कोशिश की जाएगी कि भारतीय जलयान कुल व्यापार का ५० प्रतिशत भाग अपने जहाजों से करने लगे। सरकारी क्षेत्र में जलयान का भाग १९७५-७६ तक कुल का ५० प्रतिशत हो जाए।

वायु-परिवहन

४३. नागरिक उड्डयन—१९१४-१८ के युद्ध के बाद से नागरिक उड्डयन में विशेष-तया पारन्चात्य देशों में बड़ी ही तीव्र प्रगति हुई है और इसने विश्व के परिवहन में एक नानि ला दी है।

कराची और धम्पई के बीच हवाई डाक-सेवा (पोस्टल एअर मेल सर्विस) के प्रारम्भ के साथ नागरिक उड्डयन में रुचि जाग उठी। भारत से होकर जाने वाली डच और फ्रेंच नागरिक उड्डयन सेवाओं के प्रारम्भ होने, इंग्लैण्ड और कराची के बीच नियमित साप्ताहिक साम्राज्य डाक के प्रारम्भ तथा विन्व के सभी देशों में नागरिक उड्डयन में हुई प्रगति के साथ ही भारतीय उड्डयन भी विकास की प्रेरणा पाने लगा। भारत अन्तर्राष्ट्रीय हवाई सम्मेलन (इण्टरनेशनल ऐअर कनवेंशन) में शामिल हो गया है। भारत सरकार ने नागरिक उड्डयन का एक सचालक एव उप-सचालक तथा वायुयान-प्रधान निरीक्षक नियुक्त किये हैं। व्यक्तिगत साहसोद्योगी भी सामने आये और भारत में उड्डयन सिखाने वाले अनेक उड्डयन-क्लब स्थापित हो गए हैं। उच्च उड्डयन की प्रशिक्षण के लिए उडाकों को दी गई सहायता के अतिरिक्त सरकार ने नागरिक उड्डयन छात्रवृत्तियाँ भी देना प्रारम्भ किया है। व्यक्तिगत सत्याग्रा, जैसे 'रतन और दुरावजी टाटा ट्रस्ट' तथा अन्य कम्पनियों द्वारा भी छात्र-वृत्तियाँ दी जा रही हैं। अन्तरिक्ष-विभाग ने भी उड्डयन में सुधार किये हैं।

१९३६-४५ के युद्ध ने शीघ्रता से उड्डयन का विकास करने की आवश्यकता का अनुभव कराया। केनवेल में भारतीय सैनिक शिक्षार्थियों की ट्रेनिंग के उपरान्त १९३२ में भारतीय वायु सेना छोटे पैमाने पर स्थापित हुई। युद्ध के प्रारम्भ होने पर शीघ्रता से इसके विकास का कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया और तत्कालीन प्रशिक्षण की सुविधाएँ भी काफी बढ़ा दी गईं।

जुलाई, १९४२ में एक वायु-परिवहन अनुज्ञा परिपद् (एअर ट्रान्सपोर्टिंग लाइसेंसिंग बोर्ड) की स्थापना हुई। १ अक्टूबर, १९४२ के बाद विना बोर्ड से अनुज्ञा

प्राप्त किये कोई भी वायु-सेवाएँ प्रारम्भ नहीं की जा सकेंगी। इस समय भारतीय वायु-परिवहन कम्पनियों द्वारा ६ वायु-सेवाएँ संचालित हो रही हैं। १९४७ के अन्त में एअर इण्डिया इण्टरनेशनल को स्थापना हुई, जिसमें भारत सरकार का हिस्सा ४६ प्रतिशत था जिसे वह किसी भी समय ५१ प्रतिशत कर सकती थी। ५ वर्ष में होने वाली सब हानि को सरकार पूरा करेगी, किन्तु बाद के लाभ से उसके द्वारा दिया गया धन चुकाना पड़ेगा।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में वायु परिवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिए ६५ करोड़ ६० की व्यवस्था की गई। १९५३ में वायु निगम अधिनियम पास किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत पहली अगस्त, १९५३ को एक राजकीय निगम के रूप में इण्डियन एअर लाइन्स कारपोरेशन की स्थापना की गई। यह निगम अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन सत्ता की सदस्य है। अप्रैल, १९५८ में प्रत्येक निगम के लिए एक परामर्शदात्री समिति नियुक्त की गई। इन दो निगमों के अतिरिक्त १४ उड्डयन-क्लब तथा ६ परिवहन कम्पनियाँ भी हैं, (३१ दिसम्बर, १९५८ तक)। नागरिक उड्डयन में बराबर प्रगति हुई है। १९४७ में अनुसूचित सेवाओं (शेड्यूल्ड सर्विसेज) की उड़ान की दूरी ६३,६२,००० मील तथा यात्रियों की संख्या २५५ हजार थी। १९५६ में ये संख्याएँ क्रमशः २,४६,१३,००० मील तथा ७,२२,००० थी।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में नागरिक उड्डयन के ऊपर ५५ करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। इसमें से २२-२५ करोड़ २० हवाई अड्डों तथा ३०-३३ करोड़ ६० दोनो निगमों पर व्यय होगा।^१

वर्तमान समय में भारत-उड्डयन-उद्योग उड़ने वाले जहाजों की संख्या की अधिकता का शिकार हो रहा है। कमजोर आर्थिक स्थिति का भी यही एक कारण है। सबसे आधारभूत कठिनाई जनता की दरिद्रता है, जिसके कारण यात्रियों का यात्रायत्न बहुत कम होता है। उद्योग का विकास सीमित होने से भाड़े की आय भी बहुत कम होती है। भारत में उड्डयन की प्रगति सरकारी सहायता और नियन्त्रण पर निर्भर है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में एयर इंडिया कारपोरेशन तथा इंडियन एलाइन्स कारपोरेशन पर १४.५ करोड़ तथा १५ करोड़ रुपया व्यय किया गया। एअर इंडिया ने १९६५-६६ में ३२ लाख रुपये का लाभ दिखाया और इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने १४३ करोड़ रुपया लाभ दिखाया। तीसरी योजना में एयर इंडिया की माल तथा व्यवसाय की शक्ति ६१ प्रतिशत तथा आई-ए-सी २० प्रतिशत से बढ़ गई है। चौथी योजना में १९७०-७१ के अन्त तक एयर इंडिया की ४२ और इण्डियन एयरलाइन्स की ४६ प्रतिशत और शक्ति बढ़ जाएगी।

४४ बंगलौर की वायुयान फैक्ट्री—द्वितीय युद्ध ने भारत में वायुयान-निर्माण के

१. देखिए, धर्म पारव ईअर प्लान—ए ड्रॉफ्ट आउट लाइन, पृ० २५२।

विकास की महत्ता को बहुत बढ़ा दिया । इस कार्य में भी अग्रगामी होने का श्रेय श्री चालचन्द हीराचन्द को है । एक सम्मिलित पूंजी वाली कम्पनी (ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी), जिसका नाम हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट कम्पनी लिमिटेड था और जिसकी अधिकृत पूंजी (प्रॉचराइज्ड कैपिटल) ४ करोड़ २० थी, की रजिस्ट्री दिसम्बर, १९४० में मैसूर राज्य में हुई । यह कम्पनी चालचन्द हीराचन्द और मैसूर सरकार के संरक्षण में स्थापित हुई । एक अमेरिकन विशेषज्ञ के निदेशन में यह फैक्ट्री बंगलौर में स्थापित की गई । बंगलौर में कारखानों को स्थापित करने के दो कारण थे—एक तो वहाँ सस्ती विद्युत् शक्ति सरलता से प्राप्त हो सकती थी और दूसरे भद्रावती आइरन एण्ड स्टील वर्क्स से उत्तम इस्पात प्राप्त हो सकता था । जुलाई, १९४१ में पहला वायुयान तैयार हुआ, दूसरे महीने में एक और बना । कारखाने की योजना इतनी विकसित हो गई कि १९४२ तक यह धारा की जाने लगी कि फैक्ट्री में शीघ्र ही प्रति मास १५ से ३० तक वायुयान तैयार होने लगेंगे । इसी समय भारत सरकार ने कारखाने को कम से-न्चम युद्ध काल तक स्वयं चलाने का निश्चय किया ।



अध्याय १६

भारत का व्यापार

इस अध्याय का विषय भारत का व्यापार है जिसे अव्ययन की सुविधा के लिए निम्न प्रधान शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है—(१) बाह्य व्यापार, जिसमें (क) समुद्र-वाहित व्यापार, (ख) मध्यागार (एण्ट्रीपोर्ट) व्यापार, तथा (ग) सीमा-पार व्यापार सम्मिलित हैं। (२) आन्तरिक व्यापार, जिसमें देश के अन्दर का तथा तटीय व्यापार शामिल है।

बाह्य व्यापार

१. ऐतिहासिक सिंहावलोकन—भारत के प्राचीन व्यापार का वर्णन बहुत संक्षेप में किया जाएगा, क्योंकि हमारा प्रधान लक्ष्य उन्नीसवीं शती के उत्तरार्द्ध से होने वाले विकासो से है। उन अन्य देशों में, जिनके साथ भारत का व्यापार सम्बन्ध था, चीन, अरब और फारस का नाम लिया जा सकता है। भारत या समस्त विश्व का पुराने जमाने का व्यापार दुर्लभ और बहुमूल्य वस्तुओं का व्यापार था, जबकि इसके विपरीत आज का व्यापार जनसाधारण की आवश्यकता की पूर्ति करने वाली सस्ती और भारी वस्तुओं का व्यापार है, जो वस्तुएँ दूर-दूर देशों में भेजी जाती हैं। पुराने जमाने के निर्यात की प्रधान वस्तुएँ कपड़े, धातु के बर्तन, हाथीदाँत, इत्र, रंग और मसाले इत्यादि थीं। आयात में खनिज-पदार्थों की प्रमुखता थी जिनकी भारत में कमी थी, जैसे पीतल, टिन, राँगा आदि। इनके अलावा शराब और घोड़े आदि अन्य वस्तुओं का भी आयात होता था। चूँकि उस जमाने में विदेशों से सोना अधिक मात्रा में भारत आ रहा था, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आयात की तुलना में निर्यात अधिक था। निर्यात की अधिकता भारत के विदेशी व्यापार की विशेषता थी। थोड़ा-सा मध्यागार व्यापार भी होता था। इसमें प्रधानतया चीन में चीनी मिट्टी के बर्तन और रेशम, सीलोन से मोती तथा भारतीय द्वीप-समूहों से कीमती पत्थर, बहुमूल्य हीरे इत्यादि का व्यापार सम्मिलित था। यह इस बात का द्योतक है कि भारत के पास व्यापारिक जहाजी बेड़े अवश्य थे।

मुगल दरबार के संरक्षण ने कितने ही भारतीय उद्योगों को प्रेरणा दी। इनमें विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन प्रधान था। सामुद्रिक व्यापार—विशेषकर मालाबार तट का, कुछ अंशों में केम्बे की खाड़ी और कारोमण्डल तट का—मुसलमानों के हाथ में था, जो कि बाद में वनियो और चेटियारों के हाथ में आ गया। भारतीय समुद्र से होने वाले सुदूरपूर्व और लालसागर तक के सब व्यापार का प्रधान मध्यागार मालाबार और बन्दरगाह कालीकट था। मुस्लिम-काल में व्यापार प्रायः

वैसा ही बना रहा और गिबन का यह कट्टा कथन कि, "पूर्वार्ध व्यापार की वस्तुएँ मध्य और तुच्छ थीं" वस्तुतः १६वीं शताब्दी के लिए उतना ही सागू होना है जितना कि दूसरी शताब्दी के लिए।" आयात में प्रधानतया सोना, चिक्के बनाने और प्रदर्शन के लिए, बहुत बड़ी सख्या में घोड़े, घातुओं में जस्ता, राँगा पारा, तँत्रा इत्यादि, विवास की वस्तुओं में हीरे, जवाहर और एम्बर आदि वस्तुएँ थीं। इनके बदले भारत से कपड़े, रंग की सामग्री, अफीम तथा अन्य मादक वस्तुएँ, काली मिर्च तथा कुछ अन्य मसाले भेजे जाते थे।

षट्शती शताब्दी में उत्तमासा अन्तरीप से होकर भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज हो जान से पूर्व और पश्चिम में सम्पूर्ण स्वायत्त हो गया और व्यापारिक मार्गों में युगान्तकारी परिवर्तन हुए। इसके पहले भारत का यूरोप से सामुद्रिक व्यापार हिन्द महासागर से अदन तक होना था, इसके बाद माल उतार दिया जाता था तथा जल थल के मार्गों से भूमध्य सागर तक पहुँचाया जाता था। फिर इटली के व्यापारियों द्वारा यह माल वेनिस और जिनेवा पहुँचाया जाता था और वहाँ से समुद्र द्वारा सुदूर-पश्चिम या भूमि के रास्ते से आल्प्स के उस पार राइन द्वारा एष्टवर्ष पहुँचाया जाता था जो उस समय पश्चिमी यूरोप का प्रधान वितरक था। इस लाभ को अपनायें के लिए ही पुर्तगालियों ने भारत के नवीन रास्ते की खोज प्रारम्भ की। इंग्लैण्ड, हालैण्ड तथा फ्रान्स के आकर्षण का प्रधान कारण कच्चा माल नहीं था, बरन् लिनन, छीट, होरे, जरी के काम किए हुए कपड़े, ऊनी और रेशमी वस्तुएँ आदि थीं। यही वस्तुएँ ईस्ट इण्डिया कम्पनी के लाभदायक व्यापार का आधार थीं, जिस पर अन्त में सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति और फ्रान्सीसियों की हार के उपरान्त उसे पूर्ण एकाधिकार प्राप्त हो गया। एक समय इंग्लैण्ड में भारत से व्यापार करने के कारण ईस्ट इण्डिया कम्पनी का बड़ा विरोध होना था। कारण यह था कि इंग्लैण्ड में भारतीय सफेद कपड़ों और मसालों की बड़ी माँग थी और उसके बदले में नकद रूपया देना पड़ना था, क्योंकि इंग्लैण्ड के ऊनी कपड़ों का भारत में अपत न थी। सत्रहवीं शती के अन्त में भारतीय कपड़ों का प्रयोग दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया गया। इसके लिए या तो भारतीय कपड़ों पर इतना अघिड़ आयात कर लगाया गया कि उसका आयात विलकुल बन्द हो जाए या उसके प्रयोग की विलकुल मनाही कर दी गई।

उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में इंग्लैण्ड और भारत में होने वाले व्यापार क स्वभाव में काफी परिवर्तन हो गया। अब भारत उन्हीं वस्तुओं, उदाहरणार्थ कपड़ा और चीनी, का आयात करने लगा जिनका वह अब तक निर्यात करता आया था। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक लन्सायर में कपड़े का उद्योग इतना विकसित हो गया था कि भारत में भेजी जाने वाली वस्तुओं का आयात भाग कपड़ा ही होता था।

१. बंगाल की दीवानी निज चाने पर विनियोग की विपन्न पद्धति से (जिसमें भारतीय मालगुजारी से निर्यात के माल खरीदे जाते थे) भारत में सोने का आना बन्द हो गया और भारतीय व्यापार के प्रति विरोध बन ही गया।

ने चुनौती दी। रूस और जापान के युद्ध के उपरान्त भारतीय व्यापार में जापान की दिलचस्पी तेजी से बढ़ने लगी। इन देशों का उद्देश्य भारत में अपनी निर्मित वस्तुओं की बिक्री बढ़ाना था, लेकिन इस उद्देश्य से निर्मित सगठनों ने भारत के कच्चे माल तथा खाद्यान्न, जो इन देशों के उद्योगों के लिए आवश्यक थे, के निर्यात को प्रेरणा दी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित तरीके काम में लाये गए— (१) राष्ट्रीय जहाजरानी सेवाओं का विकास, (२) राष्ट्रीय बैंकों की शाखाओं की स्थापना जैसे जर्मन ड्यूट्स्के एशियाटिक बैंक और जापानी याकोहामा स्पेशी बैंक, जो अपने देशवासियों को साख की विशेष सुविधाएँ देते थे और (३) वम्बई, कलकत्ता—जैसे व्यवसाय-प्रधान केन्द्रों में वाणिज्य-सदनों की स्थापना। इस कार्यवाही में उन देशों की सरकारों की भी पूरा सहानुभूति थी तथा उनके भारत-स्थित राजदूतों ने भी अपने देश के व्यापारिक हित को पूरा प्रोत्साहन दिया। संयुक्त राज्य अमरीका ने लन्दन द्वारा भारत से सम्बन्ध स्थापित कर रखा था। १९१४-१८ के युद्ध के प्रारम्भ होने के बाद भी भारत में व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए संयुक्त राज्य के प्रयत्न इतने जागरूक एवं कटिबद्ध नहीं थे जितने कि जापान और जर्मनी के।

४. १९१४-१८ के युद्ध के पूर्व की स्थिति का सारांश—१८७३ से शताब्दी के अन्त तक व्यापार के विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी थी। रुपये के मूल्य में भारी चढ़ाव उतार से स्वर्ण-प्रभाप वाले देशों के साथ व्यापार में एक प्रकार की अनिश्चितता और परिकल्पना (सट्टेबाजी) शुरू हो गई, जिससे व्यापार की साधारण गति रुक गई।

नवीन शताब्दी के प्रथम चौदह वर्षों में विशेषकर १९०१ के बाद, भारत के विदेश-व्यापार में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। सबसे महान् वृद्धि प्रथम विश्व-युद्ध के प्रारम्भ होने से पहले पांच वर्षों में हुई। इन वर्षों में रुपये का मूल्य प्रायः स्थिर था। रेलवे और सिंचाई-जैसे जन-कार्य बड़ी तत्परता के साथ किये जा रहे थे, शताब्दी के अन्त में पड़ने वाले दुर्भिक्षों-जैसे दुर्भिक्ष भी नहीं पड़े थे और महामारी का प्रकोप भी कम हो रहा था। इसके अतिरिक्त, जैसे कि पहले कहा जा चुका है, जर्मनी, जापान तथा संयुक्त राज्य भी कुछ अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का सगठित प्रयत्न कर रहे थे, जो इन देशों में होने वाले आर्थिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तेजी से बढ़ रहा था तथा जिसने औद्योगिक दृष्टि से उन्हें इंग्लैण्ड के समक्ष कर दिया था।

५. प्रथम विश्वयुद्ध का भारत के व्यापार पर प्रभाव—अगस्त, १९१४ में युद्ध प्रारम्भ होने पर भारत के विदेश व्यापार की दोनों शाखाओं का धक्का लगा। १९१६-१७ के बाद निर्यात का मूल्य तो अपनी पूर्व स्थिति में आने लगा, परन्तु आयात १९१८-१९ तक युद्ध-पूर्व की स्थिति से पीछे ही रहा। आयात व्यापार में विशेष रूप से कमी हुई और यह कमी युद्ध-काल में लगातार जारी रही। अब हम संक्षेप में इस परिस्थिति के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना करेंगे। युद्ध प्रारम्भ होने पर शत्रु देशों के साथ व्यापार बिलकुल ठप हो गया। मित्र-राष्ट्रों, जैसे इंग्लैण्ड, फ्रांस, बेल्जियम इत्यादि, से भी युद्ध-पूर्व स्तर पर व्यापार कायम न रखा जा सका, क्योंकि ये देश स्वयं युद्ध में संलग्न थे। निष्पक्ष देशों के साथ होने वाले व्यापार पर भी अनेक प्रतिबन्ध लगाये

गए ताकि इन देशों द्वारा युद्ध-सामग्री जर्मनी न पहुँचने पाए और भारत की सामग्री केवल मित्र-राष्ट्रों की ही उपलब्ध हो। समुद्र से शत्रु के जहाजों के हट जाने तथा अवशिष्ट जलयानों पर युद्ध के बोझ के परिणामस्वरूप किराये में काफी वृद्धि हो गई। परिणाम यह हुआ कि यूरोप में भारतीय वस्तुओं की बढ़ती हुई मांग से भारत पूरी तरह लाभ नहीं उठा पाया। व्यापार की स्थिति को बिगाड़ने वाले कारकों में सामुद्रिक सुरक्षा के अभाव तथा विदेशी विनिमयों के विस्थापन (डिस्लोकेशन) का नाम लिया जा सकता है।

१९१४-१८ के युद्ध-काल की विशेष बात निर्मित वस्तुओं के निर्यात में हुई वृद्धि है, कुल व्यापार से जिनका प्रतिशत १९१३-१४ में २२.४ प्रतिशत बढ़कर १९१८-१९ में ३६.६ प्रतिशत हो गया। युद्ध द्वारा नई कृत्रिम प्रेरणा का उल्लेख हम कपास, जूट, चमड़ा, लोहा इत्यादि के सम्बन्ध में कर आए हैं। इसी कारण निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ा।

६. दोनों युद्धों के बीच के समय में व्यापार (१९१९-२० से १९३९-४०)—इस काल के प्रारम्भिक वर्षों में निर्यात पर लगाये गए युद्धकालीन प्रतिबन्धों के हट जाने, शत्रु देशों से पूर्ववत् व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित होने, तथा किराये की स्थिति में सुधार होने के परिणामस्वरूप व्यापार में समृद्धि-माधूम होनी लगी। इसके चिह्न १९२०-२१ व अन्त में स्पष्ट रूप से लक्षित होने लगे थे। सबसे पहले निर्यात-व्यापार पर प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन, समुक्त राज्य तथा जापान ने बाजार भारतीय उत्पादनों से भर गए और अन्तर्की और से मांग काफी कम हो गई। यह ठीक है कि मध्य यूरोप के देशों में भारतीय वस्तुओं की मांग बहुत अधिक थी, लेकिन वे युद्ध से विच्छिन्न हुए साधनों तथा घटी हुई क्रय-शक्ति के कारण इन्हें खरीदने में असमर्थ थे। १९२० की असन्तोषजनक वर्षा तथा खाद्यान्नों की बढ़ती हुई कीमतों के कारण यह आवश्यक हो गया कि खाद्यान्नों के निर्यात पर लगाये गए प्रतिबन्ध जारी रखे जाएँ। जापान में भी भीषण सकट-स्थिति उत्पन्न हो जान से उस देश को निर्यात की जाने वाली कपास में रुकावट पड़ गई। सरकार द्वारा दो शिफ्ट पर रुपये के विनिमय-मूल्य को स्थिर करने के प्रयत्न ने भी पहले ही से कमजोर निर्यात-व्यापार को और भी दुर्बल बना दिया। इसक विपरीत आयात-व्यापार शीघ्रता से बढ़ता गया। युद्ध-काल में भारत की आयात-सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो सकीं। मशीन तथा अन्य निर्मित वस्तुओं के लिए दिये गए ऑर्डर अब तक वैसे ही पड़े थे। अब ये सामान दस में आने लगे। उच्च विनिमय ने भी आयात व्यापार को पर्याप्त प्रेरणा दी और बहुत बड़ी मात्रा में विदेश-निर्मित वस्तुओं के लिए ऑर्डर दिए गए। इसलिए हमें इस बात पर आश्चर्य न करना चाहिए कि भारत का व्यापारिक सन्तुलन १९२०-२१ में ७९ करोड़ रुपये से प्रतिफल था। यह सन्तुलन दूसरे वर्ष भी ३३.९४ करोड़ रुपये से प्रतिफल रहा।

७ विन्ध के आर्थिक अवसाद-काल में भारत का व्यापार—वात स्ट्रीट के आर्थिक विघटन के उपरान्त अक्टूबर, १९२९ में एक अधोमुखी प्रवृत्ति प्रारम्भ हो गई और बाद

मे स्वर्ण मुद्राओं का अदम्यमूल्यन—इन सबके प्रभाव से कितनी ही वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगे । १९३७ के पूर्वार्द्ध में मूल्यों की वृद्धि पर्याप्त रूप से दृष्टिगोचर होने लगी । इसका एक कारण और भी था—सरकारों द्वारा कितने ही देशों में शस्त्रीकरण पर काफी धन खर्च किया जा रहा था । इससे भारी उद्योगों को काफी प्रोत्साहन मिला और साधारण आर्थिक स्थिति पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ा ।

भारत ने भी विश्व की समुत्पादन-प्रवृत्ति का अनुगमन किया, हालांकि अपनी विशेष परिस्थितियों के कारण उसका मार्ग अन्य देशों से कुछ भिन्न था । १९३६ में प्रारम्भ हुई मन्दी ने भारत-जैसे कृषि-प्रधान देश को विशेष रूप से हानि पहुँचाई । इसका कारण प्राथमिक उत्पात्ति (कृषि-उत्पत्ति) के मूल्यों में हुई अमूल्यपूर्व कमी थी । कृषि-उत्पादन की कीमतों में सुधार भी कुछ पहले ही होने लगा । लेकिन जहाँ तक भारत के कृषि-उत्पादनों का सम्बन्ध है इनकी कीमतों में पर्याप्त वृद्धि १९३६-३७ के बीच ही दिखाई पड़ी (देखिए, अध्याय ११) । यह सुधार विशेष रूप से प्रारम्भिक वस्तुओं एवं कच्चे माल की बढ़ती माँग का परिणाम था ।

६. गिरावट (रिसेशन) के समय में भारत का व्यापार (१९३७-३८ से १९३८-३९ तक)—अप्रैल, १९३७ के लगभग समुक्त राज्य में व्यापार में गिरावट प्रारम्भ हुई । ज्यों-ज्यों वर्ष बीतता गया यह जोर पकड़ती गई । इससे विश्व के आर्थिक समुत्पादन को एक आकस्मिक धक्का लगा । आर्थिक दशाओं की ऊर्ध्वगामी दिशा एकाएक विपरीत हो गई । वह परिकल्पना (सट्टेबाजी) का अनिर्वास्य परिणाम था । अशत भविष्य में कच्चे माल की सम्भावित कमी से उत्पन्न घबराहट भी इसके लिए उत्तरदायी थी । इनके परिणामस्वरूप समुक्त राज्य में अकारण स्वर्ण भय उत्पन्न हो गया । बैंकों ने साख्त-सुविधाओं पर प्रतिबन्ध लगा दिए और नियन्त्रित उत्पादन की योजनाओं में टोल दे दी गई । फलतः विश्व में प्राथमिक वस्तुओं का मूल्य तेजी से घट गया और जून, १९३८ तक कम बना रहा ।

फिर भी १९३६ के प्रारम्भ में व्यापारिक क्रियाशीलता धीरे-धीरे बढ़ने लगी । इसका कारण अशत दान्यिक प्रसार की नीति और सारे सप्ताह में विशेषतया समुक्त राज्य में बढ़ता हुआ सार्वजनिक व्यय तथा अशत शस्त्रास्त्रों पर अधिकाधिक व्यय है ।

विगत वर्ष की तुलना में १९३७-३८ में भारत के समुद्र-पार व्यापार के आयात में थोड़ी वृद्धि और निर्यात में थोड़ी कमी हुई । परिणाम यह हुआ कि भारत से व्यक्तिगत सौदों का निर्यात ५१ करोड़ रुपये (१९३६-३७) से घटकर १७ ५६ करोड़ रुपये हो गया । भारतीय विदेशी व्यापार के व्यक्तिगत सौदों का कुल मूल्य (१९३६-३७ में) २६३ करोड़ ६० था, जोकि १९३८-३९ में घटकर ३२२ करोड़ ६० हो गया । निर्यात में ४१ करोड़ ६० व मूल्य की कमी कुछ अंशों में विश्व के बाजारों में प्रारम्भिक वस्तुओं की मन्दी का परिणाम थी और इसका कारण अशत भारतीय ब्यास के लिए जापान की ऋण जक्ति का घट जाना भी है । आयात की कमी का कारण कृषकों की ऋण शक्ति का ह्रास था । विगत वर्ष की अपेक्षा १९३८-

३६ में आयात में कमी होने के कारण लगभग २ करोड़ ६० से भारत का व्यापारिक सन्तुलन (वेलेंस ऑफ ट्रेड) सुधर गया।

१०. युद्ध-काल (१९३९-४५) में भारत का विदेशी व्यापार—सितम्बर, १९३९ में युद्ध के प्रारम्भिक तथा आगामी वर्षों में उसके प्रसार और घनत्व के साथ-ही-साथ भारत के विदेशी व्यापार को प्रभावित करने वाले कितने ही कारण सामने आये।^१ पहले तो इनमें से अनेक प्रतिकूल थे, लेकिन बाद में अनुकूल कारण भी दृष्टिगत हुए। वास्तविक परिणाम में कोई क्रमिक ह्रास नहीं दिखाई पड़ा, बल्कि कुछ सुधार ही हुआ। प्रतिकूल परिस्थितियाँ युद्ध-घोषणा के पूर्व की राजनीतिक अनिश्चितता का परिणाम थीं। जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड सितम्बर, १९३९ के पहले हफ्ते में ही समाप्त हो गए। १९४० के वसन्त तक नार्वे, हालैंड, डेनमार्क, बेलजियम, फ्रांस और इटली शत्रुओं द्वारा अधिकृत क्षेत्र हो गए। दूसरे वर्ष में शत्रु द्वारा पदाक्रान्त-क्षेत्र के अन्तर्गत सारा दक्षिण-पूर्वी यूरोप आ गया। रूस के साथ व्यापार पहले ही समाप्त हो चुका था, लेकिन जून, १९४१ में जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण किये जाने पर रूस से फिर व्यापार शुरू हो गया। जुलाई, १९११ में भारत द्वारा जापान की सम्बन्धि पर अधिकार कर लेने से भारत और जापान के व्यापारिक सम्बन्ध को धक्का पहुँचा। दिसम्बर, १९४१ में जापान भी एक शत्रु देश हो गया। जापान के तूफानी घावों तथा एक के बाद दूसरी विजय ने क्रमशः हिन्दचीन, स्याम, ईस्ट इण्डोनेशिया, मलाया और बर्मा-जैसे महत्त्वपूर्ण बाजारों को बन्द कर दिया।

इस तरह वे प्रधान देश, जिनके साथ भारत का व्यापार सम्भव रह गया, केवल सयुक्त राज्य, इंग्लिस्तान, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य देश और एशिया तथा अफ्रीका के निकट एव मध्य-पूर्वी देश थे, हालाँकि यहाँ भी एक बहुत बड़ी बाधा जहाजी सुविधाओं की कमी थी। जर्मनी के यू बोट के डर के कारण किराये की दरें और बीमा का मूल्य बहुत बढ़ गया था। १९४० में इटली के साथ अंग्रेजों के राजनीतिक सम्बन्धों के खराब हो जाने के कारण भारत-यूरोपीय व्यापार उत्तमाशा अन्तरीप की ओर से होने लगा। तब जहाजरानी की कमी का अनुभव बड़ी तीव्रता से हुआ। दिसम्बर, १९४१ में जापान भी युद्ध के अखाड़े में कूद पड़ा। इससे प्रशान्त महासागर के मार्ग भी अरक्षित हो गए और सयुक्त राज्य, आस्ट्रेलिया एव न्यूजीलैंड के साथ होने वाले भारतीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

उपर्युक्त कारणों में अब हम एक और कारण भी जोड़ सकते हैं। युद्ध प्रारम्भ होने के उपरान्त, जिन देशों के साथ भारत का व्यापारिक सम्बन्ध था प्रायः उन सभी ने व्यापारिक प्रतिबन्धों का एक जटिल जाल फैला दिया। भारत ने भी अपनी तरफ से ऐसी ही नीति का अनुसरण किया। युद्ध प्रारम्भ होने के ठीक बाद केन्द्रीय सरकार

१. द्वितीय विश्वयुद्ध से सम्बन्धित भारत के विदेशी व्यापार का विवरण बहुत अग्रों में प्रो० एन० एस्० पार्दर्शनी द्वारा प्रस्तुत किये गए नोट पर आधारित है।

ने निर्यात-व्यापार की अनेक सामग्रियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया। शत्रु-देशों के साथ व्यापार करना बिल्कुल बन्द कर दिया गया। यह भी दृष्टि में रखा जाता था कि किसी प्रकार परोक्ष रास्तों से भी सामान शत्रुओं तक न पहुँचे और प्रत्येक प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति को मित्र-राष्ट्रों तथा भारत की आवश्यकताओं के लिए ही सुरक्षित रखा जाए। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखकर निर्यात-प्रतिबन्धों और अनु-ज्ञाओं (लाइसेंसों) का एक विस्तृत जाल खड़ा कर दिया गया।^१ कुछ वस्तुओं के लिए निर्यात-अनुज्ञा (लाइसेंस) पूर्ति-विभाग द्वारा तथा कुछ वस्तुओं के लिए निर्यात-व्यापार-नियन्त्रक (एक्सपोर्ट ट्रेड कंट्रोलर) द्वारा दी जाती थी। मई, १९४० में आयात की ६८ मदों पर भी प्रतिबन्ध लगाये गए। इनका उद्देश्य विदेशी विनिमय को सुरक्षित करना एवं सीमित जहाजों के बोझ को कम करना था। इसमें से अधिक वस्तुएँ विलासिता की थीं, जिनमें प्रतिदिन के प्रयोग की वस्तुएँ भी शामिल थीं। इन लगाये गए प्रतिबन्धों के परिणामस्वरूप उन वस्तुओं की पूर्ति या वैकल्पिक पूर्ति के लिए कितने ही छोटे-बड़े उद्योग खड़े हो गए। इस सबका नतीजा यह हुआ कि व्यापार अपने साधारण मार्ग से बहुत-कुछ हट गया।^२

युद्ध-दशाओं के अलावा इधर हाल के कुछ वर्षों में व्यापारिक गति आवश्यक कच्चे माल, मशीन और उपभोग्य-वस्तुओं की पूर्ति को प्रोत्साहन देने वाली सरकारी नीति द्वारा अनुशासित होती रही है। सरकार की नीति राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के लिए अनावश्यक सामग्रियों के आयात को कम करने तथा आन्तरिक प्रयोग एवं हितों के लिए अनिवार्य वस्तुओं के निर्यात को पूर्णतया बन्द करने की थी।

११. ग्रंगरी-मीक मिशन—भारत सरकार ने जुलाई, १९४० में भारतीय निर्यात-व्यापार को पुनर्जीवित करने के विचार से एक व्यापारिक शिष्ट-मण्डल सयुक्त राज्य अमरीका को भेजा। इस व्यापारिक मण्डल के सदस्य डॉक्टर टी० ई० ग्रेगरी और सर डेविड मीक थे। जनवरी, १९४१ में प्रकाशित हुई अपनी रिपोर्ट में इन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि भारत को अपने खीए हुए बाजारों का स्थानापन्न अमरीकी बाजारों में नहीं मिल सकता।^३ कारण यह था कि भारत द्वारा यूरोप को भेजी जाने वाली सामग्री अधिकतर जूट, मूंगफली, कपास, खली, गेहूँ, कच्चा चमड़ा इत्यादि थी। ये सब चीजें बड़ी मात्रा में सयुक्त राज्य को नहीं भेजी जा सकती थी। अमरीका के पाम स्वयं उसकी कपास ही आवश्यकता से अधिक थी। यही बात गेहूँ और मूंग-

१. विलून विवरण के लिए देखिए, 'रिब्यू ऑफ़ ट्रि ट्रेड ऑफ़ इण्डिया' (१९३६-४०) अनुसूची।

२. युद्ध-काल के नियन्त्रणों के अन्तर्गत और स्वभाव से सम्बन्धित विशेष विवरण के लिए देखिए, श्री एल० सी० जैन की 'इण्डियन इकनामी ड्यूरींग दि वॉर', पृ० ६२-६७।

३. मार्च, १९४५ में कितने ही प्रकार की उपभोग्य-वस्तुओं एवं आवश्यक कच्चे माल का आयात के लिए ओपन जनरल लाइसेंस-प्रथा प्रारम्भ की गई।

४. देखिए, सेक्शन ११-१२ और ३६-३७।

५. रिपोर्ट, पैराग्राफ ६७।

फली के लिए भी लागू है। वह जूट के स्थान पर अधिकाधिक कपास और कागज की सामग्री का प्रयोग करता है, साथ ही अपनी खली स्वयं तैयार करता है और चमड़ा सिभाता है। दक्षिणी अमरीका में घुरी राष्ट्रों की महत्त्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए किया गया हवाना पान-अमरीकन सम्मेलन अन्तर-अमरीकी व्यापार के विकास का एक अन्य कारण है। दक्षिणी अमरीका के अनेक कच्चे माल, जैसे अर्जण्टाइन के निल, मूंगफली, खली और बीज इत्यादि, प्रत्यक्ष रूप से भारतीय सामग्री के प्रतिस्पर्धी हैं।

१२. निर्यात-परामर्श-समिति तथा अन्य उपाय—ग्रेगरी-मीक की रिपोर्ट से यह विल-बुल स्पष्ट हो गया कि भारत को अपने खोये हुए यूरोपीय बाजारों के घाटे को भरने के लिए गैर-अमरीकी बाजार ढूँढने पड़ेंगे। इसमें थोड़े-से गैर-कॉमनवेल्थ देशों से होने वाले व्यापार का भी कुछ हाथ था। अफ्रीका और अरब को निर्यात किये जाने वाले कपड़े में हुई वृद्धि को उदाहरणस्वरूप लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मई, १९४० में स्थापित निर्यात-परामर्श-समिति का भी उल्लेख आवश्यक है। इसका सभापति चाणिज्य-सदस्य होता था तथा विभिन्न व्यापारिक एवं औद्योगिक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले २९ अन्य सदस्य होते थे। इसके निम्न कार्य थे—(१) वर्तमान निर्यात-कठिनाइयों पर वाद-विवाद, (२) प्रधान निर्यात-सामग्रियों के प्रसार के लिए सुझाव तथा वैकल्पिक बाजारों की खोज, (३) भारत-निर्मित वस्तुओं के प्रसार को प्रोत्साहित करना और अन्तिम (४) भारत द्वारा अन्य समुद्र-पार देशों में भेजने वाले व्यापारिक शिष्ट-मण्डलों को दी जाने वाली सुविधाओं पर विचार।

१३. राजकीय व्यापार-निगम और तदनन्तर—१९४७ में स्वतन्त्र होने के बाद प्रारम्भिक वर्षों में भारत का निर्यात-व्यापार बहुत सन्तोषप्रद रहा था। १९४८-४९ और १९५१-५२ के बीच भारतीय निर्यात में ६० प्रतिशत वृद्धि हुई। किन्तु विश्व के निर्यात की वृद्धि की तुलना में भारत के निर्यात की वृद्धि-दर बहुत कम रही। सरकार ने १९५६ में राजकीय व्यापार निगम (स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन) की स्थापना की।

राजकीय व्यापार के सम्बन्ध में दो समितियों ने भी अपनी रिपोर्टें इसके पक्ष में प्रस्तुत की थी, किन्तु इनके अनुसार राजकीय व्यापार का क्षेत्र सीमित होना चाहिए। प्रथम समिति (१९४९), जिसका अध्यक्ष डॉ० पी० एस० देशमुख थे, ने साद्यान्त, उर्वरक, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के आयात निर्यात सम्बन्धी कार्य, पूर्वी अफ्रीका के कपास का आयात, छोटे रेशे वाली कपास का निर्यात तथा कुटीर उद्योगों की वस्तुओं के निर्यात को ऐस निगम को सौंपने की सिफारिश की थी। प्रथम योजना के द्वितीय चरण में श्री एस० बी० कृष्णमूर्ति राव की अध्यक्षता में नियुक्त दूसरी समिति ने केवल हथकरघे के कपड़े तथा चुने हुए छोटे पैमाने के कुटीर उद्योगों के निर्यात को निगम को सौंपने की सिफारिश की। कर-जाँच-आयोग (१९५३-५४) का मत राजकीय व्यापार के विरुद्ध था।

अस्तु, १८ मई, १९५६ को राजकीय व्यापार-निगम की स्थापना एक मिश्रित पूंजी वाली कम्पनी के रूप में की गई। प्राक्कलन-समिति (एस्टीमेट्स कमेटी)

ने संक्षेप में इसके कार्यक्षेत्र को इस प्रकार व्यक्त किया

(१) भारत के विदेशी व्यापार—मुख्यतः साम्यवादी देशों से—में विविधता और विस्तार लाने की कठिनाइयाँ दूर करना ;

(२) स्थिर मूल्य-स्तर बनाए रखने तथा माँग और पूर्ति में सामञ्जस्य स्थापित करने का प्रयत्न करना ,

(३) आवश्यक वस्तुओं की माँग और पूर्ति के अन्तर को पूरा करने के लिए बड़े परिमाण में आयात का प्रबन्ध करना । तथा ,

(४) निजी व्यापार के पूरक के रूप में काम करना ।

इन आधारों पर राजकीय व्यापार-निगम ने कार्य प्रारम्भ किया । जुलाई, १९५६ में कच्चे लोहे और मैंगनीज के निर्यात के लिए कुल कोटे का एक-तिहाई निगम को दिया गया । १९५७ में लोहे का सम्पूर्ण कोटा तथा मैंगनीज का आधा कोटा निगम को सौंप दिया गया । इनके इलावा नमक, कच्चे जूट का निर्यात भी इसे सौंप दिया गया और अब वह अनेक वस्तुओं के निर्यात में सलग्न है जिनकी संख्या निरन्तर बढ़ रही है । साम्यवादी देशों से व्यापार करने के कारण निगम के व्यापार में आशा-तीन वृद्धि हुई, किन्तु भारत के कुल निर्यात में १९५६-५७ में निगम का भाग १ प्रतिशत तथा १९५७-५८, १९५८-५९ में ३-४ प्रतिशत था । सरकार ने १९५६ में ही निगम को सीमेन्ट का आयात तथा भारत के रेल-केन्द्रों पर सामान मूल्य पर इसके वितरण का कार्य भी सौंपा था ।

१४. निर्यात-प्रोत्साहन—अगस्त १९५९ में निर्यात-प्रोत्साहन परामर्श-समिति (एक्सपोर्ट प्रमोशन एडवाइजरी काउन्सिल) की भववि समाप्त होने पर इसे पुनः संगठित किया गया तथा इसकी सदस्य-संख्या बढ़ा दी गई । २६ अगस्त, १९५९ को इसकी स्थायी समिति (स्टैंडिंग कमेटी) बनायी गई जो निर्यात को प्रभावित करने वाली दिन-प्रतिदिन की समस्याओं के बारे में सरकार को सलाह देती है । इस समय विभिन्न उद्योगों से सम्बन्धित ग्यारह निर्यात-प्रोत्साहन-समिति (एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल) काम कर रही हैं, यथा सूती और रेशमी वस्त्र उद्योग, लाल, चमड़ा, अभ्रक आदि में ।

नुमाइश, व्यापारिक शिष्टमण्डलों द्वारा भी निर्यात-प्रोत्साहन की दिशा में काम हो रहा है । इटली, जापान, कनाडा तथा आस्ट्रेलिया की नुमाइशों में भारतीय वस्तुओं का प्रदर्शन आयोजित किया जा चुका है । विभिन्न उद्योगों की निर्यात-प्रोत्साहन-समितियों ने व्यापारिक शिष्टमण्डल भी बाहर भेजे हैं ।

उपरोक्त उपायों का फल तो समय बीतने पर ही मिलेगा, किन्तु कुछ लाभ अब भी दिखाई पड़ रहा है । द्वितीय योजना के पहले चार वर्षों में वार्षिक निर्यात का औसत मूल्य ६१० करोड़ रु० था जबकि योजना का अनुमान ५८८ करोड़ रु० ही था ।

तृतीय योजना में विदेशी व्यापार की नीति यही रहेगी—आयात की विफलयत्न तथा निर्यात को उच्चतम स्तर तक पहुँचाना । तृतीय योजना में यह अनुमान

निहित है कि निर्यात में निरन्तर वृद्धि होगी—एक तो उत्पादन की वृद्धि द्वारा रुद्धि-निर्यात (ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट) की वृद्धि तथा दूसरे नई वस्तुओं के निर्यात की वृद्धि । १५. भारत के समुद्र-वाहित व्यापार की विशेषताओं में हुए परिवर्तन—१९४७ तक आयात और निर्यात की प्रमुख वस्तुओं का सापेक्षिक महत्त्व दृष्टिगत रखने पर प्रायः कथित इस सत्य की 'कि भारत के निर्यात का अधिकांश खाद्यान्न तथा कच्चा माल और आयात का अधिकांश निर्मित वस्तुओं का है' पुष्टि होती है ।

भारत के वैदेशिक व्यापार की दूसरी विशेषता यह भी है कि जहाँ आयात वस्तुओं की परिधि काफी विस्तृत है वहाँ उसके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुएँ बहुत थोड़ी हैं, जैसे कपास, जूट, तिलहन तथा खाद्यान्न ।

तीसरी विशेषता यह है कि भारत के विदेशी व्यापार में इंग्लैंड की दशा बहुत महत्त्वपूर्ण स्थिति में है, विशेष रूप से जहाँ तक हमारे आयात का सम्बन्ध है (देखिए, सेक्शन १५-१६) । निर्यात की दृष्टि से, यद्यपि भारत का सबसे महत्त्वपूर्ण ग्राहक ग्रेट ब्रिटेन है, किन्तु कुल व्यापार सम रूप से अनेक देशों में विभाजित है ।

१९५०-५१ के बाद

भारत के विदेशी व्यापार की उपर्युक्त विशेषताएँ १९४७ से पूर्व काल की हैं । स्वतन्त्रता के पश्चात् विशेषकर १९५१ के बाद से हमारे विदेशी व्यापार की विशेषताओं में परिवर्तन हो गया । १९५१ के बाद भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताओं में हुए परिवर्तन इस प्रकार हैं—

आयात के १९५०-५१ के आँकड़ों की तुलना १९५५-५६ के आँकड़ों से करन पर पता चलता है कि प्राथमिकता का कम लोहे और इस्पात, खाद्यान्न, तेल, रसायन और धातुओं के बीच बदल गया है तथा मशीन सदैव चोटी पर रही है ।

अब भारत के विदेशी व्यापार में यू० के० और यू० एस० ए० महत्त्वपूर्ण हो गए हैं । यू० के० (इंगलिस्तान) का भाग तो घट रहा है । इन दो देशों के अलावा इधर हाल में रूस और जर्मनी भी महत्त्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि उद्योगीकरण की आवश्यकताएँ इनके द्वारा पूर्ण की जा रही हैं ।

हमारे विदेशी व्यापार की एक अन्य विशेषता द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते हैं । इनका उद्देश्य आवश्यक पदार्थों को सुलभ करनेसी (सोफ्ट करेन्सी) क्षेत्रों से आवश्यक सामान प्राप्त करना तथा भारतीय सामान के निर्यात को प्रोत्साहित करना है ।

राजकीय व्यापार की बढ़ती हुई महत्ता विदेशी व्यापार की ऐसी विशेषता है जिसकी तुलना अन्यत्र सरलता से नहीं की जा सकती । राजकीय व्यापार निगम का उद्देश्य अन्य बातों के अलावा साम्यवादी देशों के साथ व्यापार की वृद्धि करना है ।

१६ व्यापार की रचना में हाल में हुए परिवर्तन—१९३६-४५ के युद्ध-पूर्व कच्चे माल का निर्यात अग्रगण्य था । अब उनका स्थान निर्मित वस्तुओं ने ले लिया ।

युद्ध-काल में कच्चे माल के निर्यात में जो कमी हुई उसका कारण यह नहीं था कि देश के बढ़ते हुए उद्योगों में इनका उपभोग होने लगा था । इसका वास्तविक

में ५८% हो गया।

निर्यात व्यापार में भी ग्रेट ब्रिटेन से दूर हटने की प्रवृत्ति के दर्शन हुए। सताब्दी के प्रारम्भ में भारत के निर्यात का २६% इंग्लैण्ड, २५% शेष यूरोप, २४% सुदूर पूर्व, ७% संयुक्त राज्य तथा १५% अन्य देशों में वितरित था। १६१४ में इंगलिस्तान का हिस्सा घटकर २४%, शेष यूरोप का बढ़कर २६%, सुदूर-पूर्व का केवल १७% (अफीम और सूत का निर्यात घटने के कारण), संयुक्त राज्य का बढ़कर ६% तथा अन्य देशों का २१% हो गया। इससे स्पष्ट हो गया कि व्यापार का जो भाग इंगलिस्तान ने खोया वह महाद्वीपीय यूरोप ने प्राप्त किया।

१६ युद्धकाल (१६१४-१८) में भारत के व्यापार का वितरण—इस काल में इंग्लैण्ड से दूर हटने वाली प्रवृत्तियाँ तो त्रियाशील रही ही, साथ ही उसके युद्ध में व्यस्त हो जाने व कारण वे और भी तीव्र ही गईं, क्योंकि गृह-सरकार ने निर्यात को प्रतिबन्धित कर दिया था तथा कीमतें भी काफी ऊँची हो गई थीं। अतः इंग्लैण्ड भारतीय बाजार में स्थान खोता गया। भारत के आयात-व्यापार में उसका हिस्सा ६४१% से घटकर १६१८-१९ में ४५५% हो गया। सम्पूर्ण युद्धकाल को दृष्टिगत रखन पर, उसका हिस्सा युद्ध-पूर्व औसत ६२८% से घटकर युद्धकाल में औसतन ५६५% रह गया। इससे तथा भारतीय बाजारों में जर्मनी के स्थान रिक्त करने से जो कमी हुई उसकी पूर्ति जापान और संयुक्त राज्य ने की। अथ लोहा, इस्पात और कितने ही ऐसे सामान इन देशों से भेजाए जाने लगे। जापान से शीशे के बरतन, कपड़ा तथा कागज और संयुक्त राज्य से रंग सामग्री आने लगी।

जहाँ तक निर्यात का प्रश्न है, युद्धकालीन क्रय तथा निष्पक्ष एवं शत्रु-देशों को निर्यात करने पर लगे प्रतिबन्धों के कारण, कुछ समय के लिए इंगलिस्तान और ब्रिटिश कामनवेल्थ के साथ व्यापार बढ़ा। इसका कारण यह था कि भिन्नराष्ट्र होने से इनको लाभदायक स्थिति प्राप्त हो गई थी। इसके अतिरिक्त ये युद्ध के अखाडों से काफी दूर भी थे। इनका निर्यात भी भारत के साथ पर्याप्त मात्रा में था और इन्होंने भारत के साथ अपने सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयत्न भी किये। इसके अलावा अन्यत्र औद्योगिक उत्पादन के लिए भारतीय माल की माँग भी घट गई थी। इस प्रकार कुल मिलाकर, भारत को युद्धकाल में अपनी सामग्री एक सीमित बाजार में भेजनी पड़ती थी। यह ठीक है कि इसके लिए उसे युद्ध पूर्व कीमतों से ऊँची कीमतें मिली, किन्तु इनके बदले में उसे आयात पर कहीं अधिक मूल्य चुकाने पड़े।

२०. भारत के विदेशी व्यापार (१६१४-१८) की युद्धोत्तर प्रवृत्तियाँ—युद्धोत्तरकाल में इंग्लैण्ड भारत के आयातों के सम्बन्ध में अज्ञात पूर्वस्थिति स्थापित कर ही रहा था कि फिर ह्रास आरम्भ हो गया। १६३०-३१ और १६३१-३२ में कुछ राजनीतिक कारणों ने इसमें विशेष योग दिया।

भारत के आयात व्यापार में जापान और संयुक्त राज्य को भी थोड़ा-सा स्थान छोड़ना पड़ा। जापान के स्थान छोड़ने का कारण १६२०-२१ का वाणिज्य-सङ्कट था। दोनों देशों के निर्यात को प्रभावित करन वाला अन्य कारण पुराने प्रति-

द्विद्वियों का आगमन और पुरानी होड़ का प्रारम्भ था। जापान ने १८३६-३७ तक जो हिस्सा बढ़ाया था वह १९३७-३८ में घटने लगा। इसका प्रधान कारण चीन-जापान का युद्ध था। युद्धोत्तर-काल में, विशेष रूप से १९२२-२३ में, जर्मनी आश्चर्यजनक शीघ्रता से अपनी पूर्वस्थिति स्थापित करने लगा।

निर्यात-पक्ष में इगलिस्तान से दूर हटने की प्रवृत्ति और भी निश्चित रूप से काम कर रही थी। यह उसके युद्धोत्तर औसत में स्पष्ट रूप से लक्षित होती है, जो कि घटकर २४.२% हो गया जबकि युद्ध काल का औसत ३१.१% था। धीरे-धीरे फिर वृद्धि होने लगी, जो १९२८ में पर्याप्त रूप से दृष्टिगोचर होने लगी और १९२८-२९ में २१.४% से बढ़कर १९३६-३७ में ३४.३% हो गई। वस्तुतः इगलिस्तान का निर्यात आयात से बढ़ गया और अनुकूल व्यापारिक सन्तुलन १८ करोड़ रुपये हो गया। निर्यात व्यापार में जापान की दशा में भी अपेक्षाकृत सुधार हुआ। उसका हिस्सा ७.२% से बढ़कर १५.७% हो गया (१९३४-३५)। उस देश को कच्ची कपास, घातुएँ, बोरे तथा लाख-जैसी वस्तुएँ अधिकाधिक मात्रा में भेजी गईं। बाद में भारत जापान को कम माल भेजने लगा तथा जापान का व्यापार भी विनिमय नियंत्रण द्वारा नियमित किया जाने लगा। इस प्रकार १९३९-४० में जापान का हिस्सा केवल ६.९ प्रतिशत रह गया।

२१. द्वितीय विश्वयुद्ध और उसके उपरान्त व्यापार की दिशा में परिवर्तन—स्पष्ट कारणों से युद्धकाल में यूरोपीय देशों से व्यापार प्रायः बन्द हो गया। निर्यात वस्तुओं का निर्यात बढ़ा और कच्चे माल का निर्यात घट गया। पहले से ब्रिटेन की कमजोर होती हुई स्थिति इस युद्ध में और भी बिगड़ गई। ब्रिटेन से किये गए आयात का मूल्य १९३८-३९ के ४६.५ करोड़ रु० से घटकर १९४२-४३ में २९.५३ करोड़ रु० हो गया।

१९४५-४६ में हमारा निर्यात २४०,३९ करोड़ रु० का था जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा ५५.५% था। इगलिस्तान का हिस्सा १९३८-३९ में ३४.१% था जो कि १९४५-४६ में घटकर २८.२% रह गया, परन्तु मूल्य ५५,५१ लाख रुपये से बढ़कर ६७,९१ लाख रु० हो गया। अन्य विदेशों में समुक्त राज्य ने हमारे निर्यात की सबसे अधिक मूल्य की सामग्री खरीदी, जिसका मूल्य ६१,६२ लाख रु० था। इसका लगभग आधा मूल्य काजू के कारण था।

२२. भारत का मध्यागार (पुनर्निर्यात) व्यापार—मध्यागार व्यापार देश में आयात की गई सामग्री के पुनर्निर्यात को कहते हैं। जिस देश से पुनर्निर्यात किया जाता है वह केवल विनियम के केन्द्र का काम करता है। अति प्राचीन काल से भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण थोड़ा-बहुत पुनर्निर्यात करता रहा है। सुदूर-पूर्व और पश्चिम के बीच विश्राम-स्थल की स्थिति में होने के कारण यह पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों के केन्द्र का काम करता रहा। प्राचीन समय में इस प्रकार के व्यापार की मुख्य सामग्री के रूप में चीन से रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, लकड़ा से मोती, पूर्वी द्वीप-समूहों से मसाले और कीमती पत्थर मंगाए जाते थे, जो पश्चिमी देशों को भेजे (पुनर्निर्यात किये) जाते थे तथा वेनिस के ओर्से तथा अन्य इसी प्रकार की सामग्रियाँ पश्चिम

से मंगाकर पूर्वी देशों को भेजी जाती थी।^१ इधर हाल में भी भारत के पुनर्निर्यात व्यापार में कुछ वृद्धि दिखाई पड़ी। १९२०-२१ के बाद से यह व्यापार क्रमशः घटने लगा। १९३३-३४ में पुनर्निर्यात व्यापार की दशा कुछ सुधरी और १९३२-३३ के ३२२ करोड़ रु० से बढ़कर (जो १९२०-२१ के बाद निम्नतम था) ३.४२ करोड़ रु० हो गया। १९३५-३६ से और विकास हुआ—१९३८-३९ में एक बार घटने के बाद १९४०-४१ और १९४१-४२ में फिर क्रमशः बढ़ता हुआ यह ११.८१ करोड़ रु० और १५.३३ करोड़ रु० हो गया। प्रमुख देशों के हिस्से इस प्रकार रहे—(१९४१-४२) संयुक्त राज्य ८%, बर्मा ८%, अदन तथा अन्य आश्रित देश ६%, और अरब ५%, एंग्लो मिस्त्री सूडान, ईराक और मिस्र ४%, लका ३%। पुनर्निर्यात व्यापार का अधिकांश सिन्ध और बम्बई से होकर गुजरता था, जो क्रमशः ४५% और ४३% व्यापार के लिए उत्तरदायी थे। इसके बाद बंगाल का स्थान था जिसके द्वारा व्यापार होता था। १९५१-५२ में भारत के पुनर्निर्यात का कुल मूल्य १३,७५,७४,००० रु० था। १९५६-५७ में पुनर्निर्यात का मूल्य ५,४९,६८,००० रु० था।^२

पुनर्निर्यात व्यापार प्रधानतया सूती कपड़ों-जैसी निर्मित वस्तुओं का है, जो पश्चिमी देशों से मंगाई जाती हैं तथा जिन्हें ईरान, मुस्कात और पूर्वी अफ्रीका खरीदते हैं। पश्चिमी देशों को निर्यात की जाने वाली प्रधान सामग्री कच्चा चमड़ा और ऊन हैं। ईरान से प्राप्त होने वाला थोड़ा-सा समुद्र भी बम्बई से बाहर भेजा जाता है। वही से पहले बहरीन और मुस्कात से आयात किये हुए मोती भी बाहर भेजे जाते थे।

यह ठीक है कि भारत उन एशियायी देशों के लिए जिनके पास अपने बन्दरगाह नहीं हैं, पुनर्निर्यात का यत्किञ्चित् काम करता रहेगा, किन्तु वर्तमानकालीन प्रत्यक्ष व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने की प्रवृत्ति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि पुनर्निर्यात व्यापार में भारत का भविष्य बहुत उज्ज्वल नहीं है।

२३ व्यापारिक सन्तुलन—इंग्लैण्ड के स्वर्णप्रमाण त्यागने के वर्ष (१९३१) से दिसम्बर १९३९ तक भारत से निर्यात किये जाने वाले स्वर्ण की कुल कीमत ३५१.४० करोड़ रु० थी। स्वर्ण के निर्यात ने निस्सारण (ड्रेन) की समस्या को जन्म दिया। स्वर्गीय श्री रानाडे तथा अन्य लेखकों ने इस आधार पर इसकी कटु आलोचना की कि यह अंग्रेजी सरकार के अपव्यय का परिणाम था।

व्यापारिक सन्तुलन की दृष्टि से द्वितीय विश्वयुद्ध के समय १९३९-४० में स्थिति फिर सुधरी। १९४१-४२ में जमा-बाकी १०७.९ करोड़ रु० तथा १९४२-४३ में ९१.९४ करोड़ रु० रही। यद्यपि भारत में इंग्लैण्ड की सरकार द्वारा किये गए ऋणों की गणना नहीं करती, अतः यह समझना चाहिये कि वास्तविक जमा-बाकी इनमें अधिक थी। अनुकूल व्यापारिक सन्तुलन १९४३-४४ में ८६.१७ करोड़ रु० और १९४४-४५ में ५०.६५ करोड़ रु० था। १९४५-४६ में असाकृत स्वतन्त्र आयात नीति के परिणामस्वरूप व्यापारिक सन्तुलन प्रतिकूल रहा। व्यापारिक सन्तुलन दूसरे

१. दक्षिण, ८० नी शब्द 'ट्रेड, ट्रेफिस्त एण्ड ट्रान्सपोर्ट इन इण्डिया', पृ० ९२।

२. देखिए, रेगिरीकम एन्ड्रेवेट, १९५६-५७, पृ० ७७०।

वर्ष फिर ४१ करोड़ रु० से अनुकूल हो गया। मार्च, १९४६ में समाप्त होने वाले वर्ष में आयात मूल्य ५१८ करोड़ रु० और निर्यात-मूल्य ४२३ करोड़ रु० था। इस ६५ करोड़ रु० के अन्तर में पाकिस्तान का प्रतिकूल व्यापारिक सन्तुलन शामिल नहीं है। आयात-संख्याएँ भी निम्नानुमान ही हैं, क्योंकि उनका उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है। सितम्बर, १९४६ में रुपये के अवमूल्यन के कारण निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया तथा आयात पर कठोर प्रतिबन्ध लग गए हैं। इससे व्यापारिक घाटे की समस्या नियन्त्रण में आ गई है। भारत सरकार की बाढ़ की नीति प्रधानतया लेन-देन की बाकी (बैलेंस ऑफ पेमेंट) की प्रवृत्ति से अनुशासित हुई है। पहले तो समस्या यह थी कि आयात को इस प्रकार नियंत्रित किया जाए कि लेन-देन की बाकी की कमी को समझौते द्वारा एक वर्ष में दिये जाने वाले पौड-पावने से अधिक होने से रोका जाए। इस दृष्टि से आयात को एक निश्चित सीमा के अन्दर रखना आवश्यक था। किन्तु मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को कम करने के लिए आयातों के साथ उदार नीति बरतने की भी आवश्यकता थी, अतएव १९४८ के उत्तरार्द्ध में आयात-नियन्त्रण कुछ ढीला कर दिया गया। इसका दूसरा उद्देश्य औद्योगिक तथा उपभोक्ताओं की अत्यावश्यक सामग्रियों की कमी को पूर्ति करना भी था। परिणामतः आयात में पर्याप्त वृद्धि हुई। जूट और जूट-निर्मित वस्तुओं की अमरीकी माँग घट जाने के कारण निर्यात में काफी कमी हो गई। इससे जुलाई, १९४८ से जून, १९४९ तक व्यापारिक सन्तुलन अत्यन्त प्रतिकूल हो उठा और पौड-पावने से लगभग ८१० लाख पौड वापस किये गए। अतएव मई, १९४६ में उदार आयात नीति को बदलने के उपाय काम में लाए जाने लगे। घोषण जनरल लाइसेंस ११ नरम मुद्रा क्षेत्र (साफ्ट क्रेन्सी एरिया) के लिए रद्द कर दिया गया। बिना लाइसेंस के नरम मुद्रा क्षेत्र से आयात की जा सकने वाली वस्तुओं की एक सशोधित सूची प्रकाशित की गई (घोषण जनरल लाइसेंस १५)।^१

पिछले दस वर्षों (१९५०-५१) से हमारा व्यापारिक सन्तुलन प्रतिकूल है।^२ द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में भी व्यापारिक सन्तुलन प्रतिकूल रहा है, जैसा कि नीचे दी हुई तालिका से प्रतीत होता है :

द्वितीय योजनाकाल में व्यापारिक सन्तुलन
(करोड़ रु० में) (ट्रेड बैलेंस)

	१९५६-५७	५७-५८	५८-५९	५९-६०	६४-६५
	प्रथम अर्द्ध वर्ष				
आयात	१०६६.५	१२०४.२	१०४६.२	४७३.१	१२७०.३६
निर्यात	६३५.२	५६४.७	५७६.१	२७२.६	८१३.२६
व्यापारिक सन्तुलन	४६४.३	६०९.५	४७०.४	२००.५	४८७.२८

१. देखिये, इन्डियन ईअर बुक, १९४६, पृ० ३३१-३२।

२. देखिये, 'इण्डियन फारेन ट्रेड इन द कन्टेन्ट ऑफ इकनामिक डेवलपमेन्ट'—जी० एम० कुरावाहा, इण्डियन जनरल ऑफ इकनामिक्स, जुलाई ५६।

द्वितीय योजनाकाल में आयात और निर्यात-सम्बन्धी अनुमान गलत सिद्ध हुए। निर्यात की अपेक्षा आयात-सम्बन्धी अनुमानों में अधिक गलती हुई। अतएव योजना में काट-छाँट आवश्यक हो गई। इस स्थिति के लिए मुख्यतः खाद्य-सम्बन्धी कठिनाई तथा विकास-सम्बन्धी आवश्यकताएँ ही उत्तरदायी हैं, किन्तु कुछ अन्य कारण, जैसे स्वेड का मकड़, व्यापारिक नीति को कार्यान्वित करने में प्रशासकीय कठिनाई आदि का भी हाथ है।

२४ भारत के स्थिति विवरण पत्रक (बैलेंस शीट) में नामे और जमा की-मदों—एक समुचित लेन-देन के लेखों में आयात और निर्यात में बिलकुल ठीक-ठीक गन्तुलन होगा। इस बात की स्पष्ट रूप से पूर्णता हो जाएगी, यदि हम केवल दृश्यमान लेन-देन (जैसे आयात-निर्यात-कर के विवरण में सम्मिलित तथा प्रकाशित आंकड़ों में सम्मिलित मद) को ही न देखकर महसूस मदों को भी ध्यान में रखें। महसूस मद वे हैं जिनका कस्टम या अन्य प्रकाशित आंकड़ों में विवरण नहीं होता।

इसका कारण यह है कि सौदों का आयात अधिक होगा और निर्यात कम। हमारे, विकास हेतु लिये गए ऋणों व उनके व्याज की अदायगी तथा विदेश-भ्रमण के मद को खर्च बढ़ाने वाली राशि है। विदेशी ऋणों की सहायता से देश में आयात उद्योगों की स्थापना के बाद निर्यात में वृद्धि होत तथा ऋण और व्याज की अदायगी बन्द होने के पश्चात् सम्भव परिस्थिति बदल जाएगी, किन्तु इसमें समय लगेगा।

२५ देश का (भौतिक) सीमान्त व्यापार—भारत की भूमि-सीमा २००० मील लम्बी है। पश्चिमोत्तर और उत्तर-पूर्व तक फैली यह सीमा-रेखा उसकी तटीय रेखा से अधिक लम्बी है, किन्तु घन, अनेक जंगलों और दुर्गम पहाड़ों के कारण व्यापार में अनेक बाधाएँ पड़ती हैं। दरों की कमी के कारण सीमाप्रान्त देशों में मत्तार कठिन था। हम भारत की पुराने भूमि के स्वभाव और व्यापार की ओर निर्देश कर चुके हैं। मुगल काल में विदेशी व्यापार काफ़ी जोर से चल रहा था।

स्वतन्त्रता के पश्चात् १९४७ में भारत के सीमा व्यापारों में एक मुख्य परिवर्तन हुआ। अफगानिस्तान और ईरान के साथ पाकिस्तान भी इस व्यापार का अंग बन गया। सीमा के निकटवर्ती स्थानों से तिब्बत, नेपाल, सिक्किम और भूटान से अब भी व्यापार होता है।

पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से मुख्यतः कच्चा जूट, कच्ची कपास, चमड़ा और ताम्र, फल और तरकारियाँ, नमक आदि का आयात तथा काँचला और चोक, सूती कपड़े, रेशम की धनी वस्तुएँ, मसाले, चाय आदि का निर्यात होता है। तिब्बत, नेपाल, सिक्किम और भूटान को तूत और सूती कपड़े, रजक पदार्थ, लोहे और इस्पात का सामान, चीनी, चाय आदि का निर्यात तथा जानवरों की छालें, तम्बाकू, कच्ची लून, निलहन आदि का आयात होता है।

२६ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक समृद्धि—भारत के व्यापार का आकार इतना अधिक है कि उसे विश्व के देशों में पाँचवाँ स्थान प्राप्त है।^१ निकट भूतकाल में भारत

१. अर्थ व्यक्ति व्यापार में भारत लगभग छठे स्थान पर है। स्वतन्त्रता के बाद इसकी जनसंख्या बढ़ने के कारण

की व्यापारिक वृद्धि को, जो रेलवे-प्रसार तथा सामुद्रिक सुविधाओं का परिणाम है, देश की औद्योगिक प्रमुखता का चिह्न न मानना चाहिए वरन् उसका प्रथम आवश्यक चरण मानना चाहिए ।^१

अदायगी शेष तथा निर्यात उन्नति के साधन—विदेशी सहायता के बहुत अधिक हो जाने पर भी अदायगी शेष खराब होती गई । रिजर्व बैंक के पास विदेशी मुद्रा का भण्डार ७८५ करोड़ रुपये तक रह गया और दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह गिरकर १८६ करोड़ रुपये रह गया । तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में अदायगी शेष की स्थिति और भी खराब रही यद्यपि हमने अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से १३१ करोड़ रुपया लिया । १९६३-६४ में कुछ हालत सुधरी, क्योंकि निर्यात १२० करोड़ रुपया बढ़ा और आयात १२९ करोड़ रुपया । विदेशी सहायता २२०० करोड़ रुपये के लगभग ली गई । इसके लेने के बाद भी १९६५-६६ में अदायगी शेष की हालत खराब रही । ऐसी स्थिति वाली अन्न तथा अन्य वस्तुओं के आयात होने के कारण हुई ।

तीसरी योजना में व्यापारिक नीति का सबसे बड़ा लक्ष्य योजना को सफल बनाना था । इसके लिए निर्यात को बढ़ाना, जिससे विदेशी पूंजी बर्माई जा सके, तथा निर्यात वस्तुओं के बनाने वाली फर्मों को सुविधाएँ देना था । आयात वस्तुओं और बच्चे माल की जगह स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन करना, जिससे आयात की मात्रा कम हो सके । जहाँ तक हो सके कम आवश्यकता वाली वस्तुओं का आयात बन्द किया जाए और दुर्लभ वस्तुओं का वितरण बराबर मात्रा में हो ।

तीसरी योजना में निर्यात का लक्ष्य ७४० से ७६० वार्षिक रखा गया और इसकी पूर्ति के लिए उत्पादन को प्रोत्साहन देना, यातायात के अच्छे साधन और वस्तुओं को अच्छी कोटि का बनाना था । मई १९६२ में बोर्ड ऑफ ट्रेड (Board of Trade) की स्थापना हुई । इस बोर्ड ने अनेक समितियाँ तथा स्वदेशी वस्तुओं को सर्वप्रिय बनाने का प्रयत्न किया है । अब तक १८ के लगभग समितियाँ बना दी गई हैं जिससे वस्तुओं का निर्यात बढ़ सके । इन वस्तुओं को सर्वप्रिय बनाने के लिए बोर्ड बनाये गए हैं । इस प्रकार हैंडीक्राफ्ट तथा हाथकरघा निर्यात कारपोरेशन (Handicrafts and Handloom Export Corporation) और इंडियन चलचित्र कारपोरेशन (Indian Motion Pictures Export Corporation) देश के निर्यात को उस्ताह देने में लगी है । एक निर्यात निरीक्षण सलाहकार कौंसिल (Export Inspection Advisory Council) अगस्त १९६४ में सूती कपड़े के निर्यात को बढ़ाने के लिए सूती कपड़ा उद्योग की कमेटी बनाई गई । निर्यात के लिए साख की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक

में प्रति व्यक्ति व्यापारिक वृद्धि में दृश्यमान परिवर्तन होने के लिए यह आवश्यक है कि उसका व्यापार बहुत अधिक मात्रा में बढ़े । यह देखा जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है ।

२. देखिए, खण्ड १, अध्याय ५, शकनामिक ट्रांजीशन इन इंडिया ।

तथा स्टेट बैंक सचिवालय को परिवर्तित किया गया। एक निर्यात साख और गारन्टी कारपोरेशन भी बनाई गई है। एक डाइरेक्टोरेट ऑफ एक्जीबीशन (Directorate of Exhibition) तथा इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड देश के निर्यात को बढ़ाने में जुटे हुए हैं।

इन सबके बाद भी भ्रदायगी शेष की हालत खराब है। देश की वस्तुओं का निर्यात चौथी पंचवर्षीय योजना में कुल ५१०० करोड़ रुपये होगा। इसके मुकाबले में वस्तुओं का आयात पाँच वर्षों में पी० एल० ४८० के आयात को छोड़कर ७२०० करोड़ रुपये का होगा। इस प्रकार वस्तुओं के लेखे में घाटा रिक्त (Deficit) २१०० करोड़ रुपये होगा। ऋण व्याज तथा सिद्धान्त की भ्रदायगी पर ११०० करोड़ रुपया देना होगा। इस प्रकार भ्रदायगी शेष की समस्या को दूर करने के लिए ३२०० करोड़ रुपये की विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी।

आन्तरिक व्यापार

२७. (१) तटीय व्यापार—भारतीय तटीय व्यापार को भारतीय जलयानों के लिए सुरक्षित करने के सम्बन्ध में हम उसकी (तटीय व्यापार की) वर्तमान स्थिति और भावी महत्ता देख आए हैं। तटीय व्यापार को देश के आन्तरिक व्यापार का अग्र मानना चाहिए, यद्यपि इसमें थोड़ा सा विदेशी व्यापार भी शामिल है।

सांख्यिकीय सामग्री एकत्रित करने के लिए भारतीय तट को अप्रैल १९५७ से निम्नलिखित ६ क्षेत्रों में बाँटा गया है—(१) पश्चिमी बंगाल, (२) उड़ीसा, (३) आन्ध्र प्रदेश, (४) मद्रास, (५) केरल, (६) मैसूर, (७) बम्बई, (८) अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह तथा (९) लका द्वीप, मिनिक्वाय और अमिनदिवी द्वीपसमूह। १९५६-५७ में तटीय व्यापार का कुल मूल्य ३४३ करोड़ रु० था। इसमें १८० करोड़ रु० का आयात और १६३ करोड़ रु० का निर्यात शामिल था। आयात में १६९ करोड़ रु० से अधिक का व्यापार विभिन्न क्षेत्रों के बीच तथा १० करोड़ रु० का क्षेत्र के अन्दर व्यापार शामिल था। १९५७-५८ (अप्रैल दिसम्बर) में तटीय व्यापार के आयात-निर्यात का मूल्य क्रमशः ११४,१८ लाख रु० तथा १२३,०७ लाख रु० था तथा तटीय व्यापार का कुल मूल्य २३७,२५ लाख रु० था।

भारत के तटीय व्यापार को पूरी तरह विकसित करने के लिए बन्दरगाहों का विकास की विस्तृत योजना, भारतीय व्यापारिक जहाजदानी का निर्माण और तटीय तथा रेल के यातायात का समुचित संयोजन आवश्यक है। लेकिन इस विषय पर हम विस्तृत रूप से प्रकाश डाल आए हैं।^१

२८. (२) आन्तरिक व्यापार—देश के आर्थिक विकास एवं संगठन के साथ ही आन्तरिक व्यापार भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि इससे देश के गाँवों और नगरों में सम्पर्क और भी घनिष्ठ हो जाएगा।

यह सच है कि नियति के बाढ़ जो बच जाता है वह सब विक्रय के लिए नहीं होता, क्योंकि उत्पादन का एक हिस्सा स्वयं उत्पादको द्वारा उपयुक्त होता है। उदाहरणार्थ, किसान अपने द्वारा उत्पन्न खाद्य-सामग्री के एक बड़े भाग का स्वयं उपभोग करते हैं। भारत के आन्तरिक व्यापार का महत्त्वकान इस बात से हो सकता है, "प्रत्येक १ एकड़ जमीन—जिससे उत्पन्न अन्न, तिलहन, कपास और चाय का निर्यात होता है—की तुलना में ११ एकड़ जमीन से उत्पादित सामग्री स्थानीय उत्पादको द्वारा उपभुक्त होती है।" उत्पादको द्वारा उपभुक्त इस कृषि-उत्पादन के साथ ही खनिज पदार्थों-जैसी सामग्रियों को, जिनका अल्पांश ही बाहर भेजा जाता है, ध्यान में रखना होगा।

विश्वसनीय आँकड़ों के अभाव में भारत के आन्तरिक व्यापार के आकार की कोई निश्चित रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की जा सकती और न विदेशी व्यापार से तुलना ही की जा सकती है। १९२०-२१ के 'इनलैंड ट्रेड ऑफ इण्डिया' के आधार पर इसका मूल्य लगभग १५०० करोड़ रु० आँका गया। इस प्रकार बाह्य और आन्तरिक व्यापार में १ २½ का अनुपात स्थापित किया जा सका।

राष्ट्रीय नियोजन समिति (नेशनल प्लानिंग कमेटी) की व्यापार-सम्बन्धी उप-समिति के अनुमान के अनुसार १९४० में देश के आन्तरिक व्यापार का मूल्य ७००० करोड़ रु० के लगभग था, जबकि बाह्य व्यापार ५०० करोड़ रु० के बराबर था। आन्तरिक व्यापार-सम्बन्धी आँकड़े एकत्रित करने की दृष्टि से भारत को ३६ व्यापारिक क्षेत्रों में बाँटा गया है, जो मोटे तौर पर भारत-सघ के पहले के राज्य तथा बम्बई, कलकत्ता, कोचीन और मद्रास के बन्दरगाहों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं।

जो सख्याएँ प्राप्य हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि देश के आकार और जनसंख्या को देखते हुए आन्तरिक व्यापार की मात्रा कम है।

२६ भारत के प्रधान व्यापारिक केन्द्र—इस सम्बन्ध में पहले तीन प्रमुख बन्दरगाह कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का नाम लिया जा सकता है। कलकत्ता और बम्बई केवल प्रधान बन्दरगाह ही नहीं हैं बल्कि व्यवसाय के भी प्रधान केन्द्र हैं। इसके अतिरिक्त बम्बई पार्श्वदेशों की वस्तुओं का इस देश में प्रधान वितरक भी है। बम्बई का व्यापार प्रधानतया भारतीय हाथों में है, जबकि कलकत्ता का व्यापार अधिकतर पार्श्वदेशों (यूरोपीयों) द्वारा नियन्त्रित है। मद्रास भी एक प्रधान व्यापारिक केन्द्र है, किन्तु इसकी तुलना बम्बई और कलकत्ता से नहीं की जा सकती। इन प्रधान

१. देखिए 'दि इकनामिक रिसोर्सेज आफ दि ब्रिटिश इम्पायर', स० वार्षिक, पृ० १४५।

२. के० टी० शाह के मत में यह एक निम्नानुमान है और यह भारत के आन्तरिक व्यापार का मूल्य २५०० करोड़ रु० आँकते हैं। 'ट्रेड, टेरिफ़्म एण्ड ट्रांसपोर्ट', पृ० १२२।

३. देखिये, सी० डब्ल्यू० ई० वार्दन, 'इण्डियन आर्थ कमिश्नियल इन्फ़ॉर्मेशन फॉर इण्डिया', तृतीय संस्करण, पृ० ६२-११३ तथा खण्ड १, अध्याय २।

४. इन प्रमुख बन्दरगाहों के अतिरिक्त निम्न बन्दरगाह भी महत्वपूर्ण हैं—कोचीन, गोवा, चिडगाव और विन्गापन्नम तथा काठियावाड़ में वेदी, ओखा, पोखन्दर और भावनगर।

बन्दरगाहों के अतिरिक्त दिल्ली, अहमदाबाद, अमृतसर, आगरा, लाहौर, बनारस, कानपुर, लखनऊ और नागपुर भी व्यापार के बड़े केन्द्र हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रधान रेलवे जंक्शन है तथा बम्बई और कलकत्ता के बीच स्थित है। इस प्रकार यह विदेशी और गृह वस्तुओं के वितरण का भी केन्द्र है। दिल्ली, जोकि भारत की राजधानी है, ६ रेलवे लाइनों का जंक्शन है और पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों का विकास-गृह है—विशेषकर सूती, रेशमी और ऊनी कपड़े की वस्तुओं में। बम्बई के बाद अहमदाबाद सबसे प्रधान नगर है। अमृतसर पुनर्निर्वात का ही प्रधान केन्द्र नहीं है, बल्कि यहाँ कपड़े का भी काफी व्यवसाय होता है। यह दरी और कालीनों के लिए भी मशहूर है। आगरा दरी, कालीन, पत्थर का काम और जरी के अतिरिक्त चमड़े के सकलन का भी एक प्रधान स्थान है। पंजाब के कृषि-उत्पादन के व्यापार का प्रधान केन्द्र लाहौर है। बनारस रेशम की बुनाई का केन्द्र है। लखनऊ अरब के कृषि-उत्पादन को एकत्र और वितरित करता है। नागपुर का व्यावसायिक महत्त्व बुनाई, कपास ओटने तथा दवाने की मिलों और फैक्ट्रियों के कारण है तथा यहाँ समीप ही मँगनीज की खानें भी हैं।

३० व्यावसायिक ज्ञान तथा व्यापार-संगठन—व्यापार-आयुक्त विदेशों में नियुक्त किये जाते हैं और दूतों को विदेशों में रखा जाता है, जिनका प्रधान कार्य स्वदेश को विदेशों की व्यापारिक सूचना देना होता है। इन सब बातों से भारत अभी पूर्णतया सज्जित नहीं है। यद्यपि वाणिज्य सूचना विभाग का जन्म १९०५ में ही हो गया था, फिर भी सरकार के पास जनता या व्यक्तियों तक वाणिज्य सूचना प्रसार के लिए कोई माध्यम नहीं था। इस समय स्थिति कुछ अधिक सन्तोषजनक है। १९२२ में पुनर्संगठित वाणिज्य सूचना तथा सांख्यिकीय विभाग भारत सरकार और व्यावसायिक जनता के बीच की कड़ी का काम करता है। इसके दो प्रकार के काम हैं (१) समुद्र-पार व्यापार की वे सूचनाएँ, जो भारतीय व्यापार के लिए हितकर हो सकती हैं, उनका सकलन एवं वितरण, (२) व्यापार और उद्योग आदि से सम्बन्धित अखिल भारतीय महत्त्व के आँकड़ों का एकीकरण और प्रकाशन। इस विभाग से पृथक्-पृथक् जवाब दिया जाता और (विभाग के साप्ताहिक अंग) 'इण्डियन ट्रेड जनरल' प्रकाशित किया जाता था। यह इंग्लैण्ड के उन व्यापारिक विद्वांसों के सम्पर्क में भी रहता है जो भारत के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। इसके लिए विभिन्न देशों में भारतीय व्यापार आयुक्त नियुक्त किये गए हैं। इस विभाग का काम भारत के उद्योग-संचालकों को लक्ष्य तथा अन्य देशों में स्थित भारतीय व्यापार-आयुक्तों, अंग्रेजी व्यापार आयुक्त तथा अन्य देशों के व्यापारिक अफसरों के सहयोग से होता है तथा इसका उद्देश्य समुद्र-पार के वाजारों में भारतीय उत्पादन और निर्माण की माँग को बढ़ाना है। १९२० से नियुक्त लन्दन-स्थित भारत के उच्च आयुक्त को कितने ही विविध वित्तीय काम दे दिये गए हैं, जिनमें से सरकारी भण्डारों की खरीद सबसे महत्त्वपूर्ण

है। अतः वह बाहरी देशों में भारत के वाणिज्य हितों को अधिक प्रोत्साहन देने में असमर्थ है।

ऊपर वर्णन किये गए संगठन का प्रधान काम बाह्य देशों में विदेशी वस्तुओं के लिए भारतीय बाजारों में सम्भावनाओं की सूचना का प्रसार करना है। इस प्रचार को अन्य संगठनों से, जो विदेशी बाजारों में भारतीय वस्तुओं की सम्भावनाओं और माँगों की सूचना दें, पूरा करने की भी आवश्यकता है। भारत सरकार ने टैक्स-टाइल टेरिफ बोर्ड (१९२६) के सुझाव पर विदेशी बाजारों में भारतीय सूती वस्त्रों की माँग का पता लगाने के लिए १९२८ में एक व्यापारिक शिष्ट-मण्डल (ट्रेड मिशन) नियुक्त किया है। इस दिशा में यह पहला कदम था।^१ मिशन की रिपोर्ट में मोम्बासा, अलवजेण्डिया तथा डरबन में तीन व्यापार-प्रायुक्तों की नियुक्ति का सुझाव रखा गया। तब से भारतीय व्यापारिक एजेंसी और दूत सेवाओं की स्थापना हो चुकी है। अफगानिस्तान, इगलिस्तान (यू० के०), आयरलैण्ड, जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील, पाकिस्तान, ईरान, जापान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड कनाडा, न्यूफाउण्डलैण्ड, बर्मा, मिस्र और लका में व्यापार-प्रायुक्त नियुक्त किये जा चुके हैं। अन्य देशों में शीघ्र ही व्यापार-प्रायुक्तों की नियुक्ति की सम्भावना है।

३१. भारत के वाणिज्यिक संगठन—सबसे अच्छे और सुसंगठित गैर-सरकारी व्यावसायिक संगठन यूरोपीय सौदागरों द्वारा बनाये गए। असोसियेटेड चेम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इण्डिया तथा कलकत्ता (१८३४), बम्बई (१८३६), मद्रास (१८३६) और कानपुर तथा अन्य केन्द्रों के वाणिज्य-मण्डल इसके उदाहरण हैं। उनकी सदस्यता अभी हाल तक प्रधानतया यूरोपीयों की थी, यद्यपि यह भारतीयों के लिए भी खुली थी। यह पारम्परिक व्यापारियों का भारत और पश्चिम के बीच व्यापार-सम्बन्ध स्थापित करने का स्वाभाविक परिणाम था। इस समय कितने ही विशुद्ध भारतीय संगठन हैं, जैसे बंगाल राष्ट्रीय वाणिज्य मण्डल (बंगाल नेशनल चेम्बर ऑफ कॉमर्स) (१८८७) जो कि भारतीय व्यावसायिक समुदाय का सबसे पुराना संगठन है, भारतीय व्यापार-मण्डल और कार्यालय (इण्डियन मर्चेंट्स चेम्बर एण्ड ऑफिस) बम्बई (१९०७), दक्षिण भारत वाणिज्य मण्डल (सदर्न इण्डिया चेम्बर ऑफ कॉमर्स) मद्रास (१९०६), भारतीय वाणिज्य-मण्डल (इण्डियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स) लाहौर (१९१२), भारतीय वाणिज्य-मण्डल (इण्डियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स) कलकत्ता (१९२५), महाराष्ट्र वाणिज्य-मण्डल बम्बई (१९२७) तथा यू० पी० व्यापार-मण्डल (१९३२)। एक अखिल भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल सध भी है।^२

इन सबसे भारतीय व्यावसायिक मत को प्रकट करने में बड़ी सहायता प्राप्त हो सकती है तथा व्यापारिक और औद्योगिक विकास से सम्बन्धित समस्याओं पर

१. देखिये, पी.के. २७, और इण्डिया इन १९२८-२९, पृ० १६८।

२. विस्तृत विवरण के लिए देखिये, कॉटन, पूर्वोद्धृत, भाग ४।

सरकार को राय दी जा सकती है। विभिन्न सगठन अपने हितों से सम्बन्धित मन प्रस्तुत करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, फेडरेशन ऑफ इण्डियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री, उद्योगों का मत सरकार के सामने प्रस्तुत करता रहता है। विभिन्न उद्योगों के सगठन इसके सदस्य हैं। पंचवर्षीय योजना, करारोपण तथा सरकार द्वारा की जाने वाली किसी आर्थिक जाँच के सम्बन्ध में उपर्युक्त सस्था उद्योगों का मत भली प्रकार प्रस्तावित और प्रचारित करती रहती है।



व्यापारिक समझौते

१. साम्राज्य अधिमान (इम्पीरियल प्रेकरेस) आन्दोलन का इतिहास— १९०२ में हुए औपनिवेशिक सम्मेलन ने साम्राज्य अधिमान की ऐसी रूपरेखा तैयार की, जो साधारणतया साम्राज्य के हर भाग में लागू होती थी। अतः अधिमान-कर (ग्रेट ब्रिटेन के पक्ष में) न्यूज़ीलैण्ड, साउथ अफ्रीका (१९०३) और बाद में आस्ट्रेलिया द्वारा लगाये गए। आशा की जाती थी कि ग्रेट ब्रिटेन भी इसका प्रतिदान करेगा और उन देशों को अधिमान देगा, लेकिन उस समय इंग्लैण्ड अपनी स्वतन्त्र व्यापार-नीति को छोड़ने के लिए तैयार न था। वह मुख्यतया खाद्यान्न और कच्चे माल का आयात करता था और उसका दृष्टिकोण यह था कि निर्मित वस्तुओं के निर्यात को कायम रखने के लिए आवश्यक है कि वह सबसे सस्ते बाजारों में खाद्यान्न और कच्चा माल खरीदे—विशेष रूप से खाद्यान्न के प्रश्न में वह अपने 'सब अडे साम्राज्य रूपी एक टोकरी में रखने के लिए' किसी भी कीमत पर तैयार न था। इस प्रकार उनके आयात-निर्यात-कर में (१) आगम (रेवेन्यू) कर, (२) संरक्षण-कर और (३) इंगलिस्तान के प्रति एव उसके पक्ष में तथा कभी-कभी भारत तथा साम्राज्य के अन्य देशों के पक्ष में भी करों में दी गई छूट सम्मिलित थी। वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी थी जिसमें उन वस्तुओं का नाम था, जिन पर साम्राज्य के बाहर से आने पर ही कर लगता था। साधारणतः अधिमान का उद्देश्य ब्रिटेन को लाभान्वित करने का रहा है और साम्राज्य के अन्य देशों से इस विषय पर अलग समझौते करने होते थे। १९१५ से इंग्लैण्ड ने संरक्षण की ओर कदम उठाए तथा साम्राज्य-उत्पादित कुछ वस्तुओं को अधिमान देने लगा। किन्तु कर-सम्बन्धी यह अधिमान कुछ वस्तुओं तक ही सीमित था। १९३२ (मार्च) में आयात-कर अधिनियम (इम्पोर्टेड इयूटीज एक्ट) पास होने पर ब्रिटेन ने स्वतन्त्र व्यापार-नीति को औपचारिक रूप से त्याग दिया। साम्राज्य अधिमान की दृष्टि से यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना थी।

२. साम्राज्य अधिमान के प्रति भारत का दख—साम्राज्य अधिमान को अपनाने में भारत की अनिच्छा अशक्त राजनीतिक कारणों के फलस्वरूप थी।

निम्न कारणों से साम्राज्य अधिमान से भारत को कोई आर्थिक लाभ भी नहीं था—

(१) भारत का निर्यात प्रधानतया खाद्यान्न और कच्चे माल तथा आयात निर्मित वस्तुओं का था। (२) १९१४ के युद्ध के पूर्व उसके सम्पूर्ण आयात का दो-तिहाई ब्रिटिश साम्राज्य से आता था, जिसमें सबसे बड़ा भाग इंगलिस्तान का था।

(३) १९१४-१८ के युद्ध के पहले भारतीय निर्यात के ४०% की खपत ब्रिटिश साम्राज्य में होती थी, शेष (अधिकार) अन्य देशों को भेजा जाता था। कुल निर्यात का २५% केवल इंग्लिस्तान को ही भेजा जाता था। (४) प्रथम विश्व-युद्ध के उपरान्त आयात-निर्यात दोनों में ही, परन्तु मुख्यतया आयात में ब्रिटेन और अन्य कॉमन-वेल्थ देशों का महत्त्व घटता गया।

१९०३ में भारत सरकार ने यह मत प्रकट किया कि "आर्थिक दृष्टि से साम्राज्य को भारत से बहुत थोड़ा लाभ हो सकता है तथा इसके बदले में भारत को कम या कुछ भी लाभ नहीं होगा और बहुत-कुछ खोने की सम्भावना है।"

३. ओटावा-समझौता—जुलाई और अगस्त, १९३२ में ओटावा में हुए साम्राज्य आर्थिक सम्मेलन में साम्राज्य के देशों में पारस्परिक अधिमान के आधार पर कई व्यापारिक समझौते हुए। भारत ने भी साम्राज्य अधिमान की इस विस्तृत योजना में भाग लिया, जिसके प्रति वह बड़ा विरोध प्रकट कर चुका था। भारतीय आयात-निर्यात-कर (ओटावा व्यापारिक समझौता) सशोधन अधिनियम (दिसम्बर, १९३२) ने २० अगस्त, १९३२ में भारत और इंग्लैण्ड के बीच हुए साधारण व्यापारिक समझौते के अन्तर्गत आयात-निर्यात-कर सम्बन्धी आवश्यक परिवर्तनों को लागू किया। कर-सम्बन्धी ये परिवर्तन १ जनवरी, १९३३ से लागू किये गए। लोह और इस्पात के सम्बन्ध में एक पूरक समझौता २२ सितम्बर, १९३३ को किया गया।

४. ओटावा समझौता पक्ष—१९२६ में प्रारम्भ होने वाले आर्थिक संकट की प्रथम दशा में सभी मूल्यों में भारी कमी हुई, लेकिन यह सापक्षिक कमी कच्चे माल के सम्बन्ध में अधिक थी।

अन्य देशों में भी उत्पादन बंद रहा था—विदेशी निर्यातक, जो १९१४-१८ के युद्ध के पहले अपेक्षाकृत नगण्य थे, अब सबल प्रतिद्वन्द्वी सिद्ध हो रहे थे। हमारे निर्यात की कुछ प्रधान वस्तुओं में भी प्रतिद्वन्द्विता का अनुभव किया, जैसे तिलहन, कपास, साद्यान्, लकड़ी इत्यादि। कितने ही यूरोपियन देशों तथा संयुक्त राज्य द्वारा उष्ण और अर्ध-उष्ण देशों में अपने उपनिवेशों की उत्पत्ति की मांग बढान की नीति का अनुसरण करने से स्थिति और विपन्न हो गई। एक अन्य कारण सरलित विकल्पों (सिन्थेटिक सविस्ट्र्यूट्स) का शीघ्र विकास था। इनसे भारत के निर्यात की कुछ प्रमुख वस्तुओं की मांग घट गई। इसके अनिरीक्त कितने ही देशों ने 'आर्थिक एकात्म-वाद' (इकनॉमिक आइसोलेशन) की नीति का अनुसरण किया और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के स्वतन्त्र प्रवाह पर आयात-निर्यात कर, विदेशी विनिमय कर, कठोर नियन्त्रण एवं अन्य अनेक प्रतिबन्ध लगाए तथा कर्णिकेण्ट और कोटा सिस्टम को अपनाया।

१. १९२३ में भारत के प्रतिनिधियों द्वारा साम्राज्य आर्थिक सम्मेलन के संभव यह नव पुनः दुहराया गया।

२. दिसम्बर, अक्टूबर १०, सेब्रान ४, ब्रिटेन के लिए साम्राज्यक अधिमान-कर भारत लोहा-इस्पात पैन्ना की सुरक्षा के लिए स्वीकार किये गए। देखिये, अध्याय २, सेब्रान ११ और २५।

इसी बीच (सितम्बर, १९३१) ग्रेट ब्रिटेन ने स्वर्ण-प्रमाण का परित्याग कर दिया। इससे भारत तथा साम्राज्य के प्राय सभी देश षोण्ड से सम्बद्ध हो गए। ऊपर बताये गए आयात कर अधिनियम (१९३२) के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन में कितनी ही वस्तुओं—कुल आयात का लगभग ३ भाग—पर कर लगा दिया गया, यद्यपि साम्राज्य की वस्तुओं को इस कर से मुक्ति देने की व्यवस्था की गई थी। शर्त यह थी कि वे देश (डोमिनियम और भारत) ब्रिटेन से समझौता कर लें। इन सबका अन्त ओटावा समझौता के रूप में हुआ। फ्रांस और जर्मनी जैसे अन्य देश मुद्रा-सम्बन्धी कठिनाइयों से ग्रस्त थे। स्टालिन समूह के देश अग्रेसर इन्हें कठिनाइयों से मुक्त थे। अतः इनसे व्यापार के सुव्यवस्थित और अबाध गति से चलते रहने की सम्भावना थी।

१९३१ से १९३४ के बीच अधिमान-सूची की कुल वस्तुओं का आयात इंग्लिस्तात में २२ प्रतिशत घट गया। इस संकुचित होने वाले बाजार में भारत के आयात में वृद्धि हुई। अतः यह निष्कर्ष स्वाभाविक ही था कि इसमें साम्राज्य अधिमान का हाथ अवश्य रहा होगा। गैर-अधिनिर्णय वाली वस्तुओं के निर्यात में प्रसार होना अधिक आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि इन वस्तुओं को कोई कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता था। यही कारण था कि इन्हे अधिमान-सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था। गैर-अधिनिर्णय समूह की वस्तुओं में कुछ और भी अनुकूल प्रभाव क्रियाशील थे, जिनसे इनकी माँग बढ़ गई। उदाहरणार्थ, कपास की माँग की वृद्धि अधिकांशतः लकाशायर की भारतीय कपास समिति के प्रचार के कारण थी। रबर में होने वाली वृद्धि का कारण प्रतिबन्ध योजना थी। धातुओं की माँग की वृद्धि भारी उद्योगों की बढ़ती हुई क्रियाशीलता के कारण थी। लाख की माँग की वृद्धि के कारण लदन गुट (रिंग) के परिकल्पनात्मक (स्पेकुलेटिव) क्रय थे।

समझौते के अलोचकों का यह तर्क, कि इंग्लिस्तात से हमारे निर्यात-व्यापार की वृद्धि व्यापार के प्रवाह-परिवर्तन के कारण थी, इस विपरीत तर्क से कट जाता है कि इंग्लिस्तात को किये जाने वाले निर्यात की वृद्धि ओटावा समझौते के कारण मानी जा सकती है। परन्तु अन्य देशों को होने वाले निर्यात की कमी का तो ओटावा समझौते से कोई सम्बन्ध नहीं था, क्योंकि इसका कारण तो उन देशों द्वारा अपनाई गई आत्म-निर्भरता की नीति थी। वास्तव में इस प्रतिबन्धात्मक नीति के फलस्वरूप हुई व्यापार की हानि, जिसे भारत और इंग्लैंड दोनों ही ने उठाया, ओटावा समझौते के समर्थन का प्रमुख आधार है। इसमें सन्देह नहीं कि तब तक भारत अपने दो-तिहाई निर्यात ब्रिटिश साम्राज्य से बाहर ही बेचता था, परन्तु विदेशी बाजारों पर अधिकार बनाए रखना उसके लिए कठिन होता जा रहा था। अतएव अधिमान-वृद्धि आत्म-रक्षा के रूप में भारत द्वारा अपनाई गई। ओटावा समझौता के विरुद्ध एक यह भी तर्क दिया जाता था कि इससे भारत के विदेशी ग्राहक उससे बदला लेना शुरू कर देंगे। परन्तु विदेशों द्वारा लगाये गए व्यापारिक प्रतिबन्ध केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि सभी देशों के लिए थे। व्यापार की ये नवीन नीतियाँ नये उद्देश्यों से प्रेरित थी और इन्हें कितनी भी हालत में ओटावा समझौते की विरोधी प्रतिक्रिया नहीं कहा

जा सकता ।

५. ओटावा समझौता विपक्ष—विरोधियों ने ओटावा समझौते का मुख्यतया इस आधार पर विरोध किया कि वह जान-बूझकर भारत के व्यापार की स्वाभाविक प्रगति को भिन्न दिशा में मोड़ देगा जिससे भारत को गम्भीर क्षति पहुँचेगी । कुछ वस्तुओं को दिया गया अधिमान एकदम अनावश्यक था । उदाहरण के लिए चाय का व्यापार चाय के प्रधान उत्पादकों, जैसे जावा, सीलोन और भारत, द्वारा 'चाय प्रतिबन्ध योजना' अपनाते के फलस्वरूप हुए व्यापारिक समझौते के कारण भली प्रकार चल रहा था । उन वस्तुओं के सम्बन्ध में अधिमान विल्कुल व्यर्थ था जो स्वयं बाजार में प्रधान स्थान की अधिकारी थी, उदाहरणार्थ जूट-निर्मित वस्तुएँ, बकरी के चमड़े, रेडी बेनीज, लाख, धाँकसा, अभ्रक इत्यादि । अन्य वस्तुओं के प्रसार की सम्भावना बहुत कम थी । इसके कई कारण थे—(१) साम्राज्य के अन्य देशों की प्रतिस्पर्धा, उदाहरण के लिए सिन्धे चमड़े में आस्ट्रेलिया, मूँगफली में ब्रिटिश पश्चिमी अफ्रीका, चटाइयो म लका, कहवा में ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका आदि प्रतिद्वन्दी थे । कुछ वस्तुओं, उदाहरणार्थ मूँगफली, के लिए विदेशों की तुलना में इंगलिस्तान का बाजार बहुत छोटा था । फिर, कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में भारत से होने वाला निर्यात इतना नगण्य था कि उसे अधिमान या किसी अन्य प्रकार से प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ही न थी, जैसे चावल, तम्बाकू और जौ ।^१

दूसरी आपत्ति यह थी कि अधिमान से या तो सरकार को वित्तीय हानि होती थी (कर की कमी से) या उपभोक्ता को, क्योंकि उपभोक्ता सस्ती वस्तुओं के स्थान पर महंगे अप्रेजी वस्तुएँ खरीदने के लिए बाध्य होता था । लेकिन भारत में न तो सरकार ही और न उपभोक्ता ही इस प्रकार का त्याग करने में समर्थ थे ।

साम्राज्य अधिमान उन उपनिवेशों और डोमिनियनों के लिए लाभदायक हो सकता था जिनका ब्रिटेन के साथ व्यापार पूरक-स्वभाव का रहा हो । इंग्लैण्ड की प्राथमिक वस्तुओं की आवश्यकता थी और ये वस्तुएँ उसे कनाडा तथा आस्ट्रेलिया से मिल सकती थी । ये देश ब्रिटिश निर्माणों को खपाने के लिए उत्सुक और समर्थ भी थे । इन दोनों बातों में भारत की स्थिति भिन्न थी । उसके लिए बाह्यनीय और लाभदायक यह था कि वह अपने उत्पादनों के लिए इंगलिस्तान के बाजार अन्वयत्र बाजार ढूँढ़े । उसके विविध प्राकृतिक साधनों ने उसे यह भी सोचने पर बाध्य किया कि वह क्यों न इन सब बातों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करे । इस दृष्टि से उसे अनेक अप्रेजी निर्मित वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा से सरक्षण की आवश्यकता थी ।

भारत के विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियाँ साम्राज्य से उसे दूर खींच ले जा रही हैं ।^२ अनएव यह आवश्यक था कि वह अपने विदेशी बाजारों को सुरक्षित

१. सर आश्नवर्ट ने धाराम्भा के विवाद में तम्बाकू के व्यापार को ६,०००,००० पाँड का मूल्यवान व्यापार बताया ।

२. दक्खिने, अध्याय ६, सेक्शन १८ ।

रखने का दृढ़ और व्यवस्थित प्रयत्न करे, जहाँ उसके अग्रिकाश निर्यात की खपत होती है। इस उद्देश्य तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग यह था कि वह अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक समझौता (बिलेटरल एग्रीमेण्ट) करे।^१ जब तक इंग्लैण्ड हमारा प्रधान साहूकार था और आयात से निर्यात की अधिकता द्वारा ही भुगतान किया जा सकता था, तब तक कोई खास बात नहीं थी। इंग्लैण्ड को या तो भारत के विदेशी वाजारों को स्थिर रखने के लिए उपाय करने होंगे या भारत के विदेशी वाजारों की पूर्ति के लिए अपने बाजार उन्मुक्त करने होंगे, क्योंकि इसके बिना भारत इंग्लैण्ड के प्रति अपनी देनदारियों का भुगतान नहीं कर सकेगा। तर्क का सार यह था कि यदि भारत ने ओटावा समझौते के अनुरूप अन्तर्साम्राज्यीय प्रवन्धों में भाग लेने से इन्कार कर दिया होता तो इंग्लैण्ड की ओर से प्रतिक्रियात्मक साधनों के उपयोग का कोई भय नहीं था। भारत से इसका बदला लेने पर इंग्लैण्ड का युद्ध-पूर्व (१९३६ से पहले) का ५० करोड़ रु० का वार्षिक निर्यात व्यापार भी खतरे में पड़ जाता।

इधर हाल में भारत और इंगलिस्तान के बीच व्यापारिक सन्तुलन के फलट जाने पर ओटावा समझौते के समर्थकों ने इससे खूब लाभ उठाया। १९३५-३६ तक इंगलिस्तान के साथ भारत का व्यापारिक सन्तुलन ऋणात्मक था। यद्यपि भारत 'अदृश्य आयात', जैसे गृह-व्यय, जहाजों का भाड़ा और भारत में विनियोजित विदेशी पूँजी से होने वाले लाभ, के रूप में इंग्लैण्ड को बहुत-कुछ रुपया देता था, फिर भी १९३५-३६ तक इंगलिस्तान के साथ भारत का व्यापारिक सन्तुलन ऋणात्मक था। १९३६-३७ से भारत के पक्ष में पर्याप्त निर्यात की वचन हुई है। अतः यह कहा जाने लगा कि भविष्य में होने वाले व्यापारिक समझौते में भारत को इंग्लैण्ड के साथ उदारता का बतवि करना चाहिए। व्यापार-सन्तुलन को द्विपक्षवाद के सकीर्ण आधार पर समझने से यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि इंगलिस्तान से सौदों के आयात में अदृश्य आयातों को भी जोड़ दिया जाए। यह इसलिए और भी आवश्यक हो गया, क्योंकि यूरोपीय देशों के साथ त्रिपक्षी और बहुपक्षी व्यापार में कमी आ गई थी।

ओटावा समझौते के प्रति असन्तोष का एक प्रधान कारण यह भी था कि भारतीय प्रतिनिधि मण्डल (जिसमें भारतीय वाणिज्य, उद्योग और कृषि के उत्तरदायी प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं थे) अपने सौदा करने की शक्ति का पूरा उपयोग करने में असमर्थ रहा। उसने दिया अधिक और बदले में उसे मिला बहुत कम। समझौता बड़ी शीघ्रता से हुआ और जल्दी ही कार्यान्वित किया गया। इसमें जाँच करने वाली किसी योग्य समिति, जैसे प्रशुल्क मण्डल (टैरिफ बोर्ड) इत्यादि, की सहायता नहीं ली गई, जो साम्राज्य के किसी उद्योग के प्रति अधिमानपूर्ण व्यवहार की सिफारिश करने से पहले उन्हें उसी प्रकार कसौटी पर कसती जिस प्रकार विवेचनात्मक सरक्षण प्रदान करते समय उद्योगों की जाँच की जाती है।

६ बम्बई लकाशायर टेक्स्टाइल समझौता (मोदी लीज पैक्ट)—यह समझौता बम्बई

मिल-मालिक सस्या, जिसके अध्यक्ष सर होमी मोदी थे और ब्रिटिश टेक्स्टाइल मिशन, जो सर विलियम क्लेयर लीड की अध्यक्षता में भारत आया था, के बीच हुआ। यह समझौता, जो 'मोदी-लीड' समझौते के नाम से भी प्रसिद्ध है, ३१ दिसम्बर, १९३५ तक के लिए लागू था। भारतीय सूनी मिलों के प्रतिनिधियों में काफी मतभेद था और एक सामान्य मत पर आने के प्रयत्न असफल रहे, फिर भी लकाशायर और बम्बई की मिल-मालिक सस्या के बीच समझौता सम्भव हुआ। यह समझौता आंग्ल-भारतीय पूरक समझौते का अग्रदूत था (देखिये, सेवदान ७)। इसमें उद्योगों की इगलिस्तान से भी सरक्षित रखने के भारतीय अधिकार को स्वीकार किया गया, परन्तु यह भी स्वीकार किया गया कि इगलिस्तान की तुलना में अन्य देशों से उच्चतर स्तर का सरक्षण आवश्यक था।^१

बम्बई-लकाशायर समझौता साम्राज्य के औद्योगिक सहयोग द्वारा भारतीय और अंग्रेजी हितों के संयोजन का प्रथम प्रयत्न था। कुछ लोगों के मत में यह समझौता स्वयं ही पर्याप्त रूप से न्यायोचित था। इससे लकाशायर द्वारा भारत की कपास की माँग में वृद्धि हुई और इस तरह भारत के किसानों को बड़ा लाभ पहुँचा। लकाशायर ने अपने विरुद्ध भी भारत के वस्त्र उद्योग को सुरक्षित करने की आवश्यकता को मान्यता दी और भारतीय वस्तुओं (कपड़ों) को उपनिवेशों तथा अन्य समुद्र पार देशों के बाजारों में स्थान दिलाने का प्रयत्न करने का वचन दिया।

इसके विपरीत समझौते के आलोचकों का कथन है कि इसे सम्पूर्ण (भारतीय) सूती वस्त्र उद्योग का समर्थन प्राप्त नहीं था तथा भारत ने (सूती और कृत्रिम रेशमी कपड़ों पर कर घटाकर) लकाशायर को निश्चित और पर्याप्त लाभ प्रदान किये, परन्तु इसके बदले में लकाशायर ने केवल अनिश्चित आश्वासन-मात्र ही दिये। इनका फल यह हुआ कि पहले के सरक्षण की तुलना में उद्योग का बहुत-कुछ सरक्षण हट गया। समुद्र-पार बाजारों की दृष्टि से भी जब बम्बई की मिलें अपने देश के बाजार में ही बिना सहायता के खड़ी नहीं हो सकती थी तो समुद्र पार बाजारों में लकाशायर की संहानुभूति से उनके स्थान प्राप्त करने की कम ही आशा थी। अन्त में, जहाँ तक लकाशायर की मिलों द्वारा भारतीय कपास के उपभोग का प्रश्न था, लकाशायर ने एक दही ही अनिश्चित प्रतिज्ञा की थी कि जापान के समझौते की तरह लकाशायर भारतीय कपास को कम-से-कम एक निश्चित माना खरीदने के लिए बाध्य न था।

७ (१९३५) का पूरक आंग्ल-भारतीय व्यापारिक समझौता—१९३३ के बम्बई-लकाशायर समझौते के उपरान्त १९३४ में (वस्तुतः ६ जनवरी, १९३५) एक आंग्ल-भारतीय व्यापारिक समझौता किया गया। यह ओटावा समझौते का पूरक था और उसकी अवधि तक ही लागू रहा।

इगलिस्तान की सरकार ने भी अपनी ओर से भारत के उस कच्चे माल या आधे तैयार माल के आयात को विक्रमित करने का आश्वासन दिया, जो उन वस्तुओं

के निर्माण में प्रयुक्त होता हो जिस पर भारत में भेदात्मक आयात-कर लगे हो। उन्होंने (ओटावा समझौते के दूने अनुच्छेद और मोदी लीड पेक्ट के अनुसार) भारतीय कपास की खपत को अनुसन्धान, व्यापारिक जाँच-पड़ताल, बाजार सम्बन्ध तथा प्रचार आदि हर उपाय से बढ़ाने का वचन दिया। उन्होंने भारत के खान से निकले लोहा (पिंग आइरन) को बिना कर के ब्रिटेन में प्रवेश करने का वचन दिया। शर्त यह थी कि इंगलिस्तान से आयात की जाने वाली लोहे और इस्पात की वस्तुओं के लिए लगाया गया कर १९३४ के लोहा और इस्पात अधिनियम (आइरन एण्ड स्टील एक्ट) में प्रस्तावित करों से कम अनुकूल न हो।

समझौते के समर्थकों का मत था कि इसके द्वारा ओटावा समझौते में निहित प्रतिज्ञाओं तथा मोदी लीड पेक्ट की निश्चित प्रतिज्ञाओं को कार्यान्वित किया गया। समझौते से भारत का कपास तथा कच्चे और आधे तैयार माल का उपभोग बढ़ गया और भारत का खान से निकला लोहा (पिंग आइरन) इंग्लैण्ड में बिना कर के प्रवेश पाने लगा। उपनिवेशों और सरक्षित देशों (प्रोटेक्टरेट) से इंगलिस्तान का मिलने वाली सुविधाओं में भारत को भी हिस्सा देने का वायदा किया गया था।

इसके विपरीत, गैर-सरकारी व्यापारिक मत इसके विरुद्ध था, क्योंकि इससे १९२३ में स्थापित विवेचनात्मक संरक्षण और अर्थ-स्वतन्त्रता-समझौते (फिस्कल आटोनोमी कन्वेंशन) का प्रभाव नष्ट हो गया। समझौते में पारस्परिक समता का भी अभाव था। इसमें भारतीय हितों की अपेक्षा ब्रिटिश हितों का अधिक ध्यान रखा गया था जब कि भारत ने निश्चित प्रतिज्ञाएँ कीं। ब्रिटेन ने भारतीय कपास के उपभोग के विकास-विषयक विभिन्न उपचारों पर विचार करना-भर प्रस्तावित किया और ऐसे वायदे किये जिनका निकट भविष्य में कोई वास्तविक मूल्य और उपयोग न था।

यह भी कहा गया कि इस समझौते में कोटा या कर के प्रतिशत में कमी से कहीं भयकर सिद्धान्तों की व्याख्या की गई। जब संरक्षण एक निश्चित समय के लिए स्वीकार कर लिया गया था, फिर उस प्रश्न को इंगलिस्तान के कहने से पुन उठाना वाञ्छनीय नहीं था। इस प्रकार की नीति भारत के औद्योगिक विकास के लिए बाधक सिद्ध होने के अतिरिक्त नये उद्योगों के प्रारम्भ के लिए घातक सिद्ध होगी।

यह पूरक व्यापारिक समझौता ओटावा-समझौते के साथ ही समाप्त हो गया और इसे फिर से नया करने का प्रयत्न नहीं किया गया।

८ ओटावा समझौते पर धारासभा का विरोधी निर्णय—३० मार्च, १९३६ में भारतीय धारासभा ने एक प्रस्ताव द्वारा ओटावा-समझौते तथा इसके पूरक ब्रिटिश व्यापारिक समझौते को अस्वीकृत कर दिया और इनके लागू रहने के विरुद्ध मत प्रकट किया।

२० अक्टूबर, १९३६ को वाणिज्य विभाग द्वारा प्रकाशित एक विज्ञप्ति में बताया गया कि दोनों सरकारों ने यह स्वीकार किया है कि एक नया समझौता होना तक १९३२ का समझौता लागू रहेगा, जिसे (किसी भी ओर से) तीन महीन का

नोटिस देकर रद्द किया जा सकता है। यह भी कहा गया कि समझौता न भी हो तो भी दोनों पक्षों को अपने अधिमानों को दूसरे से राय लिये बिना हटाना या रोकना नहीं चाहिए।

६. आंग्ल-भारतीय व्यापारिक समझौता (१९३६)^१—यह बातचीत टाई बर्ष तक चलती रही। इसके उपरान्त पहले के दोनों समझौतों के स्थान पर १९३६ में एक नया समझौता किया गया। गवर्नर-जनरल ने अपने प्रमाणन (मर्टिफिकेशन) अधिकार का अनुसरण करते हुए इसे वैध रूप दिया। नये समझौते में ओटावा समझौते का रूप बहुत बदल दिया गया। यद्यपि अब भी भारत के निर्यात की अनेक वस्तुएँ अधिमान-क्षेत्र के अन्तर्गत थीं, किन्तु ब्रिटेन को दिये गए अधिमान का क्षेत्र काफी मरुचिन बन दिया गया, क्योंकि पुरानी अधिमान-मदति के अन्तर्गत खाद्य, पेय, तम्बाकू तथा कच्चे और अर्ध-निर्मित माल अब अधिमान के अधिकारी नहीं रहे। नये समझौते में अधिकतर मदों का सम्बन्ध विजिट्ट उत्पादनों (जिनका भारत में उत्पादन नहीं होता था) से था, जैसे मोटरकार, साइकिल इत्यादि।

जहाँ तक अन्य मदों का सम्बन्ध था (उदाहरणार्थ ऊनी कालीन, कम्बल, औषधियाँ आदि) ब्रिटेन से इनके विशेष प्रकार मंगाए जाते थे जिनका उत्पादन भारत में नगण्य था। अधिमान की कुछ मदों की पुनः परिभाषा की गई, ताकि भारतीय उद्योगों के हित में अनेक वस्तुएँ, जो पहले अधिमान की अधिकारी थीं, अब अधिमान न पाएँ। एक महत्वपूर्ण अन्तर यह हुआ, जबकि ओटावा समझौते में भारत ने सरक्षण-प्राप्त वस्तुओं को बिलकुल अछूता छोड़ दिया था, कि नये समझौते में लकाशायर की वस्तुओं पर लगे करों की व्यवस्था को सन्निहित किया गया था, हालाँकि सरकारी तौर पर भारतीय सूती वस्त्र उद्योग सरक्षित उद्योग था।

भारत ने ब्रिटेन से आयात की जाने वाली अनेक वस्तुओं, जैसे रसायन, रंग, कपड़ों के अवशिष्ट, ऊनी कालीनों, चीन की मशीनों इत्यादि, पर १०% तथा मोटरकार, मोटर साइकिल और स्कूटर, साइकल तथा ग्राम्नीबस पर ७ $\frac{१}{२}$ % अधिमान दिया।

जहाँ तक खान से निकले लोहे (पिंग आयरन) का सवाल है, हालाँकि इनका आयात ब्रिटेन में बिना कर के था, फिर भी ब्रिटिश सरकार ने यह अधिकार सुरक्षित रखा था कि यदि १९३४ के लोहे और इस्पात-सम्बन्धी अधिनियम के समाप्त होने के बाद भारत से ब्रिटेन से भेजे गए लोहे और इस्पात की वस्तुओं पर अधिनियम में प्रस्तावित दरों से अधिक प्रतिकूल कर लगाये गए तो वह भी भारत के खान से निकले लोहे (पिंग आयरन) पर (३१ मार्च, १९४१ के बाद) कर लगा देगा।

भारत से बर्मा क अलग हो जाने पर कुछ अधिमान समाप्त हो गए (उदाहरणार्थ उत्खनित (खान से निकला) गीना, चावल इत्यादि) और कुछ का मूल्य भी घट

१. देखिए, मदन, पूर्वेष्ट, पृ० २२०-४९, तथा बा० पी० छद्दारकर, 'द इस्टिम्ड निरव्वल पानिन्सी', पृ० ५५६-६०।

गया (जैसे साखू (टीक) की लकड़ी, मोम, चावल और तम्बाकू) ।

हम इस बात की पहले ही पूरी व्याख्या कर चुके हैं कि किस प्रकार नये समझौते में कपास की वस्तुओं पर (घटते-बढ़ते क्रम से) विषय अनुमाप से कर लगाये गए और कैसे उसे एक ओर तो भारत से ब्रिटेन को निर्यात की जाने वाली कपास और दूसरी ओर ब्रिटेन से भारत आने वाले सूती कपड़ों से सम्बद्ध कर दिया गया । सच तो यह है कि यही समझौते का आधार-भाग था ।

जहाँ तक उपनिवेशों का सम्बन्ध है नया समझौता ओटावा समझौते से इस अर्थ में भिन्न था कि इसमें सीलोन के साथ एक अलग व्यापार-सन्धि की व्यवस्था थी । सीलोन को ओटावा के अधिमान प्रमाणों का समझौते के छ महीने बाद तक उपयोग करने का अवसर दिया गया ।^१ एक या दो अपवादों को छोड़कर भारत और उपनिवेशों के बीच पारस्परिक अधिमान ज्यो-के-रयो बने रहे ।

साधारण तौर पर यह कहा जा सकता है कि समझौते को न तो भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का और न व्यावसायिक संगठनों का ही समर्थन प्राप्त हो सका ।

दूसरे समझौते में उस समय की भारत की स्थिति को ध्यान में नहीं रखा गया । तत्कालीन भारत एक ऋणी देश था, जिसे 'अदृश्य आयात' के लिए ब्रिटिश साम्राज्य को बहुत अधिक देना था । अतएव उसे व्यापारिक सन्तुलन के लेखों में निर्यात की अधिकता बनाए रखना आवश्यक था । सरकार ने गैर-सरकारी परामर्श-दाताओं के मत की भी उपेक्षा की, जिसमें उन्होंने भारतीय बीमा कम्पनियों, बैंकिंग तथा जहाजी कम्पनियों के पक्ष में भेदात्मक नीति के विरुद्ध और समान अवसरों की प्राप्ति के लिए सुझाव रखा था । नवीन व्यापारिक समझौतों का मूल्यांकन करते समय यह आवश्यक था कि भारतीय इस्पात संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत इंगलिस्तान को दिये गए अधिमानों को भी ध्यान में रखा जाए ।^२

भारत में अर्थजो को प्राप्त अधिमान गैर-सरकारी परामर्शदाताओं के सुझावों से कहीं अधिक थे तथा भारत को अन्य महाद्वीपीय देशों के साथ समझौता करने से वंचित होना पड़ा, क्योंकि उन्हें बदले में देने के लिए भारत के पास बहुत कम या कुछ भी न था ।

यद्यपि भारत द्वारा इंग्लैंड को दिये गए अधिमान ब्रिटेन के लिए निश्चित ही लाभदायक थे, जबकि ब्रिटेन द्वारा भारत को दिये गए आश्वासन केवल आश्वासन अथवा नकारात्मक सुरक्षा के अलावा कुछ नहीं थे । कारण यह था कि इंगलिस्तान को दिये गए अधिमान उन वस्तुओं से सम्बन्धित थे जिनमें इंगलिस्तान के निर्यातकों

१. यह अवधि १५ फरवरी, १९४० को समाप्त हो गई, लेकिन भारतीय प्रवासियों के सम्बन्ध में सीलोन और भारत सरकार से समझौता होने की कठिनाइयों के कारण व्यापारिक सन्धि की बात सफल न हो सकी ।

२. देखिए, इण्डियन टेक्स्टाइल जनरल (अप्रैल १९३७), इण्डो-ब्रिटिश ट्रेड पैक्ट, डॉ० वी० के० आर० वी० राव ।

को यदि कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था, जबकि सरकारी अनुमान के अनुसार भारत द्वारा ब्रिटेन को निर्यात की जाने वाली अधिमान-प्राप्त वस्तुओं का व्यापारिक मूल्य ३६.८६ करोड़ रु० था और ब्रिटेन द्वारा भारत में भेजी जाने वाली अधिमान-प्राप्त वस्तुओं का मूल्य केवल ७.६८ करोड़ रु०, गैर-सरकारी अनुमान के अनुसार भारत की प्रभावपूर्ण अधिमान-प्राप्त वस्तुओं (जैसे अलसी, ऊनी कालीन, कम्बल आदि) का मूल्य केवल ६ करोड़ रु० था। इस श्रेणी में कर-मुक्त वस्तुओं की गणना करना उचित न होगा, क्योंकि ब्रिटेन उन वस्तुओं पर कर लगा ही नहीं सकता था (उदाहरण के लिए कच्चा जूट), क्योंकि ये वस्तुएँ प्रमुख ब्रिटिश उद्योगों के लिए अनिवार्य थीं। इसके विपरीत, ब्रिटेन को प्रधानतया निर्यात वस्तुओं, जैसे पेंट-रसायन, औजार और बस्त्र आदि, के सम्बन्ध में अधिमान दिया गया था, जो देश के गृह-उद्योगों के विकास में बाधक था, परन्तु ब्रिटेन द्वारा भारत को दिया गया अधिमान केवल उस कच्चे माल से सम्बन्धित था जो ब्रिटेन के उद्योगों और शस्त्रीकरण योजना के चालू रखने के लिए आवश्यक था।

लकाशायर के लिए भारतीय कपास के निर्यात को भारत में ब्रिटिश कपड़ों के आयात से सम्बद्ध करने की बहुत आलोचना हुई। इस अवस्था में गैर-सरकारी परामर्शदाताओं के मत की उपेक्षा की गई। जहाँ तक भारत का सम्बन्ध था, उसे समान लाभ मिलने की कोई व्यवस्था न थी। जहाँ तक इंगलिस्तान द्वारा एक निश्चित मात्रा में कपास खरीदने का प्रश्न था उससे ब्रिटेन की कोई विशेष हानि होने की सम्भावना न थी। यह मात्रा भी सन्धारणतया लकाशायर द्वारा खरीदी जाने वाली मात्रा से कम ही थी। इसके स्थान पर भारत से ब्रिटेन की कपास की वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा खरीदने का आश्वासन देने के लिए कहा गया जो समझौते से पूर्व के आयात से कहीं अधिक थी। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की कपास के अनुपातों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, यद्यपि भारत के कपास-उत्पादकों ने इस बात की माँग की थी कि ब्रिटेन द्वारा खरीदी जाने वाली कपास का ६५ प्रतिशत छोटे रेशे की कपास होनी चाहिए। भारतीय गैर-सरकारी सलाहकारों के इस मत के बावजूद भी कि यदि भारतीय कपास-उद्योग पर और अधिक अप्रत्यक्ष कर लगाया गया तो ब्रिटेन के कपड़ों पर भी प्रतिशुल्क लगा दिया जाएगा, लम्बे रेशे की कपास पर लगा आयात-कर दूना कर दिया गया। इससे भारत के सूती मिल उद्योग का संरक्षण कम हो गया, हाथ से बुनने वाले उद्योग पर भी बुरा प्रभाव पड़ा और नये व्यापारिक प्रस्तावों के प्रति एक विरोधी धारणा उत्पन्न की गई।

नये समझौते को सरसरी निगाह से देखने पर ऐसा लगता है कि थोटावा समझौते में काफी सुधार हुआ है। जहाँ तक अधिमानों के पारस्परिक विनिमय का प्रश्न था, कपास के अनुच्छेद (कॉटन आर्टिकल) को छोड़कर इसे न्यायसंगत भी कहा जा सकता था। जहाँ तक लकाशायर के कपड़े लेने और भारतीय कपास देने का प्रश्न है, भारत के लम्बे रेशे की कपास के आयात के द्विगुणित कर को ध्यान में रखते हुए, समझौता लकाशायर के पक्ष में बहुत अधिक था।

१०. भारत-जापानी समझौते की उत्पत्ति (१९३४)—१९०४ के पुराने भारत-जापानी व्यापारिक सम्मेलन का अप्रैल, १९३३ में भारत सरकार द्वारा विरोध किया गया था। इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। १९३२ के आरम्भ से येन के मूल्य में हुए क्रमिक ह्रास से १९३२-३३ में भारत के लिए जापान के निर्यात अत्यधिक अनुकूल हो गए। भारतीय मिल्स को गम्भीर सकट का सामना करना पड़ा और भारत सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। अगस्त, १९३२ में गैर-ब्रिटिश भूरे कपड़े पर मूल्यानुसार ५० प्रतिशत आयात कर की वृद्धि और ५१/४ आने प्रति पौण्ड का विशिष्ट कर भी जापानी प्रतिस्पर्धा कम करने में असमर्थ रहा। अतएव भारत की कपड़े की मिल्स और अधिक संरक्षण के लिए आवाज उठाती रही। भारत सरकार की ओर से ब्रिटेन की सरकार ने जापान की सरकार को छ महीने के अन्दर पुराने (१९०४) समझौते को रद्द करने की सूचना दी। उस समझौते में जापान के साथ बड़ा ही अनुकूल व्यवहार किया जाता था। जब तक १९०४ का व्यापारिक समझौता प्रभावपूर्ण था तब तक भारत सरकार अकेले जापान के विरुद्ध कोई भी कदम उठाने में असमर्थ थी, १९३३ (अप्रैल) में पास किये गए उद्योग सुरक्षा अधिनियम (सेफगाडिंग ऑफ इण्डस्ट्रीज ऐक्ट), जिसके अनुसार भारत सरकार विदेशी सस्ते माल के आयात से देश के उद्योगों को खतरा होने पर कर लगा सकती थी, से भी कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता था। भारत सरकार के इस निर्णय से जापान में भारतीय कपास के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ हो गया, लेकिन जापान के कात्से वाले और कपास के व्यापारियों के बीच भारतीय कपास स्वीकार न करने के लिए जून, १९३३ के प्रशुल्क सम्बन्धी परिवर्तन जारी किए जाने के पूर्व कोई समझौता नहीं हुआ था। इन प्रशुल्क-परिवर्तनों में यह घोषणा की गई कि विदेशों से आने वाले कपड़ों पर (जिनमें जापानी कपड़े भी शामिल हैं) मूल्यानुसार ७५% (मूल्य पर) कर लगाया जाएगा और सादे भूरे कपड़ों पर कम-से-कम ६३/४ पैस प्रति पौण्ड कर लगाया जाएगा। १९३३ में एक जापानी प्रतिनिधिमण्डल भारत आया। तीन महीने की बातचीत के उपरान्त एक समझौता हुआ। १९३४ में जापानियों ने बहिष्कार समाप्त कर दिया और भारत सरकार ने मूल्यानुसार लगाया गया कर ७५% से घटाकर ५०% कर दिया।

११ १९३४ के समझौते की धाराएँ—जापान के साथ होने वाले समझौते के दो भाग थे—(१) सप्रतिज्ञा (कनवेन्शन), (२) मसविदा या मूल (प्रोटोकल लेख)। (१) इसमें दोनों देशों के भावी व्यापार सम्बन्धों की रूपरेखा निर्धारित की गई थी। (२) इसमें जापान के अति अल्पे कपड़े और भारत के अति अल्पे कपड़ों के सम्बन्ध में हुए समझौते की विवचना की गई थी। सप्रतिज्ञा (कनवेन्शन) के बिना मसविदा (प्रोटोकल) स्वतः ३१ मार्च, १९३७ को समाप्त होने को था। यदि दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा छ महीने का नोटिस दे दिया जाता तो सप्रतिज्ञा (कनवेन्शन) भी इसा समय समाप्त होती।

सप्रतिज्ञा (कनवेन्शन) का प्रमुख व्यवस्थाएँ इस प्रकार थी—(१) दोनों

पक्षों ने एक-दूसरे के प्रति परम अनुग्रहीत राष्ट्रीय-जैसा व्यवहार करने का निश्चय किया। (२) दोनों देशों ने अपने पास समय-समय पर परिवर्तन करने और नवीन प्रवेद्य-कर लाने का अधिकार सुरक्षित रखा। यह व्यवस्था रुपये और येन के विनि-मय-मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को ठीक करने के लिए की गई थी। (३) जबकि दोनों पक्षों ने इस प्रकार के परिवर्तन के अधिकार अपने पास रखे, वे इस बात पर तैयार थे कि यदि दोनों में से कोई पक्ष चाहे तो दोनों के पारस्परिक हितों के बीच समझौता करने के कार्य में अग्रसर हो सकता है।

मसविदा (प्रोटोकल) के प्रधान अनुच्छेद इस प्रकार थे—(१) भारत में आने वाली वस्तुओं पर लगने वाले प्रवेद्य-कर निम्नलिखित दर से अधिक न होंगे—(क) सादे भूरे कपड़े (प्लेन ग्रेज) पर मूल्यानुसार ५०% या ५३/४ आने प्रति पौण्ड जो भी अधिक हो। (ख) अन्य पर मूल्यानुसार ५०%। (२) मसविदा (प्रोटोकल) में भारत में जापानी माल के आयात और भारत से कपास के निर्यात के लिए कोटा सिस्टम की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत भारत से प्रतिवर्ष (जो १ जनवरी से प्रारम्भ हो) १० लाख गॉठ कपास खरीदने पर जापान को ३२५० लाख गज कपडा प्रतिवर्ष (जो १ अप्रैल से शुरू हो) भेजने का अधिकार था। जापान द्वारा भेजे सूती कपड़े के यानों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया था—(क) सादा भूरा कपडा (प्लेन ग्रेज) ४५%, (ख) किनारेदार कपडा (ग्रेज) १३%, (ग) सफेद (कलफदार) कपडा ८%, (घ) रगीन (रंगा हुआ, छपा हुआ) ३४%।

१२. १९३४ के भारत-जापानी समझौते की कार्य-विधि—१९३४ के समझौते से दोनों देशों के बीच की दुर्भावनाएँ समाप्त हो गईं। इससे कपास के उत्पादकों, व्यापारियों और कुछ अग्रे तक मिल-मालिकों को भी राहत मिली। लेकिन सबसे अधिक लाभ भारत के कपास-उत्पादकों को हुआ और कोटा सिस्टम द्वारा वे निश्चित मात्रा से अधिक कपास जापान भेज सके। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार से स्थानीय कपड़े के उद्योग के लाभान्वित होने की सम्भावना थी, क्योंकि जनता ही स्थानीय कपड़ों की सबसे बड़ी उपभोक्ता है।

भारतीय दृष्टिकोण से १९३४ के जापान-भारत व्यापारिक समझौते को कुछ आलोचना का सामना करना पड़ा। देश में यह भावना थी कि भारत इस सौदे से घाटे में रहा। सबसे बड़ा अग्रतरोप कोटा सिस्टम के विषय में था। जुलाई, १९३६ में इस समझौते के नवीकरण के सम्बन्ध में शुरू हुई बातचीत के दौरान में भारतीय गैर-सरकारी परामर्शदाताओं ने कहा कि इस पद्धति से वचन के अन्तक उपाय थे। जापानी तथा जापान में रहने वाले भारतीय व्यापारियों ने इससे पर्याप्त लाभ उठाया। इस प्रकार समझौते का प्रधान उद्देश्य, अर्थात् जापान से आने वाले कपड़े का नियमन, पूरा न हो सका। परित्यक्त टुकड़े (फेण्ट्स)^१ कोटा सिस्टम के अन्तर्गत नहीं थे, अतः इनका व्यापार बहुत बढ़ गया। इसी प्रकार नवली रेशम की वस्तुएँ भी कोटा सिस्टम के अन्तर्गत नहीं थी, इसलिए वे बड़ी मात्रा में जापान से भारत आने

१. फेण्ट्स कपड़े परित्यक्त टुकड़ों को कहते हैं जिन्हें कम प्रवेद्य-कर पर आयात किया जाता है।

लगी। जापानी निर्यातको द्वारा कोटा सिस्टम से बचने की एक और भी कुशल विधि आविष्कृत की गई—यह थी कपड़े की बनी हुई वस्तुएँ, जैसे कमीजें, पोशाके इत्यादि, जिनकी भारतीय बाजारों में भरमार हो गई। यह भी कहा गया कि कितना ही जापानी कपड़ा अफगानिस्तान और नेपाल से होकर भारत आता है।

इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि मसविदा (प्रोटोकल) के बावजूद भी इस प्रकार निर्यात बढ गया और उसका (मसविदा का) जापानी वस्तुओं का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। गज लम्बाई के आधार का दुरुपयोग किया गया और अधिक बड़े धर्ज के कपड़े का निर्यात किया गया।

जहाँ तक जापान द्वारा भारतीय कपास की बड़ी मात्रा में खरीदने का प्रश्न है, यह कहा गया कि जापान इसे इसलिए खरीदता था क्योंकि उसे सस्ते माल की आवश्यकता थी। १९३४-३५ में, अर्थात् समझौते के बाद पूरे एक वर्ष में, जापान ने भारतीय कपास की २०,१०,६०० गॉट्स खरीदी जबकि पिछले दस वर्षों से वह प्रति वर्ष कपास की १५ लाख गॉट्स खरीदता था। इसलिए भारत में गैर-सरकारी व्यापारिक मत यह था कि जापान की कपास-सम्बन्धी न्यूनतम क्रय-मात्रा १० लाख से १५ लाख गॉट्स प्रतिवर्ष कर दी जाए। यह भी कहा गया कि कुछ आगामी वर्षों में जापान में भारत की कपास की माँग कम न होगी, जब तक कि जापान कपास के स्थान पर (स्टैपल फायबर) मुख्य (बड़े) रेशे का उपयोग नहीं करता।

१३. नवीन जापान-भारत व्यापारिक समझौता (१९३७)—१९३४ के समझौते के नवीकरण के सम्बन्ध में १९३६ से चलने वाली बातों में आलोचना के इन सब आधारों पर ध्यान दिया गया। पुराना समझौता ३१ मार्च, १९३७ को समाप्त होने वाला था। इस बार सरकार के वाणिज्य विभाग के गैर-सरकारी परामर्शदाता अपनी माँगों में एकमत थे। प्रथम यह कहा गया कि जापान द्वारा भारत की कपास के क्रय के सम्बन्ध में समझौता वैसे ही बना रहे, लेकिन भारत में आने वाले जापानी कपड़े की मात्रा में काफी कमी की जाए (उदाहरणार्थ ५०० लाख गज की कमी की जाए)। फेण्ट्स (परित्यक्त कपड़ों) के लिए भी कोटा की व्यवस्था अपनाने की माँग की गई, जो साधारण कपड़े की मात्रा के २ $\frac{1}{2}$ % से अधिक न हो। जापान से कृत्रिम रेशम के बढ़ते हुए आयात को रोकने के लिए रेशम को भी साधारण कपड़ों के कोटा में शामिल करने का सुझाव रखा गया। ऐसी ही व्यवस्था सिले हुए कपड़ों के बारे में भी लागू करने का सुझाव दिया गया। यह भी कहा गया कि कोटा गज लम्बाई के सिद्धान्त पर न लगाकर वर्गगज के हिसाब से लगाया जाए और नीचे दरजे का जापानी सूत भी (५० से नीचे का) कोटे के अन्दर आना चाहिए। विविध वस्तुओं के लिए या तो कोटा अपनाया जाए या ऐसा विशिष्ट आयात-कर लगाया जाए ताकि यह-उद्योगों की सुरक्षा हो सके।

यह सशोधित समझौता १९३७ (अप्रैल) में ३१ मार्च, १९४० तक के लिए लागू किया गया।

जहाँ तक व्यापारिक सप्रतिज्ञा (ट्रेड कन्वेंशन) का सवाल है, पुरानी स्थिति

कायम रही और फिर तीन वर्षों के लिए जापान परम अनुग्रहीत राष्ट्र का व्यवहार पाने का अधिकारी हो गया।

कुछ थोड़े-से परिवर्तनों को छोड़कर, जो १ अप्रैल, १९३७ को बर्मा के विभाजन के कारण आवश्यक हो गए थे, संशोधित मसविदा (प्रोटोकल) भी प्रायः पुराने मसविदे-जैसा ही था। जापान द्वारा १० लाख गॉटों खरीदे जाने पर उसके आयात का कोटा अब ३२५० लाख गज से घटाकर २८३० लाख गज कर दिया गया। यह कमी बर्मा-विभाजन के कारण भारतीय बाजार के संकुचन होने का परिणाम थी। इसी प्रकार जापानी कपड़े के आयात की उच्चतम सीमा, जो जापान द्वारा कच्ची कपास की १५ लाख गॉटों खरीदे जाने पर आधारित थी, ४००० लाख गज से घटाकर ३५८० लाख गज कर दी गई।

१९३७ में प्रारम्भ होने वाले समझौते में गैर-सरकारी परामर्शदाताओं की एकमत सिफारिशों का पूरा स्थान नहीं मिला और मूलतः यह पुराने समझौते से कुछ अधिक अच्छा नहीं था। भारत सरकार यदि चाहती तो जापानी प्रतिस्पर्धा से क्षति-प्रस्त भारत के नवजात उद्योगों के संरक्षण के लिए अधिक उत्तम शर्तों पर समझौता कर सकती थी, लेकिन गृह-उद्योगों की सुरक्षा की माँग पर ध्यान दिए बिना ही व्यापारिक समझौता वैसा ही रहने दिया गया। इस प्रकार दोनों देशों में व्यापारिक सम्बन्ध पहले जैसे ही रहे। अतः इस अक्षय तक समझौता जापान के लिए हितकर रहा था।

जहाँ तक कपास व मसविदा (प्रोटोकल) का प्रश्न था, जो कुछ अन्तर हुआ वह भारत से बर्मा के अलग हो जाने के कारण था। जापान ने बर्मा से दूसरा समझौता कर लिया, जिसके अनुसार बर्मा में आने वाले जापानी कपड़े की मात्रा ४२० लाख गज थी। भारत का कोटा इतना ही कम कर दिया गया। ध्यान रहे कि पुराने मसविदे का आधारभूत कोटा कम करते समय बर्मा की आवश्यकताएँ ७०० लाख गज अनुमानित की गई थीं। चूँकि बर्मा का कोटा ४२० लाख गज ही रखा गया, भारत को बाकी २८० लाख गज की खपत करनी पड़ी।

यह कहा गया कि कॉटन फेब्रिक्स को कोटे में नहीं शामिल किया गया, हालाँकि उच्चतम सीमा सूती कपड़े के कोटे की २३% अर्थात् ८६,५०,००० गज कर दी गई थी।

सिल्क फेब्रिक्स और कृत्रिम सिल्क को भी समझौते से बाहर रखने पर कड़ी आलोचना की गई। लेकिन भारतीय सिल्क और कपड़े के उद्योग को १९३७ में वृत्ति विभाग के नोटिफिकेशन से लाभ पहुँचा, जिसके अनुसार कृत्रिम सिल्क के फेब्रिक्स को भारत में आने से रोका गया और कृत्रिम सिल्क पर एक अना प्रति वर्गगज कर लगा दिया गया।

गैर-सरकारी सलाहकारों के कुछ सुझाव स्वीकार नहीं किये गए। उदाहरण के लिए विविध प्रकार की नियमित वस्तुओं, जैसे तौलिया और सूती कम्बल, के लिए अलग कोटे का इन्तजाम नहीं किया जा सका और न ही भारत के सीमाप्रान्तों से अफगानिस्तान और नेपाल के बाजारों को पुनर्नियमित करने पर रोक लगाई गई।

भारत के तटीय जहाजी व्यापार में जापान के घुस पडने के सम्बन्ध में कोई रोक-टोक नहीं की गई और जापान तथा भारत के बीच होने वाले व्यापार में भारतीय जहाजों को उचित भाग देने के सम्बन्ध में भी कुछ नहीं किया जा सका। इन दोनों कारणों से भी असन्तोष प्रकट किया गया।

सब बातों को देखकर यह कहा जा सकता है कि १९३७ के समझौते से भारत की स्थिति पहले से हदतर हो गई। यह बात अद्वय थी कि भारत ने अपनी सौदा करने की शक्ति का पूरा उपयोग नहीं किया। यह अच्छा हुमा होता कि कपास और कपड़े की अदला-बदली के स्थान पर एक विस्तृत और व्यवस्थित व्यापारिक समझौता किया गया होता, जिसमें देश के नवजात उद्योगों, जैसे चीना, साबुन, रसायन आदि, की सुरक्षा की व्यवस्था होती।

१४ १९४० का अस्थायी समझौता—जापान सरकार से यह आश्वासन पाने पर कि उनका विचार मसविदा (प्रोटोकल) और सप्रतिज्ञा (कन्वेन्शन) की समाप्ति के अन्तर से लाभ उठाने का नहीं है, दिसम्बर १९३९ में भारत सरकार ने व्यापारिक समझौते की समाप्ति के लिए जापान को छः महीने का नोटिस देना आवश्यक नहीं समझा।

३१ मार्च १९४० को मसविदा (प्रोटोकल) की अवधि समाप्त होने पर दोनों सरकारों ने निश्चय किया कि पुराने समझौते की समाप्ति और नये के निर्माण के बीच वे ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे एक-दूसरे के हित को हानि पहुँचे।

१९४१ में ब्रिटिश सरकार द्वारा जापान के साथ हुई व्यापारिक सन्धियों को त्यागने के कारण जापान के साथ जल्दी समझौता होने की आशा न रही। अतएव पुरानी जापान भारत व्यापारिक सप्रतिज्ञा (१९३४) की समाप्ति के लिए जापान को छ महीने का नोटिस दिया गया।

१५. १९४१ का नया वर्मा-भारत व्यापारिक समझौता—१९३७ (अप्रैल) में भारत में वर्मा के अलग हो जाने पर नये समझौते के होने तक वर्मा के साथ सम्बन्ध भारत-वर्मा नियम सभादेश (इण्टो-वर्मा रेगुलेशन ऑर्डर इन काउन्सिल) द्वारा निर्धारित होते रहे। इसमें दोनों देशों के व्यापारिक तथा प्रमुख-सम्बन्धी मामलों की यथावत् रक्षा गयी। वर्मा सरकार को अपनी वजह-सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण इस प्रकार की स्वतन्त्र व्यापारिक नीति ठीक नहीं जैसी और १ अप्रैल १९४० को १ अप्रैल १९४१ से सभादेश की समाप्ति करन का नोटिस दिया। इसी बीच नवीन समझौते का प्रयत्न किया गया और वह हो भी गया।

इन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत दोनों ने एक दूसरे से परम अनुग्रहीत राष्ट्र का-मा व्यवहार करने का निश्चय किया। इस समझौते की मुख्य बातें निम्न थी—

(१) वर्मा द्वारा भारत को दी गई रियायतें—(क) वर्मा ने भारत की ७३ वस्तुओं, जैसे मङ्गली, कोयला, कपास, उत्खनित लोहा (पिंग आयरन) आदि, के स्वतन्त्र प्रवेश का अधिकार दिया। (ख) कुछ वस्तुओं पर ५% से अधिक कर न लगाने का वचन दिया (जैसे आबु, नारियल, रसायन, मादक वस्तुएँ, औषधियाँ, रंग, ऊनी वस्त्र आदि)। (ग) कुछ वस्तुओं पर १०% से अधिक कर न लगाने की रियायत

दी (जैसे कॉफी, सिगार, कुछ मसाले, साबुन (नहाने के), बूट जूते आदि)। (घ) कुछ वस्तुओं पर विशेष दर से टैक्स लगाने की रिआयत दी गई—सुपारी २०%, शराब (एल बोअर) पर उत्पाद-कर के हिसाब से, तम्बाकू पर १ आना प्रति पौण्ड की दर से, और सिल्क (कृत्रिम) पर १५% के हिसाब से इत्यादि।

(२) भारत द्वारा बर्मा को दी गई रिआयतें—(क) भारत ने स्वीकार किया कि बर्मा की कुछ वस्तुएँ बिना किसी कर के भारत में प्रवेश पाएँगी (जैसे रँगने और सिझाने के सामान, गोद, लाख, लकड़ी, शहतीर, वार्निश किये सामान, कच्चा लोहा, अल्युमिनियम, जस्ता और सीसा)। (ख) कुछ वस्तुओं पर विशेष दर से कर लगाया जाएगा (जैसे आलू और प्याज ५%, कहवा १०%, सिगार १०%, तम्बाकू (न बनी हुई) १ आना प्रति पौण्ड)। (ग) बर्मा से आने वाले मिट्टी के तेल और भारत से जाने वाले कपड़े के कर की अलग व्यवस्था की गई। कपड़े के लिए समझौते में केवल ७ $\frac{३}{४}$ % की व्यवस्था थी, परन्तु बर्मा सरकार ने प्रतिज्ञा की कि इस प्रकार की वस्तुओं पर १०% से अधिक कर न लगाएगी। इसके अतिरिक्त जापानी वस्तुओं पर कोटा सिस्टम कायम रखने से भारत के कपड़ों की स्थिति और हूड हो गई। जहाँ तक मिट्टी के तेल का सम्बन्ध है, अधिमान कम करके ६ पाई प्रति गैलन कर दिया गया, जबकि पहले ११ $\frac{३}{४}$ पाई प्रति गैलन था। भारत सरकार ने युद्ध-काल में कुल अधिमान के बराबर अधिभार (सरचार्ज) लगाने का अधिकार प्राप्त कर लिया। यह अधिभार (सरचार्ज) ७ अप्रैल १९४१ को कार्यान्वित किया गया। (घ) यह भी आवश्यक समझा गया कि भारत में आने वाले शहतीर और बर्मा को भेजी जाने वाली चीनी के लिए अलग कर-व्यवस्था की जाए। बर्मा की सरकार ने युद्ध-काल में शहतीर पर नियति-कर न लगाने का आश्वासन दिया और भारत से आने वाली चीनी को विशेष सुविधाएँ दी (जहाँ तक स्थानीय परिस्थितियों में ऐसा कर सकना सम्भव था)। (ङ) चावल और हूटा चावल कर-मुक्त सूची (फ्री लिस्ट) के अन्तर्गत रखे गए और तब तक बर्मा से आने वाले माल पर चुगी न लगाने की व्यवस्था थी जब तक कि अन्य देशों के माल बिना चुगी के आते रहे। यदि हूटे चावल पर चुगी लगे तो १०% का अधिमान दिया जाए। (च) एक देश से दूसरे देश को किये जाने वाले उन निर्यातों के सम्बन्ध में, जिन पर उत्पाद-कर (एक्साइज ड्यूटी) लगता है।

१६. द्विपक्षी (बिलेटरल) व्यापारिक समझौतों की नई नीति—व्यापारिक नीति की प्रमुखतम विशेषता विशेष रूप से १९३२ के बाद से, यूरोपीय देशों में घनेक देशों द्वारा कुछ समय के लिए द्विपक्षी व्यापारिक समझौता करने की हो गई है।

अनेक प्रकार के द्विपक्षी-समझौतों में सबसे अधिक प्रचलित निम्न है—(१) निर्यात-समझौते (क्विलरिंग) तथा (२) क्षतिपूर्ति या अदला-बदली के समझौते (कम्पेंजेशन या वार्टर एग्सीमेण्ट्स)। दूसरे में वस्तुओं का सीधा विनिमय होता है। इस प्रकार चुकता करने की आवश्यकता ही नहीं उठती। इस प्रकार के समझौते दो देशों या व्यक्तियों या फर्मों के बीच हो सकते हैं। निर्यात-समझौते (क्विलरिंग एग्सीमेण्ट्स) में विनिमय की जाने वाली वस्तुएँ निश्चित नहीं होती। इनका प्रधान उद्देश्य

विदेशी विनिमय के नियमन के लिए व्यापार को इस प्रकार व्यवस्थित करना है ताकि आयात और निर्यात के बीच सम्यक् सन्तुलन स्थापित हो जाए।^१ यद्यपि अब भी परम अनुग्रहीत राष्ट्र-व्यवहार की धारा को द्विपक्षीय समझौते में जोड़ दिया जाता है लेकिन वित्तीय और कोटा-व्यवस्था-सम्बन्धी धाराओं को सम्मिलित करने और औद्योगिक प्रतिज्ञाओं तथा प्रादेशिक अधिमानों के कारण इसका कोई क्रियात्मक प्रभाव नहीं रह जाता।

सितम्बर, १९३९ में युद्ध छिड़ने से पूर्व भारत सरकार ने उन सब प्रमुख देशों के साथ व्यापारिक समझौता करने का निश्चय किया जिनके साथ भारत का वाणिज्य-सम्बन्ध था। इनमें जर्मनी, इटली, ईरान, तुर्की इत्यादि प्रमुख थे, जिनकी नियमित विनिमय-नीति से भारत के निर्यात में बड़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थी। देश के सामने प्रश्न था—क्या भारत को द्विपक्षीय समझौते के पक्ष में परम अनुग्रहीत राष्ट्र-व्यवहार की पुरानी नीति को त्याग देना चाहिए? (मार्च, १९३६) धारासभा द्वारा ओटावा समझौते का अन्त करने के पक्ष में दिये गए मत से यह विवाद और भी तीव्र हो गया।

यद्यपि भारत सरकार इस प्रकार द्विपक्षीय सन्धियाँ करने के लिए कटिबद्ध हो चुकी थी, फिर भी उन्हें इस नीति की बाध्यता पर बहुत अधिक विश्वास नहीं था। उनके विचार में पिछले कुछ वर्षों में विश्व की आर्थिक स्थिति के अध्ययन और भारत की वर्तमान परिस्थितियों के अवलोकन से ऐसा कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता जिससे किसी नीति-परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत होती हो।^२ कहा गया कि भारत के निर्यात की प्रधान वस्तुएँ कच्चे पदार्थ हैं जो विश्व के बाजारों में भेजे जाते हैं। अतएव उसकी समृद्धि के लिए आवश्यक था कि उसका व्यापारिक सन्तुलन उसके पक्ष में हो। इसलिए उसे इन बाजारों में मुक्त प्रवेश प्राप्त होना चाहिए और भारत परम अनुग्रहीत राष्ट्र के आधार पर अपने लिए खुले दरवाजों को बन्द करवाने के लिए सहज ही तैयार नहीं हो सकता। द्विपक्षीय समझौतों से न केवल समझौता करने वाले देशों का कुल व्यापार घट जाएगा, बल्कि व्यापार के अपने स्वाभाविक मार्गों से मुड़कर अन्य दिशाओं में जाने से अन्य देश भी हानि उठा सकते हैं। कुल व्यापार की मात्रा में वृद्धि की अपेक्षा अनुकूल व्यापारिक सन्तुलन को पसन्द करने की नीति से सभी व्यापारिक सन्तुलन नष्ट हो जाएँगे और इस प्रकार विश्व-व्यापार में स्थायी सकुचन आ जाएगा। इस नीति के अनुसरण से भारत को लाभ की अपेक्षा हानि ही

१. देखिए, भारत सरकार के सूचना-संचालक द्वारा प्रकाशित तीसरा नोट 'ऑन इण्डियाज़ फॉरेन ट्रेड पालिसी' (१९३६) और पाल एजिनग एक्सचेंज कन्ट्रोल, पृ० १५१-२।

२. जिन आधारों पर यह निष्कर्ष निकाला गया था वे भारत सरकार के सूचना-संचालक द्वारा प्रकाशित १९३६ के प्रेस नोटों में दिये गए हैं। और भी देखिए, बी० के० मदन का लेख 'विलेटरलिज्म एण्ड इंडियन ट्रेड', 'इंडियन जर्नल ऑफ़ इकॉनॉमिक्स' (जुलाई १९३६) और 'इंडिया एण्ड इन्पीरियल मिनेरेल्स', पृ० १९९-२००।

अधिक होगी, क्योंकि इससे उमका विदेशी व्यापार कम हो जाएगा, निर्यात बढ़ जाएगा और आयात कम हो जाएगा। जर्मनी-जैसे सकटापन्न देशों के लिए आयात का नियंत्रण आवश्यक हो सकता है, लेकिन भारत-जैसे समृद्ध देश द्वारा इस नीति का अनुसरण कोरी हार होगी।

अब भारत की स्थिति विश्व के बाजारों में प्रधान खाद्यान्न और कच्चे माल के पूरक की नहीं रही। उदाहरण के लिए अब जर्मनी, जो कि पहले अधिकतर भारत से कच्चा माल खरीदता था, अब उन देशों से खरीद रहा था जिनके साथ निकासी-समझौते (क्विलियरिंग एग्रीमेंट्स) किये गए थे। इस प्रकार कपास ब्राजील, पीरू, टर्की और मिस्र से, चमड़ा दक्षिणी अमेरिका से और तिलहन अर्जेंटीना तथा अन्य फ्रेंच उपनिवेशों से खरीदे जाने लगे। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि इन देशों की मुद्रा-सम्बन्धी अनिश्चितताएँ तथा अनिश्चित आर्थिक स्थिति इनके साथ द्विपक्षी समझौतों के समुचित संचालन में बाधा पहुँचाएंगी।

अन्य देशों के साथ भी कितनी ही कठिनाइयाँ थीं। उदाहरण के लिए फ्रांस अपने उपनिवेशों के आयात को प्रोत्साहन दे रहा था और वह चीन की हल्की सुस्वादु चाय को भारतीय चाय की अपेक्षा अधिक पसन्द कर रहा था। समुहतराज्य अब भी अपनी एकान्तवादी तिकड़ियों में लगा हुआ था और विदेशी व्यापार की अपेक्षा देश के वाणिज्य और विकास को अधिक महत्व दे रहा था। अतएव इन देशों से द्विपक्षी समझौता करने का अवसर कम ही था।

दीर्घकालीन दृष्टिकोण से तो यह कहा जा सकता है कि भारत विश्व से अलग रहकर व्यापारिक इकाई के रूप में अपना महत्त्व नहीं रख सकता। उसे अपने अतिरिक्त उत्पादन के लिए विश्व के बाजारों में स्थान ढूँढना पड़ेगा और उसकी समृद्धि अन्ततोगत्वा, विश्व के व्यापारियों की समृद्धि से सम्बद्ध है। अतएव उसका हित विश्व-व्यापार के अवाधित और उन्मुक्त प्रवाह में ही है जिस पर विश्व की समृद्धि निर्भर है।

इसके विपरीत यह कहा गया कि विश्व के समुत्थान और स्वतन्त्र व्यापार के पुनर्स्थापन की बहुत कम आशा है तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता, आर्थिक राष्ट्रीयता और व्यापारिक द्विपक्षीयता कम होने के बजाय घनीभूत ही होगी। इस परिस्थिति में सुरक्षा के लिए भारत को नवीन व्यापारिक नीति का अनुसरण करना होगा और इसका प्रारम्भ भी भारत-जापान, भारत-ब्रिटिश और भारत-जर्मनी समझौतों के रूप में हो चुका है।

अन्तरिम आयोग ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सगठन के पहले सत्र (सेशन) की तैयारी १९५६ तक कर ली थी, किन्तु हवाना चार्टर की स्वीकृति कम होने के कारण यह स्पष्ट हो गया कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सगठन की स्थापना अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगी। आज तक इस सगठन की स्थापना नहीं हुई है और व्यापार तथा निरानाम्य कर के सामान्य समझौते (जी० ए० टी० टी०—जनरल एग्रीमेण्ट ऑन ट्रेड एण्ड टेरिस्ट) के बाद यह कहा जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सगठन

की स्थापना का विचार छोड़ दिया गया है।

जी० ए० टी० टी०—१९४७ में जिस समय जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सङ्गठन का चार्टर तैयार किया जा रहा था, उसी समय चार्टर बनाने वाली समिति के सदस्यों ने आपस में निराक्राम्य (टेरिफ) कर-सम्बन्धी बातों पर भागे बढ़ने का निर्णय किया और जी० ए० टी० टी० की रूपरेखा तैयार की।

यह समझौता १ जनवरी, १९४८ से लागू हुआ और इसमें २३ देश सम्मिलित हुए। जी० ए० टी० टी० के तत्त्वावधान में जेनेवा में हुआ निराक्राम्य सम्मेलन प्रथम था। इसके अतिरिक्त तीन सम्मेलन और हुए—फ्रांस (१९४९), इंग्लैण्ड (१९५०-५१) और जेनेवा (१९५६)। इन सम्मेलनों का परिणाम यह हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सम्मिलित होने वाली ६०,००० मद्दों की निराक्राम्य दर (कस्टम ड्यूटी) घटा दी गई या स्थिर कर दी गई। इस समझौते को मानने वाले सभी देशों ने इसमें भाग लिया। वस्तुतः जी० ए० टी० टी० में शामिल होने की इच्छा रखने वाले देशों को समझौते में शामिल होने से पहले अपनी निराक्राम्य दर को घटाने के लिए तैयार होना पड़ता है।

१ जनवरी १९५६ को इस समझौते में सम्मिलित सदस्यों की संख्या ३७ थी। विश्व के सम्पूर्ण व्यापार का ८० प्रतिशत विदेशी व्यापार इन्हीं देशों द्वारा होता है।

१९५८ तक तेरह सत्र (सेशन) हो चुके थे। प्रत्येक वर्ष एक सत्र, जिसकी अवधि लगभग ६ सप्ताह की होती है, होता था।

१९५९ से कम अवधि के दो सत्र करने का निश्चय किया गया। इन सत्रों में अन्य बातों के अलावा विभिन्न देशों द्वारा प्रस्तुत शिकायतों पर भी विचार होता है।

१९५२ में भारत ने पाकिस्तान द्वारा जूट के निर्यात पर लगाए भेदात्मक करों के विरुद्ध शिकायत की। दोनों देशों की सरकारें आमन्त्रित की गईं और पाकिस्तान द्वारा भारत को जूट तथा भारत द्वारा पाकिस्तान को कोयला देने की शर्तों पर विचार करके एक दीर्घकालीन व्यापारिक समझौता किया गया तथा दोनों देश भेदात्मक करों को समाप्त करने के लिए राजी हो गए।

आधुनिक व्यापारिक समझौते—१९४८-४९ में भारत ने दस देशों के साथ व्यापारिक समझौता किया। यह व्यापारिक देशों से स्वयं—न कि इंग्लिस्तान द्वारा—सम्बन्ध स्थापित करने की नीति का फल था। दूसरा उद्देश्य सुलभ मुद्रा (साफ्ट करेंसी) के व्यय तथा दुर्लभ मुद्रा (हार्ड करेंसी) के संचय का भी था। सन् १९५३ के मुख्य समझौते में रूस, मिश्र और सीलोन के साथ किये गए समझौते मुख्य हैं। रूस और भारत समझौते में व्यापार के रूपों में अर्थ-प्रवर्धन करने की व्यवस्था की गई है।

चीन के साथ एक समझौता २९ अप्रैल, १९५४ को किया गया, जिसमें भारत और तिब्बत के चीनी प्रदेश के बीच सामान्य व्यापार की व्यवस्था की गई। १४ अक्टूबर, १९५४ को एक दूसरा समझौता हुआ, जिसमें दोनों देशों के आयात और

निर्यात की वस्तुओं की व्यवस्था की गई। इस समझौते के अन्तर्गत भारत ने चीन को बलकत्ता होकर अपना माल तिब्बत भेजने के लिए सुविधा प्रदान की। इस समझौते के साथ ही एक अलग पैक्ट भी किया गया, जिसमें भारत से ६० लाख पौ० वर्जीनिया तम्बाकू के निर्यात (चीन को) और चीन से ६० लाख पौ० कच्चे रेशम के आयात का प्रवन्ध किया गया। १४ अक्टूबर, १९५४ को समझौता दो वर्ष के लिए किया गया।

प्रतिवर्ष कुछ व्यापारिक समझौतों में सशोधन या अथवा वृद्धि की जाती है तथा नये समझौते किये जाते हैं। इनका उद्देश्य निर्यात के नये बाजार प्रस्तुत करने के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार के असन्तुलन को दूर करना है। १९५६-६० में अफगानिस्तान, बल्गेरिया, चिली, पूर्वी जर्मनी, फ्रान्स, इटली, जोर्डन, पाकिस्तान, पोलैण्ड, रूमनिया, स्विट्जरलैण्ड और यूगोस्लेविया के साथ नये समझौते किये गए। इधर हाल में फ्रांस, जोर्डन और स्विट्जरलैण्ड के साथ ये व्यापारिक समझौते पहली बार किये गए हैं। ग्रीस, हंगरी, इण्डोनेशिया और वीतनाम के समझौतों की अथवा बढ़ा दी गई। हंगरी के साथ १ जून, १९६० को ३½ वर्ष की अथवा का एक नया समझौता भी किया गया।

इस समय भारत के व्यापार और भुगतान-सम्बन्धी समझौतों की सख्या २४ है।^१

भारत के व्यापारिक समझौतों को तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है—(१) पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ किये गए समझौते, (२) पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ किये गए समझौते तथा (३) अन्य देशों के साथ किये गए समझौते। प्रथम प्रकार के समझौतों में (जैसे कि रूस, पोलैण्ड और पूर्वी जर्मनी के १९५८ के समझौतों में) भुगतान की व्यवस्था अतिवर्तनीय भारतीय रुपया में है। द्वितीय प्रकार के समझौतों का उद्देश्य भारत के आयात की अधिकता से उत्पन्न असन्तुलन को दूर करना है। इस सम्बन्ध में भारत तथा सम्बन्धित देश के प्रतिनिधियों के मध्य अतिवर्तनीय आयोग के सगठन का प्रस्ताव भी था।

इस बात में कोई सन्देह नहीं कि व्यापारिक समझौते तथा अन्य सामान्य समझौते, प्रतिनिधिमण्डल न केवल राष्ट्रों के बीच अतिवर्तनीय सम्बन्ध बनाते हैं बल्कि इसके साथ साथ देश के व्यापार को असंगठित बनाते हैं जिससे विदेशी व्यापार के रुख तथा व्यापार के नक्शे पर प्रभाव डाल सकें। १९६४ तथा १९६५ में भारत ने कई नये व्यापारिक समझौते किये तथा पुराने समझौतों के समय को और बढ़ाया। नये समझौते बुल्गेरिया, दक्षिणी कोरिया, पूर्वी जर्मनी, ईरान, ब्राजील तथा अर्जेंटीना के साथ किये गए। व्यापार समझौतों का फ्रांस, इटली, पाकिस्तान, चेका, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया और जोर्डन इत्यादि देशों के साथ पूर्व अथवा में लाया गया।

अरब गणराज्य के साथ सितम्बर १९६४ में एक समझौता के अनुसार दोनों

१. देखिये, रिपोर्ट ऑन कम्मी प्लेड फार्नेन्स, पृ० ६७, १९५६-६०।

देशों के बीच व्यापार को शत-प्रतिशत बढ़ाने की चेष्टा की गई। १९६४-६५ में देश से बहुत-से व्यापारिक प्रतिनिधि विदेशों में भेजे गए। इस प्रकार आर्थिक उन्नति के कार्य में लगे हुए राष्ट्रों के साथ सहकारिता की नींव डाली गई; विशेषतया लका, नेपाल, सूडान तथा युगांडा। अफ्रीकी तथा एशियाई देशों के साथ मिलकर औद्योगिक उन्नति की चेष्टा की गई। ६ प्रोजेक्ट एशिया के देशों के साथ और १० अफ्रीकी देशों के साथ सूती, ऊनी कपड़े, जूट, चीनी तथा हल्के तकनीकी यन्त्रों के बनाने में सहकारिता की।

देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए १९३४ के शुल्क दर कानून (Indian Tariff Act) को १९६३ में संशोधित किया गया। १९६४ में आयात में कुछ कटौती के लिए संशोधन किया गया। शुल्क-दर कमीशन की सिफारिशों पर कुछ वस्तुओं पर संरक्षण को हटाया गया, परन्तु रंग के उद्योगों पर १९६७ तथा अल्यू-मिनियम पर १९६८ तक संरक्षण की अवधि बढ़ा दी गई। मई १९६६ में शुल्क दर के प्रदान के सोच-विचार के लिए एक कमेटी डा० बी० के० आर० बी० राव की अध्यक्षता में बनाई गई।

चौथी पंचवर्षीय योजना में व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किया जाएगा, जिससे विदेशी मुद्रा का हल शीघ्रातिशीघ्र मिल सके।

न था। वैकिंग भी अभी अव्यवस्थित ही था। नवम्बर, १८६४ में भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, जिसके अनुसार सरकारी खजानों पर सावरेन और अर्द्ध-सावरेन क्रमशः १० और ५ रुपये के भाव से स्वीकार की जाने लगी तथा भारत सरकार सुविधानुसार अपने ऋणदाताओं की इच्छानुसार सावरेन और अर्द्ध-सावरेन में ऋण चुकाती थी। १८६६ में कलकत्ता व्यापार-मण्डल ने स्वर्ण चलाय (करेन्सी) अपना देने के लिए पुनः जोर दिया। भारत सरकार ने मॅन्सफील्ड आयोग की नियुक्ति की। भारतीय करेन्सी की समस्याओं पर विचार करने के लिए समय-समय पर नियुक्त समितियों और आयोगों में यह सर्वप्रथम था। इन आयोगों और समितियों ने भारतीय चलार्थ के दोषों को दूर करने लिए अनेक विरोधात्मक उपाय बताए। मॅन्सफील्ड आयोग ने सिफारिश की कि (१) १५, १० और ५ रुपये का सोने का सिक्का जारी करना चाहिए, क्योंकि जनता ऐसे सिक्को को इन्हीं मूल्य के नोटों की अपेक्षा अधिक पसन्द करेगी तथा स्वर्ण चलार्थ (करेन्सी) नोट के प्रचलन का मार्ग प्रशस्त करेगा। (२) चलाय सोने, चाँदी और कागज का होगा। १८६८ में एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके द्वारा सावरेन और अर्द्ध-सावरेन स्वीकार करने की दर क्रमशः दस रुपये आठ आने और पाँच रुपये चार आने कर दी गई, क्योंकि पहली (दस रुपये, पाँच रुपये) बाजार दर के अनुरूप नहीं थी और फलस्वरूप सरकारी खजाने के लिए पर्याप्त सोना आकृष्ट करने में असमर्थ रही। मॅन्सफील्ड आयोग का कोई हवाला न देते हुए भारत सरकार ने यह कदम उठाकर अन्ततः सोने को वैधानिक मुद्रा बनाने की इच्छा प्रदर्शित की। सोने को वैधानिक मुद्रा मानने की गलती और उसका परिणाम स्वीकार करने से पहले सरकार भारत में सोने और चाँदी के सापेक्षिक अर्थ को निश्चिन कर लेना चाहती थी। १८७२ में सर रिचार्ड टेम्पल ने एक टिप्पणी में भारत सरकार को यह सुझाव दिया कि वास्तव में भारत में स्वर्ण प्रमाण तथा करेन्सी की आवश्यकता थी तथा सोने और चाँदी की दर निश्चित करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की सिफारिश की। गवर्नर जनरल की परिषद् इस प्रश्न पर एकमत नहीं थी और भारत सरकार द्वारा इस प्रस्ताव की अस्वीकृति के साथ १८७४ में भारतीय चलार्थ (करेन्सी) के इतिहास का द्वितीय काल समाप्त हो गया।

४ तृतीय काल (१८७४-९३)—१८७४ तक द्रव्य के रूप में चाँदी की स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन प्रारम्भ हो चुका था। १८७३ में जर्मनी ने चाँदी का विमुद्रीकरण कर दिया। १८७४ में स्वीडन, नावॉ और डेनमार्क ने चाँदी के स्वतन्त्र टकन के लिए टकमालों को बन्द कर इसी मार्ग का अनुसरण किया। लंडिन यूनियन के देशों ने भी इनका साथ दिया और इसके फलस्वरूप बाजार में चाँदी की बहुतायत हो गई। नई खानों एवं परिष्कृत विधाओं के कारण चाँदी की उत्पत्ति खूब बढ़ी। भारत में मूल्यों की वृद्धि की सुनिश्चित प्रवृत्ति का कारण अत्यधिक टकन था। मूल्यों की वृद्धि सन् १८०० के बाद अधिक स्पष्ट हुई। चाँदी का मूल्य १८७५ में ५८ पैस प्रति औंस से घटकर १८७६ में ५२ $\frac{१}{२}$ पैस प्रति औंस, १८८८ में ४३ पैस प्रति औंस, १८९२ में ३ $\frac{१}{२}$ पैस प्रति औंस तथा १८९६ में २७ पैस प्रति औंस रह गया। चाँदी के अयोमूल्यन

के साथ सावरेन में रुपये का विनिमय-मूल्य अर्थात् स्वर्ण-मूल्य गिरने लगा और सन् १८७१ के २ शिलिंग से घटकर १८६२ में १ शिलिंग २ पैस के लगभग हो गया।

प्रधानतया स्वर्ण-प्रमाप को अपनाने के अभिप्राय से १८७४ से १८७८ तक रजत के स्वतन्त्र टकन के लिए टकसाल बन्द करने की दशा में सुधार की आवाज उठाई गई। १८७६ में बंगाल का व्यापार-मंडल और कलकत्ता व्यापार-संस्था ने गवर्नर जनरल को भारतीय टकसाली द्वारा चाँदी की अनिवार्य टकन क्रिया के अस्थायी अवरोध के लिए प्रार्थना-पत्र भेजा। सरकार ने इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। उनका विचार था कि सोने को प्रमाप रूप में अपनाए बिना कोई कदम उठाना सम्भव नहीं था तथा तत्कालीन अव्यवस्थित परिस्थितियों में वे स्वर्ण-प्रमाप अपनाने में असमर्थ थे। इस अनिश्चितता का प्रधान कारण चाँदी का अघोमूल्यन और सोने का अधिमूल्यन था। १८७८ में भारत सरकार ने भारत सचिव के समक्ष प्रस्ताव किया कि स्वर्ण चलार्थ (करेन्सी) के साथ स्वर्ण-प्रमाप स्थापित करने के लिए निश्चित बंदम उठाये जाएँ और इस बीच सोने के सिक्के और रुपये के बीच में निश्चित सम्बन्ध, जिसे आवश्यकता पड़ने पर समय-समय पर परिवर्तित भी किया जा सके, स्थापित करने के लिए टकसाली लाभ वसूल कर रुपये की कीमत बढ़ाई जाए। राज्य-सचिव ने यह प्रस्ताव एक समिति को सौंप दिया, जिसने विभिन्न आधारों पर इस प्रस्ताव का विरोध किया और सलाह दी कि आकस्मिक भय से प्रभावित होकर विधानों की शरण लेने की अपेक्षा शांति से बैठना अधिक श्रेयस्कृत है। इन विधानों के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता और न उनके प्रभाव ही मापे जा सकते हैं। स्वर्ण-प्रमाप के विकल्प के रूप में भारत सरकार बहुत समय तक अन्तर्राष्ट्रीय द्विधातु प्रथा अपनाए रही, जबकि सारी दुनिया इसका परित्याग करती जा रही थी। १८६० और १८६६ के बीच उत्तरी अमरीका और विभिन्न यूरोपीय देशों में मुद्रा-प्रचलन की कठिनाइयों के निवारणार्थ कम-से-कम चार अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए।

५. चतुर्थ काल (१८६३-१९००) — इस बीच चाँदी के मूल्य में लगातार कमी होने तथा संयुक्त राज्य द्वारा शर्मन कानून हटा देने से प्रतिवर्ष टकन के लिए सरकार को ५४० लाख और चाँदी खरीदनी पड़ती थी। इसके कारण चाँदी तथा फलस्वरूप भारतीय रुपये की स्थिति पहले से भी अधिक सदिग्ध हो गई। १८६२ में इन परिस्थितियों में भारत सरकार ने फिर राज्य-सचिव तक पहुँच की और अन्ततः स्वर्ण प्रमाप अपनाने के उद्देश्य से चाँदी की स्वतन्त्र दलाई बन्द करने का प्रस्ताव उस दशा के लिए रखा जबकि वुसेल्स में हो रहा द्रव्य-सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसी निर्णय पर न पहुँच सके। फलतः १८६२ में भारत सरकार के उपर्युक्त प्रस्ताव के साथ चलार्थ और विनिमय की अवस्था पर विचार करने के लिए हर्शल समिति की नियुक्ति हुई। जब हर्शल समिति बैठी हुई थी उसी समय वुसेल्स सम्मेलन छिन्न-भिन्न हो गया। उस समय भारतीय चलार्थ व्यवस्था की प्रधान कठिनाइयों के लिए हर्शल समिति को निम्न उपाय प्रस्तुत करने पड़े—(१) रजत की एकघात्विय प्रथा और स्वर्ण-प्रमाप की देशों में गिरती हुई विनिमय-दर के कारण भारत सरकार की

वित्तीय कठिनाइयाँ, (२) भारत की जनता और वाणिज्य पर विनिमय-दर के कम होने के कुप्रभाव और (३) विनिमय-दर के गिरावट के कारण भारत में यूरोपीय अफसरो की कठिनाइयाँ ।

६ भारत सरकार की वित्तीय कठिनाइयाँ—भारत सरकार की सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि इसको इंग्लैण्ड के प्रति अपनी स्वर्ण देनदारियों, उदाहरणार्थ ग्रह-ध्यय (होम चार्ज), के लिए प्रतिवर्ष काफी रुपया देना पड़ता था । इसके वास्तविक प्रभाव रुपये के स्वर्ण-मूल्य से निश्चित होते थे । यह मूल्य १८७४ तक लगातार कम होता गया और उसके बाद भी गिरने की आशंका बनी रही । १८८८ से १८९३ तक गर्वनर जनरल की परिपद के वित्तीय सदस्य सर डेविड वॉबेन ने भारत की इस कठिनाई का इस प्रकार वर्णन किया है—“हमारी वित्तीय कठिनाइयों का तारकालिक कारण सोने की तुलना में चाँदी का अधिमूल्यन था, जिसके फलस्वरूप गत दो वर्षों में भारतीय व्यय ४ करोड़ रुपये और बढ़ गया । यदि यह अधिमूल्यन रोका जा सके और इंग्लैण्ड के साथ विनिमय-दर स्थायी रूप से वर्तमान आँकड़ों पर भी निश्चित की जा सके, तो वर्तमान घाटे की समस्या का हल अपेक्षाकृत सरल हो जाए । आगामी वर्ष में हमारी वित्तीय स्थिति विनिमय तथा उन लोगों की स्थिति पर निर्भर है जो किसी भी भाँति चाँदी के मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं । यदि हम १५,६५,१०० रुपये के घाटे का बजट तैयार करें और विनिमय-दर एक पैस ही बढ़ जाए तो हमें काफी बचत हाँगी और यदि एक पैस और कम हो जाए तो ३ करोड़ से अधिक का घाटा होगा । यदि हम १½ करोड़ रुपये का कर लगाएँ तो समय-चक्र इतने ही रुपये का कर बार-बार लगाने को बाध्य करेगा और हमें बाद में ज्ञात होगा कि कर की कोई आवश्यकता नहीं थी ।”

७ विनिमय-दर की गिरावट का भारतीय जनता पर प्रभाव—पोण्ड देनदारियों को चुकता करने के लिए सरकार को अधिक रुपये की आवश्यकता थी, जिसके कारण रुपये में और अधिक कर लगाया गया । विनिमय की गिरावट के कारण स्थायी बन्दोबस्त के अन्तर्गत निश्चित सालगुजारी देने वालों का भार कुछ कम हो गया और इसी प्रकार उन लोगों का भी भार कम हो गया जिनकी सालगुजारी का बन्दोबस्त अभी हाल में नहीं हुआ था । इसके अतिरिक्त बड़े हुए नमक-कर से लोगों को बहुत कठिनाई हुई और उन लोगों पर कर और अधिक भारी हो गया जो लोग रुपये का स्वर्ण मूल्य कम हो जाने के कारण ऊँचे मूल्यों से अस्त हो चुके थे ।

धारात और निर्यात की क्रमशः स्थायी हानि और लाभ को छोड़ देने पर भी राज्य की निर्बाधता के विरुद्ध प्रमुख तर्क यह था कि भारतवर्ष के धारात का ७४% सोना प्रयोग करने वाले देशों से और २६% चाँदी प्रयोग करने वाले देशों से आती थी^१ । इस प्रकार स्वर्ण-प्रमाप वाले देशों से घनिष्ठ वित्तीय और वाणिज्य सम्बन्ध

१. इराल कमेटी रिपोर्ट, पैरा ३-६ ।

२. पूकार्पत रिपोर्ट, पैरा ३८-३४ ।

३. इसके लिए ई० डब्ल्यू० की 'गार्डन क्रेन्सी रिफार्म', पृ० २७-२८ देखिए ।

स्थापित हो चुके थे और रुपये के मूल्य में लगातार कमी होने से भारत के विदेशी व्यापार की कठिनाइयों की वृद्धि तथा परिकल्पना का उत्पन्न होना अवश्यम्भावी था। इसके अतिरिक्त रुपये के मूल्य की कमी से नियोक्ताओं को स्थायी लाभ मिला, परन्तु यह कारण मजदूरों के मत्थे जाता था क्योंकि मूल्यों की तुलना में मजदूरी की वृद्धि शिथिलतर होती है। भारत के हित को ध्यान में रखते हुए हम यह नहीं कह सकते कि विनिमय का अनवरत गिराव लाभप्रद था।

८. विनिमय और विदेशी पूँजी में गिराव—विनिमय का गम्भीर गिराव भारत में विदेशी पूँजी के विनियोग तथा अधिकांशतः उस पर निर्भर देश के विकास को रोकने लगा, क्योंकि उधार देने वाला बाजार रुग्ण था और वह स्वर्ण में ही सोचता था। विनियोग पर व्याज-सम्बन्धी अनिश्चितता तथा विनियोजित पूँजी को पुनः इंग्लैण्ड स्थानान्तरित करने में उसके मूल्य में कमी की सम्भावना ने भारत में ब्रिटिश पूँजी के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया। विनिमय के गिराव के कारण यूरोप-निवासियों की सेवाएँ प्राप्त करने के लिए विदेशी फर्मों को कठिनाई का सामना करना पड़ता था। देश में विदेशी पूँजी आकर्षित करते की कठिनाइयों का प्रतिबल प्रभाव भारत की स्थानीय सस्याओं के वित्त पर भी पड़ा।

९. यूरोपीय अधिकारियों की दशा—भारत सरकार को अपने अधिकारियों के सम्बन्ध में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विनिमय में गिराव के कारण अधिकारी वर्ग क्षतिपूर्ति माँगने लगा। उन्हें वेतन रुपये में मिलता था तथा इंग्लैण्ड में अपने परिवार की सहायता और बच्चों की शिक्षा के लिए उन्हें अपनी आय का पहले से अधिक भाग स्टैलिंग के रूप में भेजना पड़ता था। इससे अधिकारियों में गहरा असन्तोष फैल गया।

१०. हर्षाल समिति की सिफारिशें—तत्कालीन द्रव्य-व्यवस्था के शीघ्र सुधार के सम्बन्ध में हृदयत हो जाने पर हर्षाल समिति ने अपने सुझाव दिये। द्विधातु प्रणाली का अब कोई प्रश्न ही नहीं था। चाँदी के विमुद्रीकरण और स्वर्ण-प्रमाप करेन्सी के स्थान पर एक प्रकार की पगु प्रमाप की सिफारिश की गई, जिसके अन्तर्गत सोने या चाँदी के स्वतन्त्र टुकड़ों की मनाही कर दी गई।

भारत सरकार ने इसका अनुमोदन किया और १८७० के कानून और भारतीय कागजी चलार्थ अधिनियम (इण्डियन पेपर करेन्सी एक्ट) १८८२ के सुधार के लिए १८६३ में एक कानून पास किया गया। चाँदी की स्वतन्त्र ढलाई के लिए टकसालों को सुरक्षित बन्द कर देने की व्यवस्था थी, यद्यपि भारत सरकार को अपने आप (अपने लिए) मुद्रा बनाने की इजाजत थी। उसी समय शासन सम्बन्धी तीन अधिसूचनाएँ जारी की गईं। पहली अधिसूचना ने १६ पैसे = १ रु० की दर से स्वर्ण-मुद्रा और स्वर्ण-पिण्ड के बदले रुपया देने की व्यवस्था की। दूसरी अधिसूचना ने उसी भाव पर सार्वजनिक देनदारी के लिए सावरेन और अर्द्ध सावरेन को स्वीकार करने को विहित ठहराया। तीसरी अधिसूचना ने उसी भाव पर स्वर्ण-मुद्रा और स्वर्ण-पिण्ड के बदले कागजी चलार्थ कार्यालय (पेपर करेन्सी ऑफिस) से कागज के नोट जारी करने की व्यवस्था की।

के सोने पर आधारित कर देगी। साथ ही अनिश्चित सीमा तक प्राप्त रूपयो के बदले लन्दन में सोने में अदा करने की देनदारी भी भारत की होगी।

फाउलर समिति के अनुसार सोने के स्वतन्त्र आवाह-प्रवाह पर आधारित स्वर्ण-प्रमाण और चलार्थ (करेन्सी) की स्थापना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इस उद्देश्य से उन्होंने अधोलिखित प्रस्ताव रखा—(१) सावरेन और अर्द्ध-सावरेन के टकन के लिए भारत में टकसालें खोल दी जाएँ। १८६३ के निर्णय के अनुसार चाँदी के स्वतन्त्र टकन के लिए टकसाले उस समय तक के लिए बन्द कर दी जाएँ जब तक चलार्थ में सोने का अनुपात जनता की आवश्यकता से अधिक न हो जाए। (२) अन्ततोगत्वा विनिमय-दर १ शि० ४ पै० प्रति रुपया स्थिर कर दी जाए, क्योंकि यह पहले भी निश्चित की जा चुकी थी और इस दर से मूल्यो का सामञ्जस्य हो जाने के कारण किसी अन्य अनुपात की तुलना में इसका निर्वाह सरल था। (३) रुपया असीमित वैधानिक ग्राह्य बना रहे। (४) सरकार सोने के बदले में रुपया देना जारी रखे और अपने-आपको रूपये के बदले में सोना देने को बाध्य न करे, क्योंकि सोना देने के लिए वाध्य होना असुविधाजनक होगा तथा सरकार से सोने की आवश्यक माँग भी की जा सकेगी, जिसकी पूर्ति के लिए भारी लागत पर स्टैलिग ऋण लेना आवश्यक हो जाएगा। (५) रूपये को सावरेन में बदलने के लिए भविष्य में चाँदी के टकन का लाभ विशेष सुरक्षित कोष के रूप में एक स्वर्ण-कोष में जमा करना चाहिए जो पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष तथा सरकारी कोष से अलग हो। यद्यपि सरकार कानूनी तौर पर रूपये को सोने में बदलने के लिए बाध्य नहीं है, फिर भी लोगों के इच्छुक-होने तथा कोष से अदायगी सम्भव होने पर सोना देना लाभप्रद होगा। (६) जिस समय व्यापारिक सतुलन विपरीत हो, उस समय सरकार को सोना मुलभ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। समिति ने आशा की कि सोना सामान्यतः स्वर्ण सुरक्षित-कोष और विशेषतया उनके द्वारा प्रस्तावित स्वर्ण-कोष से मिलेगा, यद्यपि अन्ततोगत्वा स्वर्ण-प्रमाण और स्वर्ण चलार्थ (करेन्सी) के पूर्णतया प्रारम्भ हो जाने के फलस्वरूप प्रचलन से भी सोना प्राप्त हो सकेगा।

संक्षेप में, फाउलर समिति का मत था कि निश्चित विनिमय-दर प्रभावपूर्ण स्वर्ण प्रमाण से ही प्राप्त की जा सकती है। समिति ने लैटिन यूनियन और सयुक्त-राज्य द्वारा अपनाये गए पगु प्रमाण को नमूने के तौर पर स्वीकार किया। इस प्रमाण में सोना और चाँदी एक निश्चित वैधानिक अनुपात के साथ असीमित वैधानिक ग्राह्य मुद्रा माने गए, परन्तु टकसालों को केवल सोने की स्वतन्त्र टकन करने की आज्ञा दी गई।

१२. द्रव्य-सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपनाये गए उपाय—(१) स्वर्ण का प्रचलन—फाउलर समिति की सिफारिशों को पूरा करने के लिए उपर्युक्त बदल उठाये जाने के बाद सरकारी नीति अपने ध्येय से विचलित होकर निरुद्देश्य इधर-उधर भ्रुकने लगी और अन्ततोगत्वा कठिनाइयों को दूर करते-करते स्वर्ण विनिमय प्रमाण पर आ गई। टकसालों के बन्द करने से बड़ी तंगी आ गई जो व्यापार के

विस्तार और जनसख्या में वृद्धि के कारण अत्यधिक अनुभव की जाने लगी। इस परिस्थिति के दामन के लिए १८६८ का एक अस्थायी उपाय के रूप में पास हुआ। इस कानून के अन्तर्गत भारत सचिव द्वारा कौंसिल बिलों की बिक्री से प्राप्त राशि भारतीय पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष के अंश के रूप में बैंक ऑफ इंग्लैण्ड में सोने में रखी जा सकती थी। इस प्रकार सुरक्षित सोने के आधार पर भारत सरकार नोट जारी कर सकती थी और कोष की धनराशि को कम किये बिना भारत-सचिव के ड्रापटो को इंग नोटों से खरीद सकती थी।^१ इसका प्रभाव यह हुआ कि भारत सरकार के रूपों के भण्डार की कमी बटती गई।

(२) नोट और रुपये जारी करना—१६०० में भारत सरकार ने साधारण होकर बड़े पैमाने पर टकन क्रिया को फिर आरम्भ किया। इसके लिए अपेक्षित चाँदी लन्दन के पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष के सोने से खरीदी गई। १८६८ का सकट पूर्णतया अस्थायी था। उसके अनुसार कौंसिल बिलों की बिक्री से प्राप्त तथा पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष में जमा किया गया सोना भारत-सचिव के पास इंग्लैण्ड में रहेगा, जब तक कि वे स्वयं इसे भारत न भेज दें अथवा भारत सरकार कौंसिल बिलों की बिक्री से प्राप्त सोने के आधार पर जारी किये गए नोटों के बराबर सिक्के करेन्सी रिजर्व के भाग के रूप में अलग रखकर सोना न माँग ले। सर्वप्रथम यह कानून टाई वर्ष के लिए बटाया गया और १६०० में पुन दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इस प्रकार प्राप्त हुए सोने से भारत में सिक्का बनाने के लिए चाँदी खरीदने और उसे पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष के अंश के रूप में स्वीकार करने का अधिकार भारत-सचिव को था। इस प्रकार इंग्लैण्ड में स्वर्ण सुरक्षित कोष के तीन स्पष्ट उद्देश्य थे—(क) इससे आवश्यकता पड़ने पर टकन के लिए चाँदी खरीदने हेतु लन्दन में धन मिल सकता था। (ख) व्यापारिक सन्तुलन प्रतिबल होने तथा कौंसिल बिलों का विक्रय असम्भव अथवा अलाभप्रद होने पर भारत को विदेशी विनिमय में सहायता मिल सकती थी। ऐसी परिस्थितियों में भारत सचिव अपने व्यय को पूरा करने के लिए पत्र मुद्रा सुरक्षित कोष से सोना ले लेगा और ममान राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी।^१ (ग) अन्तिम, यह एक ऐसा कोष था जिसमें विनिमय-दर को अनावश्यक रूप से ऊँचा होने से रोकने तथा भारत के लिए अवाञ्छनीय प्रवाह बन्द करने के लिए भारत-सचिव अपनी आवश्यकता से अधिक कौंसिल बिल बेचकर राशि जमा कर सकता था। इस जमा की हुई राशि के आधार पर भारत में नोट जारी किए जाते थे।

१. जैसा कैमरर ने कहा है, यह उपाय व्यवहारतः सरकार द्वारा लिट्टे योजना को अपनाते के दस्तावेज था (जिसे एक साल बाद फाल्जर समिति की सिफारिशों पर अस्वीकार कर दिया गया)। इनका अर्थ लन्दन में भारत-रिजर्व पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष के आधार पर विक्रय करना था (उन दरों पर जो व्यवहारतः लन्दन का स्वर्ण निर्यात-विन्दु प्रदर्शित करती थी तथा जिनका प्रमुख उद्देश्य भारत में द्रव्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करेन्सी प्राप्त करना था)—कैमरर, पूर्व उद्धृत, पृ० १०२।

२. देविए, सेन्सन २४।

१९०२ में ये सारे नियम स्थायी बना दिये गए। १९०५ में भारत के सुरक्षित कोष में ५० लाख पौण्ड जमा हो गया और यह रकम लन्दन-स्थित इंग्लैण्ड बैंक को पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष में रखने के लिए भेज दी गई। यह साधारण कार्यों के लिए नहीं खर्च किया जाता था। इसका एक भाग इंग्लैण्ड की स्टॉक प्रतिभूतियों में जमा किया जाता था। १९०६ के बाद पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष का अधिकांश भाग सोने के रूप में रखा जाने लगा।

१३. स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोष—१९०० में भारत सरकार ने एक सुरक्षित स्वर्णकोष को भारत में रखना प्रस्तावित किया, जिसे फाउलर समिति भी चाहती थी। उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष धीरे-धीरे अपनी पूर्ण स्थिति पर पहुँच जाए और इसका प्रयोग केवल करेन्सी नोटों के भुगतान के लिए ही किया जाए। इसका निर्माण मुख्यतः रुपये और प्रतिभूतियों से ही हो। इसके विपरीत सुरक्षित स्वर्ण-कोष में प्रधानतः सोना ही रखा जाए।

भारत सचिव की योजना के अनुसार रुपये के टकन का लाभ लदन भेज दिया जाता था और होता यह था कि भारत में टकित रुपये के बदले लन्दन-स्थित पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष में से सोना ले लिया जाता था। १९०६ में रुपये की माँग की कठिनाई दूर करने के लिए पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष से अलग एक विशेष रूपया सुरक्षित कोष बनाया गया, जिसे स्वर्ण-प्रमाप सुरक्षित कोष की रजत शाखा का नाम दिया गया।^१ रूपया सुरक्षित कोष का उद्देश्य रुपये की विनिमय-दर को १ शि० ४ पैं० से आगे न बढ़ने देना था। अतएव इसी दर पर सावरेन के बदले में रुपये की दर निश्चित हो गई। १८९३ की अधिसूचना, जिसने ब्रिटिश स्वर्ण-मुद्रा से भिन्न स्वर्ण के बदले रुपये और नोटों के प्रचलन का अधिकार दिया था, वापस ले ली गई। इसी बीच, विभिन्न कोषों में एकत्रित सोने को लन्दन भेजने का कार्य आवश्यक रूप से ध्वंसील माना गया। इसलिए १९०४ में कौंसिल ड्राफ्ट बेचने की प्रथा अपने प्रारम्भिक उद्देश्य से आगे बढ़ गई। भारत-सचिव ने १ शि० ४ $\frac{1}{2}$ पैं० की दर पर असोमित मात्रा में कौंसिल बिल बेचने की इच्छा घोषित की। यदि इसके लिए भारत के तकद कोष अपर्याप्त हो, तो इसकी पूर्ति भारत के पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष से रूपया निकालकर की जा सकती थी और इसके बराबर सोना लदन में पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष में जमा कर दिया जाता था। भारत सरकार के पास सावरेन एकत्रित हो जाने तथा उन्हें १ शि० ४ $\frac{1}{2}$ पैं० पर भारत में निर्यात करना सदैव भौंगा न होने के कारण मिला और आस्ट्रेलिया से भारत भेजे जाने वाले सावरेन के आधार पर तार द्वारा स्थानान्तरण (टेलिग्राफिक ट्रांसफर) करना निश्चित किया गया। स्थानान्तरण की दर १ शि० ४ पैं० और १ शि० ४ $\frac{1}{2}$ पैं० के बीच थी (जो कौंसिल बिल की दर से भी कम थी)^२ ताकि ऐसे सावरेन के स्वामियों को उन्हें भारत से लन्दन भेजना लाभप्रद हो सके।

१. इस तिथि से स्वर्ण सुरक्षित कोष का नाम स्वर्ण-प्रमाप सुरक्षित कोष हो गया।

२. इस प्रथा की कार्य-विधि के वर्णन के लिए देखिए, जे० एम० केन्स की पुस्तक 'इण्डियन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स', पृ० ११४-१८।

जून १९०७ में भारतीय रेलवे वित्त सम्बन्धी मंके समिति ने सिफारिश की कि १९०७ में रुपये के टकन में हुए लाभ में से १० लाख सावरेन रेलों पर खर्च किया जाए। भारत-सचिव ने इस समिति की सिफारिश के आगे यह निर्णय किया कि जब तक स्वर्ण प्रमाण सुरक्षित कोष २०० लाख पौण्ड तक न पहुँच जाए, रुपये के टकन से हुए लाभ का आधा रेलों पर खर्च किया जाएगा।

१४. १९०७ और १९०८ का सकट—भारत के कुछ भागों में फसलों के आंशिक रूप से खराब होने तथा अन्य भागों में यथार्थतः अकाल पड़ जाने के कारण भारतीय निर्यात कम हो गए। यूरोप में भी उन्नति-काल के बाद, जो १९०७ में अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया, अवनति का प्रारम्भ हुआ, जिसके परिणामस्वरूप व्यापारिक मन्दी और बेकारी फैलने लगी। इस प्रकार यूरोप की क्रय-शक्ति नष्ट हो गई और सामान्य द्राव्यिक कठिनाई के कारण परिस्थिति और खराब हो गई। यह कठिनाई न्यूयार्क में वित्तीय सकट से उत्पन्न हुई थी, जबकि जूट, रूई और गेहूँ इत्यादि के भारतीय निर्यात कम हो गए। चांदी का आयात, विशेषकर उसकी कीमत में काफी कमी आ जाने से बंद गया। इन सभी कारणों के फलस्वरूप भारत की विदेशी विनिमय-स्थिति और खराब हो गई। सावरेन भण्डार शीघ्रता से घटने लगा और विनिमय बैंको ने इंग्लैण्ड के तार द्वारा स्थानान्तरण (टेलिग्राफिक ट्रांसफर) के विक्रय पर जोर दिया। सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया और पत्र मुद्रा सुरक्षित कोष से कुछ शर्तों पर सोना देना स्वीकार किया। एक व्यक्ति को एक दिन में १०,००० पौण्ड से अधिक सोना नहीं दिया जा सकता था। स्थिति और खराब हो जाने पर भारत-सचिव ने भारत सरकार को टेलिग्राफिक ट्रांसफर या रिजर्व कौंसिल को १ शि० ३३ $\frac{1}{2}$ पैसे प्रति रुपये की दर से वेचने की राय दी और भारत के कोषों (ट्रजरी) से लन्दन में पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष को रुपये स्थानान्तरित करने के बदले उसी कोष में से सोना दिया। उन्होंने रिजर्व कौंसिल की भुगतान की माँग को स्वर्ण-प्रमाण सुरक्षित कोष की स्टिलिंग प्रतिभूतियों को बाजार में वेचकर पूरा किया, यद्यपि इन प्रतिभूतियों का अघोमूल्यन हो चुका था। इन साधनों से सुधार हुआ और दूसरे वर्ष विनिमय-दर १ शि० ४ पैसे पर स्थिर हो गई जिसका प्रधान कारण समुत्थान था।

१५ स्वर्ण प्रमाण द्रव्यवा स्वर्ण विनिमय प्रमाण—सकट का सामना करने के लिए सरकार ने जाने अनजाने में स्वर्ण-विनिमय प्रमाण की दिशा में कदम उठाए। सर्व-प्रथम आन्तरिक प्रयोग के लिए रुपये के बदले सोना स्वतन्त्र रूप से दिया गया, परन्तु व्यक्तिगत रूप से सोना बाहर भेजने के सम्बन्ध में बहुत अनिच्छा प्रगट की गई। इससे प्रकट था कि सरकार ने अभी तक अच्छी प्रचार न विचार ही किया था और न निश्चित रूप से स्वर्ण विनिमय प्रमाण को अपनाया ही था। लेकिन बाद में रिजर्व कौंसिल की विक्री ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसने भारतीय करेन्सी को लिण्डसे योजना के समीप ला दिया। लन्दन के पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष के स्वर्ण निक्षेपों के बदले

रुपया और नोटो से भुगतान करने की क्रिया पहले से ही प्रचलित थी और १९०४ में भारत-सचिव ने निश्चित दर पर असीमित राशि के लिए अनिश्चित काल के लिए कौंसिल बिलो के बेचने की इच्छा प्रकट की। १९०७-८ में अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए रुपयो को स्टैलिंग में बदलने की क्रिया अर्थात् रिज़र्व कौंसिल की बिक्री ने स्वर्ण विनिमय प्रमाण की नींव डाली।

सकट का सामना करने हेतु उठाये गए कदमों के परिणामस्वरूप सरकार के सोने के साधन खाली हो गए। लन्दन में करेन्सी कोष में सावरेन ७० लाख पौण्ड से घटकर १५ लाख पौण्ड रह गई, जबकि भारत में सोने का सम्पूर्ण भण्डार समाप्त हो गया था।^१ इस प्रकार सरकार सुरक्षित स्वर्ण कोष को बढ़ाने की आवश्यकता से प्रभावित हुई ताकि भविष्य में ऐसे सकटों का स्थिर चित्त होकर सामना किया जा सके। १९०९ में उन्होंने भारत-सचिव के सामने प्रस्ताव रखा कि सुरक्षा के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि २५० लाख पौण्ड होनी चाहिए और जब तक इतनी रकम पूरी न हो जाए तब तक उसका कोई भाग रेलों पर खर्च न किया जाए। उन्होंने स्वर्ण प्रमाण सुरक्षा कोष को तरल रूप में रखने की भी सिफारिश की।

भारत-सचिव ने उत्तर दिया कि उनके अनुसार स्वर्ण प्रमाण सुरक्षित कोष और पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष दोनों को मिलाकर २५० लाख पौण्ड उचित राशि होगी और जब तक दोनों की संयुक्त राशि इतनी नहीं हो जाती, तब तक स्वर्ण प्रमाण सुरक्षित कोष से कोई भी रकम नहीं ली जाएगी। संयुक्त राशि के २५० लाख पौण्ड हो जाने पर इस पर विचार किया जा सकता है।

१९१२ में भारत सरकार की इच्छा के प्रति आदर भावना तथा सार्वजनिक आलोचना के कारण भारत सचिव ने यह निर्णय किया कि स्वर्ण प्रमाण सुरक्षित कोष का प्रमाण २५० लाख पौण्ड हो और ५० लाख पौण्ड का सोना बैंक ऑफ इंग्लैण्ड में प्रक्षेप के रूप में रखा जाए।^२

उपर्युक्त कदम उठाने में सरकार अनजाने में फाउलर समिति द्वारा प्रस्तावित स्वर्ण प्रमाण के सीधे और सकुचित मार्ग से भ्रमण हो गई और अनेक सवसरवादी उपायों के क्रम के फलस्वरूप लिण्डसे द्वारा प्रस्तावित योजना पर पहुँच गई। इस पद्धति के बारे में १८९३ में सोचा भी नहीं गया था और १८९८ में फाउलर समिति और सरकार दोनों ने ही इसका विरोध किया था। कोई ऐसी निश्चित तिथि बताना भी सम्भव नहीं है जिस दिन से यह विचारपूर्वक अपनाई गई हो।

स्वर्णोप सर विट्टलदास धेकरसे की प्रेरणा से सोने की टकसाल और टकन के प्रस्ताव पुनः रखे गए। इन्होंने १९१२ में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल में इस आशय का एक प्रस्ताव रखा। इस सम्बन्ध में एक वर्ष तक बातचीत चलती रही। उस समय यह निश्चित हुआ कि यह प्रश्न अन्य प्रश्नों के साथ करेन्सी आयोग के समक्ष

१. देखिए, पृष्ठ ० ५५० हॉबर्ड, 'इस्टिया परड द गोल्ड स्टैण्डर्ड', पृष्ठ ३५।

२. देखिए. शिरोज, पूर्व उद्धृत, पृष्ठ २१५।

रखा जाए जिसके बारे में विचार किया जा रहा था।

१६. स्वर्ण विनिमय प्रमाण का स्वरूप—स्वर्गीय लार्ड वेन्स ने, जो इस पद्धति के योग्यतम व्याख्याकर्ताओं में से थे तथा जिसका विकास ऊपर किया जा चुका है और जो १८६८-६९ से १९१५-१६ तक मली-भाँति कार्यशील रही, संक्षेप में निम्न विशेषताएँ बताई हैं—(१) रुपया असंमित वैधानिक ग्राह्य मुद्रा है, विधानतः अपरिवर्तनीय है, (२) सावरेन भी १ पौण्ड=१५ रुपये की दर से असंमित वैधानिक ग्राह्य मुद्रा है और जब तक १८६३ की अधिसूचना वापस नहीं ली जाती तब तक वह इसी पर परिवर्तनीय है अर्थात् सरकार को १ पौण्ड के बदले १५ रुपये देने पड़ेंगे, (३) शासन की दृष्टि से सरकार इस दर पर रुपये के बदले सावरेन देगी, परन्तु यह कार्य कभी-कभी रोका भी जा सकता है और रुपये के बदले यथेष्ट मात्रा में सोना सदैव प्राप्त नहीं किया जा सकता, और (४) शासन प्रबन्ध के विचार से सरकार लन्दन में रुपये के बदले में चुकता होने वाले बिलों को १ सि० ३^३/_४ पौ० प्रति रुपया की दर से कलकत्ता में बेचेगी।

इन प्रस्तावों में चौथा प्रस्ताव रुपये के स्टलिंग मूल्य को सहायता देने के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि इसे ठीक रखने के लिए सरकार ने कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है, फिर भी इस सम्बन्ध में असफलता उनकी पद्धति को एकदम छिन्न-भिन्न कर देगी।

इस प्रकार द्वितीय प्रस्ताव रुपये के १ सि० ४ पौ० के स्टलिंग मूल्य को भारत में सावरेन भेजने के खर्च से अधिक नहीं बढ़ने देगा और चौथा प्रस्ताव उसे १ सि० ३^३/_४ पौ० से नीचे गिरने से रोकेगा।

स्वर्ण विनिमय प्रमाण के सम्बन्ध में कहा जाता है कि स्वर्ण प्रमाण और स्वर्ण करेन्सी से कहीं अधिक सस्ता होने के साथ ही यह स्वर्ण करेन्सी के सभी लाभों से पूर्ण है। यह स्पष्ट है कि भारत में इसका प्रधान उद्देश्य रुपये और सोने का सतुलन बनाये रखना था। जिस समय विनिमय निर्बल होता उस समय तो सरकार स्टलिंग (रिजर्व कौंसिल) बेचने लगती और जब रुपये का मूल्य बढ़ता, तो वह स्थानीय (करेन्सी कौंसिल बिल) बेचने लगती। सरकार के ऐसे हस्तक्षेप का प्रभाव सोने और रुपयों के सुरक्षित कोष के पर्याप्त होने पर निर्भर था।

१७. कौंसिल ड्राफ्ट प्रथा—१९१४ तक रिजर्व कौंसिल और कौंसिल बिल स्वर्ण विनिमय प्रमाण के महत्त्वपूर्ण अंग बन चुके थे, परन्तु सरकार रिजर्व कौंसिल बेचने के लिए कभी भी विधानतः बाध्य नहीं थी। इसके अतिरिक्त उन्हें बेचने के अवसर भी बहुत काम आए, परन्तु जैसा कि हम देख चुके हैं, कौंसिल ड्राफ्ट पद्धति कौंसिल बिल और टेलिग्राफिक ट्रान्सफर भारतीय करेन्सी विनिमय और वित्त के प्रबन्ध का आधार रही है।

भारत में हुडियाँ (बिल्स ऑफ एक्सचेंज) बेचकर धन एकत्र करने की प्रथा ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय से प्रचलित थी। १८६३ तक नियम के रूप में कौंसिल

१. यह विवरण 'चेम्बरलैन कमीशन रिपोर्ट' से सञ्चित रूप में लिया गया है, पृष्ठा १७०-७६।

ड्राफ्ट की बिक्री गृह-व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत-सचिव द्वारा ही की जाती थी। यह प्रथा भारत-सचिव को अनुकूलतम दरो पर अधिक धन प्राप्त करने में सहायक होती थी। व्यापार के लिए भी यह सुविधाजनक थी, क्योंकि भारत के आयात में निर्यात की अधिकता होने के कारण भारत के प्रति अन्य देशों की देन-दारी तय करने का यह सरल साधन था। सच तो यह है कि सामान्य परिस्थितियों में निर्यात की अधिकता से हुई वचत के कारण ही कौंसिल ड्राफ्ट प्रथा सम्भव और लाभ-प्रद हो सकी।

१८६३ के बाद कुछ वर्षों तक इस प्रथा का नकारात्मक प्रयोग किया गया, अर्थात् कौंसिल ड्राफ्ट की बिक्री बन्द करके रुपये के विनिमय मूल्य को बढ़ाने की चेष्टा की गई। इसका प्रभाव यह हुआ कि रुपया स्वतन्त्रता से मिलना बन्द हो गया और स्टैलिंग में उसका मूल्य बढ़ने लगा।

यह हम देख चुके हैं कि किस प्रकार १८६८ में जब रुपया १ शि० ४ पं० के बराबर हो गया था, १८६८ के एकट ने भारतीय पत्र मुद्रा सुरक्षित कोष के अक्ष के रूप में बैंक ऑफ इंग्लैण्ड में जमा सोने के आधार पर कौंसिल ड्राफ्ट बेचने का अधिकार दिया तथा किस प्रकार कौंसिल ड्राफ्ट के लिए समान मूल्य के नोट और रुपये भारत में जारी किये जाते थे। इसका उद्देश्य केवल गृह-व्यय को पूरा करने के लिए धन एकत्रित करना नहीं था, बल्कि द्रव्य-सम्बन्धी कठिनाइयाँ होने पर जब भारत सरकार के पास कौंसिल ड्राफ्ट के लिए सरकारी खजानों में अतिरिक्त धन नहीं होता, तो व्यक्तिगत रूप से भारत को सावरेन भेजने के विकल्प के रूप में करेन्सी का विस्तार करना भी इसका उद्देश्य था।

१९०६-१० में लन्दन में मोना प्राप्त करने के लिए कौंसिल ड्राफ्टों का विक्रय स्वतन्त्रतापूर्वक किया गया। इसका विक्रय रुपये की उस बड़ी मात्रा के स्थान पर किया गया था जो सकट-काल में लन्दन में रिबर्स कौंसिल की बिक्री से भारत के स्वर्ण प्रमाण सुरक्षित कोष में जमा हो गई थी। इसका फल यह हुआ कि स्वर्ण प्रमाण सुरक्षित कोष पुनः लन्दन चला गया।

रुपयों के टकन का लाभ, जो स्पष्टतः रुपये के रूप में होता था, लन्दन में स्टैलिंग में परिवर्तित कर दिया गया। लाभ प्रदर्शित करने वाले रुपये लन्दन में बेचे गए कौंसिल ड्राफ्टों के बदले भारत में जारी कर दिए जाते थे। इस प्रकार कौंसिल ड्राफ्ट की प्रथा भारत-सचिव को धन एकत्रित करने का साधन प्रदान करने के अतिरिक्त वही अधिक विस्तृत थी। उसका उद्देश्य व्यापार में सुविधा प्रदान करना तथा सरकारी साधनों को इस प्रकार व्यवस्थित करना था, ताकि करेन्सी, विनिमय और वित्तीय मामलों में सरकारी नीति पूर्णतया प्रभावशाली रहे।

१८ चेम्बरलेन आयोग—स्वर्गीय सर आस्टिन चेम्बरलेन की अध्यक्षता में अप्रैल, १९१३ में सरकार के मुद्रा चलन और विनिमय नीति की आग्रहपूर्ण और गहरी आलोचना के कारण एक आयोग की नियुक्ति हुई, जिसने फरवरी १९१४ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके निष्कर्ष और सिफारिशें नीचे दी जा रही हैं—

(१) रुपये के विनिमय मूल्य को स्थायी आधार पर स्थापित करना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात थी। (२) रुपये के विनिमय मूल्य को स्थिर रखने के लिए अपनाये हुए उपाय १८६८ की समिति की सिफारिशों के अन्तर्गत अनुसूचित नहीं थे जितने कि उसके पूर्व थे। (३) १९०७-८ के सकट-काल में इनकी खूब परीक्षा हुई और उस समय इन्हें सन्तोषजनक पाया गया। ऐसे सकट-काल का सामना करने के लिए पहले से ही तैयार योजनाओं तथा अनुभव के अभाव में सरकार ने प्रारम्भ में कुछ गलतियाँ अवश्य कीं। उदाहरण के लिए भारत कार्यालय (इण्डिया ऑफिस) का विश्वास था कि कौंसिल बिल न दिखने पर सन्तान में भारत-सचिव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही स्वर्ण प्रमाण सुरक्षित कोप का एकमात्र अथवा प्रमुख उद्देश्य था, जबकि भारत सरकार ने पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप में निर्धारित के लिए सोना न देने की गलती की, यद्यपि आन्तरिक सोने के खर्च पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। दोनों ही अधिकारी इस बात को नहीं समझ सके कि सुरक्षित स्वर्ण कोप का प्रमुख उपयोग विनिमय के स्वर्ण बिन्दु से नीचे हो जाने पर विदेश भेजने के लिए सोने को स्वतन्त्र रूप में प्राप्य बनाना है। व्यवहार में गलतियाँ बड़ी जल्दी सुधार ली गईं। विनिमय-दर को पूर्व स्थिति पर लाने और बनाए रखने के लिए उठाये गए कदम अपर्याप्त सिद्ध हुए। (४) सन् १५ वर्षों का इतिहास साक्षी है कि स्वर्ण मुद्रा का सक्रिय चलन स्वर्ण प्रमाण की अनिवार्य दशा नहीं है, क्योंकि इस दशा के बिना भी स्वर्ण प्रमाण हटानापूर्वक स्थापित हो चुका था। (५) आन्तरिक प्रचलन के लिए सोने के अधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करना भारत के लिए हितकर नहीं था। (६) भा.न की जनता करेन्सी के रूप में प्रचलन के लिए न तो सोना चाहती थी और न वह अपेक्षित ही था। भारत की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्ततम करेन्सी रुपये क्रोनोटों की थी। (७) करेन्सी या विनिमय हेतु स्वर्ण के टुकड़ों के लिए टकसाल की कोई आवश्यकता नहीं थी, परन्तु यदि भारतीय भावनाएँ इसकी माँग करें और भारत सरकार खर्च सहने के लिए तैयार हो तो भारतीय अथवा शाही—किसी भी दृष्टिकोण से इसे स्थापित करने में कोई आपत्ति न होनी चाहिए, बसतों कि टकित सिक्का सावरेन या अर्ध-सावरेन हो। यह एक ऐसा प्रश्न था जिसमें भारतीय भावनाओं के अनुरूप कार्य होना चाहिए। (८) यदि स्वर्ण के टुकड़ों के लिए टकसाल की स्थापना नहीं होती तो अम्बई की टकसाल पर करेन्सी के बदले परिष्कृत सोना स्वीकार किया जाए। (९) सरकार का उद्देश्य जनता को करेन्सी का वह रूप प्रदान करना होना चाहिए जो वह माँगती हो, चाहे वह रुपये के रूप में हो अथवा नोट और सोने के रूप में, परन्तु नोट का प्रयोग प्रोत्साहित करना चाहिए। (१०) इन आन्तरिक करेन्सी की विनिमय दायों के लिए स्वर्ण और स्टैलिंग पर्याप्त सुरक्षित कोप से सहायता दनी चाहिए। (११) स्वर्ण प्रमाण सुरक्षित कोप की कोई निश्चित सीमा नहीं होनी चाहिए, जब तक कि स्वर्ण प्रमाण सुरक्षित कोप स्वयं भार महान योग्य न हो जाए तब तक पत्र मुद्रा सुरक्षित कोप पर ही भरोसा करना चाहिए (१२) रुपये के टुकड़ों का लाभ कम-से-कम कुछ समय तक केवल सुरक्षित कोप में जमा करना

चाहिए । (१३) सुरक्षित कोष का अधिकांश भाग सोने के रूप में होना चाहिए । इस सुरक्षित कोष और पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष के बीच सम्पत्ति के विनिमय से १०० लाख पौण्ड का सोना तुरन्त मिल सकता था । अवसर आने पर यह १५० लाख पौण्ड तक बढ़ाया जा सकता था । इसके बाद अधिकारियों को कुल सुरक्षित कोष के आधे भाग को सोने में रखना चाहिए । सुरक्षित कोष को सोने के रूप में रखना अनावश्यक और फिजूल है । सकट-काल में प्रतिभूतियों के वसूल करने से हुई हानि की रक्षा पर्याप्त राशि की सरल रूप में रखने से होती है । (१४) स्वर्ण प्रमाण सुरक्षित कोष की भारतीय शाखा समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके कारण बहुत आलोचना हुई है और सुरक्षित कोष की उपादेयता के सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न करने के लिए भी यह उत्तरदायी थी । (१५) स्वर्ण प्रमाण सुरक्षित कोष को रखने का उचित स्थान लन्दन ही था । (१६) आवश्यकता होने पर १ शि० ३/४ पौ० प्रति रुपये की दर से लन्दन की हुण्डियाँ सरकार को भारत में बेचना चाहिए ।^१

देश में, बम्बई में स्वर्ण टकसाल की स्थापना के लिए किये गए प्रदर्शन, जिनकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है, सर विट्टलदास के प्रस्ताव के रूप में चरम सीमा को पहुँच गए । इस प्रदर्शन के प्रति सहानुभूति रखते हुए भारत सरकार ने १९१२ में इस विषय पर भारत-सचिव को लिखा और जोर देकर कहा कि जनता की स्वर्ण-टकन की माँग को वे अनमनी कर दें । चेम्बरलेन आयोग ने सरकार के विचारों को एकदम नई दिशा में मोड़ने का प्रयत्न किया । आयोग के अनुसार सरकार ने अनजाने में ही स्वर्ण विनिमय प्रमाण अपनाकर भारत को अन्य देशों के साथ प्रथम पक्ति में ला दिया ।

सिफारिशों पर विचार करने और उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिलने से पहले ही १९१४-१८ के विश्वयुद्ध ने एकदम नई प्रकार की परिस्थितियाँ और समस्याएँ उत्पन्न कर दी, जिन पर हम अब विचार करेंगे ।

१९१४-१८ के युद्ध का भारतीय करेन्सी पर प्रभाव^२

१९. प्रथम युग (अगस्त १९१४ से फरवरी, १९१५ तक)—विश्वयुद्ध के प्रभाव का विवेचन दो प्रधान कालों के अन्तर्गत किया जा सकता है—(१) पहले काल की अवधि अगस्त १९१४ से फरवरी, १९१५ तक है । यह अव्यवस्था का काल था, जिसमें करेन्सी और विनिमय की स्थिति बहुत दुर्बल हो गई ।

(२) द्वितीय काल की अवधि फरवरी, १९१५ से १९१६ के अन्त तक है । यह समुत्थान-काल था । इसकी विशेषता उत्पादन-सम्बन्धी अदम्य उरसाह था । इस काल में विनिमय और चाँदी के स्वर्ण-मूल्य में अपूर्व वृद्धि हुई ।

युद्ध छिड़ जाने से जनता के विद्वान्त को बहुत बुरा धक्का लगा, जिससे

१. चेम्बरलेन क्लारिन रिपोर्ट, पैरा ०२३ ।

२. यह विवरण अधिकांशतः बकिंगटन सिन्थ समिति की रिपोर्ट पर आधारित है । दूसरे अध्याय में भारतीय करेन्सी पर द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रभाव का विवरण दिया गया है ।

सामान्यतः सभी व्यापार तथा व्यवसाय अस्त-व्यस्त हो गए। इसके प्रधान लक्षण विनिमय की निर्वलता, सेविंग बैंक में जमा रूपों को निकालना, नोटों के भुगतान की माँग तथा भारत के स्वर्ण भण्डार की अत्यधिक माँग होना है।

सर्वाई के पहले दो महीनों में ही सेविंग बैंक में जमा २४ $\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये में से ६ करोड़ रुपया निकाल लिया गया। १९१५-१६ में समय बदलने तक निकाले हुए रूपों की मात्रा ८ करोड़ हो चुकी थी। रुपया निकालने की माँग को स्वतन्त्रतापूर्वक पूरा किया गया, जिससे पुनः विश्वास उत्पन्न करने और निक्षेप आकर्षित करने में बड़ी सहायता मिली। ये निक्षेप पुनः १९१८-१९ तक १८ करोड़ रुपये हो गए (अर्थात् पूर्व राशि से ६ $\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये कम रहे)।

नोटों के रूपों में भुगतान की माँग भी पूरी की गई। मार्च, १९१५ तक १० करोड़ रुपये के नोट खजानों को वापस किये गए, परन्तु उसके बाद नोटों के प्रचलन में लगातार वृद्धि हुई।

अन्तिम, भारत के स्वर्ण भण्डार की माँग नोटों के बदले सोना माँगने के रूप में बढ़ गई। इस प्रकार प्राप्त सोने के आन्तरिक प्रयोग के लिए बरती हुई सावधानियाँ व्यर्थ सिद्ध हुईं। व्यक्तिगत कार्य के लिए सोना देना एकदम बन्द कर दिया गया और उसके बाद नोटों का भुगतान केवल चाँदी के सिक्कों में ही किया जाने लगा।

प्रथम काल के अन्त तक ये लक्षण लुप्त हो गए। सरकार ने परिस्थिति का सामना साहस और सफलता के साथ किया। बैंकिंग और व्यावसायिक समाज को घन विदेश भेजने हेतु सम्बन्ध स्थापित करने के लिए लगातार पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का आश्वासन और नोटों को रूपों में भुगतान करने की तत्परता से जनता में शीघ्र ही विश्वास पैदा हो गया।

२० द्वितीय काल (फरवरी, १९१५ से १९१९ के अन्त तक)—युद्ध के प्रथम वर्षों के समाप्त हो जाने के बाद करेन्सी यन्त्र कुछ समय के लिए बड़ी स्थिरता से काम करता रहा। १९१६ के अन्त में गम्भीर जटिलता पैदा हो गई। चाँदी का मूल्य बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा था, इसीलिए भारत में चाँदी के सिक्कों की भारी माँग को पूरा करने के लिए उसे प्राप्त करने की कठिनाइयाँ भी बढ़ती जाती थीं।

भारत सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार की ओर से भारी व्यय करने के कारण परिस्थिति और जटिल हो गई। १९१४ से दिसम्बर, १९१९ तक युद्ध के पूर्वोत्पन्न मन्त्रों में सैनिक आवश्यकताओं और अधिकृत क्षेत्रों में नागरिक व्यय के ऊपर २४०० लाख पौण्ड खर्च किया गया। इसके अतिरिक्त कुछ डोमिनियम और उपनिवेश तथा भारतीय उदात्त के अफ्रीकी आयातकर्ताओं की ओर से की गई खरीद के अर्ध प्रवन्धन के लिए भी इन खर्चों का भुगतान करना था।

इन खर्चों का सम्मिलित प्रभाव यह हुआ कि करेन्सी की माँग बहुत बढ़ गई। विदेशी सरकारों द्वारा वृद्धमूल्य धातुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फलस्वरूप उनके आयात में हुई कमी ने समस्या को और जटिल बना दिया। अनुकूल सन्तुलन

के निस्तारण के लिए युद्ध से पूर्व प्रयुक्त विधियों के उपलब्ध न होने के कारण युद्ध सफलतापूर्वक चलाने के लिए प्रति आवश्यक निर्यात व्यापार की रक्षा के लिए सरकार को एक प्रकार का स्थानापन्न प्रस्तुत करना पड़ा। अतएव उन्हें भारतीय निर्यात की अदायगी के लिए साधन प्रस्तुत करने हेतु सन्दन में बहुत बड़ी मात्रा में कौंसिल बिलो को बेचना पड़ा। इन कौंसिल बिलो की बिक्री के कारण भारत में रुपये का अत्यधिक टकन आवश्यक हो गया। इस काम में बड़ी कठिनाइयाँ थी, क्योंकि अनेक परिस्थितियों के कारण चाँदी का मूल्य बहुत बढ़ गया था।

२१. चाँदी के मूल्य में वृद्धि—करेन्सी-स्थिति पर चाँदी के मूल्य की असाधारण वृद्धि का प्रमुख प्रभाव था। युद्ध से पूर्व उत्पादन की तुलना में चाँदी की पूर्ति में अत्यधिक कमी आ गई थी, जिसका कारण मैक्सिको की आन्तरिक कलह और लागत में वृद्धि थी। इसके विपरीत सम्पूर्ण विश्व में करेन्सी के लिए इस धातु की माँग असाधारण रूप से बढ़ गई। चाँदी की माँग में वृद्धि होने का प्रमुख कारण सोने की कमी तथा युद्ध में लगी और तटस्थ सरकारों की सोने की पूर्ति को सुरक्षित रखने की चिन्ता थी। सबसे अधिक माँग भारत और चीन की थी। हम लोग मलीभाँति देख चुके हैं कि अनुकूल व्यापार सन्तुलन के निस्तारण और ब्रिटिश युद्ध-कार्यालयों (ब्रिटिश वार ऑफिस) की ओर से व्यय करने के लिए क्रय-शक्ति ढूँढने का भार मुख्यतः भारत सरकार पर डाल दिया गया था। इसने स्थानीय करेन्सी, विशेषकर रुपये की अत्यधिक माँग, का रूप धारण कर लिया। विधानतः मनाही होते हुए भी रुपया पिघलाने के कारण माँगों में और बढ़ गई, क्योंकि चाँदी के मूल्य में वृद्धि होने के कारण रुपये का वास्तविक मूल्य इसके अंकित मूल्य से बढ़ गया था। इसी दशा में प्रभावित करने वाला दूसरा कदम डालर-स्टैलिग अथवा न्यूयार्क-लन्दन विनिमय का प्रभाव था। जिस समय मार्च, १९१६ में डालर-स्टैलिग विनिमय से नियन्त्रण हटा लिया गया, तो इसका प्रभाव इंग्लैण्ड के प्रति कुल ही हुआ और अन्त में विनिमय-दर ३४० डालर=१ पौण्ड की निम्न सीमा पर पहुँच गई।

चाँदी की वृद्धि के कारणों को समझने के बाद अब इसकी वृद्धि का क्रम देखना चाहिए। १९१५ में चाँदी का न्यूनतम मूल्य २७ पैसे प्रति औंस था। १९१६ में यह ३७ पैसे प्रति औंस तथा १९१७ में ४३ पैसे प्रति औंस हो गया। (जो रुपये के १ शि० ४ पै० की विनिमय-दर पर उसके वास्तविक मूल्य के बराबर था।) सितम्बर, १९१७ में यह ५५ पैसे प्रति औंस हो गया। संयुक्तराज्य, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा आदि देशों ने चाँदी के व्यापार को नियन्त्रित किया और अनुज्ञा-प्राप्त निर्यात को छोड़ शेष निर्यात बन्द कर दिए। बाद में चाँदी का अनुज्ञा-प्राप्त निर्यात भी निर्दिष्ट मूल्य पर होने लगा। इन उपायों के फलस्वरूप चाँदी का मूल्य ४१ और ४६ पैसे प्रति औंस की सीमाओं के अन्दर आ गया। परन्तु मई, १९१८ में संयुक्तराज्य और ग्रेट ब्रिटेन ने इस नियन्त्रण को हटा दिया, जिससे चाँदी का मूल्य फिर बढ़ गया। उसी महीने में चाँदी का मूल्य ५८ पैसे प्रति औंस हो गया। उसके बाद साल-भर यह बढ़ता ही गया और दिसम्बर में ७८ पैसे प्रति औंस हो गया। फरवरी, १९२० में मूल्य उच्च-

तम हो गया, जबकि लन्दन में चाँदी का भाव ८६ पैस प्रति औंस हो गया।

२२. सरकार द्वारा किये गए उपाय—(१) सरकार का विनिमय पर नियन्त्रण—युद्ध के प्रथम वर्षके सङ्घ लेने के बाद कौंसिल बिलों की माँग नियमित-व्यापार के समुत्थान के साथ पुन उत्पन्न हो गई। अक्टूबर, १९१६ तक निर्यात स्पष्ट रूप से साधारण ही रहा। उसके बाद व्यापारिक सञ्चालन की अनुकूलता बढ़ने के साथ बढ़ता गया। इसका विस्तार सोने के आयात द्वारा सम्भव नहीं था। इससे भारत में रुपये का मुद्रास्तर कोप खाली हो गया, जिससे नोटों की रूप्यो में परिवर्तनशीलता सदिग्ध हो गई। अतएव दिसम्बर, १९१६ में कौंसिल बिलों की बिक्री पर नियन्त्रण लगाया गया और इण्टरमिडियेट कौंसिल बिलों की बिक्री बन्द कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप बाजार और सरकारी विनिमय दर में अन्तर हो गया। यह निर्यात व्यापार के लिए हानिकारक था, परन्तु युद्ध के सफल संचालन के लिए निर्यात व्यापार को अग्रगण्य रूप से बनाए रखना भी अति आवश्यक था। इसलिए सरकार ने कुछ नियंत्रण के उपायों से काम लिया तथा जनवरी, १९१७ में विनिमय-दर १ सि० ४१ पैस निश्चित कर दी गई। कौंसिल बिलों की बिक्री कुछ छुनो हुई बैंकों और फर्मों तक सीमित कर दी गई, जिन्हें नियत दरों पर एक तीसरी पाटी से व्यापार करना पड़ना था और अपने साथियों को कुछ छुनो हुई वस्तुओं के निर्यात व्यापार में लगाना पड़ता था, जो मित्र-राष्ट्रों के लिए भी महत्वपूर्ण थी। नियंत्रण के उपायों और बैंकों के सहयोग से विनिमय के चढ़ाव-उतार कुछ समय के लिए बन्द हो गए।

(२) विनिमय-दर की वृद्धि—अगस्त, १९१७ में विनिमय-दर बढ़ाकर १ सि० ५ पैस कर दी गई और कुछ समय पश्चात् भारत-सचिव ने चाँदी के स्टैलिग मूल्य पर विनिमय दर को आधारित करने की घोषणा की। नीचे दी हुई तालिका यह परिणाम दिखा रही है—

विनिमय-दर में परिवर्तन

तारीख	स्टैलिग में विनिमय-दर	तारीख	स्टैलिग में विनिमय-दर
३ जनवरी, १९१७	१ सि० ११ पैस	१२ अगस्त, १९१६	१ सि० १० पैस
२८ अगस्त, १९१७	१ सि० ५ पैस	१५ सितम्बर, १९१६	२ सि० ० पैस
१२ अप्रैल, १९१८	१ सि० ६ पैस	२२ नवम्बर, १९१६	२ सि० २ पैस
१३ मई, १९१६	१ सि० ८ पैस	१२ दिसम्बर, १९१६	२ सि० ४ पैस

३. यह घोषणा भारत में १८७३ से पूर्व विद्यमान रतत प्रमाण को पुन स्थापित करने का घोषणा के बराबर थी। १८७३ से १८८३ तक चाँदी के स्वर्ण मूल्य के परिवर्तन के साथ भारत में मूल्य वृद्धि रहे थे। भारत में हर समय चाँदी के १६५ ग्रेन का स्वर्ण मूल्य वस्तुओं के विनिमय का माप था। वस्तुओं पर विनिमय के विचार में यही बात अति ही सच थी। वकील और मुद्रा-जगत, 'कॉन्सील्ट एट मासेज इन इंडिया', पृ० ११०।

बाजार-दर तथा फरवरी, १९२० के बाद रिजर्व कौन्सिल बिलो की विक्रय-दर जनवरी से मार्च, १९२० तक २ शि० ६ पैस, २ शि० ८ पैस, २ शि० १० पैस और २ शि० ११ पैस थी। सबसे ऊँची दर १९२० के प्रारम्भिक महीने में थी।

(३) रजत-क्रय—करेन्सी की पूर्ति के लिए विशेष उपाय अपनाये गये। फरवरी, १९१६ से इस काम के लिए चाँदी खरीदी जाने लगी। व्यक्तिगत खरीदारों को धोर से प्रतिस्पर्धा दूर करने के लिए सरकार ने सितम्बर, १९१७ से निजी तौर पर चाँदी के आयात को बन्द कर दिया। सयुक्तराज्य और भारत सरकार के बीच हुए पत्र व्यवहार के फलस्वरूप सयुक्तराज्य ने पिटमेन कानून पास किया, जिसने सुरक्षित कोष को चाँदी बेचने का अधिकार दिया। १०१½ सेण्ट प्रति शुद्ध औंस के भाव से भारत सरकार ने २००० लाख औंस शुद्ध चाँदी खरीदी।

(४) चाँदी की सुरक्षा और उसकी मितव्ययता—चाँदी की सुरक्षा और मित-व्ययता के लिए और उपाय भी अपनाये गए। सोने और चाँदी के सिक्कों को पिघलाने और उसके निर्यात को रोकने के लिए सरकार ने जून, १९१७ में करेन्सी विधान पास किया। दिसम्बर, १९१७ में २½ और १ स० के नोट जारी किये गए। सबसे पहले जनवरी, १९१८ में २, ४ और ८ आने के गिलट (निकल) के सिक्के बनाये गए, जिन्हें १ रुपये तक कानूनी मुद्रा माना गया। जून, १९१७ से रुपये के स्टैलिग विनिमय मूल्य के आधार पर सरकार ने निजी तौर पर आयात किये हुए सोने को प्राप्त किया। इस प्रकार प्राप्त सोने के बल पर नोट जारी किये गए और चाँदी की करेन्सी तथा सोने की मुहर के पूरक के रूप में सोने की मुहर और सावरेन बनाई तथा जारी की गई। जून, १९१९ में उत्तरी अमेरिका से स्वर्ण-निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध हटा लेने तथा आस्ट्रेलिया और अफ्रीका के स्वर्ण बाजार स्वतन्त्र कर देने से देश में अधिक सोने का आयात होने लगा और सरकार ने भी अधिक सोना प्राप्त किया।

(५) पत्रमुद्रा-प्रसार—धानु रखे बिना जारी किये गए नोटों की वृद्धि करके भी स्थिति सुधारने का प्रयत्न किया गया। इसकी परिवर्तनीयता पर प्रतिबन्ध लगा दिये गए, उदाहरणार्थ परिवर्तन के लिए अतिरिक्त वैधानिक सुविधाओं को रोक दिया गया। नोट वालों के लिए प्रतिदिन जारी किये गए रुपये को सीमित करके भी समस्या को हल करने का प्रयत्न किया गया।

(६) आर्थिक उपाय—साधारण और पूँजी-व्यय न्यूनतम रखे गए तथा सरकार की क्रय-शक्ति बढ़ाने के लिए और अधिक कर लगाये गए। इसके अतिरिक्त भारत में ऋण लिये गए, जिससे १९१७-१८ और १९१९ में १३० करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। अक्टूबर, १९१७ से १२ महीने की अवधि के अल्पकालीन ट्रेजरी बिल भी जारी किये गए। करेन्सी की प्रत्यक्ष माँग और भारत में भेजने की भारी माँगों को पूरा करने में इन उपायों ने बड़ी सहायता की।

२३. बेबिंगटन समिति—जिस समय चेम्बरलेन समिति की सिफारिशों विचाराधीन थी, उसी समय युद्ध प्रारम्भ हो गया। हम अभी देख चुके हैं कि युद्ध ने किस प्रकार अनेक समस्याओं को जन्म दिया। अतः सर हेनरी बेबिंगटन स्मिथ की अध्यक्षता में

३० मई, १९१६ को एक दूसरी विशेष समिति की नियुक्ति की गई ।

सक्षेप में समिति की मुख्य सिफारिशों इस प्रकार हैं—^१

(१) रुपये को असीमित कानूनी मुद्रा ही रखना चाहिए । (२) इसका निश्चित विनिमय का मूल्य होना चाहिए, जो ११-३००१६ ग्रेन शुद्ध सोने के बराबर हो, अर्थात् सावरेन के सोने के $\frac{1}{10}$ के बराबर हो । (३) सावरेन को, जिसकी पहली दर १५ रुपये = १ सावरेन थी, १० रुपया = १ सावरेन की नई दर पर कानूनी मुद्रा बनाना चाहिए । (४) सोने के आयात और निर्यात से सरकारी नियंत्रण १० रुपया = १ सावरेन की दर स्थापित करते ही हटा लेना चाहिए । बम्बई में जनता द्वारा दिये गए सोने की सावरेन बनाने के लिए सोने की टकसाल खोचनी चाहिए । (५) सावरेन के बदले रुपया देने की सरकारी अधिसूचना वापस ले लेनी चाहिए । (६) निजी तौर पर चाँदी के आयात और निर्यात पर लगी बन्दिश हटा देनी चाहिए तथा राजकोपीय स्थिति के कारण आवश्यक होने तक चाँदी पर लगा आयात-कर हटा देना चाहिए । (७) स्वर्ण-प्रमाण सुरक्षित कोष में प्राप्त अनुपात में सोना रखना चाहिए तथा शेष राशि को ब्रिटिश साम्राज्य की सरकारों (भारत सरकार को छोड़कर) द्वारा जारी की गई ऐसी प्रति-भूतियों के रूप में रखना चाहिए जो १२ महीने में परिपक्व होती हों । स्वर्ण-प्रमाण सुरक्षित कोष का भाग, जो आधे से अधिक न हो भारत में रखना चाहिए । रुपये का विनिमय मूल्य सोने के बराबर निश्चित करने के सम्बन्ध में यह शर्त थी—

“यदि आशा के विपरीत विश्व के मूल्यों में शीघ्र कमी हो जाए और भारत में उत्पादन-लागत इन गिरे हुए मूल्यों से शीघ्र ही व्यवस्थित न हो सके, तो इस प्रश्न पर नये सिरे से विचार करना आवश्यक हो सकता है ।”

२४ रिपोर्ट पर सरकारी कार्यवाही—सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और उन्हें लागू करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए—

(१) विनिमय नियंत्रण—जनवरी १९२० में कॉमिल ड्राफ्ट की माँग समाप्त हो गई और रिर्वर्स कॉमिल की बहूत माँग होने लगी । जनवरी में कॉमिल ड्राफ्ट २ सि० ४ पै० की दर पर बेचे गए । यह दर कॉमिल बिलों की बिक्री के लिए निश्चित की गई थी, परन्तु समिति की सिफारिशों के अनुरूप सरकार ने अधिसूचित किया कि कॉमिल ड्राफ्ट और टेलिग्राफिक ट्रान्सफर टेण्डर द्वारा बेचे जाएँगे और उनकी कोई निम्नतम दर नहीं होगी तथा अबसर आने पर भविष्य में रिर्वर्स ड्राफ्ट और टेलिग्राफिक ट्रान्सफर भारत में भी बेचे जाएँगे । इनका भाव (दर) ११ ३००१६ ग्रेन शुद्ध सोने का स्टर्लिंग मूल्य होगा, जो विद्यमान स्टर्लिंग डालर विनिमय द्वारा निश्चित किया जाएगा । इस दर में से सोना बाहर भेजने की लागत कम कर दी जाएगी ।

१. उपरोक्त सचिव विवरण दिल्हन यंग कमीशन १९०५-२६ की रिपोर्ट की तीसरी परिशिष्ट से लिया गया है, परन्तु पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष के विधान और स्थिति-सम्बन्धी सिफारिशों में छोड़ दिया गया है ।

२. देखिए, रिपोर्ट ऑफ दि रायन कमीशन ऑन इन्फ्लेशन कण्ट्रोल पर द फाइनेंस १९२५, खण्ड २, परिशिष्ट ३ तथा एच० स्टेनली, 'वेब्लिंग पर द फ्लैसचेंज दन इंडिया', अध्याय १५ ।

(२) सावरेन के कानूनी मुद्रा-मूल्य में परिवर्तन—सावरेन और रुपये का १ : १० का आन्तरिक अनुपात उस समय तक प्रभावपूर्ण नहीं हो सकता जब तक समिति द्वारा प्रस्तावित अनुपात की तुलना में स्वर्ण-पिण्ड अधिक पसन्द किया जाएगा। हम देख चुके हैं कि किस प्रकार १९१७ से ही सरकार ने स्वर्ण पिण्ड की पसन्दगी समाप्त करने के लिए निजी तौर पर आयात किये हुए सोने को प्राप्त करना तथा सितम्बर, १९१९ से हर पन्द्रहवें दिन उसे खेचना प्रारम्भ किया था। स्मिथ समिति द्वारा प्रस्तावित मूल्य के ऊपर भी सोने की पसन्दगी बहुत अधिक बनी रही। फरवरी, १९२० में सरकार ने घोषणा की कि प्रथम छ महीने में १५० लाख तोला शुद्ध सोना बेचा जाएगा, परन्तु यह प्रोग्राम अगस्त और सितम्बर तक बढ़ा दिया गया।

२१ जून, १९२० के आर्डिनेन्स ३ से सावरेन और अर्ध सावरेन की वैधानिक ग्राह्यता बन्द हो गई। परन्तु २१ दिन तक १५ रुपये की दर से उन्हें स्वीकार करने की व्यवस्था की गई। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ब्रिटिश स्वर्ण मुद्राओं के आयात पर से प्रतिबन्ध हटा लिये गए। २१ दिन की अवधि में ही २५ लाख पीण्ड के सावरेन और अर्ध सावरेन करेन्सी कार्यालयों और खजानों में पेश किये गए।

१५ रुपये के स्थान पर १० रुपये की दर से सावरेन को कानूनी मुद्रा बनाने के सम्बन्ध में करेन्सी समिति की सिफारिश को जून, १९० के इण्डियन ब्याणनेज (अमेन्डमेण्ट) एक्ट ३६ द्वारा कार्यान्वित किया गया। इस कानून द्वारा सावरेन और अर्ध-सावरेन को कानूनी मुद्रा का रूप पुनः दे दिया गया, जिसे २१ जून, १९२० के आर्डिनेन्स ३ ने बन्द कर दिया था। नये कानून के अनुसार नई दर १० रु० प्रति सावरेन निश्चित की गई तथा खजानों और करेन्सी कार्यालयों को निर्देश दिया गया कि वे सावरेन और अर्ध-सावरेन क्रमशः १० और ५ रुपये की दर पर स्वीकार करें, परन्तु इस दर पर सावरेन या अर्ध-सावरेन जनता को न दें। सावरेन का बाजार मूल्य सर्वद्वय १० रुपये से अधिक रहने के कारण वह इस नई दर पर करेन्सी के रूप में नहीं चल सकी। अतएव बम्बई में एक स्वर्ण टकसाल खोलना आवश्यक समझा गया।

(३) युद्धकालीन प्रतिबन्धों की समाप्ति—फरवरी, १९२० में चाँदी के आयात पर लगा हुआ प्रतिबन्ध (निर्यात का नहीं) हटा लिया गया और ४ आने प्रति ग्राँस का आयात-कर भी समाप्त कर दिया गया। करेन्सी के अलावा अन्य कार्यों के लिए सोने और चाँदी को बन्द करने वाली युद्धकालीन अधिसूचनाएँ रद्द कर दी गईं। चाँदी के मूल्य में गिरावट तथा चाँदी के सिक्कों के प्रचलन में कमी हो जाने से बहुमूल्य धातुओं पर लगे शेष प्रतिबन्धों को समाप्त करना भी सम्भव हो गया। ५-१ जून को स्वर्ण-पिण्ड और विदेशी सिक्के के आयात पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया। कुछ दिनों के बाद सरकार की ओर से भुगतान करने के लिए चाँदी के प्रयोग पर से भी प्रतिबन्ध हटा लिया गया। खजानों को आदेश दिया गया कि प्राप्तकर्ता द्वारा इच्छित करेन्सी में भुगतान किया जाए। अतिरिक्त वैधानिक सुविधाओं को पुनर्जीवित करने के लिए (अर्थात् नोटों को रुपये में बदलने के लिए) भी कदम उठाये गए। ये सुविधाएँ पहले अस्थायी रूप से समाप्त कर दी गई थीं। उदाहरणतः खजानों के

लागू करने की आशा छोड़ दी थी। यह दर छः महीने के अन्दर ही स्थापित की गई और गिर गई। बाजार-दर नीचे गिरती गई और सरकार उसके गिराव को नहीं रोक सकी। बाजार-दर के अनुसरण में सरकार को अपनी दर भी कम करनी पड़ी और उसे बाजार-दर से कुछ ऊँचा रखने के नियम का ही पालन किया जा सका। परन्तु यह दर अनिश्चित काल तक नहीं रह सकती थी, अतएव सरकार ने विनिमय के नियमन के प्रयास छोड़ दिए। १९२० के प्रारम्भ से सितम्बर, १९२० तक रिवर्स कौंसिल की बिक्री ५५,३८२,००० पौण्ड तक हो गई। लन्दन में रिवर्स कौंसिल की अदायगी पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष से सम्बन्धित स्टलिंग प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिल की बिक्री से प्राप्त राशि द्वारा होती थी। ये प्रतिभूतियाँ और बिल १५ रुपये प्रति पौण्ड की दर पर खरीदे गए थे और ७ से १० रुपये प्रति पौण्ड की दर पर बेचे गए। क्रय और विक्रय मूल्य के इस अन्तर के फलस्वरूप भारतीय खजानों को ३५ करोड़ रुपये की हानि हुई।

अधिकतम हानि का कारण व्यापारियों का सरकार द्वारा निर्धारित ऊँची दर पर विश्वास करना था। माल का अॉर्डर इस आशा और विश्वास से किया गया था कि विनिमय-दर ऊँची रहेगी, परन्तु माल आने तक विनिमय-दर बहुत गिर गई। इस कारण अनेक व्यापारकर्ताओं का दिवाला पिट गया, क्योंकि सरकार द्वारा ऊँची विनिमय-दर बनाए रखने के सम्बन्ध में इन्हे इतना विश्वास था कि इन्होंने कोई सावधानी ही न बरती।

२६ सरकारी नीति की परीक्षा—इन बातों से यह सिद्ध होता है कि अनेक व्यापारी ऐसी ऊँची दर को बनाए रखना असम्भव नहीं समझते थे, चाहे वे उसकी उपादेयता के बारे में भले ही सन्देह करते हों।

सरकार स्वयं २ सि० स्वर्ण दर की व्यावहारिकता के बारे में सन्देह नहीं करती थी, क्योंकि इस विषय पर उसे स्मिथ समिति के बहुमत का समर्थन भी प्राप्त था। यह सत्य है कि सर ददीबा दलाल ने अपना भिन्न मत प्रकट करते हुए इस उच्च दर से सम्भावित दोषों की योग्यतापूर्ण विस्तृत विवेचना की थी, परन्तु उन्होंने भी इस दर को बनाए रखने की असम्भाव्यता पर विशेष बल नहीं दिया।

इसके साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब सरकार बैबिंग्टन स्मिथ समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने चली, उस समय अनेक ऐसी बातें थी जो करेन्सी प्रभाव में ऐसे परिवर्तन करने से पहले सरकार को रुकने और सोचने के लिए बाध्य कर रही थी। उदाहरण के लिए, अगस्त १९-० में, जिस समय परिवर्तित अनुपात लागू होने वाला था, उस समय सोना २३½ रुपये प्रति तोला बिक रहा था, परन्तु नये अनुपात के अनुसार उसे १५ रुपये १४ आने के भाव से बिकना चाहिए था। इस अन्तर को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाना चाहिए था कि २ सि० स्वर्ण दर को बनाए रखना यदि असम्भव नहीं तो असाधारण रूप से कठिन अवश्य होगा। इसके अतिरिक्त पुन चाँदी का मूल्य गिरकर ४४ पैस प्रति औंस हो चुका था और रुपया पिघलाने का भय लगभग समाप्त हो चुका था। यदि कहीं थोड़ा-बहुत

हया पिघलामा भी जाता तो प्रचलन में रुपये की घटती हुई मात्रा को देखते हुए इसका कोई प्रभाव न होता ।^१

भारतीय विनिमय की वृद्धि के कारणों में चाँदी के मूल्य की वृद्धि को महत्ता देकर ब्रिटीशमन स्मिथ ममिति ने परिस्थिति को बिलकुल गलत समझा । रुपये के स्टैण्डिंग मूल्य के बढ़ने का प्रधान कारण रुपये के मूल्यों की तुलना में स्टैण्डिंग के मूल्यों का अधिक बढ़ना था । सम ऋण-शक्ति सिद्धान्त के अनुसार भी सतुलन के लिए विनिमय-दर को ऊपर उठाना चाहिए था । २ सि० स्वर्ण-दर का अर्थ ऋण-शक्ति की समता की तुलना में रुपये का अधिमूल्यन था । रुपये के लिए सोने का निश्चिन्त मूल्य स्थापित करने का प्रयत्न अपरिपक्व था, क्योंकि सोने के मूल्य में स्वयं बहुत परिवर्तन हो रहे थे तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की परिस्थितियों में बड़ी अस्थिरता थी ।^२

सरकार के विरुद्ध प्रमुख आलोचना यह नहीं थी कि उसने अपनी नीति को प्रारम्भ में ही एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर बना दिया, बल्कि यह थी कि २ सि० स्वर्ण दर को प्रभावपूर्ण बनाने के सम्बन्ध में प्रयत्नों की निरर्थकता देखते हुए भी वे रिवर्स कौंसिल की दिशों में लगे रहे । जून, १९२० के अन्त तक यह स्पष्ट हो गया कि सरकार ने एक असम्भव कार्य अपने ऊपर ले लिया था । अतः प्रारम्भ में ही अपनी हार मान लेना कहीं अधिक बुद्धिमानी और साहस का काम होता, परन्तु वे विनिमय-दर को बढ़ाने में लगे रहे तथा उन्होंने स्वर्ण-माधनों को रिक्त कर दिया और इस प्रकार औद्योगिक एवं व्यावसायिक दुनिया में बड़ी उथल-पुथल मचा दी । जैसा कि सर स्टैनली रीड ने कहा है कि यह एक ऐसी नीति थी जो विनिमय की स्थिरता के लिए अनाई गई थी, परन्तु जिनके देश के विनिमय में क्रम-धिक परिवर्तन, व्यापारिक उथल-पुथल, राजकीय हानि तथा सैकड़ों व्यापारियों को दिवालिया बना दिया ।^३

२७ निष्क्रियता की नीति (१९२१-२५)—विनिमय को स्थिर करने के प्रयत्न में असफल होने पर सरकार कुछ समय तक कोई निरायं किये बिना ही घटना-चक्र को शांतिपूर्वक देखती रही ।

१९२१ में भी व्यापारिक सन्तुलन भारत के प्रतिकूल था । विदेश के मूल्यों के सोने में गिरने के कारण निर्यात-व्यापार की दशा बुरी थी । इसका दुमरा कारण

१. देखिए, अम्बरकर, पूर्व उद्धृत, पृ० २०० ।

२. परिष्कृत (मैकलेसन के साथ चाँदी के मूल्य की वृद्धि के लिये उपयोगशाली । अन्त में ममिति की आधुनिक मूल्य मूल्य पर विचार करने के लिये मूल्य-सूचकांके के अन्त में और केवल चाँदी के मूल्य पर ध्यान देने में ही । रुपये का २ सि० सोने की दर से सम्बन्धित करने में स्तन वृद्धि के वास्तविक कारण को सुना दिया और इस दर को बनाए रखने के लिए आवश्यक मुद्रा सञ्चयन को कम प्रोत्साहित । अन्य देशों में मूल्यों की गतिविध के सम्बन्ध में इनके अन्तर्गत के हान्यापक अना-रूप हैं जो कि कदाचित् ही इतिहास में मिलें । बर्लीन, मुम्बई, पूर्व उद्धृत, पृ० ३४०-४१ ।

३. मुन्डव केसुन्त मेमोरियल और सिन्डन दग कमीशन रिपोर्ट, खण्ड ३, परिशिष्ट १२ ।

४. क० ई० दादोजी विस्री ऑफ इन्डियन कॉमर्सेल एन्ड एन्ड्रोज, पृ० १३७ ।

स्टलिंग मूल्यो मे तेजी से हुई कमी थी जो इंग्लैण्ड द्वारा स्टलिंग को स्वर्ण समता पर लाने के लिए उठाये गए कदमो के फलस्वरूप हुई थी। इन परिस्थितियो मे, जैसा कि होना चाहिए था, रुपये का स्टलिंग मूल्य गिरता गया। १९२१ मे ३१,५८,००० रुपये की करेन्सी का सकुचन किया गया। यह विनिमय की निम्नगामी गति को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी, जो १ शि० ३ पैस के निम्न स्तर तक पहुँच गई थी।

१९२२-२३ मे यूरोपीय देशो मे त्रय शक्ति मे सुधार होने और भारत मे अच्छी फसल होने के कारण भारत के निर्यात का पुनरुत्थान हुआ। मुद्रा के सकुचन और निर्यात के पुनरुत्थान का सम्मिलित प्रयास रुपये के विनिमय मूल्य को धीरे-धीरे बढ़ाना था। सितम्बर, १९२३ मे रुपया १ शि० ३½ पैस सोने के बराबर था और १ शि० ४ पैस का मुद्र के पूर्व का अनुपात किसी के हित को हानि पहुँचाए बिना ही पुनः स्थापित किया जा सकता था। इसके लिए भारतीय व्यापार मण्डल ने प्रार्थना भी की थी, जो असफल रही। सरकार १ शि० ६ पैस के अनुपात को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रही थी। वास्तव मे रुपया १ शि० ६ पैस स्टलिंग के स्तर पर अक्तूबर, १९२४ मे पहुँच गया। इसके बाद सरकारी कार्य रुपये के मूल्य को इस स्तर से अधिक न बढ़ने की ओर प्रेरित हुआ। उस परिणाम को प्राप्त करनेके लिए, सरकारी विप्रेषण के लिए आवश्यक, स्टलिंग खरीदने की विधि का स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग किया गया और इस खरीद के बल पर नई करेन्सी चालू की गई, जिससे द्रव्य-सम्बन्धी कठिनाई भी कम हुई। अप्रैल, १९२५ मे रुपये का विनिमय मूल्य १ शि० ६ पैस स्वर्ण होगया और २१ सितम्बर, १९३१ तक इसी प्रकार बना रहा। जैसा कि अग्लोचको का कथन है, उसे इतना ही रखा गया।'

अब निष्क्रियता-नीति का अन्त दृष्टिगोचर होने लगा। अनेक ओर से की गई प्रार्थनाओ के उत्तर मे सरकार ने १९२५ के आरम्भ मे करेन्सी-स्थिति की जाँच करने के लिए एक अधिकृत समिति की स्थापना का वादा किया। सरकार को यह आशा थी कि तब तक विश्व की परिस्थितियो मे स्थिरता आ जाएगी। लेफ्टिनेण्ट कमाण्डर हिल्टन-यंग की अध्यक्षता मे भारतीय करेन्सी और विनिमय के राजकीय आयोग की नियुक्ति हुई।

आयोग के मत और निर्णय पर विचार करने से पहले, हम भारतीय पत्र-मुद्रा पद्धति का विवरण देने।

भारतीय पत्र-मुद्रा

२८ प्रारम्भिक इतिहास—१८०६, १८४० और १८४३ के कानूनों के अन्तर्गत बंगाल, बम्बई और मद्रास के प्रेसीडेन्सी बैंको को यह अधिकार दिया गया कि वे नोट जारी करें, जिनका वाहको द्वारा माँगे जाने पर भुगतान कर दिया जाए। इन नोटो के जारी करने के सम्बन्ध मे अधिकतम सीमा और सुरक्षित कोष-सम्बन्धी नियमों का पालन

करना आवश्यक था। परन्तु उनका प्रयत्न व्यवहारत तीन प्रेसीडेन्सी नगरों तक ही सीमित था। १८६० में भारत के प्रथम वित्त सदस्य श्री जेम्स विल्सन ने सरकारी पत्र-मुद्रा और प्रेसीडेन्सी बैंको द्वारा नोट जारी करने के अधिकारों के उन्मूलन के लिए योजना बनाई। १८४४ के इंगलिश बैंक चार्टर एक्ट के आधार पर उस समय के भारत-सचिव सर चार्ल्स वुड ने निम्नलिखित सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया—

नोट जारी करने के दृष्टिकोण से पहले देश तीन निर्गम क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जिनके प्रधान कार्यालय बलकत्ता, बम्बई और मद्रास थे। केन्द्रों की सख्या १९१० में बढ़कर सात हो गई। चार अतिरिक्त केन्द्र रगून, कराची, कानपुर और लाहौर थे। १०, २०, ५०, १००, ५००, १०००, १०००० रुपये के नोट जारी किये गए। ५ रुपये का नोट १८६१ में जारी किया गया। ब्रिटिश स्वर्ण मुद्रा और रुपये के बदले वे जनता में बेरोक-टोक जारी किये जा सकते थे। करेन्सी के कण्ट्रोलर की आज्ञा पर वे स्वर्ण-पिण्ड के बदले भी जारी किये जा सकते थे। अपने-अपने क्षेत्र के भीतर वे सरकारी खजानों और जनता के लेन-देन के लिए असीमित कानूनी मुद्रा मान गए।

जारी किये गए नोटों के बराबर मूल्य का सुरक्षित कोप धातु-पिण्ड और निक्को के रूप में बनाया गया, जिसका एक छोटा भाग भारत सरकार की 'रूपी सिक्कोरिटीज' में उनकी परिवर्तनीयता की गारण्टी देने के लिए विनियोजित था।

केवल नोट जारी करने वाले क्षेत्र के प्रधान कार्यालय पर ही नोटों का भुगतान कराने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता था, साथ ही सरकार खजाने, रेलवे कम्पनी और यात्रियों के लिए अन्य क्षेत्रों के नोटों का भी भुगतान करती थी। सरकारी देनदारियों का भुगतान किसी भी क्षेत्र के नोटों में किया जा सकता था।

२६ नकद भुगतान और कानूनी मुद्रा-सम्बन्धी प्रतिबन्ध—भारत एक विशाल देश है तथा व्यापारिक दशाओं के कारण वर्ष के विभिन्न समयों में देश के एक भाग से दूसरे भाग को रुपये भेजे या मँगाये जाते हैं। नोटों का सबसे पहला प्रयोग विप्रेषण के लिए सोना भेजने के बजाय अधिक सुविधापूर्वक नोट भेजना होगा, यदि सरकार ने जारी करने वाले क्षेत्र तक ही नोटों को कानूनी मुद्रा न बनाया होता, तो सरकार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नकदी भेजनी पड़ती। इसके विपरीत, यदि नोटों को पूर्णतया कानूनी मुद्रा बना दिया जाता और उनका भुगतान केवल प्रेसीडेन्सी नगरों तक ही सीमित होता, तो निस्सन्देह वर्ष में कुछ समय लोग सिक्कों को अधिक पसन्द करते तथा नोटों की लोकप्रियता कम हो जाती।

क्षेत्र-पद्धति (सर्किल सिस्टम) के कारण नोटों की लोकप्रियता और विस्तार में बहुत बाधा पहुँची और इसे समाप्त करने के लिए १९०३ में पहला कदम उठाया गया, जबकि ५ रुपये का नोट बर्मा को छोड़कर सर्वत्र कानूनी मुद्रा बना दिया गया। यह रोक भी १९०६ में हटा ली गई। १९१४-१८ के युद्ध ने इस विकास को रोक दिया, क्योंकि इस समय रुपये के टकन में कठिनाई थी तथा विकसित आधार पर जारी किये गए नोटों का प्रचलन बंद गया था। बैंकिंग समिति ने युद्धकालीन प्रतिबन्धों को

समाप्त करने तथा नोटो को अधिक लोकप्रिय बनाने हेतु उनके भुगतान के लिए अतिरिक्त वैधानिक सुविधाओं के विस्तार की सिफारिश की। १९३१-३२ में ५०० और १००० रुपये के नोट भी सर्वत्र कानूनी मुद्रा बना दिये गए।^१

३०. पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष—१८६१ के कानून के अन्तर्गत सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में ४ करोड़ रुपये तक स्थायी विश्वासाश्रित निर्गम (फिक्स्ड फिड्युयरी इश्यू) करने की व्यवस्था है। यह सीमा समय-समय पर विशेष कानूनो द्वारा बदल दी गई। यह १८७१ में ६ करोड़, १८६० में ८ करोड़, १८६७ में १० करोड़ तथा १९०५ में १२ करोड़ रुपये कर दी गई। अब तक ये प्रतिभूतियाँ भारत में रखी हुईं भारत सरकार की रुपये वाली प्रतिभूतियाँ थीं, परन्तु १९०५ के कानून ने २ करोड़ तक की स्टलिंग प्रतिभूतियों को इंग्लैण्ड में रखने की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार सुरक्षित कोष में विनियोजित भाग का कुछ अंश स्टलिंग प्रतिभूति के रूप में रखा जाने लगा।^२ १९११ में प्रतिभूतियों की अधिकतम सीमा १४ करोड़ निश्चित की गई, जिसमें से ४ करोड़ स्टलिंग प्रतिभूतियों में रखने की व्यवस्था थी।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, १८६८ तक स्थायी विश्वासाश्रित भाग को छोड़कर अतिरिक्त सम्पूर्ण पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष चाँदी के रूप में था। १८६८ में गोल्ड नोट एक्ट ने सरकार को सुरक्षित कोष के धातु वाले भाग के अंश को स्वर्ण-मुद्रा में रखने का अधिकार दिया। १९०० के कानून ने इन स्वर्ण मुद्राओं को लन्दन में रखने का भी अधिकार दिया। १९०५ के कानून ने सुरक्षित कोष के घाटवीय भाग को अथवा उसके किसी अंश को, लन्दन अथवा भारत में, स्वर्ण-मुद्रा या स्वर्ण-पिण्ड या रजत-पिण्ड में रखने का अधिकार दिया; परन्तु सभी टंकित रूपों को भारत में ही रखने की व्यवस्था थी।

इसके फलस्वरूप नोटों की परिवर्तनीयता निश्चित करने के लिए अत्यधिक सुरक्षित कोष रखा गया। कुल जारी किये गए नोटों के कुछ प्रतिशत या अनुपात को तरल रूप में रख और विनियोजित भाग को बढ़ाकर इससे बचा जा सकता था। इस प्रकार भी विश्वासाश्रित सीमा बढ़ाने के लिए वैधानिक आश्रय की आवश्यकतान पड़ती।

३१. पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष की आलोचना—१९१४ से पहले पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष के विरुद्ध प्रमुख आलोचना इन आचारों पर थी—(१) घाटवीय कोष का अनावश्यक रूप से अधिक होना, (२) विशेष कानून के बिना स्थायी विश्वासाश्रित कोष को बढ़ाने की असम्भावना और (३) पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष के भाग का इंग्लैण्ड में स्टलिंग प्रतिभूतियों में विनियोजित होना।

(१) और (२) के कारण व्यवस्था लोचहीन हो गई। जहाँ तक (३) का सम्बन्ध है इस प्रथा का समर्थन इस आचार पर किया गया कि स्टलिंग प्रतिभूतियाँ

१. रिपोर्ट ऑफ दि कण्ट्रोलर ऑफ कर्न्सी (१९३१-३२), पैरा ६०। १०० रुपये से अधिक के नोट का १९४७ से सरकारी आर्बिनेन्स द्वारा निमुनीकरण कर दिया गया।

२. पीब्ले सेक्शन १२, अन्तिम पैरा।

रुपये का विनिमय-मूल्य बनाए रखने के लिए आवश्यक थी और उनसे एक लाभ यह भी था कि भारत में आन्तरिक सकट आने की दशा में उनके भ्रवमूल्यन की सम्भावना नहीं थी। इसके विपरीत यह कहा गया कि रुपये के विनिमय-मूल्य को बनाए रखना पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष का काम नहीं है। भारत में आन्तरिक सकट होने पर स्टैलिग प्रतिभूतियों में भ्रवमूल्यन भले ही न हो, परन्तु नोट निर्गम के सम्बन्ध में जनता का विश्वास सम्पूर्ण सुरक्षित कोष को भारत में रखने से ही हो सकता है।^१

नोट निर्गम का कार्य पूर्णतया बैंकिंग के कार्यों से एकदम अलग कर दिया गया। केन्द्रीय बैंक की तरह कोई चीज नहीं थी, इसलिए कोई सरकारी बैंक भी नहीं था। केवल रिजर्व ट्रेजरी व्यवस्था थी, जिसके अन्तर्गत विशेष सरकारी खजानों में रुपया रखा जाता था, जिसके फलस्वरूप वर्ष में कुछ समय के लिए द्रव्य बाजार में कठिनाई उपस्थित हो जाती थी।

कुछ प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों को छोड़कर चँको और निक्षेपों का तरीका भारत में अब भी अधिक प्रचलित नहीं है। दूसरा तरीका स्मिथ समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था और स्वीकार भी कर लिया गया था। तीसरा तरीका भी रिजर्व ट्रेजरी की समाप्ति और सरकारी कोष को इम्पीरियल बैंक में रखकर अपनाया गया है। रिजर्व बैंक के खुलने से पहले १९२१-२५ के इम्पीरियल बैंक में सरकारी बैंक की तरह काम किया। सामान्य लोचहीनता दूर करने के लिए स्मिथ समिति का सुभाव था कि घातीय भाग कुल निर्गम के ४०% से कम नहीं होना चाहिए। उनका विचार था कि कारोबार के दिनों में परिनिमित्त निम्नम सीमा से अधिक कर रखना ही वाञ्छनीय होगा। इस प्रकार कानून का आश्रय लिये बिना ही प्रचलन के विस्तार के साथ-ही-साथ विश्वासाश्रित सुरक्षित कोष भी बढ जाएगा। जैसा कि हम बाद में देखेंगे, सरकार ने स्मिथ समिति के सुभाव को १९०० में स्वीकार कर लिया, यद्यपि उन्होंने घातीय कोष की अधिक प्रतिधन को अर्थात् ५०% को अपनाया।^२

३२. १९१४-१८ के युद्ध का पत्र-मुद्रा पर प्रभाव—हम ऊपर देख चुके हैं कि किस प्रकार, १९१४ में युद्ध के छिड़ने पर, प्रारम्भ में भय के कारण नोटों के भुगतान के लिए लोग पेश करेन्ती ऑफिस पर जमा होने लगे तथा किस प्रकार विश्वास के उत्पन्न हो जाने पर नोट प्रचलन में विस्तार हुआ। मार्च, १९१५ से आगे पत्र-मुद्रा पर युद्ध के प्रभावों को संक्षेप में इस प्रकार दिखाया जा सकता है -

(१) करेन्सी की अत्यधिक माँग के कारण पत्र-मुद्रा का प्रसार हुआ, जिसकी पूर्ति रुपये जारी करने से नहीं की जा सकती थी। इस समाधारण माँग के कारणों का विवेचन हम पहले ही कर चुके हैं। (२) विभिन्न कानूनों के परिणामस्वरूप विश्वासाश्रित (फिड्यूशरी) सुरक्षित कोष बहुत बढ गया। इन कानूनों के पूरक आर्डिनेन्स गवर्नर जनरल द्वारा जारी किए जाते थे। सुरक्षित कोष में रखने के लिए पर्याप्त

१. पत्र मुद्रा सुरक्षित कोष की आलोचना के लिए कृपया अध्याय देखिए।

२. देखिए, सेन्सन २३।

मुद्रा पाने की कठिनाई के कारण सुरक्षित कोप का अपूर्व विस्तार आवश्यक हो गया। इंग्लैंड की ओर से भारत में किये गए युद्ध के व्यय भारत सचिव द्वारा लन्दन में ले लिये गए। इसे लन्दन-स्थित पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप में सोने के रूप में रखना राजकीय हित के विरुद्ध समझा गया। अतएव उसे ब्रिटिश ट्रेजरी बिल्स अथवा अल्पकालीन स्टॉक प्रतिभूतियों में रखने के विकल्प को अपनाया गया।^१ यद्यपि कुछ भाग का विनियोग भारतीय ट्रेजरी बिल में भी किया गया। (३) घात्वीय सुरक्षित कोप १९१४ में ७८९% था। १९१९ में यह ३५८% रह गया। (४) चाँदी की मित-व्ययता के उपाय के रूप में १९१७ और १९१८ में क्रमशः १ और २½ रुपये के नोट जारी किये गए जो स्पष्टतः इंग्लैंड में जारी किये गए १ पौण्ड और १० शि० के नोट के अनुकरण-मात्र थे। जनता ने प्रारम्भ में इनके प्रति उदारता नहीं दिखाई। १ रुपये का नोट खूब चलने लगा। ३१ मार्च, १९१९ को १०५० लाख रुपये के एक रुपये वाले नोट चल रहे थे जबकि २½ रुपये के नोट का प्रचलन केवल १८४ लाख रुपया था।^२ (५) रुपये की कमी के कारण नकदी भुगतान के लिए, अतिरिक्त वैधानिक सुविधाओं^३ को समाप्त कर दिया गया। (६) १९१८ के पत्र-मुद्रा एक्ट का सामना करने के लिए पिटमैन कानून के अन्तर्गत २००० लाख औंस अमरीकी चाँदी का आयात हुआ।

३३. पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप का पुनर्निर्माण—सितम्बर, १९१९ में पत्र-मुद्रा कानून के अस्थायी सुधार से पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप के विनियोग की अधिक सीमा १२० करोड़ रुपये कर दी गई, जिसमें १०० करोड़ रुपया ब्रिटिश ट्रेजरी बिलों में लगाना आवश्यक था।

मार्च, १९२० में छः महीने के लिए एक अस्थायी कानून बनाया गया जिसने सुरक्षित कोप के विनियोजित भाग को १२० करोड़ रुपया रखने की आज्ञा दी, परन्तु इसने विनियोग के स्थान और उसके स्टॉक अथवा रुपये के प्रकार-सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटा दिए। इंग्लैंड को सोना भेजने की तत्कालीन माँग और राजसचिव के नकद कोप से इसे पूरा करने की असम्भावना ने इसे अनिवार्य कर दिया। लन्दन-स्थित पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप में रखी स्टॉक प्रतिभूतियों के विनय से माँग पूरी हो गई। वर्तमान कानून के अनुसार रुपये के मूल्य में स्टॉक प्रतिभूतियों के बराबर १५ ह० = १ पौ० की दर से नोटों की वापसी और रद्दी आवश्यक हो गई।

१. ब्रिटिश ट्रेजरी बिल में विनियोग करने का प्रधान कारण यह था कि अल्पकालिक होने के कारण उनके अधोमूल्यन का भय नहीं था। इसके विपरीत स्टॉक प्रतिभूतियों में होने वाले युद्ध के कारण अधोमूल्यन हो रहा था।

२. भारत सरकार ने १ जनवरी १९२६ से १ और २½ रुपये के नोट को समाप्त करने का निश्चय किया। उनका स्थान चाँदी के रुपये और १० रुपये के नोट ने ले लिया। देखिए अगला अध्याय।

३. जैसा कि कहा गया है, वे सुविधाएँ १९२०-२१ में पुनः प्रारम्भ कर दी गईं और इम्पीरियल बैंक की शाखाओं की वृद्धि के साथ बढ़ती गईं, जहाँ जनता की सुविधा के लिए नोटों के भुगतान की व्यवस्था है।

चेम्बरलेन आयोग और स्मिथ समिति की आलोचना तथा युद्ध काल में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए मार्च, १९२० के अस्थायी कानून के स्थान पर नया कानून पास करना आवश्यक हो गया। अतएव भारत में पेपर करेन्सी अमेण्डमेण्ट एक्ट^१ १ अक्टूबर, १९२० को कानून बना दिया गया। इस कानून के विधान (१) स्थायी और (२) अस्थायी दो भागों में विभाजित किये जा सकते हैं।

(१) स्थायी विधान^२

(क) कुल सुरक्षित कोष का ५०% घात्विक रूप में होना चाहिए। स्मिथ समिति द्वारा प्रस्तावित ४०% से अधिक (५०%) को स्वीकार करने का कारण यह था कि भारत जैसे देश में नोटों का तुरन्त नकद भुगतान करना और बारबार के दिनों में फसलों की गति के लिए आर्थिक सहायता हेतु, जब नोट सामान्यतः भुगतान के लिए उपस्थित किए जाते हैं, पर्याप्त सिक्का सुरक्षित रखना आवश्यक होता है।

(ख) २० करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों को छोटकर, जो भारत में रखी जाती थीं, शेष रूपया स्मिथ समिति के अनुसार १२ महीने या उससे कम अवधि की अल्पकालीन प्रतिभूतियों के रूप में इंग्लैण्ड में रखा जाता था।

(ग) ६० दिन में परिपक्व होने वाली मुनाई हुई अल्पकालीय ट्रेण्डियों के आधार पर करेन्सी का कण्ट्रोलर ५ करोड़ रुपये के नोट जारी कर सकता था। अतिरिक्त निर्गम इम्पीरियल बैंक को दिये ऋण के रूप में हो सकता था, जिस पर बैंक को ८% ब्याज और स्वीकार की हुई ट्रेण्डियाँ सरकार को देनी पड़ती थीं। १९२३ के इण्डियन पेपर करेन्सी अमेण्डमेण्ट एक्ट द्वारा ५ करोड़ की सीमा बढ़ाकर १२ करोड़ कर दी गई। परिनियत घात्विक कोष के ५०% सम्बन्धी विधान का अतिरिक्त निर्गम से कोई सम्बन्ध न था, क्योंकि घात्विक कोष निश्चित करने के लिए इस निर्गम पर विचार नहीं किया जाता था।

(घ) राज्य सचिव लन्दन में ५० लाख पाउण्ड के स्वर्ण-पिण्ड से अधिक नहीं रख सकता था।

(२) अस्थायी विधान

१५ रु० = १ सावरेन के स्थान पर १० रु० = १ सावरेन की दर से सोने और प्रतिभूतियों का पुनः मूल्यांकन करने हेतु उत्पन्न कठिनाई के कारण स्थायी विधान होने तक अस्थायी विधान बनाना आवश्यक समझा गया। १० रु० की दर से पुनः मूल्यांकन करने पर सुरक्षित कोष का घात्विक भाग ५०% से कम हो जाता, अतएव कुछ समय के लिए विनियोजित पूंजी ८५ करोड़ रुपये निश्चित कर देने की

१. यह सामान्यतः १९२३ के पेपर-करेन्सी एक्ट की धारा में उल्लिखित करता है जो कन्वेंशन्स एक्ट में उल्लिखित है।

२. ये विधान व्यवहार में स्मिथ समिति की निशानियों के समान हैं।

व्यवस्था की गई।^१ दूसरी कठिनाई सोना और प्रतिभूतियों को पहली दर की $\frac{3}{4}$ पर पुन मूल्यन करने से उत्पन्न अन्तर को पूरा करने के सम्बन्ध में थी। इस कठिनाई को हल करने के लिए सरकार को अधिकार दिया गया कि वह रुपये वाली प्रतिभूतियाँ (जिन्हे तदर्थ प्रतिभूतियाँ कहा जाता था) उत्पन्न करे और उन्हें पत्र मुद्रा सुरक्षित कोष को निर्गमित करे। चूँकि ये प्रतिभूतियाँ रुपये वाली प्रतिभूतियों की कानूनी सीमा पार कर जाएँगी, इसलिए यह प्रस्तावित किया गया कि इस सीमा से आगे बढ़ी हुई प्रतिभूतियाँ धीरे धीरे स्टैलिग प्रतिभूतियों में परिवर्तित कर दी जाएँ। चूँकि यथेष्ट स्टैलिग प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए कोष नहीं था, अतएव १२ करोड़ ६० की अनुज्ञेय सीमा से अधिक उत्पन्न की गई रुपये वाली प्रतिभूतियों को कम करने के लिए यह व्यवस्था की गई कि पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष का व्याज, नये रुपये के टकन का लाभ तथा ४०० लाख पौण्ड से अधिक होने पर (३० सितम्बर १९२१ को यह अधिक हो गया था) अस्थायी निर्गम की सुरक्षा के लिए कण्ट्रोलर ऑफ करेन्सी के पास जमा व्यापारिक ढुण्डियों के व्याज का लाभ पत्र मुद्रा सुरक्षित कोष में जमा कर दिया जाए।

१९२७ के इण्डियन पेपर करेन्सी एक्ट के अनुसार १ अप्रैल, १९२७ से पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष की प्रतिभूतियाँ, जिनका मूल्यन १९२० में १० रुपये प्रति सावरेन की दर पर हुआ था, अब इनका मूल्यन १३ ६० १ आ० ३ पा० की दर से किया गया। इसके परिणामस्वरूप सोना और स्टैलिग में ३० लाख ६० की वृद्धि हो गई, जिसे इतनी ही मात्रा के भारतीय ट्रेजरी बिल रह करके बराबर कर दिया गया। इसके फलस्वरूप ट्रेजरी बिल ४६७७ लाख रुपये से घटकर ४०४७ लाख रुपये रह गए।^१

३४ ३१ मार्च १९२५ और १९३५ के बीच पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष की वनावट और स्थिति—१९२५ और १९३५ के बीच पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष में परिवर्तन किये गए। १९२६-३० और १९३०-३१ के वर्षों में नोटों के प्रचलन में बहुत कमी आ गई, जिसका कारण वस्तुओं के गिरते हुए मूल्य के साथ मुद्रा-सकुचन का होना था। मूल्यों में सामान्य कमी १९२६-३० के अन्तिम भाग से प्रारम्भ हुई। दूसरा कारण निर्यात व्यापार में मूल्यों के गिर जाने के कारण विनिमय में कमजोरी आने की प्रवृत्ति थी, जिसके लिए अद्यत भारत की अनिश्चित राज-

१ द्रव्य-सम्बन्धी कठिनाई दूर करने के लिए फरवरी, १९२५ के सरोधन कानून द्वारा यह सीमा १०० करोड़ ७५ टों गई। इस कानून के अनुसार भारत सरकार द्वारा उत्पन्न की हुई प्रतिभूतियों की मात्रा ५० करोड़ ६० से अधिक नहीं होनी चाहिए।

२. १९३१-३२ के लिए वन्द्रीय वजट और अध्याय ६ का सैरशन १७ भी देखिए।

३. १९२४ ०५ से १९३४ ३५ तक करेन्सी कण्ट्रोलर की रिपोर्ट देखिए। १९३५ के पत्र-मुद्रा चलन सुरक्षा कोष की वनावट और स्थिति का एक ११वें अध्याय में दिया गया है।

३. पत्र-मुद्रा के सम्बन्ध में हिल्टन यह आयोग की सिफारिशों और द्वितीय महायुद्ध के प्रभावों के लिए अगला अध्याय देखिए। निगम काय रिजर्व बैंक को सुपुर्न करने तथा नोटों के लिए सुरक्षित कोष रखने के लिए नये प्रधान रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट (१९३४) के अन्तर्गत अध्याय ११ में दिये गए हैं।

नीतिक और सामाजिक दना तथा १ सि० ४ पै० की दर की पुन स्थापना की परि-
 कल्पना के कारण पूंजी स्थानान्तरित करने की प्रवृत्ति भी उत्तरदायी थी। घरेलू
 व्ययों को पूरा करने के लिए राज्य सचिव को विप्रेषण (रेमिटेन्स) करने में कठिनाई
 पंदा हो गई और यही पत्र मुद्रा सुरक्षित कोप में १९३१ से १ स्टलिंग प्रतिभूतियों के
 पूरा कोप का कारण बताती है, क्योंकि भारत में नोटों के सङ्कुचन के अनुसार इन
 प्रतिभूतियों को भारत सचिव को हस्तान्तरित करना पड़ता था। तथा प्रतिभूति में
 १९३०-३१ में और कमी आ गई जो इन प्रतिभूतियों के साथ करेन्सी के सङ्कुचन से
 स्पष्ट है। इसी वर्ष सुगुप्त कोप में सोने की मात्रा में कमी होने का प्रमुख कारण
 ८३ करोड़ रु० का सोना स्वर्ण प्रमाण सुरक्षित कोप की भारतीय शाखा को चुका देना
 था। नवम्बर, १९३० और फरवरी, १९३१ के बीच विनिमय-सम्बन्धी परिवर्तन
 और राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित जनता की माँग के प्रत्युत्तर में गृह-कोप
 (होम ट्रेजरी) की सहायता तथा १ सि० ५ $\frac{५}{८}$ पै० की परिणित दर पर स्टलिंग की
 विज्ञी को पूरा करने के लिए ६२ लाख पौ० की स्टलिंग प्रतिभूतियाँ पत्र-मुद्रा कोप
 के इंग्लैण्ड स्थित भाग से निकाल लेने के कारण ही उपर्युक्त राशि (८३ करोड़ रु०)
 भारतीय शाखा को दी गई थी। पत्र मुद्रा सुरक्षित कोप का निर्माण में अन्य उल्लेख्य
 परिवर्तन कोप में चाँदी के सिक्कों की वृद्धि थी, जिसके कारण नीचे दिये गए हैं।
 इसमें और वृद्धि हुई होनी, परन्तु हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के अनुसार विक्रय
 के लिए कुछ चाँदी निकाल लेने के कारण ऐसा नहीं हुआ।

माघ १९ - से १९३५ तक भारत सरकार ने २२८,१८२,२५५ डॉलर शुद्ध
 चाँदी खरी। इस विक्रय से प्राप्त राशि का विनियोग स्टलिंग प्रतिभूतियाँ में किया
 गया जो स्वर्ण प्रमाण सुरक्षित कोप को स्थानान्तरित कर दी गई, परन्तु इसके विरुद्ध
 इस कोप में सोना पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप को स्थानान्तरित कर दिया जाता था जिसमें
 समान मूल्य की रूपया प्रतिभूति रद्द कर दी जाती थी। स्टलिंग की चालू आवश्यकताओं
 से अधिक खरीद के अनिश्चित (सरप्लस) का प्रयोग भी इसी प्रकार किया गया।
 इन कारणों के फलस्वरूप पत्र मुद्रा सुरक्षित कोप का स्वर्ण भाग बढ़ गया, परन्तु चाँदी
 और चाँदी के सिक्के कम हो गए। १९३३-३४ और बाद के वर्षों में गृह कोप (होम
 ट्रेजरी) के अनिश्चित धन और चाँदी के विक्रय के लाभ का प्रयोग स्टलिंग प्रतिभूतियों
 के क्रय में किया गया और इस प्रकार पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप की स्टलिंग सम्पत्ति
 बढ़ाई गई। सरकारी करेन्सी कार्यों को रिजर्व बैंक को हस्तान्तरित करत समय पत्र-

१ रिजर्व नकल ३५।

२ रिजर्व बैंक को हस्तान्तरित करत समय २९ माघ, १९३५ का भारत सरकार का स्वर्ण-मंडार ४४ ४७
 करोड़ था, जिसमें से ४९ ६५ करोड़ पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप में था और ४ करोड़ १० स्वर्ण प्रमाण
 मंडार का भी था। इस स्थिति में भारत सरकार (दर) (१ १० = ४७ ड्रेन सोने) का स्थिति था।
 उक्त बात का ज्ञान मूल्य लागू ५५ करोड़ रुपये था।

मुद्रा कोष की यह स्थिति स्वागत योग्य थी।^१

२० सितम्बर, १९३१ को इंग्लैण्ड के स्वर्ण प्रमाप त्यागने तथा रुपये का मूल्य १ शि० ६ पै० निश्चित करने के फलस्वरूप रुपयो में सोने का मूल्य बढ़ जाने से ३१ दिसम्बर १९३७ तक ३०८ करोड़ रुपया बाहर भेजा गया।^१

३५. नोट प्रचलन और करेन्सी की खपत—इस भाग में २ मुख्य प्रश्नों का विवेचन प्रस्तावित है—

(१) कुल और सक्रिय नोट प्रचलन—जब हम पत्र-मुद्रा के प्रचलन की बात करते हैं तो हमें जानना चाहिए कि हम कुल प्रचलन की बात कर रहे हैं अथवा सक्रिय प्रचलन की।

(क) कुल प्रचलन का अर्थ जारी किये गए नोटों के कुल मूल्य से है जिनका भुगतान नहीं हुआ है। (ख) १ अप्रैल, १९३५ से जब नोट चलाने का कार्य रिजर्व बैंक ने ले लिया, सक्रिय प्रचलन का अर्थ बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोटों को छोड़कर जारी किये गए शेष नोटों की संख्या से है।

हास के वर्षों में सक्रिय नोट प्रचलन की वृद्धि से देश में नोटों का अधिक प्रयोग और पुनस्तथान प्रकट होता है। युद्धजनित दशाओं के परिणामस्वरूप १९३६-४० में हुई वृद्धि को दूसरे अध्याय में समझाया गया है।

(२) करेन्सी के विभिन्न रूपों की खपत—१९१४-१८ के युद्ध के पूर्व, मध्य और बाद में मुद्रा चलन के शोषण और नोट तथा रुपये की अपेक्षाकृत लोकप्रियता में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। नोट और रुपये के रूप में बड़े पैमाने पर युद्धकालीन मुद्रा चलन का प्रसार भली प्रकार जाँचे गए साधनों के कारण विशेषों द्वारा स्पष्ट हो रहा है। १९२०-२१ में मुद्रा चलन का विस्तृत संकुचन प्रतिफल व्यापारिक सन्तुलन और हुण्डियों के विक्रय के प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है। १९१४-१८ के बाद के २० वर्षों में बिना अपवाद के एक ओर खजानों से चाँदी के रुपये के लाभ का काल था और दूसरी ओर नोटों द्वारा रुपयों का पक्षपातपूर्ण स्थान-परिवर्तन था। यह तालिका युद्ध-पूर्व, युद्ध-काल तथा युद्धोत्तर-काल में सिक्कों और पत्र-मुद्रा की सापेक्षिक खपत और लोकप्रियता के विशेष परिवर्तन को स्पष्ट करती है। इन आँकड़ों से रुपये और नोटों का युद्धकालीन विस्तार भली भाँति प्रकट हो जाता है। १९२०-२१ में मुद्रा का संकुचन प्रतिफल व्यापारिक सन्तुलन और रिजर्व कौंसिल की बिक्री प्रदर्शित करता है। १९१४-१८ के बाद २० वर्ष तक का समय चाँदी के रुपयों की वापसी तथा अशतः सिक्कों का नोट से प्रतिस्थापन का युग था, यद्यपि कुछ थोड़े-बहुत अपवाद भी थे। रुपयों की वापसी का एक कारण यह था कि लोग धन जोड़ने के लिए उसके स्थान पर सोने का प्रयोग करने लगे, क्योंकि २१ सितम्बर, १९३१

१. देखिए अध्याय ११, करेन्सी कंट्रोलर की रिपोर्ट (१९३३-३४), पैरा ३६ और (१९३४-३५) पैरा ३१।

२ अधिक स्पष्टीकरण के लिए अगला अध्याय देखिए और नोट प्रचलन के आन्वेषों के लिए ११वाँ अध्याय देखिए।

को भारत के स्वर्ण प्रमाण छोड़ने से पहले सोने का मूल्य १९१४-१८ के स्तर से भी नीचा हो गया था (दूसरा अध्याय देखिए)। सर जार्ज युस्टर का कहना था कि करेन्सी का सकुचन विश्व मूल्यों में कमी आने का फल था तथा अत्यधिक सकुचन नहीं किया गया था।^१ मूल्यों की वृद्धि और असातः आर्थिक पुनरुत्थान के कारण नोटों की खपत बढ़ गई, परन्तु चाँदी के सिक्के की वापसी के कारण यह असातः समाप्त हो गई। वेचे गए, बाहर भेजे गए तथा जोड़े गए सोने के स्थान पर नोट की सार्वजनिक माँग का सकेत हम ऊपर दे चुके हैं। १९३६-३७ में करेन्सी की कुल खपत की मात्रा २३०४ करोड़ रु० थी। आर्थिक मन्दी के परिमाणस्वरूप १९३७-३८ में १४७५ करोड़ रु० और १९३८-३९ में ९६२ करोड़ रु० की वापसी हुई। १९३९-४० में करेन्सी की खपत की मात्रा ५९५३ करोड़ रु० थी। खपत में १००८ करोड़ रु० और ४९४५ करोड़ रु० के नोटों की वृद्धि हुई। १९१८-१९ का छोड़कर, जबकि सितम्बर, १९३९ में युद्ध छिड़ने के उपरान्त मूल्यों की वृद्धि और व्यापारिक तेजी के कारण खपत ९४२० करोड़ रुपये हो गई थी, अन्य किसी वर्ष करेन्सी की इतनी खपत नहीं हुई। यह भारत में व्यापारिक क्रियाओं की वृद्धि और १९३९ के युद्ध के बाद मूल्य की वृद्धि को चिह्नित करती है। १९१९-२० के बाद किसी भी वर्ष करेन्सी की खपत १९३९-४० से अधिक नहीं हुई। किसी हद तक यह व्यापारिक तेजी और अच्छी फसलो के कारण भी थी, परन्तु असातः युद्धजनित परिस्थितियों के कारण धातु और सिक्कों को जोड़ने की प्रवृत्ति भी इसका कारण थी। युद्धजनित तनाव बढ़ने के साथ यह प्रवृत्ति भी बढ़ती गई। तब जुलाई १९४० में भारत सरकार को एक रुपया के प्रचलन द्वारा इसे रोकना पडा (अगला अध्याय देखिए)। १४ फरवरी, १९४७ को जारी किये गए कुल नोटों की मात्रा १२५७ करोड़ रुपये से कुछ अधिक थी।

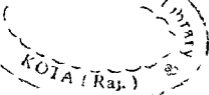
युद्ध चलाने हेतु सामान की भारी खरीद के लिए अपनाई गई विशेष विधि के फलस्वरूप इंग्लैण्ड-स्विन करेन्सी कोष में स्टर्लिंग प्रतिभूतियों की अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे देश के नोट प्रचलन में बहुत वृद्धि हो गई, जैसा कि १९४०-४१ से १९४४-४५ तक के आँकड़ों से प्रकट है।^२ १९४५ में युद्ध समाप्त होने के साथ करेन्सी की वृद्धि की गति मिथिल होती गई।

प्रत्येक महीने में करेन्सी की खपत का अध्ययन इस तथ्य को प्रकट करता है कि करेन्सी की खपत सामान्यतः नवम्बर से जून तक कारोबार के महीनों में और जुलाई से अक्टूबर तक के मन्दी महीनों में करेन्सी कार्यालयों और खजानों को वापस खीट आती है।^३

१. केन्ट्रिय बन्ड १९३१-३२, पृष्ठ २८-२९, अध्याय ९ का संकशान १७ भी देखिए।

२. देखिए अध्याय १२, स्टर्लिंग सन्तुलन का मैकान।

३. अध्याय ११ भी देखिए।



अध्याय २२

चलार्थ और विनिमय (भाग २)

कार्यरत हिल्टन यंग कमीशन

१ स्वर्ण विनिमय प्रमाप के दोष—४ जुलाई, १९२६ को हिल्टन यंग आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। भारत के लिए द्रव्य प्रमाप-सम्बन्धी अपनी योजना के प्रतिपादन के पूर्व ही आयोग ने पद्धति की निम्नलिखित विद्यमान बुराइयों की ओर संकेत किया।^१

(१) यह पद्धति सरल और ग्राह्य नहीं थी। करेन्सी में दो संकेत मुद्राएँ—रपया और नोट—तथा पूर्ण मूल्य की सावरेन नामक एक तीसरी मुद्रा थी, जिसका लेश-मात्र प्रचलन नहीं था। संकेत मुद्रा का एक रूप, अर्थात् रपया, जिसमें दूसरी संकेत मुद्रा अर्थात् नोटों को परिवर्तित करने का असीमित दायित्व था, बहुत ही व्ययशील था और चाँदी का मूल्य एक निश्चित स्तर से ऊपर हो जाने पर जब यह संकेत मुद्रा नहीं रह जाता, तो इसके गुप्त होने की सम्भावना थी।

(२) सुरक्षा स्वर्ण प्रमाप तथा पत्र-मुद्रा और बैंकिंग सुरक्षित कोप के रूप में दोहरे सुरक्षित कोप थे। करेन्सी और साख नीति के नियन्त्रण के लिए उत्तरदायित्व का पुराना और भयानक विभाजन था। जबकि अन्य देशों में यह दायित्व किसी एक केन्द्रीय बैंक पर होता है, भारत में करेन्सी का नियन्त्रण सरकार के हाथ में था और साख का नियन्त्रण केवल इम्पीरियल बैंक द्वारा किया जाता था।

(३) इस पद्धति में करेन्सी का स्वाभाविक प्रसार और सकुचन सम्भव नहीं था। इस प्रकार का प्रसार या सकुचन पूर्ण रूप से करेन्सी अधिकारी अर्थात् सरकार की इच्छा पर निर्भर था। सुरक्षित कोप के रिक्त होने से साथ-साथ इस पद्धति में स्वभावतः आन्तरिक करेन्सी का सकुचन नहीं होता था।

इस प्रकार करेन्सी प्रसार के सम्बन्ध में अनेक अवसरों पर सरकार ने मुद्रा-प्रसार के बिना ही स्टॉलिंग खरीदने के दायित्व को पूरा किया—पहले पहल सरकारी कोप से न्य किया गया और मुद्रा प्रसार सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया।

(४) अन्ततः इस पद्धति में लचक नहीं थी। स्मिथ समिति की सिफारिश पर की गई लचक की व्यवस्था को भारतीय व्यापार के अर्थ प्रवर्धन के विभिन्न ढंगों द्वारा कार्यान्वित किया गया। ये ढंग नवद साख अथवा अभियाचन प्रतिज्ञा अथपत्र

१. देखिए हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट, पैरा २१।

(डिमाण्ड प्रोमोसरी नोट्स) के आधार पर अग्रिम देन पर आधारित थे, इसलिए करेंसी की सामयिक वृद्धि की सुरक्षा के रूप में देन के अन्दर व्यापारिक वृष्टियों की कमी हो गई और सितम्बर, १९२४ में सरकार ने घोषित किया कि आवश्यकतानुसार वे लन्दन-स्थित पत्र मुद्रा सुरक्षित कोष में जमा ट्रेजरी बिल के आधार पर करेंसी जारी करने के अधिकार का प्रयोग करेंगे ।

२. सुरक्षित कोष और शेष (बैलेन्स) — हम देख चुके हैं कि किस प्रकार एक विशेष उद्देश्य के लिए निर्मित सुरक्षित कोष और शेष अन्य कार्यों के लिए विवेकहीनता से प्रयुक्त होने थे । सुरक्षित कोष और शेष का उपयोग किसी उचित नीति में नियन्त्रित नहीं होना था, जिसके फलस्वरूप उन्हें कभी एक-दूसरे से अलग समझा जाता था और कभी दोनों को मिला दिया जाता था, जिससे काफी गड़बड़ पैदा होती थी ।

जहाँ तक स्वर्ण प्रमाण सुरक्षित कोष की रचना (बनावट) का सम्बन्ध है, स्थिति असन्तोषजनक थी । प्रधानतया इसे दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में लगाया जाना था और इसका बहुत थोड़ा भाग द्रव्य रूप में रखा जाता था । चम्बरलेन आयोग^१ ने सिफारिश की कि इसके अधिकतर भाग को तरल रूप और सरलतापूर्वक वसूल होने वाली प्रतिभूतियों में रखना चाहिए तथा स्वर्ण प्रमाण सुरक्षित कोष की रचना शाखा का उन्मूलन कर देना चाहिए । अन्तिम प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार कर लिया, परन्तु शेष सिफारिशें १९१४ का युद्ध प्रारम्भ हो जाने के कारण कान्यन्वित न हो सकीं । उस युद्ध के समय लगभग सारा शेष लन्दन में प्रतिभूतियों के रूप में रखा था और ब्रिटिश युद्ध बॉण्ड और ट्रेजरी बिल खरीद गए । अल्पकालीन प्रतिभूतियों में घन लगाकर सरलता से वसूल होने वाली प्रतिभूतियों का सम्बन्ध में की गई सिफारिश पूरी की गई ।

समिति ने सिफारिश की थी कि सुरक्षित कोष के पर्याप्त भाग का सन्धन रखना वाछनीय था । उन्होंने यह भी सिफारिश की थी कि च प्रतिभूतियाँ भारत सरकार के अनिच्छित ब्रिटिश साम्राज्य की किमी अन्य सरकार द्वारा जारी की गई अल्पकालीन प्रतिभूतियों के रूप में होनी चाहिए ।

पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष का मिलन से पहले और १ अप्रैल, १९२५ से रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को हस्तान्तरित होने से पूर्व, स्वर्ण प्रमाण सुरक्षित कोष की स्थिति यह थी कि इसका अधिकतर भाग विभिन्न रूपों में अल्पकालीन पत्रों में लन्दन में रखा गया ।

पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष का एक भाग लन्दन में रखा गया । चम्बरलेन आयोग ने लन्दन में स्वर्ण प्रमाण सुरक्षित कोष की स्थिति को इस आधार पर उचित ठहराया कि लन्दन विदेश का निवास गृह और शरण-दाता है । इसके अनिच्छित भारत का प्रधान ग्राहक इंग्लिस्तान (यूनारटड किंगडम) था और लन्दन वह प्रधान स्थान था

१. इल्लिए अन्वय ८, मन्थन १८ ।

२. आगे सेक्शन २४ और अन्वय ११ देखिए ।

जहाँ भारत की ओर से राज सचिव के व्यय और इंग्लैण्ड तथा विश्व के प्रति भारत की व्यापारिक देनदारियाँ चुकाने के लिए रुपये की आवश्यकता होती थी। यदि सुरक्षित कोष भारत में रखा जाता तो इसे लन्दन भेजना पड़ता जिससे अनावश्यक बिलम्ब और व्यय होता। भारत में कोई अल्पकालीन साख बाजार नहीं था और सुरक्षित कोष का यहाँ रखना बेकार ही था, क्योंकि उस पर किसी प्रकार का व्याज नहीं मिल सकता था। इसके अतिरिक्त कुछ यूरोपीय देशों की केन्द्रीय बैंको द्वारा दृष्टियाँ रखने की प्रथा ने लन्दन में सुरक्षित कोष रखने की भारतीय प्रथा के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया।

सुरक्षित कोष की स्थिति-सम्बन्धी यह पेचीदा व्यवस्था सम्भवतः व्यापार के प्रतिकूल सन्तुलन द्वारा उत्पन्न विनिमय की कठिनाइयों का ठीक रखने के लिए की गई थी। इस तथ्य को दृष्टि में रखने पर कि भारत के लिए प्रतिकूल व्यापारिक सन्तुलन एक असाधारण बात थी (जो हर दस वर्ष में होती थी) यह प्रतीत होगा कि कभी होनवाली इस घटना के लिए ऐसे विस्तृत और स्थायी प्रबन्ध आवश्यक न थे।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापारिक सन्तुलन प्रतिकूल होने पर अन्य देश विदेशी बैंको में सुरक्षित कोष नहीं रखते हैं। उदाहरण के लिए, प्रतिवर्ष व्यापारिक देनदारियों के भुगतान के लिए अन्य देशों द्वारा भारत में कोई सुरक्षित कोष नहीं रखा जाता था।

इन दिशाओं में कोई प्रयास करने के बजाय, सरकार ने चाँदी के आयात पर कर लगाकर ऐसे बाजार के विकास को रोक दिया। अगर क्रय लन्दन में ही किये जाते थे, तो कोष वहाँ रखने के बजाय आवश्यकता पड़ने पर भारत से हस्तान्तरित करने में ही कौनसी विशेष हानि थी? प्रचलित सन्देह और असन्तोष को कम करने के लिए आवश्यक धन इंग्लैण्ड भेजने की असुविधा और अतिरिक्त व्यय उचित ही थे। यह भी प्रकट ही है कि आवश्यकता पड़ने पर भारत से हस्तान्तरण न होने पर इंग्लैण्ड में आवश्यक धन एकत्र करने का प्रबन्ध, उदाहरणार्थ बैंक ऑफ इंग्लैण्ड की सहायता से, किया जा सकता था। अन्ततः चाँदी की खरीद के सम्बन्ध में बरती जाने वाली गोपनीयता ने स्वभावतः ही अनेक विरोधी आलोचनाओं को जन्म दिया।

३ विप्रेषित धनराशियों (रेमिटेन्सेज) का प्रबन्ध—जैसा कि हम कह चुके हैं, राज-सचिव द्वारा कौंसिल ड्राफ्ट की विधि भारत से लन्दन में कोष जमा कराने का एक यन्त्रमात्र थी। इस सम्बन्ध में यह शिकायत थी कि अत्यधिक धनराशि, विशेषकर १९०४ के बाद से, इस प्रकार अनावश्यक रूप से लन्दन भेजी गई। इसका समर्थन हम आघार पर किया गया कि इससे राज-सचिव की आर्थिक स्थिति दृढ़ हो गई, परन्तु इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं किया गया कि इस प्रकार की दृढ़ता की क्या आवश्यकता थी। इसी प्रकार यह भी कहा गया कि राज-सचिव के लिए यह वाञ्छनीय है कि वह कौंसिल बिलों की अत्यन्त लाभपूर्ण दरों का, जब कभी वे प्राप्त हों, लाभ उठाए। यहाँ पुनः यह अनुमान निहित है कि धन की अपेक्षा का प्रश्न एक गौण प्रश्न है। प्रायः इस बात का भी दावा किया गया कि अपने व्यय

की आवश्यकता से अधिक रुपया एकत्र करने से राज-सचिव ने ऋण से बचाव या उसमें कमी सम्भव कर दी। इस प्रकार अधिक धन लेने की प्रवृत्ति ने भारत में बचत की आद्य-व्यय की नीति को प्रोत्साहित किया। ऋणों से बचाव करने या उन्हें कम करने के स्थान पर भारत में कर कम करने की क्रिया का अनुसरण कहीं अधिक वाञ्छनीय होता।^१ इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि राज-सचिव का नकद शेष (बाकी) अधिक होने पर भी लन्दन में भारी ऋण लिये गए।

इस प्रकार राज-सचिव के हाथ में एकत्र अतिरिक्त रुपया लन्दन में बहुत थोड़े व्याज पर 'स्वीकृत' ऋणकर्ताओं को उधार दिया जाता था। इन ऋणकर्ताओं की एक सूची राज-सचिव के पास रहती थी। सामान्य शिकायत यह थी कि इन ऋणों के सम्बन्ध में काफी पक्षपात दिखाया जाता था और ये शिकायतें इसलिए और गम्भीर हो गईं क्योंकि राज-सचिव की कौंसिल की वित्त समिति के सदस्य ही वे सचालक और व्यापारी थे जो ऋण देने के लिए व्यक्तियों का चुनाव करते थे।

लन्दन में रुपये की आवश्यकता न होने पर भी कभी-कभी स्वर्ण आयात विन्दु से निम्न दर पर भी कौंसिल बिलों की बिक्री की प्रथा पर आपत्ति की गई।

राज सचिव की आवश्यकता से ऊपर कौंसिल बिलों की बिक्री का समर्थन मुख्यतया इस आधार पर किया गया कि यह भारत के विदेशी व्यापार के लिए बहुत सहायक था। परन्तु व्यापार को इस सहायता की आवश्यकता ही नहीं थी। वास्तव में व्यापार के अर्थ-प्रबन्धन के लिए व्यापार को वैकल्पिक साधन ढूँढने में कोई कठिनाई न थी और कौंसिल बिलों की बिक्री कम कर देने पर भी व्यापार को कोई कठिनाई नहीं हुई। अतः व्यापार की सहायतायें सरकार को अपना मार्ग छोड़ने के लिए कोई विशेष कारण तो नहीं था। उन्हें केवल इनना ही करने की आवश्यकता थी कि निर्यात के लिए स्वर्ण को स्वतन्त्रतापूर्वक प्राप्य बना देते।

बैकिंग्टन स्मिथ समिति को दिये गए अपने स्मृतिपत्र में, सर स्टैनली रीड ने भारतीय विनिमय पर राज-सचिव के नियन्त्रण के उन्मूलन की जोरदार सिफारिश की। उन्होंने कहा कि भारत की सरकार और राज-सचिव दोनों पर ही भारत की अधिकांश जनता सन्देह करती थी। राज-सचिव भारत के बड़े वित्तीय केन्द्रों से ६००० मील की दूरी पर बैठकर काम करते थे। वे अभारतीय हिन्दों से आवृत्त और स्वभावतः उन्हीं के पोषक थे। वे गोपनीयता के साथ काम करते थे और भारत में उन उपायों के मूल आधारों की—भले ही वे उपाय किन्हीं हों बुद्धिमानी से भरे और आवश्यक क्यों न हों—कोई भी सूचना प्राप्त करना सम्भव था। ऐसे पूर्ण अधिकार, जो जनता से इतनी दूर गोपनीय ढंग से कार्यान्वित होते थे, की राज-नीतिक हानियों की अतिरिक्त नहीं की जा सकती।

भारतीय प्रथा के प्रति मुख्य आपत्ति उसके प्रबन्धित होने के सम्बन्ध में नह

थी—क्योंकि सभ्य देशों में किसी-न-किसी रूप में प्रबन्ध तो आवश्यक ही होता है—वरन् उसके कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में थी। प्रोफेसर निकल्सन के शब्दों में, 'किसी देश की अधिकांश जनता का यह सोचना कि करेन्सी में कुछ दोष है, उस देश के लिए बुरा है। स्वर्ण विनिमय प्रमाण की निहित विशेषताएँ चाहे कुछ भी हों, परन्तु उसके कारण निश्चय ही भारतीय यह सोचने लगे थे कि देश की करेन्सी प्रथा बड़ी गड़बड़ है।'

४. मुद्रास्फीति और मूल्यों की वृद्धि—जैसा हम देख चुके हैं कि हिल्टन यंग आयोग ने कहा था कि भारतीय पद्धति स्वन चालित नहीं थी और अतिरिक्त करेन्सी को सङ्कुचित करने की दृष्टि से विशेष रूप से दोषपूर्ण थी। इसका स्वभाविक परिणाम मुद्रा स्फीति और मूल्यों की अत्यधिक वृद्धि हुई। जैसा कि चेम्बरलेन आयोग की रिपोर्ट की आलोचना में प्रोफेसर निकल्सन ने कहा था, रुपये की परिवर्तनीयता आशिक होने और कभी-कभी बन्द कर देने तथा और अधिक रुपया जारी करने के सम्मिलित प्रभाव से मूल्य-वृद्धि अवश्यम्भावी थी।

अत्यधिक शुभचिन्तना के बावजूद भी देश की करेन्सी-सम्बन्धी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में सरकार के अनुमान गलत होने की सम्भावना तो थी ही। रुपयों की माँग वास्तविक और आवश्यक होने पर भी बहुधा ऐसी ही प्रतीत होती थी, अतएव गलत निर्णय बहुत सरल थे, क्योंकि जनता को एक बार जारी किया गया रुपया पूरे देश में फैलकर शीघ्रता से वापस नहीं आता था।

५. अविचारित एवं ध्वंशशील पद्धति—किसी विचारपूर्वक अपनाये गए उद्देश्य के प्रतिकूल शासन-सम्बन्धी अधिसूचनाओं ने भारत में स्वर्ण विनिमय प्रमाण को जन्म दिया। बहुत-सी प्रथाएँ, जो इस पद्धति के मुख्य भाग के रूप में प्रचलित हो गई थी, वैध नहीं थी। जैसा कि अपना मतभेद प्रकट करते हुए (मिनट ऑफ डिसेप्ट, पैरा ५६-६०) स्वर्गीय सर ददीवा दलाल ने कहा था, इस पद्धति की स्पष्ट व्याख्या कभी नहीं की गई और सामान्यतः इसका प्रभाव स्थायित्व के प्रतिकूल ही पड़ा।

स्वर्ण प्रमाण की तुलना में स्वर्ण विनिमय प्रमाण का संस्थापन ही प्रधानतः इसकी प्रशंसा का कारण था। यदि हम ऊपर स्पष्ट की गई सारी हानियों का उचित मूल्य आके तो हमारा यह निष्कर्ष क्षम्य होगा कि यह सस्ती पद्धति सचमुच बहुत महंगी पड़ी।

यह पद्धति जनता की आसपड़न प्रवृत्ति को नष्ट करने और करेन्सी के मितव्ययी रूपों के प्रयोग के लाभ सिखाने में असफल रही।

६. आन्तरिक बनाम बाह्य स्थिरता—स्वर्ण विनिमय प्रमाण के प्रति न्याय करने के लिए हमें इसकी सफलता और असफलता दोनों पर ही ध्यान देना चाहिए। इसे श्रेय देने वाली एक सफलता यह है कि इस देश को विनिमय स्थायित्व का दीर्घ काल प्रदान किया। सचमुच १९१४-१८ के युद्ध में यह बुरी तरह क्षिन्न-भिन्न हो गया, परन्तु उस समय विश्व में लगभग प्रत्येक देश की करेन्सी भी ऐसी ही हो गई

थी। फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि रजत प्रमाप की तुलना में स्वर्ण विनिमय प्रमाप विदेशी विनिमय को अधिक स्थायित्व प्रदान करने में अवश्य सफल रहा। परन्तु समस्त आलोचक इतना भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि युद्धकाल को निकाल देने पर भी स्वर्ण विनिमय प्रमाप प्रस्तावित (स्थापित्व प्रदान करने की) कसौटी पर खरा नहीं उतरता। युद्ध से पहले केवल १९०७-८ के सकटकाल में ही इसकी परीक्षा हुई थी और उस समय इसे बाहरी सहायता से ही बनाए रखा जा सका। सरकार ने प्रमाप को बनाए रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर उधार लेने का आश्वासन दिया और सोने को रखने के लिए मजबूरन कर बढ़ाया, अतएव यह केवल अनुकूल परिस्थितियों की प्रथा थी तथा प्रतिकूलता के चिह्न-मात्र उपस्थित होने पर इसके निष्प्राण होने का भय रहता था।

७. स्वर्ण-पिण्ड प्रमाप—मुधार के अनेक प्रस्तावों की परीक्षा करने के अनन्तर आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि भारत की तत्कालीन परिस्थितियों में सच्चे स्वर्ण प्रमाप की आवश्यकता थी। उन्होंने यह भी कहा कि स्वर्ण को प्रचलन में लाए बिना भी सच्चा स्वर्ण प्रमाप सम्भव था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि भारत में प्रचलन का साधारण माध्यम वर्तमान नोट और चाँदी का रूपया ही रहे और स्वर्ण में करेन्सी का स्थायित्व करेन्सी को प्रत्यक्ष रूप से सारे उद्देश्यों के लिए सोने में परिवर्तनीय बना देने से प्राप्त किया जाए, परन्तु सोने को करेन्सी के रूप में आदि में अन्त तक कभी नहीं चलना चाहिए। (पैरा ५४)

आयोग के अनुसार सोने के प्रचलन के विरोध का प्रधान कारण यह था कि प्रचलन में सोने की जितनी ही अधिक मात्रा लाई जाएगी उतना ही स्वर्ण सुरक्षित कोष कम होता जाएगा और उस पर आधारित साख-व्यवस्था अधिक बेलोचदार हो जाएगी। उन्होंने चेम्बरलेन आयोग के इस विचार का समर्थन किया कि विनिमय की सहायता के लिए स्वर्ण प्रचलन की उपादेयता सन्दिग्ध थी। आयोग ने यह भी कहा कि स्वर्ण पिण्ड प्रमाप से तुरन्त ही पूर्ण स्वर्ण प्रमाप की स्थापना हो जाएगी तथा अन्य योजनाओं में विचारित कोई सक्रमण-काल भी नहीं होगा। विरव की स्थितियों में कोई गड़बड़ी उत्पन्न किये बिना ही इससे स्वर्ण सुरक्षित कोष में अधिक हट होगे ही, साथ ही यह स्वर्ण करेन्सी के चलन के साथ व्यवस्थित भी की जा सकती थी। यद्यपि स्वर्ण करेन्सी का तुरन्त प्रचलन असम्भव था, परन्तु इसके लिए द्वारपुला रखना ही पड़ेगा। आयोग का मत था कि किसी भी स्थिति में स्वर्ण करेन्सी का चलन बुद्धिमानी की दान न होगी और उन्होंने आशा प्रकट की कि कुछ समय बाद भारत इसे जीर्ण-शीर्ण और पुराना आदर्श मानने लगेगा। युद्ध न यूरोपीय देशों को स्वर्ण-मुद्रा की व्यपत्तिल विलासिता से दूर रहना सिखा दिया। वास्तव में कुछ ऊँचे अधिकारियों के अनुसार स्वर्ण करेन्सी का प्रचलन पिछड़ी हुई सम्पत्ता का चिह्न समझा जान लगा। आयोग की योजना के अन्तर्गत करेन्सी अधिकारियों पर कानूनन केवल इतना दायित्व रखा गया कि वे कम-से-कम ४०० बीस मुद्रा सोने की माना में, सोने और रूपये की समता के हिसाब से निश्चित दरों पर सोने का क्रय-विक्रय करेंगे ताकि रूपये के मूल्य

और निर्दिष्ट समता के स्वर्ण-विन्दुओं के बीच (विदेशी) विनिमय की स्थिरता बनी रहे। स्वर्ण प्राप्त करने के उद्देश्य पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया।

८. स्वर्ण की क्रय-विक्रय दरें—आयात लागत अथवा स्वर्ण समता की दृष्टि से करेन्सी के मूल्य के परिवर्तन पर ध्यान दिये बिना रुपये के सम-मूल्य के आधार पर निश्चित स्वर्ण की क्रय विक्रय दरें करेन्सी अधिकारियों को सोने के लिए सबसे सस्ता बाजार बना देंगी। ये केवल भारत में स्वर्ण-पिण्ड बाजार को ही नहीं नष्ट करेंगी बरन् करेन्सी अधिकारियों को अद्रव्यात्मक कार्यों के लिए सोना बेचने का कार्य भी सौंप देगी, जो वास्तव में इनका कार्य नहीं है। इस बन्धन से स्वतन्त्र करने के लिए आयोग ने सिफारिश की कि स्वर्ण का विक्रय मूल्य ऐसी दरों पर निश्चित किया जाए ताकि सोने के भण्डार की पुनः पूर्ति किसी हानि के बिना ही इंग्लैण्ड से आयात करके सम्भव हो सके।^१

आयोग ने सावरेन के कानूनी मुद्रा होने के गुण को तब तक के लिए हटाने का प्रस्ताव किया, जब तक कि सुरक्षित कोष में स्वर्ण करेन्सी को प्रारम्भ करने के लिए पर्याप्त सोना न हो जाए तथा स्वर्ण करेन्सी प्रारम्भ करने के पक्ष में निश्चित निर्णय न हो जाए, अन्यथा करेन्सी के सकुचन को रोकते और विनिमय के क्षतिपूर्क प्रभावों का प्रतिरोध करते हुए सोना सुरक्षित कोष में प्रचलन में चला जाएगा।

९. नोटों की परिवर्तनीयता—आयोग ने भारतीय करेन्सी पद्धति में एक प्रकार के नोटों को अर्थात् कागजी नोटों को दूसरे प्रकार के नोटों अर्थात् रुपयों, जो केवल चाँदी पर अंकित नोट हैं, में बदलने के दायित्व से उत्पन्न गड़बड़ी को दूर करने की सिफारिश की ताकि पद्धति चाँदी के मूल्य की वृद्धि से उत्पन्न भय से मुक्ति पा सके। निस्सन्देह वर्तमान नोटों को रुपये में बदलने की प्रतिज्ञा तो पूरी करनी ही चाहिए, परन्तु नये नोटों को चाँदी के रुपयों में बदलने का कोई दायित्व नहीं होना चाहिए। फिर भी यह वाञ्छनीय था कि जनता का विश्वास और नोटों की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए धातु के रुपयों और नोटों के स्वतन्त्र विनिमय की सुविधाएँ दी जाएँ।

नोटों की रुपयों में परिवर्तनीयता के कानूनी अधिकार को वापस लेने के कारण यह आवश्यक हो गया कि एक रुपये के नोटों को छोड़कर समस्त कानूनी द्रव्य के छोटे नोटों और चाँदी के रुपयों में बदलने का परिनियत दायित्व करेन्सी अधिकारियों पर रखा जाए। नोटों के बदले चाँदी के रुपयों देना करेन्सी अधिकारियों की इच्छा पर था, यद्यपि धारिक करेन्सी के लिए जनता की समस्त उचित माँगों को व्यवहार में पूरा करना चाहिए।

१०. सुरक्षित कोष का एकीकरण और बनावट—आयोग ने सिफारिश की कि पत्र-मुद्रा और स्वर्ण प्रमाण सुरक्षित कोष को मिलाकर एक सुरक्षित कोष कर देना चाहिए ताकि इसकी कार्य-क्षमता का आश्वासन हो सके तथा यह और अधिक सरल होकर जनता की समझ में आ सके।

१. आयोग द्वारा प्रस्तावित रुपये का सम-मूल्य १ शिलिंग ६ पैसे था (८.४७ ग्रेन शुद्ध स्वर्ण)।

नये सुरक्षित कोप के सम्बन्ध में आयोग ने निम्न सिफारिशें प्रस्तुत की—
 (१) विनिमय के क्षतिपूरक प्रभाव, करेन्सी के प्रसार और सकुचन को निश्चित करने के लिए सुरक्षित कोप की बनावट और प्रगति कानून द्वारा निर्धारित होनी चाहिए।
 (२) अनुपातिक सुरक्षित कोप पद्धति अपनानी चाहिए। स्वर्ण तथा स्वर्ण प्रतिभूतियाँ सुरक्षित कोप का कम-से-कम ४० प्रतिशत भाग हों। करेन्सी अधिकारियों को चाहिए कि वे इन्हें सुरक्षित कोप का ५० या ६० प्रतिशत तक कर दें। शीघ्र-से शीघ्र स्वर्ण सुरक्षित कोप का २० प्रतिशत यथाशीघ्र स्वर्ण के रूप में हो जाना चाहिए और १० वर्ष के अन्तर्गत यह स्वर्ण २५ प्रतिशत हो जाना चाहिए। इस बीच में सोना सुरक्षित रखने के लिए किसी भी प्रकार का अनुकूल अवसर हाथ से न जाने देना चाहिए। स्वर्ण भण्डार का कम-से-कम $\frac{1}{2}$ भाग भारत में रहना चाहिए। (३) १० वर्ष के सत्रमण-काल में सुरक्षित कोप में रजत भण्डार को बाकी कम कर देना चाहिए। (४) शेष सुरक्षित कोप व्यापारिक हुण्डियों और भारत सरकार की प्रतिभूतियों के रूप में रखना चाहिए। १० वर्ष के अन्तर्गत 'उत्पन्न की गई प्रतिभूतियों' का स्थान विपणन योग्य प्रतिभूतियों को ले लेना चाहिए। (५) रुपया प्रचलन के सकुचन की दृष्टि से ५० करोड़ रुपये का दायित्व पर्याप्त समझना चाहिए। प्रचलन में चाँदी के रूप की समस्या में की गई वृद्धि अथवा कमी के $\frac{1}{2}$ भाग के बराबर की मात्रा इस दायित्व में जोड़ना अथवा घटाना चाहिए और इस प्रकार होने वाला लाभ अथवा हानि सरकारी आगम को सहना चाहिए।

आयोग ने कहा कि ऊपर कहे गए रूप में स्वर्ण सुरक्षित कोप का दृढ करने में निम्नतम जोखिम और व्यय होगा और यह निम्न कारणों से आवश्यक भी था—
 (१) ताकि करेन्सी अधिकारी करेन्सी के बदले सोना बचने के दायित्व को पूरा कर सकें—विशेषकर नये नोटों की स्वर्ण में परिवर्तनीयता के कारण। (२) स्वर्ण प्रमाण-पत्रों (गोल्ड सर्टीफिकेट्स) के लोकप्रिय होने पर सरकार उन्हें भुनान योग्य बना सके। (३) स्वर्ण करेन्सी के प्रचलन को सुविधा देने के लिए यदि इसे रखने का निश्चय किया जाए।

आयोग ने सिफारिश की कि सुरक्षित कोप में भारत सरकार की रुपया-प्रतिभूतियों की मात्रा वापस न होने वाले प्रचलन के बराबर और इतनी अधिक राशि तक सीमित कर दी जाए जो सरकार की साख को बिगाड़े बिना ही सरलता से बसूल हो सके, क्योंकि ये प्रतिभूतियाँ व्यापारिक हुण्डियों से कम वाञ्छनीय हैं। रुपया-प्रतिभूतियों की तुलना में व्यापारिक हुण्डियाँ करेन्सी अधिकारियों की इच्छा और नियंत्रण से स्वतन्त्र देश की आवश्यकताओं के अनुसार करेन्सी के स्वाभाविक प्रसार और सकुचन का गुण रखती हैं। इससे अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर सरकारी प्रतिभूतियों का घसूलना कठिन हो जाएगा। १९३५ में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना के बाद से पत्र-मुद्रा के निर्गम और सुरक्षित कोप की स्थिति-सम्बन्धी नये प्रबन्धों का विवेचन अध्याय ११ में किया गया है।

स्वर्ण-पिण्ड बनाम स्वर्ण करेन्सी प्रमाप

११. स्वर्ण पिण्ड प्रमाप की आलोचना—आयोग ने स्वर्ण-पिण्ड प्रमाप का समर्थन किया और इसके पक्ष में कहा कि इससे स्वर्ण ही एकमात्र अर्थ का प्रमाप हो जाएगा और हर काम के लिए आन्तरिक करेन्सी की स्वर्ण में परिवर्तनीयता का आश्वासन रहेगा, यद्यपि इसके अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था की गई कि देश में करेन्सी के बदले स्वर्ण सदैव उपलब्ध रहेगा तथा करेन्सी के विनिमय-मूल्य की सहायता के लिए केन्द्रीय सुरक्षित कोष में भी रहेगा परन्तु वह प्रचलन में नहीं आएगा।^१ अन्तिम उद्देश्य की पूर्ति सावरेन के विमुद्रीकरण और दण्ड (बार) के रूप में करेन्सी अधिकारियों द्वारा सोने के विक्रय से की गई। गैर-मुद्राचलन उद्देश्यों के लिए अधिकारियों द्वारा जनता से स्वर्ण-क्रय के प्रति इस प्रकार सावधानी बरती गई कि कम-से-कम ४०० औंस (१०६५ तोला) की मात्रा में प्रस्तुत किये जाने पर ही सरकार खरीद करे तथा खरीद की दर में लन्दन से बम्बई तक सोना भेजने की लागत भी शामिल हो।

१९१४-१८ के युद्ध के पहले स्वर्ण विनिमय प्रमाप के अन्तर्गत अनुमानत. ६,०००,००० पौण्ड की सावरेन जनता के हाथ में थी। इंग्लैण्ड में भी १९२५ के करेन्सी-सम्बन्धी नये प्रबन्धों के अन्तर्गत सावरेन का विमुद्रीकरण नहीं किया गया।

१२. भारत में स्वर्ण करेन्सी प्रमाप का पक्ष—आयोग की स्वर्ण-पिण्ड प्रमाप वाली योजना स्पष्टतः अप्रेञ्ची पद्धति से प्रभावित थी। यह कहा गया कि १९२५ में इंग्लैण्ड में पिण्ड प्रमाप के रूप में स्वर्ण प्रमाप की पुनर्स्थापना १९२२ में जेनेवा सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार विश्व करेन्सी की आदर्श पद्धति—अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय प्रमाप—के विकास की ओर कड़ा कदम था। इस पद्धति के अन्तर्गत आन्तरिक करेन्सी अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा की होगी और स्वर्ण केवल विदेशी ऋणों के भुगतान के लिए उपलब्ध होगा। १९२६ में भारतीय परिस्थितियाँ स्वर्ण प्रमाप एवं स्वर्ण मुद्रा चलन का निर्देश कर रही थी। इन परिस्थितियों में स्वर्ण मुद्रा अनावश्यक विलासिता अथवा स्वर्ण प्रमाप से सम्बद्ध परम्परागत शिष्यता नहीं सभनी जा सकती थी। इसीलिए लगभग असन्दिग्ध सभी भारतीय साक्षी और कुछ यूरोपीय साक्षी, जैसे डॉ० कैनन और डॉ० ग्रेगरी^२, ने हिस्टन यंग आयोग से स्वर्ण करेन्सी प्रमाप अपनाने के लिए आग्रह किया। १३ आयोग के प्रस्तावों के विरुद्ध अन्य आपत्तियाँ—आयोग द्वारा प्रस्तावित स्वर्ण की क्रय-विक्रय दरें भी प्रतिकूल आलोचना का विषय थी। दरो के ऐसे व्यवस्थापन से, कि करेन्सी अधिकारी सबसे सस्ता होने पर सोना खरीदें और सबसे महंगा होने पर बेचें, भारत में स्वर्ण का क्रय-विक्रय लगभग नहीं के बराबर हो जाएगा। यह बात करेन्सी अधिकारियों द्वारा स्वर्ण-विक्रय पर विशेष रूप से लागू होगी। जनता तो निर्यात कार्य के लिए आवश्यक होने पर ही खरीद करेगी। इसके अतिरिक्त विनिमय-

१. २३ नवम्बर, १९०६ को दिल्ली में सर बेसिल ब्लैकेट का भाषण देखिए।

२. देखिए, हिस्टन यंग कमीशन रिपोर्ट, परिशिष्ट ८० और ८१।

दर उच्चतर स्वर्ण-विन्दु से नीचे होने पर वम्बई की तुलना में लन्दन में अधिक अनुकूल दर पर सोने की बिक्री के सम्बन्ध में आयोग के प्रस्ताव का उद्देश्य लन्दन में स्वर्ण देने (बित्रय के लिए) को प्रोत्साहित करना था। इससे स्वर्ण विनिमय प्रमाप की बुराईयाँ तो बनी ही रहेंगी, इसीलिए इसका विरोध किया गया।^१ इस सम्बन्ध में हम आयोग की इस सिफारिश की ओर संकेत कर सकते हैं कि रिजर्व बैंक स्वर्ण सिक्को प्रथवा स्वर्ण-पिण्ड का कम-से-कम आधा भाग भारत में रखेगा। शेष आधा भाग देश के बाहर उसकी शाखाओं, एजेन्सियों अथवा उसके खाते में अन्य बैंको में रखा जा सकता है। बैंक के स्वर्ण की कोई भी मात्रा, चाहे वह एक साल में हो प्रथवा विप्रेरण के मार्ग में, कोप का एक भाग मानी जाएगी। आयोग की सिफारिश के अनुसार स्वर्ण प्रति-भूतियों के रूप में विशाल भण्डार रखने का अर्थ यह है कि उस सीमा तक हमारा सुरक्षित कोप बाहर विनियोजित किया जाएगा। लन्दन में सुरक्षित कोप रखने के कारण उत्पन्न सन्देह और अविश्वास के कारण भारतीय द्रव्य के लन्दन में रखने से सम्बन्धित किसी भी प्रवन्ध को प्रस्तावित करने के लिए विशेष ध्यान देना आवश्यक था।

रुपये का स्थायित्व

१४ स्थायित्व का अनुपात—आयोग ने सिफारिश की कि स्वर्ण के साथ रुपय का स्थायित्व १ सि० ६ पैस की विनिमय दर पर किया जाए और इस प्रकार रुपय को ८४७ ग्रेन जुद्ध सोने के मूल्य के बराबर कर दिया गया। उनका विचार था कि उस दर पर विश्व के मूल्यों के साथ भारत के मूल्य व्यवस्थित हो चुके थे और उससे परिवर्तन करने का अर्थ व्यवस्थापन का कठिन समय तथा अत्यधिक आर्थिक अस्त-व्यस्तना होगी।

आयोग ने तर्क उपस्थित किया कि जब विनिमय और मूल्य पर्याप्त समय तक स्थिर रहे तो विपरीत स्केतो के अभाव में यह स्वीकार करना उचित ही था कि मजदूरी का उनसे सामञ्जस्य हो चुका था। विदनी व्यापार के आँकड़ों से भी इस अनुमान की पुष्टि होती थी। सविदा के सम्बन्ध में आयोग का तर्क यह था कि वे अधिकतर अल्पकालीन थे और इसलिए उच्चतर अनुपात से प्रभावित नहीं थे।

यदि मूल्य और श्रम के साथ १ सि० ६ पैस की दर के व्यवस्थापन को हम न भी मानें तो भी यह गम्भीरतापूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि वे किसी भी तरह १ सि० ४ पैस की दर से व्यवस्थित थी, क्योंकि गत ८ वर्षों में यह दर कभी भी पर्याप्त रूप से प्रभावपूर्ण नहीं रही। जहाँ तक व्यवस्थापन अथवा सामञ्जस्य का प्रश्न है, यह १ सि० ६ पैस पर ही हुआ होगा। इन परिस्थितियों में १ सि० ४ पैस की दर स्थापित करने से मूल्यों में १२ $\frac{१}{२}$ प्रतिशत वृद्धि होना अवश्यम्भावी था जिससे

१. देखिए, पी० वी० जुनरकर, एन इन्वन्विशेसन ऑफ़ दि करन्सी बनीगन रिपोर्ट, पृष्ठ ५५।

साधारणतया उपभोक्ताओं और विशेष रूप से कम वेतन वाले शिक्षित वर्ग की कठिनाइयाँ बहुत बढ़ जाएँगी। इससे श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी में भी कमी होगी, जिसके औचित्य अथवा आवश्यकता का किसी भी आधार पर समर्थन नहीं किया जा सकेगा। १ शि० ४ पैस की दर से केन्द्रीय और प्रान्तीय दोनों सरकारों की वित्त-व्यवस्थाएँ बुरी तरह से अश्वस्थित हो जाएँगी जिससे प्रान्तीय अनुदानों की समाप्ति अनिश्चित काल के लिए स्वगित हो जाएगी।

१५. विमति टिप्पणी (मिनट ऑफ डिसेण्ट)—सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने अपनी विमति टिप्पणी में बताया कि किस प्रकार सरकार ने विनिमय दर बढ़ाकर १ शि० ६ पैस कर देने का विचार किया और इस निश्चय से आयोग की जाँच और निष्कर्ष दोनों को प्रभावित किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि किस प्रकार सितम्बर और अक्टूबर, १९२४ में युद्ध के पहले की १ शि० ४ पैस की दर पर रुपये को स्थिर करने के अवसर को सरकार ने त्याग दिया और विनिमय दर बढ़ाने के लिए २ शि० स्वर्ण की झूठी दर का प्रयोग किया, जिससे करेन्सी में भयावह रूप से संकुचन हुआ। उनके प्रधान निर्णय इस प्रकार थे—

(१) मजदूरी में कोई भी सामंजस्य नहीं हुआ था। बिना भण्डे के कोई सामंजस्य सम्भव भी नहीं था। (२) पूर्ण सामंजस्य होने तक १ शि० ६ पैस की दर ने अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी निर्माताओं को १२ $\frac{1}{2}$ प्रतिशत की आर्थिक सहायता दी, जिससे भारतीय उद्योग पर अधिक भार पड़ा। (३) अनुपात में परिवर्तन का अर्थ ऋणकर्ताओं पर, जो कृपक है, १२ $\frac{1}{2}$ प्रतिशत का अतिरिक्त भार बढ़ाना था। ऋण पुराने होने के कारण यह अनुमान करना स्वाभाविक था कि अधिकांश ऋण १ शि० ४ पैस के आधार पर ही लिये गए होंगे। (४) अतः १ शि० ४ पैस की दर स्थापित करने से राजस्व पर पड़ने वाले प्रभावों को बढ़ा-चढ़ाकर कहा गया था। (५) १ शि० ४ पैस का धुरा प्रभाव जनता के छोटे भाग (लगभग २१ प्रतिशत) तक ही सीमित था जिसमें कम वेतन वाले शिक्षित वर्ग के लोग थे। इसकी तुलना में ऊँची दर से ७६ प्रतिशत व्यक्तियों को कष्ट होगा। जहाँ तक श्रम का सम्बन्ध है, १ शि० ४ पैस की दर अपनाते से मूल्य में सम्भावित वृद्धि से पारिश्रमिक की वर्तमान दर, जो काफी ऊँची थी, व्यवस्थित हो जाएँगी। प्रत्येक दश में निम्न दर से उद्योग और कृषि अधिक समृद्ध होते और इससे रोजगार बराबर मिलता रहता, जबकि उच्च अनुपात से इन दोनों को हानि पहुँचती। (६) १९१४-१८ के पूर्व-प्रचलित १ शि० ४ पैस का अनुपात विश्व के अन्य देशों के अनुपात की तरह ही अश्वस्थित हो गया, परन्तु अन्य देशों ने स्थायी रूप से युद्ध के पहले के अनुपात को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न किया। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि दोनों दशाओं में उत्पन्न गड़बड़ी समान थी, तो निर्णय १ शि० ४ पैस के ही पक्ष में होगा।

१६. विनिमय दर के विवाद का परोक्षण—बहुमत की रिपोर्ट और विमति टिप्पणियों ने एक ऐसा दृष्टान्त प्रस्तुत किया जिससे दोनों ओर के प्रतिद्वन्द्वियों ने भयानक विवाद में अपने-अपने हथियार खींच लिए। देखने में तर्क कितने ही युवितसगत क्यों

न दिखाई पड़े, परन्तु सूक्ष्म परीक्षण पर नये अनुपात के समर्थको और विरोधियों द्वारा दिये गए तर्कों में अनेक दोष दिखाई पड़ेंगे।

(१) बहुमत के तर्कों की आलोचना—बहुमत के अनुसार १ शि० ६ पैसे की दर पर मूल्यों के व्यवस्थापन का तर्क देशनाको पर आधारित था। देशनाक किसी प्रकार भी पय-प्रदर्शक नहीं थे।^१

जूट उद्योग के अतिरिक्त किसी अन्य उद्योग में १ शि० ६ पैसे के साथ मजदूरी का सामजस्य दिवाने के लिए बहुमत ने कोई सांख्यिकीय साक्षी प्रस्तुत नहीं की। दीर्घकालीन सविदाओं में सम्बन्ध में आयोग ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि १ शि० ६ पैसे की दर कठोर सिद्ध नहीं होगी क्योंकि, उदाहरण के लिए, १९१४ के मूल्यों में वृद्धि के कारण मालगुजारी बन्दोबस्त का वास्तविक आयात (इन्सीडेन्स) कम हो गया था। उन्होंने विनिमय के हेर-फेर के कारण मजदूरी के पारिश्रमिक को छिपी हुई कमी के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किया। तर्कसंगत होने के लिए उन्हें मालगुजारी की छिपी हुई वृद्धि को १ शि० ६ पैसे की दर के विरुद्ध समझना चाहिए।

बहुमत का दृढतम तर्क यह था कि उच्चतर दर लगभग १ वर्ष से अधिक लागू रही और इसलिए पर्याप्त सामजस्य अवश्य हो गया होगा। इसके विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि पर्याप्त सामजस्य के लिए एक वर्ष का समय काफी नहीं था, अतएव यह तर्क सामजस्य के विपक्ष में अधिक पड़ता है।^२

(२) १ शि० ४ पैसे की दर के पक्ष का आलोचनात्मक परीक्षण—यह भी भली भाँति सिद्ध किया जा सकता है कि १ शि० ४ पैसे के समर्थको न भी ऐसे तर्कों का आश्रय नहीं लिया जिनका कोई अपवाद न हो। उदाहरण के लिए उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि १ शि० ६ पैसे के अनुपात को ठीक रखने के लिए सरकार ने मुद्रा का अत्यन्त सकुचन किया। यदि मुद्रा सकुचन संचमुच इतना अधिक किया गया था, तो वह अवश्य ही मूल्यों के सामान्य स्तर को काफी नीचे ले आता। मूल्यों में पर्याप्त कमी को स्वीकार करने का अर्थ होगा कि हम १ शि० ६ पैसे की दर पर सामजस्य को स्वीकार करते हैं।

उच्चतर अनुपात के विरोधियों ने ग्रामीण ऋणिता के बढ़ते हुए भार पर तो बल दिया, परन्तु किसानों को सस्ते औजारों की उपलब्धि और सामान्यतः कम लागत के रूप में प्राप्त अनुपात के क्षतिपूर्क प्रभावी पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे यह समझने में भी असफल रहे कि अधिकांश कृषि ऋण वस्तुओं के रूप में लिया जाता है और

१. देखिए, विल्डम यंग कमीशन रिपोर्ट, पैरा १७८-९।

२. अपनी विनति टिप्पणी (मिनिट आफ डिसेण्ट) में (पैरा ८०) सर पुरपोसमदान टाडूरदान ने केम्ब्रिज इस विचार को उद्भूत किया कि अग्निस्तान-जैसे देश में विनिमय के १० प्रतिशत परिवर्तन के सामनस्य के लिए लगभग ० वर्ष का समय आवश्यक है। यदि एक ऐसे देश में, जिनके व्यापार का अधिकांश भाग बाह्य है, इतना समय आवश्यक है, तो भारत-जैसे देश में यह समय अवश्य ही अधिक होना चाहिए, जिनका आंतरिक व्यापार विदेशी व्यापार की तुलना में बड़ी अधिक है।

इसका कुछ भाग अल्पवालीन होता है ।^१

भविष्य के आर्थिक इतिहासवेत्ता नये अनुपात के बाद के समय को वैभव-शाली समय के रूप में अंकित नहीं करेंगे तथा नये अनुपात के बाद देश के कठिन समय और १९२६-३३ के आर्थिक अवसाद ने सरकारी विनिमय पर किये जाने वाले आक्रमणों को और उग्र बना दिया था । तर्क के रूप में यह कहा जा सकता है कि यदि देश पुराने अनुपात को रखता तो उद्योग और वाणिज्य की और भी बुरी दशा ही गई होती । परन्तु इस तर्क में तो यह मान लिया गया है कि १ शि० ६ पैसे की दर पर आधे से अधिक सन्तुष्टि पूरा हो चुका था, जबकि यही सिद्ध करना है । हम लोग ऊपर कह चुके हैं कि सामंजस्य-सम्बन्धी आयोग के विचार के पक्ष में दी गईं साक्षियाँ विश्वसनीय नहीं हैं । हम तो यहाँ तक कह चुके हैं कि यदि १ शि० ४ पैसे की दर में अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक अव्यवस्था की सम्भावना को मान भी लिया जाए—समस्त साक्षी पर निष्पक्ष रूप से विचार करने वाला व्यक्ति भी इससे अधिक नहीं मान सकता—तो भी पुराने अनुपात के लिए इस अवस्था की जोखिम उठाना श्रेयस्कर था । यह नितान्त स्पष्ट होना चाहिए कि जितने अधिक समय तक नई दर^२ बनी रहेगी, उतनी ही उसके सदर्भ में परिस्थितियों के व्यवस्थित होने की भावना दृढ़ होती जाएगी और पुराने अनुपात को पुनः स्थापित करने का पक्ष निर्बल होता जाएगा ।^३

१७ अनुपात (विनिमय दर) के विवाद का तदनन्तर विकास (अप्रैल १९२० से सितम्बर १९३१ तक)—शरद १९२६ में अमेरिका से प्रारम्भ होने वाली आर्थिक सकट की हवा धीरे-धीरे विश्व-भर में फैल गई और सम्पूर्ण विश्व में वस्तुओं और प्रतिभूतियों के मूल्य एवम् गिर गए । भारतीय प्रतिभूतियों का भी यही हाल हुआ । इन परिस्थितियों में विनियोजकों की दुर्बलता विनियोग-सम्बन्धी हिचक के रूप में प्रकट हुई । इस प्रवृत्ति को कठिन राजनीतिक विरोध से और भी बल मिला । विश्व आर्थिक अवसाद की प्रमुख विशेषता मूल्यों, विशेषकर कृषि-मूल्यों, का तीव्र गिराव था, जिससे भारत के कच्चे माल के निर्यात को बहुत हानि पहुँची ।

इन परिस्थितियों में सरकार १ शि० ६ पैसे की विनिमय दर बनाये रखने और विशेष आर्थिक उपायों को अपनाने के लिए विवश हो गई । विनिमय की दृढ़ता के लिए साख नियन्त्रण हेतु अपनाये गए इन उपायों में विनिमय बैंको तथा अन्य क्रेताओं को ट्रेजरी बिलों के निगम तथा इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया की बैंक दर को वृद्धि को गिनाया जा सकता है ।

विश्व आर्थिक अवसाद के बीच मन्दी की व्याख्या के लिए एकमात्र नये अनुपात

१. देखिए, सर जे० सी० कोयानी, इण्डियाज करेंसी, पेसचेज एण्ड बैंकिंग प्रॉब्लेम्स, पृष्ठ १० ।

२. देखिए, नीचे सेक्शन १६, मार्च, १९२७ के इण्डियन करेंसी ऐक्ट द्वारा १ शि० ६ पैसे की नई दर वैध घोषित की गई ।

३. देखिए, सेक्शन २०, २३ और २५ ।

को मुख्य कारण के रूप में चुनना अनम्भव है। हम यह आशा कर सकते हैं कि अनुपात के कारण उत्पन्न आर्थिक अश्वस्थता अनुपात स्थापित करने की निकटतम अवधि में उन्नत होगी और धीरे-धीरे समय बीतने के साथ यह कम होती जाएगी।

परिस्थितियों में मौलिक परिवर्तन होने और अनुपात किसी भी समय बदला जा सकता है, नले ही किसी समय उसका कितना ही सामग्रस्य क्यों न हो गया हो। मिनम्बर, १९३१ में इंग्लैण्ड द्वारा स्वर्ण प्रमाण स्थापने के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी जिनके कारण यह कहा जा सकता है कि इस विषय पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो गया था।^१ एकमात्र आर्थिक दृष्टिकोण से भी प्रश्न १ सि० ६ पै० और १ सि० ४ पै० के बीच चुनाव करने का ही नहीं है। नये अनुपात के परिष्कार की सम्भावना का अर्थ १ सि० ४ पैस के पुराने अनुपात की स्थापना नहीं है। हम इसके लिए तत्पर रहना चाहिए कि यदि स्थिति का सम्पूर्ण और निष्पक्ष पुनर्विचोचन वर्तमान अनुपात का परिवर्तन आवश्यक नमनना है (१ सि० ६ पै० स्टलिंग) तो यह भी सम्भव हो सकता है कि इन परिवर्तित परिस्थितियों में उपयुक्ततम अनुपात १ सि० ४ पैस न होकर कोई अन्य अनुपात ही हो।

१८ सरकार द्वारा हिल्टन यंग आयोग की रिपोर्ट का स्वीकरण—१६ जनवरी १९२७ को सरकार ने तीन बिल प्रकाशित किए जिनमें आयोग की सिफारिशें निहित थी—(१) पहला बिल ब्रिटिश भारत के लिए स्वर्ण प्रमाण करेन्सी स्थापित करने और रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का निर्माण करने के लिए था। (२) दूसरा बिल १९२० के इम्पीरियल बैंक कानून को सुधारने के लिए था। (३) तीसरा बिल कुछ उद्देश्यों के लिए १९२३ के पत्र-मुद्रा कानून और १९०६ के टकन कानून को सुधारने और स्वर्ण विनियम (वाद में बदलकर स्टलिंग हो गया) के खरीदने और वेचन के सम्बन्ध में सरकार पर कुछ दायित्व रखने के लिए था। बैंकिंग के अध्याय में हम पहले और दूसरे बिल की चर्चा करेंगे। यहाँ हम तृतीय बिल से सम्बन्धित हैं जो विधानसभा में ७ मार्च, १९२७ को सर वेसिल ब्लैंकेट द्वारा प्रस्तावित किया गया। वित्त-मन्त्री ने करेन्सी बिल क सिद्धान्तों को स्पष्ट किया, जिसमें कहा गया कि रुपये को स्थिर करने का समय आ गया था और भारत के वित्तीय इतिहास में पहली बार इन प्रकार निश्चित दर अनुपात को बनाए रखने के लिए करेन्सी अधिकारियों को कानूनन उत्तरदायी ठहराया।

१९. मार्च १९२७ का करेन्सी एक्ट—बम्बई की टक्काल में २१ ₹० ३ भा० १० पा० प्रति तोला शुद्ध स्वर्ण की दर से कम-से-कम ४० तोला (१५ औंस) वाले स्वर्ण-दण्ड के रूप में अमीनिन स्वर्ण क्रय सम्बन्धी कानून बनाकर सरकार ने १ सि० ६ पैस के नये अनुपात को स्थापित किया। चाँदी के रुपये और कागजी नोटों के स्वामी कलकत्ता व करेन्सी-नियन्त्रक (करेन्सी कंट्रोलर) अथवा बम्बई के करेन्सी

उपनियन्त्रक (डिप्टी करेन्सी कण्ट्रोलर) को प्रार्थना-पत्र देकर बम्बई की टकसाल से सोना अथवा सरकार की इच्छानुसार लन्दन में तुरन्त अर्पित करने के लिए स्टर्लिंग प्राप्त कर सकते थे, परन्तु शर्त यह थी कि २१ रुपया ३ आना १० पाई प्रति तोला शुद्ध स्वर्ण की दर पर कम-से-कम १०.६५ तोला (४०० ग्रांस) शुद्ध सोना अथवा स्टर्लिंग की मांग करे और उसका दाम चुकाएँ।^१ बम्बई से लन्दन तक के यातायात व्यय की छूट देकर स्टर्लिंग का विक्रय भी उसी कीमत पर होता था। इन दायित्वों को पूरा करने के लिए स्टर्लिंग की सरकारी विक्रय दर १ शि० ५ $\frac{५}{८}$ पै० नियत की गई।^२ १ अप्रैल, १९२७ को, जब इण्डियन करेन्सी एक्ट लागू किया गया, बम्बई टकसाल में स्वर्ण स्वीकार करने की शर्तें प्रकाशित की गईं।

इस कानून के अनुसार सावरेन और अर्ध-सावरेन भारत में कानूनी मुद्रा न रही^३, परन्तु सरकार पर यह दायित्व रखा गया कि वह इन सिक्कों को सभी करेन्सी कार्यालयों और खजानों में २१ रु० ३ आ० १० पा० प्रति तोला शुद्ध स्वर्ण के मूल्य पर अर्थात् १३ रुपया ५ आना ४ पाई प्रति सावरेन की दर पर स्वीकार करे। इन सिक्कों के कानूनी मुद्रा न रहने पर भी भारत में सावरेन का प्रशासनीय आयात हुआ। १९२७ के करेन्सी एक्ट ने देश में स्वर्ण-पिण्ड एव स्टर्लिंग विनिमय प्रमाप की स्थापना की। स्टर्लिंग देना सरकार की इच्छा पर निर्भर होने के कारण सकुचित अर्थ में इस प्रकार स्थापित प्रमाप स्टर्लिंग विनिमय प्रमाप था, यद्यपि व्यवहार में २० सितम्बर, १९३१ तक इमने स्वर्ण विनिमय प्रमाप के रूप में काम किया, क्योंकि तब तक स्टर्लिंग और सोने का मूल्य समान था। यदि सरकार रुपये के बदले में स्वर्ण देने के विकल्प का प्रयोग करती तो व्यवहार में भारत में स्वर्ण प्रमाप ही होता। १९२७ के स्टर्लिंग विनिमय प्रमाप में स्वर्ण प्रमाप बनने की क्षमता थी। इससे यह प्रकट होता था कि स्वर्ण प्रमाप निश्चय ही सरकार का उद्देश्य था।^४

२०. स्टर्लिंग और स्वर्ण का सम्बन्ध तथा भारत में इसकी प्रतिक्रियाएँ—ग्रेट ब्रिटेन तथा अन्य कई देशों में स्वर्ण प्रमाप की समाप्ति के फलस्वरूप विश्व-करेन्सी तथा विनिमय स्थिति में हुए नाटकीय परिवर्तनों के कारण १९२७ के कानून द्वारा स्थापित द्राव्यिक प्रमाप को मौलिक स्वर्ण (पिण्ड) प्रमाप में परिवर्तित होने का उचित अवसर नहीं मिला। २१ सितम्बर, १९३१ से ग्रेट ब्रिटेन ने स्वर्ण प्रमाप को त्याग दिया। उसी तिथि को सोना अथवा स्टर्लिंग बेचने के दायित्व को स्थगित करते हुए गवर्नर जनरल ने एक आर्डिनेंस जारी किया और राज-सचिव ने १ शि० ६ पै० स्टर्लिंग की दर पर रुपये को बनाये रखने के निर्णय की घोषणा की। २४ सितम्बर को गवर्नर जनरल

१. देखिये एल० सी० जैन, मॉनिटरी प्रावलेम ऑफ इण्डिया, पृष्ठ ३२।

२. रिपोर्ट ऑफ दि कण्ट्रोलर ऑफ करेन्सी (१९२६-२७), पृष्ठ ३।

३. यहाँ यह जानना आवश्यक है कि ब्रिटिश गोल्ड स्टैंडर्ड एक्ट १९२५ द्वारा स्वर्ण मुद्रा का विमुद्रीकरण नहीं किया गया, हालांकि स्वतंत्र मुद्रण बन्द कर दिया गया।

४. जैन, पूर्वोक्त, पृ० ३५।

ने गोल्ड एण्ड स्टैलिग सेल्स रेगुलेशन आर्डिनेन्स को जारी किया, जिसने पुराने आर्डिनेन्स को रद्द कर दिया और पारिभाषिक रूप में १९२७ के करेन्सी कानून के विधानों को पुनः लागू किया, परन्तु इस आर्डिनेन्स के अन्तर्गत व्यवहार में स्टैलिग की बिन्नी पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण रखा गया और इस प्रकार नियन्त्रित स्टैलिग विनिमय प्रमाण प्रारम्भ किया गया। नये आर्डिनेन्स के अन्तर्गत, स्टैलिग कुछ मान्यता प्राप्त बैंकों को ही बेचा जा सकता था जो इस सम्बन्ध में अपना उत्तरदायित्व समझते थे। व्यापार को सामान्य आवश्यकताओं और २१ सितम्बर तक बिये गए ठेकों के अर्थ-प्रबन्धन तथा उचित व्यक्तिगत एवं घरेलू उद्देश्यों के लिए यह पहलो दर अर्थात् १ सि० ५६^६/_{१००} पैसे की पुरानी दर पर बेचा जाता था। यह पिण्ड (बुलियन) के आयात अथवा परिकल्पनात्मक विनिमय के अर्थ प्रबन्धन के लिए नहीं बेचा जाता था। भारत से धन के प्रवाह को रोकने और सरकार के स्वर्ण एवं स्टैलिग साधनों पर अनुचित भार न पड़ने देने के लिए इस प्रकार की सावधानियाँ बरती जाती थीं। इन नियन्त्रणों के लिए इम्पीरियल बैंक की एजेन्सी से काम लिया जाता था। स्टैलिग से सम्बन्ध होने के कारण सोने तथा उस पर आधारित अन्य करेन्सियों, जैसे डालर और फ्रैंक, के सम्बन्ध में रूपया स्टैलिग के अवमूल्यन एवं उतार-चढ़ाव में स्वाभाविक रूप से भागी होता था। स्टैलिग डालर-क्रॉस रेट में द्रष्टव्य स्वर्ण के मूल्य की स्टैलिग में वृद्धि का अर्थ रूपयो में भी स्वर्ण के मूल्य की वृद्धि होता था। सोने का मूल्य अगस्त, १९३१ के अन्त तक २१ रूपया १३ आना ३ पाई प्रति तोला था, परन्तु दिसम्बर, १९३१ में यह बढ़कर २६ रूपया २ आना प्रति तोला हो गया।^१ ऊँचे मूल्यों की प्रेरणा और अशत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित आर्थिक कठिनाई ने जनता को सोना बेचने के लिए प्रस्तुत कर दिया।

सरकार की करेन्सी और विनिमय सम्बन्धी नीति के इस पहलू ने तीव्र विवाद को जन्म दिया। भारतीय विधानमण्डल की राय लिये बिना ही राज-सचिव ने एक नई करेन्सी नीति की घोषणा कर दी, जिससे लोग अप्रसन्न हो गए। इसके अनिश्चित सरकार के विपरीत की गई आलाचनाएँ दो भागों में विभाजित हो गईं—(१) १ सि० ६ पैसे पर रूपये का स्टैलिग से सम्बन्ध, (२) भारत से सोने का अनियमित निर्यात।

२१ रूपये को १ सि० ६ पैसे से सम्बन्धित करना—सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के सन्धान में दिव गए मुख्य तर्क निम्नलिखित हैं—(१) सरकार के पास दो विकल्प थे। रूपय को स्टैलिग से सम्बद्ध कर अपेक्षाकृत स्थायित्व प्राप्त करना तथा रूपये के विनिमय मूल्य को नियमित करने के किसी प्रयास के अभाव में पूर्ण अस्थायित्व का जोखिम उठाना। इन विकल्पों में से पहला विकल्प निश्चय ही अधिक पसन्द करने

^१ बाद के वर्षों में सोने का मूल्य और अधिक हो गया। ७ मार्च, १९३५ को ३६ रूपया १३ आना ३ पाई प्रति तोला हो गया। अंग्रेज द्वारा स्वयं प्रमाण क्षेत्रों में के बाद यह स्वयं उँचा मूल्य था। मनुअल मार्केट रिब्यू (प्रेसिडेंट रायचन्द एण्ड सन्स) १९३५, पृष्ठ ८०।

योग्य था। (२) यद्यपि हिल्टन यंग आयोग का मत रुपये को स्टर्लिंग से सम्बद्ध करने के विपरीत था, परन्तु इस विचार का, जो साधारण समय में बहुत ठीक था, कठिन परिस्थितियों में अनुसरण नहीं किया जा सकता था। भारत का वार्षिक ऋण ३२० लाख पाउण्ड स्टर्लिंग का था और १५० लाख पाउण्ड का स्टर्लिंग ऋण १९३२ के प्रारम्भ में परिपक्व होने वाला था। रुपये को स्टर्लिंग से सम्बद्ध किये बिना इन उद्देश्यों के लिए आवश्यक कोष एकत्र करने में अनेक कठिनाइयाँ थीं। स्टर्लिंग रुपये की स्थिरता के अभाव में भारतीय आय-व्ययक (बजट) विनिमय की छूट क्रीड़ा (जुआ) हो जाएगा। (३) जब तक भारत ऋणी देश था, तब तक रुपये को अकेला छोड़कर एक अज्ञात दिशा में अचानक कूद पड़ने का जोखिम इंग्लैण्ड-जैसे साहूकार देशों की तुलना में बहुत अधिक था। (४) स्टर्लिंग पर आधारित देश तथा लन्दन से होने वाला भारत का व्यापार उसके कुल विदेशी व्यापार का बहुत बड़ा भाग था, अतएव इस व्यापार के लिए स्थायी आधार प्राप्त करना उचित ही था। (५) सोने में रुपये के अवमूल्यन के कारण स्वर्ण प्रमाप वाले देशों के साथ भारत के निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन—चाहे वह अल्पकालीन क्यों न हो—मिलेगा। (६) सरकार के जो आलोचक रुपये को १ शि० ६ पै० से कम पर स्थिर करना चाहते थे, उनसे तब यह शिकायत करते नहीं बनी जब प्रचलित क्रॉस रेट पर रुपये का मूल्य १ शि० ४ पैस से कहीं कम था।

दूसरे पक्ष के प्रधान तर्क इस प्रकार थे—(१) रुपये को स्टर्लिंग से सम्बद्ध करने से भारत स्टर्लिंग के उतार-चढ़ाव का भागी हो गया, जिससे भारत की ही नहीं बरन् इंग्लैण्ड की आर्थिक दशा प्रदर्शित होती थी। इसके विपरीत रुपये को अकेला छोड़ देने से निस्सन्देह अस्थायित्व पैदा हो जाता, परन्तु वह स्वयं भारत की दशाओं को प्रदर्शित करता। इस प्रकार विदेशी व्यापार और आन्तरिक मूल्य-स्तर के सम्बन्ध में अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल विनिमय-दर अपनाने की स्वतन्त्रता भारत सँझी ली गई। (२) उत्तरी अमरीका जैसे स्वर्ण प्रमाप वाले देशों को निर्यात के लाभ के विपरीत इन देशों से आयात की हानियों को भी ध्यान में रखना चाहिये। साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिये कि रुपये को स्टर्लिंग से सम्बन्धित करना इंग्लैण्ड को दिये गए साम्राज्य अधिमान का एक रूप ही था। () यह भय भी था कि १ शि० ६ पैस की दर पर रुपया स्थिर करने के प्रयास से देश के शेष सुरक्षित स्वर्ण-कोष समाप्त हो जाते। उसे सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा किये गए प्रबन्धों, यथा जनता को स्टर्लिंग बेचने के प्रतिबन्ध, के कारण यह भय अधिक गम्भीर नहीं था। (४) अन्त में यह तर्क भी उपस्थित किया गया कि यद्यपि सोने में रुपये का अवमूल्यन हो गया था, फिर भी १ शि० ६ पैस की दर पर रुपया अधिमूल्यित था, जबकि येन और अन्य करेंसियों का स्टर्लिंग में अवमूल्यन हो चुका था। इस प्रकार भारत को काफी हानि उठानी पड़ी।^१

१. भारत में स्वर्ण-निर्यात-विवाद के दोनों पक्षों की विवेचना के लिए, बी० आर० रिनाय और बी०

२२. भारत से स्वर्ण-निर्यात—सितम्बर, १९३१ में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा स्वर्ण प्रमाप त्यागने के बाद से जनवरी, १९४० के अन्त तक भारत से ३५१.४० करोड़ रुपये के स्वर्ण का निर्यात किया गया। इस निर्यात की व्याख्या भारत के स्वर्ण साधनों की दरवादी, देशी बैंकिंग प्रणाली की छिन्न भिन्नता तथा पीडियों की वचत की समाप्ति के रूप में की गई। यह तर्क उपस्थित किया गया कि स्वर्ण निर्यात के आकस्मिक सह-योग ने १ सि० ६ पैस की दर पर रुपये के अधिमूल्यन को छिया दिया और सोने के अनियन्त्रित निर्यात ने देश का स्वर्ण-प्रमाप के उद्देश्य तक पहुँचना असम्भव बना दिया। ऐसे अपूर्व पैमाने पर निर्यात किये गए सोने का पुन खरीदना भारत के लिए आसान नहीं था। भारत के विपरीत विश्व के अन्य देश अपने स्वर्ण-भण्डारों को सुरक्षित रखे हुए थे और सम्भव होने पर उनमें वृद्धि करते जाते थे।

सरकारी नीति के समर्थन में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वित्रीत सोना करन्सी-स्वर्ण नहीं था वरन् व्यापारिक स्वर्ण था और मूल्य के भण्डार के रूप में काम करने वाली वस्तु थी। यह इसलिए देखा गया क्योंकि इसके स्वामियों को इससे लाभ प्राप्त हो रहा था। इसे बेचने का एक अन्य कारण यह भी था कि अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए अनेक व्यक्ति अपनी सम्पत्तियों को नकद रुपये में बदलने के लिए विवश थे। प्रचलित आर्थिक कठिनाई अत्यन्त शोचनीय थी, परन्तु स्पष्टतया परेशान व्यक्तियों का हित सबसे महँगे बाजार में सोना बेचने के लिए दी गई असीमित स्वतन्त्रता में था। पुन यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि व्यक्तिगत अधिकार से सरकार सोन को उस समय तक प्राप्त नहीं कर सकती जब तक कि सोन का मूल्य उसके अधिकारियों के लिए पर्याप्त रूप से आकर्षक न हो। निर्यात किया हुआ सोना भारत के कुल सोने का एक अंशमान था। कुल स्वर्ण भण्डार ७५०० लाख पौण्ड अनुमानित किया गया था। इस देश में जनता की प्रसिद्ध स्वर्ण-भूख का अकस्मात् लोप नहीं हो सकता था, अतएव कालान्तर में मूल्यों के सामान्य हो जाने पर वह पुन खरीदकर वापस आ जाएगा। इस बीच में स्वर्ण-विक्रय व्यापारिक चक्र को स्निग्ध तथा उत्पादन की सहायता कर रहा था। व्यापारिक सन्तुलन पर इसका प्रभाव अनुकूल पड़ा और इसने गतिहीन धातु की सजीव मुद्रा का रूप प्रदान किया। राज-सचिव के लिए स्टर्लिंग विप्रेरण और स्टर्लिंग सुरक्षित कोष को हड़तर करन की दृष्टि से सरकार की आर्थिक स्थिति पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा। इसने रुपया स्टर्लिंग वित्तमय को १ सि० ६ पैस की दर पर स्थायित्व प्रदान करने में भी सहायता पहुँचाई और लन्दन तथा विश्व में भारत की साख को सुचारु दिया। स्वर्ण निर्यात ने नोट प्रचलन, पोस्टल केश सर्टिफिकेट, पोस्टल सेविंग्स डिपॉजिट, बैंक की जमा आदि में वृद्धि की सामान्यतः सस्ते द्रव्य की स्थिति उत्पन्न कर देश के व्यापारिक पुनरुत्थान में सहायता पहुँचाई।

२३. अनुपात का प्रश्न और रिज़र्व बैंक बिल—हम देख चुके हैं कि किस प्रकार सितम्बर, १९३१ में रुपये को स्टैलिंग से सम्बद्ध किया गया और मार्च, १९२७ के करेन्सी एक्ट लागू रहने पर भी किस प्रकार भारतीय द्रव्य प्रमाप स्टैलिंग विनिमय प्रमाप के रूप में काम करने लगा। प्रस्तावित रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया पर लगाए जाने वाले विनिमय-सम्बन्धी दायित्वों और वन्धनों की प्रकृति के सम्बन्ध में उचित द्रव्यात्मक प्रमाप और अनुपात का सम्पूर्ण प्रश्न पुनः विवाद का विषय बन गया। रिज़र्व बैंक विधान की लन्दन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट (अगस्त, १९३३) में कहा कि बैंक पर लगाए जाने वाले विनिमय-दायित्व के सम्बन्ध में उठने वाले प्रश्न वर्तमान परिस्थितियों में कठिनाई उपस्थित करते हैं। विश्व की वर्तमान द्रव्यात्मक अस्तव्यस्तता के समय में (रिज़र्व बैंक) बिल में उन प्रस्तावों को रखना असम्भव है जो द्रव्यात्मक पद्धति के पुनः स्थिर होने पर उचित होंगे। इन परिस्थितियों में भारत के लिए सबसे सुन्दर मार्ग स्टैलिंग प्रमाप पर रहना ही है। इस आधार पर बिल में निहित विनिमय-दायित्व बिल पेश करते समय विद्यमान रूपया और स्टैलिंग के अनुपात के अनुसार होना चाहिए। यह कथन वर्तमान अनुपात के शुष्ण और भ्रवगुण पर कमेटी का कोई मत प्रकट नहीं करता है। बिल में अनुपात-सम्बन्धी प्रस्तावों से यह स्पष्ट है कि रिज़र्व बैंक एक्ट के कार्यान्वित होने से ही वस्तुस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम सब लोग इसमें सहमत हैं कि किसी भी दशा में इसको प्रस्तावना में स्पष्ट कर देना चाहिए कि भारत के लिए उचित द्रव्यात्मक प्रमाप पर उस समय पुनः विचार किया जाए जब अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति स्पष्ट रूप से समक्ष आ जाए और स्थायी विधान के लिए पर्याप्त रूप से स्थिर हो जाए। (पैरा १६) जैसा कि कमेटी ने स्पष्ट स्वीकार किया है, भारतीय प्रतिनिधियों के बहुमत ने अपने इस विचार को अंकित करना अपना कर्तव्य समझा कि रिज़र्व बैंक के कार्यों की सफलता के लिए उचित विनिमय-अनुपात का होना आवश्यक था। पिछले कुछ वर्षों में विश्व के लगभग सारे देशों में करेन्सी के आधारी और करेन्सी नीति में पर्याप्त परिवर्तन हो चुके थे। उनके अनुसार भारत को करेन्सी पद्धति पर निम्नतम भार रखने के विचार से भारत सरकार और विधानमण्डल की इन बातों की परीक्षा करनी चाहिए। एक पृथक् नोट में सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया के उद्घाटन से पूर्व अनुपात के पुनर्विलोकन का जोरदार समर्थन किया और आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैण्ड और संयुक्तराज्य के उदाहरण प्रस्तुत किये, जिन्होंने व्यापारिक सन्तुलन के सुधार और मूल्य-वृद्धि के लिए अपनी करेन्सियों का अवमूल्यन किया था। उन्होंने भारत के इस दृढमत को उच्चृत किया कि १ सि० ६ पै० के वर्तमान अनुपात की कमी से किसानों को बहुत सहायता मिलेगी। रिज़र्व बैंक बिल सितम्बर, १९३३ में संयुक्त प्रवर समिति (ज्वायण्ट सलेक्ट कमेटी) को सौंपा गया।

२४ नये करेन्सी अधिकारी के रूप में रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया का विनिमय-दायित्व—१९३४ के कानून में निहित अनुपात-सम्बन्धी धाराओं (४० और ४१) ने रिज़र्व बैंक विधान के लिए नियुक्त लन्दन समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित

किया। रिज़र्व बैंक से वर्तमान अनुपात (१ सि० ६ पै० स्टलिंग) को उच्चतर और निम्नतर बिन्दु के बीच व्यवस्थित करने के लिए कहा गया, मानो रुपया स्वर्ण-प्रमाण पर था। चालीसवीं धारा के अनुसार रिज़र्व बैंक अपने कार्यालयों—बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली और रगून—में कानूनी मुद्रा में भुगतान करने पर किसी भी व्यक्ति को लन्दन में देने के लिए १ सि० ५ $\frac{1}{2}$ पैस की दर पर स्टलिंग बेचने के लिए बाध्य था। इस विधान का अर्थ रुपये को १ सि० ५ $\frac{1}{2}$ पैस से नीचे गिरने से बचाना है, जो रुपये के निम्नतर बिन्दु के अनुरूप था। (१ सि० ६ पैस—स्टलिंग की इस मात्रा को लन्दन में रखन का व्यय) इसके विपरीत धारा ४१ के अनुसार तत्काल ही लन्दन में देने के लिए १ सि० ६ $\frac{3}{4}$ पैस की दर पर किसी भी व्यक्ति से स्टलिंग खरीदना बैंक के लिए आवश्यक था। यह दर रुपये के उच्चतर बिन्दु के अनुरूप थी (१ सि० ६ पैस—इस मात्रा की स्टलिंग को लन्दन से बम्बई आयात करने का व्यय)। यह भी निर्धारित किया गया कि कोई भी व्यक्ति १० हजार पाउण्ड से कम मात्रा में स्टलिंग की माँग बेचने और खरीदने के लिए नहीं कर सकता।^१

करेन्सी के सम्बन्ध में आधुनिक व्यवस्था

मूल अधिनियम के अन्तर्गत यह प्रस्तावित था कि जारी किये गए नोटों के पीछे एक निश्चित अनुपात में सोना और विदेशी प्रतिभूतियाँ रखी जाएँ। कुल सम्पत्ति (एमेट) का ४० प्रतिशत सोना, सोने का सिक्का और विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में होना चाहिए, किन्तु किसी भी समय सोने और सोन के सिक्कों का मूल्य ४० करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए। यह व्यवस्था लगभग २० वर्ष तक चलती रही।

नोट निर्गमन को विदेशी प्रतिभूतियों से सम्बन्धित करना अब भूतकाल की बात हो गई है। युद्ध एवं युद्धोत्तरकालीन वर्षों में केन्द्रीय बैंक-सम्बन्धी अधिनियमों की सामान्य प्रवृत्ति नोट निर्गमन से विदेशी सुरक्षित कोष को असम्बद्ध करने की रही है। अब लगभग सभी यह मानते हैं कि विदेशी विनियम के सुरक्षित कोष का सामान्य उद्देश्य यही है कि देश भुगतान सन्तुलन के प्रतिकूल परिवर्तनों का सफलतापूर्वक सामना कर सके। भारतीय अर्थ व्यवस्था में द्रव्य का प्रसार तथा विकास-योजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक क्रियाओं की तीव्र प्रगति के फलस्वरूप चलार्थ (करेन्सी) में पर्याप्त विस्तार अपेक्षित होगा। इन सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखकर ही रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया (संशोधन) अधिनियम १९५६, जो ६ अक्टूबर १९५६ से लागू हुआ, के अन्तर्गत आनुपातिक व्यवस्था के स्थान पर विदेशी सुरक्षित कोष की एक निम्नतम राशि अर्थात् ४०० करोड़ रु० की विदेशी प्रतिभूतियाँ तथा ११५ करोड़ रु० का सोना या सोन के सिक्के रखन का विधान है। इस अधिनियम ने अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्यात्मक कोष (आई० एम० एफ०) द्वारा मान्य सोन का मूल्य रु० ६२ ५० प्रति तोला

१. अप्रैल, १९४७ के रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया एमेन्डमेंट १९४७ ने धारा ४०-४१ को रद्द कर दिया और इसलिए अब स्टलिंग को बेचने और खरीदने का कोई परिनिश्चित दायित्व रिज़र्व बैंक पर नहीं है।

निश्चित किया जबकि पहले यह मूल्य २० २१-२४ प्रति तोला था ।

यह परिवर्तन नितान्त अगोपचारिक था और इसका अभिप्राय बैंक के स्वर्ण कोप के अर्थ को नये मूल्य के अनुसार प्रदर्शित करना था । इसके परिणामस्वरूप ही सुरक्षित स्वर्ण-कोप की मात्रा ११५ करोड़ ६० निश्चित की गई थी जबकि पहले (अर्थात् जब सोने का मूल्य २० २१-२४ प्रति तोला था) यह ४० करोड़ ६० था । १९५७ में अधिनियम में पुनः परिवर्तन किया गया । रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (द्वितीय संशोधन) अधिनियम १९५७ ने यह निर्धारित किया कि सोना, सोने के सिक्के तथा विदेशी प्रतिभूतियों का कुल मूल्य किसी भी समय २०० करोड़ ६० से कम नहीं होना चाहिए । पहले की तरह इसमें से ११५ करोड़ ६० के मूल्य का सोना अथवा सोने का सिक्का होना चाहिए । इस अधिनियम के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को यह अधिकार भी दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बाद वह विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में कुछ भी न रखे, किन्तु ११५ करोड़ ६० के मूल्य का सोना उसे सदैव रखना चाहिए ।

२५. अवमूल्यन का पक्ष और विवक्ष—उपर्युक्त प्रबन्ध सरकार की करेन्सी नीति के आलोचकों और भारतीय व्यापारिक समाज में अवमूल्यन के समर्थकों को सन्तुष्ट न कर सका (सेक्शन २३ भी देखिए) । इसके अतिरिक्त वित्त सदस्य के विचार में अनुपात कम करने से भारत की आय-व्ययक-सम्बन्धी समस्याएँ, जो अभी बहुत कठिन हैं, हल न हो सकेंगी । (१९३६-४५ के युद्ध के कुछ पूर्व क आय व्ययक की बचत इस तर्क के विरुद्ध थी ।) सस्ते द्रव्य की विद्यमान प्रचुरता में, जो मूल्य-वृद्धि का मान्यता-प्राप्त सामान्य साधन है, भारत में अस्वास्थ्यकर परिवर्तन की परिस्थितियों को जन्म दिया, जिससे प्रतीत होता था कि कृषि-प्रधान देश में मूल्य की वृद्धि के लिए सस्ता द्रव्य-मात्र ही पर्याप्त नहीं है । वित्तमन्त्री के विचार में सस्ते द्रव्य के अतिरिक्त यह भी आवश्यक था कि विश्व के देशों में अपनी-अपनी करेंसियों को स्थिर करने और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रतिवन्ध कम करने की सहमति हो । अक्टूबर, १९३६ में रुपये के अवमूल्यन के सम्बन्ध में विवाद उठ सड़ा हुआ, जो सितम्बर में फ्रांस तथा स्वर्ण-समूह देशों की करेंसियों के अवमूल्यन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भारत में उत्पन्न हुआ था । अवमूल्यन के समर्थकों ने विधानसभा में काम स्थगित करने का प्रस्ताव पेश किया जो केवल सभापति के वोट से ही हराया गया ।

इसके विपरीत अवमूल्यन के विरोधियों ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उस समय भारत द्वारा करेंसी का अवमूल्यन (१९३६) इंगलिस्तान (यूनाइटेड किंगडम), संयुक्तराज्य और फ्रांस द्वारा किये गए त्रिपक्षी द्वाब्यिक समझौते को भंग कर देगा और इससे विश्व की करेंसियों के स्थिरीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । भारत द्वारा रुपये का अवमूल्यन अन्यत्र प्रतिकारों को उत्तेजित करेगा और करेंसी-युद्ध को

५. अवमूल्यन-सम्बन्धी विवाद के विरुद्ध आलोचनात्मक विवरण के लिए देखिए, वी० एन० अदारकर 'विन्सुशान ऑफ दी रुपी' (१९३७) ।

पुनर्जीवित कर देगा। स्टलिंग से सम्बद्ध होकर सोने की तुलना में रुपये का ४० प्रतिशत अवमूल्यन हो चुका था। अतएव रुपये के और अधिक अवमूल्यन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उपर्युक्त अवमूल्यन के फलस्वरूप भारत स्टलिंग क्षेत्र के आर्थिक पुनरुत्थान में भाग लेने योग्य हो गया था। रुपये की अधिमूल्यता नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि करेन्सी के अधिमूल्यन का कोई चिह्न ही न था। उदाहरण के लिए, बजट का पाटा, द्रव्य की ऊँची दर, करेन्सी सुरक्षित कोष में सोने की कमी, ह्याममान व्यापारिक सन्तुलन और मुद्रा-मकुचन-जैसे कोई चिह्न विद्यमान नहीं थे। यूरोपीय करेन्सियों के अवमूल्यन ने भारत को अधिक प्रभावित नहीं किया और विदेशी करेन्सियों के अवमूल्यन के फलस्वरूप हुए राशिपतन से अपने उद्योगों की सुरक्षा के लिए १८६४ के प्रचलक अधिनियम (टेरिक एक्ट) से भारत सुमज्जित था। जहाँ तक हमारे अति अभिलषित निर्यात व्यापार के पुनरुत्थान का सम्बन्ध है, अवमूल्यन प्रतिवार की भावना को उत्तेजित कर स्थिति को और बिगाड़ देगा। वास्तविक कठिनाई विदेशों की आर्थिक राष्ट्रीयता और व्यापारिक प्रतिबन्ध थे, अतएव इसका उचित हल अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना और शान्ति की वृद्धि तथा करेन्सियों का स्थिरीकरण था। अन्त में यह भी कहा गया कि अवमूल्यन करना भारत के लिए बुद्धिमानी न होगी, क्योंकि इनसे नए विज्ञान के अन्नगंत प्रान्तीय स्वतन्त्रता प्राप्त होने के समय क्रोटो-निमेयर (आर्थिक) निर्णय गड़बड़ हो जाएगा।

१९३७-३८ की आर्थिक मन्दी के परिणामस्वरूप सोन और व्यापारिक माल के निर्यात में अवनति से रुपये के विनिमय अर्थ में हुई कमी ने अवमूल्यन आन्दोलन को पुनः जागृत करने के लिए समर्थन प्रदान किया। इण्डियन नेशनल काँग्रेस की कार्य-कारिणी समिति न रुपये के अनुपात को सशोचन कराने का काम अपने हाथ में ले लिया। भारत सरकार परिनियत अनुपात में किसी भी प्रकार के परिवर्तन व विरुद्ध थी और उसने घोषणा की कि रुपये का वर्तमान मूल्य बनाए रखना भारत के हित में आवश्यक था तथा इस कार्य के लिए रिजर्व बैंक और भारत सरकार के पास स्वर्ण एवं स्टलिंग सम्पत्ति प्रचुर मात्रा में थी। फिर भी आन्दोलन जोर पकड़ता गया और सितम्बर, १९३८ में भारतीय द्रव्यात्मक पद्धति के स्थायी आधार को निश्चित करने तथा रुपये के अनुपात के सम्पूर्ण प्रश्न पर रिपोर्ट देने के लिए एक कमेटी की नियुक्ति का असफल प्रयत्न केन्द्रीय विधान सभा के कुछ गैर सरकारी सदस्यों द्वारा किया गया।

रुपया, जो १९३८ में अधिमूल्यित समझा जाता था, मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी के साथ युद्ध की घोषणा करने के बाद अवमूल्यन समझा जाने लगा।

२६. अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्यात्मक कोष और रुपये का सम-मूल्य—३१ दिसम्बर, १९४५ से पहले दोनों समझौतों पर हस्ताक्षर करके भारत सरकार ने ब्रैटन वुड्स समझौते पर डटे रहने तथा अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्यात्मक कोष एवं अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की प्रारम्भिक सदस्यता के लाभ भारत के लिए प्राप्त करने का निर्णय

किया।^१

देश के जानकार लोग केवल भौतिक लाभ के लिए ही नहीं वरन् देश की अन्तर्राष्ट्रीय महत्ता और प्रतिष्ठा के कारण भी इन महत्त्वपूर्ण सगठनों मे भारत के भाग लेने के पक्ष मे थे। इसलिए सरकार ने विधानसभा की स्वीकृति से पहले ही कदम उठाना उचित समझा, ताकि प्रारम्भिक सदस्यता का लाभ समाप्त न हो जाए। बाद मे विधानसभा की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई। प्रारम्भिक सदस्यता के निम्न-लिखित लाभ थे—(१) भारत को सदस्यता की शर्तें और अपना कोटा ज्ञात था, जबकि ३१ दिसम्बर, १९४५ के बाद सदस्यता की शर्तें कोष और बैंक द्वारा निश्चित की जाती। (२) प्रारम्भिक सदस्य की हैसियत से भारत प्रारम्भ से ही प्रशासन सचालको मे स्थान ग्रहण करने का अधिकारी होता, जबकि बाद मे इस अधिकार के लिए भारत को कम से-कम दो वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पडनी।

अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्यात्मक कोष के समझौते की धाराओं मे धारा २० सेक्शन ४ (क) के अन्तर्गत १२ सितम्बर, १९४६ को भारत सरकार से निवेदन किया गया कि वह २८ अक्टूबर, १९४५ अर्थात् समझौते प्रारम्भ होने से साठ दिन पूर्व प्रचलित दरो के अनुसार रुपये का सम-मूल्य अमरीकी डालर अथवा सोने के रूप मे स्पष्ट कर १२ अक्टूबर, १९४६ तक कोष को सूचित कर दे। उस दिन प्रचलित विनिमय दरो, जैसे १ रु० = १ शि० ६ पै, १ पाँड = ४०३ डालर और १ औंस शुद्ध सोना = ३५ डालर, के आधार पर सोने के रूप मे रुपये का सम-मूल्य ०००६३५७ औंस शुद्ध सोना हुआ और यही कोष को सूचित कर दिया गया। ..

सोने को भाजक सख्या के रूप मे प्रयोग करते हुए सिद्धान्तत एक रुपये मे ४१४५१४२८५७ ग्रेन शुद्ध सोने के तत्व समझे जाने चाहिए। सोने के इस वजन से रुपये और डालर की दर ३३०८५१९४ रुपया (अमरीकी) हुई और स्वर्ण का सम-मूल्य २११५ रु० १२—६ २५०५६ प्रति औंस शुद्ध सोना हुआ।^१

सम-मूल्य को परिवर्तित न करने के मुख्य कारण निम्नलिखित थे—

(१) प्रचलित आर्थिक दशाओं की अनिश्चितता और सक्रमणकालीन रूप को देखते हुए विश्वास के साथ यह कहना सम्भव नहीं था कि उपयुक्ततम अनुपात कौनसा होगा। अतएव परिस्थितियों के और अधिक स्थायी होने तक अनुपात परिवर्तन के प्रश्न को स्थगित करना वाञ्छनीय था।

१. भारत की ओर से वाशिंगटन में भारत के एलेग्जट जनरल ने जिस दिन दस्तखत किये वह दिन २७ दिसम्बर १९४५ था।

२. यह १९१४ के पूर्व के अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण प्रमाण का सुधार-भाज ही नहा था। जब स्वर्ण और पैसों के प्रवाह का १९१४ की पद्धति-जैसा मद्दत्त नहीं रहेगा। इसका एक कारण यह है कि अब केन्द्रीय बैंकों ने ऐसे प्रवाहों को प्रभावहीन बनाने की विधि पूर्ण कर ली है। इसके अतिरिक्त सदस्य देशों की स्थिति को ठीक करके विनिमय स्थायित्व बनाए रखने की जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय द्रव्यात्मक कोष की होगी। इस रूप में स्वर्ण का पहले जैसा निर्यातात्मक भाग नहीं रहेगा।

(२) यद्यपि ब्रिटेन और संयुक्तराज्य की तुलना में भारत के ऊँचे मूल्य स्तर रुपये के अवमूल्यन की आवश्यकता का संकेत करते प्रतीत हो रहे थे, परन्तु इस बात की भी सम्भावना थी कि निकट भविष्य में मूल्य के दोनों स्तर भारत में मूल्यों के गिराव और इंगलिस्तान (युनाइटेड किंगडम) तथा संयुक्तराज्य में मूल्यों की वृद्धि के फलस्वरूप एक-दूसरे के अत्यन्त निकटतर आ जाएँगे।

(३) अवमूल्यन भारतीय मूल्यों के अत्यन्त ऊँचे स्तर को और ऊँचा कर देगा और अत्यधिक ऊँचे मूल्यों को कम करने के लिए अत्यधिक समर्थन-प्राप्त घाट उत्पादन तथा स्वतन्त्र आयात की नीति में बाधक सिद्ध होगा।

अवमूल्यन से मशीनों आदि के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। औद्योगीकरण के लिए भारत विदेशों से इनका आयात करने के बारे में सोच रहा था। अतएव इनका रुपया-मूल्य बढ़कर अवमूल्यन औद्योगीकरण में भी बाधक सिद्ध होगा।

(४) कोप की योजना के अन्तर्गत भविष्य में यदि अनुपात में उचित परिवर्तन करना आवश्यक हो, तो यह सर्वत्र सम्भव होगा। सदस्य देश स्वयं सम-मूल्य के १० प्रतिशत तक परिवर्तन कर सकता था और मौलिक असन्तुलन को ठीक करने के लिए और अधिक परिवर्तन बाद में कोप की आज्ञा से किया जा सकता था।

२७ रुपये का अवमूल्यन (सितम्बर १९४६)—१९ सितम्बर, १९४६ को ब्रिटिश सरकार ने पौड स्टैलिंग के अवमूल्यन की घोषणा की। पौड डालर विनिमय की सरकारी दर १ पौड = ४ ०३ डालर थी। नया अनुपात १ पौड = २ ८० डालर निश्चित किया गया। भारतीय रुपये ने इसका अनुसरण किया। परिणामत रुपया १ शि० ६ पै० के बराबर रहा, परन्तु डालर में ३० २२५ अमरीकी सेण्ट के स्थान पर वह २१ सेण्ट के बराबर ही रह गया।^१

आवश्यक आयात की कमी होने पर आर्थिक विकास और औद्योगिक प्रसार की हमारी योजनाओं को पूरा करना कठिन हो जाएगा। अन्य देशों में सामान्यत आना यह थी कि इंगलिस्तान द्वारा अवमूल्यन किये जाने पर भारत भी अवमूल्यन से बच नहीं सकेगा, अतएव पुरानी विनियम-दरों पर किसी भी प्रकार का व्यापार करने में यह भावना मनोवैज्ञानिक बन्धन का काम करती और व्यापार ठप हो गया होता। इसलिए भारत ने भी अन्य स्टैलिंग वाले देशों की तरह एक रक्षात्मक उपाय के रूप में रुपये का अवमूल्यन करने के लिए अपने को विवश पाया। सरकार को आशा थी कि अल्पकाल में अल्पकाल में मुद्रा के अत्यन्त उच्च स्तर पर नहीं पड़ेगा जो प्रधानत हमारे रहन-सहन के व्यय से सम्बन्धित है। चासू वर्ष से डालर वाले देशों से छादानों का कोई आयात होने वाला नहीं था इसलिए यह आशा की गई कि छादानों के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा व्यापार के लिए डालर क्षेत्र

१. यदि १ पौड २८० सेण्ट के बराबर हो तो १ शि० ६ पै०, जो रुपये का सम-मूल्य है, २१ सेंट के बराबर हुआ। धाम में शुद्ध स्वर्ण का सम-मूल्य प्रति रुपया ० १८६६२१ हुआ, जिसके अनुसार प्रति औंस शुद्ध सोने का मूल्य १६६ ६६६ रुपया हुआ।

की अपेक्षा स्टर्लिंग क्षेत्र पर हमारी निर्भरता अधिक होने के कारण सामान्य मूल्य-स्तर अथवा उत्पादन लागत में वृद्धि नहीं होगी और वस्तुओं का आन्तरिक मूल्य भी प्रभावित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त मूल्यों की वृद्धि की किसी भी प्रवृत्ति का सामना नियमन अधिकार युक्तीकरण और उत्पादन की वृद्धि से किया जा सकता है।

स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों में केवल पाकिस्तान ने अपनी करेन्सी के अवमूल्यन के विरुद्ध निर्णय किया, क्योंकि देश के व्यापारिक भुगतानों में मौलिक असन्तुलन नहीं था, तथा पाकिस्तान के निर्यात का कोई विशेष प्रसार, जो प्रायः कच्चे माल का ही था, अवमूल्यन से सम्भव नहीं था। मुद्रा अवमूल्यन न करने से देश की आर्थिक व्यवस्था को हानि तो होगी ही नहीं बरन् इसके विपरीत देश को अनेक महत्वपूर्ण लाभ भी होंगे। इससे आयात सस्ते हो जाएँगे, जिसका देश में रहन-सहन के व्यय पर स्वागत-योग्य प्रभाव पड़ेगा—विशेषकर पूर्वी पाकिस्तान में, जहाँ कुछ समय से मुद्रा स्फीति स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही है। मशीनों और आवश्यक कच्चे माल को मुद्रा-अवमूल्यन वाले देशों से कहीं अधिक अनुकूल मूल्यों पर प्राप्त किया जा सकेगा और इस प्रकार औद्योगिक विकास में सुविधा होगी।

२८. द्वितीय विश्वयुद्ध का भारतीय चलार्थ (करेन्सी) और विनियम पर प्रभाव—भारत की आर्थिक व्यवस्था पर युद्ध के प्रारम्भिक प्रभाव अनेक क्षेत्रों में युद्धजनित अवश्यम्भावी अस्वभाव्यता के बावजूद भी देश के लिए लाभदायक थे, उत्पादन-मूल्य और विदेशी व्यापार को काफी प्रोत्साहन मिला और कृषक की स्थिति में भी सुधार हुआ। १९१४-१८ के युद्ध के प्रारम्भ होने पर रुपया-स्टर्लिंग विनिमय की निर्बलता के विलकुल विपरीत है। उस समय (१९१४-१८) तो रुपया अनुपात की सहायता के लिए सरकार द्वारा स्टर्लिंग की वित्री की गई थी।

यद्यपि स्टर्लिंग के सम्बन्ध में रुपया स्थिर रहा, परन्तु डालर, येन और महाद्वीपीय करेन्सियों के सम्बन्ध में पौण्ड की मन्दी के बाद इसका (रुपये) मूल्य कम हो गया। (जर्मनी द्वारा धिरे होने अथवा अविच्छिन्न होने के कारण प्रमुख महाद्वीपीय करेन्सियों की विनिमय-दरों की सूचनाएँ समाप्त हो गईं) १ पौण्ड = ४०२ डालर की दर पर स्टर्लिंग को डालर के साथ स्थिर करने के कारण रुपया और डालर की विनिमय दर १००० डालर = ३३२ रुपये के आसपास स्थिर रही। युद्ध प्रारम्भ होने के बाद बढ़ती हुई व्यापारिक क्रियाशीलता और वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि के प्रत्युत्तर में जब बैंक ऑफ इण्डिया ने १९३६ में सितम्बर और दिसम्बर के बीच बैंक नोट और सिक्कों के रूप में ४८ करोड़ रुपये से करेन्सी का विस्तार किया तो सक्रिय प्रचलन में नोटों की औसत संख्या सितम्बर, १९३६ में १८६०६ करोड़ रुपये थी। जून, १९४० में यह २३७२६ करोड़ रुपये हो गई। करेन्सी का यह विस्तार रिजर्व बैंक द्वारा

१. देखिए, 'एन्नुअल रिपोर्ट ऑफ दि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया' (फरवरी १९४०, पृ० १४, २३-२४; अगस्त १९४०, पृ० ११-१२, १८), और 'रिपोर्ट ऑन करेन्सी ऐण्ड फ़ाइनेन्स' (१९३६-४०), पैरा २३-२४।

ट्रेजरी बिल और स्टॉलिंग की पर्याप्त खरीद के फलस्वरूप हुआ। अतः कोई आश्चर्य नहीं कि इस बीच रुपया-स्टॉलिंग विनिमय बहुत स्थिर रहा।

२६ रुपये के सिक्के को प्रचलन से बापस लेना और एक रुपये के नोट का प्रचलन—यद्यपि, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भारतीय करेंसी पद्धति ने युद्ध की कठिनाइयों का सामना भली प्रकार किया और सामान्यतः कागजी करेंसी में विश्वास बना रहा, परन्तु यूरोप में युद्ध-स्थिति खराब हो जाने से १९४० की मई-जून में प्रतिकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। रुपये के सिक्के में नोटों का भुगतान करने के लिए रिजर्व बैंक से माँग की गई। बैंको से निकाला जाने वाला रुपया, जो पहले औसतन एक करोड़ रुपया प्रति सप्ताह निकाला जाता था, अकस्मात् ४५ करोड़ ६० प्रति सप्ताह हो गया। युद्ध होने के बाद रिजर्व बैंक ने ४३ करोड़ से अधिक रुपये के सिक्को की पूर्ति की, जिनका आमचयन कर लिया गया जो निर्गम विभाग (इश्यु-डिपार्टमेंट) में रुपये के सिक्के के भण्डार की कमी से भी स्पष्ट है। युद्ध के आरम्भ में निर्गम विभाग में ७५ ४७ करोड़ रुपये के सिक्के थे और ५ जुलाई, १९४० को केवल ३२ करोड़ रुपय के सिक्के थे। इन परिस्थितियों में सरकार ने रुपये की स्वतन्त्र बापसी की प्रारम्भिक नीति में परिवर्तन करने का निश्चय किया। यद्यपि भारत सरकार का रजत-भण्डार पर्याप्त था, तथापि भारत की टकसालों में उस दर पर रुपया बनाना असम्भव मालूम पड़ता था, जिस दर पर रुपया जनता द्वारा आसक्ति किया जा रहा था। इसलिए २५ जून, १९४० को भारत सरकार ने व्यक्तिगत अथवा व्यापारिक आवश्यकता से अधिक रुपय के सिक्के की प्राप्ति के लिए दण्ड की व्यवस्था करने वाली एक अधिसूचना प्रकाशित की। कुछ समय तक रुपये के सिक्को को नोटों से अधिक मूल्य पर माँगा गया और रुपये के सिक्को तथा छोटे-छोटे सिक्को (रेजगारी) का अभाव हो गया। इन कठिनाइयों को शीघ्रता से हल किया गया और रिजर्व बैंक ने छोटे सिक्को के विस्तृत प्रचलन तथा रुपये की उचित माँग को पूरा करने के लिए प्रवन्ध किया।

३०. चाँदी के सिक्कों के रजत-तत्त्व में कमी—देश के रजत साधनों को सुरक्षित रखने का दूसरा उपाय कुछ सिक्को के रजत-तत्त्व की शुद्धता के स्तर को कम करना था। अप्रैल, १९४० में केन्द्रीय विधानमण्डल ने सरकार को चवन्नी के $\frac{1}{4}$ रजत-तत्त्व को $\frac{1}{2}$ रजत-तत्त्व तक कम करने का अधिकार दिया। इसका उद्देश्य साधारण तौर पर घातुओं के सरकारी भण्डार को और अधिक सेवा योग्य बनाना है। इस उद्देश्य के लिए १९०६ के इण्डियन कॉयनेज एक्ट को सुधारने के लिए २६ जुलाई, १९४० को भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक आदेश के अन्तर्गत अठन्नी के रजत-तत्त्व में भी इसी प्रकार की कमी की गई। रुपय के आसचयन के बाद चवन्नी और अठन्नी की बढ़ती हुई माँग के फलस्वरूप यह कदम उठाया गया। २२ दिसम्बर, १९४० को रुपये में भी आधी चाँदी और मिलावट की व्यवस्था की गई। अप्रैल, १९४७ में इण्डियन कॉयनेज एक्ट को सुधारने के लिए एक बिल पाम हुआ, जिसके फलस्वरूप गिल्ट के रुपये ने चाँदी के रुपये का स्थान ग्रहण कर लिया। इस प्रकार संयुक्त राज्य को

चुकाने के लिए २२६० लाख अंस चाँदी की वचत हुई, जिसे भारत ने उधार-पट्टे के अन्तर्गत उधार लिया था।

दशमलव प्रणाली—दशमलव प्रणाली लागू करने के लिए १९०६ के भारतीय टंकन अधिनियम (इण्डियन व्वायनेज एक्ट) को संशोधित करने के लिए ७ मई, १९५५ को लोक सभा में एक बिल पेश किया गया। यह बिल २७ जुलाई, १९५५ को पास हो गया तथा १ अप्रैल, १९५७ से लागू हुआ। इस तिथि से रुपये को १०० नये पैसे के छोटे सिक्को में विभाजित किया गया। एक न० पैसे, दो न० पैसे, पाँच न० पैसे, दस न० पैसे, पचास न० पैसे के सिक्को के जारी करने की व्यवस्था की गई। १ अप्रैल, १९५७ से सारे सरकारी विभाग, मिश्रित पूँजी वाली तथा सहकारी बैंक—सभी नई प्रणाली के अनुरूप हिसाब रखने लगे। पुराने सिक्को के ३ वर्ष तक चलते रहने की व्यवस्था की गई थी।

१९६० में जनता के हाथ में द्रव्य की मात्रा २७४० करोड़ रु० (जिसमें हाली सिक्का भी शामिल था) थी जो १९५६ की तुलना में २१८८ करोड़ रु० अधिक थी। इस मात्रा में १२४६.८७ लाख रु० के मूल्य के दशमलवी सिक्के भी सम्मिलित थे। दशमलव सिक्को का यह मूल्य ३१ अक्टूबर, १९६० तक प्रचलन में आये हुए सिक्को के लिए है।

३१. विनिमय-नियन्त्रण—युद्ध प्रारम्भ होने पर केन्द्रीय सरकार ने भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को सिक्को, धातु-पिण्डो, प्रतिभूतियों और विदेशी विनिमय के लेन-देन सम्बन्धी नियमों को कार्यान्वित करने का अधिकार दिया।

विदेशी विनिमय का लेन-देन अधिकृत व्यापारी विनिमय बैंक तथा अनुज्ञा-प्राप्त सम्मिलित पूँजी वाली बैंक ही कर सकती थी। कुछ अपवादों को छोड़कर साम्राज्य की करेन्सी के क्रय-विक्रय पर सामान्यतः कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया, परन्तु साम्राज्य के बाहर की करेन्सियों का क्रय विक्रय व्यापारिक उद्देश्यों, यात्रा-व्यय और व्यक्तिगत विप्रेषण तक सीमित कर दिया गया। विनिमय नियन्त्रण की नीति इस बात को निश्चित करने के लिए थी कि भारत में विदेशी विनिमय का सारा लेन-देन लन्दन विनिमय नियन्त्रण द्वारा उद्धृत दरों तथा स्टर्लिंग के लिए रुपये की चालू दरों के आधार पर किया जाए। विदेशियों से प्रतिभूतियों की खरीद पर भी नियन्त्रण लगाया गया और रिजर्व बैंक की आज्ञा लिये बिना प्रतिभूतियों का निर्यात नहीं हो सकता था। इन उपायों का अभिप्राय भारत से पूँजी के निर्यात तथा युद्ध-जनित परिस्थितियों से प्रोत्साहित विनिमय सम्बन्धी परिकल्पना को रोकना था।

मई, १९४० में सरकार ने विदेशी विनिमय को सुरक्षित रखने तथा रोक लगी वस्तुओं का बिना आज्ञा भ्रुगतान रोकने के लिए आयात को अनुज्ञा प्रदान करने की पद्धति का प्रारम्भ किया। ये प्रतिबन्ध, जो प्रारम्भ में वस्तुओं की छोटी सूची पर ही लागू थे, दूसरे वर्ष कनाडा की कुछ वस्तुओं को छोड़कर सभी देशों की वस्तुओं पर लगा दिये गए। ये उपाय केवल विदेशी विनिमय के व्यय में मितव्ययता प्राप्त करने के लिए ही आवश्यक नहीं थे, वरन् सयुक्तराज्य में जहाजों में स्थान तथा

उत्पादन-क्षमता सुरक्षित रखने के लिए भी आवश्यक थे, क्योंकि यूरोप से पूर्ति बन्द हो जाने के कारण इस देश से आयात बढ़ रहे थे। जापान के युद्ध में उतर आने के बाद जहाजरानी की स्थिति और भी खराब हो गई। अतएव अनुज्ञा (लाइसेंस) देने में पहलुओं में स्थान की सुलभता पर अधिक महत्त्व दिया जाने लगा। १९४२-४३ में आयात की अदायगी से प्राप्त डालरों में काफी कमी हुई। यह कमी प्रधानतः मशीन और स्टील आदि के आयात के कारण हुई, जिसके लिए पहले बहुत अधिक मात्रा में डालर की आवश्यकता होती थी तथा जो उधार-पट्टे के अन्तर्गत थे। इस प्रकार के माल का आयात करने वाले भारत सरकार को रुपये में ही मुगतान कर देते थे और विदेशी विनिमय का कोई लेन-देन नहीं होता था। १९४४-४५ में तत्कालीन विनिमय-नियन्त्रण पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। स्टर्लिंग क्षेत्र के बाहर वाली करेन्सियों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा रहा और इन देशों को निर्यात की आज्ञा इस शर्त पर दी जाती थी कि प्राप्त राशि विदेशी विनिमय के अधिकृत व्यापारियों के हाथ बँधी जाए। इस प्रकार देश के विदेशी विनिमय के साधनों की पूर्ण सुरक्षा और उनका उपयोग किया गया। यद्यपि पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तथापि विदेशी विनिमय की माँग के लिए अपनाई गई नीति में परिवर्तन किया गया और देश के लिए महत्त्वपूर्ण समझे जाने वाले कार्यों के लिए विदेशी विनिमय को उदारतापूर्वक सुलभ किया जाने लगा।

आयात की घनीभूत माँग को पूरा करने और मुद्रास्फीति को समाप्त करने के साधन के रूप में १९४५-४६ में भारत सरकार ने आयात अनुज्ञा पद्धति (इम्पोर्ट लाइसेंस सिस्टम) के अन्तर्गत, उपभोग की वस्तुओं का आयात का कौटा काफी बढ़ा दिया। इससे विशेषकर सयुक्तराज्य के साथ भारत व (अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के) लेन-देन के सन्तुलन की अनुकूलता में तेजी से कमी घा गई।

१९४५ में युद्ध के समाप्त होने पर विनिमय-नियन्त्रण-नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जहाजरानी की दसा में सुधार होने के कारण विनिमय-विचारों से अप्रभावित स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों के आयात पर लगे प्रतिबन्ध ढीले कर दिए गए, परन्तु सयुक्तराज्य के डालर के व्यय के सम्बन्ध में कठोर मितव्ययना चलती रही।

३२ स्वर्ण के आयात-निर्यात पर प्रतिबन्ध—ब्रिटिश भारत के अन्दर सोने के स्थानान्तरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था, परन्तु स्वर्ण का आयात-निर्यात रिजर्व बैंक द्वारा दी गई अनुज्ञा के आकार पर ही हो सकता था। सोधारणतया आयात के लिए अनुज्ञा दे दी जाती थी, परन्तु निर्यात की अनुज्ञा तभी मिलती थी जबकि सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड को भेजा जाता हो। अमरीका भेजने के लिए अनुज्ञा उस समय दी जाती थी जब प्राप्ति डालर बैंक ऑफ इंग्लैंड की ओर से फंडरल रिजर्व बैंक को बंध दिये जाएँ।

यद्यपि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का निर्गम विभाग (इस्यू डिपार्टमेंट) में स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ १ सितम्बर, १९३६ को ५६ ५० करोड़ रुपये थी और १ सितम्बर,

१९४० को ये बढ़कर १३१.५० करोड़ रुपये हो गई, परन्तु रिजर्व बैंक के स्वर्ण-भण्डार में कोई वृद्धि नहीं हुई तथा वह ४४.४२ करोड़ रुपया ही रहा।^१

३३. साम्राज्य का डालर सचय तथा युद्धोत्तर डालर कोय (अम्पायर डालर पूल एण्ड पोस्ट-वार डालर फण्ड)^१—युद्ध से पूर्व बहुत-से देश, जो सामान्यतया स्टर्लिंग समूह के देश कहे जाते थे, अपने सम्पूर्ण विदेशी विनियम या उसका अधिकांश भाग स्टर्लिंग के रूप में लन्दन में रखा करते थे। उस समय स्टर्लिंग अन्य करेंसियों में स्वतन्त्रतापूर्वक परिवर्तनीय था, इसीलिए अपने-अपने विदेशी विनियम का स्टर्लिंग के रूप में रखने वाले देश अपने अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए अपनी इच्छा और आवश्यकतानुसार उन्हें किसी भी करेंसी में बदल सकते थे। युद्ध के प्रारम्भ होने और स्टर्लिंग की परिवर्तनीयता की कठिनाई के साथ इस पद्धति में कठोरता आ गई, जिसका पहला अनुमान ही नहीं किया गया था। स्टर्लिंग समूह के उन सदस्यों ने, जो स्टर्लिंग क्षेत्र के सदस्य बने रहे, विदेशी विनियम को अपने संरक्षण में रखने का अधिकार छोड़ दिया तथा विदेशी विनियम के व्यय पर प्रतिबन्ध लगाना तय किया ताकि स्टर्लिंग क्षेत्र के विदेशी विनियम वे सीमित साधनों का युद्ध चक्र रखने के लिए भली प्रकार उपयोग किया जा सके। सम्पूर्ण स्टर्लिंग क्षेत्र के विदेशी विनियम की राशि एक ही स्थान पर बैंक ऑफ इंग्लैंड तथा ब्रिटिश ट्रेजरी के संरक्षण में रखी हुई थी। इस सचय में डालर सबसे महत्वपूर्ण करेंसी थी, अतएव इसका नाम स्टर्लिंग एरिया पूल ऑफ फारिन एक्सचेंज न होकर अम्पायर डालर पूल पड़ गया। साम्राज्य डालर सचय में स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों द्वारा व्यय के लिए व्यक्तिगत रूप से विभिन्न विदेशी करेंसियों का भाग निर्दिष्ट नहीं किया गया था।

भारत सरकार दुर्लभ करेंसी के अर्जन और व्यय का हिसाब रखती थी। युद्ध के प्रारम्भ से ३१ मार्च, १९४६ तक भारत ने ४०.५ करोड़ ६० के अमरीकी डालर का अर्जन किया और २४० करोड़ रुपये का डालर व्यय किया। इस प्रकार उसके पास १६.५ करोड़ रुपये के डालर की बचत हुई, परन्तु अन्य दुर्लभ करेंसियों (जैसे कनाडा, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और पुर्तगाल) के सम्बन्ध में भारत ने अर्जित राशि से ४१ करोड़ रुपये अधिक व्यय किये, इसलिए १९४५-४६ के अन्त तक सचय में भारत का वास्तविक अशदान लगभग १२४ करोड़ रुपया था।

१९४६ में जून तक खाद्यान्न के आयात तथा अन्य सरकारी मदों के भुगतान की अदायगी के लिए सचय से भारत ने काफी रुपया लिया।

१. स्टर्लिंग क्षेत्र के भुगतान के लिए कुछ स्टर्लिंग प्रतिभूतियों के विक्रय के लिए अध्याय ११ और १२ देखिये।

२. स्वर्ण का मूल्यांकन २१ रुपया ३ आना १० पाइ प्रति तोला की दर पर ही किया गया, जबकि बाजार में ३१ मार्च, १९४७ को सोने का भाव १०३ रुपया ८ आना था।

३. यह सेमशन 'अधिकारता' ७ अक्टूबर, १९४६ को भारत सरकार द्वारा प्रकाशित प्रेस नोट से उद्धृत किया गया है।

पोस्ट-वार डालर फण्ड नाम का एक और कोष था जिसने १९४४ के लिए मंचय ने २०० लाख डालर दिए। १९४३-४४ में साम्राज्य डालर सचय के प्रति पर्याप्त असादान देने और सयुक्त राज्य को पारस्परिक सहायता देने की हमारी इच्छा के कारण राजाधिराज सरकार ने जापान ने साथ युद्ध समाप्त होने पर सयुक्त राज्य म पूंजी व्यय के लिए २०० लाख डालर का एक पृथक् कोष भारत को दिया। इन उद्देश्यों के सारे व्यय को इसी कोष में पूरा किया जाता था और इसके समाप्त होने तक इस प्रकार के व्ययों के लिए सचय से डालर नहीं लिये जा सकते थे। यह २०० लाख डालर हमारे १९४४ के व्यापारिक खाते का प्रतिदात अदा था तथा राजाधिराज सरकार इन बात पर राजी हो गई कि १९४५ में हमारी अर्जन आय १९४४ के बराबर होने पर वह इस कोष में हमें अधिक-से-अधिक २०० लाख डालर १९४५ के वर्ष के लिए भी देगी। १९४५ के लिए राजाधिराज सरकार ने २०० लाख डालर देने की सूचना दी।

सरकार की आयात-नियन्त्रण नीति की आलोचना दो बातों पर आधारित थी—(१) आयात अनुज्ञा प्रदान करने वाला शासन-यन्त्र तिथिल और अकुशल था। (२) विनिमय नियन्त्रण की सखी के कारण आयातकर्ताओं के लिए मशीन और अन्य वस्तुएँ स्टलिंग क्षेत्र के बाहर से मँगाना बहुत कठिन हो गया। युद्ध की समाप्ति के कारण परिवर्तित परिस्थितियों के फलस्वरूप भारत सरकार ने इस आयात के साथ आयात-नियन्त्रण के शासन में परिवर्तन किया कि आयात के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने की विधि मक्षिप्त और सरल हो जाए। उन्होंने नियन्त्रित वस्तुओं की सूची से यथा-सम्भव वस्तुओं को हटाने और उन्हें स्टलिंग क्षेत्र के लिए अनुज्ञापुक्त (ओपन जनरल लाइसेन्स) बनाने की नीति अपनाई। कुछ अन्य वस्तुएँ पूर्णतया अनुज्ञायुक्त सूची (सुनिवर्त्यव ओपन जनरल लाइसेन्स) के अन्तर्गत रखी गईं, जिसका अर्थ यह था कि वस्तुओं का आयात स्वतन्त्रतापूर्वक स्टलिंग क्षेत्र के अन्दर या बाहर वहाँ से भी किया जा सकता था।

स्टलिंग क्षेत्रों में तुलनात्मक वस्तुओं के गुण, मूल्य और उन्हें प्राप्त करने की प्रवृत्ति का ध्यान में रखते हुए अलम्बना को निश्चिन किया जाता था। अलम्बना निश्चि करने का भार आयातकर्ताओं से हटाकर सरकार को दे दिया गया, ताकि सरकार अपनी जाँचों से नन्नुष्ट हो सके कि बाहर से आयात की जाने वाली वस्तुएँ स्टलिंग क्षेत्र के अन्दर सुलभ थी अथवा नहीं। एक दूसरा परिवर्तन करेन्सियों को प्राप्त करने की कठिनाई के अनुसार उनको क्रमवद्ध करना तथा उन्हें प्राप्त करने की सरलता के अनुसार आयातों के लिए अनिवार्यता और अलम्बना की कसौटियों को ह्रासमान कठोरता के साथ अपनाना था।

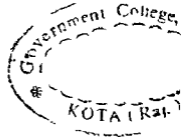
जुलाई १९४७ से स्टलिंग क्षेत्र के देशों को भी सम्मिलित करने की दृष्टि से विनिमय-नियन्त्रण का क्षेत्र बड़ा दिया गया। भौगोलिक निकटता तथा व्यापार के अनीतचारिक ह्य के कारण अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए यह नियन्त्रण फरदरे, १९४१ ने लागू हुआ।

१९४७ के बाद विनिमय-नियन्त्रण में कोई सरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) परिवर्तन नहीं हुए हैं, किन्तु पन्द्रहवर्षीय योजनाओं के सदर्भ में उसका अर्थ और आशय बदल गया है। प्रारम्भ में विनिमय-नियन्त्रण युद्धजनित आवश्यकताओं को पूरा करने या युद्ध के समय लागू रोक (रेस्ट्रिक्शन) से उत्पन्न परिस्थितियों के लिए अपनाया गया था। यह स्थिति १९५० तक समाप्त हो गई। इसके पश्चात् विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए, जो स्वभावतः कई वर्षों तक चलेगी, विनिमय-नियन्त्रण आवश्यक हो गया। १९५७ तक आयात की चालू आवश्यकताओं को निम्नतम कर दिया गया था। विकास-मन्त्रालयों आयात तथा विदेशी ऋण की अदायगी को दृष्टिगत रखते हुए यह कहा जा सकता है कि भविष्य में भी विनिमय-नियन्त्रण का महत्त्व बना रहेगा। विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम, १९४७ के २५ मार्च १९४७ से लागू होने पर विनिमय-नियन्त्रण की व्यवस्था को स्थायी रूप मिल गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार और रिजर्व बैंक को भारत में विदेशी विनिमय और विदेशी प्रतिभूतियों के नियन्त्रण और नियमन आदि का अधिकार मिला।

३४ साल संभरण तथा मुद्रा—१९६४ में साल का सभरण जनता के पास ३६१ ३ करोड़ रुपया (१०.२%) बढ़ गया। मुद्रा का परिभ्रमण (रुपया तथा छोटे सिक्के) २८०२१ करोड़ तक जा पहुँचा और इस प्रकार १९५२-६४ में मुद्रा-परिभ्रमण १५२६ ६ करोड़ बढ़ गया (१२.०३%)। यह बढोतरी अधिकतर बैंक साल सरकार के प्रति है (फरवरी १९६६ में परिसन्ध्या बैंको का रिजर्व बैंको के पास जमा घन २६२२ करोड़ रुपया था)। दूसरे कारण मुद्रा बढने के ये थे—

- (१) कुल (Net) बैंक साल निजी क्षेत्र में।
- (२) कुल विदेशी पूँजी की परिसम्पत्ति रिजर्व बैंक के पास बढना।
- (३) सरकारी मुद्रा देयता जनता के लिए।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस मुद्रा सभरण में नोटों तथा छोटे सिक्कों का थोडा हाथ है और रुपयों का अधिक। पहली जून १९६४ को नये पैसे के स्थान पर पैंसा शब्द निर्धारित किया और पैसे के सिक्के १ जुलाई १९६४ से चालू किये गए। अक्टूबर १९६४ से तीन पैसे वाले सिक्के भी पहली बार चालू किये गए। १४ नवम्बर १९६४ में जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में ५० पैसे तथा एक रुपये के सिक्के जारी किये गए जो कि देश के वैधानिक रूप से चालू मुद्रा के अन्य सिक्कों में सम्मिलित कर लिये गए।



अध्याय २३ भारतवर्ष में मूल्य

१. १८६१ से हुए मूल्य-परिवर्तनों पर एक विहंगम दृष्टि—१८७३ को आधार वर्ष मानकर नीचे दी हुई तालिका १८६१ से मूल्य-परिवर्तनों की साधारण गति दिखा रही है।^१ सामान्य देशनाक (इण्डेक्स नम्बर) ३६ वस्तुओं के थोक-मूल्यों पर

वर्ष	३६ वस्तुओं का सामान्य देशनाक (अभारित) ^१	भारित देशनाक (१०० वस्तुएं) १८७३ में १०० के बराबर	वर्ष	३६ वस्तुओं का सामान्य देशनाक (अभारित)	भारित देशनाक (१०० वस्तुएं) १८७३ में १०० के बराबर
१८६१	६०	६३	१९२४	२२१	२५७
१८६५	१०७	१०६	१९२६	२१६	२६०
१८७०	१०२	१०७	१९२७	२०२	—
१८७५	६४	६६	१९२८	२०१	—
१८८०	१०४	१०६	१९२९	२०३	—
१८८५	८७	१०६	१९३०	१७१	—
१८९०	१००	११७	१९३१	१२७	—
१८९५	१०४	१२०	१९३२	१२६	—
१९००	११६	१४३	१९३३	१२१	—
१९०५	११०	१३५	१९३४	११६	—
१९१०	१२२	१५०	१९३५	१२७	—
१९१४	१४७	१८७	१९३६	१२५	—
१९१८	२२५	२१५	१९३७	१३६	—
१९१९	२७६	३०१	१९३८	१३२	—
१९२०	२८१	३०२	१९३९	१४२	—
१९२१	२३२	२७३	१९४०	१६३	—
१९२३	२१५	२५६	१९४१	१७४	—

(फरवरी)

१. १८७३ को आधार वर्ष इसलिए चुना गया है, क्योंकि उस वर्ष बहुत सामान्य थी तथा उम्मी वर्ष से चांदी और उसके परिणामस्वरूप रुपये का अर्थमूल्यन प्रारम्भ हुआ।
२. देखिए, इण्डेक्स नम्बर आक इन्डियन प्रोड्यूस, १८६१-१९३१ तथा वार्षिक परिशिष्ट। उपयुक्त तालिका के तीसरे तथा छठे खाने में दिये हुए देशनाक इन्डियन फाइनेन्स डिपार्टमेंट के एफ० जी० एटकिन्सन द्वारा संकलित किये गए थे। १९०६ के बाद के देशनाक उनके आधार पर डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने संकलित किये।
३. सन् १९३७ से एक वस्तु आयत की हुई वस्तुओं का सूची से निकाल दी गई है।
४. सन् १९४२-४३ से (१६ अगस्त, १९३६ सप्ताह की समाप्ति पर ≈ १००) थोक-मूल्य के देशनाक

आधारित है (जिनमे से २८ निर्यात की तथा ११ आयात की वस्तुएँ हैं)। खाद्यान्न अर्थात् ज्वार, बाजरा, जौ, राई और चना को छोड़कर उपर्युक्त वस्तुओं के १८६७ से पहले के थोक-मूल्य प्राप्त नहीं हैं।

चूँकि १८७३ को आधारवर्ष मानकर बताया गया अखिल भारतीय देशनाक पुराना पड़ गया है, अतः बम्बई और कलकत्ता की थोक कीमतों के अको की ओर निर्देश किया जाता है। अब १८७३ का आधार वर्ष तुलना के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार वस्तुओं का सापेक्षिक महत्त्व भी घट-पड़ गया है।

२ १८६१ से १८६३ तक—इस काल में कीमतों का सामान्य चढ़ाव-उतार निम्न-प्रकार है—(१) घटती हुई कीमतें १८६१-६—अमरीकी गृह-युद्ध के कारण कपास की कमी हो गई। इस प्रकार चढ़ी कीमतों के कारण भारत में बहुत स्वर्ण आया और चाँदी के सिक्कों का टकन खूब हुआ जिससे कीमतें बढ़ गईं। इस प्रकार भारत के मूल्य-स्तर पर प्रथम बार बाह्य कारणों का प्रभाव स्पष्ट हुआ। (२) गिरते हुए मूल्य १६६६-८३—१८७६ से १८७६ तक दुर्भिक्ष के कारण खाद्यान्नों के मूल्य में हुई आकस्मिक वृद्धि के अतिरिक्त इस काल की कीमतें गिरती रही। मूल्यों का यह गिराव १८७४ में पाश्चात्य देशों की कीमतों की निम्नगामी प्रवृत्ति का प्रतिरूप मात्र था। स्वर्ण के उत्पादन में शिथिलता, रजत प्रमाप के देशों द्वारा स्वर्ण प्रमाप अपनाना, चाँदी का स्वतन्त्र टकन बन्द होने से रजत करेन्सी के प्रसार में रकावट, बैंकिंग का शिथिल विकास, भाड़े में कमी हो जाने से व्यापार का प्रसार, और उत्पादन-विधि में सुधार आदि इसके कारण थे। (३) बढ़ती हुई कीमतें १८८३-९३—पश्चिम के स्वर्ण प्रमाप देशों की अपेक्षा भारत में गिरती हुई कीमतें शीघ्रता से रुक गईं। इसका कारण रुपये का अवमूल्यन था। यह स्वीकार करना होगा कि हालाँकि स्वर्ण की तुलना में चाँदी का मूल्य १८७४ से ही घटने लगा था, किन्तु उत्पादन में सामान्य वृद्धि के कारण १८८३ तक कीमतें गिरती ही रही। १८८५ के बाद जब रजत का उत्पादन वस्तुओं के उत्पादन से निश्चित रूप से बढ़ गया तो कीमतें बढ़ने लगीं। १८९३ से १८९६ के अल्प मध्यान्तर को छोड़कर १९२० तक ऐसा ही रहा।

३ मूल्य जाँच-समिति (मूल्य १८९० से १९१२)—१९१० में भारत सरकार ने दत्ता समिति नियुक्त की। इसका काम मूल्यों की लगातार वृद्धि के कारणों का पता लगाना था। इसने छानबीन के लिए १८९० से १९१२ तक का समय चुना। इस

इस प्रकार थे

१९४२-४३	१७१	१९४७ (मार्च)	२६२ ७
१९४३-४४	२३६ ५	१९४८ (अप्रैल)	३४८
१९४४-४५	२४४ २	१९४९ (मार्च)	३७० ०
१९४५-४६	२४४ ९	१९५० (अक्टूबर)	४११ ४
१९४६-४७	२७५ ४		

१. देखिए, इरविग फ़िरार, 'परचेसिंग पावर ऑफ़ मनी', पृ० १४२।

कालावधि में समस्त भारत में सामान्य रूप से मूल्य बढ़ रहे थे। १९०५ से यह वृद्धि स्पष्टतः लक्षित हुई, विशेषकर चमड़ा, खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, तिलहन इत्यादि में, जिनमें ४०% से भी अधिक वृद्धि हुई। कपास और जूट में क्रमशः ३३% और ३१% वृद्धि हुई, जबकि अन्य सामग्रियों—खाद्यान्न, घातुएँ तथा अन्य कच्चे और निर्मित माल के मूल्य २५% तक बढ़ गए। देशी चीनी में थोड़ी-सी वृद्धि हुई, लेकिन इसके विपरीत चाय, कहुवा, आयात की हुई चीनी, सोने और सिम्बाने के सामान, विशेष रूप से नील, कोयला, लाख आदि की कीमतों में काफी कमी हुई। कपड़ों की कीमतें थोड़ी सी गिरी। मूल्यों की वृद्धि भारत में सबसे अधिक थी। यदि १९०७-११ के पंचवर्षीय काल के मूल्य-स्तर की तुलना १८९४-८ के पंचवर्षीय मूल्य स्तर में की जाए, तो भारत की कीमतों में ४०% वृद्धि हुई, जबकि इसी समय में इंगलिस्तान में २१%, अमरीका में ३८% और आस्ट्रेलिया में २०% वृद्धि हुई।

४ १९१४-१८ के युद्ध से पूर्व मूल्यों की वृद्धि के कारण—मूल्य जाँच समिति ने कारणों को दो वर्गों में विभाजित किया—(१) विशेष रूप से भारतीय कारण और (२) ऐसे कारण, जो भारत तक ही सीमित न थे अर्थात् विश्व-व्यापी कारण, हालाँकि उन्होंने स्वीकार किया कि ये दोनों कारण एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं।

(१) विशेष रूप से भारतीय कारण—(क) कृषि उत्पादनों, विशेषकर खाद्यान्न एवं कच्चे माल की कमी, (ख) इन वस्तुओं की माँग में वृद्धि, (ग) भारत में रेलवे तथा अन्य संचार-साधनों में विकास और प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रूप से भारत तथा उसके बन्दरगाहों और विदेशों के बीच परिवहन लागत में कमी, सामान्य रूप से बैंकिंग सुविधाओं, द्रव्य और साख इत्यादि में सुधार, (घ) करेन्सी के आकार में वृद्धि।

(२) विश्व-व्यापी कारण—इनमें (क) दुनिया के बाजारों में प्रधान वस्तुओं की पूर्ति में कमी और माँग में वृद्धि, (ख) दुनिया की खानों से सोने की अधिक पूर्ति, (ग) साख का विकास, (घ) विनाशकारी युद्ध तथा थल और जल-सेना में वृद्धि, जिससे पाश्चात्य देशों और तत्सुक्त राज्य में श्रम और पूँजी अनुत्पादक माँगों में लगाई जान लगी। इससे कितनी ही प्रकार की सामग्रियों की माँग भी बढ़ गई। १८९३ में रजत प्रभाव का परित्याग करने के कारण भारत भी शेष दुनिया के साथ मुद्रा-मान (करेन्सी गेज) के प्रवाह में आ गया और असदृश्य रूप से दुनिया में होने वाली कीमतों के परिवर्तन का भागी बना।

१९०८ में विशेषज्ञ श्री हैरिसन ने इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल में इस मत को प्रकट किया कि अधिक टकन के कारण ही कीमतें जँगी उठी हैं। १८९८ में गोखले ने भारत में रुपये का मण्डार १३० करोड़ ६० अनुमानित किया था। विगत दस वर्षों में सरकार ने लगभग १०० करोड़ रुपये का और टकन किया। इस प्रकार की आक-

१. समिति के मत में इस कमी के कारण (क) जनसंख्या के साथ किसी भी उत्पादन का न बढ़ना, (ख) अनिश्चित वृद्धि, (ग) खाद्य फसलों के स्थान पर अजान्य फसलों का प्रतिस्थापन और (घ) जुताई के लिए सी गई जमीन की कमी का है।

स्मिक स्फीति का स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि कीमतें बढ़ जाएँगी। सरकार द्वारा निर्गमित रुपये देश के आन्तरिक भाग में वास्तविक क्रेशों के हाथों में पहुँच जाते हैं, लेकिन वे शीघ्रता से व्यापार केन्द्रों या बैंकों की ओर नहीं बहते। इस प्रकार सौदों के लिए नये रूपों की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए पुराने रूपों ही पर्याप्त होते। इसी बीच रूपों का गलाना बन्द हो गया, क्योंकि रूपों का धब चाँदी का नहीं रहा और उसका कृत्रिम विनिमय-मूल्य वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक हो गया, अतएव प्रत्येक निर्गम करनेवाले के आकार को प्रसारित करता है।^१ १९०३-७ के प्रत्येक वर्ष में मुद्रा की अनुमानित वृद्धि और मूल्य-स्तर में बड़ी ही समानता थी।

५. पूर्व अवसाद-काल तथा युद्ध-काल (१९१४-१८) में मूल्य—पूर्व युद्ध-काल में—१९१४ से १९२०—विशेषकर इस अवधि के उत्तरार्ध में युद्ध-जनित परिस्थितियों के कारण मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। किन्तु भारत में अन्य देशों, विशेषकर युद्ध में सलग्न देशों, की अपेक्षा कीमतें कम बढ़ी। विदेशी मूल्यों की वृद्धि साधारणतः आयात की कमी और निर्यात के प्रसार से ठीक की जा सकती थी। तज्जनित स्वर्ण के आयात से भारत की आन्तरिक कीमतें इतनी अवश्य बढ़ती कि वे बाह्य कीमतों के बराबर हो जाती। किन्तु सरकार द्वारा सोने के आयात और वस्तुओं के निर्यात पर लगाये गए प्रतिबन्धों तथा युद्धकालीन कीमतों के नियन्त्रण के कारण यह व्यवस्थापन सम्भव न हो सका। यही कारण था कि भारत अधिक सुरक्षित कोष का निर्माण न कर सका और युद्धकालीन समृद्धि के अनन्तर मन्दी आने पर प्रतिस्पर्धी सामग्रियों का आयात करने वालों की तुलना में घाटे में रहा। फिर सरकारी हस्तक्षेप के अभाव में विनिमय पहले ही और अधिक शीघ्रता से ऊपर उठ गया होता। इसमें आयात की प्रेरणा मिलती तथा आयात की कीमतों में वृद्धि भी अपेक्षाकृत कम होती। भारत को अपने निर्यात का अधिक मूल्य मिलता और वह युद्धोत्तरकालीन पुनर्निर्माण का खर्च आसानी से प्राप्त कर सकता, किन्तु विनिमय की स्वतन्त्रता के कारण युद्ध की नाजुक स्थिति के समय व्यापारिक विस्थापन के भय से भारत सरकार ने हस्तक्षेप करना उचित समझा।

१९१४-१८ में भारत में प्रायः सभी कीमतें बहुत ऊँची हो गईं। युद्ध प्रारम्भ होने के बाद १९१६ में खाद्यान्न के मूल्य ६३% बढ़ गए। आयात किये हुए कपड़ों तथा भारत में बने कपड़ों के मूल्यों में क्रमशः १६०% तथा ६०% वृद्धि हुई। हम पहले ही कह आए हैं कि आयात की गई वस्तुओं—कपड़ा, लोहा, इस्पात, चीनी, रंग आदि—का मूल्य निर्यात सामग्रियों से कहीं अधिक ऊँचा उठा। जहाजों में स्थान की कमी और निर्यात पर लगे सरकारी नियन्त्रण के कारण मूल्यों की वृद्धि भी कुछ हद तक रुक गई।

६. मुद्रा-स्फीति—हम पहले ही देख चुके हैं कि १९१४-१८ का युद्ध प्रारम्भ होने के कुछ समय बाद तक व्यापारिक सन्तुलन भारत के पक्ष में था। इसी समय खजाने के आयात

१. देखिए, श्री गोखले के भाषण, पृ० १५०।

मे भी काफी कमी हो गई। इस प्रकार निर्यात व्यापार की सारी जिम्मेदारी सरकार पर पड़ी। इस आर्थिक कमी को सरकार ने अधिक नोट छापकर पूरा किया। व्यापार की मात्रा में वृद्धि की अपेक्षा सब प्रकार की मुद्रा में बहुत अधिक वृद्धि हुई। सरकार द्वारा अपनाई गई युद्ध के अर्थ-प्रबन्ध की पद्धति से मुद्रा-स्फीति को और भी बल मिला। युद्ध के विनाश खर्च को पूरा करने के लिए सरकार ने अशत कर और कर्ज से रूपया प्राप्त किया तथा अशत नोट छापे। सरकार द्वारा लिये गए युद्ध-ऋणों में भी मुद्रा-स्फीति बढ़ी। ऋण का अल्पांश ही जनता की वास्तविक बचत से प्राप्त हुआ। रुप ने बैंक साख और निक्षेप का रूप धारण किया। बैंकों ने सरकार की ओर से भी अपने उन ग्राहकों की ओर से, जो युद्ध ऋण देना चाहते थे, चेक दिये। भारत सरकार द्वारा जारी किये गए अल्पकालीन ट्रेजरी बिल भी, जो आय-व्ययक क घाटे को पूरा करने के लिए प्रचलित किये गए थे, तथा युद्ध बन्ध-पत्र (वार फण्ड) भी मुद्रा-स्फीति के कारण सिद्ध हुए, क्योंकि बैंक उनकी सुरक्षा पर निर्भर ऋण दिया करते थे। इस प्रकार बैंकों के निक्षेप में भारी वृद्धि हो गई। उनके प्रचलन की गति भी तीव्र हो गई। इससे क्रय शक्ति की वृद्धि हुई और कीमतें ऊँची उठी। अन्य कारण भी थे जिनसे कीमतें बढ़ी—उदाहरणार्थ युद्ध-वर्षों में रोलिंग स्टॉक की कमी १९१८-१९ तथा बाद में १९२० में भी मानसून की असफलता। १९२० में कीमतें चम्प शिखर पर जा पहुँची।

७. ऊँची कीमतों का प्रभाव—मूल्य जाँच समिति के मत में युद्ध (१९१४-१८) के पूर्व मूल्यों में हुई वृद्धि से देश को लाभ ही हुआ। सरकार ने भी इससे सहमति प्रकट की, जबकि १९१४ में उन्होंने समिति की रिपोर्ट पर प्रस्ताव पास किया। समिति के अनुसार भारत एक ऋणी देश था, अतः उन वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने से उसे लाभ ही हुआ जिनका निर्यात वह अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए किया करता था। अब वह वस्तुओं की थोड़ी मात्रा निर्यात करके अपने विदेशी दायित्वों की पूर्ति कर सकता था, किन्तु इन बढ़ती हुई कीमतों के विरुद्ध हमें आयात के बढ़ते हुए खर्च और बढ़ती हुई उत्पादन लागत का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि मुद्रा-प्रसार से उत्पन्न हुई ऊँची कीमतों की परिधि अपने-आपमें कोई ऐसे स्थायी लाभ प्रदान कर सकती है, जो उसकी सर्वविधित हानियों को दूर कर सकें। जोशी का मत इस सम्बन्ध में अत्यन्त पुष्ट है कि “धन तथा समृद्धि की वृद्धि राष्ट्र और व्यक्तियों में एक ही प्रकार से आती है। यह वृद्धि न तो रूपयों के ढेर से और न कीमतों की वृद्धि से ही आती है, जो (कीमतों की वृद्धि) भारत में फलता की कमी, मानसून की असफलता तथा दुर्भाग्य व कारण होती है। देश की वास्तविक समृद्धि औद्योगिक क्रियाशीलता, कुशलता और कार्य क्षमता तथा पूँजी के उत्पादक

१ पन्डित, 'दि इकॉनॉमिक कॉन्डिशनस ऑफ़ दि इंडिया', पृ० ३१७-१८।

२ देखिए, अध्याय ११।

३. देखिए, किन्ले शिराउ, पब्लिक फ़ाइनेन्स, पृ० २३० और ४१०-११।

प्रयोग से होती है।" १९१४-१८ के पूर्वकाल के लिए कीमतों तथा पारिश्रमिक की गतिविधि से श्रीमती वेरा एन्स्टे^१ ने राष्ट्रीय समृद्धि के सम्बन्ध में कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। उनका कहना है कि इस प्रकार से निकाले गए निष्कर्ष विभिन्न तिथियों पर तथा अनुमानित राष्ट्रीय आय-सम्बन्धी आँकड़ों के निष्कर्षों से अधिक विश्वसनीय हैं जिनकी चर्चा अध्याय ४ में की जा चुकी है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि मूल्य-परिवर्तनों की छानबीन स्वतः घन-उत्पादन की प्रगति या गतिरोध या प्रगतिगामिता का कोई अनुमान नहीं दे सकती। इससे केवल इस बात का पता लगता है कि विभिन्न वर्गों में वितरित घन कीमतों के स्तर के परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होता है। इसके अनिश्चित राष्ट्र के होने वाले लाभ या हानि के निष्कर्ष विभिन्न वर्गों के कल्याण की सापेक्षिक महत्ता-सम्बन्धी सदिग्ध मान्यताओं पर आधारित है। यह कहा जाता है कि भारत के अधिकांश व्यक्ति उस वर्ग के हैं जो कीमतों के बढ़ जाने से लाभान्वित होते हैं। ऋणी वर्ग इस लाभ के योग्य है। यद्यपि उनका लाभ कर्ज देने वाले वर्ग की हानि होती है, परन्तु यह शोचनीय नहीं है क्योंकि ऋण देने वाले खून पीने वाली जोक के समान होते हैं। किन्तु इस प्रकार का 'योग्य'-'अयोग्य' वर्ग-सम्बन्धी विभाजन अनुचित है। सब वर्गों की समृद्धि ही वास्तविक राष्ट्रीय समृद्धि है। साथ ही कठिनाई यह है कि कितने ही व्यक्ति ऋणी और साहूकार दोनों ही हैं तथा सम्पूर्ण ऋणदाता-वर्ग की भर्त्सना भी अनुचित है। श्रीमती एन्स्टे के मतानुसार प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व के मूल्य-परिवर्तनों से देश के अधिकांश किसान अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे, क्योंकि निर्यात की सामग्रियों, जिन्हें किसान बेचता है, उदाहरणार्थ जूट (४३%), चमड़ा और खाल (५९%), तिलहन (४५%), और खाद्यान्न (४२%) के मूल्यों में अधिक वृद्धि हुई। इसके विपरीत आयात सामग्रियों में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई। उदाहरणार्थ कपड़े की सामग्रियों (२५%), घातु (२०%), चीनी (९%), मिट्टी का तेल (कोई परिवर्तन नहीं), और नमक में ३०% कमी हुई। इस प्रकार की वस्तुओं के मूल्यों के सापेक्षिक परिवर्तन से निश्चय ही किसानों को लाभ पहुँचता है।

युद्ध-काल में आयात-मूल्य निर्यात की अपेक्षा अधिक बढ़े। परिणामस्वरूप किसानों का व्यय आय से अधिक होने लगा। इसे सभी स्वीकार करते हैं कि इससे कृषक-वर्ग को हानि हुई। यहाँ इस साधारण मत का स्रण्डन होता है कि कीमतों की वृद्धि से भारतीय जनता के अधिकांश को अवश्य लाभ होता है।

८. किसानों पर प्रभाव—ऐसा कहा जाता है कि गाँव में जमीन वाले और सामान्यतः ग्रामीण वर्ग कृषि-उत्पादन के मूल्यों की वृद्धि से अवश्यमेव लाभान्वित होते हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि जिनके पास बेचने के लिए सामग्रियाँ बचती होंगी केवल उन्हीं को लाभ होगा और यह लाभ तभी होगा, जबकि उनके द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का

१. जोशी, एपीसेज एण्ड राइटिंग, पृ० ६१०।

२. दि इकनामिक डिबेलपमेंट ऑफ इण्डिया, पृ० ४४५।

मूल्य उनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं के अनुपात में नहीं बढ़ता। भारत में कृषकों को होने वाला लाभ मध्यस्थों द्वारा हड़प लिया जाता है। फलतः ऊँची कीमतों से किसानों की आर्थिक दना में कोई उन्नति नहीं होती। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अपनी भूमि या लम्बे पट्टे की जमीन के किमान, जो अपने धर्म पर निर्भर रहते हैं तथा, जिनके पास बेचने के लिए कुछ बचना है, ऊँचे मूल्यों से लाभान्वित होते हैं, परन्तु यह बात दूसरों से लगान पर भूमि लेने वाले कृषकों या श्रमिकों में मजदूरी पर काम कराने वाली पर लागू नहीं होती।

श्री दत्ता के अनुसार ग्रामीण मजदूरों की मजदूरी १९१४-१८ के युद्ध में फुटकर कीमतों से अधिक बढ़ी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह वृद्धि ३८% थी। इन प्रकार युद्ध और युद्धोत्तर-काल में ग्रामीण मजदूरी और कीमतों में व्यवस्थापन होता रहा। १९२१ के बाद कीमतों के घटने पर ग्रामीण मजदूरों की वास्तविक मजदूरी में वृद्धि हुई।

१९०६ के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी घटने लगी। १९२६-३३ की आर्थिक मन्दी में इसकी गति और तीव्र हो गई। मजदूरी बढ़ी तेजी में घटी, हालांकि खाद्यान्नों एवं जीवन की अन्य आवश्यक सामग्रियों का मूल्य भी कम हो गया।

लगान पर कीमतों की वृद्धि के प्रभाव के सम्बन्ध में सुरक्षित या सुविधा-प्राप्त तथा अरक्षित वर्ग के किसानों में भेद करना आवश्यक होगा। दलीलकार (मोहसी) किसानों (जो पहले वर्ग के किसानों का उदाहरण है) का लगान धीरे-धीरे बढ़ेगा, जबकि अरक्षित किसान के लगान में अधिक वृद्धि होगी।

६ उद्योगों पर प्रभाव—(१) दस्तकारी—हम देशी दस्तकारी में लग व्यक्तियों के आर्थिक गतिराश की चर्चा कर चुके हैं। इसका कारण मशीनों से बनी वस्तुओं की होड़ थी। कीमतों के बढ़ जाने से यह होड़ भी बढ़ गई। इससे दस्तकारों की दना और खराब होनी गई। (२) पूंजीपति-निर्माता—१९१४-१८ के युद्ध के पहले और बाद में निर्माताओं को अतदिग्ध रूप से लाभ हुआ। लेकिन य लाभ उच्च लाभों के वितरण में समाप्त हो गए और इनसे सुरक्षित कोष नहीं बनाया जा सका। परिणामा पर ध्यान न देकर भाग घटने रहने का दण्ड उन्हें भुगतना पला।

१०. ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरों के श्रमिक—१९१४ के पहले वास्तविक और नकद मजदूरी बढ़ी। गाँवों में वृद्धि ३८% और नगरों में २८% रही। १९१७-२० के बीच कीमतों में तीव्रता से होने वाली वृद्धि के कारण हड़तालों की महामारी फैल गई। कितनी ही दशाभा में दग हुए और बाजार तक लूट गए। किन्तु १९२१ के बाद औद्योगिक श्रमिकों की दशा निरिचन रूप से सुधरन लगी, मजदूरी भी बढ़ी और रहन सहन का खर्च भी कम हुआ। किन्तु मन्दी के दिनों में फिर उद्योग की हालत खराब हो गई। मजदूरी घट गई, व्यापक रूप से बेकारी फैली और श्रमिक वर्ग को बड़ा बप्ट हुआ। १९३८ में आंशिक सुधार हुआ। दम्बई में मजदूरों की कटौती बन्द कर दी गई तथा कुछ अन्य प्रान्तों में भी ऐसा ही किया गया (दखिए अध्याय ३)।

११. स्थिर आमदनी वाले व्यक्तियों पर प्रभाव—कीमतों के ऊँची होने से सबसे अधिक कष्ट स्थिर आमदनी के व्यक्तियों—बलकों, पेन्शन वालों, निम्न श्रेणी के सरकारी और व्यावसायिक कर्मचारियों, प्रतिभूतियों तथा लाभांशों की आय पर निर्भर करने वालों तथा पेरोवर लोग, जिनकी फीस निश्चित थी—को हुआ। ये वर्ग—जिन्हें सामूहिक रूप से मध्य वर्ग कहा जाता है—कीमतों के ऊँची होने पर कष्ट उठाते हैं। कारण यह है कि इनकी आमदनी तो स्थिर होती है, किन्तु अन्न, वस्त्र, प्रकाश, किराया-मकान तथा उनके द्वारा रखे जाने वाले मजदूरों की मजदूरियाँ आदि सभी बढ़ जाती हैं।

१२ अवसाद और उसके बाद के समय में मूल्य—१९२० में चरम शिखर पर पहुँच कर कीमतें १९२१ में घटनी शुरू हुईं। कुछ समय तक इंग्लिस्तान में प्रतिया भारत से तीव्रतर थी। इससे सरकार की रुपये के मूल्य को दो शिलिंग पर स्थिर करने की नीति खतरे में पड़ी। १९२० में रिर्वर्स-कौंसिल के विक्रय तथा तज्जन्य मुद्रा-सकुचन के कारण कीमतें घटी। १९२०-२१, १९२१-२२ के प्रतिकूल व्यापारिक सन्तुलन के परिणामस्वरूप भारत से स्वर्ण का निर्यात हुआ।

विश्व आर्थिक-मन्दी के काल में कीमतों की अधोमुखी गति और तीव्र हो गई। विश्व-मन्दी अक्तूबर, १९२९ में अमेरिका में वॉलस्ट्रीट पतन के साथ प्रारम्भ हुई।^१ इससे सभ्य जगत् का कोई कोना न बच सका, यह नीचे की तालिका से स्पष्ट है। प्राथमिक (कृषि) वस्तुओं की कीमतें निर्मित वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गिरी और भारत जैसे औद्योगिक देश ब्रिटेन और अमरीका-जैसे औद्योगिक देशों की अपेक्षा अधिक बुरी तरह प्रभावित हुए। कलकत्ता का थोक मूल्य देशनाक (जुलाई १९१४=१००) सितम्बर, १९२९ में १४३ था। सितम्बर, १९३१ में जब ब्रिटेन ने स्वर्ण-प्रमाण का परित्याग किया तो देशनाक ९१ हो गया, अर्थात् युद्ध-पूर्व काल के अंक से भी नीचे चला गया। रुपया उस समय पौण्ड से सम्बद्ध था। उसकी प्रतिक्रियास्वरूप मूल्य-स्तर दिसम्बर, १९३१ में ९८ हो गया। १९३२ में यह लाभदायक स्थिति न रही। कीमतें नीचे गिरी। देशनाक दिसम्बर, १९३२ में ८८ और मार्च में ८२ हो गया। लेकिन इसके पश्चात् मूल्य-स्तर स्थिर हो गया। क्रमिक आर्थिक पुनरुत्थान भारत में भी होने लगा। अप्रैल, १९३३ से १९३७ तक मूल्यों का आंशिक पुनरुत्थान हुआ। अगस्त, १९३७ तक जब कलकत्ता देशनाक १०५ हो गया, कीमतें ११ दरजा ऊँची उठ गईं। यह वृद्धि विश्वजनीन शस्त्रीकरण का परिणाम थी। इसमें समृद्धि-दशा और सट्टेबाजी ने भी योग दिया। इस आंशिक पुनरुत्थान को अमरीका तथा अन्य देशों में होने वाली व्यापारिक बिश्थान्ति (प्रत्यावर्तन) से घबका पहुँचा (१९३७ के मध्य में)। इसका भारत के मूल्यों पर बुरा प्रभाव पड़ा। विश्व के बाजारों के साथ कलकत्ता के बाजार का मूल्य देशनाक भी गिरने लगा और १९३८ के अप्रैल में निम्नतम स्तर पर पहुँच गया। जून, १९३८ तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जुलाई, १९३८ से

जनवरी, १९३६ तक देशनाक ६५ रहा। धीरे-धीरे मई, १९३६ तक बढ़कर यह १०१ हो गया। इसका कारण चीनी, चाय, कच्चे जूट और निर्मित जूट की स्थिरता थी। जुलाई में देशनाक बढ़कर १०० हो गया जबकि युद्ध की छाया तथा राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद यूरोप में छा गया था। अगस्त तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यद्यपि युद्ध के चिह्न क्षितिज पर दृष्टिगोचर होने लगे थे। इस प्रकार कलकत्ता का देशनाक १०० पर स्थिर रहा, जैसा कि प्रथम युद्ध प्रारम्भ होने के पूर्व १९१४ में था।

उदाहरण के लिए १९२६ के शिखर से मन्दी के निम्नतम गत तक प्रतिशत कमी भारत में ४४.३, ब्रिटेन में ३०.४, अमेरिका में ३८, अस्ट्रेलिया में २८.५ और जापान में ३५.५ थी। अमेरिका में मार्च, १९३३ में भयंकर पतन के बाद परिस्थिति धीरे-धीरे सुधरने लगी। देश के घोक मूल्य-स्तर में १९३५ में ८ दरजे की वृद्धि हुई। इसका कारण डॉलर का अवमूल्यन, राष्ट्रीय पुनर्स्थापन प्रशासन (नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन) और कृषि व्यवस्थापन प्रशासन (एग्रीकल्चरल एडजस्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन) थे। १९३१ में स्वर्ण प्रमाण त्यागने वाले जापान में, विशेषकर १९३५ से उर्वर्णगामी प्रवृत्ति लक्षित होने लगी। स्वर्ण प्रमाण दल के सबसे महत्त्वपूर्ण देश फ्रांस में मूल्यों की गति अघोषणी रही, यहाँ तक कि फ्रैंक के अवमूल्यन के बाद सितम्बर, १९३६ के अन्त में उसे भी स्वर्ण प्रमाण त्यागना पड़ा। इसके बाद फ्रांस की कीमतें भी शीघ्रता से बढ़ी। पुनर्स्थापन-काल में भारत की कीमतें अन्य देशों के बराबर नहीं बढ़ी। देशनाक का उच्चतम बिन्दु १९३७ में ७५ था (१९२६=१००) जबकि इंग्लिस्तान का ६७.५ और संयुक्तराज्य का ६१.८ था।

भारत में मूल्यों के गिराव का एक गम्भीर पहलू निर्मित और कच्चे माल की कीमतों की विपमता थी। यह निर्यात और आयात की वस्तुओं के देशनाकों से स्पष्ट है, जिनमें क्रमशः प्रधानतया कच्चा माल तथा निर्मित वस्तुएँ होती थीं। १९३२ के मार्च में सितम्बर, १९२६ की अपेक्षा कलकत्ता देशनाक के अनुसार निर्यात-वस्तुओं का मूल्य ५१% गिरा, जबकि आयात-वस्तुओं का मूल्य २७% ही गिरा। इस विपमता से कृषि प्रधान वस्तुओं पर विनिमय करने वाले भारत को अधिक हानि हुई। १९३६ के बाद मूल्यों का आर्थिक पुनर्स्थापन-काल में निर्मित वस्तुएँ धीरे-धीरे निर्यात वस्तुओं के साथ सन्तुलन स्थापित करने लगीं। यह इससे स्पष्ट है कि निर्यात-मूल्य मार्च १९३७ में ३६% कम हुए, जबकि आयात-मूल्यों का मूल्य २५% ही घटा (आधार-वर्ष १९२६)। इस प्रकार दोनों के बीच का अन्तर ४०% ही रह गया। भारत की आर्थिक व्यवस्था पर इसका लाभकारी प्रभाव पड़ा, किन्तु इस कृषि और उद्योग-वस्तुओं के मूल्यों का सन्तुलन फिर आर्थिक विश्रान्ति-काल में नष्ट हो

१. १९३०-३३ में कृषि के प्रधान उत्पादन चावल, गेहूँ, जौ, जूट, लिह्वन और कपास के मूल्यों में भयंकर वृद्धि हुई।

गया। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्राथमिक (कृषि) वस्तुएँ मूल्य-परिवर्तन-चक्र से सीधे प्रभावित होती हैं।

१३. मूल्यों के घटने के कारण और प्रभाव—मूल्यों के विश्वव्यापी गिराव के कारण द्राव्यिक और अद्राव्यिक दोनों थे। चीन, भारत और दक्षिणी अमेरिका में राजनीतिक अशान्ति होने के कारण मन्दी की दशा और भयकर हो गई। हम पहले ही कह आए हैं कि रुपये का मूल्य १ सि० ६ पैसे वर देने से भारत की कीमतें गिर गईं। यह असन्तुलन की प्राथमिक अवस्था की बात है। इससे स्पष्ट है कि आन्तरिक कारणों की तुलना में विश्वजनीन कारण अधिक दोषी थे। १९३७ (अप्रैल) में प्रारम्भ हुई अमरीकी आर्थिक विश्रान्ति—जो भारत में मूल्यों के परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी थी—सट्टेवाजी के पतन का परिणाम थी। इसमें स्वर्ण-भय—प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की चेतावनी की कीमतें अधिक ऊँची उठ रही हैं—तथा वैको द्वारा साख-मुविद्याओं पर लगाये गए प्रतिबन्धों का भी बहुत-कुछ हाथ था। भारतीय कीमतों की अद्योगामी प्रवृत्ति चीन-जापान के युद्ध के कारण अधिक तीव्र हो गई। इससे भारत के प्रधान कपास-कैना के घट जाने से भारत की व्यापार-शक्ति कम हो गई। भारत के विदेशी व्यापार और व्यापारिक सन्तुलन पर पड़े प्रभाव का (मन्दी और विश्रान्तिकाल में) निव्वरण किया जा चुका है। (देखिए, अध्याय ६, सेक्शन ६ और २३) किमानो का बड़ी कठिनाई हुई, क्योंकि उनकी आमदनी सीधे से घटने लगी और इसके विपरीत मालगुजारी, लगान, ब्याज इत्यादि के रूप में लिये जाने वाले भुगतान यद्यपि नाम में वैसे ही रहे, किन्तु वास्तविक रूप में बढ़ गए। इससे किसानों की अयशक्ति घट जाने से आर्थिक मन्दी और भी बढ़तर हो गई। यह ध्यान में रखना होगा कि कीमतों के घट जाने से हमारा कृषि-उत्पादन नहीं गिरा। कुछ क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। भारतीय दशाओं में कृषक को जो कीमत मिले वही लेनी पड़ती है। इस प्रकार एक विपाक चक्र प्रारम्भ हो जाता है, जिससे कीमतें घट जाने से उत्पादन अधिक हो जाता है और अधिक उत्पादन होने से कीमतें और घट जाती हैं। रबर और जूट-जैसी औद्योगिक सामग्रियों के उत्पादन में कुछ कमी हुई। इस आर्थिक अघट से राजस्व भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। कर बढ़ गए, छँटनी प्रारम्भ हो गई, मुद्रा-सकुचन होने लगा, सोना बाहर जाने लगा तथा बजट में घाटा होने लगा।

मार्च, १९३३ से अगस्त, १९३७ के पुनरुत्थान-काल में भारत की आर्थिक दशा में थोड़ा सुधार ही हुआ। शेष दुनिया की तरह भारत में भी वस्तुओं के मूल्य, प्रविभूतियों के लाभ तथा औद्योगिक लाभ कम हो गए। लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारम्भ होने के पहले ही विश्रान्ति घटने लगी थी और इसके बाद कीमतें सीधे से घटने लगीं।

१४. सितम्बर १९३६ के बाद कीमतें—युद्ध प्रारम्भ होने के बाद सितम्बर, १९३६

१. पृष्ठ ० वी० इन्सून, स्लम्प एण्ड रिक्वरी, पृ० ४४०-४२।

२. देखिए, रिपोर्ट ऑफ करेन्सी एण्ड फाइनेन्स, १९३६-४० से १९४६-४७।

में औद्योगिक उत्पादन और सामग्रियों की कीमतें बढ़ने लगी, क्योंकि यह आशा की जाने लगी थी कि युद्ध के कारण भारतीय कृषि और उद्योग का भविष्य उज्ज्वल होगा।

जापान के युद्ध में प्रवेश तथा अफ्रीका में युद्ध तीव्र होने से सयुक्त राष्ट्रों के पूर्वी और मध्य-पूर्वी मोर्चों का आधार भारत ही बना। पूर्ति-विभाग द्वारा दिये गए युद्ध के ठेके की मात्रा बढ़ती गई। ब्रिटेन की सरकार द्वारा युद्ध की सामग्री और सेवाओं के लिए किए गए भुगतान से ब्रिटेन में पौण्ड पावना (Sterling Balances) जमा होने लगे और देश में भुगतान करने के लिए बहुत मात्रा में करेन्सी निर्मित की जाने लगी। देश का सुरक्षा-व्यय भी काफी बढ़ गया। इसी प्रकार ऋण भी बढ़ गया। इस वर्ष में नोटों का प्रचलन, अनुसूचित बैंकों की माँग और देनदारी भी बढ़ी। इसी प्रकार रिजर्व बैंक द्वारा निरीक्षित विकास ष्ट्रों में चेकों की गहवा भी बढ़ गई। प्रागे दी गई तालिका से स्पष्ट है कि १९३६ से १९४४ के बीच कीमतें काफी ऊँची उठ गईं। तालिका की सहायता से विश्वों से तुलना भी की जा सकती है। योज कीमतें (आर्थिक परामर्शदाता देशनाक) ५% बढ़ गईं। बलकता का देशनाक और भी ऊँचा उठा (७९%)। जीवन यापन का व्यय भी थोक कीमतों का अनुसरण करने लगा। बम्बई का देशनाक ५२% बढ़ गया।

युद्ध प्रारम्भ होने के बाद तुरन्त ही भारत में वस्तुओं की कीमतें शीघ्रता से बढ़ने लगी, क्योंकि लोगों का यह विश्वास था कि आर्थिक युद्ध के घनीभूत होने से भारतीय उद्योग और कृषि का भविष्य उज्ज्वल होगा। भारतीय वस्तुओं की बढ़ती माँग के कारण निर्यात-निर्ण तीव्र थी। जहाजों की कठिनाइयाँ, बीमा के खर्च के कारण आयात में कमी, मुनाफे और भविष्य की व्यवस्था के लिए खरीद, सट्टेबाजी तथा वस्तुओं के मूल्यों की भावी गतिविधि के सम्बन्ध में आशापूर्ण वातावरण का प्रसार, इन सबके सम्मिलित प्रभाव से युद्ध प्रारम्भ होने के प्रथम चार महीनों (सितम्बर, १९३६—दिसम्बर, १९३६) में कीमतें ऊपर उठ गईं।

जनवरी, १९४० से जून, १९४० तक कीमतों की ऊर्ध्वगति में होने वाला आकस्मिक परिवर्तन, सट्टेबाजी की वजह से बढ़ी कीमतों के विरुद्ध प्रतिक्रिया का परिणाम था, जो कि प्रथम चार महीनों में क्रियाशील रही थी। मूल्य-नियन्त्रण के शीघ्रता से लगाए जाने, मूल्यों पर सरकारी नियन्त्रण के बढ़ने का भय, अधिक लाभ-कर (एक्सेस प्रॉफिट टक्स) की धोपणा तथा महाद्वीप के वाज्जारों के समाप्त होने से कीमतें कुछ घटने लगीं। अन्य सहायक कारणों में निर्यात-प्रतिबन्ध, विनिमय-नियन्त्रण तथा ४० करोड़ से अधिक मूल्य के सात को जो वकार धानु के रूप में बन्द थी, वापस लेने का नाम लिया जा सकता है।^१

१९४२ से कीमतों की गति ऊर्ध्वमुखी रही है (दखिए पृ० २९६ पाद-

१. देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सदस्यों की हकी वार्षिक रिपोर्ट और रिजर्व बैंक १९४० की वार्षिक रिपोर्ट।

टिप्पणी) । द्वितीय विश्वयुद्ध से उत्पन्न मुद्रास्फीति प्रथम युद्ध से अधिक दिनों तक रही । प्रथम युद्ध समाप्त होने के तीन वर्ष बाद (१९२१) से ही कीमतें नीचे गिरने लगी, लेकिन द्वितीय महायुद्ध के पाँच वर्ष बाद तक भी मुद्रास्फीति की प्रक्रिया वंसी ही बनी रही, क्योंकि प्रथम महायुद्ध की अपेक्षा द्वितीय महायुद्ध से अधिक धन तथा उत्पादन-क्षमता का विनाश हुआ । इस महायुद्ध में व्यय भी अधिक हुआ तथा कहीं अधिक ऋण-शक्ति की भी वृद्धि हुई । परन्तु ऋण-शक्ति की यह वृद्धि बचाने वालों की अपेक्षा उन लोगों के हाथ में गई जिन्हें उसे खर्च करने की आवश्यकता थी । अन्त में, प्रथम महायुद्ध के बाद का तो बहुत-सा समय शान्तिमय कार्य-सम्पादन में ही बीता था, पर १९४५ में समाप्त हुए युद्ध के बाद के समय की विशेषता जोर-शोर से शस्त्रीकरण तथा सामरिक और बुनियादी सामग्रियों की माँग ही रही । २५ वर्ष पूर्व की अपेक्षा आज भारतवर्ष बाह्य जगत् के अधिक सम्पर्क में है, अतः उस पर इन सभी विश्वव्यापी कारणों का प्रभाव भी अधिक पड़ा ।

१५. द्वितीय महायुद्ध-काल तथा युद्धोत्तर-काल में मूल्य-परिवर्तनों का प्रभाव—द्वितीय महायुद्ध के कारण कीमतों में हुई वृद्धि के फलस्वरूप भारतीय कृषकों की उन्नति की आशा की जाती थी । लोगों की धारणा थी कि मदी की लम्बी अवधि के बाद कृषक-वर्ग अपने ऋण को चुकाकर काफी मुनाफा प्राप्त करेगा । यह भी आशा की जाती थी कि कालातीत ऋणों के भार से दवा हुआ सहकारी आन्दोलन उससे छुटकारा प्राप्त कर सके और इस प्रकार उसे विकास की प्रेरणा मिले । पर यथार्थतः सड़क के उन प्रारम्भिक चार महीनों में भी, जबकि मूल्य काफी अधिक था, किसानों को कोई विशेष लाभ न मिला, क्योंकि वे अपनी फसल को पहले ही बेच चुके थे ।

कीमतों में १९४० से हुई अत्यधिक वृद्धि का काफी प्रभाव भारत के वन-वितरण पर पड़ा । व्यापार तथा उद्योग में लग हुए व्यक्ति अत्यधिक समृद्धिवादी हो गए । यह लाभ कुछ असों में कृषि-वस्तुओं के उत्पादकों तक भी पहुँचा, जिससे कृषीय ऋण तथा सरकारी देनदारी का भार भी हलका हो गया, परन्तु निश्चित आय वाले व्यक्तियों की हानत बहुत बुरी हो गई, जिसका स्पष्ट दृष्टान्त बंगाल के अकाल में काल-नचलित लगभग दस लाख व्यक्ति हैं । इंगलिस्तान तथा संयुक्तराज्य ने इस विपत्ति का सामना राशनिंग, मूल्य-नियन्त्रण तथा मुद्रास्फीति विरोधी उपाय अपनाकर बड़ी सफलता से किया ।

स्वतन्त्रता के उपरान्त मूल्य

१५ अगस्त, १९४७ को भारत स्वतन्त्र हुआ । कांग्रेस ने स्वतन्त्रता-संग्राम के दिनों में पूँजीवाद के विरुद्ध जो आवाज़ उठाई थी अब उसके कार्यान्वयन की आशका से उद्योगपति भी दुविधा में पड़ गए । इसका प्रभाव उत्पादन पर अच्छा नहीं पड़ा । ऐसी स्थिति में मूल्यों के गिरने की कोई सम्भावना नहीं थी । कुछ वस्तुओं पर युद्ध-कालीन मूल्य-नियन्त्रण बने रहे । धीरे-धीरे मूल्य-नियन्त्रण हटाने की नीति अपनायी

गई। १९५१ से पंचवर्षीय योजनाएँ प्रारम्भ हुईं। अतएव खाद्यान्न और कृषि-वस्तुओं के मूल्यों के परिवर्तन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो गए।

प्रथम पंचवर्षीय योजनाविधि में कृषि और खाद्यान्न के मूल्यों ने कोई समस्या उपस्थित नहीं की। वस्तुतः कृषि-उत्पादन-सम्बन्धी लक्ष्य पूरे हो जाने के कारण कृषि-मूल्यों पर इसका प्रभाव स्वास्थ्यप्रद ही पड़ा। दूसरी योजना में भारी उद्योगों को महत्त्व देने के कारण न्य-रहित तो जनता के हाथ में आ गई किन्तु उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं हुई। परिणामतः मूल्य बढ़ने लगे। द्वितीय योजना के प्रत्येक वर्ष में मूल्य बढ़ते रहे।

१९५६-६० के वर्ष में सामान्य मूल्य-स्तर में हुई वृद्धि 'औद्योगिक कच्चे माल' तथा 'निमित्त' वस्तुओं के समूह में मूल्यों की वृद्धि के फलस्वरूप हुई। खाद्य-पदार्थों के मूल्यों में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई। १९५६-६० में मूल्य वृद्धि अधिकांशतः ऊँची दर पर विनियोग करन तथा पर्याप्त मात्रा में द्रव्य की पूर्ति और बैंक की साख के विस्तार के फलस्वरूप हुई। कुछ विशेष वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि उत्पादन की कमी के फलस्वरूप हुई। उदाहरण के लिए रेशे वाले पदार्थों की मूल्य-वृद्धि का यही कारण था।

द्वितीय योजना-काल में हुई मूल्यों की वृद्धि के कारणों को हम प्रकार गिनाया जा सकता है (१) विकास-कार्यक्रमों के फलस्वरूप विनियोग की ऊँची दर, (२) द्रव्य की पूर्ति और बैंक साख का विस्तार, (३) कुल माँग (एग्जिस्ट डिमाण्ड) में वृद्धि तथा अनिपय विशेष वस्तुओं की माँग में वृद्धि, जैसे औद्योगिक कच्चा माल, (४) उत्पादन की सापेक्षिक वृद्धि की ग्लूना, (५) उत्पादन के उचित विनियोग का अभाव आदि।

मूल्य नीति—मूल्यों की वृद्धि को रोकने के लिए उठाये गए उपायों को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है, या यों कहिए कि मूल्य-नीति के दो पहलू हैं (क) द्रव्यात्मक तथा साख-सम्बन्धी उपाय तथा (ख) गैर-द्रव्यात्मक उपाय।

(क) के अन्तर्गत निम्न उपाय अपनाये गए (१) चयनित साख नियन्त्रण (सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल), जिसका १९५६-६० में और अधिक विस्तार किया गया, (२) नैतिक आग्रह तथा (३) प्रथम बार सुरक्षित कोष के अनुपात में परिवर्तन, जो १९५६-६० के अन्त में अपनाया गया।

(ख) के अन्तर्गत अपनाये गए उपायों में मुख्य (१) आयात तथा वसूली द्वारा खाद्यान्नों की पूर्ति में वृद्धि, (२) उचित मूल्य की दकानों द्वारा नियन्त्रित विनियोग की प्रथा का विस्तार, (३) (क) खाद्यान्न के अग्रिम व्यापार (फारवर्ड ट्रेडिंग) पर रोक जारी रखना, (ख) आवश्यक परिवर्तनों सहित खाद्यान्नों के अन्तर्राज्यीय आवागमन पर रोक तथा क्षेत्रीय व्यवस्था (जोनल एरेन्जमेण्ट) को जारी रखना, (ग) आठ की चकियों द्वारा गेहूँ की खुली खरीद पर रोक, (घ) आवश्यक पदार्थ अधिनियम १९५५ (एलेमिनियल कमोडिटीज एक्ट) की धारा ३ की उपधारा (३घ) की व्यवस्था का विस्तार, निम्ने अन्तर्गत नकार किली नी व्यवृत्ति क खाद्यान्न क नग्यार

को पिछले तीन महीनों के बाजार-मूल्य के औसत मूल्य पर बेचने को बाध्य कर सकती है तथा सरकार स्वयं उनके स्टॉक ले सकती है। (५) सम्पूर्ण खाद्यान्न व्यापार तक अनुज्ञा-पद्धति का विस्तार।

इस प्रकार हम देखते हैं कि १९४६ को आधार वर्ष मानते हुए उपभोक्ता मूल्यांक १९५५-५६ में ६६ से बढ़कर मार्च १९६१ में १२५ हो गया। तीसरी पंच-वर्षीय योजना में यह और भी बढ़ गया और १९६५ में १५६ तक पहुँच गया। १९६५-६६ में विशेष तौर से पाकिस्तान से लड़ाई तथा १९६६ के बजट के बाद कीमतें बढ़ती ही चली गई हैं, यहाँ तक कि देश में योजना तथा प्रजातन्त्र एक सकेट में पड़ गया है। दुख की बात तो यह है कि द्वितीय योजना में कीमतों के बढ़ने पर भी तीसरी योजना में कोई विशेष रूप से मूल्य-नीति निर्धारित नहीं की गई। तीसरी योजना में मूल्य नीति का अध्याय उपोद्घर्षण तथा असामर्थ्य है। इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया कि एक वर्धन अर्थव्यवस्था के लिए मूल्य-नीति का कितना महत्त्व है। इस समय देश में कुल माग कुल पूर्ति से कहीं अधिक है। और इस प्रकार हर उद्योग तथा खेती का क्षेत्र एक प्रकार से विक्रेता बाजार में बँट गया। इस बात को हमें याद रखना होगा कि जिस प्रकार मुद्रास्फाति में से हम गुजर रहे हैं, इससे छुटकारा नहीं मिल सकता जब तक कि खाद्य पदार्थों का उत्पादन न बढ़ाया जाए, बढ़ती जनसंख्या को रोकधाम हो, कीमतों को स्थिर रखा जाए, चोरबाजारी को खत्म किया जाए और अस्वच्छीकरण धन पर कब्जा किया जाए। अगर चौथी योजना में इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखा गया तो लोकतन्त्र को राष्ट्र में किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा।



अध्याय २४

अधिकोषण (बैंकिंग) और साख'

भारतीय अधिकोषण का इतिहास

१ देशी अधिकोष—भारतीय अधिकोष प्रणाली इतनी ही पुरानी है जितनी कि यहाँ का व्यापार। सम्भवतः भारतवर्ष में ससार के अन्य देशों से भी पहले तथा उनसे भी अधिक, अधिकोष प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। चाणक्य के अर्थशास्त्र (३०० ई० पू०) में ऐसे व्यापारी महाजनो के शक्तिशाली सधो का वर्णन है जो रपया जमा लेते, उधार देते तथा अनेक ऐसे कार्यों का सम्पादन करते थे, जो आधुनिक अधिकोष करते हैं।

भारतवर्ष पर मुसलमानों के आक्रमण के साथ ही यहाँ उयल-भुयल तथा अ-रक्षा काल का प्रारम्भ होना है, जो अधिकोष व्यवस्था के लिए प्रति हानिकारक है। अपने सचिंत धन को किसी को सौंपना खतरे से खाली न था, अतः इसे ब्रव छिद्राकर सचिंत किया जाने लगा। तो भी व्यक्तिगत साहूकार समृद्धिशाली होते ही गए। साधारणतया वे व्यापार तथा महाजनी दोनों कार्य साथ-साथ ही करते थे। वे राज्य को कर्ज देते थे तथा अनेक प्रभावशाली महाजन परिवारों का सम्बन्ध किसी-न-किसी देशी राजदरवार से होता था। 'बिना दरवारी महाजन के शाही दरवार अपूर्ण समझा जाता था। ऐसे महाजन को प्रायः एक मन्त्री की शक्ति प्रदान की जाती थी।' दगल के नवाबों के खानदानों महाजन जगतसेठ परिवार का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि इन महाजनो का देश की राजनीति में कितना हाथ था।

अब भी देशी अधिकोष प्रणाली इस देश की द्रव्य व्यवस्था का प्रधान अंग है। प्रत्येक गाँव, कस्बे तथा नगर में देशी महाजन^१ मौजूद हैं। एक ओर गाँव में ये छोटे

१. भारतीय अधिकोष तथा साख विषयक प्रामाणिक सूचना १९२६-३० में नियुक्त विभिन्न प्रांतीय अधिकोष खोज-समितियों तथा केन्द्रीय अधिकोष खोज समिति के साक्ष्य के विवरण तथा पुस्तकों में विस्तारपूर्वक दी गई है। अपनी रिपोर्टें पेश करने के पूर्व केन्द्रीय अधिकोष खोज समिति की प्रांतीय समितियों की रिपोर्टें तथा विदेशी विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से भी विचार करना था। विदेशी विशेषज्ञों ने अलग से अपनी एक रिपोर्टें तैयार की थी, जिसे केन्द्रीय समिति ने अपनी रिपोर्टें में ही शामिल कर लिया। इन परिच्छेद में केन्द्रीय अधिकोष खोज समिति तथा उसके अनु-दैदा का निर्देश क्रमशः "के० अ० रि०" तथा अर्थों द्वारा किया गया है।

२. देखिए, एच० सिन्हा द्वारा लिखित 'अर्ली यूरोपियन बैंकिंग इन इण्डिया', पृष्ठ १-३।

३. केन्द्रीय अधिकोष खोज समिति ने निम्नलिखित परिभाषा दी है—“देशी महाजनों से बनारा अभि-प्राय इन्धेरियल बैंक अॉक इण्डिया, विनिमय बैंक, मिश्रित पूँजी के बैंक तथा सहकारी समितियों को

पूँजीपतियों के रूप में हैं, दूसरी ओर देश-विदेश में एजेन्सियाँ रखने वाले व्यापारिक महाजनों ने सम्पन्न और व्यक्तिगत साम्प्रदायियाँ—विशेषतः कौटुम्बिक साम्प्रदायियाँ—बना रखी हैं, जो सम्पन्न तथा सुसंगठित हैं। इन देशी महाजनों की एक विशेष श्रेणी मद्रास के चेट्टी हैं, जिनके व्यापार में सारी जाति की करीब-करीब सम्मिलित जिम्मेदारी होती है।^१ मद्रास के मदुरा जिले के नाट्टकोट्टई चेट्टी व्यापारी महाजन रूप में विशेष प्रसिद्ध हैं और प्रायः उनका कार्यक्षेत्र ससारव्यापी है। भारतीय सर्राफों तथा साहूकारों द्वारा सम्पादित कुल महाजनी व्यापार अवश्य अत्यधिक होगा तथा इन महाजनों की कारबार-सम्बन्धी नैतिकता अति उच्चकोटि की मानी गई है। भारतीय देशी अधिकोप प्रणाली का संगठन मिश्रित पूँजी के आधार पर नहीं है। निक्षेप रूप में तो प्रायः थोड़ी-सी ही पूँजी आती है, पर इसकी वापसी चेक द्वारा नहीं, बल्कि नकद में होती है। यहाँ हिस्सा-पूँजी की प्रथा नहीं है और उत्तरदायित्व वैयक्तिक अथवा साम्प्रदायी में सम्मिलित और असीमित होता है।

आधुनिक अधिकोप तथा देशी अधिकोप प्रणाली के बीच दो महान् अन्तर हैं—(१) आधुनिक युग में मिश्रित पूँजी वाले अधिकोपों का विकास और (२) निकासी गृह के माध्यम द्वारा रूपया भेजने के लिए चेक का सार्वभौमिक प्रयोग। अतीत काल में सर्राफ लोगों का प्रधान काम मुद्रा भुनाई था।

२ देशी अधिकोप की वर्तमान स्थिति—सर्राफ वर्ग अब भी भारतीय द्रव्य बाजार तथा व्यापारी समुदाय के बीच की अनिवार्य कड़ी के रूप में देश की आर्थिक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भाग ले रहा है। वह कृपको, साधारण जिल्लियों और व्यापारियों को रूपया उधार देता, उपभोग के स्थानों और बन्दरगाहों तक फसलों के पहुँचाने में सहायक होता तथा देश के भीतरी भाग में सब प्रकार की चीजों का वितरण करता है। फसल कटने के मौसम में आवश्यकतानुसार अपने एजेंट को रेल द्वारा नकद रुपये के साथ भेजता है अथवा सरकारी खजाने पर हुण्डी खरीदता तथा रुपये की आवश्यकता पड़ने पर उस हुण्डी को इम्पीरियल बैंक या व्यावसायिक शहरों के अन्य बैंकों में बट्टा करा लेता है।^१ कुछ अंशों में ये देशी साहूकार आधुनिक प्रणाली के आधार पर संगठित मिश्रित पूँजी वाले बैंकों के घोर प्रतियोगी भी हैं। ऊँची दर की सूद लेकर कभी-कभी ये बड़े-बड़े बैंकों से भी अधिक निक्षेप (डिपॉजिटस) इकट्ठा कर लेते हैं। निजी विश्वास पर भी वे कर्ज देते हैं तथा आधुनिक बैंकों की अपेक्षा इन महाजनों द्वारा माँगी गई जमानत की पूर्ति अधिक आसानी से होती है। उन्हें एक और भी लाभ है। आज की स्थिति में हमारे देश के आधुनिक बैंक मुट्ठी-भर बड़े व्यापारियों की सहायता भले ही कर सकें, पर वे समूचे देश के व्यापारी-वर्ग से निकट सम्पर्क

छोड़कर अन्य सभी महाजनों से हैं। निक्षेप लेने, हुण्डियों का कारबार करने तथा रूपया उधार देने वाले व्यक्तिगत तथा निजी फर्म भी इसी कोटि में आते हैं।^२ (अनुच्छेद १०७)। जो निक्षेप नहीं लेते उनकी गणना देशी साख एजेन्सी की अन्य कोटि में होती है।

१. पन् ० एम० एम० गुप्ते द्वारा लिखित 'इण्डियन बैंकिंग इन इण्डिया', पृ०-११-१२।

२. देखिए, शिराज कृत 'इण्डियन फाइनेन्स एण्ड बैंकिंग', पृ० २४१।

स्थापित कर उन्हें सुविधा प्रदान नहीं कर सकते। इस स्थिति में भारतीय साहूकार अनिवार्य मध्यस्थ है। बैंकिंगतन्त्र समिति के निम्नलिखित शब्दों से यह स्पष्ट है कि देशी महाजनो तथा आधुनिक द्रव्य-व्यवस्था के बीच किस प्रकार का सम्बन्ध है—जिन लोगों का बैंको से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है वे प्रायः प्रसिद्ध शहरों के अच्छी स्थिति वाले सर्राफ ही होते हैं। वे अपनी निजी पूँजी से कारबार करते हैं और साधारणतया छोटे छोटे सर्राफों तथा दूसरे लोगों की ढुण्डियाँ खरीद लेने के पश्चात् ही वे बैंको का आश्रय लेते हैं। जिन सर्राफों की ढुण्डियाँ बड़े सर्राफ खरीदते हैं वे अपने से भी छोटे सर्राफों को रूपा देते हैं। इस प्रकार यह रूप गाँव के बनियो, भनाज बेचने वालों तथा मुनारो तक चलता है।

३. पुरानी तथा नई अधिकोप प्रणाली के एकीकरण की आवश्यकता—साधारणतया यह अनुभव किया जा रहा है कि देश के पूँजी के साधनों का उपयोग करने तथा इसके साख के सगठन के नियन्त्रण में एकता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि देशी अधिकोप-पद्धति और आधुनिक मिथित-पूँजी-प्रणाली के बीच निकटतम घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया जाए। १९३३ में सर जॉर्ज गुस्टर ने असेम्बली में रिजर्व बैंक विधेयक पर बोलते हुए कहा था कि “भारत के सम्पूर्ण बैंकिंग तथा साख के सम्बन्ध में देशी महाजनो द्वारा किये गए कार्यों को बढा-चढाकर वर्णन करना अति दुष्कर है। यह कथन अत्युक्ति नहीं कि इनका सगठन सम्पूर्ण साख-सगठन के ६० प्रतिशत से भी अधिक है। दुर्भाग्यवश यह भी सत्य है कि सहकारी समितियों के विकसित होने तथा इम्पीरियल बैंक की सौ नई शाखाओं के खुल जाने के बावजूद भी देशी अधिकोप तथा आधुनिक अधिकोप-प्रणाली का सम्बन्ध अभी भी मामूली और अपरिपक्व दशा में ही है। देशी महाजनो के रूप में प्रकट (रिप्रेजेंटेटिव) भारत के इस बृहत् अधिकोप तथा साख-सगठन का सहयोग जब तक आधुनिक द्रव्य बाजार के साथ, जिसका नियन्त्रण रिजर्व बैंक करता है, नहीं होगा, तब तक रिजर्व बैंक के लिए साख तथा सिनके पर पूर्ण नियन्त्रण करना असम्भव है, यद्यपि पाश्चात्य देशों के केन्द्रीय बैंको का यह कर्तव्य समझा जाता है। भारत के गाँवों में निवास करने वाली जनता के लिए भी यह सम्भव नहीं होगा कि वह उचित शर्त पर साख तथा अधिकोप-सम्बन्धी वह लाभ प्राप्त कर सके, जिसे प्रदान करना एक सुसंगठित अधिकोप-प्रणाली का कर्तव्य है।”

४. देशी साहूकारों से सम्बन्ध स्थापित करने की रिजर्व बैंक की योजना—रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट १९३४ की धारा ३५ (१) (अ) के अनुसार रिजर्व बैंक को तीन वर्षों के अन्तर्गत ही शीघ्रातिशीघ्र गवर्नर जनरल की परिषद (गवर्नर जनरल इन

१. इ ढियों तीन उद्देश्यों से लिखी जाती हैं—(क) कर्तृ प्रग्न करने के लिए (इस ढालत में हु ढी व्याव-सायिक हु ढी तथा हस्तपत्रक (हैंड विल) के समान होती है।) (ख) व्यापार को नैतिक योग देने के लिए जबकि यह विनिमय-पत्र के समान होती है, परन्तु विनिमय-पत्र की भांति हु ढियों के साथ विक्री के सौदे, धीमक, गोशाम की रमीद आदि स्क्व-अधिकार-पत्र सदैव नरुधी न्ही किये जाते। साधारण-तया केवल हु ढी ढी ढी जाती है। (ग) रुपये को व्यापार या किसी अन्य अभिप्राय से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए।

कौंसिल) के सामने ऐसे प्रस्तावों के साथ विवरण प्रस्तुत करना था जिसके अनुसार रिजर्व बैंक एक्ट में अनुसूचित अधिकोषों को प्रदत्त सुविधाएँ और ब्रिटिश भारत में बैंकिंग व्यापार ऐसे व्यक्तियों और फर्मों को प्रदान किया जाए जो अनुसूचित नहीं हैं।^१

१९३७ ई० में रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर ने केन्द्रीय अधिकोष खोज समिति की सिफारिश तथा १९३६ ई० में सशोधित इण्डियन कम्पनी एक्ट में बैंकिंग कम्पनी के नियमों के अनुसार ही निजी साहूकारों को सयुक्त करने की योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया।^२ रिजर्व बैंक ने यह सुझाव रखा कि अगर देशी साहूकारों को रिजर्व बैंक से सम्बन्धित होना है तो उन्हें अपनी महाजनी व्यवस्था को मिश्रित पूँजी वाले बैंकों के अनुरूप बनाना होगा तथा महाजनी के निक्षेप (डिपॉजिट) पक्ष को अधिक विकसित करना होगा। जिन साहूकारों के पास कम-से-कम दो लाख की स्वीकृत पूँजी हो तथा जिसे वे ५ वर्ष में ५ लाख तक कर लेंगे वे वैयक्तिक बैंक बनने के लिए रिजर्व बैंक को आदेदन-पत्र भेज सकते हैं। उन्हें एक निश्चित समय के भीतर गैर-महाजनी कारबार बन्द करना होगा। उनकी अभियाचना का उत्तरदायित्व (डिमांड लाइ-बिलिटी) जब तक उनकी निक्षेप देनी उनके कारबार में लगी पूँजी पाँच गुना या उससे अधिक न हो जाएगी तब तक उन्हें रिजर्व बैंक में अनिवार्य निक्षेप (डिपॉजिट) नहीं रखना पड़ेगा। वे हिसाब के उचित खाते रखें तथा हिसाब का संप्रक्षण किसी निवृत्त संरखाता से कराएँ। वे अपने हिसाब-किताब का सत्रिक (पीरियोडिकल) द्रव्य रिजर्व बैंक को भेजें तथा अधिकोषों की भाँति उनके लिए बने अधिनियम में निर्धारित आंकड़ों को अपने निक्षेपकों की जानकारी के लिए प्रकाशित करें। इन शर्तों को पूरा करने वाले देशी महाजन मान्य पत्रों के आधार पर अपने विनियम-पत्रों का रिजर्व बैंक से सीधे बढ़ा करा सकेंगे। अतः रिजर्व बैंक ने भारत सरकार को सूचित किया कि वह रिजर्व बैंक अधिनियम में सशोधनार्थ ऐसी कोई तात्कालिक सिफारिश नहीं कर सकता जिसके अनुसार अनुसूचित बैंक सम्बन्धी धाराओं को देशी साहूकारों के सम्बन्ध में लागू किया जा सके।

अक्टूबर, १९५३ में केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से रिजर्व बैंक ने एक समिति (जिसे आफ समिति कहते हैं) यह विचार करने के लिए नियुक्त की कि वैयक्तिक साहस-क्षेत्र में वित्त-व्यवस्था की, विशेषतः अधिकोषों द्वारा, सुविधा कैसे उपलब्ध की जाए। समिति की रिपोर्ट में साहूकारों और सर्राफों के सम्बन्ध में भी कुछ सिफारिशों की गई हैं जिनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं—

(क) सर्राफों और साहूकारों का रिजर्व बैंक से सम्बन्धीकरण करने की चेष्टा अधिक लगन के साथ की जाए।

(ख) सर्राफ उपयुक्त खाते हिन्दी या अग्रेजी में रखें और रिजर्व बैंक की

१. नीचे सेवरात ४३ देखिए।

२. देखिए, सेवरात २६।

स्वीकृति से अपना अधिकृत भारतीय सगठन बना लें।

(ग) सराफि उद्योग तथा व्यापार को वित्तीय योग देते हैं। अतः उन पर ऋण-सम्बन्धी अधिनियम न लागू हो।

(घ) सराफि दरांनी हुण्डियों के स्थान पर ६० दिन की हुण्डियों का प्रयोग करें और प्रोत्साहनस्वरूप उनकी ऐसी हुण्डियों की आधी स्टाम्प ड्यूटी सरकार कम कर दे।

(च) रिजर्व बैंक, आवश्यकता हो तो, रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन कराके, अनुसूचित बैंकों के माध्यम से सराफों, विशेषतः शिकारपुरी सराफों की मुहूर्ती हुण्डियों का पुनर्वर्द्धा करे, जब तक सराफों का रिजर्व बैंक से सीधा सम्बन्ध नहीं स्थापित हो जाना।

(छ) व्यापारिक बैंकों को चाहिए कि छोटे व्यापारियों तथा उद्योग-वन्धियों द्वारा लिखी तथा सराफों द्वारा पृष्ठांकित हुण्डियों का वट्टा करे, वरन् हुण्डी-सम्बन्धी पक्षों का बैंक को विश्वास हो।

५. आधुनिक अधिकोपण का उदय—कलकत्ता के एजेन्सी हाउसों ने सर्वप्रथम इस देश में यूरोपीय अधिकोपण प्रणाली का आरम्भ किया। उन लोगों के कारोबार के सहायक अंग के रूप में ही इसका उदय हुआ। साहूकारों की हैसियत से ये एजेन्सी हाउस यहाँ के घनी सौदागरों तथा उद्योगपतियों के साथ कारोबार करते थे तथा उनके जहाजों तथा नील की फँवट्टियों को बचक रखकर उन्हें बर्ज देते थे। भारत में निवास करने वाली यूरोपीय जाति तथा ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकारिगण अपनी वचत सरकारी सिक्कूरिंग की अपेक्षा व्याज की ऊँची दर के लोभवश एजेन्सी हाउसों के हवाले करते थे। सट्टेबाजों के कारण एजेन्सी हाउसों को मुसीबत का सामना करना पड़ा और १८२६-३२ के व्यावसायिक सङ्कट में तो उनका गला ही घोट दिया। अस्तु यूरोपीय प्रणाली के आधार पर सगठित बैंक न तो उस समय ही मिश्रित पूँजी वाले थे, न आज ही वे पूर्णतया वैसे हैं। ग्रिडलेज-जैसी यूरोपीय प्रणाली में निजी अधिकोपण विभाग होना है। सर्वप्रथम अलेग्जेंडर एण्ड कम्पनी न कलकत्ता में बैंक ऑफ हिन्दुस्तान की स्थापना की, जो पूर्णतया यूरोपीय प्रणाली पर आधारित प्रथम अधिकोपण था। १८२६-३२ के व्यावसायिक सङ्कट के समय अलेग्जेंडर कम्पनी और साथ में उस बैंक का भी दिवाला निकल गया। उसी ध्वसावशेष पर तत्पश्चात् कलकत्ता के प्रायः सभी प्रमुख एजेन्सी हाउसों के सहयोग से अनिधन बैंक नामक मिश्रित पूँजी वाले बैंक की स्थापना की गई, पर १८४८ में वह भी बन्द हो गया।^१

६. प्रेसीडेन्सी बैंक—प्रेसीडेन्सी बैंकों में सबसे पुराने तथा शक्तिशाली बैंक ऑफ बंगाल की कलकत्ता में १८०६ में ५० लाख की पूँजी के साथ ईस्ट इण्डिया कम्पनी की एक सनद द्वारा स्थापना हुई। इन पूँजी में १० लाख रुपया ईस्ट इण्डिया कम्पनी

१ इनके बाद भारत में मिश्रित पूँजी वाले बैंकों की उन्नति का विवरण आगे पैरा १६ व १७ में दिया है।

ने ही दिया था। १८४० में पहली 'बैंक ऑफ बम्बई' की स्थापना ५२ लाख रुपये की पूंजी के साथ हुई। इसमें सरकार ने तीन लाख रुपये के हिस्से लिये थे। अमरीका के गृह-युद्ध तथा कपास के अकाल से उत्पन्न तीव्र संकटों में इस बैंक ने भी हिस्सा बंटया और उसी के कारण १८६८ में इसका दिवाला भी निकल गया। द्वितीय बैंक ऑफ बम्बई की स्थापना उसी साल एक करोड़ रुपये की पूंजी के साथ हुई। १८४३ में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना ३० लाख रुपये की पूंजी के साथ हुई, जिसमें ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने तीन लाख रुपये के हिस्से लिये थे। कुछ दिनों से यह कल्पना की जा रही थी कि बैंक ऑफ बंगाल अखिल भारतीय बैंक का स्थान ग्रहण कर लेगा, पर इन तीनों बैंकों की स्थापना ने इस सम्भावना को समाप्त कर दी। प्रारम्भ से ही प्रेसीडेन्सी बैंक का निकट सम्पर्क सरकार के साथ था, जिसने केवल उनकी हिस्सा-पूँजी में ही योग नहीं दिया वरन् कुछ डाइरेक्टरों की नामदजगी का भी उसे अधिकार था। १८५७ तक सिविल सर्विस दरजे के अपसर ही बैंक का मन्त्री, सेक्रेटरी तथा कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। इसके बदले बैंको को कुछ रिभायर्तें मिलती थी, जिसमें सरकारी अधिकोपीय व्यापार का एकाधिकार सर्वप्रमुख था। उस समय बैंक के पास नोट छापने का अधिकार तो था, पर इस पर भी कुछ नियन्त्रण थे, जैसे दर्शनी उत्तरदायित्व नकद कोष का तीन गुना—और बाद में चौगुना से अधिक नहीं होना चाहिए। इन प्रतिबन्धों की वजह से व्यवहार में इस अधिकार का मूल्य नहीं के बराबर था। १८३६ के बाद तो नोट छापे जा सकने की कुल मात्रा तक निश्चित कर दी गई। जैसा हम देख ही चुके हैं, १८६२ में सरकार ने नोट छापने का अधिकार भी छीन लिया और स्वयं अपनी पत्र-मुद्रा का निर्गमन किया। बैंक की क्षति-पूर्ति स्वरूप सरकारी नकद प्रेसीडेन्सी नगरों के प्रेसीडेन्सी बैंको में रखे गए।

भारत सरकार ने १८७६ के प्रेसीडेन्सी एक्ट के अनुसार अपने हिस्से की पूंजी वापस ले ली तथा डाइरेक्टर, मन्त्री और कोषाध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार भी त्याग दिया। इसके बाद प्रेसीडेन्सी बैंको का सरकारी स्वरूप न रहने पर भी अन्य बैंको से उनकी भिन्नता इस अर्थ में थी कि वे १८७६ के विशेष अधिकोप-अधिनिषेध द्वारा शासित थे तथा जनता और सरकार दोनों ही उन्हें इस देश की पद्धति का प्रधान अंग तथा सरकारी खजानों का अनिवार्य अंग मानती थी।

७ सुरक्षित कोष पद्धति—१८६३ से सन् १८७६ ई० तक मुख्यावासों (हेड क्वार्टर्स) की सारी सरकारी रकम प्रेसीडेन्सी बैंको में ही रखी जाती थी, लेकिन बंगाल तथा बम्बई के बैंको से इन निधिओं की वापसी में कठिनाई अनुभव होने के कारण भारत सरकार ने १८७६ में बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में निजी सुरक्षार्थ खजानों की स्थापना की। तदनन्तर सरकारी रकम विशेषतया इन्हीं तीन सुरक्षित खजानों में रखी जाती थी। जिला और ताल्लुका के खजानों में तो थोड़ी रकम सुरक्षा तथा दैनिक आवश्यकता के लिए रहती थी। १८७६ में प्रारम्भ होने वाली नई व्यवस्था के अनुसार सरकार इस बात से सहमत हो गई कि अगर वास्तविक निक्षेप निश्चित निम्नतम निक्षेप से कम पड़े तो वह अन्तर-निधि पर बैंको को सूद देगी। वास्तविकता

तो यह भी कि बैंको में निम्नतम से भी अधिक रकम रहती थी, लेकिन वे तो इतने से ही सन्तुष्ट नहीं थे। राजस्व का एक बड़ा भाग सरकारी खाते में ऐसे समय में पड़ा रहता था, जबकि द्रव्य-बाजार में उसकी अत्यन्त आवश्यकता थी। हमारे देश में साधारणतया नवम्बर से जून तक कारोबार का मौसम तथा जुलाई से अक्तूबर तक सिधिल मौसम होता है। केवल कलकत्ता में कारोबार का मौसम जुलाई से अक्तूबर तक का होता है। जनवरी से अप्रैल तक के ही चार महीनों में लगान की वसूली होने के कारण लगान का मौसम तथा व्यस्त कारोवारी मौसम एव ही साथ पड़ते हैं। सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में कार्यशील रकम रखनी होती थी, क्योंकि मालगुजारी की प्राप्ति वारहों मास तो एक समान होती नहीं, पर उसे लगान वसूल करने का व्यय तो मालभर समान रूप से करना पड़ता है। इन सब परिस्थितियों से इस बात की सम्भावना समझी गई कि कारोबार के मौसम में सरकार अपनी वित्तीय स्थिति को क्षति पहुँचाए बिना ही द्रव्य बाजार की अधिकाधिक सहायता कर सकती है।

८ प्रेसिडेन्सी बैंक के कारोबार तथा विकास—प्रेसिडेन्सी बैंको को (१) विदेशी विनिमय-सम्बन्धी कार्य करने और (२) दूसरे पत्रों से द्रव्य उधार लेने से मना कर दिया गया तथा (३) ऋण देने के लिए ऋण की मात्रा, ऋण-काल, ऋण के बन्धक-पत्रों सम्बन्धी कुछ प्रतिबन्ध लगा दिए गए।

इन सब प्रतिबन्धों तथा विघ्नों के होते हुए भी प्रेसिडेन्सी बैंको की अनवरत समृद्धि रुकी नहीं। जिस तेजी के साथ उनका विकास हो रहा था उसमें इन प्रतिबन्धों ने प्रभाव तो अवश्य ही डाला, पर दूसरी ओर इन्हीं सबके कारण उन बैंको की स्थिरता तथा शक्ति में वृद्धि भी हुई—विशेषण १९१४-१८ के युद्ध के पूर्वकाल में इन बैंको में निजी निक्षेपों की मात्रा में सतत वृद्धि हुई। भारतवर्ष के मिश्रित-पूँजी वाले बैंको से भिन्न प्रेसिडेन्सी बैंक अपने उत्तमदायित्व के ३० प्रतिशत से भी अधिक रक्षित नकद रखकर अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाये हुए थे। इन बैंको में सरकार हर समय कुछ-न-कुछ रकम रखती थी, जो प्रायः निश्चित निम्नतम सीमा से अधिक ही हुमा करती थी तथा जहाँ-जहाँ भी इन बैंको की शाखाएँ होती वहाँ वे कुछ सामान्य सरकारी कारोबार कर दिया करते थे, जिसके बदले उन्हें निश्चित पारिश्रमिक की प्राप्ति हो जाती थी। इसके अनिश्चित करेन्सी नोटों को प्रचलित करन का उद्देश्य से ये बैंक अपनी शाखाओं में नोटों को मुनाने में भुगतान का सुभीता भी प्रदान करते थे। सरकारी सहयोग प्राप्त बैंको के असोसियेशन ने लाभदायक शर्तों पर निजी निक्षेप तथा बैंकिंग कारोबार को आकर्षित कर बैंको की प्रतिष्ठा में चार चाँद लगा दिए और देश की अधिकोप-पद्धति में इन बैंको को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया।

९ विनिमय बैंक (विदेशी बैंक)—अगर हम उल्लेख कर ही चुके हैं कि प्रेसिडेन्सी बैंको को विदेशी विनिमय-सम्बन्धी कार्य करने तथा विदेश में पूँजी इकट्ठा करने की मनाही थी, लेकिन इस देश के विदेशी व्यापार की वृद्धि के साथ इन दोनों कार्यों का

महत्त्व बढ़ता ही गया। अतः अब एक ऐसी श्रेणी के बैंक के लिए काफी क्षेत्र उपलब्ध हो गया जो विशेषतया विदेशी विनिमय-सम्बन्धी कार्य करे।

१९१४ के पूर्व केवल इण्डियन स्पेशी बैंक ही प्रमुख भारतीय मिथित पूंजी वाला बैंक था, जिसकी विनिमय बैंको की भाँति लन्दन में एक शाखा थी जिसको खोलने का उद्देश्य विदेशों में बैंक के चाँदी तथा मोती के कारोबार में सहायता प्रदान करना था। अपने जीवन के कुछ प्रारम्भिक वर्षों में भारत के किसी भी विनिमय बैंक ने विनिमय का जितना कारोबार किया उससे कम एलायेन्स बैंक ऑफ़ शिमला (१९२३ में जिसका दिवाला निकल गया), टाटा इण्डस्ट्रियल बैंक (सेण्ट्रल बैंक ऑफ़ इण्डिया के साथ इसका एकीकरण १९२३ में हुआ) ने नहीं किया। आज भी कुछ मिश्रित पूंजी वाले बैंक इस कारोबार में हाथ बँटाते तो हैं, पर अभी वे इस क्षेत्र में विशेष विकास नहीं कर पाए हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश के विदेशी विनिमय के व्यवसाय पर विदेशी बैंको का ही एकाधिकार रहा है। विदेशी केन्द्रों में शाखाओं को स्थापित करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रमुख कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है—(१) इतनी अधिक पूंजी नहीं है कि इन केन्द्रों के द्रव्य-वाञ्छार में साख बनी रहे, (२) जब तक विदेश स्थित ये शाखाएँ आत्मनिर्भर नहीं हो जातीं, तब तक इनके संचालन में घाटा उठाना पड़ता है, (३) अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय कार्य की शिक्षा पाये हुए ऐसे कर्मचारियों की कमी, जिन पर निर्भर रहा जा सके, (४) विदेशी बैंको का वैर-भाव, तथा (५) भारतीय बैंको के प्रधान कार्यालयों के भारतवर्ष में ही रहने की वजह से वे अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य की स्थिति के निकट सम्पर्क में नहीं रहते तथा आयात निर्यात की हुण्डी (इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट बिल) एवं वसूली के लिए विनिमय-पत्रों का व्यापार प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। १९३६ में बार्कलेज बैंक, लन्दन के साथ इसका एकीकरण हो गया।

लेकिन बाद में इस देश का सम्पर्क अन्य राष्ट्रों के साथ बढ़ा, जिसके परिणाम-स्वरूप अन्य देशों के प्रमुख बैंको की शाखाएँ भी यहाँ खुलने लगीं। भारतवर्ष के व्यपार में होने वाले विघ्न तथा कुछ विदेशों के, जिनका पहले भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अति छोटा स्थान था, महत्त्वपूर्ण आधिपत्य के कारण विदेशी बैंको को इस देश में अपनी शाखाएँ खोलने का प्रोत्साहन मिला। अतः भारत स्थित विनिमय बैंक अधिकांश लन्दन-स्थित बैंको की शाखाएँ हैं। अब यूरोपीय देशों, सुदूरपूर्व तथा अमरीका की बैंको की शाखाओं की संख्या भी बढ़ रही है। विनिमय बैंको का वर्गीकरण हम यों कर सकते हैं—(१) जो भारत में अत्यधिक कारोबार करते हैं, और (२) जो सारे एशिया में कारोबार करने वाले बैंको की एजेन्सी मात्र हैं।

१०. विनिमय बैंकों के कारोबार तथा उनकी वर्तमान स्थिति—प्रारम्भ में विनिमय

बैंको का कार्य केवल देश के बाह्य व्यापार की वित्तीय व्यवस्था करने तक ही सीमित था, पर इधर हाल में उनमें से अर्थविकास ने देश में, जहाँ-जहाँ इनकी शाखाएँ हैं, वहाँ के अन्तरिक व्यापार का वित्तीय योग देना काफी प्रारम्भ कर दिया है। विनिमय-बैंकों की अधिकांश टुण्डियाँ भारतीय नियंत्रणों की नियमित-टुण्डियाँ हैं, जो लन्दन के उन बैंकों या साख गृहों के नाम होनी हैं जिनसे नियंत्रण को साख-सुविधा प्राप्त होनी है। ये नियमित टुण्डियाँ अधिकतर त्रैमासिक तथा स्वीकार करने पर दी जाने वाली डी० ए० होती हैं, यद्यपि कुछ मूल्य-प्राप्ति पर दी जाने वाली (डी० पी०) भी होती हैं। लन्दन में विनिमय बैंक डी० पी० टुण्डियों को अपने पास तब तक रखते हैं जब तक ये लौटा नहीं ली जाती या इनकी अवधि पूरी होने पर ये चुकता नहीं हो जाती। डी० ए० बिल का बट्टा (या पुनर्बट्टा) प्रायः स्वीडिशि के तुरन्त ही बाद में ही जाना है। इंग्लैण्ड में इनका पुनर्बट्टा इंग्लैण्ड तथा स्कॉटलैण्ड की मिश्रित पूँजी वाले बैंको या बैंक ऑफ इंग्लैण्ड द्वारा होता है। इस प्रकार विनिमय बैंकों द्वारा भारतवर्ष में दिये रुपये के बराबर इंग्लैण्ड में पाँड मिल जाते हैं। व्यापार मन्दा होने या भारतवर्ष में कोष की तात्कालिक माँग न होने की हालत में कभी कभी वे टुण्डियों को अवधि पूरी होने तक रोक भी लेते हैं।^१ इस प्रकार भारतवर्ष के नियंत्रण व्यापार की वित्तीय व्यवस्था मुख्यतः ब्रिटिश बैंको की पूँजी से ही होनी है। लन्दन के द्रव्य बाजार में टुण्डियों का पुनर्बट्टा कराने की सुविधा—भारत की अपेक्षा वहाँ बट्टा दर भी कम होती है—विशेष लाभदायक है, क्योंकि विनिमय बैंक जितनी निधि की टुण्डियों को अवधि पूरी होने तक अपने पास रख सकते हैं उतसे अधिक निधि की टुण्डियाँ खरीद लेते हैं।

विनिमय बैंको द्वारा भारत की नियंत्रण-टुण्डियों खरीदने का अर्थ है अपने कार्य को लन्दन भेजना। जब तक कौन्सिल बिल तथा टेलीग्राफिक ट्रान्सफर खरीदने की पद्धति थी, तब तक विनिमय बैंक अग्न कापो की भारत वापसी के लिए खुलकर इन दोनों का न्य लन्दन में करते रहे। अब वे अपनी निधि को लन्दन भेजने के लिए अपनी स्थिति की विक्री रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के हाथ करते हैं। भारत में अपने कोष की वृद्धि करने के उनके कुछ अन्य तरीके भी हैं, जैसे आयात की टुण्डियों के पक जाने पर उसे भुना लेना विदेश स्थित भारतीय छात्रों, मुसाफिरो तथा अन्य भारत से रकम भेजने वाले व्यक्तियों को ड्राफ्ट बेचकर तथा टेलीग्राफिक ट्रान्सफर करके तथा लन्दन में खरीदे गए भारतीय ऋणपत्रों को भारत में बेचकर, इत्यादि। अप्रैल १९३५ में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना के पश्चात् इस बैंक से व लन्दन में भुगतान के लिए स्टैबिल ड्राफ्ट खरीद सकते हैं।^२

भारतीय आयात व्यापार की वित्तीय व्यवस्था या तो भारतीय आयातकों पर किये गए साठ दिनों की दरौनी टुण्डियों द्वारा या लन्दन बैंक की स्वीडिशि 'हाउस

१ भारतवर्ष तथा यूरोप, मयुक्तराज्य अफ्रीका तथा अरबिदेशों के बीच स्थिति में ही टुण्डियों की जाती हैं। भारत और जपान के बीच येन में तथा भारत और चीन के बीच टुण्डियाँ रुपये में की जाती हैं।

२ हाल में की गई विनिमय नियन्त्रण की सुविधा, ६वें परिशिष्ट के २६वें पैरा में देखिए।

पैपर' हुण्डी द्वारा की जाती है। भारतीयों द्वारा किये गए आयात के लिए प्रायः पहले तरीके का उपयोग होता है। स्टर्लिंग में लिखे ऐसे ड्राफ्ट को लन्दन-स्थित विनिमय बैंक भुगतान करते हैं और फिर अपनी भारत-स्थित शाखाओं के पास वसूली के लिए भेज देते हैं जो इन्हे स्वीकृति तथा भुगतान के लिए आयातकों के सामने पेश करते हैं। आयात करने वाले बिना पूरा भुगतान किए ही वस्तुओं को दो तरीकों से प्राप्त कर लेते हैं—(१) विनिमय बैंक की ओर से ट्रस्ट रसीद पेश करके आयातक वस्तुओं को प्राप्त करना तथा चीजों की अन्तिम चुकती होने के पूर्व उन्हें अपने पास धरोहर स्वरूप रखकर। दूसरा उपाय यूरोप के उन आयातकर्ताओं को प्राप्य है, जिनके लन्दन में पुराने बैंक हैं। ये अपनी लन्दन-स्थित धंको के नाम हुण्डियाँ लिखते हैं जो उन बैंकों द्वारा स्वीकृत होने पर लन्दन में ही बट्टे पर भुनाई जा सकती हैं। उनका बट्टा करने वाले बैंक सम्बन्धित पत्रों की अपनी भारत-स्थित शाखाओं को भेज देते हैं। शाखाएँ हुण्डियों की अग्रधि पूरी होने के पहले रकम वसूल करने लन्दन भेज देती है। विनिमय बैंक के विदेश-स्थित कार्यालय तथा शाखाएँ भारतवर्ष के आयात व्यापार की वित्तीय व्यवस्था करने में प्रमुख भाग लेती हैं। भारतीय शाखाओं का तो साधारणतया यही कार्य होता है कि वे आयात की हुण्डी की अग्रधि पूरी हो जाने पर उसकी वसूली करें तथा हुण्डी भुगतान करने वालों की शक्ति तथा स्थिति-सम्बन्धी सूचना अपनी शाखाओं को दे। निर्यात की हुण्डियों के विपरीत आयात की हुण्डियों का भारतवर्ष में पुनर्वट्टा न होने के कारण विनिमय बैंक निर्यात-व्यापार की अपेक्षा आयात व्यापार को ही अधिक वित्तीय सहायता देते हैं। अगर आयात की हुण्डी के बट्टा बाजार को हम विकसित करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि इन्हे रुपये में ही किया जाए तथा ये स्वीकृति पर देय हो। इन सुधारों द्वारा भारत के आयातकर्ताओं की यथार्थ शिकायतों को दूर करने में भी सहायता मिलेगी।

सन् १९५७ में भारत में विनिमय बैंकों—विदेशी बैंकों की संख्या १७ थी। इस वर्ष निक्षेप की राशि २०४१४ करोड़ रु० थी जबकि १९५६ में यह १८७५४ करोड़ रु० थी। फरवरी, १९६६ में भारत में विनिमय बैंकों की संख्या १५ थी और इनका कुल निक्षेप ३५२८६ करोड़ रुपये था।

११. विदेशी बैंकों पर प्रतिबन्ध—अब हम विनिमय बैंकों के दोष और उन्हें दूर करने के लिए प्रस्तावित प्रतिबन्धों की चर्चा करेंगे। अनुमान है कि इस देश के विदेशी व्यापार में भारतीयों का हिस्सा केवल १५ से २० प्रतिशत है।^१ अतः कमीशन, दलाली तथा बीमा के रूप में गैर भारतीयों को बहुत-सी रकम देकर हमें काफी घाटा उठाना पड़ता है। लोगों की यह धारणा है कि भारत के विदेशी व्यापार में विदेशी मस्याओं की अधिकता इसलिए है कि ये विदेशी विनिमय बैंक भारत के साथ व्यापार करने वाले अपने देशवासियों को बहुत सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, इन बैंकों को विदेशी व्यापार की वित्तीय व्यवस्था

१. विमल सा० घोष द्वारा लिखित 'द स्ट्रॉन्ग ऑफ़ दि इन्डियन मनी मार्केट', पृ० ८७।

करने का एकाधिकार है और यह कहा जाता है कि भारतीय व्यापारियों की हानि करने के लिए वे इस अधिकार का दुरुपयोग करते हैं।^१

केन्द्रीय अधिकोप समिति स कुछ गवाहों ने विनियम बैंकों के कार्यों के सम्बन्ध में कानून बनाने की प्रार्थना की, क्योंकि उन पर किसी प्रकार का भारतीय कानूनी प्रतिबन्ध नहीं था, यहाँ तक कि वे भारत में रजिस्टर्ड मिश्रित पूंजी वाले बैंकों पर लगाये गए अल्पसंख्यक कानूनी प्रतिबन्धों से भी मुक्त थे। यह भी कहा गया है कि यद्यपि वे भारत में ही निक्षेप इकट्ठा करते हैं, फिर भी भारतीय निक्षेपकों को किसी प्रकार का सरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। अन्ततोगत्वा राष्ट्रीय दृष्टिकोणों से भी जापान तथा अन्य देशों के ही समान विनियम बैंकों की भारत विरोधी नीति के शोषकस्वरूप तथा भारतीय व्यापारियों को कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी उनके नियन्त्रण का समर्थन किया गया (कि० अ० रि०, ४७७)।

अगर कोई विदेशी बैंक भारत में महाजनी का कारोबार करना चाहना हो तो उसे लाइसेंस की निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए—

(१) रिजर्व बैंक के आदेशानुसार वे अपने भारतीय कारोबार-सम्बन्धी आदेश तथा दायित्व का वार्षिक विवरण रिजर्व बैंक को दें।

(२) कम से-कम कुछ वर्ष तक वे अपने भारतीय तथा अन्तर्देशीय कारोबार का विवरण समय-समय पर रिजर्व बैंक को दें।

(३) वार्षिकिकता के आधार पर अन्य शर्तों की रची जा सकती है। अनेक देशों ने अपने यहाँ कार्यशील अन्य राष्ट्रीय बैंकों पर कानूनी प्रतिबन्ध लगा दिया है। भारत सरकार भी भारतवर्ष में अधिकार-पत्र-प्राप्त विदेशी बैंकों पर इन्हीं शर्तों को लगाने की अपनी शक्ति का उपयोग करे। इस प्रकार भारत सरकार विदेशी बैंकों के साथ परस्परानुवर्ती व्यवहार कर सकती है (कि० अ० रि०, ४५१)।

१२ भारतीय विनियम बैंक का श्रीगणेश—विदेशी बैंकों पर लगाय गए इन तरह के प्रतिबन्ध हमारी वर्तमान स्थिति में कितना ही सुधार ला दें, पर वे हमारी कम-जोरी के मूल कारण को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि भारतवासी आयात और निर्यात व्यापार तथा ऐसे व्यापार की बैंक-सम्बन्धी सुविधा के निर्देश में बहुत ही कम हिस्सा

१. केन्द्रीय अधिकोप खोज समिति के सनच अनेक व्यावसायिक सुरक्षाओं ने कहा था कि विनियम बैंक विदेशी निर्यातकों को भारतीय व्यावसायिकों के बैंकों के सम्बन्ध में असन्तोषजनक सन्तन देते हैं, भारतीय व्यापारियों को स्वीकृत होने पर देय डाफ्ट की सुविधा प्राप्त नहीं हाता; स्वीकृत साख वल्लेख-पत्र की प्राप्ति के लिए भारत के आयातकर्ताओं को बल्लुओं की कीमत का १० से १५ प्रतिशत तक विदेशी बैंकों में जमा करना पड़ता है (नविक विदेशी आयात पर यह शर्त लागू नहीं है), आयात-हुएटी स्टॉकिंग मुद्रा में की जाती तथा इस पर ब्याज-दर ऊँची (६%) हानी है भारत के बैंकों तथा बीना कम्पनियों के साथ विनियम बैंकों का व्यवहार प्रतिवृत्त होता है, उनमें भारतीयों की नियुक्ति जिम्मेदार पद पर नहीं की जाती, शर्थादि। देखिए कि० अ० रि० ४३६-४५। रिपोर्ट में भारत सरकार को यह सुझाव दिया गया कि वह इन शिकायतों को दूर करने के लिए विनियम बैंकों के साथ उपयुक्त परिणामी का सृजन करे।

लेते हैं। केन्द्रीय अधिकोप खोज समिति न निम्नलिखित युक्तियाँ बताईं जिनके द्वारा भारतवर्ष बैंकिंग तथा व्यापार में उचित स्थान प्राप्त कर सकता है (के० अ० रि०, ४८१)—(१) सुस्थापित मिश्रित पूँजी वाले बैंको को इस प्रकार का विदेशी सम्पर्क करना चाहिए जो उनके ग्राहको के लिए लाभदायक हो। (२) रिजर्व बैंक की स्थापना के साथ-ही-साथ इम्पीरियल बैंक पर विदेशी विनिमय कार्य-सम्बन्धी प्रतिबन्धों को हटाने के पश्चात् इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया को भारत के विदेशी व्यापार में सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। (३) अप्रैल १९३५ को रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया के विदेशी विनिमय कार्य सम्बन्धी पुराने प्रतिबन्धों को हटा दिया गया है तथा इम्पीरियल बैंक की नियुक्ति रिजर्व बैंक के एकाकी एजेंट-रूप में भी हुई है। (४) समिति ने यह भी सिफारिश की कि अगर इम्पीरियल बैंक भारत के विदेशी व्यापार की वित्तीय व्यवस्था ठीक तरह से नहीं कर पाता तो एक भारतीय विनिमय बैंक की स्थापना की जाए (के० अ० रि० ४८५)। इस बैंक की ३ करोड़ रुपये की ऐसी पूँजी होनी चाहिए जिसे भारत में रजिस्टर्ड मिश्रित पूँजी वाले बैंक पहली किस्त में ही खरीद लें। अगर सम्पूर्ण हिस्सा-पूँजी की बिक्री निश्चित समय के भीतर नहीं हो जाती तो सरकार बाकी रकम की पूर्ति करके उसे जनसाधारण के हाथ बेच दे। जब तक ५० प्रतिशत से अधिक पूँजी सरकार की हो, तब तक सचालकों की नियुक्ति में उसका विशेष हाथ होता चाहिए। सरकार के प्रेषण-सम्बन्धी कार्यों को रिजर्व बैंक द्वारा नियन्त्रित किसी नए बैंक को सौंपने के प्रश्न पर इस शर्त पर रिजर्व बैंक के साथ विचार करना चाहिए कि उस नये बैंक को यह स्वीकृति न दी जाएगी कि वह एजेण्ट की हैसियत से खुले बाजार में इस प्रेरणा का उपयोग मुनाफा कमाने के लिए करे। (५) ऐसे बैंको की स्थापना की जानी चाहिए जिन पर भारतीय तथा विदेशी सम्मिलित नियन्त्रण बराबरी के हिस्सेदार की हैसियत से हो।

इस समय विदेशी बैंको का नियन्त्रण करने की दृष्टि से बैंकिंग कम्पनी अधिनियम १९४६ में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है—

(क) प्रत्येक विदेशी बैंक के पास त्रैमासिक के अन्त पर उसके भारतीय दायित्व (माँग और सावधि) के ७५% के आदेय भारत में होने चाहिए।

(ख) बम्बई और कलकत्ता में स्थित विदेशी बैंको की पूँजी तथा रिजर्व कम से-कम २० लाख रुपये तथा अन्य स्थानों में स्थित होने पर १५ लाख रु० होना चाहिए। ये विधियाँ भारतीय बैंको के लिए निर्धारित सीमाओं से अधिक हैं।

(ग) विदेशी बैंक का दिवाला निकलने पर भारतीय निक्षेपको और ऋण-दाताओं का उनके भारत-स्थित आदेय पर प्राथमिक अधिकार होगा।

१. समिति के ३ सदस्यों की (जिनमें सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास भी थे) विमति निष्पत्ती में इस कृत की जोरदार सिफारिश की गई थी कि राज्य द्वारा अपनी ही ३ करोड़ रुपये की पूँजी के साथ शोधातिशील विनिमय बैंक की स्थापना की जाए।

(घ) प्रत्येक वर्ष विदेशी बैंक अपने भारतीय कारोबार का हानि-लाभ विवरण तथा स्थिति-विवरण तैयार करके प्रकाशित करेंगे ।

१३ मिथित पूंजी के बैंकों का इतिहास—भारतवर्ष के बढ़ते हुए व्यापार के कारण आधुनिक और सुव्यवस्थित श्रेणी के बैंकों की आवश्यकता थी । पर इस आवश्यकता की पूर्ति न तो प्रेसीडेन्सी बैंक ही कर सकते थे जो अनेक प्रतिबन्धों से मुक्त अर्ध-सार्व-जनिक सस्या थे तथा कुछ ही बड़े शहरों में जिनकी शाखाएँ थीं और न विनिमय बैंक ही, जिन पर विदेशी व्यापार की पूंजी ने पहले से ही अपना अधिकार जमा रखा था । व्यवस्थित बैंकिंग की प्रगति १८६० तक, जबकि इस देश में पहले-पहल सीमित दायित्व का सिद्धान्त अपनाया गया, बहुत ही धीमी रही । इस यथेष्ट प्रगति के रुके रहने के कारण थे, रुई की तेजी द्वारा लाया हुआ १८६५ का वित्तीय सकट तथा रुपये के विनिमय मूल्य का गिर जाना । इस श्रेणी का सर्वप्रथम बैंक था बैंक ऑफ़ अफ़र इण्डिया (१८६३), जिसका अनुसरण इलाहाबाद बैंक (१८६५) तथा कुछ अन्य बैंकों ने भी किया, जिनमें एलाएस् बैंक ऑफ़ शिमला भी (१८७४), जिसका दिवाला १९२३ में निकल गया, एक था । १८७० में इस प्रकार के सात बैंक थे । १८९४ में यह सस्या १४ हो गई । उस समय उनमें से अधिकांश यूरोपीय प्रबन्ध में थे तथा अब भी उनकी वही दशा है । अवध कमर्शियल बैंक पहला बैंक था जिसकी स्थापना १८८१ में केवल भारतीय साहसियों द्वारा की गई । १८९४ में लाला हरकिशन लाल के प्रयत्नों से पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई । १९०१ में पीपुल्स बैंक की स्थापना का श्रेय भी इन्हीं को था । पीपुल्स बैंक की प्रगति बहुत ही अच्छी रही । १९१३ में इसका दिवाला निकलने के समय इसके पास १०० शाखाएँ तथा १३ करोड़ रुपये से अधिक निक्षेप थे ।^१

१४ बैंकों का दिवाला^१—धारम्भ के कुछ दिनों तक तो इन बैंकों में अवश्य ही बड़ी प्रगति दिखाई, पर असल में बढ़ते-का कारोबार सट्टेबाजी से पूर्ण और अरक्षित था, तथा उनका नकद रिजर्व दायित्व की अपेक्षा इतना क्षीण था कि केन्स-जैसे विद्वान् के लिए उनके शीघ्र पतन की भविष्यवाणी करना कठिन बात नहीं थी । केन्स ने दुख के साथ अपनी इस भविष्यवाणी को सच होते भी देव लिया ।^१ १९१३-१४ के बीच लगभग ५५ बैंकों की प्रतिक्रिया हुई । १९१४-१८ के युद्ध के समय तथा बाद की

१. देखिए श्री० टी० एच० एल्वर द्वारा लिखित 'अर्ग्युमेंट्स टोवार्ड्स इन्डियन बैंकिंग', पृ० ३१-३२ ।

२. देखिए, श्री एस० के० मुरव्जन द्वारा लिखित 'मॉडर्न बैंकिंग इन इण्डिया' का ९वां परिच्छेद, निम्नमें कुछ बैंकों के विरोध उल्लेख के साथ भारतवर्ष के बैंकों के दिवाले का अति पठनीय और स्पष्ट विश्लेषण दिया गया है ।

३. केन्स ने भारतीय बैंकों के दिवाला निकलने के पूर्व १९१३ में लिखा था कि "दोटे-दोटे बैंकों का कारोबार ऐसे देश में है जहाँ अब भी सुबह की ही प्रथमता है तथा ऐसे लोगों के साथ है, जिनके लिए बैंकिंग एक नई चीज है एवं इन बैंकों की नकद रकम भी अति अपत्यान्त दिखाई पड़ती है । अब" इतमें सन्देह करने की कोश भी गुणाशर नहीं कि आगामी मन्दी के समय ये तहस-नहस हो जाएंगे !"

नेजी ने नये बैंको को सडा होने की और भी प्रेरणा प्रदान की, पर बाद की मन्दी ने अनेकों का दिवाला निकाल दिया। भारत के मिथित पूंजी वाले बैंको के लिए १९१३-२४ के बीच के वर्ष अति भयावह थे। इस अवधि में लगभग ६३ करोड़ रुपये के प्राप्त हिस्सा-पूंजी वाले करीब १६१ बैंको का दिवाला निकला। पुद्दोत्तर-वालीन दिवालो में १९२३ में हुए बैंक ऑफ शिमला का दिवाला प्रमुख है। इसका प्रभाव सुदूर व्यापी तथा अति दुःखदायी था।

१५. बैंको का दिवाला निकलने के कारण—बैंको के दिवाले के, विशेषत १९१३-१४ में होने वाले दिवालो के, कारण निम्न प्रकार थे—(१) निक्षेप-दायित्वो के अनुपात में नकद का प्रतिशत कम अर्थात् औसतन १० से ११ प्रतिशत था, (२) प्राप्त हिस्सा-पूंजी की कमी की पूर्ति हेतु निक्षेप आकर्षित करने के लिए दी जाने वाली व्याज-दर अधिक थी, (३) स्वीकृत और विकी हुई हिस्सा पूंजी में तथा विकी हुई हिस्सा-पूंजी और प्राप्त हिस्सा-पूंजी के बीच उचित अनुपात का अभाव, (४) बैंकिंग कारोबार जानने वाले योग्य प्रबन्धको तथा निर्देशको का अभाव और सचालक-मण्डल द्वारा उचित निरीक्षण का न होना, (५) कुछ सचालको तथा प्रबन्धको का कपट व्यवहार, (६) भोले-भाले निक्षेपको का आँकड़ो की तडक-भडक तथा पूंजी में से भी बाँट लाभांश के कारण ठगा जाना, (७) ऐसे समतकारी उपायो का अभाव जिनकी पूर्ति केवल सरकारी या अर्द्ध-सरकारी सस्थाओ द्वारा हो सकती थी, तथा (८) आपस में बैंको के बीच सहयोग की परम्परा का अभाव।

जैसा कि श्री डोगस्वामी ने लिखा है भारतीय बैंको के दिवालापन के पप पर यूरोपियोनो द्वारा सचालित सस्थाओ के दिवाले भी पडे मिलते हैं।^१ इसकी पुष्टि वह प्रथम बैंक ऑफ बम्बई (१८६८), आर्बन्थनाट बैंक तथा एलाएन्स बैंक ऑफ शिमला की असफलताओ के दृष्टान्त द्वारा करते हैं। यद्यपि कुछ हद तक कपट-प्रबन्ध इन बैंको के दिवालापन का कारण अवश्य ही पाया गया, पर उनका प्रधान कारण तो अनुभव तथा ज्ञान की कमी ही थी। बैंको की इन असफलताओ ने यह सबक सिखाया कि बैंकिंग न तो सीधा कारोबार है, न केवल कपटपूर्ण ही तथा सक्ताति के खतरो को कम करने के लिए बैंक की व्यवस्था-प्रणाली के सुधार, कर्मचारियो का सावधानी से चुनाव और स्वस्थ बैंकिंग व्यवस्था का पालन करना अति आवश्यक है।

१९३८ के दक्षिण भारत के बैंकिंग सक्टाट ने अनुसूचित बैंको को रिजर्व बैंक के घनिष्ठ सम्पर्क में रहने की आवश्यकता का अनुभव करा दिया, ताकि इसके समक्ष वे अपनी स्थिति तथा व्यापार का स्पष्ट चित्रण रख सकें, जिससे सक्टाट के समय रिजर्व बैंक योग्य सस्थाओ को साख सहायता दे सकें।^२ इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि

१. 'यह बात ठीक वैसी ही है कि बिना बिना शिबित अन्तर को साथ लिये तथा अधिकारियो की आडा लिये ही सेना लवाई में चली जाए।'—शिवाउ लिपित इन्डियन फिनान्स एण्ड बैंकिंग, पृष्ठ ३३६।

२. देखिए, श्री एस० वी० डोगस्वामी द्वारा लिपित इन्डियन फिनान्स, करेन्सी एण्ड बैंकिंग, पृ० ३।

३. यह पहला बैंकिंग सक्टाट था जिनका मुआवला रिजर्व बैंक को करना पडा।

अनुसूचिन बैंको के पास पुनर्भुगतान योग्य पर्याप्त आदेय का न होना उन्हें पेशगी प्रदान करने की कठिनाइयों में से एक है। १९१३-१४ तथा बाद में होने वाले दिवालों में भी अधिकोपण सिद्धांत तथा व्यवहार-सम्बन्धी उचित शिक्षण की व्यवस्था की आवश्यकता को स्पष्ट कर दिया। विस्तीर्ण प्रचार का महत्त्व भी सुशिक्षित बैंक कर्मचारियों तथा बैंक-सम्बन्धी कानूनों से कम नहीं है। जनता इसके सहारे किसी भी समय बैंको की स्थिति का अनुमान आसानी से लगा लेती है। इसके अलावा यह भी आवश्यक है कि बैंक अपनी गौरवशाली परम्परा तथा जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी को बनाए रखे।

१६. पर्याप्त नकद कोष का महत्त्व—बैंको के प्राप्य पर्याप्त नकद का रहना स्वस्थ महाजनी की प्रारम्भिक आवश्यकता है, पर अनेक देशों में प्रायः देखा गया है कि इसके प्रति असह्यवानी के कारण काफी बरबादी उठान के बाद ही वे इस कल्पाणकारी सबक को सीखते हैं। ऐसा लगता है कि भारत के मिथिन पूँजी वाले बैंको ने दिवाले के रूप में काफी घुल्क चुकाकर कम-से-कम इस सबक को सीखा ही लिया है। इनका प्रमाण है हाल में उनके द्वारा की गई काफी सुरक्षित धन रखन की स्तुत्य आकांक्षा। इस विषय की महत्ता बम्बई अधिकोपण सौज समिति के उस मुझाव से स्पष्ट हो जाती है जिनमें इसने कहा था कि सयुक्तराज्य अमरीका के समान हमारे देश के बैंक को एजेन्सियाँ पर्याप्त नकद कोष रखने के लिए कानून द्वारा बाध्य की जानी चाहिए। पर केन्द्रीय अधिकोपण सौज समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। उन्हें इस बात का भय था कि कानून द्वारा निश्चित की गई निम्नतम सीमा को बैंक के प्रबन्धकता अधिकतम सीमा मानने लगेंगे तथा कानूनी पारन्द्वी से बचन के लिए अन्य उपायों का भी सहारा लिया जाएगा। समिति ने यह विषय बैंको की ही सदबुद्धि तथा विवेक पर छोड़ देना अच्छा समझा (कि० अ० रि०, ७०६)। लेकिन १९३६ में संशोधित कम्पनी एक्ट द्वारा निम्नतम नकद रखने का विधान कर दिया गया है (आगे देखिए, पैरा १६) तथा १९३६ में रिजर्व बैंक ने एक बैंक एक्ट के लिए जो प्रस्ताव रखा उसका प्रयोजन बैंको के साधनों की पर्याप्त तरलता की प्राप्ति करना ही है (आगे देखिए, पैरा २०)।

१७. बैंक सम्बन्धी नियमन—बार-बार होने वाली बैंको की उपयुक्त भयावह असफलताओं तथा स्वस्थ राष्ट्रीय आधार पर बैंको को विकसित करने के विचार से इनका साभिप्राय नियमन आवश्यक समझा गया। सरकार द्वारा परम्परागत निहस्त-क्षेप की नीति अपनाए जान के कारण इस सम्बन्ध में हमारे देश की स्थिति १९३६ तक असन्तोषजनक ही रही। दूसरी सम्मिलित पूँजी वाली कम्पनियों के ही समान १९३६ तक सम्मिलित पूँजी वाले बैंक भी इण्डियन कम्पनी एक्ट १९१३ द्वारा शासित थे। इस कानून के केवल थोड़े से परिच्छेद ही सम्मिलित पूँजी वाले बैंको से विशेष रूप में सम्बन्धित थे। इस पुराने कानून में बैंको के लिए बार्थिक बैलेन्स शीट को तैयार कराने तथा साल में दो बार व्यवस्था-विवरण-पत्र को प्रकाशित करने की रीति के सम्बन्ध में थोड़े नियमों का पालन करने के अलावा और था ही क्या।

१८. सशोधित इण्डियन कम्पनीज एक्ट (१९३६) में बैंकिंग कम्पनियों से सम्बद्ध विशेष विधान—पाँच वर्ष के विलम्ब के पश्चात् भारत सरकार ने अधिकोपो से सम्बद्ध विशेष विधानों को अपने इण्डियन कम्पनीज (एमेण्डेड) बिल में सम्मिलित करने का निश्चय किया। नये विधान निम्नलिखित हैं और इनका प्रारूप तैयार करते समय केन्द्रीय अधिकोप खोज समिति की सिफारिशों का ध्यान रखा गया।^१

(१) बैंकिंग कम्पनी वह है जो खपया उधार देने, हुण्डियों का बट्टा करने, विदेशी विनिमय की खरीद या बिक्री करने, साख-पत्रों की मजूरी देने, वेशकीमती वस्तुओं को सुरक्षण में रखने, पूँजी-हिस्से, ऋण-पत्र आदि का धोना करने तथा उनका लेन-देन करने, और प्रत्यासों को ग्रहण तथा उनका सम्पादन करने आदि कार्यों में से किसी एक या सभी को करने के अतिरिक्त चालू खाते पर या अन्य प्रकार से निक्षेप स्वीकार करने का, जिसकी वापसी चेक, हुण्डी या आर्डर द्वारा हो सकती है, अपना प्रमुख व्यवसाय करती है। (२) अधिकोप कम्पनी की रजिस्ट्री इस शर्त पर की जाएगी कि कम्पनी के विधान-पत्र में यह उल्लिखित हो कि कम्पनी केवल साधारण बैंक-सम्बन्धी कार्य करेगी। (३) भविष्य में बैंको के प्रबन्ध-हेतु प्रबन्ध अभिकर्ताओं की नियुक्ति निषिद्ध है। (४) हिस्सा-पूँजी के बँटवारे द्वारा ५०,००० रुपये की कार्य-शील पूँजी एकत्र हो जाने का प्रमाण-पत्र देने पर ही कम्पनी कार्य आरम्भ कर सकती है। इस प्रकार निम्नतम पूँजी का रखना अनिवार्य हो गया है। (५) किसी भी बैंकिंग कम्पनी को यह अनुमति नहीं है कि वह अपनी अदन पूँजी पर किसी प्रकार का दायित्व लादे। (६) किसी भी प्रकार के वार्षिक लाभांश वितरण की घोषणा करने के पूर्व लाभ का कम-से-कम २० प्रतिशत सुरक्षित कोप में जमा करना अनिवार्य है, जब तक यह कोप चुकाई हुई पूँजी के बराबर न हो जाए। इस प्रकार एक सुरक्षित रकम का होना अनिवार्य कर दिया गया है। अवधि-दायित्व (टाइम लाइबिलिटीज) का १३ प्रतिशत तथा माँग-दायित्व (डिमाण्ड लाइबिलिटीज) का ५ प्रतिशत का एक नकद निम्नतम नकद कोप रखना आवश्यक है तथा अनुमचित बैंको को छोड़कर अन्य बैंकिंग कम्पनियों द्वारा इस प्रकार की रकम तथा दोनों प्रकार के दायित्वों का विवरण रजिस्ट्रार के यहाँ दाखिल करना आवश्यक है। (७) किसी बैंकिंग कम्पनी को यह इजाजत नहीं कि वह एक ऐसी कम्पनी के अतिरिक्त, जिसका निर्माण स्वयं उसी ने, प्रत्यास को ग्रहण करने एवं उनका सम्पादन करने या जायदाद के प्रबन्ध आदि को लेने आदि उद्देश्यों से, ओ निक्षेप को स्वीकार करने से सम्बद्ध नहीं है, किया है, किसी अन्य सहायक कम्पनी से हिस्सा निर्मित करे या उत्पन्न करे। (८) बैंकिंग कम्पनियों को अल्पकालीन कठिनाइयों के कारण दिवालापन से बचाने के लिए अदालत को यह अधिकार दिया गया कि बैंकिंग कम्पनियों के दरखास्त करने पर, वस्तुतः कि दरखास्त के साथ रजिस्ट्रार का विवरण भी हो, वह इन कम्पनियों के

१. देखिए १९३६ का एक्ट (जो कुछ विशेष अभिप्राय से भारतीय कम्पनी एक्ट १९१३ में सशोधन हेतु बना) भाग १० प, धारा २७७ एफ से २७७ एन तक।

बिलाफ की जाने वाली कार्यवाही को रोक सके। रजिस्ट्रार को यह अधिकार है कि इस हेतु वह कम्पनी के ही खर्च पर उसकी वित्तीय व्यवस्था की जाँच कर सके।

१६ बैंकिंग के नियमन-हेतु हाल में की गई वैधानिक व्यवस्थाएँ^१—नवम्बर, १९२६ में रिजर्व बैंक ने सरकार के सामने जिन थोड़े-से प्रस्तावों को रखा वे इस सामान्य सिद्धान्त पर आधारित थे कि निक्षेपकों के हित की रक्षा करके देश में जनता के मध्य अधिकोप-प्रणाली का प्रचलन बढ़ाना ही सर्वप्रधान उद्देश्य होना चाहिए। वे सुसंचालित तथा श्रायिक दृष्टि से सुदृढ़ अधिकोपों का जाल फैलाना चाहते थे, जिससे रिजर्व बैंक को देश के साख-मगठन का समन्वय करने तथा रिजर्व बैंक ऐक्ट द्वारा निर्दिष्ट साख-विस्तार की शक्ति का उचित उपयोग करने में समर्थ बना सके।

११ अप्रैल, १९४५ को असेम्बली ने रिजर्व बैंक के प्रस्ताव के आधार पर नया कानून बनाया। इस कानून (बैंकिंग कम्पनी बिल १९४५) को अपनी कार्य-सूची में रख लिया, पर असेम्बली के भंग हो जाने से यह विधेय गिर गया। १५ मार्च १९४६ को इसे पुनर्निर्वाहिन असेम्बली के सामने पुनः रखा गया। जनमत को दृष्टि में रखते हुए इस बिल में कुछ संशोधन इस उद्देश्य से कर दिया गया कि बैंकों के ऊपर रिजर्व बैंक का अधिक नियन्त्रण रह सके।

जिन समय व्यवस्थापिका सभा में इस बिल पर विचार हो रहा था, उसी समय केन्द्रीय सरकार ने १५ जनवरी, १९४६ को एक अध्यादेश जारी करके [बैंकिंग कम्पनी बिल (इन्सपेक्शन) आर्डिनेंस १९४६] सरकार को यह अधिकार प्रदान किया कि रिजर्व बैंक के निरीक्षण के विवरण के अवलोकन के पश्चात् अगर सरकार यह समझती है कि किसी बैंकिंग कम्पनी की कार्यवाहियाँ उसके निक्षेपकों के हित के विरुद्ध हैं तो वह उसे सुधारने का उपाय कर सकती है। जहाँ भी आवश्यकता पड़े सरकार तत्काल बैंकिंग कम्पनी को नया निक्षेप लेने से निषेध कर सकती, उसे अनुसूचित बैंकों की सूची में लेने से इनकार कर सकती या अगर वह पहले से ही इस सूची में ही तो उसे निकाल भी सकती है। बैंकिंग कम्पनी बिल पर विचार-काल में शाखाओं के अनियोजित विस्तार को नियन्त्रित करने तथा शाखाओं के साधनों की अपेक्षा उन पर अधिक खर्च करने एवं अप्रतिष्ठित (अनट्रेड) कर्तृ-वर्ग को रखने आदि अवाञ्छित विकास को रोकने के उद्देश्य से बैंकिंग कम्पनी ऐक्ट (शाखाओं पर प्रतिबन्ध) १९४६ को पास किया गया जो २२ नवम्बर, १९४६ से लागू हो गया।

द्वि बैंकिंग कम्पनी बिल (क्यूटो) आर्डिनेंस, १९४८ में बैंकिंग कम्पनी बिल की कुछ धाराओं को सुरक्षित ही इस उद्देश्य से कार्यान्वित किया गया कि वह बैंकिंग पद्धति को ठीक तरह से नियमित करने में रिजर्व बैंक की सहायता कर सके। इसके

१. रिपोर्ट आन क्लॉक एण्ड टाइम्स, १९४८-४९ का अनु-वेद ६५ दखिए।
 २. अनुसूचित बैंकों के १९४६ में अधिनियम नं. ७६, अगस्त से जून तक ७३ तथा जुलाई से सितम्बर, १९४६ में तक १४० शाखाएँ खोलीं।

अन्तर्गत रिजर्व बैंक को यह अधिकार मिला कि वह अपनी समझ के अनुसार पर्याप्त जमानत पर आवश्यक पेशगी दे और बैंको की उधार देने की नीति तथा उनके कारोबार की जांच कर सके। अधिनियम के अन्तर्गत यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक बैंक त्रैमासिक अवधि के अन्त में इस देश के अपने प्रवधि तथा मांग-दायित्व का कम-से-कम ७५% आदेय को भारत में रखे। रिजर्व बैंक की सहमति से ही बैंको के बीच एकीकरण प्रबन्ध की योजना तथा समझौते का होना सम्भव था।

अधिकोपीय अधिनियम, १९४६—अन्ततोगत्वा भारतीय ससद ने १७ फरवरी १९४६ क अधिकोप अधिनियम को पारित कर दिया तथा १६ मार्च, १९४६ से इस लागू कर दिया गया। १९१३ के कम्पनी-अधिनियम के अन्तर्गत दी हुई बैंक-सम्बन्धी धाराओं तथा तब से अब तक के अधिनियमों और अध्यादेशों की बातों का नये अधिनियम में समावेश था और जहाँ तक अधिकोपो का प्रश्न था, केवल नया अधिनियम ही उन पर लागू होगा। इसमें कतिपय नई धाराओं का समावेश भी है—

(१) यह कानून सहकारी बैंको को छोड़कर सभी अधिकोपो पर लागू है तथा भारतीय ससद को भारतीय सभ में शामिल हो जाने वाले जिन राज्यों के लिए बैंकिंग कानून बनाने का अधिकार है वे राज्य तथा इस देश के सब प्रदेश इस अधिनियम के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत हैं। इस अधिनियम ने बैंक-कार्यों की परिभाषा यो दी है— कर्ज देना या विनियोग के प्रयोजन से जनता से ऐसे निक्षेप स्वीकार करना, जिन्हें मांगते ही या अन्य प्रकार से लौटाना हो तथा जो चैक, हुण्डी, आर्डर या अन्य उपाय द्वारा वापस माँगे जाने के योग्य हों। सुरक्षा तथा तात्कालिक वापसी की दृष्टि से जिन सस्थाओं में कोष जमा किया जाता है उन तक अधिनियम के क्षेत्र को सीमित करते तथा १९३० के इन्डियन कम्पनीज एक्ट की २७७वीं धारा में दी 'प्रमुख व्यापार' शब्द की परिभाषा के कारण उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए उपर्युक्त सरल परिभाषा आवश्यक थी।

(२) रिजर्व बैंक इस कानून के अन्तर्गत आने वाले सारे बैंको की वित्तीय स्थिति की दृढ़ता के प्रति निश्चित हो जाने के बाद उन्हें अधिकार-पत्र प्रदान करेगा, पर अगर कोई देश भारत में निवन्धित बैंको के प्रति भेद-भाव प्रदर्शित करता है तो उस देश में रजिस्टर्ड (इनकारपोरेटेड) बैंक को अधिकार-पत्र नहीं दिया जा सकता।

(३) अधिनियम में बैंक के भौगोलिक कार्य-क्षेत्र को दृष्टि में रखते हुए उसकी प्राप्त हिस्सा-पूँजी तथा सुरक्षित कोष की निम्नतम सीमा भी निर्धारित कर दी गई है।

(४) अधिनियम के अनुसार और अनुसूचित बैंको के लिए भी यह अनिवार्य है कि वे अपने पास या रिजर्व बैंक में कम-से-कम अवधि दायित्व का २०% तथा मांग-दायित्व का ५% धन सुरक्षित रखें तथा प्रत्येक शुक्रवार के नकद एवं समय व मांग-दायित्व के आँकड़े प्रतिमास रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करें।

(५) प्रत्येक बैंक के लिए यह आवश्यक है कि इस कानून के लागू होने के दो वर्षों के अन्दर अपने समय और मांग-दायित्व का २०% नकद में या प्रचलित वाजार-

दर के अनुसार मूल्यांकित स्वर्ण या ऋणमुक्त स्वीकृत प्रतिभूतियों में रहें। इसके अनिश्चित प्रत्येक त्रैमासिक अवधि के अन्त में उनके समय तथा भाग-दायित्व की ७५% निधि को अपने क्षेत्र में ही रखना भी आवश्यक है।

(६) किसी अधिकोपण के संचालकगण को दूसरी कम्पनी का संचालन करने, प्रबन्ध अधिकर्ता (डिरेक्टिंग एजेंटों) की नियुक्ति करने या किसी ऐसी फर्म को, जिसमें किसी संचालक का स्वार्थ निहित हो या किसी संचालक को असुरक्षित ऋण या पेशगी देने का निषेध है।

(७) रिजर्व बैंक के इस समय निम्नलिखित कानूनी अधिकार तथा कर्तव्य हैं—(क) बैंको को ऋण-सम्बन्धी नीति तथा उसकी सीमा निश्चित करने व मूद्र लेने के सम्बन्ध में निर्देश जारी करना, (ख) किसी विशेष कार्य व किसी प्रकार के कार्यों के सम्बन्ध में चेतावनी देने या उन्हें करने से निषेध करना, समय-समय पर तथा एतदर्थ व्यौरा माँगना एवं उसे प्रकाशित करना, (घ) स्वयं ही या सरकारी आज्ञा-नुसार बैंको का निरीक्षण करना, (च) नये शाखा-कार्यालयों को खोलने या किन्हीं वर्तमान शाखा-कार्यालयों का अन्तरण (ट्रान्सफर) करने की अनुमति देना या न देना, (ङ) किसी बैंकिंग कम्पनी के कारोबार को बन्द करने वाले मुकद्दमे के सिलसिले में न्यायालय से स्वयं को सरकारी निस्तारक की नियुक्ति की माँग करना, (ज) देश में अधिकोपीय उन्नति व प्रवृत्ति के बारे में केन्द्रीय सरकार को एक वार्षिक विवरण देना व इसे समृद्धिशासी बनाने के उपायों के बारे में सुझाव देना। निरीक्षण के फल-स्वरूप पता चलता है कि बैंको के कार्यों में निम्नलिखित उल्लेखनीय बुराइयाँ हैं—अपर्याप्त रिजर्व, अति कम नकद-आदेय, अवधि पर न चुकाए ऋण, अचल सम्पत्ति के आधार पर दिये अधिक ऋण तथा सन्देहात्मक ऋणों का अधिक अनुपात।

अधिकोपीय (सशोधन) अधिनियम १९५२ तथा अधिकोपीय (सशोधन) अधिनियम १९५६ के बाद १९५९ में पुनः अधिकोपीय (सशोधन) अधिनियम पास किया गया जो १ अक्टूबर १९५९ से लागू हुआ।

१९५९ के सशोधन अधिनियम की दो विशेषताएँ हैं. एक ओर तो वह बैंको की कार्यवाही को लचीलापन प्रदान करता है, दूसरी ओर वह बैंकिंग व्यवस्था के ऊपर रिजर्व बैंक के अधिकारों का अज्ञात विस्तार करता है। उदाहरण के लिए इस सशोधन अधिनियम के अन्तर्गत रिजर्व बैंक की लिखित अनुमति प्राप्त होने पर बैंकिंग कम्पनियों विदेशों में सहायक कम्पनियों खोल सकती है। बैंकों की हर आदेश (एसेट) की गणना के लिए रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, तथा रिफाइनन्स कारपोरेशन से लिये गए ऋण देय-राशि में नहीं सम्मिलित किये जाएंगे आदि। रिजर्व बैंक को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह किसी बैंक के अध्यक्ष (चेयरमैन), संचालक या प्रबन्धक या मुख्य प्रशासकीय अधिकारी को हटा सकता है, बशर्ते कि उसे किसी ट्रिब्यूनल या अधिकारी ने किसी विधान की व्यवस्था भंग करते पाया हो तथा रिजर्व बैंक को यह सन्तोष हो कि बैंक के साथ ऐसे व्यक्ति का सहयोग अवाञ्छनीय ही है। किसी संचालक की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति तथा प्रतिफल (चाहे संचालक

पूरे समय काम करता हो या कुछ समय तक ही) सम्बन्धी व्यवस्था में कोई परिवर्तन रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। १९५६ के संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत रिजर्व बैंक की अस्वीकृति केवल प्रबन्धक, सचालक (मैनेजिंग डाइरेक्टर), प्रबन्धक (मैनेजर) या मुख्य प्रशासकीय अधिकारी तक ही सीमित थी।

२०. निकासी-गृह—'निकासी-गृह' पद्धति का आरम्भ इंग्लैण्ड में १८वीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थांश में हुआ। अनेक प्रतिदावों (क्रासक्लेम्स) का सन्धान (एडजस्टमेण्ट) इसने नकद या द्रव्य के वास्तविक उपयोग के बिना ही कर दिया। इस पद्धति के कारण ही इंग्लैण्ड तथा अन्य देशों की बैंक पद्धति का आशातीत विकास हुआ है। इस पद्धति की अत्यधिक सफलता के लिए यह आवश्यक है कि निकासी गृह के सदस्य बैंकों में से एक बैंक भुगतान बैंक या बैंको का बैंक के रूप में कार्य करे तथा दूसरे बैंक इसके पास कुछ रकम रखें ताकि प्रतिदावों का भुगतान पूर्णरूपेण तथा आसानी से हो जाए।

केन्द्रीय अधिकोप खोज समिति के सम्मुख इम्पीरियल बैंक के तत्कालीन मैनेजिंग गवर्नर श्री मंकडानहड ने निपटारा करने वाले बैंकों की एक परिपद् की स्थापना का सुझाव रखा था। निकासी-गृह के निजी नियम होने चाहिए तथा प्रत्येक निकासी-गृह का विस्तारपूर्वक प्रबन्ध करना चाहिए। प्रत्येक सदस्य बैंक के अपने-अपने तथा निकासी-गृह के सहकार बैंक होने चाहिए। हमारे देश में रिजर्व बैंक की स्थापना होने के पहले तक इम्पीरियल बैंक ही इन कामों को करता था। इस कारण गड़बड़ी भी पैदा हो जाती थी तथा अन्य बैंक प्रायः इम्पीरियल बैंक में रखे हुए अपने कोष को निकासी-गृह में रखे हुए एक अंश के समान ही इस निपटारे के अन्तर्गत् बराबर करने का एक साधन मान लेते थे और वे इस बात को भूल जाते थे कि रकम की आवश्यकता केवल निपटारे की भिन्नता को ही पूरा करने के लिए ही न होकर अन्य बैंक-सम्बन्धी कार्य को पूरा करने के लिए भी है। बैंक का व्यवहार केवल व्यावसायिक सहरो तक में ही होने के कारण अभी यह अपने शोशब-काल से ही गुजर रहा है, पर अब धीरे-धीरे यह देहात की ओर भी फैल रहा है और इम्पीरियल बैंक की बहुत-सी शाखाओं के खुलने के बाद तो यह प्रवृत्ति विशेष स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। सहकारी बैंकों द्वारा जारी किये गए चेक भी आंतरिक क्षेत्रों की जनता को बैंक-पद्धति से परिचित बना रहे हैं। निकासी गृह-पद्धति को लोकप्रिय बनाने तथा उसका विस्तार करने के लिए यह आवश्यक है कि देहात की वयक्तिक फर्मों के चेकों के निपटारे के लिए उन्हें अधिक सुविधा दी जाए तथा निकासी-गृहों की सुविधा उचित स्थिति वाली रजिस्टर्ड निजी फर्मों को भी दी जाए। चेकों का व्यवहार तो निरसन्देह ही दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है, तब भी इस देश के बृहत् आकार तथा जनसंख्या की दृष्टि से अभी यह नहीं के ही बराबर है। दूर-दूर तक फैली हुई निरक्षरता भी इस पद्धति के विकास के बाधकों में है।

२१. पोस्टल सेविंग बैंक—१८३३ तथा १८३५ के बीच प्रेसिडेंसी नगरों में सरकारी सेविंग बैंकों की स्थापना की गई। १८१७ में कुछ क्षेत्रों में जिला सजानों से

सम्बन्धित जिला बैंकिंग बँको की स्थापना हुई। १९१४ में किसी व्यक्तिगत निक्षेप की सम्भावी वार्षिक तथा कुल निक्षेप की रकम की सीमा बढ़ाकर और निक्षेपों की सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग करने की सहायता देकर सरकार ने निक्षेपकों को अधिक सुविधा प्रदान की। फलस्वरूप अत्यधिक सख्या में निक्षेप आने लगे। विशेषतः १९१३-१४ की बैंक असफलताओं के कारण व्यक्तिगत बैंको पर जनता का विश्वास उठ गया था। १९१४-१८ का युद्ध टाक खाने के निक्षेपों में कुछ मदी तो अवश्य ही लाया, पर युद्धोत्तर-काल में इस दिशा में काफी प्रगति भी हुई। १९२२-२३ के उपरान्त निक्षेप की रकम (२३ १९ करोड़ रुपया) १९१४-१८ की लड़ाई के पूर्व के निक्षेप की अपेक्षा बढ़ गई थी, पर यदि हम रुपये की शक्त-शक्ति के गिर जाने वाले समय का भी खयाल करें तो यह स्थिति उत्तनी सतोषप्रद नहीं रह जाती। विगत वर्षों में स्वर्ण-विक्रय के कुछ अंश का विनियोग कर देने के फलस्वरूप निक्षेप की रकम में अत्यन्त वृद्धि हो गई है। सितम्बर १९३६ में लड़ाई दृष्टि से ही सेविंग बैंको से वापस होने वाली रकम ७ ६५ करोड़ तक थी, पर बाद के महीनों में पुनः विश्वास जमाने के साथ-साथ इस दिशा में काफी प्रगति हुई।

सेविंग बैंको को अधिक लोकप्रिय बनाने के सुझावों में कुछ निम्नलिखित हैं—(१) निक्षेपों पर दिये जाने वाले सूद की दर अधिक हो, (२) आकस्मिक वापसी के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाकर हर साल जमा होने वाली रकम तथा रकम की बाकी की सीमा बढ़ा दी जाए, (३) चेक द्वारा निक्षेप स्वीकार किये जाएँ तथा चेक द्वारा हाया निकालने दिया जाए, और (४) नये सेविंग बैंक खोलने के लिए प्रचार किया जाए।

पोस्ट ऑफिस में जनता की बचत कैश-सर्टिफिकेट द्वारा भी आती है। ये सर्टिफिकेट १० रुपये या उसके अपवर्त्य (मल्टिपल) रकम में जारी किये जाते हैं तथा एक व्यक्ति अधिक-से-अधिक दस हजार रुपये के अर्ध मूल्य तक के सर्टिफिकेट खरीद सकता है। त्रय के दिन से ५ वर्ष के पश्चात् उनका भुगतान होता है तथा वे बट्टे पर जारी किये जाते हैं, जिसका अर्थ है कि ५ वर्ष के बाद ही उनके अर्ध मूल्य का भुगतान होता है। लड़ाई प्रारम्भ होत समय सितम्बर १९३६ में अत्यधिक कैश सर्टिफिकेट मुनाये गए तथा नये कैश सर्टिफिकेट की बिक्री काफी गिर गई। इन पर जनता का पुनर्विश्वास हो जाने पर कैश सर्टिफिकेट की मुनाई कम हो गई। निर्गमित कैश सर्टिफिकेट का कुल मूल्य १९४६-४७ में ३६ २२ करोड़ ६० तथा १९४८-४९ में (प्रारम्भ में) केवल ७ ५० करोड़ ६० था।

१९४० में दसवर्षीय डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का प्रचलन हुआ। इनकी बाकी

१- साल-भर में निक्षेपक ७५० रुपये तक ही जमा कर सकता है और उन्हें वित्तों की कुल रकम ५००० २० तक ही आ सकती है। एक बार कन्सेन्स चार आना तक जमा किया जा सकता है तथा रुपये की वापसी सम्बन्ध में केवल एक ही बार हो सकती है। सूद की दर को घटाकर सन् १९३३ में ३% से २½%, १९३६ में २% तथा १९३८ में १½% कर दिया गया।

रकम १९४६-४७ में ५.४८ करोड़ रुपया तथा १९४८-४९ में (प्रारम्भ में)—७६ लाख रुपया थी। १ अक्टूबर, १९४३ से उनके बदले में द्वादशवर्षीय नेशनल सेविंग सर्टिफिकेटों को चलाया गया, जिनकी बाकी रकम १९४६-४७ में ७०.६२ करोड़ रुपया तथा १९४८-४९ में (प्रारम्भ में) २५.०१ करोड़ रुपया थी। इसमें १ जून, १९४८ से प्रचलित किये गए पंचवर्षीय तथा सप्तवर्षीय नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की भी बाकी रकम थी। डिफेन्स सेविंग बैंक का कार्यारम्भ १ अप्रैल, १९४१ को हुआ तथा इनका निक्षेप १९४६-४७ में १०.९३ करोड़ रुपया एवं १९४८-४९ में (प्रारम्भ में)—४.०७ करोड़ रुपया था।

भारत तथा पाकिस्तान सरकार के बीच १५ अगस्त, १९४७ के पूर्व जारी किये गए एवं एक देश के पोस्ट ऑफिस में दूसरे देश के पोस्ट ऑफिस के नाम पर दर्ज पोस्ट ऑफिस कौश एवं डिफेन्स तथा नेशनल सर्टिफिकेटों को ३० जून, १९४९ तक हस्तान्तरित करने के लिए सुविधा प्रदान करने का समझौता हुआ। इसमें यह भी तय हुआ कि १५ अगस्त, १९४७ के पूर्व के बाकी तथा ३१ मार्च, १९४९ के पूर्व या उस दिन तक निर्गमन कार्यालय द्वारा हस्तान्तरणार्थ प्रमाणित सर्टिफिकेट साधारण ऋण के समान भारत का वित्तीय दायित्व होगा तथा उसके साथ इस प्रकार व्यवहार किया जाएगा मानो विभाजन के पूर्व वह एक भारतीय पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी किया गया हो। ३१ मार्च, ४८ के बाद हस्तान्तरित सर्टिफिकेट उस देश के दायित्व होंगे, जिसमें मूल निर्गमन पोस्ट ऑफिस है तथा जिस देश से वे हस्तान्तरित हुए हैं उसी से उनके बोनस तथा निरसन (डिस्चार्ज) की प्राप्ति की जाएगी।

१ जून १९५७ से बारहवर्षीय राष्ट्रीय योजना सर्टिफिकेट जारी किये गए जिससे ७१४५ लाख रु० की प्राप्ति हुई। डाकखाने के सेविंग बैंक निक्षेप १९५५-५६ में ३७ करोड़ रु० थे। १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में वे घटकर २९ करोड़ रु० तथा १७ करोड़ रु० हो गए। १९५८-५९ में पुनः कुछ वृद्धि हुई और निक्षेप की राशि २१ करोड़ रु० हो गई। १९५९-६० के लिए डाकखाने के सेविंग बैंक के निक्षेप की अनुमानित राशि २७ करोड़ रु० है। १९६४-६५ में डाकखाने के सेविंग बैंक का निक्षेप बढ़कर २९३.६८ करोड़ रुपया हो गया।

२२. भारतीय द्रव्य बाजार की विशेषताएँ तथा त्रुटियाँ—भारत के द्रव्य-बाजार की अनेक विशेषताएँ तथा त्रुटियाँ हैं, जिनमें से कुछ का नीचे उल्लेख किया जाता है। पहले ही बर्णन किया जा चुका है कि भारत का द्रव्य-बाजार अनेक हिस्सों में बँटा हुआ है तथा इन हिस्सों का आपसी सम्बन्ध भी बिलकुल ही शिथिल-सा है। स्टेट बैंक, विनिमय बैंक, मिश्रित पूँजी वाले बैंक, सहकारी बैंक, देशी साहूकार आदि खण्डों सम्बन्धी मस्याएँ अलग अलग विशेष श्रेणी के कारोबार तक अपने को सीमित रखती हैं। द्रव्य-बाजार के सदस्यों के बीच का आपसी सम्बन्ध भी उत्तम नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के काम करते हुए बहुत दिन गुजर चुकने के पश्चात् भी निकट भविष्य में उसमें किसी क्रान्तिकारी परिवर्तन की आशा नहीं की जा सकती। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कारण उल्लेखनीय हैं—सर्वप्रथम, अभी तक रिजर्व बैंक

तथा देशी साहूकारो के बीच का सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाया है और दूसरी बात यह है कि इसके पूर्व किसी सुसम्बद्ध तथा सुव्यवस्थित द्रव्य-बाजार का आविर्भाव हो सके, कुछ समय का व्यतीत होना भी आवश्यक है जिसके बीच केंद्रीय बैंकिंग ढाँचे का प्रभाव देश की साख-व्यवस्था पर पड़ सके। रिजर्व बैंक की स्थापना हुए २५ वर्ष से अधिक हो गए हैं किन्तु सुव्यवस्थित द्रव्य-बाजार का सगठन अभी नहीं हो सका है। इसका एक कारण भारत में बैंकिंग सेवाओं की सामान्य कमी है। इस दोष को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। स्टेट बैंक स्वयं शाखाएँ खोलकर बैंकिंग सेवा का प्रसार कर रही है।

२३ द्रव्य की दरों में भ्रामकता तथा गोलमाल—द्रव्य-बाजार की अन्य विशेषता द्रव्य-दर की भिन्नता है। इस देश की द्रव्य-व्यवस्था अनेक खण्डों में विभाजित रहने के परिणामस्वरूप द्रव्य-दर में भ्रामकता तथा अनेकरूपता का होना अनिवार्य है। केंद्रीय अधिकोपण समिति ने यह कहकर अत्युक्ति नहीं की कि माँग-दर ३%^१, हुडी-दर ३%^२, बैंक-दर ४%^३, तथा बम्बई में छोटे छोटे व्यापारियों की हुण्डियों की बाजार-दर ६ $\frac{३}{४}$ %^४ एवं कलकत्ता में ऐसी ही हुण्डियों की बाजार-दर १०% एक ही साथ होने का स्पष्ट अर्थ यह है कि विभिन्न-बाजारों के बीच साख की गति शिथिल है। पर इसके ठीक विपरीत लन्दन के द्रव्य-बाजार में द्रव्य की विभिन्न दरों में बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। अन्ततोगत्वा सभी दर बैंक दर पर ही निर्भर करती हैं तथा उस दर में थोड़ा भी परिवर्तन होने पर ठीक उसी के अनुसार अपना भी समायोजन कर लेती हैं। भारत की द्रव्य दर की दूसरी विशेषता कलकत्ता तथा बम्बई-जैसे दो प्रमुख केन्द्रों की दरों के बीच स्पष्ट अन्तर का होना है। इसी कारण प्रतिभूतियों की कीमत में उतार-चढ़ाव तथा व्यापार की गति में प्रतिक्रिया होती रहती है। १९५६ में बम्बई में अन्तर-अधिकोपीय द्रव्य दर लगातार हट रही। गत वर्षों से इसकी तुलना करने में कठिनाई यह है कि सितम्बर, १९५८ तक प्रकाशित द्रव्य-दरों में दलाली भी सम्मिलित थी। बम्बई की बड़ी बैंकों की माँग-दर मई, १९५६ तक ३ $\frac{१}{२}$ -३ $\frac{३}{४}$ प्रतिशत रही। किन्तु जुलाई, १९५६ तक उतरकर ३-३ $\frac{३}{४}$ प्रतिशत तथा अक्टूबर के बाद ३-२ $\frac{१}{४}$ प्रतिशत हो गई। कलकत्ता के द्रव्य-बाजार में भी लगभग

१. माँग (या माँग-द्रव्य) दर से तात्पर्य उस व्याज की दर से है जो कम-से-कम २४ घण्टे के विनियोग हेतु प्राप्त द्रव्य पर ली जाती है।

२. इम्पीरियल बैंक जिस दर पर त्रैमासिक बिल प्रथम श्रेणी की इण्डो का बट्टा करे वह (इम्पेरियल बैंक की) हुडी-दर है।

३. रिजर्व बैंक की स्थापना के पूर्व जिस दर पर इम्पीरियल बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के निमित्त माँग श्रेण्य देने को तैयार रहता था उस दर का निर्देश यहाँ (पुराना) बैंक-दर से किया गया है। अब इसे इम्पीरियल बैंक की अग्रिम दर कहा जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बैंक दर के आधार का स्पष्टीकरण पैरा ४६ के नीचे किया गया है।

४. कलकत्ता तथा बम्बई में स्थान लोग जिस दर पर हुण्डियों का मुगलान करते हैं, उसे बाजार-दर कहा जाता है।

इसी प्रकार की प्रवृत्तियाँ लक्षित हुईं, यद्यपि अनिक्तम दर कुछ अधिक थी, विशेषकर मार्च और अप्रैल में, जब वह ३१-४ प्रतिशत और ३१-४^१ प्रतिशत थी।

विभिन्न द्रव्य-दरों की समानता का आविर्भाव शर्त-शर्त विकास द्वारा ही सम्भव है। 'हमारा अन्तिम उद्देश्य देश के सारे चल साधनों का एक ऐसे बृहत् कोष के रूप में व्यवस्थित करना होना चाहिए जिससे हुण्डियों का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र तथा कम-से-कम मध्यस्थों के हस्तक्षेप से हो जाए।' रिजर्व बैंक की स्थापना के पश्चात् ऐसी आशा की जाती थी कि द्रव्य-दरों की गोलमाल की समाप्ति तथा द्रव्य-बाजार में प्रचलित अनियन्त्रित दर पर नियन्त्रण के पश्चात् हुण्डियों के बाजार की उन्नति ही सवेगी (अगले सेवशन देखिए)।

२४ द्रव्य-सम्बन्धी मौसमी तर्गो (सोजनल मोनेटरी स्ट्रिजेन्सी)—द्रव्य-सम्बन्धी मौसमी तर्गों तथा साल के कुछ महीनों तक द्रव्य की दर का अधिक रहना हमारे देश के द्रव्य-बाजार की दूसरी विशेषता है। भारत में साल स्पष्टतया दो पृथक् कालों में विभाजित है—(१) नवम्बर से जून तक का समय कारोवारी है। इन दिनों फसल क देहानी इलाकों से बन्दरगाहों तथा देश के भीतरी भागों में उपभोग करने वाले केंद्रों तक ले जाने के लिए द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है। (२) जुलाई से अक्तूबर तक मन्दी का मौसम होता है। इस समय पाट (बुलियन) तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य के रूप में द्रव्य द्वितीय केंद्रों को लौट आता है। हर साल के दोनों कालों के बीच द्रव्य-दरों में बहुत ही उतार-चढ़ाव होते रहते हैं।^१ १९५६ के मन्दी के मौसम में बैंक द्वारा उधार दी गई राशि ७६ करोड़ ६० की कमी हुई। नवम्बर १९५६ से अप्रैल १९६० तक के कारोवारी मौसम में बैंक द्वारा उधार दी गई राशि में १८६ करोड़ २० का विस्तार हुआ जो १९५८-५९ के कारोवारी मौसम के साक्ष विस्तार (जो १८२ करोड़ ६० था) से अधिक था। यह विशेषकर चीनी के अधिक उत्पादन तथा चीनी उद्योग के मौसमी स्टॉक की वृद्धि के कारण ऐसा हुआ।

फसलों के परिवहन हेतु द्रव्य माँग के कारण द्रव्य-बाजार में मौसमी तर्गी उपस्थित हो जाती है, पर ठीक इसी समय ल्यूहरों तथा शादी आदि के लिए रुपये की अत्यधिक माँग इम कठिनाई को और भी बढ़ा देती है। द्रव्य की ऊँची दर का एक मौलिक कारण पूँजी की कमी है, जो हमारे देशवासियों की गरीबी का साक्षात् फल है। अधिकांश व्यक्तियों की आमदनी इतनी कम है कि वे कुछ भी बचा नहीं पाते। दूसरा कारण है हमारी सम्भाव्य पूँजी का संचित धन के रूप में पड़े रहना। लाभ-दायक विनियोग के लिए आकर्षित करने वाले बैंकिंग सुविधाओं के न होने के कारण संचित राशि बकार तथा अनुत्पादक ही बनी रहती है। ये त्रुटियाँ ऐसी बैंकिंग व्यवस्था की आवश्यकता की ओर इंगित करती हैं जो आवश्यक साधनों का वितरण देश के विभिन्न भागों तथा साल के विभिन्न मौसम में समान रूप से करें।

१. के० अ० रि०, ५८१।

२. भारत में द्रव्य-दर पर द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रभाव की विरोध जानकारी के लिए सेवरान ५० देखिए।

२५ हुण्डी के बाजार का अभाव—हुण्डियों की कमी, जो हुण्डियों में लगे बैंकों के आदेय की छोटी मात्रा से ही स्पष्ट है, के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं—(१) चूंकि भारतीय बैंकों को पाश्चात्य देशों की अपेक्षा अधिक तरल (लिक्विड) स्थिति कायम रखनी होती है, अतः उनके आदेय का अधिकांश भाग सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रह जाता है। (२) अप्रैल, १९३५ में रिजर्व बैंक की स्थापना के पूर्व तक बैंक अपनी हुण्डियों का मुगलान इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया के साथ इसलिए नहीं करना चाहते थे कि ऐसा करने से वे बाजार में कमजोर समझे जाते थे। (३) मिश्रित पूंजी वाले बैंक पुनर्वट्टा के लिए अपनी हुण्डियों को देने की अपेक्षा मरक़ारी ऋण-पत्र पर इम्पीरियल बैंक से उधार लेना इस कारण पसन्द करते थे कि इम्पीरियल बैंक तो खुद ही प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक बैंक था, अतः कोई भी अन्य प्रतिस्पर्धी बैंक अपनी हुण्डी का रहस्य इसके सामने रखना क्यों पसन्द करता? इसके अतिरिक्त चूंकि इम्पीरियल बैंक मन्त्रके प्रति एक से मापदण्ड और नीति के आधार न रखकर अपनी मरजों के अनुसार हुण्डियों का बढ़ा करता था, कोई भी मिश्रित पूंजी वाला बैंक वित्त-योग प्राप्त करने के लिए अपने ग्राहकों द्वारा प्राप्त हुण्डी पर निर्भर नहीं रह सकता था। (४) एक दूसरी बाधा यह है कि बाजार में प्रचलित हुण्डियों की विभिन्नताओं के कारण बैंक उनका बढ़ा तक नहीं करते जब तक बैंकों द्वारा माग्य सराफों में से कोई सराफ़ निजी जमानत न दे। बाजार में प्रचलित हुण्डी से यह स्पष्ट नहीं होता कि वह शुद्ध द्वितीय हुण्डी है या किमी व्यापारी कार्य हेतु लिनी गई है, क्योंकि उसके साथ बिक्री के सविदे, बीजक तथा स्वत्वधिकार पत्र जैसे अधिकार-पत्र तो रहते नहीं जिससे यह समझा जा सके कि यह किसी फनल या वस्तु से सम्बन्धित है। हुण्डियों में लिखी जाने वाली भाषाओं में भी अनेक भेद, रिधायती दिन आदि की विभिन्नता तथा आम जनता की अधिकांश आदि कुछ अन्य कठिनाइयाँ भी हैं। (५) एक अन्य कारण मकद-साख की पद्धति भी है, जिसका उपयोग भारत के देशी व्यापार में अधिक होता है।

२६ हुण्डी के बाजार की वृद्धि करने के उपाय—केन्द्रीय अतिकोप खोज समिति ने भारत में हुण्डी के बाजार की उन्नति करने के लिए अनेक सुझाव दिये हैं (के० अ० रि० १९३३)—(१) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को व्यावसायिक कार्यों से सम्बद्ध प्रथम श्रेणी की व्यापारिक हुण्डियों तथा प्रपत्रों के प्रकाशित बैंक-दर (जो निम्नतम हों) पर खरीदने या बढ़ा करने को तैयार रहना चाहिए तथा अधिकृत प्रतिभूतियों के आधार पर मांगे गए ऋण पर अपनी इच्छानुसार अधिक व्याज-दर लेनी चाहिए। मिश्रित पूंजी वाले बैंकों को रिजर्व बैंक की अपना प्रतिद्वन्द्वी न समझना चाहिए। उनसे तो यह आशा है कि वे रिजर्व बैंक द्वारा दिये गए व्यापारिक पत्रों के पुनर्वट्टा-सम्बन्धी

१ और अधिक बरतन के लिए के० अ० रि० का 'दि बैंकिंग डिप्टम एण्ड मना मार्केट' नामक परिच्छेद देखिए।

सुविधाओं से लाभ उठाएँ। रिजर्व बैंक को योग्य व्यावसायिक पत्रों का पुनर्बंट्टा करने का अधिकार प्राप्त है, पर अभी तक वह भारत में हुण्डी के बाजार को विकसित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने में समर्थ नहीं हो सका है। (२) बट्टा-व्यय घटाना चाहिए तथा एक ही बार बट्टा देना पड़े, इस हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक प्रादेशिक राजधानी में हुण्डियों के लिए निकासी-गृहों की स्थापना की जाए। (३) भारत के विभिन्न भागों में गोदामों की स्थापना की जानी चाहिए, क्योंकि इनके कारण व्यापारियों तथा सर्राफों द्वारा लिखी गई शुद्ध व्यावसायिक (या वित्त योग हेतु लिखी) हुण्डियों का स्थान ऐसी बिल्टी-सहित हुण्डियाँ ले सकेंगी, जिनका बैंक खुशी से पुनर्बंट्टा करेगा। (४) हुण्डियों पर आवश्यक टिकट-व्यय (स्टाम्प ड्यूटी) भी कम कर देना चाहिए। (५) उचित है कि डाकखानों में अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में हुण्डियों के छपे फार्म मिल सकें। हुण्डी के मालिक को असुविधा तथा कष्ट से बचाने के लिए बैंको, सर्राफों तथा व्यापारियों की अधिकृत संस्थाओं द्वारा की गई हुण्डी आदि की अस्वीकृति की सूचना (नोटिंग ऑफ डिस्ग्रॉन्टर) और निकरार्ड-सिवरार्ड (नोटिंग ऑफ प्रोटेस्ट) को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। हुण्डियों का चलन बढ़ाने के उद्देश्य से उनसे सम्बन्धित रस्मों का प्रमाणीकरण कर देना चाहिए। (६) बैंक-स्वीकृत-विपत्रों के निर्माण-कार्य में बैंको को अग्रणी होना चाहिए। ये हुण्डियाँ साधारण व्यापारी हुण्डियों की अपेक्षा आसानी से विनिमय-साध्य होगी। (७) हुण्डी के दलाली-कार्य को देशी साहूकारों के व्यापार का एक अंग बनाकर तथा रिजर्व बैंक की सरक्षता में इन साहूकारों तथा उनके घनी निक्षेपकों द्वारा एक बट्टा-गृह स्थापित करके एक हुण्डी बट्टा बाजार की स्थापना की जानी चाहिए। (८) हुण्डियों के उपयोग का विस्तार कृषकों को फसल उपजाने के कार्य के लिए पेशगी देने, फसल-बिक्री हेतु वित्त-प्रबन्ध करने, गाँव के साहूकारों को सर्राफों द्वारा आर्थिक सहायता देने, शहरों से वस्तुओं को देश के भीतरी भागों में ले जाने के कार्य का वित्तीय प्रबन्ध करने तथा देश के विदेशी व्यापार के वित्तीय प्रबन्ध करने के लिए कर देना चाहिए।

जनवरी १९५२ में रिजर्व बैंक ने बिल बाजार के सगठन के लिए एक योजना बनाई। प्रारम्भ में यह योजना उन अनुसूचित बैंकों तक सीमित रखी गई जिनके पास १० करोड़ रुपये या इससे अधिक के निक्षेप हों, ऋण तथा बिल की निम्नतम सीमा क्रमशः २५ लाख रु० और एक लाख रु० निश्चित की गई। रिजर्व बैंक ने बैंक-दर से $\frac{1}{2}$ प्रतिशत कम दर से व्याज लेने तथा आधी स्टाम्प ड्यूटी स्वयं वहन करने की सुविधा प्रदान की। ये सुविधाएँ १ मार्च १९५६ से समाप्त हो गईं। जून १९५३ में यह योजना ५ करोड़ रु० या इससे अधिक निक्षेप वाले बैंकों तथा जुलाई १९५४ में उन सभी बैंकों पर लागू हो गई जिन्हें १९४६ के बैंकिंग कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत

१. बैंक-स्वीकृत-विपत्र वह हुण्डी है जिसे वस्तु-विक्रेता लिखता है और वस्तु-क्रेता के स्थान पर उसका बैंक उसकी स्वीकृति देता है। उधार क्रय करने की दृष्टि से वस्तु-क्रेता पहले से ही अपने बैंक से इस सम्बन्ध में बातचीत किये रहता है।

लाइसेन्स प्राप्त थे। चार वर्ष की अवधि में बैंको द्वारा प्राप्त अधिम की मात्रा १९५२ के ५१ करोड ह० से बढ़कर १९५५ में २२५ करोड २० हो गई। १९५५-५६ में निर्यात-बिलों को एक वर्ष के लिए प्रयोगात्मक रूप से बिल बाजार योजना में सम्मिलित करने का निर्णय किया गया।

२७ केन्द्रीय बैंक की उपयोगिता—१९२० में द्रुसेस्त में हुए अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सम्मेलन में यह प्रस्ताव पास हुआ कि 'जिन देशों में केन्द्रीय बैंक नहीं है, वहाँ उनकी स्थापना की जानी चाहिए।' इस प्रस्ताव के मूल में यह विचार है कि वित्तीय स्थिरता तथा केन्द्रीय बैंकिंग व्यवस्था के बीच बहुत घना सम्बन्ध है। इस प्रस्ताव में निहित राय का अनुसरण यूरोपीय देशों तथा अभी हाल तक के 'विकेन्द्रीय बैंकिंग के देश' समुत्तराज्य अमेरिका में हुआ।^१ हमारे देश में परिस्थितियों के वक्ष में होकर स्वयं सरकार ही नोट जारी करने, नकद रकम का प्रवन्ध करन, विदेशी विनिमय की व्यवस्था करने आदि प्रमुख कार्यों को करने लगी थी, पर ऐसा अनुभव किया जाने लगा कि ये काम केन्द्रीय बैंक द्वारा अच्छी तरह से सम्पादित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन कार्यों को बैंकिंग कारोबार से अलग रखना भी बहुत बड़ी वृष्टि थी। इस सम्बन्ध-विच्छेद न ही वक्षत को सरकारी वक्षत तथा साहूकारों की वक्षत नामक दो भागों में विभक्त कर दिया। इन दोनों का सम्बन्ध भी अस्पष्ट था तथा इसके कारण ही द्रव्य पद्धति अत्यधिक लोचहीन हो गई। केन्द्रीय बैंकिंग अधिकारी के अभाव के ही कारण देश की बैंक-सम्बन्धी नीति अनियन्त्रित-सी थी। सिद्धान्त तो हमारे यहाँ बहुसुरक्षित कोष प्रणाली थी, जिसका अर्थ यह था कि विभिन्न बैंक अपना-अपना सुरक्षित कोष रखते थे, पर व्यवहार में ये धन कदापि ही पर्याप्त हा पाते थे तथा इस बात का खतरा बना रहता था कि सङ्कटकाल में ये बैंक एक-दूसरे से सहायता की ही आशा करेंगे। १९१३-१४ की बैंक-अगफलता न इस तर्क की और भी पुष्टि की। एक केन्द्रीय बैंक से जिन अन्य लाभों की आशा की जाती थी वे ये थे—बैंक-दर के अत्यधिक उतार-चढ़ाव में कमी करना तथा बैंकिंग साधनों की वृद्धि एवं आपसी सहयोग द्वारा सामान्यतया ऊँचे रहन वाले द्रव्य-दर को स्तर को कम करना। केन्द्रीय बैंक पर्याप्त पुनर्वर्द्धा की सुविधा भी प्रदान कर सकता था, जिससे दूसरे बैंक अपने आदेय को तरल बनाने में असमर्थ हो सकते थे। इस सुविधा से उनकी साख में भी वृद्धि हो जाती। यह केन्द्रीय बैंक सरकारी कर्मचारियों से उन वित्तीय तथा अर्द्ध-वित्तीय कर्तव्यों की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेता, जिन्हें वे ठीक तरह से नहीं कर पा रहे थे। हमारे देश में निपुण परामर्श तथा अनुभव के ही अभाव के कारण वित्तीय मामलों की शक्ति का केन्द्र इस देश से हटकर 'इण्डिया ऑफिस' तथा 'इण्डिया काँसिल' के हाथ में चला गया, जो पर्याप्त रूप से भारतीय परिस्थिति के सम्पर्क में नहीं थे। केन्द्रीय बैंक प्रशिक्षित अनुभव तथा परामर्श दे सक्ता तथा भारत-सचिव और जन-सालोचना के बीच मध्यस्थ वा भी काम करेगा। मुद्रा में स्थिरता रखन की ही वृष्टि

१. बीरा एण्ड एलकिन, 'सिस्टम बैंकिंग', पृष्ठ २।

से वट्टे की दर पर नियन्त्रण रखने का कार्य केन्द्रीय बैंक के ही क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ना है। इसी बैंक से यह भी आशा की जाती है कि वह सरकारी विधि का व्यापारिक तथा औद्योगिक कार्य-हेतु उचित उपयोग करेगा।

२८ इम्पीरियल बैंक की रचना—इम्पीरियल बैंक की केन्द्रीय परिषद् के लिए साझा में कम-से-कम एक बार प्रत्येक स्थानीय प्रधान कार्यालय में एकत्रित होना आवश्यक था। पहले तीनों प्रेसीडेन्सी बैंकों की पूंजी का योग ७ करोड़ रुपये ही था, पर अब पूंजी तथा सुरक्षित धन को १५ करोड़ रुपये करके बैंक के पूंजी के आधार को विस्तृत कर दिया गया।

अतः इम्पीरियल बैंक एक निजी निगम ही है, पर १९३५ में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना तक यह राज्य बैंक भी इस सीमित अर्थ में था कि भारतीय व्यवस्थापिका के एक विशिष्ट कानून द्वारा इसका निर्माण हुआ था तथा कुछ अंशों में इसका नियन्त्रण, सहायता तथा निरीक्षण सरकार ही करती थी। इम्पीरियल बैंक और इंग्लैण्ड तथा फ्रान्स के केन्द्रीय बैंकों के बीच मुख्य भेद यह था कि यह बैंक राज्य-बैंक के बहुत बड़े कार्यों को कर पाता था।

२९. इम्पीरियल बैंक का विधान—इम्पीरियल बैंक का नियन्त्रण गवर्नरों की एक केन्द्रीय परिषद् के सुपुर्द कर दिया गया। गवर्नर जनरल को वित्तीय नीति या सरकारी रकम की सुरक्षा से सम्बन्धित किसी विषय पर बैंक को आदेश देने का अधिकार था। केन्द्रीय परिषद् के कर्तव्य थे—सामान्य नीति से सम्बन्धित मामलों को तय करना, स्थानीय परिषदों की नियन्त्रण-सम्बन्धी साधारण शक्ति का उपयोग करना, बैंक की निधि के दौटवारे तथा बैंक दर का निर्णय करना (जिसे अब अग्रिम दर कहा जाता है) तथा बैंक के हिसाब के साप्ताहिक प्रकाशन की जिम्मेदारी लेना। स्थानीय परिषद् अपने-अपने क्षेत्र के दैनिक कारोबार से अपना सम्बन्ध रखते थे। दैनिक साधारण (केन्द्रीय) प्रबन्ध के लिए केन्द्रीय परिषद् के तीन सदस्यों की एक समिति होती थी जिनमें से एक मुद्राध्यक्ष होता था। इस सम्बन्ध में एक नई बात यह थी कि बैंक को लन्दन में शाखा स्थापित करने की कानूनन इजाजत थी। यह बैंक लन्दन में भारत-सचिव, सार्वजनिक सस्थाओं, दूसरे बैंकों तथा प्रेसीडेन्सी बैंक के पुराने ग्राहकों के साथ-साथ भारत सरकार की ओर से व्यापार का कारोबार तो कर सकता था, पर विदेशी विनिमय के सिलसिले में जनता के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखने की इजाजत इसे नहीं थी।

३०. इम्पीरियल बैंक के कार्य—१८७६ के पुराने प्रेसीडेन्सी बैंक एक्ट के बाद १९२० में एक एक्ट यह स्पष्ट करने के लिए बनाया गया कि यह बैंक किस प्रकार का कारोबार करे। इम्पीरियल बैंक को निम्नलिखित कार्यों को करने की अनुमति दी गई—(१) भारत तथा इंग्लैण्ड की सरकारों के कुछ विशिष्ट ऋण-पत्रों तथा बन्दरगाह-समितियों, कुछ नगर-निगमों, सरकारी सहायता-प्राप्त रेलवे एवं कुछ जिला परिषदों के ऋण-पत्रों में पूंजी लगाना। (२) उपर्युक्त किसी भी ऋण-पत्र के आधार पर रुपया पेशगी देना। (३) स्वीकृत हुण्डी, प्रपत्र तथा बैंकों के सुपुर्द की गई वस्तुओं या स्वत्वाधिकार-पत्रों के आधार पर रुपया पेशगी देना। (४) भारत

तथा लका मे भुगतान होने योग्य हुण्डियो तथा दूसरे विनिमय साध्य ऋण-पत्रो को लिखना, स्वीकार, बट्टा तथा विक्रय करना तथा गवर्नर जनरल इन-कौंसिल की आज्ञा-नुसार विदेशो म चुकता होन योग्य हुण्डियो का बट्टा, खरीद तथा विक्रय करना । जिन व्यक्तियो की जापदाद का प्रबन्ध बैक करता हो उनके लिए तथा अन्य व्यक्तिगत सस्थाओ एव ग्राहको की निजी आवश्यकता के लिए हुण्डी-लेखन तथा साख पत्रो की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार बैक को दिया गया । (५) भारत मे ऋण लेना, निक्षेप लेना, सुरक्षित धरोहर-स्वरूप ऋण पत्र रखना एव उसका सूद वसूल करना तथा सोना-चाँदी खरीदना तथा बेचना । (६) बैक की लन्दन-शाखा बैक के व्यापार के लिए बैक के आदेय की सुरक्षा पर इग्लैण्ड मे रुपया उधार तो ले सकती थी, पर उस रोक ऋण (क्रेडिट) खाते खोलने, दूसरो के नकद हिसाब रखने या प्रेसीडेन्सी बैक के पहले के ग्राहको व अतिरिक्त किसी अन्य से निक्षेप लेने की आज्ञा नहीं थी ।

३१. सार्वजनिक सस्था के रूप मे कार्य—सरकारी बैक के रूप मे इम्पीरियल बैक के निम्नलिखित कार्य थे—

(१) इस बैक ने भारत सरकार के बैक-सम्बन्धी सभी साधारण कार्यों का जिम्मा ले लिया । वह सरकार की ओर से रुपये-मैस स्वीकार करता तथा सरकार के लिए खर्च भी । जहाँ-जहाँ इसके प्रधान कार्यालय तथा शाखाएँ थी, सरकारी खजाने की सारी निधि इन्ही म रखी जाती थी । इस प्रकार सुरक्षित खजान की पदति समाप्त हो गई । (२) एक विशेष पारिश्रमिक पाने के बदले यह बैक सार्व-जनिक ऋण का प्रबन्ध करने लगा । (३) बैक से कहा गया कि वह १०० नई शाखाएँ खोले, जिनके चतुर्थांश के स्थान का निर्णय सरकार करेगी । (४) बैक से ऐसी आशा की गई कि वह जनता को अपनी शाखाओ के बीच द्रव्य हस्तान्तरण की सुविधा मुद्राव्यक्ष द्वारा स्वीकृत उचित दर पर प्रदान करेगा । जिन दो स्थानो मे इम्पीरियल बैक का कारोबार हो वहाँ सरकार ने उनके बीच जनता को रकम भेजने की सुविधा देना बन्द कर दिया । (५) जनवरी, १९२१ म स्थापित बैक की लन्दन शाखा ने भारत सरकार के कारोबार के कुछ ऐसे भाग को अपने जिम्मे ले लिया जो पहले बैक ऑफ इग्लैण्ड के हाथ मे थे (जैसे भारत के हाई कमिश्नर का चालू हिसाब) ।

३२. इम्पीरियल बैक की आलोचना के विषय—१९२१ मे निर्मित इम्पीरियल बैक की बहुत ही आलोचना की जा चुकी है । इम्पीरियल बैक पर भारतीय फर्मों तथा सस्थाओ से विभेद रखने तथा यूरोपीय फर्मों तथा सस्थाओ के प्रति अनुचित पक्षपात दिखाने का आरोप भी लगाया गया । बैक द्वारा घोषित अत्यधिक लाभारा का मेल राष्ट्रीय कल्याण की वृद्धि क उद्देश्य के साथ नहीं बैठता था, जिसक लिए इस बैक की सृष्टि हुई थी । बैक तथा राज्य के बीच मुनाफे व बंटवारे के लिए कोई भी प्रबन्ध नहीं था । १९२० के एक्ट व अन्तर्गत बैक के ऊपर राज्य का उतना प्रभावशाली नियन्त्रण नहीं था जितना होना चाहिए, क्योंकि मुद्राव्यक्ष द्वारा हस्तक्षेप की सम्भावना तभी की जानी थी जबकि राज्य का हित खतरे मे पड गया हो । बैक की शाखा

खोजन की नीति बहुत सफल नहीं रही। कभी-कभी तो य शालाएँ ऐसी जगहों में खोली गईं जहाँ पहले से ही अन्य बैंकों की पर्याप्त सुविधाएँ प्राप्य थी और इस प्रकार तत्कालीन अन्य भारतीय बैंकों के साथ उस इम्पीरियल बैंक की अनुचित स्पर्धा हुई जिसे रिजर्व बैंक की स्थापना के पूर्व विशेष अधिकार प्राप्त थे और जिसका सरकारी कोष के ऊपर अधिकार था। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि बैंक को बहुत ही थोड़े कार्यों का दायित्व सुनिश्चित किये जाने के कारण इसकी कुछ भी उपयोगिता नहीं रह पाती। सरकार द्वारा किये जाने योग्य बैंकिंग तथा मुद्रा-सम्बन्धी कार्य करने के सम्बन्ध में यूरोप के बैंकों के साथ इस बैंक की बहुत ही कम समानता थी। इसको केवल सरकारी भेद रकम रखने तथा बैंकिंग के साधारण कारोबार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कागजी मुद्रा, स्वर्ण-मानकोष तथा भारत सरकार के इंग्लैण्ड में खर्च के भुगतान के लिए भेजे जाने वाली रकम का प्रबन्ध स्वयं सरकार ही करती थी। नोट छापने का अधिकार अपने हाथ में न होने के कारण इम्पीरियल बैंक बैंक-दर की सहायता से उतनी अच्छी तरह से द्रव्य-वाञ्छार पर नियन्त्रण नहीं कर सकता था जैसा अन्य बड़े-बड़े केन्द्रीय बैंक किया करते हैं।

३३ इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया सशोधन एक्ट, १९३४—यह सर्वसम्मत बात थी कि देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक की स्थापना के पश्चात् इम्पीरियल बैंक के मिश्रित रूप के कारण इसके ऊपर रखे गए नियन्त्रण को हटाने तथा इसके कार्य के ऊपर सरकारी नियन्त्रण में सशोधन की दृष्टि से इम्पीरियल बैंक के विधान को बदलना आवश्यक होगा। अतः १९३४ में रिजर्व बैंक बिल के पारित होने के साथ-ही-साथ इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट (१९३४ का तीसरा) के रूप में इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया सशोधन बिल को भी पारित किया गया।^१ सशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन किये गए—

(१) बैंक के विधान में परिवर्तन—केन्द्रीय परिषद् की स्थापना निम्नलिखित सचालकों को मिलाकर की गई—(क) इस कानून द्वारा स्थापित स्थानीय परिषदों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, (ख) इस कानून द्वारा स्थापित हर स्थानीय परिषद् के सदस्यों में से ही उन्हीं द्वारा चुना गया एक सदस्य, (ग) केन्द्रीय परिषद् द्वारा ५ वर्ष के लिए नियुक्त एक प्रबन्ध सचालक, जिसे वह परिषद् अधिक से-अधिक और ५ वर्ष के लिए रख सकती है, (घ) गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल द्वारा मनोनीत अधिक-से अधिक दो सदस्य जो सरकारी अफसर न हों, (च) केन्द्रीय परिषद् द्वारा नियुक्त एक उप-प्रबन्ध-सचालक, (छ) लोकल बोर्डों के सचिव, (ज) इस कानून द्वारा स्थापित किसी नई स्थानीय परिषद् का प्रतिनिधित्व करने वाले वे सदस्य, जिनकी व्यवस्था केन्द्रीय परिषद् ने की हो। (च) तथा (छ) में निर्दिष्ट सचालकों को केन्द्रीय परिषद् की सभा में मत देने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार बैंक के कारोबार पर से सरकारी

१. इम्पीरियल बैंक को केन्द्रीय बैंक में रूपान्तरण करने के सरकार के निर्णय के सम्बन्ध में आगे सेक्शन ३६ देखिए।

नियन्त्रण अब कम हो गया। (२) इम्पीरियल बैंक अब सरकार का महाजन नहीं रह गया (रिजर्व बैंक ने अब यह पद ग्रहण कर लिया), पर उसे रिजर्व बैंक के साथ इकरार करने का यह अधिकार प्रदान किया गया कि वह उसके एकमात्र एजेंट रूप में सरकारी कारोबार का प्रबन्ध कर सके (आगे सेवशन ४१ में यह और भी स्पष्ट है।)

(३) बैंक के लन्दन शाखा के कार्यों पर लगाये गए पुराने प्रतिबन्ध हटा लिये गए। बैंक को भारतवर्ष तथा विदेशों में शाखाएँ या एजेन्सियाँ स्थापित करने की छूट दी गई। (४) केन्द्रीय परिषद् को यह अधिकार प्रदान किया गया कि पहले में गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल की आज्ञा लिये बिना भी वह स्थानीय परिषदों की स्थापना या अपनी पूँजी बढ़ाए। (५) बैंक के कारोबार-सम्बन्धी कुछ प्रतिबन्धों को हटाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित परिवर्तन किये गए—बैंक को विदेशों में चुकता होने योग्य हुण्डियों को खरीदने, भारत से बाहर रुपया उधार लेने तथा विदेशी विनिमय-कार्य करने के अधिकार प्रदान किये गए। मौसमी कृषि-कार्यों की वित्तीय व्यवस्था-सम्बन्धी पेशगी तथा कर्ज की (भुगतान की हुण्डी की भी) अवधि को बढ़ाकर ६ से ६ महीने तक कर दिया गया। बैंक को यह अधिकार था कि वह किसी ऐसी चल या अचल सम्पत्ति, जो किसी ऋण या पेशगी के लिए जमानत हो या जमानत से सम्बद्ध हो, सम्बन्धी अधिकार को प्राप्त करे, अपने अधिकार में रखे तथा अपने काम में लाए। रिजर्व बैंक के हिस्से की म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकारान्तर्गत गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल की आज्ञा से निर्गमित ऋण पत्र, देशी राजाओं के अधिकारान्तर्गत निर्गमित ऋण-पत्रों तथा केन्द्रीय बोर्ड की आज्ञानुसार सीमित दायित्व वाली कम्पनियों के ऋण-पत्रों पर रुपया पेशगी और कर्ज देने तथा रोक-ऋणखाला खोलने का भी अधिकार बैंक को प्रदान किया गया। बैंक को यह भी अधिकार दिया गया कि अगर केन्द्रीय परिषद् विशेष आज्ञा दे तो जमानत पर रेहन की गई वस्तु के आधार पर पेशगी या रोक-ऋण दिया जा सकता है। कुछ पुराने प्रतिबन्ध (जैसे जमीन के रेहन, या पेशगी और ऋण की अवधि (पूर्व-वर्णित सशोधनों के साथ), व्यक्तियों को दिये जाने वाले ऋण की मात्रा-सम्बन्धी तथा बैंक के हिस्से पर कर्ज देने के नियम इत्यादि) अब भी चलते रहे।

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया—ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिश मानकर भारत सरकार ने ५ जुलाई, १९५५ से इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया। उसका नया नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया है जिसको इम्पीरियल बैंक के सभी आदेय और दायित्व हस्तांतरित कर दिये गए।

स्टेट बैंक का संचालन १८-२० संचालकों के एक केन्द्रीय संचालक मण्डल द्वारा किये जाने की व्यवस्था है जो निम्न प्रकार से निर्वाचित या मनानीत होगे—

(१) स्टेट बैंक के सभापति तथा उपसभापति, जिन्हें रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार नियुक्त करेगी।

(२) रिजर्व बैंक तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत एक-एक सचालक ।

(३) क्षेत्रीय अथवा आर्थिक हितों के प्रतिनिधित्व हेतु रिजर्व बैंक के परामर्शसहित केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत आठ सचालक ।

(४) रिजर्व बैंक को छोड़कर अन्य हिस्सेदारों द्वारा निर्वाचित छः सचालक ।

(५) भारत सरकार की स्वीकृति से स्टेट बैंक के केन्द्रीय सचालक-मंडल द्वारा मनोनीत सदस्य, जिनकी सख्या दो तक हो सकती है ।

जहाँ रिजर्व बैंक की शाखा नहीं है तथा जहाँ वह स्टेट बैंक से कहे वहाँ स्टेट बैंक—यदि उसकी वहाँ शाखा है तो—रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि रूप में काम करेगा । भारत सरकार की अनुमति से स्टेट बैंक अन्य बैंकों के कारोबार, आदेय व दायित्व कम कर सकता है ।

स्टेट बैंक इम्पीरियल बैंक की भाँति उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय की सेवा करेगा और बैंकिंग विकास को तीव्र बनाएगा । गोदाम और वित्री-विकास हो जाने पर यह आशा की जाती है कि स्टेट बैंक ग्रामीण साक्ष प्रसार का महत्त्वपूर्ण साधन सिद्ध होगा । अगले पाँच वर्षों में वह ४०० शाखाएँ खोलेगा, द्रव्य भेजने की अधिक सुविधाएँ देगा और ग्रामीण बचत प्राप्त करने में योग्य भी देगा ।

१९५६ तक स्टेट बैंक ने ३५६ शाखाएँ खोल दी थी । इसी वर्ष स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (सब्जिडियरी बैंक्स) सहायक बैंक अधिनियम पास हुआ, जिसे १० सितम्बर १९५६ को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की । इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य से सम्बन्धित आठ बैंकों—बैंक ऑफ वीकानेर, बैंक ऑफ इन्दौर, बैंक ऑफ जयपुर, बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ पटियाला, ट्रावनकोर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद तथा स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र—को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के सहायक बैंकों के रूप में संगठित किया गया । इसी वर्ष स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (सशोधन) अधिनियम भी पास किया गया, जिसे राष्ट्रपति ने २८ अगस्त १९५६ को स्वीकृति प्रदान की । सशोधन अधिनियम की धाराएँ स्पष्टीकरण तथा स्टेट बैंक एक्ट की धारा ३५ के अन्तर्गत स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा किसी बैंक के कार्य को ले लेने की पद्धति सरल बनाने के लिए हैं ।

३४. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट १९३४—१९३३ में प्रकाशित भारतीय सुधार-सम्बन्धी श्वेतपत्र में यह शर्त रखी गई कि केन्द्र को वित्तीय जिम्मेदारी सौंपने के पूर्व यह आवश्यक है कि भारतीय व्यवस्थापिका सभा राजनीतिक प्रभावों से रहित एक रिजर्व बैंक की स्थापना करे । जुलाई, १९३३ में रिजर्व बैंक विधेयक-सम्बन्धी लन्दन समिति ने इस प्रस्ताव का सपरीक्षण फिर किया । इस समिति ने अगस्त, १९३३ में अपनी रिपोर्ट दी तथा इसी की सिफारिश के आधार पर निर्मित रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बिल की ८ सितम्बर, १९६३ को व्यवस्थापिका सभा में प्रस्तुत किया गया और ६ मार्च, १९३४ को इसने अधिनियम का रूप धारण कर लिया ।

(१) यह निर्णय हुआ कि यह बैंक हिस्सेदारों का बैंक होगा । मूल पूँजी ५ करोड़ रुपये की होगी जो पूर्णतया प्राप्त हिस्सा तथा सौ सौ रुपये के हिस्सों में

बंटी हुई होगी। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास तथा रगून में हिस्सेदारों के अलग-अलग रजिस्टर रखे गए। इन खानों में पहले से निर्दिष्ट किये गए हिस्सों का नामांकित मूल्य इन प्रकार था—बम्बई १४० लाख रुपया, कलकत्ता १४५ लाख, दिल्ली ११५ लाख, मद्रास ७० लाख तथा रगून ३० लाख। बाद में होने वाले हस्तांतरण की वजह से हिस्सों के क्षेत्रीय वितरण में अत्यधिक परिवर्तन आ गए तथा बोटों के एक्त्रीकरण और उनको निष्फल करने की प्रवृत्ति विशेषतः बम्बई क्षेत्र में अत्यधिक बढ़ गई। अप्रैल १९३५ से ३० जून १९४० तक हिस्सेदारों की संख्या ६२,०४७ से घटकर ५६,०५७ हो जाने से यह स्पष्ट है। अतः बैंक के हिस्से को थोड़े लोगों के हाथों में एकांकित होने से रोकने के उद्देश्य से मार्च, १९४० में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में संशोधन किया गया। इस संशोधन द्वारा यह निर्धारित हुआ कि अगर किसी व्यक्ति ने मार्च, १९४० के बाद अकेले या सम्मिलित रूप से किसी ऐसे अनिश्चित हिस्से को प्राप्त किया है, जिससे उसके नाम के कुल हिस्सों का कुल मूल्य २०,००० रुपये से अधिक हो जाता है तो वह इस हिस्से के लिए हिस्सेदार निवृत्त नहीं किया जा सकता।^१

३५. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया कार्यरूप में—१ अप्रैल, १९३५ को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का उद्घाटन हुआ और बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास तथा रगून में इसके कार्यालयों की स्थापना हुई। बाद में कानून द्वारा विधित सन्धन में भी एक शाखा खोलने की व्यवस्था की गई।

इसने बैंकिंग कम्पनी से सम्बन्धित नये विधानों को इण्डियन कम्पनीज एक्ट में समावेश करने के सम्बन्ध में बहुमूल्य राय दी तथा भारतवर्ष में बैंक एक्ट बनाने का लाभकारी प्रस्ताव १९३६ में रखा। इसमें देश के अन्तर्गत रुपया भेजने की सस्ती सुविधा दी है तथा व्याज की दर कम करने में सहायता की है। देश में बैंक की सुविधा के विस्तार के लिए भी इसने अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन दिया है।

इसने केवल अनुसूचित बैंकों, जो विधिवत् सदस्य-बैंक हैं, के ही साथ लाभकर सम्पर्क स्थापित नहीं किया बल्कि अग्रणी छोटे-छोटे गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ भी दान तथा साख के अधिकारों की हैसियत से विगत युद्धकाल में अनेक कठिनाइयों को बड़ी चतुरापूर्वक मेलकर द्रव्य-वाञ्छार में स्थिरता लाने में योगदान दिया। “यह स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक व्याज-दर को उन मौसमी विभिन्नताओं को दूर करने में अत्यधिक हिस्सा लेता रहा है, जिनका भारतवर्ष के भविष्य की आर्थिक स्थिति पर बहुत ही प्रभाव पड़ता।”^२ इसने कृषि-साख तथा सहकारी आन्दोलन के अध्ययन के सम्बन्ध में बहुत काम किया है और ग्रामीण साख-संगठन-सम्बन्धी अनेक बुद्धियों को दूर करने के सम्बन्ध में भी बहुमूल्य सुझाव दिए हैं।

३६ रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (सार्वजनिक स्वामित्व का हस्तान्तरण) एक्ट

१. रिजर्व बैंक का वार्षिक विवरण (अगस्त, १९६०), पृ० ६।

२. सुरेन्द्र, ‘मॉडर्न बैंकिंग इन इण्डिया’, प्रथम उद्धारण, पृष्ठ २८५।

१९४८—बैंक को राज्य-अधिकृत सत्या का रूप देने के सरकारी निर्णय को कार्य-रूप में परिणत करने के उद्देश्य से इस अधिनियम को पारित किया गया, जिससे इसके कार्यों का नियन्त्रण सार्वजनिक हित के लिए किया जा सके तथा द्रव्य सम्बन्धी आर्थिक एवं वित्तीय नीति के बीच समन्वय स्थापित हो सके। १ जनवरी, १९४९ को यह कानून लागू हो गया तथा बैंक की पूंजी के सारे हिस्सों को केन्द्रीय बैंक द्वारा हस्तान्तरित समझा गया।

शाखाएँ और कार्यालय—बैंक का मुख्य कार्यालय बम्बई में है। बैंक को जो कार्य सौंपे गए हैं उन्हें सम्पूर्ण देश में सन्तोषप्रद ढंग से करने के लिए रिजर्व बैंक ने स्थानीय कार्यालय-शाखाएँ बंगलौर, बम्बई, बलकत्ता, बानपुर, मद्रास, नागपुर और नई दिल्ली में स्थापित की है। इनमें दो तो ही—बैंकिंग और निर्गम—विभाग हैं। अन्यत्र इसका प्रतिनिधित्व इसके एजेण्ट करते हैं। इसके अलावा रिजर्व बैंक की बैंकिंग विभाग की एक शाखा लन्दन में भी है। बैंकिंग विभाग के प्रादेशिक कार्यालय बंगलौर को छोड़कर उपर्युक्त स्थानों तथा त्रिवेन्द्रम में है। कृषि-साल विभाग के प्रादेशिक (रीजनल) कार्यालय बलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली में हैं तथा विनियम नियन्त्रण विभाग के कार्यालय कलकत्ता, मद्रास, नई दिल्ली और कानपुर में हैं।

प्रबन्ध—इस समय बैंक के कार्यों की देखभाल १५ सदस्यों से निर्मित केन्द्रीय संचालक परिषद् (सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ डाइरेक्टर्स) के हाथ में है।

छः संचालक अधिनियम की धारा ८ (१) (स) के अन्तर्गत तथा एक सरकारी अधिकारी धारा ८ (१) (द) व अन्तर्गत नियुक्त होता है। धारा ८ (१) (स) के मन्तव्य संचालको की कार्यवाही चार साल होती है और वे बारी बारी (रोटेशन) से अवकाश ग्रहण करते हैं। धारा ८ (१) (ब) के अन्तर्गत संचालको की कार्यवाही स्थानीय परिषद् की सदस्यता पर निर्भर होती है। केन्द्रीय संचालक परिषद् की बैठक वर्ष में कम-से-कम छ माह तथा तीन माह में कम-से-कम एक बार अवश्य होनी चाहिए। व्यावहारिक सुविधा के लिए परिषद् ने अपने कुछ कार्य एक समिति को सौंप दिए हैं जिसकी बैठक गवर्नर के मुख्य कार्यालय में प्रति सप्ताह होती है।

केन्द्रीय संचालक परिषद् का अध्यक्ष तथा बैंक का मुख्य प्रशासकीय अधिकारी गवर्नर होता है। उसके सहायक तीन उप-गवर्नर होते हैं।

रिजर्व बैंक के कार्य—रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया अधिनियम १९३४ की प्रस्तावना में कहा गया है कि बैंक का मुख्य कार्य देश में स्थिरता रखने की दृष्टि से नोट निर्गमन का नियमन तथा सुरक्षित कोष रखना तथा देश के हित में सख्त व्यवस्था का संचालन करना है। (१) बैंक को नोट निर्गमन का एकमात्र अधिकार है। (२) रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों, जिनमें राज्तीय सहकारी बैंक भी सम्मिलित हैं, के बैंकर के रूप में कार्य करता है। उनका नकद कोष (केश रिजर्व) रिजर्व बैंक की सुरक्षा में रहता है तथा वह इन्डियानुसार उन्हें सहायता (एकमोडेसन) प्रदान करता है। (३) रिजर्व बैंक साल-ब्यवस्था का नियमन करता है। इस कार्य

के लिए वह बैंक दर, खुले बाजार कार्यों (मोनन मार्केट ऑपरेशन) के सामान्य उपायों के अतिरिक्त अधिकोपीय अधिनियम १९४६ (बैंकिंग कम्पनीज एक्ट १९४६) के अन्तर्गत धरनिन साख नियंत्रण (नेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल) तथा प्रत्यक्ष साख नियमन का प्रयोग कर सकता है। (४) रिजर्व बैंक का एक अन्य मुख्य कार्य सरकार के बैंकिंग और वित्तीय कार्यों का सम्पादन करना है। (५) एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य रुपये के विनिमय मूल्य को स्थिर रखना है। राष्ट्र के आर्थिक विकास और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में पतिल्ल सम्बन्ध होने के कारण यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इन कार्यों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षित कोष (इण्टरनेशनल रिजर्व) रिजर्व बैंक की सरक्षता और प्रबन्ध के अन्तर्गत रहना है।

देश में आर्थिक विकास की बढ़ती हुई गति के साथ बैंक के कार्यों की परिधि में लगातार विस्तार हो रहा है। अनेक कार्यों, जो पहले केन्द्रीय बैंक के क्षेत्र से बाहर समझे जाते थे, रिजर्व बैंक द्वारा किये जा रहे हैं।

नोट निर्गमन—मूल अधिनियम के अन्तर्गत नोट निर्गमन के लिए स्वर्ण और विदेशी प्रतिभूतियों का आनुपातिक सुरक्षा कोष निर्धारित किया गया था। इसके अनुसार कुल आदिये का ४० प्रतिशत स्वर्ण और स्वर्णमुद्रा तथा विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में होना चाहिए, किन्तु सोने का मूल्य ४० करोड़ २० से कम न होना चाहिए। यह व्यवस्था लगभग २० वर्ष तक रही। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (यशोधन) अधिनियम १९५६ ने आनुपातिक सुरक्षा पद्धति के स्थान पर एक विदेशी सुरक्षा कोष की निरूपेक्ष रानि निर्धारित कर दी। १९५६ से ४०० करोड़ ६० की विदेशी प्रतिभूतियाँ तथा ११५ करोड़ ६० का स्वर्ण या स्वर्णमुद्रा सुरक्षित कोष के रूप में रखा जाने लगा। द्वितीय यशोधन अधिनियम १९५७ पास किया गया। इसके अनुसार निर्गम विभाग के स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण तथा विदेशी प्रतिभूतियों का कुल मूल्य २०० करोड़ ६० से कम नहीं होना चाहिए। इनमें स्वर्ण मुद्रा और स्वर्ण का मूल्य ११५ करोड़ ६० से कम नहीं होना चाहिए।

विदेशी विनिमय—केन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक का एक मुख्य कार्य रुपये के बाह्य मूल्य को स्थिर रखना है। भारत के विदेशी लेन-देन का ७०% स्टर्लिंग में, १०% डालर में तथा शेष रुपये में होता है अतएव पीण्ड स्टर्लिंग और रुपये का सम्बन्ध अब भी बना हुआ है। रुपये और स्टर्लिंग की विनिमय दर अब भी १ सि० ६ पैसे प्रति रुपया है। यह दर १९२७ में निर्दिष्ट हुई थी और तब से अब तक चली आ रही है। बैंक के विदेशी विनिमय-सम्बन्धी दायित्व रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट की धारा ४० के अन्तर्गत निर्धारित है। विदेशी विनिमय के नियन्त्रण द्वारा भी रिजर्व बैंक अपने उत्तरदायित्व को पूरा करता है।

अनुसूचित तथा गैर-अनुसूचित बैंक—रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद सम्मिलित पूँजी वाली बैंक दो वर्गों में विभाजित हो गई—(१) अनुसूचित तथा गैर-अनुसूचित। अनुसूचित बैंक वे हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित हैं। इनकी तुलना ५० एस० ए० की सदस्य-बैंकों से की जा सकती है।

अनुसूचित बैंको को रिजर्व बैंक से कुछ सुविधाएँ प्राप्त होती है और साथ ही कुछ दायित्व भी होते हैं। निम्न जतों को पूरा करने पर ही कोई बैंक अनुसूचित हो सकती है। (१) बैंक की परिदत्त पूँजी तथा कोप (रिजर्व) का कुल मूल्य ५ लाख ६० से कम नहीं होना चाहिए। (२) रिजर्व बैंक को इस बात का विश्वास होना चाहिए कि उसकी कार्यवाही निक्षेपको (रूपया जमा करन वालो) के विरुद्ध नहीं है। (३) १९५६ के कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक कम्पनी होनी चाहिए या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित संस्था या भारत के बाहर विधान के अन्तर्गत (जो लागू हो) कारपोरेशन या कम्पनी होनी चाहिए। मार्च, १९५८ में ४०० बैंकिंग कम्पनियों में से ६२ अनुसूचित बैंक थीं। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम की धारा ४२ (१) के अन्तर्गत अनुसूचित बैंको को रिजर्व बैंक के पास माँग दायित्व (डिमाण्ड लाइबिलिटी) तथा सावधि दायित्व (टाइम ला. लिबिलिटी) का नमूना कम-से-कम ५% और २% तक कोप रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। ११ मार्च १९६० को एक अधिसूचना द्वारा सभी अनुसूचित बैंको के लिए यह आवश्यक हो गया कि वे माँग-दायित्व तथा सावधि दायित्व की वृद्धि का २५% अतिरिक्त निक्षेप के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखें, किन्तु किसी भी समय यह माँग-दायित्व के २०% तथा सावधि-दायित्व के ८% से अधिक न होना चाहिए क्योंकि ये (अधिनियम द्वारा निश्चित) अधिकतम दरें हैं। ६ मई १९६० को पूर्व अधिसूचना को रद्द कर एक नई अधिसूचना निकाली गई, जिसके अनुसार, (१) ११ मार्च १९६० की तुलना में ६ मई, १९६० को कुल दायित्व (सावधि तथा माँग) की वृद्धि का २५ प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखा जाए तथा (२) ६ मई १९६० के बाद कुल दायित्वों में जो वृद्धि हो उसका ५० प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखा जाए। रिजर्व बैंक ने इन अतिरिक्त निक्षेपों के लिए व्याज देना स्वीकार किया। यह निश्चय किया गया कि व्याज हर छमाही दिया जाए तथा व्याज की दर उस छमाही के लिए अनुसूचित बैंक द्वारा दी जाने वाली व्याज दर से $\frac{1}{2}$ प्रतिशत ज्यादा हो, किन्तु ४ $\frac{1}{2}$ प्रतिशत से अधिक न हो।

कृषि साख विभाग—रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम की धारा ५४ के अन्तर्गत अप्रैल १९३५ में कृषि साख विभाग की स्थापना की गई। प्रारम्भ में उसके परिचालित कार्यों में कृषि-साख से सम्बन्धित प्रश्नों के अध्ययन हेतु विशेषज्ञ को रखना तथा कृषि सख प्रदान करने वाली संस्थाओं—जैसे राज्तीय सहकारी बैंक और रिजर्व बैंक—के कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करना था। ग्रामीण अर्थ-प्रबन्धन के विस्तार के साथ-साथ कृषि साख विभाग के कार्यों का भी विस्तार हो गया है। १९५६ में कृषि-उत्पत्ति (विकास और भण्डार) निगम अधिनियम के पास होने के बाद यह विभाग कृषि उत्पत्ति के विक्रय को सुविधाजनक बनाने के लिए भण्डार गृहों के देश यापी संगठन की स्थापना के लिए केन्द्रीय और राज्तीय सरकारों से सहयोग करता है। इस समय इसका कार्य चार भागों में विभाजित है—(१) वित्त और निरीक्षण, (२) नियोजन और पुनर्संगठन, (३) सहकारी प्रशिक्षण और प्रकाशन तथा (४) दृष्ट

करधा वित्त । प्रत्येक एक उप-मुख्य-अधिकारी (डिप्टी चीफ अफसर) के अन्तर्गत है । कृषि साख विभाग के प्रादेशिक कार्यालय भी बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली में स्थापित किये गए हैं ।

३७ १९३९ के बाद भारतीय बैंकिंग—द्वितीय महायुद्ध के विस्फोट तथा दिसम्बर, १९४१ में जारानी युद्ध क प्रारम्भ होने के तुरन्त बाद ही भय के कारण जनता बैंको से अपना रुपया वापस करने लगी, पर थोड़े ही दिनों बाद जनता न इस त्रास की निरर्थकता को महसूस कर लिया और अपने को युद्ध की परिस्थिति के अनुकूल बनाने में समर्थ हो गई । १९३९ में अनुमूचित बैंको का निक्षेप-दायित्व २४९ ४५ करोड़ रुपये का था, पर जुलाई १९४४ के अन्त तक यह बढ़कर ७५९ २९ करोड़ रुपय हा गया । इसके दो मुख्य कारण हैं—बैंकिंग तथा राजस्व का घनिष्ठ सम्बन्ध तथा लड़ाई के कारण मुद्रा-प्रसार, जो साख को और भी अधिक बढ़ाने में सहायक होता है ।

अवधि-निक्षेप (टाइम डिपोजिट) को अपना माँग-निक्षेप में अधिक वृद्धि हुई, जिसका कारण था जनसाधारण द्वारा तरलता को अविमान दिया जाना । वे अपना रुपया पूँजी-रूप में न लाकर लाभदायक विनियोग के अवसर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे ।

माँग-दायित्व के अपेक्षाकृत बड़ जान के कारण बैंक अपनी स्थिति को अत्रिकाधिक तरल रख रहे थे । पशगी तथा हुण्डियाँ (जो बैंक के आदेय के लाभकारी मद हैं) तो बड़ रही थी, पर कुल निक्षेप में उनका प्रतिशत १९३९ में ५३ था जो १९४४ में केवल ३० रह गया । इसके दो मुख्य कारण थे—युद्ध के समय में व्यावसायिक विनियोग का अवसर कम हो गया तथा बैंको न अपनी रकम को युद्ध ऋण (वार-नोन्स) में लगा दिया । उपर्युक्त अधिक तरलता की इच्छा न हो सरकारी प्रतिभूतियों में रुपया लगाने की प्रेरणा दी । हिस्सा-पूँजी तथा रक्षित काय की रकम भी बड़ी पर वह निक्षेप जितनी न बढ़ सकी । १९४५ के मध्य में, जबकि युद्ध का अन्त समीप ही था, माँग तथा अवधि-दायित्व का असम अनुपात स्वयं ही ठीक होने लगा । १९४६ ४७ में रिजर्वे वर्क के समान माँग-निक्षेप की अपेक्षा अवधि-निक्षेप अधिक तेजी से फल बड़े ही नहीं बल्कि जिस समय माँग-निक्षेप में कम होने की प्रवृत्ति थी उस समय भी अवधि-निक्षेप बढ़े । इससे स्पष्ट था कि जनता क तरलता-अविमान (क्विविडिटी प्रेफरेंस) में ह्रास होने लगा तथा निक्षेप का टाँचा युद्ध-पूर्व की स्थिति के समान बदल रहा था ।

१९१४ १९ के युद्ध की तरह १९३९-४५ के द्वितीय विश्व-युद्ध में द्रव्य-सम्बन्ध स्थिति तग तथा बैंक-दर ऊँची नहीं हुई । व्याज की दर पर कठोर नियन्त्रण युद्ध के खर्च को पूरा करने की नई शैली रही है तथा इसकी सफलता इसी से सिद्ध हा जाती है कि अत्यधिक बड़े सार्वजनिक व्यय तथा सरकार द्वारा अत्यधिक उधार लेन की अपेक्षा होते हुए भी ब्रिटेन तथा भारत क द्रव्य-सम्बन्धी अधिकारी व्याज की दर को कम बनाये रहे हैं ।

प्रथम युद्ध क सहस्र विगन युद्ध में भारतीय बैंको के नकद कोष की स्थिति

को अधिक सक्षम ही बनाया है। निकासी गृह के माध्यम से होने वाले भुगतान का सन् १९३८-३९ में २०.०३ अरब रुपये से बढ़कर १९४४-४५ में ५६.१७ अरब रुपया हो जाना भी प्रगति का ही सूचक है। १९४५-४६ तथा १९४६-४७ के क्रमशः ६५.४२ अरब रुपये तथा ७१.६८ अरब रुपये हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि भारतीय बैंकिंग पद्धति ने अत्यधिक जीवन-शक्ति दिखाई है तथा युद्ध ने साधारणतया इसे और भी सशक्त बनाया है।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारतीय बैंको की प्रगति में दो उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। देश-विभाजन के बाद बैंको तथा उनकी शाखाओं की संख्या तथा उनके निक्षेपों में ह्रास ही रहा था, परन्तु १९५३ के पश्चात् दोनों ही में पुनः वृद्धि की प्रवृत्ति स्पष्ट है। १९५४ में यद्यपि बैंको की संख्या में २३ की कमी हुई, परन्तु शाखाओं को लेकर कुल बैंको की संख्या में २२ की वृद्धि हुई। वृद्धि अधिकतर अनुसूचित बैंको में हुई थी। गैर-अनुसूचित बैंको में तो ह्रास ही हुआ है। १९५४ में बैंको में कुल निक्षेप १०६३ करोड़ रुपये थे, जो दो साल पहले की अपेक्षा लगभग १०० करोड़ रुपये अधिक है। इस वर्ष प्रति साठे दस हजार व्यक्तियों के पीछे एक बैंक है। यह भी उल्लेखनीय है कि ५५% अनुसूचित बैंक तथा ३३% गैर-अनुसूचित बैंक ५०,००० से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में स्थित हैं। मिश्रित पूँजी वाले बैंको की विदेशों में १०७ शाखाएँ हैं।

१९५५ में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना भारतीय बैंकिंग की एक महत्वपूर्ण घटना है। स्टेट बैंक का परिचालित कार्य शाखाओं के विकास द्वारा बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार करना है। कुछ राज्यों की बैंको को स्टेट बैंक की सहायक बनाने तथा करेन्सी रिजर्व को घटाकर २०० करोड़ ६० निश्चित करने के अधिनियम की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। १९५४ के सचोद्यन अधिनियम के अन्तर्गत रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि सार्व (दीर्घकालीन) कोष की स्थापना की। इस कोष के लिए कम-से-कम ५ करोड़ ६० प्रतिवर्ष का अनुदान पाँच वर्ष तक देने की व्यवस्था है। कोष की स्थापना १० करोड़ ६० से हुई। इसका उद्देश्य राज्य सरकारों को ऋण देना है ताकि वे सहकारी समितियों की हिस्सा पूँजी खरीद सकें। १९५७ में अनुसूचित बैंको की संख्या ६१ थी तथा इनके कार्यालयों की संख्या ३२७३ थी। १९५६ में अनुसूचित बैंको की संख्या ८६ थी और कार्यालयों की संख्या २६६४ थी।

तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हो रही है। वित्तीय व्यवस्था का आधार होने के कारण बैंको को इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करना है। अतएव उन्हें भावी आवश्यकताओं के लिए अपने-आपको सक्षम बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। नियोजन के फलस्वरूप बैंको को व्यापार की नई दिशाओं में प्रवेश करना ही होगा। इस दृष्टि से निश्चित समय के लिए रुपया उधार देने का काम अवश्य ही एक नई दिशा है। अतएव उन्हें इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। १९५८ में रिफाइनेन्स कारपोरेशन की स्थापना के बाद इस दिशा में कार्य करने की सुविधा और बढ़ गई है, क्योंकि रिफाइनेन्स कारपोरेशन प्रतिशोधन (रिम्बर्समेंट) की सुविधा प्रदान करता है

ताकि वे मध्यकालीन अग्रिम सरलता से दे सकें। १९६० के 'ट्रेन्ड्स एण्ड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इण्डिया' (प्रकाशित जून १९६१) में कहा गया है कि तृतीय योजना के अन्त तक बैंकिंग व्यवस्था द्वारा सम्पादित कार्य लगभग दूना हो जाएगा। तृतीय योजना की चुनौती स्वीकार करने के लिए बैंकों को निक्षेप प्राप्त करने के प्रयत्न बढ़ाने चाहिए। उपर्युक्त प्रकारान में इस हेतु तीन सुझाव दिये गए हैं—(१) अग्रिम नाचाएँ खोली जाएँ। (२) निक्षेपकों में विश्वास उत्पन्न किया जाए। (३) व्यापार नई दिशाओं में मोटा जाए।

३. औद्योगिक वित्त—औद्योगिक वित्त की सुसंगठित पद्धति का अभाव भारत के आर्थिक ढाँचे की सबसे बड़ी कमी है। जर्मनी के बैंकों ने अपने देश के उद्योगों की आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति में अत्यधिक योग दिया है। वे उद्योगों की प्रारम्भिक पूँजी के अधिकांश भाग का बन्दोबस्त करते हैं, जिसे कालान्तर में विनियोग करने वालों से प्राप्त कर लेते हैं। जोखिम को आपस में बाँटने के उद्देश्य से अनेक बैंक अपने सघ (कोन्सोसियम) बना लेते तथा निर्गमन हिस्सों के कुछ अंश को लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। पर औद्योगिक कम्पनियों के हिस्सों में बैंकों का यह विनियोग औद्योगिक बैंकों द्वारा किए विनियोग के सहन दीर्घकालीन विनियोग नहीं है, बल्कि इसे बैंक के साधनों की प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों के विनियोगों की भाँति सुरक्षित विनियोग समझा जाता है, जिसे बैंक अल्पकाल के लिए करते हैं। इन कारणों से बैंकों को लाभ ही होता है, क्योंकि इस प्रकार उन्हें व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित करने तथा अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिलता है। नई पूँजी की प्राप्ति करने के लिए जर्मन औद्योगिक कम्पनियाँ सामान्यतः उन्हीं बैंकों से पूँजी की माँग करती हैं जिनके साथ उनका स्थायी बैंक-व्यवहार है। पर यह बात स्मरणीय है कि बैंक अपने साधनों का एक सीमित अंश ही औद्योगिक वित्त में लगाते हैं तथा उनका प्रधान कार्य बैंक का साधारण कारोबार करना ही होता है।^१ केन्द्रीय अधिकोषण खोज-समिति ने जर्मन पद्धति को यथोचित संशोधनों के पश्चात् अपना लेने का स्वागत किया तथा यह सुझाव रखा कि इस दिशा में ह्याति प्राप्त व्यापारिक बैंक कार्य का शीघ्र शोध करें। इस कार्य में अत्यधिक अनुभव तथा विवेक के अतिरिक्त अधिक निजी पूँजी होनी चाहिए एवं प्रतिभूतियों के निर्गमन तथा विनियोग में सट्टेबाजी के प्रलोभन का संवरण करना आवश्यक है। ये गुण आज के थोड़े से ही बैंकों के पास हैं। अगर देश के प्रमुख बैंकों को उद्योगों के प्रति सच्चा तथा सहानुभूतिपूर्ण अनुग्रह हो तो इन कठिनाइयों के होते हुए उद्योगों को काफी वित्तीय सहायता दी जा सकती है। जर्मन नमूने का अनुकरण कुछ हद तक हम पारस्परिक विश्वास की सृष्टि करने के लिए कर सकते हैं, वरन् स्वस्थ बैंकिंग से असंगत उलझनों से बचे रहे। बैंकों के प्रबन्ध-

१. 'इण्डस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन इन इण्डिया' के पृष्ठ २४१-४२ पर डॉ० पी० एस० लोकनाथन यूरोपीय श्रेणी निक्षेप बैंकिंग के अनुकूल भारतीय व्यावसायिक बैंकिंग के निरूपण की कठिनाइयों का स्पष्ट करते हैं।

सचालको तथा प्रबन्धको की सम्बन्धित उद्योगो के सचालको के रूप मे नियुक्त करके बैंको तथा उनसे सहायता पाने वाले उद्योगो के बीच उपयोगी सम्बन्ध स्थापित कर सकते है ।

उपर्युक्त व्यावसायिक बैंको के सहयोग द्वारा नि सन्देह ही बहुमूल्य परिणाम की आशा की जा सकती है, पर केवल इसी विधि द्वारा पर्याप्त औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति सम्भव नहीं है । अपने-अपने क्षेत्र में उद्योगो का विकास करना प्रादेशिक सरकारो का कार्य है । इन कार्यों को सम्नोपजनक ढंग से करने के लिए प्रादेशिक सरकार द्वारा प्रारम्भिक अवस्था मे या स्थायी रूप से दो गई पूंजी के साथ प्रांतीय औद्योगिक नियमो और उनकी शाखाओं की स्थापना उपयोगी सिद्ध हो सकती है । इन निगमो द्वारा विशेषतः उन उद्योगो को सहायता मिलनी चाहिए जो जनता के लिए लाभदायक हो, उस प्रदेश की उत्पादन-शक्ति बढ़ाएँ तथा जिनसे लोगो को रोजगार मिले ।^१ अखिल भारतीय औद्योगिक निगम की आवश्यकता भी स्पष्ट है । राष्ट्रीय महत्त्व के कुछ ऐसे उद्योग है जिन्हें विकसित करने की जिम्मेवारी प्रांतीय सरकारो की नहीं वरन् केन्द्रीय सरकार की समझी जानी चाहिए ।

३६ औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८—गान्धे ने १३ फरवरी, १९४८ को औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम को पारित किया । इस कानून के अनुसार १ जुलाई १९४८ को औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना भारतवर्ष तथा विलयिन देशो राज्यों मे ऐसी मिश्रित पूंजी वाली रजिस्टर्ड कम्पनियो तथा सहकारी समितियो को मध्यम तथा दीर्घकालीन ऋण देने के लिए हुई जो वस्तुओं का उत्पादन करने, खान खोदने तथा विद्युत या किसी अन्य प्रकार की शक्ति को पैदा करने या बाँटने के कार्य से सम्बद्ध हो । इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक षण्ठो को आज की अपेक्षा अधिक आसानी से मध्यम तथा दीर्घकालीन साख को उपलब्ध बनाना है । कॉरपोरेशन की हिस्सा पूंजी १० करोड़ रुपये की है, परन्तु अभी ५ करोड़ रुपया प्राप्त हिस्सा-पूंजी के रूप मे है । इन १० करोड़ रुपये मे से १ करोड़ केन्द्रीय सरकार, १ करोड़ रिजर्व बैंक, ३ करोड़ अनुसूचित बैंक, बीमा कम्पनियो, विनियोग ट्रस्टो आदि तथा ३ करोड़ सहकारी बैंको द्वारा प्रदान किया गया । जर्जरत के समय शेष पूंजी को सरकार की अनुमति के अनुसार निर्गमित किया जाएगा । केन्द्रीय सरकार ने पूंजी के लौटाने तथा प्राय-कर से मुक्त वष से कम २३% लाभांश देने की गारन्टी दी है । इस निगम पर सरकार तथा रिजर्व बैंक, इम्पेरियल बैंक, अनुसूचित बैंक, बीमा कम्पनियो आदि का स्वामित्व रहेगा । इसके हिस्से का ४० प्रतिशत सरकार तथा रिजर्व बैंक के हाथ

१ डा० लोकमान ने प्रांतीय बैंको को सब काटि के उद्योगो को आर्थिक सहायता देने की स्वतन्त्रता से उत्पन्न होने वाले खतरों को रपध करते हुए यह सुझाव दिया है कि वे वरन् सार्वजनिक सेवा-उद्योगों को ही आर्थिक सहायता दें । देखिये, वही, पृष्ठ २६८ ।

२ यह अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और सहकारी अधिनियम से बंधा है ।

में तथा १० प्रतिशत सहकारी बैंको के हाथ में रहेगा। इसमें सरकारें, रिजर्व बैंक (१ जनवरी, १९४६ को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया) तथा इम्पीरियल बैंक के हिस्से का योग कुल हिस्सों का ५२ प्रतिशत होगा जिससे इस पर सरकारी नियन्त्रण का होना निश्चित-सा हो जाना है।

निगम का प्रबन्ध १२ सदस्यों की एक समिति को सौंप दिया गया है, जिसमें मैनजिंग डाइरेक्टर भी सम्मिलित हैं। यह १० करोड़ रुपये तक के निक्षेप स्वीकार कर सकता है, किन्तु उसको प्रथम पाँच वर्षों से कम नहीं होनी चाहिए। ऋण केवल सीमित दायित्व वाली कम्पनियों और सहकारी समितियों को प्रदान किया जाना है, परन्तु यह रहनी है कि वे स्वयं अपने प्रयत्न द्वारा भी वाञ्छित धन के एक उचित अनुपात की पूर्ति करें। ऋण देने के ढंग ये हैं—(१) ऋण देकर या २५ वर्षों के अन्तर्गत चुकता होने वाले औद्योगिक मस्याओं के ऐसे ऋण पत्रों को खरीदकर, जो सुरक्षित हैं या जिनके साथ जायदाद आदि वस्तुएँ भी गिरवी समझी जाती हैं, (२) कम्पनी के हिस्से, स्टॉक तथा विन्नी हेतु ऋण-पत्रों की स्वयं गारण्टी करने और (३) बाजार में बचे जाने वाले २५-वर्षीय ऋण की वापसी की गारण्टी देकर।

ऋण के प्रार्थना पत्रों पर विचार करते समय इन बातों पर ध्यान रखा जाता है—(क) आवदक कम्पनी की आर्थिक स्थिति, जो लन देन के बिट्टों का अध्ययन करने और खातों की जाँच करने के उपरान्त प्रकट होती है, (ख) योजना की यान्त्रिक दृढ़ता व व्यवस्था की कार्यकुशलता, और (ग) देश के आर्थिक टाँचे में उस उद्योग का महत्त्व। निगम को अधिकार है कि वह पूँजीगत वस्तुओं को प्राप्त करने की सुविधा के लिए कम्पनियों को आवश्यकतानुसार भारतीय या विदेशी मुद्रा में ऋण दे।

निगम आय कर के दायित्व से मुक्त नहीं है। मार्च, १९६० तक कारपोरेशन ने ७२ १८ करोड़ ६० का ऋण मजूर किया था। ४७ ४८ करोड़ ६० का ऋण वितरित किया जा चुका है। मजूर किये गए ऋणों में दो-तिहाई ऋण स्वतन्त्रता के पश्चात् स्थापित नए कारखानों का दिये गए। १९५७ के औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम द्वारा निगम की साधन-सम्बन्धी स्थिति और दृढ़ हो गई है तथा उसके कार्यों की परिधि भी विस्तृत हो गई है।

भारतीय राज्यों में प्रादेशिक वित्त निगमों के बन जाने के कारण यह निर्णय हुआ है कि (१) १० लाख रुपये और (२) अपने प्रदेश के वित्त निगम की प्राप्त पूँजी के दस प्रतिशत तक के ऋण के आवदकों को औद्योगिक वित्त निगम ऋण न दे।

दिसम्बर, १९५६ तक भारत में १४ राज्यीय वित्त निगम बनाए जा चुके थे। १९५१ के अधिनियम के अनुसार ये निगम वाड तथा ऋणपत्र निर्गमित कर सकते हैं, कम्पनियों को गारण्टी दे सकते हैं तथा उनके ऋण-पत्रों आदि की विन्नी की सुविधा भी दे सकते हैं, परन्तु ये सभी कार्य कुल निधि रूप में निगम की प्राप्त पूँजी तथा सुरक्षित कोष के पाँच गुने से अधिक न हों। १९५६-६० के अन्त तक निगमों के ऋण और अधिम की मात्रा १४ १७ करोड़ ६० थी।

इसके अतिरिक्त तीन अन्य निगम अखिल भारतीय स्तर पर स्थापित किए गए हैं—

(१) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (१९५४) की स्वीकृत पूंजी १ करोड़ ६० तथा प्राप्त पूंजी १० लाख ६० है। निगम नियोजित विकास-हेतु उद्योगों को वित्तीय सहायता देगा। वह स्वयं भी उद्योग स्थापित कर सकता है तथा औद्योगिक योजना की जाँच भी। इस सम्बन्ध में वह वैयक्तिक औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध औद्योगिक विशेषज्ञों के ज्ञान का पूर्ण लाभ उठाएगा।

(२) औद्योगिक साख तथा विनियोग-निगम (१९५५) की स्वीकृत पूंजी २५ करोड़ ६० थी तथा निर्गमित पूंजी ५ करोड़ ६० है, जिसमें से दो करोड़ ६० के हिस्से भारतीय बैंक तथा बीमा-कम्पनियों ने, १ करोड़ अंग्रेजी कम्पनियों ने, ०.५ करोड़ अमरीकी कम्पनियों ने तथा शेष भारतीय जनता ने लिए हैं। निगम इस बात का प्रयत्न करेगा कि इसके सदस्य विस्तृत क्षेत्र के हों। भारत सरकार पन्द्रह वर्ष बाद से अगले पन्द्रह वर्षों में चुकाने की शर्त पर ७.३ करोड़ रुपये का ऋण दे रही है। भारत सरकार की गारण्टी पर पुनर्निर्माण तथा विकासार्थ अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने भी १ करोड़ डालर का ऋण निगम को ४ $\frac{1}{2}$ % वार्षिक सूद की दर पर १५ वर्ष की अवधि के लिए देना स्वीकार किया है।

(३) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (१९५५) की १० लाख रुपये की स्वीकृत पूंजी १०० रुपये वाले १०,००० हिस्सों में बँटी है, जो पूर्णतः भारत सरकार ने प्रदान की है। भारत सरकार चालू पूंजी हेतु भी पर्याप्त निधि देगी। निगम पाँच लाख से कम पूंजी वाले शक्ति-चालित परन्तु ५० से कम श्रमिक वाले तथा बिना शक्ति-चालित और १०० तक श्रमिक वाले उद्योगों को सहायता, वित्त, संरक्षण तथा विकास-योग देगा। फरवरी, १९६६ में इसका उत्तरदायित्व और सम्पत्ति १३२ ६१ करोड़ रुपये थी।

रिफाइनंस कारपोरेशन - २५ जून, १९५८ को इसकी रजिस्ट्री हुई। इसका मुख्य उद्देश्य मध्यम आकार (जिनकी परिदत्त पूंजी और कोष २.५ करोड़ ६० से अधिक न हों) की औद्योगिक इकाइयों की सहायता हेतु बैंकिंग व्यवस्था को साधन उपलब्ध कराना है। १९५९ में तीन सदस्य बैंकों से २.२३ करोड़ ६० के लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। स्थापना से लेकर अब तक ४.२१ करोड़ ६० के लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। दिसम्बर, १९५९ तक ४०३ करोड़ ६० का अर्थ-प्रबन्ध (रिफाइनंस) सञ्चर किया गया। जिन उद्योगों ने सदस्य बैंकों के माध्यम से सहायता माँगी थी उनमें सूती वस्त्र उद्योग, सीमेन्ट आदि थे।

इसकी अधिकृत पूंजी २५ करोड़ ६० है। दिसम्बर, १९६४ के अन्त तक इसने ५ कृषि प्रगति प्रोजेक्टों पर २१ ८३ करोड़ रुपये व्यय किया।

४०. सचय करने की प्रवृत्ति—यह कथन सर्वविदित है कि भारतवर्ष बहुमूल्य धातुओं का अत्यल्प कूप है। भारतवासियों की सोने-चाँदी के प्रति तथाकथित अमिट तृष्णा के सम्बन्ध में अत्यन्त चित्रमयता से यह कहा गया है कि 'एक कृष्णवर्ण जाति

बहुमूल्य धातुओं का भूमि से उद्धार करती है और दूसरी उन्हें पुनः भूमि के भीतर दफना देती है। यह भी कहा जाता है कि जो स्वर्ण भारत में सामान्य उपयोग के लिए पहुँच जाता है, वह शेष ससार के लिए सदैव के लिए लुप्त हो जाता है। दीर्घकाल तक यूरोपवासी भारत में बहुमूल्य धातुओं की निरन्तर खपत पर हर्ष, आश्चर्य और मतोप के साथ विचार करते थे। यदि भारत में सोने-चाँदी की इतनी अधिक खपत न हुई होती, तो इधर पिछले वर्षों में नई खानों के अन्वेषण और धातु निकालने की प्रणाली में सुधार हो जाने के फलस्वरूप सोने-चाँदी के उत्पादन में विपुलता आ जाने व मूल्यों में भारी वृद्धि हो जाने के कारण यूरोपीय देशों के आर्थिक जीवन में एक भीषण असन्तुलन आ जाता। किन्तु जून १९२४-२५ में इंग्लैण्ड व यूरोप के अन्य देश अपनी मुद्राएँ स्थिर करने के लिए सवर्षरत थे, भारत यूरोप की आवश्यकताओं को तनिक भी ध्यान में न रखते हुए कम-से-कम ५० लाख पौंड के मूल्य का स्वर्ण पत्र कर चुका था। तब यूरोपीय देशों ने अनुभव किया कि भारत सचय करने के अपने ढर्रे को पूरी सरगर्मी से जारी रखकर उनके मुद्रा स्थिर करने के प्रयास में भारी बाधा पहुँचा रहा है।^१

भारत में इन सचिंत धन के सम्बन्ध में अनेक अनुमान सगाये गए हैं। कदाचित् सबसे पहला अनुमान श्री मेक्लायड (एच० डी०) का था। यह पहले अर्थशास्त्री थे जिनके मस्तिष्क में इस सचिंत धन के सम्बन्ध में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उनका विश्वास था कि यह ३०० लाख पौंड से कम नहीं होना चाहिए। लार्ड कर्जन का अनुमान था कि यह ८२५ करोड़ ६० के निकट होगा, जबकि आर्नल्डराइट ने दिसम्बर १९१६ क किनामिन्गल रिव्यू ऑफ ग्लोबल में लिखते हुए उसे ७००० लाख पौंड ठहराया था।

भारत के सोने व चाँदी के उपभोग की शिकायत करते हुए यूरोपीय लेखकों ने सारा दोष भारतवासियों के ही गले नड दिया है और स्वर्ण के उपभोग के सम्बन्ध में भारत को द्वेषपूर्ण दायित्व का दोषी करार करने के प्रयास के फलस्वरूप उत्तेजनापूर्ण प्रत्युत्तर तक नौजत आ पहुँची और दोषारोपित करने वालों के सिर भी दोष मड़े गए। यह इंगित किया गया कि स्वर्ण-सचय करने का दुर्वसन केवल भारतीयों के साथ ही नहीं है। संयुक्तराज्य अमरीका में ही १९१६ से लेकर १९२३ के बीच लगभग ५० करोड़ पौंड का सोना खप गया और न्यूयार्क में द्रव्य के नाम पर स्वर्ण का

१. जब हम सितम्बर, १९३१ (जब १ रुपया १ शि० ६ पै० के बराबर था) से जनवरी, १९४० के बीच के ३५१ करोड़ ६० के सोने का भारत से निर्यात का ध्यान करते हैं, तो उपयुक्त दलील में कोई जान नहीं दिखाई पड़ती। पीछे अध्याय ६, सेक्शन २२ देखिए। तिस समय भारत से इतनी बड़ा मात्रा में सोने का निर्यात हो रहा था, ठीक उसी समय संयुक्तराज्य अमरीका तथा अनेक यूरोपीय देशों में (विशेषतः फ्रांस में) इसका अत्यधिक सचय किया जा रहा था।

२. सर स्टैनली रीड द्वारा वैकिंगटन रिमथ समिति को दिया गया बक्तव्य।

३. वाडिया और जोशी, 'दि वेल्थ ऑफ इण्डिया', पृ० ३८८-८९।

उ० भाग से भी अधिक स्वर्ण संचय करने के उपरान्त संचय करने की वृत्ति को केवल भारतीय एकाधिकार नहीं कहा जा सकता। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन केन्द्रों में स्वर्ण का अधिकांश भाग केन्द्रीय बैंक के सुरक्षा-नोप में एकत्र था। परन्तु यदि भारत में स्वर्ण का ऐसा उपयोग नहीं किया गया तो क्या इसका कारण यहाँ की दूषित मुद्रा-प्रणाली (स्वर्ण-विनिमय-मान), जो यहाँ पर्याप्त समय तक चलन में रही, आंशिक रूप से नहीं है? जो लोग भारत के संचय पर खेद प्रकट करते हैं, सामान्यतः वे यह भूल जाते हैं कि यहाँ की खपत में आने वाले स्वर्ण के एक अंश का उपयोग औद्योगिक और घरेलू आवश्यकताओं के लिए भी होता रहा है।

जब इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर एक बार यह स्वीकार कर लिया गया कि सोने-चाँदी के लिए भारत की माँग असामान्य नहीं है, तो दूसरे देशों की मुद्रा की स्थिरता में उत्पन्न होने वाली बाधाओं के विशिष्ट दायित्व से भारत को बरी कर दिया गया।

जो कुछ भी ऊपर कहा गया है उसका उद्देश्य यही प्रदर्शित करना था कि भारत में संचय की मात्रा के सम्बन्ध में अत्यधिकपूर्ण उल्लेख हुए हैं। हाँ, संचय के अस्तित्व से बिलकुल इनकार करना तो सत्य की उपेक्षा करना होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मुद्रा के अतिरिक्त अन्य उपयोगों में स्वर्ण की भारी खपत होती है और संचय द्वारा जड़ (अचल) बनी बहुमूल्य धातु की वर्तमान राशि पर्याप्त विपुल होगी।

यह कहना कठिन होगा कि यह प्रवृत्ति घन और सम्पन्नता की परिचायक है। अधिकांशतः यह संचित घन लाखों पृथक्-पृथक् व्यक्तियों के पास छोटी-छोटी राशियों में बिखरा पड़ा है और उत्पादक-कार्यों में इसका उपयोग नहीं हो रहा है। यह उचित ही है कि इन्हें सम्पन्नता का मकेनक न स्वीकार करके निर्धनता का कारण माना जाता है।^१

सोने तथा चाँदी के आभूषणों को भी साधारणतया संचित राशि का एक हिस्सा माना तो जाता है, पर इसकी स्वीकृति विवादास्पद विषय है। यह समझना कठिन है कि अगर हम दाँत में लगाए सोने को संचित घन नहीं मानते तो शृंगार के लिए उपयोग किये गए सोने को ऐसा क्यों मानें? सच्ची बात यह है कि भारतवासी सोने तथा चाँदी के गहने दो उद्देश्यों से बनवाते हैं— निजी शृंगार के लिए तथा आपत्ति-काल में सहायता के लिए।^२ फिर भी इन दोनों प्रयोजनों में भेद करना

१. भारत में सोने का आयात कानून द्वारा बन्द है। तब भी चोरी-चोरी विदेशों से काफी सोना बंदरगाहों पर आता तथा बिकता है। भारत सरकार ने इस चोरी से किये आयात को रोकने के कई उपाय किये हैं। इसके तथा अन्धरी फूमलों के कारण किसान की बहुमूल्य धातुओं की बड़ी माँग के कारण स्वर्ण का मूल्य बढ़े है।

२. बैरिस्टर रिमथ समिति ने भी इस व्यावहारिक सत्य को स्वीकार किया है कि जिस विसी भी हिन्दू या मुस्लिम महिला के पास सोने एवं चाँदी के आभूषण तथा आभूषण के ही रूप में परिवर्तित सिक्के होते हैं, उसे यह अधिकार है कि वह उन्हें अपनी निजी जायदाद समझे।

आवश्यक ही है तथा इन बहुमूल्य पदार्थों को हम संचित धन तभी कह सकते हैं जबकि प्रयोजन मूल्य के संचिन करने से सम्बद्ध हो।

बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार जिस प्रकार नशाखोरी की फिजूलखर्चों को कम करने का साधन नहीं है, उसी प्रकार यह भ्रातृपण पर की गई फिजूलखर्चों का भी साधन नहीं हो सकता (जब तक हम गहने को बैंक का स्थानापन्न न मानें)। वास्तव में भारतीय दृष्टिकोण से हमारे राज्य प्रायः मच्छरदानी तथा भोजन-जैसी आवश्यक वस्तुओं पर खर्च करने के बजाय अपने तथा अपनी पत्नी के भ्रातृपण के लिए खर्च करता है। कभी-कभी तो रीति-रस्मों के कारण सोने तथा चाँदी का व्यवहार करना पड़ता है, धार्मिक तथा परम्परागत उत्सवों में भी इनका प्रमुख स्थान होता है। यह दुःख की बात तो प्रबन्ध ही है, पर इन्हें दूर करने के लिए हमें मूल्य के समुचित ज्ञान तथा शिक्षा एवं सामान्य चेतना के प्रसार द्वारा सामाजिक तथा धार्मिक रस्मों को मृदुल बनाना पड़ेगा। इसके साथ-ही-साथ यह भी नहीं भूलना होगा कि इस पहलू का सम्बन्ध वास्तविक सञ्चय से न होकर उपभोग तथा व्यय की अच्युत या बुरी रीति से है।

बैंकिंग के जिस विस्तार को सञ्चय वन्द करने के उपाय के रूप में बताया जाता है सञ्चय व कारण वह खुद ही कठिन हो जाता है, क्योंकि जब तक जनता बैंकों में रुपया जमा नहीं करती तब तक वे अपना कार्य-संचालन ही कैसे कर सकते हैं, पर इसके साथ यह कहना भी ठीक है कि जब तक कोई बैंक ही नहीं तब तक उसमें कोई अपना रुपया जमा ही कैसे कर सकते हैं? अतएव यह प्रश्न क्रिया-प्रतिक्रिया से ही सम्बन्धित है और हमारे सामने केवल यही रास्ता बच जाता है कि हम अधिकाधिक बैंकों तथा लोगों की आवश्यकता तथा रुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार के बैंकों की स्थापना करें तथा और बातों को शिक्षा एवं सतत प्रचार पर छोड़ दें।

संचय की प्रवृत्ति को दूर करने के उपाय—उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि जो संचय आपत्ति-काल के लिए जेबरात के रूप में किया जाता है, उसे दूर करने का एक उपाय आपत्ति-काल के संचय के लिए वैकल्पिक साधनों को उपलब्ध कराना है। इस दिशा में पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक तथा विभिन्न प्रकार के वचत सर्टिफिकेट उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इनकी चर्चा की जा चुकी है। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक चेक जारी करने की सुविधा प्रदान कर काफी निक्षेप प्राप्त कर सकती है। ऐसा करने से सेविंग्स बैंक को अधिक निक्षेप मिलेंगे, साथ ही जनता में चेक का प्रयोग बढ़ेगा और संचय की प्रवृत्ति कम होगी।

१९५६-६० में ८४ करोड़ ६० अल्पवचत के रूप में प्राप्त हुआ जो १९५८-५९ की ८० करोड़ ६० की राशि से अधिक है। यह राशि स्वतः बहुत बड़ी नहीं है, किन्तु इसकी वृद्धि इस बात की सूचक तो है ही कि संचय की प्रवृत्ति के स्थान पर अल्प-वचत की प्रवृत्ति बढ़ रही है। बड़े कारखानों और संस्थाओं में कर्मचारियों की अनुमति से अल्पवचत के लिए वेतन मितलन से पूर्व कटौती कराने की व्यवस्था है। इस समय

दो गैर-सरकारी सस्याएँ राष्ट्रीय वचन की केन्द्रीय परामर्श समिति (नेशनल सेविंग सेण्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड) तथा राज्तीय परामर्श समिति—अल्प वचन ग्रान्दोलन के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देती हैं ।

४१. भारतीय बैंकरो की संस्था—जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, हमारे देश में आधुनिक बैंकिंग की अज्ञानता १९१२-१४ के बैंक संकट का एक कारण थी । २० अप्रैल, १९२८ को इण्डियन कम्पनीज एक्ट के अनुसार स्थापित इण्डियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स (भारतीय बैंकरो की संस्था) का उद्देश्य इन्ही गृष्टियों को कुछ हद तक दूर करने का है । इस संस्था के कुछ मुख्य उद्देश्य ये हैं—(१) विशेषतः भारतवर्ष में बैंकिंग कारोवार करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार, पद तथा हित की रक्षा तथा सहायता करना । (२) बैंकिंग के सिद्धान्त के अध्धयन को प्रोत्साहन देना तथा इसी उद्देश्य से एक व्यवस्था करना तथा इस सम्बन्ध में सर्टिफिकेट, ध्यावृत्ति तथा इनाम देना । (३) भाषणों, वादविवाद, समाचार-पत्रों, पुस्तकों, सार्वजनिक सस्याओं तथा व्यक्तियों से पत्र-व्यवहार द्वारा बैंकिंग तथा उससे सम्बद्ध विषयों की सूचना का प्रचार करना । (४) भारतीय बैंकिंग से सम्बद्ध आँकड़े इकट्ठा करना तथा उनका प्रसार करना ।^१

सितम्बर १९५४ में रिजर्व बैंक ने अधिकोपो के निरीक्षण कर्मचारियों को अधिकोपीय व्यवहार की शिक्षा देने के लिए बम्बई में एक बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलिज की स्थापना की है । कॉलिज ने अब तक २६ पाठ्यक्रम (कोर्स) सञ्चालित किये हैं, जिनमें देश-भर की विभिन्न बैंकों से ६३९ कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया । १९४९-६० में पाँच पाठ्यक्रम सञ्चालित किये गए तथा १३९ कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया । अब उप-प्रबन्धको तथा खजाचियों आदि तक प्रशिक्षण-सुविधाओं का विस्तार करने की दृष्टि से एक माध्यमिक पाठ्यक्रम (इण्टरमीजियट कोर्स) बनाकर बैंकों को भेजा गया है । राज्तीय वित्त निगम तथा रिफाइनेन्स कारपोरेशन के सदस्य बैंकों के निरीक्षण-वर्ग के कर्मचारियों के लिए जुलाई १९६० से प्रारम्भ होने वाले 'औद्योगिक वित्त' के विशेष पाठ्यक्रम (एडवान्स कोर्स) की योजना भी रिजर्व बैंक ने बनाई है । बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलिज अधिकोपीय प्रशिक्षण के क्षेत्र में बहुत बड़ी कमी दूर करेगा ।

४२. बैंको की वर्तमान स्थिति—१९६३ के मुकाबले में १९६४ में बैंको का निक्षेप विशेषतया चालू जमा में था । बैंको के ऋण में बढ़ोतरी का कारण एक तो यह था कि १९६३-६४ के व्षन समय में बहुत बढ़ोतरी हुई । मन्दे समय में इतनी अधिक सविदा साख में नहीं हुई । १९६४ में बैंको में जमा पत्र ११.९ प्रतिशत से बढ़े और उनके ऋण १४.६ प्रतिशत बढ़े और इस प्रकार जमा-उधार अनुपात ७१.८ प्रतिशत हो गया । १९६४ में बैंको (Scheduled) की सख्या ८० से गिरकर ७६ हो गई । एक विशेष बात यह है कि पहली जुलाई १९६० से लघु उद्योगों की साख गारन्टी स्कीम को और बढ़ाया गया और इस समय ९४ साख सस्याएँ कार्य कर रही हैं । जब से यह

१. इण्डियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स के मेमोरेण्डम तथा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देखिए ।

स्कीम बनी है (जुलाई १९६०), तब से लेकर १९६४ तक इस स्कीम के नीचे १२,४७७ गारन्टियाँ, ४९ ५३ करोड़ रुपये की कीमत की दी गई।

बढ़ती हुई कीमतों तथा ऊँची दर व ऋण और बैंकों की साख को देखते हुए रिजर्व बैंक ने मार्च सितम्बर १९६४ में अपनी साख दर की नीति को और कड़ा कर दिया। बैंक दर का ५ प्रतिशत बढ़ा दिया और उधार दर की नीति को और ऊँचा कर दिया जिससे अ प बैंकों को साख की बढ़ोतरी के लिए रिजर्व बैंक के पास आशय लेने का प्रयत्न करें। इस प्रकार १९६४ में रिजर्व बैंक ने साख पर लगाये गए प्रति बन्धन को तैलों और खाद्य पदार्थों पर और भी मजबूत कर दिया।

१९६५ में रिजर्व बैंक की साख नीति के कारण थोक वस्तुओं की कीमतों में ६ प्रतिशत बढ़ोतरी हुई जो कि १९६४ का $\frac{2}{3}$ हिस्सा है। १९६५ की नीतियाँ इसलिए अपनाई गई थी कि जल्द ही कामों के लिए साख मिल सके और बढ़ती कीमतों का रोकना जाए। लोगों के पास धन की पूर्ति १०-२% में बढ़ी। बैंक दर को ५ से ६ प्रतिशत बढ़ाने और रिजर्व बैंक की अनुकूलता को कम करने के बाद भी व्यस्त समय में बैंक साख ४०७ करोड़ रुपये हो गई। इस प्रकार जब तक अच्छी साख की नीतियाँ नहीं अपनाई जाएँगी और बढ़ती कीमतों की रोकथाम नहीं की जाएगी, तब तक राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक स्थिति संकट से दूर न हो सकेगी।



वित्त और कर

१. परिचयात्मक विचार—१९१४-१८ के महायुद्ध के पहले समस्त भारत के लिए एक ही आय-व्ययक (बजट) होता था तथा प्रान्तीय सरकारों को स्वतन्त्र रूप से कर लगाने का अधिकार नहीं था। केवल केन्द्रीय सरकार को ही कर लगाने का अधिकार था। इस युद्ध के पश्चात् प्रान्तीय अर्थ-प्रबन्धन केन्द्रीय अर्थ-प्रबन्धन से सर्वथा पृथक् कर दिया गया और भारतीय अर्थ-व्यवस्था की रूपरेखा सघीय अर्थ-प्रबन्धन के ढंग पर विकसित हो रही है। अफीम, जो अभी हाल तक आय का एक महत्वशाली साधन था और जिसका मालगुजारी के बाद दूसरा स्थान था, लगभग पूर्ण रूप से भारत की परोपकारी अर्थ-व्यवस्था की नीति पर जोर देने के फलस्वरूप लुप्त हो गया और जो थोड़ी-सी आय इस शीर्षक में बजट में दिखाई जाती है वह १९३५ के बाद से भारत में प्रयोग में आने वाली अफीम की बिक्री के उत्पाद-कर से प्राप्त होती है।

आय के केन्द्रीय शीर्षक

२. निराक्राम्य (कस्टम) प्रशुल्क का इतिहास—(क) १९१४-१८ के महासमर के पहले आयात प्रशुल्क पद्धति शुद्धरूपेण स्वतन्त्र व्यापार-नीति पर आधारित थी। इसके कारण बहुत साधारण आयात-कर लगाया जाता था। जो माल इंग्लैण्ड के प्रतिरिक्त अन्य देशों से आता उस पर अग्रेजी माल की तुलना में दूना कर लगाया जाता है।

मेनचेस्टर को प्रसन्न करने के विचार से भारतीय मिलों में तैयार किये हुए २० अथवा २० से अधिक काउण्ट के सूत पर भी ५% कर लगाया गया। सूत पर लगाये हुए इस कर से लकाशायर को पूर्ण सन्तुष्टि नहीं हुई, इसलिए १८९६ में सूती वस्त्रों पर आयात-कर की दर घटाकर ३३% कर दी गई और उसी दर से भारतीय मिलों में बने हुए कपड़ों पर लगा दिया गया, सूत को—चाहे देशी अथवा विदेशी हो—इस कर से पूरी छूट दे दी गई।

भारत में इस कर का घोर विरोध हुआ। इस उत्पाद-कर से मेनचेस्टर को किसी प्रकार का लाभ पहुँचाए बिना ही भारत को घाटा हो रहा था। सर जेम्स बेस्टलैण्ड के कथनानुसार भारत के ९४% सूती वस्त्र के निर्माण से मेनचेस्टर की प्रतिद्वन्द्विता की कोई सम्भावना ही नहीं थी। भारतीय माल के मोटे होने के कारण महीन वस्त्रों के सम्बन्ध में मेनचेस्टर का एकाधिकार ही था और उसका अधिकार

व्यापार २० तथा उससे अधिक काउण्ट के महीन कपडो तक ही सीमित था । भारत बड़ी कठिनाई के साथ बहुत थोड़ी मात्रा में २६ या उससे थोड़े अधिक काउण्ट के वस्त्र तैयार कर सकता था । अन्त में यह भी कहा जा सकता है कि आयात-कर ५ से ३½ प्रतिशत कर देने से विदेशी वस्त्रों के घनी उपभोक्ताओं को ही विशेष लाभ होता, पर देशी सूती वस्त्रों पर लगाया हुआ ३½% कर गरीबों को विशेष हानि पहुँचाता । इसलिए देशी सूती वस्त्रों के उत्पादन पर ३½% कर कभी भी न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता ।

(ख) १९१४-१८ के महासमर के पहले निर्यात प्रशुल्क—१८६० तक निर्यात-कर प्रारम्भिक प्रशुल्क नीति का मुख्य अंग था और प्रायः प्रत्येक निर्यात की वस्तु पर ३% कर लगाया जाता था । यद्यपि यह कर बहुत कम था और प्रायः की दृष्टि से लगाया गया था, पर निर्यात कर के लगाये जाने का सिद्धान्त आर्थिक दृष्टिकोण से अनुपयुक्त समझा जाता था । इससे विदेशी प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलने के कारण निर्यात-व्यापार को धक्का पहुँचने का भय था । इस विचार से १८६० से १८८० तक निरन्तर इस कर को हटा देने की नीति का ही अनुसरण किया गया । फलतः १८८० में केवल चावल पर ही यह कर लगा रहने दिया गया । १९०३ में भारतीय चाय उद्योग की प्रार्थना पर चाय के निर्यात पर एक साधारण कर लगा दिया गया ।^१

३. युद्धकालीन तथा उत्तर-युद्धकालीन निराक्राम्य प्रशुल्क पद्धति—युद्ध-काल में तथा उसके पश्चात् निराक्राम्य प्रशुल्कों में विस्तृत परिवर्तन हुए । उनका सारांश निम्न-लिखित है—

(क) आयात कर—मूल्यानुसार लगाया जाने वाला कर सभी वस्तुओं, जैसे सूती वस्त्र, लोहा और इस्पात, रेल से सम्बन्धित वस्तुओं इत्यादि, पर बढ़ा दिया गया । उदाहरण के लिए चीनी पर लगा मूल्यानुसार कर १९१६-१७ में ५% से बढ़ाकर १० प्रतिशत कर दिया गया और १९२२-२३ में १५ से २५ प्रतिशत कर दिया गया । रुई कातने और बुनने की मशीनों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं पर १९२१-२२ में २½% कर लगाया गया, पर बाद में यह कर हटा लिया गया । विलासिता की सभी वस्तुओं, जैसे मोटरकार, सिनेमा के फिल्म, घड़ियाँ, रेसम के कपड़े इत्यादि, पर लगे कर १९२१-२२ में ७½ प्रतिशत से बढ़ाकर २० प्रतिशत और १९२२-२३ में बढ़ाकर ३० प्रतिशत कर दिये गए । १९२७-२८ में टेबलेटान इनक्वायरी कमेटी की सिफारिशों के अनुसार, जिसमें मोटर परिवहन को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया था, मोटरकार पर कर ३० से २० प्रतिशत कर दिया गया और टायरों पर ३० से १५ प्रतिशत कर दिया गया । तीव्र आर्थिक अवसाद तथा केन्द्रीय बजट के महान् घाटे ने अधिक आय प्राप्त करने के लिए आयात-करों में भारी और विस्तृत वृद्धि करने पर बाध्य कर दिया । उदाहरणार्थ, मार्च १९३१ के वित्त अधिनियम न (१) शराब, चीनी, चाँदी

१. दलित, खण्ड १, अध्याय ६, पैरा ७, II (ii) ।

श्रीर सिनेमा फिल्मो पर लगाए कर की दर मे विशेष वृद्धि कर दी । (२) २३ स १५ प्रतिशत अनिरीकृत कर अधिभार के रूप मे लगा दिए । १ नवम्बर १९३१ के पूरक वित्त अधिनियम ने रुई, मशीनरी, रग, कृत्रिम रेशमी सूत, रेशमी बस्त्र, बिजली के बल्ब आदि वस्तुओं के आयात-करो मे वृद्धि कर दी, और प्रचलित आयात कर तथा अधिकर, जो पिछले अधिनियम ने लागू कर रखे थे, की एक-चौथाई मात्रा का अधिभार लगा दिया ।

भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधित) अधिनियम (मई, १९३६) ने ऐसे परिवर्तनों को कार्यरूप दिया जो भारत और इंग्लैण्ड के बीच हुए नये व्यापारिक समझौते के अन्तर्गत थे । इस समझौते ने पिछले उठावा समझौते का स्थान ले लिया । इस नये समझौते के अनुसार भारत के लिए इंगलिस्तान को $७\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रशुल्क अधिमान विशेष प्रकार की मोटरगाडियो पर तथा १० प्रतिशत का अधिमान किन्हीं विशेष वस्तुओं पर देना आवश्यक हो गया ।^१ इस नये समझौते के अन्तर्गत इंग्लैण्ड के सूती कपडों पर आयात-कर मे भी कमी की गई । १९४१ के वित्त-अधिनियम ने कृत्रिम रेशम के सूत और डोरे पर आयात-कर ३ आने से ५ आने कर दिया । १९४२-४३ मे वर्तमान आयात प्रशुल्क के ऊपर (कपास, पेट्रोल और नमक को छोड़कर) सभी वस्तुओं पर २० प्रतिशत का निराकाम्य अधिभार लगा दिया गया । पेट्रोल पर भी २५% टैक्स बढ़ा दिया गया । १९४४ मे तम्बाकू और स्प्रिट पर भी अधिभार बढ़ा दिया गया । १९४२ मे कॉटन फण्ड आर्डिनेन्स के अन्तर्गत १ आना प्रति पौण्ड के कर को मिलाकर २ आना प्रति पौण्ड (बिना अधिभार के) कर दिया गया जो कि पूर्ण-रूपेण भारतीय प्रशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत लागू किया जा सकता था, और विदेश से मंगाये हुए सोने के सिक्के पर २५ रु० प्रति तोला, जिसमे १८० ग्रेन शुद्ध सोना हो, का प्रामाणिक कर (बिना अधिभार के) लगाया गया तथा चाँदी पर ३ आना ७ पाई के वर्तमान कर (जिसमे अधिभार सम्मिलित है) को ८ आना प्रति औंस (बिना अधिभार के) कर दिया गया ।

१९४८-४९ मे मोटरकार पर आयात-कर ४५% से ५०% कर दिया गया, पर इंगलिस्तान को $७\frac{1}{2}$ % का अधिमान दिया गया । दिमासलाई पर कर प्रति ग्रुस १ रु० १२ आना से २ रु० ८ आना कर दिया गया और टायरो पर ५०% कर बढ़ा दिया गया (जो अगले वर्ष और अधिक बढ़ाया गया) ।

१९४९-५० मे मोटर की स्प्रिट पर आयात-कर १२ आने से १५ आने प्रति गैलन (ऐसी ही वृद्धि उत्पादन-कर मे भी की गई) कर दिया गया । मोटरो मे प्रयुक्त टायरो के मूल्य पर कर १५% से ३०% कर दिया गया और सुपारी पर कर ५ आना प्रति पौण्ड से $७\frac{1}{2}$ आना प्रति पौण्ड कर दिया गया, परन्तु अग्नेज उप-निवेशो से मंगाई हुई सुपारी पर ६ पाई प्रति पौण्ड का अधिमान मिलना रहा ।

१. विशेष विवरण के लिए अध्याय ७ देखिए ।

१९५१ से नियोजन-युग प्रारम्भ हुआ तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना चालू हुई। अब आयात और निर्यात कर नीति के पीछे मुख्यतः दो बातें हैं—आयात-कर उन वस्तुओं पर लगाया जाए या उन वस्तुओं पर उमकी दर बढ़ाई जाए जो देश में निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करती हो या उनके विकास में बाधक हो, निर्यात-कर इस ढंग से लगाया जाए ताकि (अ) सबन्धित उद्योग देश की आन्तरिक उपयोग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्यात करे तथा (ब) कर की मात्रा इस प्रकार निर्धारित की जाए कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा शक्ति न घटे। निर्यात-उद्योगों के विकास-सम्बन्धी आयातों को अपेक्षाकृत अधिक सुविधा देन की व्यवस्था की जाए। योजना-काल के बजट इन्हीं प्रवृत्तियों को लक्षित करते हैं। १९६१-६२ के बजट में लगभग ४१ वस्तुओं पर कर (ड्यूटी) बढ़ा दिया गया। देश में मशीनों का निर्माण का तेजी से विकास हो रहा है। उनके विकास में सहायता करने के लिए मशीनों और उनके पुर्जों पर लगे कर की परिमित दर मूल्यानुसार १० प्रतिशत से बढ़ाकर मूल्यानुसार १५ प्रतिशत कर दी गई। जी० ए० टी० टी० के अन्तर्गत आने वाले सामान पर कोई बृद्धि नहीं हुई।

(ख) निर्यात-कर—१९१६-१७ में दो नये निर्यात-कर चाय और जूट पर लागू किये गए। चाय पर तो निर्यात-कर १ रु० ८ आ० निश्चित कर दिया गया। १९२७-२८ में यह कर हटा दिया गया, परन्तु इसके हटाने का घाटा चाय उद्योग के मुनाफे पर लगे आय-कर में वृद्धिद्वारा पूरा कर दिया गया। जूट की ४०० पीण्ड की प्रत्येक गाँठ पर २ रु० ४ आ० निर्यात कर निश्चित किया गया, जो कि लगभग ५ प्रतिशत के मूल्यानुसार लगाए कर के बराबर था। जूट से बने माल पर १० रु० प्रति टन बोरो पर और १६ रु० प्रति टन टाट पर कर लगाया गया। १९१७-१८ में जूट पर निर्यात-कर दुगुना कर दिया गया। अक्टूबर, १९१९ में कच्चे चमड़े पर भारतीय चमड़ा सिम्भान के उद्योग की रक्षा के लिए १५ प्रतिशत मूल्यानुसार कर लगाया गया। १९३० के वित्त अधिनियम ने चावल पर लागू निर्यात-कर में एक-चौथाई की कमी कर दी अर्थात् ३ आने से घटाकर २ आना ३ पाई प्रति मन कर दिया, ताकि चावल के मूल्य में हुई सस्कार-व्यापी कमी का मुकाबला किया जा सके तथा बर्मा और स्वाम की, जोकि इस व्यापार में उसके मुख्य प्रतिद्वन्दी थे, मुकाबला कर सके और बर्मा के किसानों की सहायता एवं उनके प्रति न्याय हो सके।

१९१४-१८ के युद्ध-काल में धन की आवश्यकता तथा युद्धोत्तरकालीन आर्थिक घाटे के कारण निराश्राम्य कर पर अधिकाधिक निर्भर रहने की प्रवृत्ति बढ़ती गई। निराश्राम्य-कर से प्राप्त आय में द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण शत्रु देशों से व्यापार बन्द होने के ही कारण नहीं बरन् आयात में प्रतिबन्ध लग जान तथा जहाजों द्वारा माल के ले आने तथा ले जान की सुविधा में कमी होने से बहुत कमी हो गई। जब से युद्ध समाप्त हुआ है, निराश्राम्य-कर पर निर्भरता की प्रवृत्ति पुनः बढ़ती जा रही है।

१९०४ तक प्रमुख में ये परिवर्तन (कच्चे चमड़े पर निर्यात-कर को छोड़कर)

आय के ही दृष्टिकोण से नियमित थे । कुछ कर इतनी ऊँची दर के थे कि उनका प्रभाव निश्चित रूप से सरक्षणरूपक होता था । इससे वर्तमान अव्यवस्थित सरक्षण-प्रणाली के स्थान पर, जो अनायास स्थापित हो गई थी, एक सुव्यवस्थित विचारपूर्ण सरक्षण-प्रणाली की स्थापना की आवश्यकता का लोगो को अनुभव हुआ । १९२४ के स्टील प्रोटेक्शन एक्ट के पास होने के बाद से अनेक सरक्षण करों का आरोप किया गया । उदात्ता ट्रेड एग्जिमेण्ट (१९३२) तथा इण्डो-ब्रिटिश ट्रेड एग्जिमेण्ट (१९३६) के परिणामस्वरूप भारतीय प्रशुल्क पद्धति सम-यवहार वाली न रह सकी, क्योंकि उसमें इंग्लिस्तान, उपनिवेशों और सरक्षक शासनाधीन राज्यों से आने वाली कुछ वस्तुओं को अधिमान प्राप्त थे । इस प्रकार विभिन्न देशों की वस्तुओं के आयात के सम्बन्ध में विभिन्न नीति बरती जाती थी ।

१९३४ के वित्त अधिनियम ने कच्चे चमड़े पर लगा निर्यात-कर उठा दिया, क्योंकि चमड़े का निर्यात-व्यापार विशेषकर जर्मनी से घटता जा रहा था । १९३५ के अधिनियम ने सामान्य निर्यात-व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए कच्चे पशु-चर्म पर लगे निर्यात-कर को हटा दिया । १९४० के एग्रिकल्चरल प्रोड्यूसर्स एक्ट के अन्तर्गत कुछ विशेष वस्तुओं पर, जैसे हड्डी, मक्खन, गेहूँ, बीज, चमड़ा, तम्बाकू, कच्चा ऊन इत्यादि, जिन पर अभी तक कोई निर्यात-कर अथवा किसी प्रकार का उप कर नहीं लगा हुआ था, राजकीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (इम्पीरियल काउन्सिल ऑफ एग्रिकल्चरल रिसर्च) की आर्थिक स्थिति को दृढतर बनाने के दृष्टिकोण से १/१० का उप-कर लगा दिया गया । १९४६ में चाय और रूई पर नये निर्यात-कर लगाये गए और जूट के निर्यात पर कर बढ़ा दिया गया । १९४७ में चाय पर निर्यात-कर २ आ० से ४ आ० प्रति पौण्ड कर दिया गया । १९४८-४९ में (१) कपड़े का निर्यात-कर २५% के मूल्यानुसार कर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया । (करधे द्वारा निर्मित वस्त्रों को छोड़ दिया गया), (२) सूत पर लगाया हुआ कर उठा दिया गया, और (३) ८० रु० प्रति टन का निर्यात-कर तिलहन पर और १६० रु० प्रति टन का निर्यात-कर वनस्पति तेल पर लगा दिया गया । (अगले वर्ष दोनों कर उठा लिये गए) । १९४९-५० में १५% का एक नया मूल्यानुसार कर रिगार, सिगरेट और चुहट पर लगा दिया गया ।

निराक्राम्य करों (कस्टम्स) से प्राप्त आय १९६१-६२ में १९६०-६१ के सशोधित अनुमान की तुलना में १ करोड़ रु० अधिक होगी । कुल मिलाकर १९६१-६२ में ४१ मदी पर निराक्राम्य-कर की दर बढ़ा दी गई, जैसे अनिर्मित तम्बाकू, सुपारी आदि, जिनकी चर्चा की जा चुकी है । १९६५-६६ के बजट के आगहन के अनुसार यह ५०१ करोड़ रुपये थी और १९६६-६७ में ५६१ करोड़ रुपये की सम्भावना है । ४ केन्द्रीय उत्पाद-कर—उत्पाद-कर केन्द्रीय सरकार की आय के प्रमुख साधनों में से है । १९६०-६१ में १४ वस्तुओं पर केन्द्रीय उत्पाद कर लगा था, उदाहरण के लिए मोटर, स्विच, मिट्टी का तेल, चीनी, दियासलाई, लोहा, टायर, तम्बाकू, वनस्पति घी, सुपारी, कद्दावू, चाय और कोयला आदि । मिट्टी के तेल का उत्पादन

पर्याप्त न होने के कारण बाहर से मँगाना पड़ता है। अतएव मिट्टी के तेल के उपयोग की दर कम करने की दृष्टि से अच्छे प्रकार के मिट्टी के तेल पर उत्पाद-कर ४२% बढ़ा दिया गया और इस प्रकार उत्पाद-कर ६५ ५५ रु० प्रति किलोमीटर हो गया। इस प्रकार ४४५ रु० के वर्तमान अतिरिक्त-कर को सम्मिलित कर लेने पर कुल कर की मात्रा १०० रु० प्रति किलोमीटर हो गई। निम्न कोटि का मिट्टी का तेल, जिसका उपयोग अधिकतर गाँवों में होता है, पर यह कर नहीं लगाया जाएगा।

परिष्कृत डीजेल तेल तथा डीजेल तेल के बीच उत्पाद-कर में भारी अन्तर होने के कारण डीजेल तेल को परिष्कृत डीजेल तेल में मिलाने का चलन हो गया है। अतएव डीजेल तेल पर २८ १५ रु० का कर बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया।

औद्योगिक विकास के साथ ही अनेक वस्तुओं पर उत्पाद-कर लगाना सम्भव हो गया। अतएव १९६१-६२ के बजट में निम्न प्रस्ताव किये गए। सोडा एश, कास्टिक सोडा और ग्लिसरीन पर मूल्यानुसार १५ प्रतिशत उत्पाद-कर, पेटेण्ट दवाओं पर (जिनमें एलकोहल न हो) १० प्रतिशत तथा शृंगार-प्रसाधनों पर २५ प्रतिशत उत्पाद-कर लगाया गया। इसी प्रकार प्लास्टिक के सामान पर मूल्यानुसार २० प्रतिशत कर लगाया गया। मिल के बने ऊनी और सूती धागे पर एक विशिष्ट कर लगाने का प्रस्ताव किया गया। इस प्रकार होजरी तथा कुछ अन्य वस्त्र भी उत्पाद-कर की परिधि के अन्दर आ गए। शीशे और शीशे के सामान, पोर्सलीन तथा चीनी मिट्टी के सामान, जिनमें प्याले-प्लेटें भी शामिल हैं, पर मूल्यानुसार ५ प्रतिशत से १५ प्रतिशत तक का उत्पाद-कर लगाने का प्रस्ताव किया गया। शैक्षणिक तथा अनुसन्धान-शालाओं में प्रयोग होने वाले शीशे के सामान पर कम दर से उत्पाद-कर लगाने की व्यवस्था की गई। १९६१-६२ के बजट में ताँबे और जस्ते पर भी उत्पाद-कर लगा दिया गया। गोलाकार और चादरो पर २०० रु० प्रति मीट्रिक टन तथा नली और ट्यूब (पाइप और ट्यूब) पर मूल्यानुसार १० प्रतिशत कर लगा दिया गया। वानानुकूल मशीनरी (एग्रर कण्ट्रीजनिंग मशीनरी), रिफ्रिजरेटर, बतार के सेट यानी रेडियो (वायरलेस सेट) पर भी उत्पाद-कर लगाने का प्रस्ताव किया गया। १५० रु० के मूल्य के रेडियो उत्पाद-कर से मुक्त थे। १५० रु० से ३०० रु० तक के मूल्य के रेडियो सेट पर रिग्रामती दर से उत्पाद-कर लगा था। ३०० रु० से अधिक मूल्य के रेडियो पर मूल्यानुसार अधिक-से-अधिक २० प्रतिशत कर लगाया जा सकता था। मिल के बने सिल्क के कपड़े पर अभी तक राज्यों द्वारा विक्री-कर लगाया जाता था। उसके स्थान पर एक अतिरिक्त उत्पाद-कर लगा दिया गया।

१९६१-६२ के प्रस्तावों के फलस्वरूप उत्पाद-करों से ३०-६० करोड़ रु० अधिक की प्राप्ति होगी। इसमें से २-३ करोड़ रु० राज्यों को मिलेगा। १९६५-६६ में केन्द्रीय उत्पाद-कर ७०४ करोड़ रुपये मिलने की आशा थी जबकि १९६६-६७ में ७६६ करोड़ रुपये।

५. आय-कर का इतिहास—१८७७ तक कोई नया कर नहीं लगाया गया, पर

सिल्विको और व्यापारिको पर लाइसेन्स-कर, दुर्भिक्ष बीमा-अनुदान (फेमोन इन्स्योरेन्स ग्राण्ट) के खर्च के एक अंश को पूरा करने के लिए आरोपित कर दिया गया और १८७८ में इसके लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास, बंगाल और बम्बई प्रान्तों में अधिनियम पास कर दिये गए। ये अधिनियम १८८६ तक लागू रहे। १८७८ का लाइसेन्स कर १८८६ के आय-कर अधिनियम द्वारा साधारण आय-कर के रूप में परिणत कर दिया गया, जो समस्त भारत पर लागू हुआ। इस अधिनियम के अनुसार कृषि के अतिरिक्त आय के अन्य सभी साधनों पर कर लगा दिया गया। ५०० रु० से लगाकर २००० रु० तक की आय पर, चाहे वह वेतन से प्राप्त हो या प्रतिभूतियों के व्याज से प्राप्त हो, प्रति रुपया ४ पाई कर लगा दिया गया, और २००० रु० के ऊपर की आय और कम्पनियों के लाभ पर ५ पाई प्रति रुपया कर लगाया गया। इसके अनिश्चित कर का और कोई वर्ग न था। इसी प्रकार के अन्य साधनों से प्राप्त आय पर लगभग इसी दर से कर लगाया गया। दान तथा धार्मिक संस्थाओं की आय को छोड़ दिया गया। १९०३ में आर्थिक स्थिति के अच्छे होने के कारण ५०० रु० से १००० रु० तक की आय की छूट प्रदान कर दी गई।

१९१४ के पहले आय-कर से प्राप्ति बहुत कम थी, अर्थात् लगभग ३ करोड़ रुपये के लगभग थी, और घनी वर्ग के लोग बड़ी आसानी से ही मुक्त हो जाते थे। १ अप्रैल, १९३७ से वर्मा के अलग हो जाने से १४० करोड़ रुपये का घाटा हुआ। १९४२-४३ में अधिक-से-अधिक प्रतिशत अनुपात ६४%, १९४३-४४ में ६६% और १९४४-४५ में ६८% थे।

आय-कर से प्राप्त धनराशि-सम्बन्धी इधर हाल के आँकड़े इस प्रकार हैं—

१९५६-५७	२०२९२ करोड़ रु० (एकाउन्ट्स)
१९५७-५८	२१९८३ करोड़ रु० (एकाउन्ट्स)
१९५८-५९	२१८५० करोड़ रु० (बजट का संशोधित अनुमान)
१९५९-६०	२२५०० करोड़ रु० (बजट)

केवल १९५८-५९ के वर्ष को छोड़कर प्रतिवर्ष आय-कर से प्राप्ति बढ़ती रही है। १९५७ के वर्ष में यह देखा गया कि यदि अधिकर और अधिभार को छोड़ दिया जाए तो सबसे अधिक आय कर १५००१—२०,००० रु० के वर्ग से प्राप्त हुआ।

१९६१ के वित्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक विवाहित हिन्दू और अविभाजित हिन्दू परिवार, जिनकी आय २०,००० रु० (वार्षिक) से अधिक नहीं है, के लिए निम्न दरें प्रस्तावित की गई हैं। विवाहित व्यक्ति के लिए यदि उसके कोई बच्चा न हो, कर-मुक्त आय ३००० रु० है। यदि उस पर एक बच्चा ही आश्रित हो तो कर-मुक्त आय की सीमा ३३०० रु० होगी तथा दो या दो से अधिक बच्चों के आश्रित होने पर कर-मुक्त आय की सीमा ३६०० रु० होगी।

कुल आय में १ लाख रु० से अधिक अर्जित आय होने पर अधिभार की दर में परिवर्तन हो जाता है। विशेष अधिभार भी लगता है। १९६१ के वित्त अधिनियम में आय-कर अधिनियम के सम्बन्ध में कुछ संशोधन भी हुए हैं। उदाहरण के

लिए धारा १५ सी के अन्तर्गत सस्थान (अडरटेकिंग) में होटल भी शामिल कर लिया गया है। धाराएँ २३ ए, २५ तथा ५६ ए में भी संशोधन किये गए हैं।

प्रतिवर्ष वित्त अधिनियम (फाइनेन्स एक्ट) पास होता है तो उसके अन्तर्गत आय-कर में प्रतिवर्ष कुछ-न-कुछ परिवर्तन प्रस्तावित होते रहते हैं। १९६० में निम्न परिवर्तन हुए—(१) नये औद्योगिक सस्थानों की आय कर से मुक्ति की अवधि (आय-कर अधिनियम की धारा १५ सी) ५ वर्ष के लिए—१९६५ तक—बढ़ा दी गई। (२) दान में दी जाने वाली धनराशि की कर-मुक्ति सीमा १ लाख ₹० या कुल आय के ५% से बढ़ाकर १½ लाख ₹० या कुल आय के ७½ प्रतिशत तक कर दी गई। (३) १ अप्रैल १९५० से पहले निर्मित सम्पत्ति पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा लगाए गए कर की पूर्ण राशि मरम्मत की करारोप्य आय निर्धारित करने में घटा दी जाने लगी। अभी तक स्थानीय अधिकारियों द्वारा लगाये गए करा की केवल आधी राशि ही घटाई जाती है। (४) कृषि ग्रामीण साख तथा कुटीर उद्योगों से सम्बन्धित सहाकारी समितियों को छोड़कर शेष सहाकारी समितियों की १५,००० ₹० से अधिक आय पर आय-कर लगा दिया।

१९५९-६० के वर्ष की महत्वपूर्ण घटना प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति (डाइरेक्ट टैक्सेज एडमिनिस्ट्रेशन इन्व्वाइरी कमेटी) की रिपोर्ट थी। सरकार ने १९६०-६१ में उसकी सिफारिशों की परीक्षा कर ली तथा अनेक सिफारिशों के सम्बन्ध में अपने निर्णय की घोषणा की। इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है। विधान आयोग को यह कार्य सौंपा गया था कि वह आय कर अधिनियम की मूल-सरचना को प्रभावित किये बिना ही उसमें ऐसा संशोधन प्रस्तुत करे ताकि उसके अन्तर्गत दी गई व्यवस्थाएँ अधिक स्पष्ट हो जाएँ। १९६६-६७ के बजट में १६४ करोड़ ₹० आय-कर से मिलने की सम्भावना है जबकि १९६५-६६ के संशोधन आगणन के अनुसार १:७ करोड़ ₹० आय-कर रूप में प्राप्त हुआ।

६. आय कर में सुधार—सर वाल्टर लेटन ने, जो साइमन कमीशन (१९३०) के वित्त सदस्य थे, तरकारीन आय-कर पद्धति व अनेक दोष बताए तथा उनके सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत किये।

उनके द्वारा सुझाये गए बहुत-से सुधारों (आय कर की प्रणामिता को अधिक तीव्र बनाने) को १९३१-३२ के बजट में ही स्थान दे दिया गया। अक्टूबर, १९३५ में भारत सरकार ने भारतीय आय-कर पद्धति तथा प्रशासन की सम्पूर्ण जांच एक कमेटी द्वारा करवाई, जिसके सदस्य दो अथेज विशेषज्ञ तथा सबसे अधिक अनुभव-प्राप्त एक आय-कर कमिश्नर था। भारतीय आय-कर का संशोधन करने के लिए कमेटी की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय धारासभा द्वारा १९३६ में एक बिल पास किया गया। इसने पहले प्रचलित सीटी-प्रणाली, जिसके अनुसार समान कर की दर पूरी आय पर आरोपित की जाती थी, के स्थान पर वर्ग-प्रणाली (स्लैब सिस्टम) का प्रयोग आरम्भ कर दिया, जिसमें बढ़ती हुई दर से आय के विभिन्न अंशों पर कर आरोपित किया जाता था। आय-कर देन वालों के वर्गों की इस प्रणाली में कुछ

ऐसी व्यवस्था कर दी गई थी कि थोड़ी सख्या वाले धनी लोगो से वसूली अधिक हो और निर्धनो पर भार कम हो तथा कुल वसूली भी पहले की अपेक्षा अधिक मिल सके। अधिनियम की बहुत-सी आशाएँ जाइंट स्टॉक कम्पनियो से सम्बन्ध रखती थी, विशेषकर अवक्षयण अधिदेय (डेप्रिसिएशन एलाउन्स) की परिवर्तित व्यवस्था के कारण इस अधिनियम में पारिवारिक अधिदेय के रूप में आय-कर में छूट देने की व्यवस्था नहीं थी। पारिवारिक अधिदेय (फैमिली एलाउन्स) देने के विरुद्ध मुख्य आपत्ति यह थी कि ऐसी छूट बहुत बड़ी सख्या से देनी पड़ेगी जो छूट बहुत महंगी सिद्ध होगी।

७. कृषि आय पर कर—आय-कर के सुधार का दूसरा अंग कृषि-आय पर कर से सम्बन्धित था। सर वाल्टर लेटन ने इस बात की सिफारिश की थी कि कृषि-आय की कर-मुक्तता निश्चित अवधि में धीरे धीरे हटा देनी चाहिए। यह तर्क कि अन्य देशो में मालगुजारी आय-कर के ही स्थान पर वसूल जी जाती है और यदि आय-कर भी आरोपित कर दिया जाए तो एक प्रकार से दुहरा कर लग जाएगा, युक्तिसंगत नहीं लगता, क्योंकि मालगुजारी उत्पादकता की वृद्धि के अनुपात में अस्थायी बन्दो-बस्त में ही नहीं बढ़ाई जा सकती और स्थायी बन्दोबस्त में तो बिलकुल ही नहीं बढ़ाई जा सकती है। बार-बार तथा पर्याप्त मात्रा में मालगुजारी में हेर-फेर करने से बहुत सी राजनीतिक कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं और बड़े-बड़े भूस्वामियो के साथ-ही साथ छोटे पर भी उसका अनुचित भार पड़ता है। यदि कृषि-आय पर कर आरोपित कर दिया जाए तब ये आपत्तियाँ उपस्थित नहीं होती। भूमि-सम्बन्धी लेखा सुरक्षित रखने तथा प्रशासन और मालगुजारी वसूल करने से सम्बन्धित वर्तमान विशद पद्धति का प्रयोग कृषि लाभ का अनुमान करने में बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकता है। इस कर का एक सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हर प्रकार की आय—कृषीय तथा गैर-कृषीय आय—का हिसाब रखन के कारण उन लोगो की जिनके पास भूमि भी है, गैर-कृषीय आय पर ऊँची दर से आय-कर आरोपित किया जा सकेगा। इसके साथ ही-साथ यह परिवर्तन करके बचाव के लिए उद्योगो में बचाये हुए धन को भूमि में लगाने की प्रवृत्ति की रोकथाम भी करेगा।

१९३५ के गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट ने प्रत्येक प्रान्त को व्यक्तिगत रूप से अनुमति दे रखी थी कि यदि वे चाहें तो अपने प्रान्त की कृषि-आय पर कर आरोपित कर सकते हैं। १९३६ में आसाम की धारातमा ने कृषि-आय-कर विधेयक, जिसे सरकार की ओर से पेश किया गया था, थोड़े से चोटो के आधिनय से पास कर दिया। बंगाल, बिहार और ट्रावनकोर ने भी आसाम का अनुकरण किया और कृषि-आय पर कर लगा दिया।

हैदराबाद में कृषि-आय पर १९५०-५१ में कर लगाया गया, परन्तु विधान और नियमों के लाभू न हो सकने के कारण उस वर्ष यह कर वसूल न किया जा सका। कृषि-आय पर कर लगाने के सम्बन्ध में राजस्थान के विधानमण्डल ने २६ अप्रैल, १९५३ को कानून पास किया। १९५४-५५ के बजट में मद्रास सरकार ने

घाय, कहवा, खर और काली मिर्च पर कृषि-आय-कर लगाना प्रस्तावित किया।

यू० पी० कृषि-आय-कर विधान को संशोधित करने के लिए ११ मई, १९५४ की धारासभा में एक बिल पेश किया गया, जिसके अन्तर्गत अधिकर (सुपर टैक्स) समाप्त करने और कर-मुक्ति की सीमा ८,००० रु० निर्दिष्ट करने की व्यवस्था थी। बिल में कर की नई दरें भी प्रस्तावित की गईं, यथा—

कर लगने वाली आय के पहले १५०० रु० पर कोई कर नहीं लगेगा।

बाद के ३५०० रु० पर १ आ० प्रति रु० का कर लगेगा।

, १०,००० ,, ,, २ आ० प्रति रु० ,, ,,

,, १०,००० ,, ,, ४ ,, ,, ,, ,,

,, १०,००० ,, ,, ८ ,, ,, ,, ,,

,, शेष आय पर १० ,, ,, ,, ,,

८ उत्तराधिकार-कर—१५ अक्टूबर, १९५३ से हमारे देश में उत्तराधिकार-कर (एस्टेट ड्यूटी) लागू कर दिया गया है। इस कर को लगाने के सम्बन्ध में बहुधा यह तर्क उपस्थित किया जाता है कि सम्पत्ति को एकत्र करने में सरकार का बहुत योग होता है। अतः व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त कर के रूप में इन सम्पत्ति का कुछ भाग ले लेना उचित ही है। परन्तु सच तो यह है कि उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति कर देने की क्षमता की सूचक है, अतएव उस पर कर लगाना उचित है। व्यक्तियों के लिए कर की न्यूनतम सीमा १ लाख रु० और समुक्त परिवार के लिए ५०,००० रु० है।

मिर्च, १९५८ में उत्तराधिकार कर (संशोधन) अधिनियम पार हुआ। इसके अन्तर्गत (१) मुक्ति-सीमा एक लाख रु० से घटाकर पचास हजार रुपये कर दी गई, तथा कर की दर निम्न वर्गों के लिए कुछ कम कर दी गई। (२) मिताक्षर, महमकदूम या अलियसयान की विधान प्रणाली का अनुसरण करने वाले अविभाजित हिन्दू परिवार के मृत सदस्य की सम्पत्ति पर कर के लिए समुक्त पारिवारिक सम्पत्ति में न केवल मृतक के वरन् पैतृक वंशजों के सदायद हितों (कोगार्सनरी) को ध्यान में रखने की व्यवस्था की गई है। (३) निर्धारण (एसेस-मेण्ट) तथा अपील-सम्बन्धी व्यवहार अन्य प्रत्यक्ष करों के अनुरूप कर दिया गया है। कृषि भूमि पर उत्तराधिकार-कर राज्याय विषय है। संविधान की धारा २५२ के अन्तर्गत उत्तराधिकार-कर (संशोधन) अधिनियम १९५८ के राज्यो ने स्थित कृषि-भूमि पर लागू होने के लिए राज्याय विधानमण्डलों की स्वीकृति आवश्यक थी। अप्रैल, १९६० में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त हुई। सभी 'स्वीकृति' को कार्य-रूप देने के लिए उत्तराधिकार-कर (संशोधन) अधिनियम १९६० पार हुआ। दोनों संशोधन अधिनियम (१९५८, १९६०) १ जुलाई, १९६० से ही लागू हुए। १९५८ के संशोधन के अन्तर्गत (१) और (२) व्यवस्था (जिसकी ऊपर चर्चा की जा चुकी है) तभी लागू होगी जबकि मृत्यु १ जुलाई १९६० या उसके बाद हुई हो।

उत्तराधिकार-कर (संशोधन) अधिनियम १९६० यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत

करता है कि जम्मू और काश्मीर, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल को छोड़कर शेष सभी राज्यों में स्थित कृषि-भूमि पर यह लागू होगा। १९५६-६० में इस कर से २७८ करोड़ रु० प्राप्त हुए। सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सशोधित अधिनियम को लागू करने के लिए उत्तराधिकार-कर नियमों में आवश्यक सुधार कर लिया है। १९६६-६७ में भू-सम्पत्ति कर नियम में कुछ परिवर्तन किए जाएंगे, जिससे ७० लाख रुपया सरकार को अधिक मिलेगा। १ लाख रुपये को छोड़कर बाकी सारी रकम राज्य सरकारों को बाँट दी जाएगी।

६. सम्पत्ति-कर (वैल्य टैक्स)—इस कर के सम्बन्ध में डॉ० वाल्डर ने अपनी रिपोर्ट (रिपोर्ट ग्रान इण्डियन टैक्स रिफार्म) में सुझाव दिया था। यह कर एक व्यक्ति की वास्तविक सम्पत्ति पर लगता है। यह कर वार्षिक है तथा व्यक्तियों पर दो लाख रु० तक नहीं लगता। वास्तविक सम्पत्ति कुल सम्पत्ति के मूल्य से देय ऋण घटा देने पर मावूम होती है। इस कर के लिए निजी स्वामित्व के अन्तर्गत चल और अचल सभी प्रकार की सम्पत्ति है, किन्तु कुछ सम्पत्तियाँ विशेष रूप से मुक्त हैं। उदाहरण के लिए—

- (१) कृषि-भूमि।
- (२) ट्रस्ट के अन्तर्गत दातव्य सम्पत्ति।
- (३) लकड़ी का सामान, बरतन आदि।
- (४) जेवरात २५००० रु० तक।
- (५) डाइग, चित्रकारी आदि।
- (६) अदायगी के लिए अपरिपक्व बीमा पॉलिसी की रकम।
- (७) नये औद्योगिक सस्थानों के हिस्से आदि।

१०. व्यय-कर (एक्सपेन्डीचर टैक्स)—यह पूर्णतः वैयक्तिक कर है, जो व्यक्तियों तथा अविभाजित हिन्दू परिवारों के वैयक्तिक उपयोग पर किये व्यय पर लगता है। यह कर कम्पनियों पर लागू नहीं होता। निम्न व्यय कर-मुक्त हैं—

- (१) अचल सम्पत्ति प्राप्त करने पर व्यय।
- (२) बीड, निक्षेप (डिपॉजिट), हिस्से और प्रतिभूतियों में विनिपुक्त घन।
- (३) उधार लिये ऋण की अदायगी।
- (४) उपहार।
- (५) जीवन-बीमा तथा आग और चोरी के बीमा का प्रीमियम।
- (६) दिये गए कर।
- (७) किसी दाव (कचहरी के) में किये गए वैधानिक व्यय।
- (८) निश्चित सीमा के अन्दर अपने आश्रितों के विवाह, इलाज, शिक्षा आदि पर व्यय।

१९६६-६७ के वजट के अनुसार इसको हटा देने का निश्चय किया गया है, क्योंकि इससे कर कम इकट्ठा होता है और कर इकट्ठा करने पर बहुत घन व्यय हो

जाना है।

११ उपहार-कर—यह पहली अप्रैल १९५७ के बाद दिया गए सभी उपहारों पर लागू है तथा १९५८-५९ के वर्ष से लागू किया गया है। यह कर सभी के द्वारा देय है चाहे व्यक्ति हो या कम्पनी। यह कर देन योग्य उपहारों के कुल मूल्य पर लगाया जाता है। यह कर निम्न दत्ताओं में नहीं लगता—

(१) भारत से बाहर स्थित अचल सम्पत्ति के उपहार पर कोई कर नहीं

लगता।

(२) भारत में रहने वाले विदेशियों पर भारत से बाहर स्थित चल सम्पत्ति पर भी कोई कर नहीं लगता।

(३) विदेशी कम्पनी को भारत से बाहर स्थित चल सम्पत्ति पर उसी हालत में कर लगना है जबकि कम्पनी भारत में हो।

इनके अलावा कुछ उपहार कर-मुक्त हैं

(१) दातव्य सस्या या कोष को दिए उपहार।

(२) पत्नी को किसी एक वर्ष या कई वर्षों में अधिक से अधिक १ लाख रु० का उपहार।

(३) बच्चों की शिक्षा के लिए उपहार।

(४) बोनस, ग्रेचुटी, पन्धान।

(५) करदाता द्वारा किए जाने वाले राजस्व, या पक्षे के लिए उपहार

आदि।

उपहार-कर १९५६-५७ के बजट के अनुसार इनकी दरों में कुछ परिवर्तन किए जाएंगे ताकि उन्हें भू-सम्पत्ति-कर के बराबर कर दिया जाए। इस प्रकार दरों को कम करने से १७१ करोड़ रुपया सरकार को पहले से कम मिलेगा।

१२ अफीम—१९३५ के अन्त तक अफीम से आय प्राप्त करने के तीन माध्यम थे—

(१) विद्वानों का भेजन के लिए मन्कारी कारखानों में निमित्त अफीम से प्राप्त एकाधिकार लाभ, (२) अफीम की खरीदारी पर आरोपित नियामक कर से प्राप्त आय जो कि राजपूताना और मध्यभारत की रियासतों से भेजी जाती थी, और (३) ब्रिटिश भारत में अफीम के उपभोग से प्राप्त एकाधिकार लाभ, जोकि लाइसेंस फीस अथवा ठेकादारी की फीस के रूप में मिलता था। यह आय उत्पाद-कर के अन्तर्गत दिखलाई जाती थी और पहन दो साधनों से प्राप्त आय अफीम के अन्तर्गत दिखलाई जाती थी।

फरवरी, १९०५ में लार्ड रीडिंग ने यह घोषणा की कि भविष्य में सरकार की नीति अफीम के निर्यात का लीग ऑफ नेशन्स के आदेशानुसार औपनिवेशिक अफीम प्रयोगों का दोहन और सब प्रकार के प्रयोगों के लिए पूर्ण बन्द कर देना की है। भारत सरकार इस बात से भी सहमत हो गई कि १९३५ के पहले ही अफीम का निर्यात पूर्ण बन्द कर दिया जाएगा, जिसका फल यह हुआ कि अन्य प्रयोगों के लिए अफीम के निर्यात से प्राप्त आय का १९३५ से अन्त हो गया। अब अफीम से प्राप्त

आय भारत में उपयोग के लिए उसकी बिन्धी पर सीमित है जो बहुत ही नियमित है।

आजकल अफीम से प्राप्त आय पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गई है, जबकि १९१३ के पहले के तीन वर्षों की वार्षिक औसत आय लगभग ८ करोड़ रुपये थी, १९५६-५७ में केवल २.३० करोड़ रुपये^१ से भी कम हो गई है। १९५६-६० में अफीम से प्राप्त आय ४ १६ करोड़ रु० थी। १९६०-६१ के बजट (सशोधित) अनुमान के अनुसार प्राप्त आय ५ ६६ करोड़ रु० थी तथा १९६१-६२ के बजट अनुमान में अफीम से प्राप्त आय ६ २५ करोड़ रु० आंकी गई है।^२

राज्यीय आय के साधन

१३. मालगुजारी—खण्ड १ के अध्याय १२ में इस विषय पर हम प्रकाश डाल चुके हैं। १९५६-५७ में कुछ प्रमुख राज्यों की मालगुजारी की आय इस प्रकार थी—आन्ध्र ७.५१ करोड़ रु०, आसाम २.२४ करोड़ रु०, केरल १.०५ करोड़ रु०, उड़ीसा १ ५८ करोड़ रु०, उत्तर प्रदेश १६.०८ करोड़ रु० तथा पश्चिमी बंगाल ४.४ करोड़ रु०। १-११-११५६ से ३१-३-१९५७ की अवधि के लिए पंजाब, राजस्थान, मध्य-प्रदेश, मद्रास तथा बिहार की मालगुजारी आय क्रमशः १.५६ करोड़ रु०, २.३५ करोड़ रु०, ४ २२ करोड़ रु०, २ ४२ करोड़ रु० तथा ३.६५ करोड़ रु० थी।^१

१४. आबकारी (एक्साइज)—आबकारी की आय नशे की वस्तुओं, जैसे गाँजा, भाँग, अफीम इत्यादि, के बनाने तथा बिक्री से प्राप्त होती है।

मद्यपान के दोष को रोकने के विषय में इस बात पर सभी सहमत हैं कि बड़े साहस और अध्यवसाय के साथ काम करना आवश्यक है, पर यह कैसे किया जाए इस पर एकमत नहीं है। कांग्रेस मन्त्रिमण्डल द्वारा प्रान्तीय सरकार का कार्य भार अपने हाथों में लेने के पहले सरकार यथासम्भव मूल्य बढ़ा देने के उपाय पर विशेषतया निर्भर थी, परन्तु मूल्य इतना अधिक नहीं बढ़ाया जाता था कि अवैध रूप से शराब बनाना आरम्भ हो जाए। शराब के उपयोग में कमी करने के दूसरे उपाय राशनिंग, दुकानों की सख्या में कमी, पास रखी जाने वाली शराब की मात्रा में कमी, शराब की तैली में कमी, बिक्री के घण्टों में कमी आदि थे। बहुत-से प्रान्तों ने मद्य-निषेध का कार्यक्रम आरम्भ कर दिया जो कि विभिन्न प्रान्तों की स्थानीय स्थिति और इसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली आर्थिक कठिनाई को सहन करने की शक्ति पर निर्भर था। इस मामले में मद्रास सरकार ने बड़े साहस से सलेम जिले में पूर्ण मद्य-निषेध करके नेतृत्व किया। बिहार ने इसका अनुकरण किया। जुलाई, १९३८ में बम्बई ने अहमदाबाद नगर में तथा अगस्त, १९३९ में बम्बई नगर तथा टापू में पूर्ण मद्य-निषेध प्रचलित

१. ये केन्द्रीय सरकार का आय से सम्बन्धित आँकड़े हैं।

२. देखिए, इण्डिया १९६१, पृ० २१५।

३. देखिए, स्टैटिस्टिकल यन्ट्रिब्यूट १९५७-५८, पृ० २१७-२१८।

कर दिया। दम्बई में कांग्रेस सरकार की पूर्ण निषेध की नीति प्रचलित करने में कुछ कानूनी और व्यवस्था की कठिनाइयों के कारण १९४० में निषेध-नियमों को कुछ ढीला करना पड़ा। कुछ प्रान्तों ने छोटे-छोटे क्षेत्रों को चुना, अन्य ने दुकानों को बन्द करवाकर शराब की बिक्री को रोकथाम की और लाइसेन्स पर नियन्त्रण रखा। मद्रास ने २ अक्टूबर, १९४८ से पूर्ण मद्य-निषेध प्रचलित कर दिया है, जिससे १७ करोड़ रुपये की आय का घाटा हुआ। दम्बई ने ४ वर्ष में पूर्ण निषेध का इरादा किया, जो कि १९४७ से आरम्भ हुआ और ७ अप्रैल, १९५० में पूरा हो गया। यदि अन्य राज्य जरा धीमी गति से चलने के लिए बाध्य हैं तो ऐसा आधिक विचारों के फलस्वरूप अनिवार्य हो गया है। परन्तु सभी राज्य यथासम्भव तीव्र गति से एक ही दिशा में चल रहे हैं और सबने एकमत होकर पूर्ण निषेध को ही मद्यपान के दोष दूर कर देने का एकमात्र उपाय मान लिया है।

मद्य-निषेध के विरोधी बराबर यह कहा करते हैं कि यदि इसकी रोक के लिए जल्दी की गई अथवा कठोर नियम प्रचलित किये गए तो दोहरी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो तुरन्त आय में कमी हो जाएगी और प्रतिबन्ध लगाने वाली मस्याओं पर, जो चौर्यपण तथा अवैध शराब खींचने की रोकथाम के लिए स्थापित की जाएंगी, खर्च भी बढ़ जाएगा। करोड़ों रुपये, जो अन्यथा शिक्षा, सिंचाई की सुविधाओं तथा देश की उन्नति के लिए अन्य कामों पर खर्च किए जा सकते हैं, वे सब व्यर्थ हो जाएंगे। यदि पूर्ण मद्य-निषेध के लिए एकबारगी प्रयास किया गया तो यद्यपि वे कठिनाइयाँ बड़े भयकर रूप में उपस्थित होंगी। दूसरा भय इस बात का है कि घुराई, जो भय के कारण दबा दी जाती है, वह कोई दूसरा उग्रतर रूप धारण करके उपस्थित होती है। इस प्रकार यह शिकायत की जाती है कि देशी शराब के प्रयोग पर रोकथाम लगाने के परिणामस्वरूप विदेशी शराब के प्रयोग में वृद्धि हुई है और लोग शराब के स्थान पर मेथिलेटिड स्पिरिट पीते पाये गए हैं।

तीसरी पञ्चवर्षीय योजना में केन्द्रीय आवधिकारी से ३९८.८७ करोड़ रु० राज्यों को मिला। १९६६-६७ के इस वर्ष १६५.६६ करोड़ रु० मिलेगा।

१५ आय के अन्य साधन—(१) स्टाम्प—स्टाम्प से आय व्यापार तथा न्यायालय-सम्बन्धी स्टाम्पों की बिक्री से प्राप्त होती है। न्यायालय-सम्बन्धी स्टाम्प वे हैं जो मुकदमों और अन्य आवश्यक कागज़ों की फीस के रूप में माल और फौजदारी की कचहरियों में जमा किये जाते हैं। व्यापारिक स्टाम्प वे हैं जिनका प्रयोग जन व्यापारिक लेन-देन में होता है जो लिखा-पढी में होते हैं, जैसे जायदाद, भूमि और हुण्डी आदि एक व्यक्ति से दूसरे के पास जाने में। न्यायालय में प्रयोग किए जाने वाले स्टाम्प की आय कुछ लोगों के मत से वास्तव में कर से प्राप्त आय नहीं है, क्योंकि वे इसे न्यायालय-जैसे महुँगे विधान की सेवामें के लिए दी जाने वाली रकम समझते हैं। मद्रास राज्य के विभाजित होने से पूर्व स्टाम्पों से सबसे अधिक आय मद्रास में होती थी और सबसे कम आसाम में। मद्रास के विभाजित होने पर सबसे अधिक आय

बम्बई में है।

(२) वन—इस सावन से आय मुख्यतः लकड़ी तथा अन्य उत्पत्ति की बिक्री, पशु चराने की फीस, पेड़ों तथा जंगल की अन्य उत्पत्ति को काटने के लाइसेंस की फीस द्वारा प्राप्त होती है। इस प्राप्त आय की वृद्धि की बहुत अच्छी सम्भावना दिखाई पड़ती है। राष्ट्रीय सरकार, जिनके अधिकार में ये जंगल दे दिये गए हैं, प्रतिवर्ष करीब २३ करोड़ रुपये का वास्तविक लाभ आर्थिक अवसाद-काल के आरम्भ तक उठाती रही है। १९५६-५७ में विभिन्न प्रान्तों के वनों से निम्न आय प्राप्त हुई—आंध्र १.५८ करोड़ रु०, आसाम ६६.२६ लाख रु०, बम्बई २.६३ करोड़ रु०, बिहार ५७.१६ लाख रु०, मध्य प्रदेश ३.३५ करोड़ रु०, मद्रास ६७.६५ लाख रु० तथा उत्तर प्रदेश ५.०२ करोड़ रु०। जंगलों से अधिक और स्थायी आय प्राप्त करने के लिए आरम्भ में बहुत अधिक खर्च की आवश्यकता है।

(३) रजिस्ट्रेशन—रजिस्ट्रेशन से आय न्यायालयों में प्रयोग किये जाने वाले स्टाम्पो से प्राप्त आय की ही तरह होती है और विशेषकर रजिस्ट्री किए जाने वाले प्रलेखों (डॉक्यूमेंट) के मूल्य पर निर्भर होती है। दानपत्रों तथा स्थायी सम्पत्ति के अय-विक्रय के सम्बन्ध में रजिस्ट्री होना अनिवार्य है और अन्य मामलों में ऐच्छिक। रजिस्ट्रेशन की फीस को एक प्रकार से सेवाओं का मूल्य कह सकते हैं। इससे लाभ तर्क में स्थिरता, उभय पक्ष वालों का सारी कार्यवाही को प्रकाशित कर देने के लिए बाध्य होना तथा लिखा-पढ़ी में एक सन्तोषप्रद सबूत का होना, जिससे या तो भविष्य में मुकदमेबाजी कम हो जाए अथवा न्यायालयों में उनका निर्णय जल्दी हो जाए, आदि है।

(४) परिगणित टैक्स—१९२१ के सुधारों के अनुसार प्रान्तीय सरकारों को इन करों के आरोप का अधिकार दे दिया गया था, पर प्रान्तों ने इन करों के विनाश लाभदायक न होने अथवा किसी अन्य कारण से अपन इस अधिकार का समुचित रूप से प्रयोग नहीं किया। जुए और मनोरंजन पर कर अनेक प्रान्तों द्वारा लगाये गए हैं, जैसे बंगाल, बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश और आसाम। उनसे प्राप्त आय बढ़ रही है। १६. प्रान्तीय स्वायत्त-शासन के अन्तर्गत नये कर : बिक्री-कर—गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया एक्ट १९३५ के अन्तर्गत प्रान्तीय स्वायत्त शासन के १ अप्रैल १९३७ से आरम्भ होने के कारण प्रान्तों में कुछ ऐसे नये कर लगाये गए जिनके आरोपण का अधिकार उन्हें नये विधान में प्राप्त था। इन नये करों के आरोपित करने का आशय आय और व्यय के बीच के व्यवधान को पूरा करता था। यह व्यवधान कुछ तो कांग्रेस मन्त्रिमण्डल की मर्यादा-निर्बंध नीति और कुछ सामाजिक सेवा-संस्थाओं को अधिन शक्तिशाली बनाने के लिए किये गए व्यय के कारण उत्पन्न हो गया था। इन नये करों से, जिन्हें प्रान्तों ने प्रचलित किया, बिक्री-कर (सेल्स टैक्स) यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

बम्बई के १९३६ के बिक्री-कर अधिनियम (सेल्स टैक्स एक्ट) के अनुसार चुनी हुई दो वस्तुओं—मोटर स्प्रिट तथा मशीनों द्वारा निर्मित वस्त्र—की फुटकर

विक्री पर विक्री-कर लगाने का अधिकार प्राप्त था। व्यवस्था की कठिनाइयों के कारण कपड़े पर विक्री-कर लागू नहीं किया गया। १९३६ का मद्रास का सामान्य विक्री कर अधिनियम (जनरल सेल्स टैक्स एक्ट) सर्वांगीण था, जो सभी वस्तुओं पर लागू होता था। यह कर मद्रास में कुल विक्री से आवश्यक खर्चें निकाल देने पर वास्तविक विक्री पर लगाया जाता था। वस्तुओं की विक्री पर इसी प्रकार का सामान्य कर बंगाल में बंगाल वित्त अधिनियम द्वारा १९४१ में आरोपित किया गया।^१

नये करों ने प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकारों के करारोपण और वसूली के वैधानिक अधिकारों के प्रश्न को जन्म दिया। उदाहरण के लिए पेट्रोल-कर, जिसे मध्य प्रदेश की सरकार ने लगाया था, के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार ने सघानीय न्यायालय में यह मुकदमा चलाया कि प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार के कर लगाने (उत्पाद-कर) के अधिकारों का, जो उन्हीं के लिए सुरक्षित हैं, अतिक्रमण कर रही है। सघानीय न्यायालय ने इस आधार पर प्रान्तीय सरकारों के हित में न्याय किया कि केन्द्रीय विधानमण्डल को वस्तुओं पर उत्पाद-कर लगाने का उसी समय तक एकाकी अधिकार है जब तक कि वे किसी प्रान्त-विशेष की सम्पत्ति नहीं बन जाती (अर्थात् उत्पादन अथवा निर्माण की स्थिति तक ही) और उसके बाद प्रान्तीय सरकारों को उन वस्तुओं की विक्री पर कर लगाने का एकाकी अधिकार है। सघानीय न्यायालय के इस हितकारी फैसले ने 'वस्तुओं की विक्री पर' (देखिए सेक्शन ३७) वाक्यांश का वास्तविक अर्थ स्पष्ट कर दिया और प्रान्तों के लिए कर लगाने का एक विस्तृत क्षेत्र खोल दिया। साथ-ही-साथ, जैसा कि प्रधान न्यायाधीश ने भी नोट किया था, पारस्परिक सहनशीलता की अत्यन्त आवश्यकता है, ताकि करारोपण के अधिकार वाली दोनों सरकारों कहीं अपने-अपने अधिकारों का एक साथ ही प्रयोग करके आन्तरिक परोक्ष-कर इतना न बढ़ा दें कि वस्तु का मूल्य इतना अधिक ऊँचा हो जाए कि उसका उपभोग अत्यन्त कम हो जाए। १९६५-६६ के वजत अनुसार इससे २८७३ करोड़ ६० इकठ्ठा होगा।

मोटर वेहिकल्स अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित कर तथा कुछ अन्य कर भी प्रांतीय आय के साधन हैं। मोटर वेहिकल्स अधिनियम के अन्तर्गत १९५६-५७ में पश्चिमी बंगाल को १.३६ करोड़ ६०, उत्तर प्रदेश को १.४० करोड़ ६०, उड़ीसा को ४७ ८३ लाख ६०, केरल को ५१.४८ लाख ६०, आसाम को ५४.५२ लाख ६० तथा आन्ध्र को २.०० करोड़ ६० की आय हुई, जबकि १-११-१९५६ से ३१-३-१९५७ की अवधि में बम्बई को ८६.७३ लाख ६०, बिहार को २.४८ लाख ६०, दिल्ली को १.०१ लाख ६०, मध्य प्रदेश को ७.१७ लाख ६०, मद्रास को २५.३५ लाख ६०, पंजाब को २५.०४ लाख ६०, राजस्थान को १६.६५ लाख ६० की आय हुई।^२

१. अन्य वस्तुएँ, जो सेल्स टैक्स के लिए चुनी गईं, बिजली, तम्बाकू तथा विलासिता का वस्तुएँ, जैसे मोटरगाड़ी, रेडियो आदि थीं। बिहार में १९४८ से कोयला, बोक और गन्ना भी विक्री-कर के अन्तर्गत आ गए हैं।

२. देखिए, स्टेटिस्टिकल एक्सट्रेण्ड, १९५६-५७, पृ० २१७-२२१।

१७. भारत में सार्वजनिक व्यय—सार्वजनिक व्यय का निम्न वर्गीकरण किया जा सकता है ।^१

(१) राष्ट्रीय सुरक्षा—पैदल सेना, समुद्री सेना और हवाई सेना, सरहद्दी तथा सैनिक महत्ता वाली रेलें, बन्दरगाह तथा रक्षा से सम्बन्धित कारखाने और युद्ध, जैसे सरहद्दी मोर्चा इत्यादि, पर किया जाने वाला व्यय इसके अन्तर्गत आता है ।

(२) आन्तरिक शांति और व्यवस्था कायम रखना—इसके अन्तर्गत (क) पुलिस, न्यायालय और जेल पर किया जाने वाला व्यय, (ख) सामान्य प्रशासन का व्यय, (ग) कर-वसूली पर किया जाने वाला व्यय, (घ) राजनीतिक व्यय, जिसमें विधानमण्डल पर खर्चा, विदेशों के प्रतिनिधियों तथा राजदूतों पर किया जाने वाला व्यय और (च) कर्मचारियों की पेन्शन, भत्ते तथा अन्य व्यय आते हैं ।

(३) राष्ट्रीय उन्नति—इसके अन्तर्गत (क) नैतिक तथा (ख) आर्थिक उन्नति के हेतु किये जाने वाला व्यय आता है । पहले शीर्षक में वैज्ञानिक तथा अन्य प्रकार की शिक्षा, उपचार तथा सफाई-सम्बन्धी खर्च और दूसरे शीर्षक में रेल, सिंचाई, सरकारी सड़कें तथा इमारतों के बनाने के विभाग पर खर्च, कृषि तथा अकाल पर व्यय, तार और डाक पर खर्च और सरकारी ऋण पर दिये जाने वाला व्याज आदि आते हैं । अनुत्पादक ऋण का व्याज पहले अथवा दूसरे शीर्षक के ही अन्तर्गत रखा जाना चाहिए ।

भारत का सार्वजनिक व्यय लगातार बढ़ता रहा है । स्वर्गीय गोखले ने बहुत दिन हुए कहा था, “राजकीय व्यय की वृद्धि हमेशा चिन्ता और भय का कारण नहीं होनी चाहिए ।” इस बारे में बहुत-कुछ इस बात पर निर्भर रहता है कि व्यय की वृद्धि किसलिए की गई है तथा उसका परिणाम क्या हुआ है ।

सितम्बर, १९३६ में द्वितीय विश्व-युद्ध छिड़ जाने और विशिष्ट रूप से १९४१-४२ के पश्चात् जापान के युद्ध में सम्मिलित हो जाने के बाद रक्षा का व्यय बहुत अधिक बढ़ गया ।

युद्ध छिड़ जाने के ठीक पूर्व भारतीय सेना को नवीनतर रूप देने के सम्बन्ध में चेटफील्ड कमेटी के सुझावों को इंग्लैंड तथा भारत की सरकार ने स्वीकार कर लिया था । भारतीय सेना को नवीनतम रूप देने के व्यय का अनुमान लगभग ४५-७७ करोड़ रुपये कर दिया गया था, जो इंग्लैंड की सरकार से ५ वर्ष के अन्दर प्राप्त होने वाला था, जिसका ३ भाग तो भेंट के रूप में और बाकी ३ कर्ज के रूप में था, जिसे भारत सुविधा के साथ धीरे-धीरे लौटाता । युद्ध छिड़ जाने के कारण इन प्रस्तावों पर फिर से विचार करना आवश्यक हो गया, क्योंकि सेना का अभिनवीकरण तत्कालीन आवश्यकता के अनुसार तथा बड़े हुए मूल्य के आधार पर होना चाहिए था । इसके अतिरिक्त भारत में ही पूरी शक्ति पर उत्पत्ति करने के लिए बहुत अधिक खर्च की आवश्यकता थी, ताकि कारखानों, युद्ध और आवश्यकताओं की

१. देखिए, शाह, 'सिमसोनी ईअर्स ऑफ इण्डियन किनाल्स', पृष्ठ ४४-४६ ।

वस्तुओं के निर्माण की शक्ति बढ जाए और बहुत-सा सामान सुरक्षित रखा जा सके। भारत को युद्ध का मोर्चा लेने के लिए तैयार रखने के उपायों पर खर्च करने से भी रक्षा-व्यय पर काफी धन खर्च किया गया। इन सब बातों को विचाराधीन रखते हुए नवम्बर, १९३६ में इंग्लैण्ड की सरकार और भारत सरकार के बीच एक आर्थिक समझौता हुआ, जिसके अन्तर्गत भारत को निम्न व्यय अपने ऊपर लेने पड़े—

(क) लड़ाई के पहले के व्यय की निर्धारित ३६ ७७ करोड़ रु० की रकम,

(ख) मूल्य की वृद्धि के लिए अतिरिक्त धन (३५५ करोड़ रु०),

(ग) युद्ध-सम्बन्धी उन उपायों का खर्च, जिनके लिए पूर्ण रूप से भारत को इसलिए उत्तरदायी समझा जा सकता था क्योंकि वे व्यय भारत अपने हित के लिए कर रहा था (३५.४० करोड़ रुपये), और

(घ) एक करोड़ रुपये की एकत्र रकम जो भारत की रक्षा-सेना को समुद्र-पार बनाए रखने के लिए विदेशों में रखी गई थी (८४१ करोड़ रु०)।

पहले शीर्षक से चौथे तक का योग ८४.१३ करोड़ रुपये होता है। युद्धकाल में भारत का रक्षा पर वार्षिक व्यय जितनी रकम से पहले से तीसरे शीर्षक तक के खर्चों के योग से बढना था वह रकम इंग्लैण्ड की सरकार से मिलनी थी। केवल शर्त इतनी थी कि युद्ध क पश्चात् जो-कुछ भी समझौता भारत में दोनों देशों के हित के दृष्टिकोण से खरीदी हुई युद्ध-सामग्री के बचे हुए कोश के सम्बन्ध में होगा, उसका अनुसार परिवर्तन हो सकता था। अग्रभाववाली खर्चों के विषय में अलग से विचार होना था। भारत को अपनी उत्पात्ति में से ही अपने युद्ध-सम्बन्धी उपाय पर जो-कुछ खर्च करना था उसके लिए तथा युद्ध-सम्बन्धी सयुक्त उपायों पर व्यय होने वाली रकम में से अपने हिस्से के लिए, जिसमें वस्तुओं को सुरक्षित रखन का खर्च भी सम्मिलित था, मूल्य देना था और इंग्लैण्ड की सरकार को बाकी सभी इक्की रखा जाने वाली युद्ध-सम्बन्धी वस्तुओं के लिए तथा उस सारी पूंजी के लिए, जो उत्पात्ति तथा एकत्र रखने की सुविधाओं के बढाने के लिए लगाई गई थी।

युद्ध-काल की तरह पूरी सेना को बनाए रखने के स्थान पर शान्ति-काल में ऐच्छिक पद्धति के अनुसार थोड़ी-सी सैनिक सेवा बनाए रखने का भी सुझाव दिया गया था। युद्ध की समाप्ति के बाद आशा की जाती थी कि रक्षा-व्यय में भारी कमी होगी, परन्तु यह आशा सफल नहीं हो सकी जैसा कि नीचे के आंकड़ों से प्रकट है—

भारत का रक्षा-व्यय करोड़ रु० में (ग्रॉस रेवेन्यू अकाउण्ट)

१९४७-४८ १९४८-४९ १९४९-५० १९५०-५१

(७^१ माह)

८६.६३ १४६.०५ १४८.८६ १६४.१३

१. कोष्ठक में लिखा हुए संख्याएँ १९४९-५० के रक्षा-व्यय से सम्बन्धित हैं। १९३६ का आर्थिक समझौता ३१ मार्च, १९४७ को रद्द कर दिया गया।

सेना के भारतीयकरण की योजना लगभग पूर्णतया कार्यान्वित हो चुकी है और अब लगभग सारी सैन्य-शक्ति भारतीयों से ही निर्मित है। स्वतन्त्रता के बाद रक्षा-व्यय के बढ़ने के प्रधान कारण विभाजन के फलस्वरूप भारत की सीमा का बढ़ जाना, देशी राज्यों की रक्षा का भार भारत के कंधों पर पड़ना, रक्षा के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता का प्रयत्न करना, आदि हैं।

१९५१-५२ के बाद सार्वजनिक व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई है। १९५१-५२ में केन्द्र तथा राज्याधीय सरकारों का कुल व्यय ९९८ करोड़ रु० था। १९५५-५६ में यह राशि १,४७० करोड़ रु० हो गई तथा १९६०-६१ के बजट-अनुमान के अनुसार यह २,५८७ करोड़ रु० है। हर्ष की बात यह है कि सार्वजनिक व्यय की यह वृद्धि चिन्ता का विषय नहीं है, क्योंकि वृद्धि मुख्यतः विकास कार्यों पर व्यय बढ़ने के कारण हुई है। विकास-कार्यों पर किए जाने वाले व्यय का कुल व्यय से अनुपात १९५१-५२ में ४८ प्रतिशत, १९५५-५६ में ६० प्रतिशत तथा १९६०-६१ में ६६ प्रतिशत था। केन्द्रीय सरकार का कुल खर्चा राजस्व-लेखा के लिए १९६६-६७ के लिए २१७० करोड़ रुपया निर्धारित किया गया, जिसमें से रक्षा-व्यय ७९८ करोड़ रुपया और नागरिक प्रशासन के लिए १३७२ करोड़ रुपया और पूंजी लेखा २२०७ करोड़ रुपया होगा। कुल व्यय ६२७, विकास के लिए ५२७, अविकसित १०० तथा रक्षा के लिए १२१ करोड़ रुपये होगा।

१८ नागरिक प्रशासन पर व्यय—नागरिक प्रशासन पर व्यय में हुई वृद्धि के सम्बन्ध में लोगों का सामान्य विरोध यही था कि भारतीय प्रशासन सप्ताह-भर में सबसे अधिक मँडगा था और जो वेतन तथा भूति उच्चाधिकारियों को दिए जाते थे, जिसमें कुछ दिन पहले तक अधिकतर अग्रज ही थे, बहुत अधिक थे।

द्वितीय विश्व-युद्ध के आरम्भ हो जाने के बाद से प्रशासन पर व्यय बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है। इसमें सन्देह नहीं कि युद्ध के समय अनेक विभागों के विस्तार की आवश्यकता थी, पर आश्चर्य तो इस बात का है कि युद्ध समाप्त हो जाने पर व्यय का स्तर पहले की अपेक्षा अधिक ऊँचा था। युद्ध के पहले शासन-व्यवस्था पर व्यय १८७ करोड़ रुपया था। १९४४-४५ में, जबकि युद्ध अपनी चरम सीमा पर था, यह व्यय ४२४ करोड़ रु० था, १९४६-४७ में यह ६२३ करोड़ रु० था और १९४७-४८ में अनुमान किया गया कि उसमें ९ लाख रु० की कमी होगी।

वर्तमान समय में व्यय-वृद्धि अशत सरकार द्वारा वेतन आयोग (वे कमीशन) की सिफारिशों की स्वीकृति तथा विकास-योजनाओं के परिणामस्वरूप विभागीय सेवाओं की स्थापना तथा प्रसार के कारण है। पर यह भी मानते हैं कि अपठ्यय दूर करने तथा खर्च कम करने का बहुत अवसर है। प्रशासन के प्रत्येक विभाग में मित-व्ययता के गम्भीर प्रयत्नों की सबसे बड़ी आवश्यकता है और जिन लोगों के अधिकार में सरकारी कोष है उन्हें कर देने वाले के दृष्टिकोण से अपनी स्थिति का पूरा ज्ञान होना चाहिए तथा उसके ध्येय के ढग में पूरी जागरूकता का परिचय देना चाहिए।

नागरिक प्रशासन की इनर हाल की वृद्धि इस बात से स्पष्ट है कि १९५२-५३ में यह व्यय २.९५ करोड़ रु० था जबकि १९५५-५६ में यह बढ़कर ३.३३ करोड़ रु० तथा १९५६-५७ में ४.८५ करोड़ रु० हो गया ।^१

भारत सरकार ने १ अप्रैल, १९५३ को कर-जाँच आयोग की नियुक्ति की, जिसके अध्यक्ष डॉ० जान माईथ थे।^२ १९२५ में विद्यमान कर-जाँच आयोग द्वारा रिपोर्टें प्रस्तुत करने के बाद से लेकर अब तक भारत की आर्थिक स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन हो चुके थे। अतएव इन नई परिस्थितियों में इस आयोग को अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय, राज्यीय तथा स्थानीय करारोपण का विभिन्न राज्यों में विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले भार की परीक्षा का कार्य सौंपा गया। आयोग ने ३० नवम्बर, १९५४ को अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की।

आयोग के मतानुसार ग्रामीण क्षेत्र से नगर-क्षेत्र की ओर बढ़ने पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय से रोकड़ व्यय का अनुपात भी बढ़ता जाना है, अधिक करारोपित वस्तुओं की अधिक खरीद के कारण रोकड़-व्यय से कर का अनुपात भी बढ़ता जाता है। इनके फलस्वरूप नगर-क्षेत्रों में कर-भार (टैक्स एलिमेण्ट) और कर-भार बढ़ता जाता है, यद्यपि ग्रामीण जनसंख्या के आधिक्य के कारण अप्रत्यक्ष करों के प्रति ग्रामीण क्षेत्रों का कुल अदादान वही अधिक है।

युद्ध-पूर्व काल की तुलना में नगर-क्षेत्रों में कर का कुल भार अपेक्षाकृत बढ़ गया है।

१९ कर-भार का वितरण—अर्थशास्त्र में कर-भार की समस्या सबसे अधिक जटिल समस्याओं में से एक है और भारत में तो प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय के वितरण के सम्बन्ध में ठीक-ठीक आँकड़े न प्राप्त होने के कारण और भी अधिक जटिल हो गई है। १९२४ में कर-भार के वितरण के विषय में जाँच करने तथा इस बात की परीक्षा करने के लिए कि केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय करारोपण की प्रणाली वैज्ञानिक और न्यायोचित है अथवा नहीं, कर जाँच समिति (टैक्सेशन इन्वैस्टिगटरी कमेटी) नियुक्त की गई। उन्होंने जनसंख्या से कुछ विशेष वर्गों को चुनकर कुछ मारान निकाले। कमेटी को इस बात का पता चला कि कर का भार किसी भी वर्ग के लिए दुबंहा नहीं था, पर उसका वितरण असमान था। कुछ वर्ग अपने हिस्से के उचित कर को भी बचा जाते थे, जैसे बड़े-बड़े जमींदार और गाँव का महाजन।^३ १९१४ के पहले कर-भार समाज के विभिन्न वर्गों में बहुत ही असमान ढंग से बँटा हुआ था। निम्न लोग मालगुजारी, नमक कर, उत्पाद-कर, स्टाम्प आदि के रूप में कर का भार पूरा पूरा बहन करते थे और धनी वर्ग के लोग अपना न्यायपूर्ण भाग भी बचा जाते थे, जैसा कि प्रोफेसर वे० टी० शाह द्वारा १९२३-२४ के लिए दी गई निम्न

१. देखिए, स्टेटिस्टिकल एक्जैम्प्लर, १९५७-५८, पृ० २१५।

२. देखिए, टेक्सेशन इन्वैस्टिगटरी कमेटी, १९५३-५४, खण्ड १।

३. देखिए, टेक्सेशन इन्वैस्टिगटरी कमेटी रिपोर्ट, पैरा ४७८-६२।

तालिका से प्रकट है—^१

करोड़ रुपयो मे

आय के शीर्षक	कर-भार की मात्रा जो वहन की गई	
	घनी वर्ग द्वारा	निर्धन वर्ग द्वारा
निराक्राम्य-कर	२०	२१
मालगुजारी और सिंचाई-कर	२० ^३ / _४	२१ ^३ / _४
आय-कर	२०	...
उत्पाद-कर	..	२०
नमक	१ ^३ / _४	७ ^३ / _४
जगल और रजिस्ट्रेशन	२	५
स्टाम्प	६ ^३ / _४	६ ^३ / _४
रेलवे	२३	६०
डाकखाना	५	५ ^३ / _४
नगरपालिका-कर	३	१०
ज़िला परिषद-कर	.	१०
कुल	१११ ^३ / _४	१६७

इस तालिका से प्रो० शाह इस निराय पर पहुँचे कि 'आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर तथा कम योग्य थे वे ही लोग भार में कर-भार का अविशाल वहन करते थे। रेल, डाक आदि कुछ करोड़ों अपवाद मानते हुए भी हम यह कह सकते हैं कि जबकि घनी वर्ग १०० करोड़ रुपया कर के रूप में देते हैं तो निर्धन वर्ग के लोग १५० करोड़ रुपया देते हैं। परिवार की १००० रु० और इससे अधिक औसत वार्षिक आय के दृष्टिकोण से कर की कुछ वसूली, ६०० करोड़ रुपये की आमदनी में से, जोकि कुल जनसंख्या के $\frac{१}{३}$ अंश से कम लोगों द्वारा उपयोग की जाती है, लगभग १०० करोड़ रुपये के होती है, और बाकी १५० करोड़ रुपया १००० या १२०० करोड़ रुपये की कुल आमदनी में से, जो बाकी जनसंख्या के ६६% लोगों द्वारा उपयोग की जाती है, वसूल किया जाता है। यह वितरण मितव्ययी अथवा न्यायोचित नहीं कहा जा सकता।'

इण्डियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स के सलाहकार श्री ए० सी० सम्पत आयगर

१. देखिए, शाह और खन्वाड, 'वैश्व एण्ड टेक्सेवल केपेसिटी', पृष्ठ २८६-६१, और शाह, 'सिक्सटी इंचर्स ऑफ इण्डियन फिनांस', दूसरा संस्करण, पृष्ठ ३७३-७४।

ने कुछ समय हुआ (१५ नवम्बर, १९४६) अपनी एक पुस्तक प्रकाशित करवाई, जिसमें उन्होंने उच्च अथवा मध्यम और निम्नवर्ग के लोगों के ऊपर केन्द्रीय तथा राज्यीय करों का कितना भार पड़ता है, इसका सांख्यिक अनुमान लगाने का प्रयास किया है। इस अध्ययन में उन्होंने २००० मासिक आय को दोनो वर्गों के पार्यवय की सीमा माना है। केन्द्रीय और प्रांतीय करों से प्राप्त आय को १९४६-५० के बजट में दो वर्गों में बाँटा गया है। पहला वह वर्ग, जिसमें निम्न वर्गों से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और दूसरा वह वर्ग, जिसमें उच्च अथवा मध्यम वर्ग वाले लोगों के साथ-साथ निम्न वर्ग के लोग भी कर देते हैं। पहले वर्ग के उदाहरण हैं आय-कर, निगम-कर, व्यवसायो पर कर, कृषि-आय कर और ऐसी वस्तुओं पर निराक्राम्य कर, जैसे शराब, स्प्रिट, बूट और जूते, बेतार के तार के झोंडार, तम्बाकू, कृत्रिम रेशम के सूत और थोरे, चाय पर निर्मात कर, शराबों के उत्पादन पर तथा व्यापारिक वामों में आने वाली स्प्रिट पर उत्पाद-कर और नगर-स्थित अचल सम्पत्ति पर कर इत्यादि। दूसरे वर्ग की वस्तुओं पर विभिन्न प्रतिशत में निम्नवर्ग वाले लोगों द्वारा कर दिया जाता है। योजनाओं के फलस्वरूप करों की मात्रा में लगातार वृद्धि हुई है, किन्तु इसके आपार पर कर-भार के वितरण के सम्बन्ध में निश्चयात्मक परिणाम नहीं निकाला जा सकता। द्वितीय योजना-काल में केन्द्र द्वारा ७६७ करोड़ ६० की अनिश्चित-कर आय प्राप्त की गई तथा राज्यों द्वारा २४४ करोड़ ६० नये करों द्वारा प्राप्त किया गया। इस प्रकार द्वितीय योजना-काल में कुल १०४१ करोड़ ६० अति-रिक्त-कर आय के रूप में प्राप्त हुआ। किन्तु कर-आय और राष्ट्रीय आय (चासू मूल्यों पर) के अनुपात पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। १९५५-५६ में कर-आय राष्ट्रीय आय के ८ प्रतिशत के बराबर थी और १९६०-६१ में ६ प्रतिशत के बराबर है। यह तो निश्चित है कि अनिश्चित-कर आय का अधिकांश बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय से प्राप्त हुआ है।

२०. भारतीय वित्त का संक्षिप्त इतिहास—ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापारिक और शासन-प्रबन्ध सम्बन्धी खातों में गड़बड़ी, कम्पनी के प्रशासन में सदा रहने वाला घाटा, गदर का आर्थिक भार, कालान्तर में पृथक् वित्त सदस्य की नियुक्ति, आर्थिक विकेन्द्रिकरण की ओर धीरे-धीरे विकास, दुर्भिक्षों, सरहद्दी युद्ध और विदेशी विनिमय में कमी के कारण उत्पन्न कठिनाइयाँ, सरकार की ऋण-नीति, १९१४-१८ के महा-युद्ध के पहले बजट में वचत इत्यादि मुख्य समस्याएँ हैं।

प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ जाते ही युद्ध के पहले की आर्थिक सुगमता तथा बजट में वचत का युग अनायास ही समाप्त हो गया। युद्ध-काल में भारतीय वित्त की विशेषताएँ बजट में घाटा, व्यय कम करन के कठोर उपायों का अपनाना, रेल और सिंचाई की सुविधाओं में भारी कमी, निराक्राम्य-करों में वृद्धि, आय-कर, नमक-कर, उत्पाद-कर और भारत में ही जनता से बड़े-बड़े बज्रें लेना आदि थीं।

२१. घाटे के बजट—१९१४ के पहले के अनिश्चित बजटों के विपरीत अब केन्द्रीय तथा प्रांतीय अर्थ-प्रबन्धन में निरन्तर घाटे के बजट दिखाई पड़ने लगे। यूरोपीय युद्ध के

कारण हुए व्यय के अतिरिक्त भारत पर अफगानिस्तान के आक्रमण के कारण भी कठिनाइयाँ बढ़ गईं, जिसके फलस्वरूप कई करोड़ रु० का खर्च बढ़ गया। इसके अतिरिक्त सैनिक तथा अर्थनिक प्रशासन का खर्च भी उत्तरोत्तर बढ़ता गया। रेल-प्रबन्ध का खर्च भी बहुत बढ़ गया और व्यापारिक अवसाद के कारण, जो युद्ध के पश्चात् क्षणिक अभिवृद्धि-काल के समाप्त होते ही आरम्भ हो गया था, आमदनी घट गई। रेल की आय की कमी के अतिरिक्त आय कर से होने वाली प्राप्ति में भी कमी आई थी। इन सब कारणों का संयुक्त प्रभाव १९१४-२२ के बीच के काल में करो की वृद्धि के होते हुए भी घाटे के बजटों में लक्षित हुआ।

रिट्टेचमेण्ट कमेटी^१ (१९२२-२३) की सिफारिशों के अनुसार १९२२-२४ में अर्थनिक व्यय में ६६ करोड़ रुपये की कमी और सैनिक व्यय में ५५ करोड़ रु० की कमी की गई। परन्तु बजट के असन्तुलन को संभालने के लिए केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था और वाइसराय को नमक-कर ढूना अर्थात् १ रु० ४ आने से २ रु० ८ आने करने के लिए बाध्य होना पड़ा। १९२३-२४ में स्थिति ने पलटा खाय़ा और आय के अनुमान से आवश्यकता से अधिक सावधानी बरतने, रुपये की विदेशी विनिमय-दर १ सि० ६ पैसे पर निश्चित हो जाने, आय-दर पर करों के आरोप को ज्यों-का-त्यों बनाए रखने और उद्योग और व्यापार में धीरे-धीरे उन्नति होने के कारण अस्थायी रूप से बजट में अनिरेक की पुरानी प्रवृत्ति फिर से दिखाई पड़ने लगी। इन अतिरेकों का प्रयोग प्रान्तों के अनुदान को घटाने तथा अनुत्पादक ऋण को कम करने में किया गया। १९२७-२८ के पश्चात् बजट के असन्तुलन में फिर से गड़बड़ पैदा हुई और प्रान्तीय अनुदान के पूर्ण रूप से हटा देने के पश्चात् बजट बराबर घाटे प्रदर्शित करते रहे।

१९३६-४० के व्यापार में निरन्तर होती हुई अवनति के कारण घाय में बहुत घाटा हुआ। विशेष रूप से निराक्राम्य-कर में और नये प्रचलित आय-कर की वर्ग-प्रणाली (स्लैब सिस्टम) के अन्तर्गत वृद्धि के होने हुए भी ऋण पर ब्याज देने और रक्षा पर व्यय करने में कमी करते हुए भी बजट में लगभग ५० लाख का घाटा पूरा करने के लिए बाकी रह गया। यह कमी कच्ची हुई पर आयात-कर को ढूना करके पूरी की गई।^२ सितम्बर १९३६ में लड़ाई छिड़ जाने से बजट में अगले महीने में विभिन्न परिवर्तन हुए। १९३६-४० के आय-व्यय का अन्तिम परिणाम ७७७ रु० के अनिरेक में लक्षित हुआ, जिसके कारण रक्षित आय-कर कोष में ६८६ लाख रुपये अधिक जमा किया जा सका। यह आय में ६८१ लाख रु० की वृद्धि और व्यय में ५ लाख रुपये की कमी के कारण सम्भव हो सका।

१९४०-४१ में रेल की आय में वृद्धि होते हुए भी पूरे वर्ष के लिए इस प्रथम युद्धकालीन बजट ने ७१६ लाख रुपये की सम्भावित कमी को नवीन साधनों से आय

१. देखिए, 'रिट्टेचमेण्ट कमेटी की रिपोर्ट', पृष्ठ ११, पैरा ८।

२. ६ पैसे प्रति पौण्ड से १ आना प्रति पौण्ड कर दी गई।

में वृद्धि करके पूरा करने की आवश्यकता की ओर संकेत किया था, जो कि युद्धजनित अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण हुई थी। केवल रक्षा-बजट ही ५२ ५२ करोड़ रुपये का था।

१९४१-४२ के बजट में १९४०-४१ के संशोधित अनुमानों के अनुसार ८४२ करोड़ रु० की तथा १९४१-४२ के बजट में २०४० करोड़ रु० की कमी दिखाई गई थी। १९४१-४२ के बजट में होने वाली २०४० करोड़ रु० की भारी कमी बहुत बड़े रक्षा-बजट के कारण पैदा हुई, जिसमें ८४१३ करोड़ रुपये रक्षा पर तथा युद्ध के कारण शासन-व्यवस्था पर व्यय किये जाने का अनुमान किया गया था। यह प्रस्ताव किया गया था कि यह कमी ६६१ करोड़ रु० तक नये करों के आरोप द्वारा तथा शेष ऋण लेकर पूरा कर ली जाएगी।

१९४२-४३ का बजट पेश करते समय वित्त-मन्त्री ने १७ करोड़ रुपये की उमीद वर्ष और ४७ करोड़ की अगले वर्ष कमी दिखाई थी। १९४२-४३ में रक्षा पर १३३ करोड़ रु० का व्यय अनुमान किया गया था। यह प्रस्ताव किया गया था कि इस कमी को ३५ करोड़ रुपये के बर्जों द्वारा और १२ करोड़ रु० के नये करों की वृद्धि द्वारा पूरा किया जाएगा।

१९४३-४४ के बजट-आगणन में १९६३ करोड़ रुपये की आय का अनुमान किया गया था, जबकि १९४२-४३ के संशोधित आगणन में आय केवल १७८७६ करोड़ रुपये ही थी और २५६५६ करोड़ रुपये के व्यय की सम्भावना की गई थी। ६०२६ करोड़ रुपये की कमी को २००१ करोड़ रुपये तक नये करों के आरोप द्वारा और बाकी बर्जों द्वारा पूरा करने का इरादा था। उस वर्ष संशोधित आगणन में २५५० करोड़ रुपये की आय में वृद्धि और ८७३४ करोड़ रुपये की व्यय में वृद्धि दिखाई गई। इस प्रकार वर्ष के अन्त में आय में ६२४३ करोड़ रुपये की कमी रही।

१९४४-४५ के बजट में वर्तमान समय में आरोपित कर के स्तर पर कुल आय का अनुमान २८४६७ करोड़ रुपये था और कुल व्यय ३६३१८ करोड़ रुपये था, इसलिए होने वाली कमी ७८२१ करोड़ रु० की अनुमानित की गई थी, जिसको कुछ सीमा तक नये करों के आरोप द्वारा और कुछ सीमा तक अनिवार्य रूप से जमा कराए गए धन द्वारा पूरा करने का इरादा था। ऐसे आय-तर के पेशगी जमा कर दिये जाने की मुविधा, जिस पर उद्गम के स्थान पर ही कर नहीं वसूल कर लिया जाता था, एक बहुत बड़ा आय का साधन था।

१९४५-४६ की आय का अनुमान ३५३७४ करोड़ रुपये किया गया था। रक्षा पर लगभग ३६४२३ करोड़ रुपये और आय की प्राप्ति के साधनों और पूँजी लगान में ५६४१ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान किया गया था। शासन-व्यवस्था पर व्यय १२३४० करोड़ रुपये के लगभग रखा गया था। १६३८६ करोड़ रुपये की जो कमी होने वाली थी उसे मुख्यतः १५५२६ करोड़ रुपये तक ऋण लेकर और ८६० करोड़ रुपये तक करों के द्वारा पूरा करने का विचार था (जो तम्बाकू पर कर बढ़ाकर, डाक द्वारा भेजे जाने वाली पारसल की दर बढ़ाकर और तार-टेलीफोन

के क्रियाये तथा ट्रककाल की फीस पर अधिभार लगाकर पूरी की गई थी।) यह पहला अवसर था जब कि बजट में अर्जित और अनर्जित आय में अन्तर माना गया।

१९४७-४८ के बजट के आगणन के अनुसार व्यय ३२७.८२ करोड़ रुपये और आय २७९.४२ करोड़ रुपये वर्तमान करो के आधार पर की गई। इसके परिणामस्वरूप बजट में ४८.४६ करोड़ रुपये का घाटा था। रक्षा पर १२२.७१ करोड़ रुपये के व्यय और शासन-व्यवस्था पर १३६.१७ करोड़ रुपये के लगभग अनुमान किया गया।

१९४७-४८ में भारत का अधिक इतिहास दो भागों में बाँटा जा सकता है— पूर्व-विभाजन काल तथा उत्तर विभाजन काल। आय में ४८.४६ करोड़ रुपये की कमी, जिसका ऊपर जिक्र आ चुका है, पूर्व विभाजन काल के बजट में तमक कर के हटा देने से ८२.४ करोड़ रुपये से और बढ़ गई और ५६.७ करोड़ रुपये हो गई।

अन्तर्कालीन बजट में, जोकि ७^{वाँ} महीने के लिए था, १७१.२ करोड़ रुपये की आय और १६७.४ करोड़ का व्यय तथा आय में २६.२ करोड़ की कमी थी। इस कमी का १.६ करोड़ रुपये का अक्ष सूती कपड़े पर ३% के मूल्यानुसार कर के स्थान पर ४ ग्रामा प्रति वर्ग गज की दर से और रई के सूत पर ६ ग्रामा प्रति पीण्ड की दर से परिमाण कर लगाकर पूरा किया गया। जिस कमी को पूरा नहीं करना था वह १४.६ करोड़ रुपये की थी और वह असामान्य कारणों से थी, जैसे २२ करोड़ रुपया लोगों को पाकिस्तान से रक्षित अवस्था में लिवना लाना और शरणार्थियों को सहायता देना तथा २२.५ करोड़ रुपया विदेश से मँगाये हुए अन्न की सहायता देना आदि। देखने में बहुत अधिक लगने वाला रक्षा पर ६.२७ करोड़ रुपये का खर्च बंटवारे के पश्चात् सेना के घीमी गति से स्थानान्तरण तथा सामान्य काल से अधिक सेना के रखने के कारण था।

अर्धनिक व्यय में बजट के अनुमान से ४८.१४ करोड़ रुपये की वृद्धि (१) बंटवारे के पूर्वकाल के ऋण को देने के लिए २०.७५ करोड़ रुपये के अलग रख देने के कारण, (२) १२.०५ करोड़ रुपये के व्यय की विदेशों से मँगाए जाने वाले अन्न से सहायता देने के निमित्त तथा प्रांतीय सरकारों को अपने-अपने राज्य की सीमा में अन्न एकत्रित कर लेने में सहायता देने के कारण और (३) सहायता तथा पुनर्वास पर अधिक व्यय कर देने के कारण हुई।

१९४६-५० के बजट के अनुसार कुल आय ३२३ करोड़ रुपये और कुल व्यय ३२२.३ करोड़ रुपये था। सञ्चित आगणन में आय ३३२ करोड़ रुपये से कुछ अधिक और व्यय ३३६ करोड़ रुपये से कुछ अधिक था, इस प्रकार बजट में केवल ३.७४ करोड़ की कमी रह गई थी। रक्षा पर व्यय १२.३ करोड़ रुपये से बढ़ गया था। इसके विरुद्ध निराक्राम्य-कर में अनुमानित आय से ६ करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई थी। इन दोनों के बीच का अन्तर कमी की मात्रा के लगभग बराबर था। रक्षा पर व्यय ऊँचे ही स्तर पर रखना पड़ा, क्योंकि काश्मीर की समस्या का शान्ति से सुलभाव, जिसकी आशा की जाती थी, नहीं हो सका। निराक्राम्य-कर में वृद्धि

उदार आयान-नीति के कारण तथा निर्वाण-कर से राजे का अवमूल्यन हो जाने के कारण अधिक आय की प्राप्ति के कारण हुई।

वर्तमान कर के स्तर पर १९५०-५१ में कुल आय ४०५ ८६ करोड़ रुपये और कुल व्यय ३४६ ६४ करोड़ रुपये ५९'२२ करोड़ रुपये के अतिरिक्त के साथ भागणित किये गए थे। इनके तीन कारण थे—(१) भारतीय सभ में मिलने वाली देशी रियासतों में प्राप्त आय, (२) कर की बढ़ाया रकम की तत्परता के साथ वसूली और (३) आय-कर अधिनियम के १८ (अ) भाग के अन्तर्गत पेशगी वसूली।

मुद्राकालीन तथा मुद्रोत्तरकालीन घाट के दृष्टियों में अर्थ-प्रबन्धन की प्राचीन मान्यताओं को बदल दिया। 'सन्तुलित बजट' का मिथ्यात्व केवल आदर्श-मान रह गया। १९५१ में अखिल भारतीय स्तर पर नियोजन प्रारम्भ होने के कारण विकास की मरदों पर व्यय की आसानीत वृद्धि हुई। परिणाम यह हुआ कि घाटे के बजट नमाप्त नहीं हुए। वस्तुतः घाटे के बजट के बारे में अब यह धारणा हो गई है कि जब तक वे मूल्य-वृद्धि को अनावश्यक रूप से बचाव न दें, तब तक उन्हें देश के आर्थिक विकास के अर्थ-प्रबन्धन के माध्यम के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। १९५५-५६, १९५६-५७, १९५७-५८ में भारत सरकार की आय व्यय से क्रमशः ४० ४५ करोड़ ६०, ८९'४० करोड़ ९०, ४२ ०५ करोड़ ६० अधिक थी, किन्तु १९५८-५९, १९५९-६० में क्रमशः ५ २५ करोड़ ६० तथा १५ ३९ (संशोधित अनुमान) करोड़ ६० का घाटा हुआ। १९६०-६१ के बजट में ६० ३७ करोड़ ६० के घाटे का अनुमान था। २९ फरवरी, १९६१ को १९६१-६२ का बजट सदन के समक्ष पेश हुआ। इस बजट में प्रस्तावित व्यय १,०२३ ५२ करोड़ रुपये तथा प्रस्तावित आय (कर के वर्तमान स्तर पर) ९६२ २९ करोड़ रुपये हैं। इस प्रकार ६० ६० करोड़ ९० का घाटा इस बजट में निहित है, किन्तु नये करों से ६० ८७ करोड़ ९० की अनुमानित आय को ध्यान में रखने पर बजट में नाम मात्र के लिए २७ लाख ६० की बचत होगी, ऐसा अनुमान है।

१९६५-६६ में श्री० टी० टी० कृष्णामाचारी ने जो बजट सदन के सामने रखा था वह बाजों में सर्वश्रेष्ठ था। पहली बार कई वर्षों के बाद इस बजट में कुछ लोगों को नये बोझ के स्थान पर परिहार प्राप्त हुए। दूसरे, कई वर्षों के बाद पहली बार देशी का बजट नितान्त गया जो कि न केवल राजस्व बजट में बसो दिखाई गई, घाटे के वित्त को विलकुल रह करते हुए देशी दिखाई गई। उस प्रकार कृष्णामाचारी ने कर-नीति को इस प्रकार बनाया जिसमें निजी कर और कम्पनी-कर में परिवर्तन किये, जिन्हें कर टैक्स को एक अन्दे और उचित आधार पर खड़ा कर दिया।

२८ फरवरी १९६६ में देश के नये वित्त मंत्री श्री सचीन चौधरी द्वारा देश की आर्थिक दशा और आर्थिक उन्नति के नियमित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ध्यान रखा गया। इस प्रकार नये बजट में राष्ट्र के सभी वित्तीय क्षेत्रों में उत्पादन-शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न किया है। वित्त मंत्री के आदेशानुसार जमा की बढ़ाने के लिए इस प्रकार का बाजारकरण बना देना चाहिये जिससे सचन-शक्ति बट सके और यह

ठीक क्षेत्रों में इसका निवेश होगा। साथ ही बजट में इस बात पर भी जोर दिया कि खर्चों में कुछ कमी हो और ऐसे प्रोजेक्ट, जिनकी सरकारी उत्पादन शक्ति को बनने में समय लगेगा, उन्हें इतना अधिमान न दिया जाए जितने का उन उद्योगों को, जिनकी आवश्यकता जल्दी है।

इस बजट के प्रस्तावों के अनुसार नये करो से १०१५ करोड़ रुपया और प्राप्त होगा। नए प्रस्तावों का विशेष रूप इस प्रकार है—

- (१) बोनस शेयर कर को हटा दिया जाए।
- (२) लाभांश कर को ठीक रूप दिया जाए।
- (३) कुछ परिहार समवाय पर करो का लगाना।
- (४) १० प्रतिशत स्पेशल अधिभार बड़ी आय वाले लोगों पर।
- (५) कम आय वाले लोगों पर कुछ परिहार और अन्त में
- (६) समवाय क्षेत्रों को कुछ प्रोत्साहन दिए जाएँ ताकि धन का निवेश तथा पूँजी का संचय बढ़ सके।

१९६६-६७ के बजट में ११७ करोड़ रुपया मौजूदा करो को देखते हुए, घाटे का भाग रहेगा। एक बड़ा अंश इस घाटे का करो से पूरा किया जाएगा, बाकी भाग राज-कोष पत्रों को रिजर्व बैंक को जारी कर पूरा किया जाएगा। १९६६-६७ के बजट में कुछ मजबूरियों के कारण जनपद प्रशासन ऋण-व्यय, नये वित्त कमीशन के प्रस्तावों के अनुसार राज्य सरकारों को अधिक अनुदान देने के कारण, राजस्व व्यय २१७० करोड़ रुपया हो जाने की सम्भावना है। उसके मुकाबले में राजस्व प्राप्ति नये करो से धन को मिलाकर २४८१ करोड़ रुपये की सम्भावना है। इस प्रकार राजस्व लेखे में ३११ करोड़ रुपये की बचत होने की सम्भावना है। परन्तु विशेष जमा तथा वित्त पूँजी-गणना १९६५-६६ में १८७३ करोड़ रुपये हो जाएँगे और इस प्रकार पूँजी-गणना में ३३४ करोड़ रुपये का घाटा होगा। इस प्रकार इस वर्ष कुल १६५ करोड़ रुपये के घाटे के मुकाबले में १२५ करोड़ रुपये का घाटा होगा।

१९६६-६७ के लिए लोक क्षेत्र खर्चों के लिए १२३ करोड़ रुपया और बढ़ने से कुल १३७३ करोड़ रुपया हो जाएगा। ऋण-व्यय इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सरकार को स्वदेशी तथा विदेशी ऋण व्यय का कर देना होता है। १९६६ में रक्षा पर १०० करोड़ हमया खर्च हुआ। केन्द्रीय सरकार का भुगतान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को उधार तथा अनुदान दे रही है योजनाओं की पूर्ति के लिए। चौथे वित्त कमीशन के प्रस्तावों के अनुसार राज्य सरकारों का भाग केन्द्रीय आय-कर में बढ़ गया है। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार की सहायता राज्य सरकारों को ६७० करोड़ रुपये (१९६२-६३) से बढ़कर १४०६ करोड़ रुपये (१९६६-६७) हो जाने की सम्भावना है। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार की उधार तथा केन्द्रीय सरकार का सार्वजनिक ऋण विशेषकर योजनाओं की पूर्ति के लिए दिन-प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। मार्च १९६६ में कुल सशोधित ऋण ११,३८३ करोड़ रुपये था (पहली योजना में यह ऋण ६४६ करोड़ रुपये, दूसरी

योजना म ३,०३३ करोड़ रुपये और तीसरी योजना मे ४,८३६ करोड़ रुपये) मार्च १९६७ क अन्त तक यह बढ़कर १२,३६ - करोड़ रुपये हो जाएगा ।

२२ भारत मे लोक-ऋण का सर्वेक्षण—१८६७ के बाद, जब से लोक-निर्माण-कार्य करन की नीति अपनाई गई, जिसे बाद मे उत्पादक-कार्य कहा जाने लगा, जैसे रेल, सिंचाई आदि, लोक निर्माण ऋण अथवा उत्पादक ऋण मे निरन्तर वृद्धि हुई है । १८७६ के बाद से अनुत्पादक ऋण को साधारण ऋण कहा जाने लगा । जब से सरकार को भी कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ी, कुछ रेलो को कम्पनियो से खरीदने के लिए अथवा कर्ज देने के लिए सरकार के उत्पादक ऋण मे वृद्धि हुई । १८७८ मे प्रवर समिति (सिलेक्ट कमेटी) की सिफारिशो के अनुसार किसी एक वर्ष की अनिरेक धाय का प्रयोग ऋण की अदायगी मे नहीं होना चाहिए, वरन् उसका प्रयोग उत्पादक कार्यों मे करना चाहिए, जिसके लिए अग्यथा सरकार को ऋण लेना ही पडता । साधारण ऋण मे कमी का अर्थ दूसरी और लोक निर्माण कार्य के लिए लिये गए ऋण मे वृद्धि थी ।

१९१४-१८ के युद्ध के पहले भारत के लोक-ऋण का अधिकांश इंग्लैंड मे लिया गया था । सरकार ने नीति का अनुमोदन इस आधार पर किया कि इंग्लैंड और भारत मे व्याज की दर मे इतना अन्तर था कि इंग्लैंड मे उधार लेने से यदि कोई हानि की सम्भावना हो तो वह पूरी हो जाए । उन्हे भारत के द्रव्य-बाजार का बहुत ही भ्रमपूर्ण ज्ञान था, जिसकी उधार देने की शक्ति के किसी भी वर्ष ५ करोड़ रुपये से अधिक नहीं समझते थे । १९१४-१८ के महायुद्ध मे यह सिद्ध हो गया कि उनका यह अनुमान बहुत कम था । इस काल मे साधारण लोक-ऋण वही तीव्र गति से बढ़ा । ३१ मार्च, १८१६ मे ३१ करोड़ रुपये था और मार्च १९२४ मे वह २५७.७० करोड़ रुपये हो गया । यह भारत के युद्धकालीन १००० लाख पौण्ड' का प्रशदान नई दिल्ली के व्यय और केन्द्रीय सरकार के युद्धोत्तरकालीन घाटे के बजटो के फलस्वरूप था । इन आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए भारत में लगातार युद्धकालीन ऋण लिये गए । इंग्लैंड के द्रव्य-बाजार पर वही की सरकार द्वारा युद्ध के लिए मांगे हुए बर्ज का भार पहले ही शक्ति-भर पड चुका था और भारत से १९१७ मे ५३ करोड़ रु० का और १९१८ मे ५७ करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हो चुका था । इससे और अधिक ऋण पाने की आशा भी थी । युद्ध-काल में भारत की धन के बाजार की ऋण देने की शक्ति का जो परिचय मिला वह युद्धोत्तर-काल मे भी जारी रहा । युद्ध-सम्बन्धी ऋण की बड़ी मात्रा क अतिरिक्त इस ऋण की एक दूसरी विशेषता ऋण देने वालो की सख्या थी । इसके लिए हमे प्रभावशाली विज्ञापन और लोक-ऋण प्रसासन द्वारा अधिकाधिक सुविधाओ, जो राज्य के खजानो और

१ १९१८ में युद्ध के और अधिक चलने की दशा में युद्ध-सम्बन्धी ४५० लाख के अतिरिक्त प्रशदान का बचन दिया जा चुका था, परन्तु १९१६-२० में अफगान-युद्ध के कारण १६० लाख पौण्ड का भारी खर्च हो जाने के कारण युद्ध-सम्बन्धी अशदान की मात्रा बहुत घटा दी गई ।

उप-खजानो में प्राप्त थी, का आभारी होना चाहिए। इस सम्बन्ध में डाकखाने की युद्ध सम्बन्धी ऋण शाखा और कॅश सर्टिफिकेट की प्रणाली, जिसे सरकार की ऋण नीति में स्थान मिला था, विशेष उल्लेखनीय है।

ट्रेजरी बिल १९१४-१८ की लड़ाई की देन थे, जो सर्वप्रथम १९१७ के ब्रिटिश युद्ध-कार्यालय की तरफ से सरकार द्वारा वितरण के लिए जारी किये गए। युद्धोत्तर-काल में आय का कमी पूरी करने के लिए ये फिर जारी किये गए थे, जबकि पुराने बिलों की रकम नये बिल जारी करके अदा की गई थी। अन्त में ट्रेजरी बिल की बहुत बड़ी बकाया रकम लम्बी अवधि के ऋण से प्राप्त धनो द्वारा दी गई, जोकि अन्धे अर्थ-प्रबन्ध की दृष्टि से अनुचित थी। १९२९-३० से ट्रेजरी बिल का जारी करना केन्द्रीय अर्थ-प्रबन्ध का एक साधारण कार्य हो गया है।

१ फरवरी, १९४१ से छ-वर्षीय सुरक्षापत्र (डिफेन्स-बॉण्ड) के स्थान पर ३% का दूसरा सुरक्षा ऋण (डिफेन्स लोन) अधिक लम्बी अवधि के लिए जारी किया गया। १९४२-४३ में सुरक्षा ऋण में लोनो ने ११५ करोड़ रुपया लगाया। बाद में तीसरा, चौथा तथा अनेक ऋण जारी किये गए, जिनमें १९४३-४४ में कुल २७९ करोड़ रुपया जमा हुआ और यदि युद्ध-आरम्भ-काल से ही हिसाब लगाया जाए तो कुल ५४७ करोड़ रुपया जमा हुआ। ऊपर वर्णित ऋणों में अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए डिफेन्स सर्विस प्राविडेण्ट फण्ड आरम्भ किया गया, जिससे सरकारी कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से रुपया जमा करने की सुविधा हो गई। एक सरल ढंग सर्वसाधारण के लिए रुपया जमा करने का पोस्ट ऑफिस डिफेन्स सेविंग्स बैंक अकाउण्ट को नई योजना द्वारा प्रचलित किया गया, जिसमें जमा किया हुआ रुपया माँगने पर नहीं बल्कि युद्ध-समाप्ति के एक वर्ष बाद मिल सकता था। इसे प्रोत्साहित करने के लिए इसमें व्याज की दर साधारण पोस्ट सेविंग्स बैंक अकाउण्ट से १% अधिक रखी गई।

१९३७-३८ से भारत के लोक-ऋण को निम्न मुख्य विशेषताएँ रही हैं—

- (१) व्याज वहन करने वाले भारत सरकार के ऋण की मात्रा में निरन्तर वृद्धि (जिसमें अनिश्चित काल के ऋण और निश्चित काल के ऋण सम्मिलित थे), (२) १९४२-४३ तक सावधि और बिना अवधि के ऋण की मात्रा में, जो किसी सीमा तक स्टॉलिंग ऋण की अदायगी के सम्बन्ध में प्रचलित किये गए थे, निरन्तर वृद्धि, (३) १९४२-४३ तक अल्पकालीन ऋण में वृद्धि, जिसका प्रतिनिधित्व ट्रेजरी बिलों द्वारा किया जा रहा था, जिसकी मात्रा युद्ध के पहले से ६ गुनी बढ़ गई थी जो स्टॉलिंग ऋण की अदायगी के लिए प्रचलित किये गए थे, (४) अगले चार वर्षों में अल्पकालीन ऋण में कमी होना और अनिश्चित काल के ऋण की मात्रा में वृद्धि, (५) १९४२-४३ तक छोटी मात्रा में वचत म कमी, पर बाद के वर्षों में फिर से मात्रा बढ़ना (विशेषकर नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट के प्रचलन के कारण), और (६) स्टॉलिंग ऋण का अन्त, जो युद्ध के समय में रुपये के ऋण से बढ़ गया था, आदि।

१९४२-४३ से युद्धकालीन वित्त सम्बन्धी विकास का नया रूप आरम्भ हुआ, जिसकी एक विशेषता लोक-ऋण की वृद्धि की गति में तीव्रता तथा युद्धकालीन ध्यय में निम्नतर वृद्धि के कारण घाटे के बजट और मुद्रा-प्रसार का बढ़ता हुआ भार था।

१९५३-५४ में यह २६९५ करोड़ रुपये था। इसमें से २५१४ करोड़ ६० आन्तरिक ऋण था तथा शेष १४१ करोड़ ६० बाह्य ऋण था। १९५४-५५ में भारत का ऋण बढ़कर ३०३६ करोड़ ६० हो गया। इसमें से २९०० करोड़ ६० आन्तरिक और १३६ करोड़ ६० बाह्य ऋण था। आशा की जाती है कि मार्च, १९५६ के अन्त तक ऋण में ४७० करोड़ ६० की वृद्धि होगी और ऋण बढ़कर ३५०६ करोड़ ६० हो जाएगा।

१९६० के सन्तोषित अनुमान के अनुसार भारत के आन्तरिक लोक-ऋण की मात्रा ३८३४.८१ करोड़ ६० थी तथा १९६१-६२ के बजट अनुमान में इसकी मात्रा ४०५६.६२ करोड़ ६० प्रस्ताविन है। इन्हीं वर्षों के लिए बाह्य ऋण की मात्रा—जिसमें इंग्लैंड, यू० एस० ए०, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी, जापान, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, यूगोस्लाविया, स्विट्जरलैंड तथा विन्सव बैंक व ऋण भी सम्मिलित हैं—६२६०.६० करोड़ ६० तथा ७११०.१३ करोड़ ६० है।^१ १९६६-६७ में बाह्य ऋण की मात्रा ३२६३.४४ करोड़ रुपये हो जाएगी।

यहाँ लोक-ऋण के सम्बन्ध में एक बात स्पष्ट कर देना अच्छा होगा। जो ऋण भारत में लिया जाता है उसे रुपये का ऋण कहा जाना है, क्योंकि रुपये में ही यह प्राप्त होता है और मूलधन तथा व्याज आदि सब रुपये ही में अदा किए जाते हैं। भारत में रुपये का ऋण दो भागों में विभाजित है—प्रथम भारतीय विनियोजक और दूसरा यूरोपीय विनियोजक। यह सुभाव दिया गया है कि सभी ऋण, चाहे रुपये के हो और चाहे स्टर्लिंग के, चाहे भारत में प्राप्त हुए हो और चाहे इंग्लैंड में, यदि गैर-भारतीयों द्वारा किये गए हैं तो बाह्य ऋण हैं और यदि भारतीयों द्वारा किये गए हैं तो आन्तरिक ऋण हैं।

२३. पौण्ड-पावना—पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष के भाग के रूप में भारत मर्देव से इंग्लिस्तान में स्टर्लिंग रखता आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट के अन्तर्गत निर्गम-विभाग (इसू डिपार्टमेण्ट) की सम्पत्ति का कम-से-कम ४० प्रतिशत स्वर्ण या स्वर्ण-सिक्के अथवा स्टर्लिंग प्रतिभूतियों के रूप में होना आवश्यक है। साथ ही शर्त यह भी थी कि स्वर्ण की मात्रा का मूल्य कम-से-कम ४० करोड़ रुपये हो। सितम्बर, १९३६ में पौण्ड-पावने ५२० लाख पौण्ड थे। १४ अगस्त, १९४७ को यह ११,३७० लाख पौण्ड थे। पौण्ड-पावना एकत्रित होने का मुख्य साधन युद्ध के लिए ब्रिटिश सरकार और मित्र देशों द्वारा भारत से भण्डार और अन्य वस्तुओं का भय था। इस क्रम के लिए रुपा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट की उस धारा के अन्तर्गत प्राप्त किया गया, जिसके अन्तर्गत वक्त असीमित मात्रा में स्टर्लिंग खरीदने के लिए बाध्य

१. बेल्जिय, इण्डिया १९६१, पृ० २२८।

था। पौण्ड-पावना भारतीय जनता का भारी त्याग प्रदर्शित करते है, जो भारत की अपनी सुरक्षा की लागत तथा ब्रिटेन और मित्र देशों की सरकार के युद्ध-सम्बन्धी प्रयासों के लिए वस्तुएँ और सेवाएँ प्रस्तुत करने के कारण कठोर अभाव और मुद्रा-स्फीति के रूप में प्रकट हुआ। यह लागत भी भारत को अपनी इच्छा के विरुद्ध केवल वाइसराय के अप्रजातन्त्रात्मक आदेश से युद्ध में सम्मिलित होने के कारण उठानी पड़ी। अतएव भारत का पूरा भुगतान दिलाने का अधिकार बहुत ही दृढ़ है और उसके प्रति पहले की अपेक्षा अब बहुत कम विरोधी है।

३१ दिसम्बर, १९४७ तक की अवधि के लिए भारत के पौण्ड-पावनों के सम्बन्ध में एक अन्तर्कालीन समझौते (इण्टरिम एग्रीमेण्ट) पर लन्दन में १४ अगस्त, १९४७ को हस्ताक्षर हुए। इस समझौते की मुख्य बातें निम्न थी—

(१) रिजर्व बैंक को दो खाते रखने के लिए कहा गया। खाता न० १ खास चासू खाता होगा, जिसमें परिवर्तनीय मुद्रा होगी। पौण्ड-पावने से दी जाने वाली रकम और भविष्य की अर्जित राशि इसी खाते में जमा की जाएगी।

खाता न० २ शेष एकत्रित राशि होगी।

(२) खाता न० १ में ३५० लाख पौण्ड जमा करना था।

(३) ३५० लाख पौण्ड के अलावा विदेशों को भुगतान करने के साधनों की कमी पूरा करने के लिए खाता न० १ में ३०० लाख और जमा किया गया।

१९४८ के एक नए समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसकी मुख्य बातें निम्न थी—

(१) भारत में इंगलिस्तान के भण्डार—१ अग्रेल, १९४७ को दिये गए सारे भण्डारों आदि के पूरे और अन्तिम भुगतान के लिए १००० लाख पौण्ड (१३३ करोड़ रुपया) दिया जाएगा।

(२) स्टॉलिंग पेन्शन (निवृत्ति-वेतन)—इंगलिस्तान की सरकार को १४७५ लाख पौण्ड (१९७ करोड़ रु०) दिया जाएगा और भारत सरकार क्रमशः ह्रासमान वार्षिक वृत्ति (एनुइटी) खरीद लेगी, जो १९४८ में ६३,००,००० पौण्ड से शुरू होगी। धीरे-धीरे ६० वर्ष में शून्य हो जाएगी।

(३) सुरक्षा व्यय योजना—अविभाजित भारत के १९४८-४७ के अन्तिम लेखों के अनुसार भारत और इंग्लैण्ड के बीच सुरक्षा-व्यय निर्धारण योजना के अन्त-गत इंगलिस्तान पर ४९० लाख पौण्ड (६५ करोड़ रुपया) था। इस योजना में विचारित अवधि की अन्व देयताओं को ध्यान में रखकर अन्तिम रकम ६५० लाख पौण्ड (७३ करोड़ रु०) निश्चित की गई।

(४) पौण्ड-पावना की अदायगी—१ जुलाई, १९४८ से तीन वर्ष की अवधि में इंगलिस्तान ८०० लाख पौण्ड पौण्ड-पावने में से देगा और भारत खाता न० १ में पौण्ड-पावने की इससे पहले अदा की गई रकम से ८०० लाख पौण्ड जमा रखेगा।

(५) बहु-परिवर्तनशीलता (मल्टीलेटरल कन्वर्टिबिलिटी)—पहले वर्ष यानी

१९४८ में १५० लाख पौण्ड (२० करोड रु०) देने की व्यवस्था थी और ३ वर्ष के अन्त में स्थिति के पुनर्विलोकन की व्यवस्था थी ।

जैसा ऊपर (४) कहा जा चुका है, सैनिक भण्डारों, पेन्शनो आदि के मद में भुगतान करने के बाद भारत के पौण्ड-पावने ८००० लाख पौण्ड थे । यदि पहले तीन वर्षों में मिलने वाला १६०० लाख पौण्ड इसमें से घटा दिया जाए तो पौण्ड-पावने कुल ६४०० लाख पौण्ड क थे ।

किन्तु जून, १९५१ में समाप्त होने वाले स्टर्लिंग समझौते को ३० जून, १९५७ तक के लिए बढ़ा दिया गया और उसमें निम्न परिवर्तन किये गए—

(१) (करेन्सी) मुद्रा-मुरक्षित-शेप के रूप में रिजर्व बैंक द्वारा रखे जाने के लिए खाता न० २ से ३१०० लाख पौण्ड खाता न० १ में स्थानान्तरित कर दिये गए ।

(२) १ जुलाई, १९५१ से १२ महीने की ६ अवधियों में प्रत्येक वर्ष खाता न० २ से खाता न० १ में अधिक-से-अधिक ३५० लाख पौण्ड स्थानान्तरित किया जा सकता था, बशर्ते कि (क) खाता न० १ की न्यूनतम राशि ३४०० लाख पौण्ड बनाए रखने के लिए स्थानान्तरण हो, या दोनों सरकारों को मान्य इससे कम रकम का स्थानान्तरण इसी उद्देश्य से हो, (ख) ३५०० लाख पौण्ड का स्थानान्तरण योग्य कोई भी भाग, जो किसी अवधि में स्थानान्तरित न किया जाए, वह बाद के वर्षों में स्थानान्तरण-योग्य राशि में जोड़ दिया जाए, (ग) यदि किसी अवधि में भारत सरकार खाता न० २ से ३५०० लाख पौण्ड से अधिक लेने की आवश्यकता समझे तो बाद की अवधि में स्थानान्तरण-योग्य राशि ५० लाख पौण्ड कर दी जाएगी । यदि भारत सरकार बाद की अवधि में इससे अधिक की आवश्यकता समझे तो दोनों सरकारों इसे आपस में तय कर लेंगी, (घ) ३० जून, १९५७ को खाता न० २ में जो कुछ भी होगा वह खाता न० १ को स्थानान्तरित कर दिया जाएगा ।

फरवरी १९५२ में पौण्ड-पावने के १९५१ के समझौते को ३० जून, १९५७ तक के लिए बढ़ा दिया गया । जुलाई, १९५३ में एक औपचारिक समझौता और किया गया, परन्तु पौण्ड-पावने की १९५१ की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया ।

प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकारों के बीच वित्तीय सम्बन्ध

२४. १९१९ के मुचारों के पूर्व के वित्तीय सम्बन्ध—१८३३ से १८७१ तक वित्त-शक्ति पूर्ण रूप से भारत सरकार के ही हाथों में केन्द्रित थी और वही प्रान्तीय सरकार के व्यय की छोटी-से-छोटी बातों पर नियन्त्रण रखती थी ।

१८७७ में लॉर्ड निटन द्वारा विवेन्दीकरण की और एक कदम और उठाया गया, जिसमें वित्त-मन्त्री सर जॉन स्ट्रेची ने सहयोग दिया । प्राय के प्रान्तीय प्रकृति के सभी साधन, जैसे मालगुजारी, उत्पादन, स्टाम्प, सामान्य प्रशासन, न्याय आदि, प्रान्तों को दिये गए । विभागों से प्राप्त प्राय और प्राचीन धन के अनुदान के अतिरिक्त कुछ प्राय के साधन, जैसे उत्पाद-कर, स्टाम्प और न्याय प्रान्तीय सरकारों को दे दिये गए । इस प्रबन्ध के अन्तर्गत प्राय के साधनों को प्रान्तीय और केन्द्रीय दो

भागो में बाँट दिया गया ।

१८८२ में लार्ड रिपन ने वित्त-सदस्य मेजर बेरिंग की सहायता से प्रान्तीय समझौते में कुछ सुधार किये । अब हर पाँचवें वर्ष इन समझौतों का पुनर्विलोकन होता था । उन्होंने निश्चित इकट्ठी रकम के अनुदान को बन्द कर दिया और निम्न प्रकार से आय के साधनों का फिर से बटवारा किया—

- (१) केन्द्रीय मद—अफीम, नमक, निराक्राम्य-कर, व्यापारिक कार्य इत्यादि ।
- (२) प्रान्तीय मद—नागरिक विभाग, प्रान्तीय निर्माण-कार्य और प्रान्तीय कर ।
- (३) विभाजित मद—उत्पाद-कर, आरोपित कर, स्टाम्प, वन, रजिस्ट्रेशन इत्यादि ।

अपना घाटा पूरा करने के लिए निश्चित धनराशि का अनुदान देने के स्थान पर उन्हें मालगुजारी का एक विशेष प्रतिशत दे दिया गया और उसके साथ-साथ निश्चित रोकड़ उसी मद के अन्तर्गत हस्ताकित कर दी गई जोकि व्यवस्थापन का एक महत्त्वशाली साधन बन गई । इसी प्रकार के समझौते सिद्धान्तों में परिवर्तन किये बिना १८८७, १८९२ और १८९७ के सिद्धान्तों में किये गए, यद्यपि प्रान्तों में कुछ असन्तोष और मतभेद रहा ।

वित्तीय नीति की अनिश्चितता और निरन्तरता की कमी दूर करने के लिए पञ्चवर्षीय प्रान्तीय समझौते को लॉर्ड कर्जन ने १९०४ में अर्द्ध-स्थायी बना दिया, अर्थात् पूर्वस्थिति में काफी परिवर्तन होने अथवा अकाल या युद्ध-जैसे विपत्ति-काल के उपस्थित होने पर ही उन्हें बदला जा सकता था ।

१९१२ में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा यह समझौता स्थायी घोषित कर दिया गया और निम्न विभाजन किया गया । जहाँ तक आय से सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार ने वे सारे आय के स्रोत अपने पास रखे जो बाँटे नहीं जा सकते थे या किसी प्रान्त-विशेष के नहीं थे । इनको साम्राज्य (इम्पीरियल) आय-स्रोत कहा गया, जैसे अफीम, रेल, निराक्राम्य-कर, नमक, टकसाल, विनिमय, डाक और तार, सेना द्वारा आय और देशी रियासतों से प्राप्त धन । बचे हुए में से कुछ तो पूर्णरूपेण प्रान्तीय थे, जैसे जंगल, उत्पाद-कर, (बंगाल और बम्बई में) रजिस्ट्रेशन तथा विभागों से प्राप्त आय, जैसे शिक्षा, न्याय आदि । अन्त में एक बहुत महत्त्वशाली आय का स्रोत विभाजित मद थे, जैसे मालगुजारी, आय-कर, उत्पाद-कर (बंगाल और बम्बई को छोड़कर), सिचाई और स्टाम्प । सुधार के पूर्व की प्रणाली में अनेक दोष थे—(१) दोनों सरकारों के बीच बँटने वाले आय के स्रोत निरन्तर केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तक्षेप के साधन बने थे और प्रान्तों के विकास में बाधक थे, (२) समय-समय पर प्रान्तीय सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनी बचत से दी हुई 'सभिक्षा' (डोल्स) का प्रभाव प्रान्तीय वित्त पर अस्त-व्यस्तकारी था, (३) इसने अन्तर्प्रान्तीय वित्त-सम्बन्धी सम्भोर असमानता को जन्म दिया, (४) प्रान्तीय सरकारों को करारोपण तथा ऋण लेने का स्वतन्त्र अधिकार नहीं था, (५) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रान्तों के बजट और व्यय पर बहुत विशद नियन्त्रण लगाया गया था । उदाहरण के लिए प्रान्तीय

सरकारों घाटे को पूरा करने का न तो कोई प्रबन्ध ही कर सकती थी और न अपने अनिरेक को स्वतन्त्रतापूर्वक खर्च ही कर सकती थी।

२५. १९१६ के सुधारों के अन्तर्गत पारस्परिक आर्थिक सम्बन्ध—सुधार के बाद से केन्द्रीय सरकार के साथ आर्थिक सम्बन्ध दिनकुल बढ़ने लगे। आय-व्यय का नवीन बटवारा निम्न प्रकार किया गया—(१) केन्द्रीय आय के साधन—अफीम, नमक, निराकाम्य-कर, आय कर, रेल, डाक और तार, सेना से आय, (२) प्रान्तीय आय के साधन—मालगुजारी (सिचाई को सम्मिलित करते हुए), स्टाम्प (व्यापारिक और न्यायिक), रजिस्ट्रेशन, उत्पाद-कर और वन। जो माप्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार और मेस्टन कमेटी द्वारा आय-कर केन्द्रीय करार दिया गया था, उसे प्रान्तों से पूर्णरूपेण ले लिये जाने के विरुद्ध मुख्यतः बम्बई और बंगाल के औद्योगिक प्रान्तों द्वारा आन्दोलन करने के कारण अन्त में यह निर्णय किया गया कि प्रान्तों को इस कर से प्राप्त आय का एक छोटा-सा अंश दे दिया जाए, जोकि आठ-वर्ष १९२०-२१ में आय-कर की निर्धारित आय के उपरान्त जितने रुपये की आय पर कर-निर्धारण किया गया, उससे प्राप्त करके प्रत्येक रुपये के ३ पाई के बराबर होगा। टेक्सेशन इन्व्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यह नियम अपने उद्देश्य में असफल रहा। वस्तुतः किसी एक आठ-वर्ष के अनुसार बटवारा करना निरान्त अशुद्ध था।^१

२६. मेस्टन परिनिर्णय—घाटे जाने वाले आय के स्रोतों के अन्त और कुछ स्रोतों, जैसे मालगुजारी और स्टाम्प आदि, को प्रान्तों को दे देने का परिणाम यह हुआ कि केन्द्रीय सरकार की आय में ६८३ लाख रुपये की कमी हो गई, जिसको प्रान्तीय अंशदान की किसी योजना से पूरा करना था। १९२० में एक कमेटी लार्ड मेस्टन के सम्पादन में इस प्रश्न पर तथा इससे सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई और इसकी सिफारिशें मेस्टन परिनिर्णय के नाम से पुकारी जाती हैं। इस कमेटी ने इस बात के बटवारे के लिए यह प्रस्ताव किया कि १९२१-२२ में प्रान्त एक प्रारम्भिक अंशदान दें, जिसकी मात्रा प्रान्तों की बढ़ी हुई व्यय-शक्ति के आधार पर निर्दिष्ट की जाए।

२७. प्रान्तीय अंशदान का अन्त—मेस्टन परिनिर्णय से कोई प्रसन्न न था, वरन् प्रान्तों में इससे बड़ा असन्तोष फैल गया। बम्बई और बंगाल के औद्योगिक प्रान्त आय-कर के घाटे को सहन करने को कभी भी तैयार न थे और कृषि-प्रधान प्रान्त, जैसे मद्रास, पञ्जाब और उत्तर प्रदेश, इस बात से असन्तुष्ट थे कि उनका प्रारम्भिक अंशदान बहुत अधिक था। ये अंशदान यथार्थ में भार लगने लगे, जबकि प्रान्तों को मेस्टन कमेटी के अनुमानित सुखदायी अनिरेक के स्थान पर लगातार आय की कमी का सामना करना पडा। जो आय के स्रोत उनको दिए गए थे, जैसे मालगुजारी, वे सामान्य विकास-सम्बन्धी व्यय के लिए ही—समय-समय पर आने वाली विपत्तियों की कौन बड़े—अभ्याप्त और लोचहीन थे। इसलिए अंशदान के अन्त के लिए निरन्तर मांग होती रही।

१. देखिए, टेक्सेशन इन्व्वायरी कमेटी रिपोर्ट, पैरा ५०६।

केन्द्रीय सरकार की आय में धीरे-धीरे वृद्धि होने के कारण १९२५-२६ और १९२६-२७ में कुछ सहायता सम्भव हो सकी। १९२७-२८ में जो कुछ अशदान का अवशेष था उसको कम कर दिया गया और १९२८-२९ में उसका अन्त कर दिया गया।

२८. भारत में संघात्मक वित्त की समस्या—प्रान्तीय अशदान के अन्त से प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकारों के बीच आय के स्रोतों के बटवारे के भगड़े का अन्त नहीं हुआ। प्रान्तों, विशेषकर औद्योगिक प्रान्तों, जैसे बंगाल और बम्बई की मुख्य आपत्ति फिर भी बनी रही। आपत्ति यह थी कि यद्यपि केन्द्रीय सरकार के व्यय स्थायी बने रहे, जिनमें केवल सेना के बनाए रखने का व्यय और लोक-वृद्धि पर व्याज के व्यय ही सम्मिलित थे, केन्द्रीय सरकार ने अपने लिए आय के ऐसे स्रोतों को, जैसे आय कर और निराकाम्य-कर आदि, अपना लिया था, जिनमें वृद्धि हो रही थी अथवा जिनमें वृद्धि की सम्भावना थी और उन्होंने प्रान्तों के लिए आय के ऐसे स्रोत छोड़ रखे थे जो लोचनीय और न बढ़ने वाले थे, जैसे मालगुजारी और उत्पाद कर आदि, हालांकि प्रान्तों की आवश्यकताएँ तीव्र गति से बढ़ रही थीं। कुछ स्थानों पर मालगुजारी पहले से ही बहुत अधिक थी और सर्वत्र बहुत लम्बी अवधि के लिए निश्चित की जा चुकी थी। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की वृद्धि के लिए जनता सहमत नहीं थी। मध्य-निषेध की नीति अपनाने के कारण उत्पाद-कर में अवनति अवश्यम्भावी थी। वन विभाग के विस्तार के लिए बड़ी मात्रा में पूँजी के विनियोग की आवश्यकता थी। केवल स्टाम्प ही एक ऐसा स्रोत था जिसमें वृद्धि की कुछ सम्भावना थी। प्रान्तों पर ही राष्ट्रीय उन्नति के विभागों, जैसे शिक्षा, औद्योगिक, कृषि आदि, का उत्तरदायित्व था, जिन पर बड़ी मात्रा में विनियोजन अत्यन्त आवश्यक था। दुर्भिक्ष-सम्बन्धी व्यय भी प्रान्तों ही के कंधों पर डाल दिया गया था। नये मुधारों के अन्तर्गत अतिरिक्त आय के बटवारे में जो भाग प्रान्तों को हस्तान्तरित किया जाता था, उसकी मात्रा का निर्णय अनियमित ढंग से किया जाता था और उसका सम्बन्ध न तो प्रान्तों की आवश्यकताओं से ही था और न उनसे वसूल की जाने वाली कुल आय से ही। निस्सन्देह १९२० के आय-स्रोतों के बटवारे के परिणामस्वरूप सब प्रान्तों को अधिक व्यय-शक्ति मिली। इसका लाभ असमान मात्रा में अनुभव किया गया और अशदान के अन्त ने प्रान्तीय आय-स्रोतों की असमानता को और भी अधिक बढ़ा दिया। जब साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी (१९३०), तो उस समय स्थिति यह थी कि प्रान्तों की आय तो स्थिर थी पर उसकी भावी आवश्यकताएँ सर्वत्र असीमित थीं।^१

२९. १९३५ के विधान के अनुसार केन्द्र और प्रान्तों के बीच आय स्रोतों का बटवारा—गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट के अनुसार यह व्यवस्था की गई थी कि कर

१. साइमन कमीशन रिपोर्ट, खण्ड २, पैरा २६०-६१ और २६३।

२. गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट की वित्त-सम्बन्धी व्यवस्था उस एक्ट के १३७-४४ सेक्शनों में दी हुई है।

मिलाकर १३ करोड़ रुपये से कम होती, उस समय तक आय कर छोड़ा जाने वाला नहीं था।

जिस प्रतिशत अनुपात में प्रान्तों के बीच आय बटने वाली थी, वे निम्न हैं— मद्रास १५, बम्बई २०, बंगाल २०, यू० पी० १५, पंजाब ८, बिहार १०, मध्य प्रदेश ५, आसाम २, उ० प० सीमाप्रान्त १, उड़ीसा २ और सिन्ध २।

३१. प्रान्तों की सहायता—प्रान्तीय स्वायत्त शासन के आरम्भ-काल से ही कुछ प्रान्तों को तुरन्त सहायता देने के लिए सर आर्टो निमेयर ने प्रस्ताव किया था। यह सहायता कुछ सीमा तक नकद सहायता के रूप में थी, कुछ सीमा तक १९३६ के पहले लिये वास्तविक ऋण (कुछ चीजें घटाकर) के विलोपन के रूप में थी और कुछ सीमा तक १२½% के झूट-कर के बटवारे के रूप में थी। बंगाल, बिहार, आसाम, उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त और उड़ीसा के सम्बन्ध में सारा वास्तविक ऋण विलोपित कर दिया गया था और मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में १९३६ के पहले के आय के घाटे के कारण लिये गए ऋण और उसके साथ १९२१ के पहले का लगभग २ करोड़ रुपये का ऋण भी विलोपित कर दिया गया था।

वार्षिक अर्थ-सहायता निम्न प्रकार थी—उत्तर प्रदेश २५ लाख पाँच वर्ष तक, आसाम ३० लाख, उड़ीसा ४० लाख, उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त १०० लाख, (पाँच वर्ष पश्चात् इस पर पुन. विचार करना आवश्यक था), सिन्ध १०५ लाख, जो दस वर्ष बाद धीरे-धीरे कम किया जाना था।

सर आर्टो निमेयर का कहना था कि पर्याप्त मात्रा में न्याय तभी हो सकेगा जबकि बाँटने की दर कुछ तो निवास-काल और कुछ जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाएगी। इन दोनों सिद्धान्तों के प्रति कट्टर सिद्धान्तवादी आदर दिखाना असंभव और अन्यायपूर्ण होगा।

३२. समझौते के सिद्धान्त—रिपोर्ट के मुख्य अंश नीचे दिये जाते हैं—गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट तक जितने वादविवाद इस सम्बन्ध में हुए हैं सबसे यह बात मान ली गई थी कि प्रान्तीय स्वायत्त शासन के आरम्भ-काल से ही प्रत्येक प्रान्त को इस प्रकार सम्पन्न कर देना चाहिए कि आर्थिक सतुलन बनाए रखने की सम्भावना पर उनमें विश्वास रहे और विशेष रूप से स्थायी आर्थिक हीनता की दशा का, जिसमें कुछ प्रान्त पड़ गए थे, अन्त हो जाए। इसलिए मेरा सर्वप्रथम ध्येय प्रान्तों की वर्तमान और भावी आर्थिक स्थिति की परीक्षा करना और इस बात का पता लगाना रहा है कि इस ध्येय को पूरा करने के लिए किस सीमा तक सहायता की आवश्यकता पड़ेगी और दूसरे यह समझ लेना भी आवश्यक रहा है कि किस सीमा तक केन्द्रीय सरकार अपनी आर्थिक समृद्धि को हानि पहुँचाए बिना इस प्रकार की सहायता प्रदान करने की स्थिति में है। अन्त में हमें भविष्य की ओर भी देखना और सुझाव देना था कि कब और किस सीमा तक केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकारों के समक्ष आय कर की प्राप्ति में से खर्च करने के लिए और अधिक घट दे सकेगी।

प्रान्तीय दृष्टिकोण से इस ध्येय की प्राप्ति की बाध्यता अस्वीकार नहीं

की जा सकती, पर एक ही प्रश्न (यद्यपि वह कठिन प्रश्न है) उठना है कि पक्षपात-रहित न्यायपूर्ण बटवारे का आधार कैसे निश्चित किया जाए और दूसरी ओर केन्द्रीय सरकार के दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि भारत की आर्थिक दृढ़ता, स्थिरता और साख का ध्यान सर्वप्रथम होना चाहिए।

भारत सरकार ने सर आर्टो निमेयर के सुझावों को पूर्ण स्वीकार कर लिया और प्रान्तीय स्वायत्त-शासन आरम्भ करने के लिए १ अप्रैल, १९३७ की तिथि प्रस्ताविनी की। इसलिए २७ मई, १९३६ को कौन्सिल से आय के बटवारे तथा प्रान्तीय स्वायत्त-शासन के आरम्भ की आज्ञा जारी की गई।

३३ प्रान्तों द्वारा आपत्ति—जैसी कि आशा थी बहुत-से प्रान्त असंतुष्ट थे और उन्होंने अन्याय की शिकायत की। उड़ीसा को यह शिकायत थी कि उसके लिए अर्थ सहायता कबल ५० लाख रुपये की थी, जबकि मिन्य के लिए १०५ लाख रु० थी। इस बात की भी शिकायत की गई कि प्रान्तों को दी गई सहायता का बटवारा वास्तविक आवश्यकता के विचार से किया गया था, न कि उनके गुणों के विचार से, इसलिए प्रान्तों में आय का बटवारा अन्यायपूर्ण और निराधार था। वे प्रान्त, जिन्होंने अपना अर्थ-प्रबन्ध मिन्ययना और योग्यता से नियमित किया था, व ऐसे प्रान्तों की तुलना में, जो फिजूलखर्ची करने वाले और अयोग्य थे, सबसे अधिक घाटे में रहे। उदाहरण के लिए बम्बई इसलिए दुखी था कि इतने वर्षों की उसकी कष्टकारी भित्थ्यता, जिसके लिए उसे मेस्टन के परिनिर्णय के कारण बाध्य होना पड़ा था, उचित ध्यान नहीं रखा गया। उसने आय-कर में से अधिक बड़े भाग की इस अनिश्चित आधार पर माँग की थी कि २५% से अधिक आय-कर बम्बई में ही वसूल होता था और बम्बई को औद्योगिक जनसंख्या के हित के लिए अनेक महँगी सेवाओं की व्यवस्था करनी पड़ती थी। बम्बई ने इस बात पर आपत्ति की कि आय-कर से सहायता का बटवारा पूर्णरूपेण रेलवे विभाग की सफलता पर आधारित था और इस बात पर जोर दिया कि काल्पनिक ऋण, जिसका सृजन अनुस्वादक विभाई के साधनों के सम्बन्ध में किया गया था और जिसे आय से पूरा किया जाता था न कि ऋण से, विलोपित कर दिया जाए। बम्बई सरकार की ओर से यह तर्क भी उपस्थित किया गया था कि यदि बंगाल को जूट के निर्यात-कर से लाभ मिलना था तो उसे भी रूई के निर्यात-कर से लाभ मिलना चाहिए। इस प्रकार मद्रास की यह भावना थी कि उसे अधिक मिलना चाहिए था, क्योंकि यदि जनसंख्या को ही आधार बनाया जाए तो उसे २० प्रतिशत के स्थान पर आय-कर का लगभग २४ प्रतिशत मिलना चाहिए था। मद्रास सरकार ने अपनी तुलना बंगाल-जैसे प्रान्तों से की जिसमें अपनी आय-व्यय का समतुलन करने की तनिक भी चिन्ता नहीं की थी और यह शिकायत की कि बम्बई को आय-कर का बहुत बड़ा भाग दिया गया है। बिहार ने अपने को सबसे अधिक निचले प्रान्त कहकर अधिक सहायता की माँग उपस्थित की और यह इच्छा प्रकट की कि बटवारे का आधार यदि जनसंख्या होता तो अधिक अच्छा होता। पंजाब की यह शिकायत थी कि उसके उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त से पृथक किये जाने की बहुत

पुरानी बात को आवश्यकता से अधिक महत्त्व दिया गया है और बेकार ही यह धारणा बना ली गई कि यदि सीमाप्रान्त अलग न किया गया होता तो उसके ऊपर वह एक बहुत भारी बोझ के रूप में होता ।

प्रान्तों की कुछ शिकायतें अवश्य उचित थीं और उनका उपचार सम्भव था, पर ऐसा असम्भव था कि उनके कारण पुनर्विलोकन आवश्यक सिद्ध कर दिया जा सकता । एक प्रकार के तर्कों के समक्ष दूसरे बराबर के युक्तिपूर्ण तर्क उपस्थित करना तो सरल था । यह स्मरण रखना चाहिए कि एक दल को अधिक दे देने का अर्थ दूसरे को कम देना था, चाहे वह केन्द्र हो या अन्य प्रान्त हो और यह सम्भव था कि केन्द्र की आवश्यकता अधिक तीव्र हो अथवा वह राष्ट्र की जनता के साधारण हित के लिए हो और इसलिए उसका पर्याप्त रूप से पूरा करना आवश्यक हो ।

३४ केन्द्र की आवश्यकताएँ—यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्रान्तों को यथेष्ट मात्रा में देश का विकास करने वाले विभागों पर व्यय करने की पर्याप्त शक्ति प्रदान की जाए, और यह भी सत्य है कि केन्द्रीय सरकार की आवश्यकताएँ तुलनात्मक दृष्टि से स्थायी हैं, इसलिए उसके आय के साधन भी स्थायी होने चाहिए । सर ऑटो निमेयर का यह विचार बिलकुल सत्य था कि केन्द्रीय सरकार का अर्थ-प्रबन्ध स्थायी और पर्याप्त होना एक मूल आवश्यकता थी । अखिल भारतीय कार्यों पर व्यय करने के लिए केन्द्र के पास पर्याप्त धन होना चाहिए जैसे देश की सख्त बनाए रखना, बाह्य देशों के आक्रमण से अपने देश की रक्षा करना और आन्तरिक अशान्ति को शान्त करना, इत्यादि । इस बात पर भी जोर दिया गया था कि बिना केन्द्रीय सरकार की समृद्धि पर दृढ़ विश्वास हुए भारतीय रियासतें सघ की सदस्य बनने में आनाकानी करेंगी, और चूंकि नई व्यवस्था में केन्द्रीय सरकार को थोड़ा-सा अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा, जैसे सघीय न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में, और चूंकि उसने कुछ स्रोत अब उतने विद्वसनीय नहीं रहे जितने वे पहले थे ।^१

सर ऑटो की योजना की सफलता विशेषकर उस भाग की, जिसका सम्बन्ध आय-कर के केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के बीच बटवारे से था, रेल-विभाग के सन्तोषपूर्ण ढंग से काम करने पर निर्भर थी । प्रान्तीय सरकारों को अपने ही हित के लिए भारत सरकार के साथ रेलवे की समृद्धि को पुनः स्थापित करने के लिए तथा उनको पुनः देश की आय के प्रति पर्याप्त मात्रा में अशदान देने योग्य बनाने के लिए सहयोग करना चाहिए था । इसके लिए प्रान्तीय मडक नीति को नियमित करना आवश्यक था, ताकि सड़के रेलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय रेलों की सहायता करें । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा रेल-विभाग के व्यय का भी आद्योपान्त सुधार होना अत्यावश्यक था और विभिन्न प्रकार के मातायात के साधनों का सामंजस्य भी जरूरी था । १९३७-३८ में रेल-विभाग की आय में अनिरेक होने से, रेल-विभाग

१. सरक्षण की नीति के कारण निराशास्य-कर से कम आय होने की सम्भावना थी और आयात व्यापार पर शुल्कों का बहुत बुरा प्रभाव पडा था और रेल की आय की कोई निश्चिन्ता नहीं थी ।

की देयता का अन्त होने से और केन्द्राय सरकार की आय में वृद्धि होने से निमेयर परिनिर्णय के अन्तर्गत यह सम्भव न हो सका कि प्रान्तों को आय-कर का निर्णीत भाग १९३७-३८ के आधिक वर्ष से देना आरम्भ किया जा सके।

३५ प्रान्तों को आय-कर का भाग अभिहस्तांकित करने में निमेयर-सूत्र में संशोधन— फरवरी, १९४० में आय-कर में से प्रान्तों को उनका भाग देने के सम्बन्ध में निमेयर के सूत्रों में मसद ने सशोधन कर दिया। कौन्सिल की सशोधित आज्ञा के अन्तर्गत (जो १ अप्रैल, १९३९ से लागू हुई है) रेल-विभाग का अशदान पूर्ण रूप से केन्द्रीय धन-राशि की गणना से, जोकि प्रान्तों को बाँटने के लिए प्राप्त थी, अलग कर दिया गया और केन्द्र का भाग बाँटी जाने वाली धनराशि में पिछले तीन वर्षों के औसत पर नियत कर दिया गया, अर्थात् ४ $\frac{1}{2}$ करोड़ रुपया १९३९-४०, १९४०-४१, १९४१-४२ के लिए था, बाकी हमया प्रान्तों के बीच बाँट दिया गया। बाद के सशोधनों के साथ यही व्यवस्था १९४२-४३, १९४३-४४, १९४४-४५ में लागू रही। प्रान्तों के भाग में से जितना केन्द्र को अपने पास रखना था वह घटाकर १९४५-४६ में ३७५ करोड़ रु० और १९४७-४८ में ३ करोड़ रु० कर दिया गया। इस परिवर्तन का औचित्य युद्ध के कारण आर्थिक परिस्थितियों में हुआ परिवर्तन था, जिसके फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार को व्यय का बहुत अधिक भार उठाना पड़ा था और जिसने निरा-काम्य कर की आय में बहुत कमी कर दी थी।

३६ देशमुख परिनिर्णय—भारत के बंटवारे के कारण पहले के बंगाल, पंजाब और आसाम प्रान्त के अश पाकिस्तान में चले गए। इसलिए यह निश्चित करना आवश्यक हो गया कि इन प्रान्तों के कुछ अश के पाकिस्तान में चले जाने के कारण उनके लिए निश्चित आय के अश में से कितना वापस ले लिया जाए और भारतीय सभ के राज्यों में वह पुनः किस प्रकार बाँटा जाए। नये विधान की धारा २७ के अन्तर्गत जूट निर्यात-कर की आय में भाग पाने वाले प्रान्तों के लिए अनुदान निश्चित करने का प्रश्न भी हल करना आवश्यक था। ये दोनों जाँच और सिफारिश के लिए नवम्बर, १९४९ में श्री चिन्तामणि देशमुख को सौंप दिये गए।^१ श्री देशमुख का परिनिर्णय, जो भारत सरकार के पास जनवरी, १९५० तक भेजा गया, १ अप्रैल, १९५० से लागू हुआ।

निमेयर-परिनिर्णय के अन्तर्गत आय-कर के बाँटे जाने वाले भाग के बंटवारे का प्रतिशत अनुपात ऊपर दिया जा चुका है। पाकिस्तान में चले गए प्रान्त के भागों के प्रतिशत की गणना करने में श्री देशमुख ने इस समस्या को हल करने में यह जानने का प्रयत्न किया कि पाकिस्तान में चले गए भागों को अलग प्रान्त मान लेने पर इनके समान क्षेत्रफल और वित्तीय स्थिति वाले प्रान्तों की तुलना में निमेयर इनके लिए कितना भाग निश्चित करते।

जूट के निर्यात-कर के सम्बन्ध में देशमुख-परिनिर्णय के अन्तर्गत सहायक

१. पहले रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के गवर्नर थे और १९५० में भारत सरकार में वित्तमंत्री थे।

अनुदान (ग्रान्ट्स इन-एड) लाख रुपयों में निम्न प्रकार है—पश्चिमी बंगाल १०५, आसाम ४०, बिहार ३५ और उड़ीसा ५। यह परिनिर्णय वित्त आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने तक लागू रहने की था जिसे २२ नवम्बर, १९५१ की सविधान की धारा १८० (१) के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने श्री के० सी० नियोगी की अध्यक्षता में नियुक्त किया। इस आयोग की नियुक्ति कुछ करों की आय का केन्द्र और राज्यों के बीच वितरण, राज्यों को सहायक अनुदान तथा केन्द्र और राज्यों के बीच धारा २७८ (१) के अन्तर्गत किये गए समझौते आदि के सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिए की गई थी। आयोग ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट ३१ दिसम्बर, १९५२ को प्रस्तुत की। इस आयोग ने वर्तमान परिस्थितियों में राज्यों की आय निश्चित करने के लिए जनसख्या को आधार बनाया और आय-कर की विभाज्य राशि में से २०% राज्यों की सापेक्षिक वसूली के आधार पर और ८०% (१९५१ की जनगणना) सापेक्षिक जनसख्या के आधार पर बाँटने की सिफारिश की।

जूट निर्यात-कर—देशमुख-परिनिर्णय के अनुसार पश्चिमी बंगाल, आसाम, बिहार और उड़ीसा को जूट निर्यात-कर के स्थान पर सहायक अनुदान दिये जाते परन्तु ये राज्य इन अनुदानों से सन्तुष्ट नहीं थे और अधिक की माँग करते थे। इस सम्बन्ध में वित्त-आयोग ने निम्न अनुदानों की सिफारिश की—

(लाख रु० में)

राज्य	देशमुख-परिनिर्णय के अन्तर्गत दी जाने वाली रकम	वित्त-आयोग द्वारा प्रस्तावित रकम
पश्चिमी बंगाल	१०५	१५०
आसाम	४०	७५
बिहार	३५	७५
उड़ीसा	५	१५

सघीय उत्पाद-कर—इन करों की बढ़ती हुई आय के कारण राज्य की सरकारों ने इनमें भाग माँगना शुरू कर दिया। राज्यों ने वित्त आयोग से इस आय में से भाग देने की माँग की। आयोग ने कुछ वस्तुओं के उत्पाद-कर को वितरित करने का निश्चय किया।

सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और मार्च, १९५३ में यूनियन इयूटीज ऑफ एक्ससाइज (डिस्ट्रीब्यूशन) एक्ट पास किया।

जून १९५६ में दूसरा वित्त आयोग नियुक्त किया गया। वित्त आयोग की निम्न बातों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी—

- (१) केन्द्र और राज्यों के बीच करों का विभाजन,
- (२) राज्यों को सहायक अनुदान (ग्रांट इन एड) देने के नियम, तथा
- (३) भारत सरकार द्वारा राज्यों को दिये गए ऋण की व्याज-दर और

अदायगी में यदि अपेक्षित हो तो, परिवर्तन ।

वित्त आयोग का मत यह था कि आय-कर में राज्यों को दे दिया जाने वाला भाग जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए, न कि कर की वसूली के आधार पर । विनरएण के सिद्धान्त के रूप में कर की वसूली को उन्होंने धीरे-धीरे दूर करने की सिफारिश की और यह प्रस्ताव किया कि राज्यों के भाग का वितरण १० प्रतिशत कर की वसूली और ९० प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर किया जाए ।

प्रथम वित्त आयोग ने तम्बाकू (निर्मित तम्बाकू सम्मिलित है), दियासलाई, वनस्पति पदार्थ (वेजीटेबिल प्रोडक्ट्स) पर लगे उत्पाद-कर की ४० प्रतिशत आय को वितरित करने की सिफारिश की थी । द्वितीय वित्त आयोग ने इस सूची में चीनी, चाय, कच्चा, कागज तथा वेजीटेबिल तेल के उत्पाद-करों को जोड़ दिया, किन्तु वितरित करने के लिए प्रतिशत घटाकर २५ कर दिया ।

द्वितीय वित्त आयोग की अन्य महत्वपूर्ण सिफारिश उत्तराधिकार कर (एस्टेट ड्यूटी) के सम्बन्ध में है । इससे पूर्व इस मद से प्राप्त आय राज्यों के बीच आय कर के अनुपात में ही बाँटी जाती थी । द्वितीय आयोग की सिफारिश थी कि इस आय का एक प्रतिशत सघीय क्षेत्रों के लिए अलग कर देने के बाद शेष राशि अचल तथा अन्य सम्पत्ति के कुल मूल्य (ग्रॉस वैल्यू) के अनुपात में बाँट दी जाए । तदनन्तर अचल सम्पत्ति की राशि प्रान्तों में स्थित अचल सम्पत्ति के अनुपात में बाँट दी जाए तथा अन्य सम्पत्ति की आय जनसंख्या के आधार पर बाँट दी जाए ।

सहायक अनुदानों के सम्बन्ध में आयोग ने सिफारिश की कि अनुदान के लिए राज्य की उपयुक्तता का निर्णय विस्तृत अर्थ में वित्तीय आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए जो योजना की प्राथमिकताओं और व्यवस्था के अनुरूप हो । दूसरे राज्य की आय और व्यय के अन्तर के करो में भाग प्राप्त करके ही पूरा करना चाहिए तथा सहायक अनुदान को अवशिष्ट (रेजीडुअरी) सहायता के रूप में सामान्य और बिना शर्त के अनुदान के रूप में होना चाहिए । बृहद् उद्देश्यों के लिए भी सहायक अनुदान दिये जाएँ, किन्तु उनका व्यय उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होना चाहिए ।

सरकार ने राज्यों को दिये गए ऋण के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों को छोड़कर शेष सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया ।

इस आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय करो में प्रान्तीय भाग दून से भी अधिक हो गया । १९५६-५७ में केन्द्रीय कर आय से राज्यों को प्राप्त हुई आय कुल ७६ ४ करोड़ ६० थी । १९५८-५९ १९५९-६०, १९६०-६१ (संशोधित अनुमान) में यह क्रमशः १६२१ करोड़ ६०, १६६६ करोड़ ६० तथा १७८८ करोड़ ६० थी । १९६१-६२ (वर्जट अनुमान) में यह १६००० करोड़ ६० होगी ।

इस समय तीसरा वित्त आयोग, जिसे राष्ट्रपति ने २ दिसम्बर, १९६० को नियुक्त किया था, कार्यशील है तथा निकट भविष्य में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । आयोग को निम्न विषयों के सम्बन्ध में सिफारिशें प्रस्तुत करनी हैं—

(क) सघ और राज्यों के बीच में केन्द्रीय करो की वास्तविक आय का वितरण ।

(ख) केन्द्र द्वारा राज्यों को दिये जाने वाले सहायक अनुदान (ग्राण्ट इन एड) को निश्चित करने के नियम ।

इनके अतिरिक्त राष्ट्रपति ने निम्न विषयो पर भी आयोग से सुझाव देने के लिए कहा है—

(१) तृतीय योजना का आवश्यकताओं के लिए राज्यों को धारा (घाटि-किल) २७५ के अन्तर्गत दिये जाने वाले सहायक अनुदान तथा राज्यों द्वारा उपलब्ध साधनों से अतिरिक्त आय की प्राप्ति ।

(२) धारा २६६ के अन्तर्गत कृषि-भूमि के अलावा अन्य सम्पत्ति पर उत्तराधिकार-कर (एस्टेट ड्यूटी) की वास्तविक आय को किसी वित्तीय वर्ष में राज्यों के बीच वितरित करने से सम्बन्धित नियमों में परिवर्तन ।

(३) धारा २६६ के अन्तर्गत रेल के किराये पर लगे करो से प्राप्त आय के वितरण-सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन ।

(४) निम्न वस्तुओं पर लगे अतिरिक्त उत्पाद-कर से प्राप्त आय के वितरण-सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन—(१) सूती वस्त्र, (२) रेयन या कृत्रिम रेसम के वस्त्र, (३) ऊनी वस्त्र, (४) चीनी और (५) तम्बाकू, जिसमें निर्मित तम्बाकू भी सम्मिलित है ।

मई १९१४ में डॉक्टर पी० वी० राजामनार मद्रास के हाईकोर्ट के मुख्य सेवा से मुक्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक चौथा वित्त कमिशन नियुक्त किया गया । इसकी सिफारिशें १९६६-६७ से लेकर १९७०-७१ तक लागू रहेगी और केन्द्रीय तथा राज्यों में वित्त वितरण पर प्रभाव डालेगी ।

३७ वर्तमान प्रान्तीय अर्थ-प्रबन्ध—प्रान्तीय स्वायत्त-शासन के आरम्भ होने के बाद से प्रान्तीय सरकारों की आय और उनके व्यय दोनों में ही बहुत काफी वृद्धि हुई है—विशेषकर द्वितीय युद्ध के बाद । आय में वृद्धि कृषि की उत्पत्ति के मूल्य में वृद्धि, प्रान्तीय आय के साधनों, जैसे जंगल के उत्तरोत्तर प्रयोग, अनेक प्रान्तों में अतिरिक्त अथवा नये करो के आरोपण, जो मुद्रा-प्रसार के प्रभाव को रोकने के लिए थे, और केन्द्र के पास एकत्रित आय-कर से प्रान्तों के भाग में प्रतिवर्ष वृद्धि के कारण हुई थी ।

व्यय के अन्तर्गत वृद्धि पुलिस और नागरिक रक्षा के उपायों के कारण अतिरिक्त आर्थिक भार, मँहगाई तथा अन्य अधिदेयों, साक्ष सामग्री पर विनियोग पूर्ति तथा वितरण सम्बन्धी योजनाओं, कुछ प्रान्तों द्वारा अपने ऋण के भार को कम करने के लिए केन्द्र को धन देना, राष्ट्र विकास की योजनाओं पर अधिक व्यय करने और अधिकतर प्रान्तों द्वारा युद्ध के पश्चात् पुनर्निर्माण कार्यों पर व्यय करने के लिए धन पृथक् करने आदि कारणों से हुई थी ।

दूसरी विशेषता युद्ध-काल के प्रत्येक वर्ष में आय का अतिरिक्त होना था, जोकि

केन्द्र के बड़े घाटों के वज्रट में नितान्त त्रिपरीत रक्षा पर अधिक व्यय के कारण था ।^१

प्रान्तीय कर व्यवस्था में कृषि-आय पर कर उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है । अनेक प्रांतों, जैसे पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, उड़ीसा आदि, न पहले से ही यह कर लगा रखा है और दूसरे प्रान्त लगाने की बात साच रह है ।

१९५१-५२ में नियोजन-युग के सूत्रपात के पश्चात् प्रान्तीय आय-व्यय में बहुत वृद्धि हुई है । इसका कारण, जैसा पहले भी कहा जा चुका है, विकास-कार्यों के लिए सेवाओं की स्थापना और प्रसार है । इसके अतिरिक्त आर्थिक प्रगति के लिए अपेक्षित विनियोग के फलस्वरूप पूँजी व्यय भी बहुत बढ़ गया है । १९५८-५९ (एकाउण्ट्स) में भारत के सभी राज्यों के पूँजी-व्रजट सम्मिलित करने पर १२,९६ लाख रु० का घाटा था । १९५९-६० (संशोधित अनुमान) में यह ३६,३८ लाख रु० था तथा १९५०-५१ के व्रजट में १२,७७ लाख रु० था । आय के मद में इन्हीं वर्षों में ४८,३१ लाख रु०, २३,४७ लाख रु० तथा ५६८ लाख रु० की वृद्धि थी ।

रेल-वित्त

३८ सेपेरेशन कान्वेंशन के अन्तर्गत रेल विभाग के आर्थिक परिणाम—१९२४ के सेपेरेशन कान्वेंशन के अन्तर्गत रेल-विभाग के कार्यों के आर्थिक परिणामों का सारास निम्न प्रकार दिया जा सकता है—१९२४-२५ से १९३५-३६ तक के काल पर विचार करने से यह पता लगता है कि प्रथम ६ वर्ष उत्कर्ष के वर्ष थे और अन्तिम ६ वर्ष अपकर्ष के । यदि पूरे काल को लिया जाए तो पहले ६ वर्षों में कुल अतिरिक्त आय जो अर्जित की गई वह ५२,६४ लाख रुपये थी और पिछले ६ वर्षों की कमी ११,६३ लाख रुपयों की थी । इस बदलते हुए भाग्य की लंबी अवधि में ११०१ लाख रुपये का वास्तविक अतिरिक्त हुआ, अर्थात् नित्य-प्रति के कार्यों का व्यय काटकर, अवक्षयण की व्यवस्था करके और ऋण ली हुई पूँजी पर पूरा-पूरा व्याज देकर प्रतिवर्ष १ करोड़ रुपये से कुछ कम का अतिरिक्त हुआ ।

१९३०-३१ के वर्ष से घाटे का युग आरंभ हुआ, जो कि मुख्यतः विश्वव्यापी आर्थिक अवसाद, वस्तुओं के मूल्य में कमी, गेहूँ के निर्यात में कमी राजनीतिक स्थिति में अशान्ति, बाढ़ और भूकंपों से पहुँचाई हुई हानि, सड़कों की तीव्र प्रतिस्पर्धा, नदी और समुद्र की बढ़ी हुई प्रतिযোগिता, मजदूरी में वृद्धि के कारण नित्य-प्रति के कार्यों के खर्च में वृद्धि आदि के कारण था । सप्तर के समस्त देशों की, जिनमें से अधिकांश शान्तिकाल से हमारे सर्वोत्तम ग्राहक थे, प्रशुल्क-पद्धति ने रेल की आय की शक्ति पर बुरा प्रभाव डाला ।

१ बंगाल, जिसके बज में १९४३-४४ व १९४४-४५ में बहुत बड़ी कमी हो गई थी, एक अपवाद था ।

२. वैजुड इन्वार्सी कमेटी (१९३७) के अनुमान से सबक यातायान द्वारा रेलवे को ४३ करोड़ प्रतिवर्ष का घाटा रखा—रिपोर्ट, पैग १६६ ।

इन लगातार होने वाले घाटों के कारण १९३१-३२ के बाद देश की सामान्य आय के प्रति रेलवे कोई भी अशदान न कर सती। सेपेरेशन कान्वेंशन के अन्तर्गत एकत्रित किया हुआ अशदान का बकाया १९३१-३२ से लगाकर १९३६-३७ तक ३० ७४ करोड़ रुपये हो गया था। १९३६-० के अन्त तक यह सध्या बढ़कर ३६½ करोड़ रुपये हो गई थी। इस काल में रेल-विभाग ने यही नहीं कि अपना सामान्य-कोष कम कर दिया हो, वरन् अवक्षयण कोष से भी उन्होंने ३१३४ करोड़ रुपया ऋण पर ब्याज भ्रदा करने के लिए उधार ले लिया। यह नितात असंभव था कि लगभग ६२ करोड़ रुपये की इतनी बड़ी देयता भविष्य में होने वाले अतिरेक से थोड़े-से नये हुए समय के अन्दर भ्रदा की जा सके। इसी बीच नये विधान के अन्तर्गत प्रांतीय स्वायत्त शासन के प्रचलित हो जाने के साथ-ही-साथ और अधिक आय के साधनों की प्राप्ति के लिए जोर लगाया जा रहा था। चूंकि वर्तमान सेपेरेशन कान्वेंशन के अन्तर्गत अवक्षयण कोष से लिये हुए ऋण भविष्य के अतिरेक पर सबसे प्रथम अधिकार समझे जाते थे और उसके पश्चात् सामान्य आय की देयता भी पूरी करती थी। इसलिए सामान्य आय को रेल से अशदान पाने के लिए बहुत काफी प्रतीक्षा करनी आवश्यक थी। इससे बचने का उपाय देयता पूरी करने के लिए १९३७ से तीन वर्ष के विलम्ब-काल में निहित था।^१ इस विलम्ब-काल के कारण यह सम्भव हो सका कि ब्याज देने के बाद रेल-विभाग की वास्तविक आय के अतिरेक को, जो १९३६-३७ से दिखाई पड़ने लगा था, व्यवस्था की जा सके, ताकि ६२ करोड़ रुपये का भारी ऋण पूरा किये बिना ही सामान्य आय में अशदान देना तुरन्त आरम्भ किया जा सके। इससे केन्द्रीय सरकार को भी १९३७-३८, १९३८-३९ और १९३९-४० में निमेयर परिनिर्णय के अन्तर्गत आय-कर की प्राप्ति को सीमित मात्रा में प्रान्तों को हस्ताकित करने का अवसर प्राप्त हुआ।

१९३८-३९ में प्राप्त अतिरेक १ ३७ करोड़ रुपये का था, परन्तु १९३९-४० में वह बढ़कर ४३३ करोड़ रु० हो गया। वर्ष के आरम्भ में अनिश्चित अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति के कारण कुछ वस्तुओं की लोगों ने राशि एकत्रित कर ली और मात्रियों की सख्या तथा भेजे जाने वाले माल से प्राप्त आय में कमी आ गई। युद्ध की घोषणा के पश्चात् परिवर्तन हुआ, विशेषकर भेजे जाने वाले माल से प्राप्त आय में और बाद में यात्रियों से भी, क्योंकि लोगों की आरम्भ में ही आर्थिक स्थिति कुछ सुधर गई थी। समुद्र-मार्ग से हटकर रेल मार्ग से यात्रा बढ़ जाने के कारण भी रेल की आर्थिक स्थिति में उन्नति हुई, जैसा कि १ मार्च, १९४० से किराया और शुल्क बढ़ने से हुआ था।

१९४५-४६ के हिसाब में ३८ २० करोड़ रुपये का लाभ दिखाई पड़ा। १९४३ के निर्णय के अनुसार, जिसमें सामान्य आय में ३२ करोड़ रुपये का अशदान दोनों वर्षों के लिए (१९४४-४५ और १९४५-४६) निश्चित किया गया था, ३२ करोड़ रुपया

१. बाद में यह काल ३१ मार्च १९४२ तक बढ़ा दिया गया।

सामान्य आय में जमा कर दिया गया और ६२० करोड़ की बेची हुई रकम रेलवे रक्षित कोष में जमा कर दी गई, जिससे उस कोष में अब कुल ३८ १३ करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। १९४६-४७ के पुनरोक्षित आगणन के अनुसार अनिरेक ८६४ करोड़ रुपये का आँका गया था। पिछले वर्ष के समझौते के अनुसार, जिसमें १९४६-४७ में रेल-विभाग के सामान्य आय के अशदान को उतनी रकम पर निश्चित कर दिया था जितनी कि बराबर होनी है, व्यापारिक ढंग पर पूँजी के ऊपर लगाई हुई १ प्रतिशत रकम के, जिसमें से सैनिक महत्व रखने वाली रेलों पर घाटा निकाल दिया जाए और जिसमें २ करोड़ रुपया सुधार-कोष (जो १९४६ में कायम हुआ, जिसमें प्रारम्भ में ही १२ करोड़ रुपया रेलवे रक्षित कोष से यात्रियों और कर्मचारियों को सुविधा देने के लिए निकाल लिया गया था) में जमा कर देने के बाद जितना बचे उसका आधा जोड़ दिया जाए, बाद को सामान्य आय में ५ ६१ करोड़ रुपये के दिये जाने की सम्भावना थी। बटवारे के फलस्वरूप भारतीय सभ को कुल ३३,८६५ मील रेल की लाइन ६७८ करोड़ रुपये की पूँजी के साथ तथा अवक्षयण-कोष ६३ २२ करोड़ रुपया, रेलवे-रक्षित कोष ७ ६८ करोड़ रुपया और सुधार-कोष ११ ७१ करोड़ रुपया प्राप्त हुआ।

बहुत बड़ी मात्रा में प्रतिस्थापन के बकाया और मूल्यों के बढ़ जाने से प्रतिस्थापन के व्यय में वृद्धि होने के कारण भारतीय रेलवे जाँच कमेटी (कुजरू कमेटी) ने पाँच वर्षों तक २२ करोड़ रुपये के वार्षिक अशदान का प्रस्ताव किया है। १९४६ ५० के पुनरोक्षित आगणन के अनुसार ११ ०२ करोड़ रुपये का अतिरेक था, जिसमें ७ करोड़ ६० सामान्य आय में जमा किया गया और ४ ०२ करोड़ ६० अवक्षयण कोष में।

१९२४ का कान्फेन्शन १ अप्रैल, १९४३ से रह ही गया—मार्च, १९४३ में विधानसभा द्वारा स्वीकृत प्रस्तावानुसार अवक्षयण-कोष का बकाया ऋण दन क पश्चात् १९४३-४४ में व्यापारिक रेलों से लाभ सामान्य आय के साथ ३ १ के अनुपात में बाँटा जाने वाला था। इसके अतिरिक्त व्यापारिक रेलों पर अनिरेक सामान्य आय और रेलवे-रक्षित कोष के बीच दोनों की आवश्यकतानुसार बाँट जाने वाले थे।

१९४६ में बिठाई गई कान्फेन्शन कमेटी ने १९२४ के जटिल सूत्र को अस्वीकृत कर दिया और दूसरी सरल तथा काम में लाई जाने योग्य व्यवस्था को अपनाया, जिसके अन्तर्गत सामान्य आय में ४% का लाभांश प्रयुक्त पूँजी पर (केपिटल एट चार्ज) दिया जाता। १९५०-५१ में ३१ ८५ करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था की गई। १९५०-५१ में आय के अतिरेक की गणना १४ ०१ करोड़ रुपये की की गई (आय २३३ ५० करोड़ ६०, व्यय २१८ ४६ करोड़ ६०)।

१. इन्में २ ५७ करोड़ रुपया सम्मिलित है, जो लगभग ६५०० मील दूर तक फैली हुई १० रिया-सनों की रेलों के लिए था और जो १ अप्रैल, १९५० से केन्द्रीय नियन्त्रण के अन्तर्गत आ गई थी।

नवम्बर, १९५४ में रेलवे कान्वेन्शन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह कमेटी दिसम्बर, १९४९ के कान्वेन्शन प्रस्ताव के अनुसार, मई १९५४ में बिठाई गई थी। अन्य बातों के साथ इस कमेटी के परीक्षा के विषय निम्न थे—

- (१) रेलवे द्वारा सामान्य आय को दिया जाने वाला लाभांश,
- (२) पूंजी और आय के खाते में रेलवे व्यय का विवरण, और
- (३) तीनों रेलवे कोष—अवक्षयण सुरक्षित कोष, विकास-कोष तथा सुरक्षित आय-कोष—को दी जाने वाली रकम।

कमेटी ने भी १९५५-५६ से ५ वर्ष तक ४% के लाभांश की सिफारिश की। अवक्षयण सुरक्षित कोष को दी जाने वाली रकम ३० करोड़ से बढ़ाकर ३५ करोड़ रुपये करने की सिफारिश भी की गई।

रेलवे व्यय तथा अशदान

(करोड़ों में)

	प्रथम योजना	दूसरी योजना	तीसरी योजना
योजना अनुसार रेलवे पर व्यय	४२३ २३	१,०४३ ६९	१,३८१ ००
रेलवे का अशदान योजनाओं में	२८० ००	४६५ ००	५३१ ००
विदेशी मुद्रा का रेलवे योजनाओं में भाग		३१९ ४५	२८३ ५०

स्थानीय वित्त

३९ स्थानीय (गाँव-सम्बन्धी) बोर्ड—चूँकि भारत के अधिकांश लोग गाँवों में निवास करते हैं, इसलिए नगर-पालिकाओं की तुलना में, जो सख्या में बहुत कम जनसंख्या की सेवा करती हैं, जिला और उपजिला-बोर्डों की महत्ता बहुत अधिक है। किसी समय में भूमि पर प्रांतीय शुल्क अथवा अधिकार केन्द्रीय सरकार के बजट के मुख्य अंग हुआ करते थे। आज वे स्थानीय और जिला बोर्डों की आय के मुख्य अंग हो गए हैं। ये आरम्भ-काल में बम्बई और मद्रास में १८६५ और १८६९ के बीच शुरू किये गए थे और सड़कों के निर्माण तथा मरम्मत के लिए, स्कूलों और अस्पतालों को चलाने के लिए, गाँव की सफाई के लिए तथा अन्य स्थानीय खर्चों के लिए भूमि पर लगाये गए थे। इस सिद्धान्त का लार्ड मेयो की विकेन्द्रिकरण-योजना के अनुसार प्रसार किया गया था। इसी प्रकार के उत्तर बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में लगाए जाने के लिए अनेक विधेयक आस किये गए। पंजाब और अवध में सड़कों, स्कूलों और जिलों के डाकखानों के लिए मालगुजारी का बन्दोबस्त होते समय निर्धारित उपकर, नये सामान्य उपकर के साथ-साथ जारी रहे। ऐसे ही बन्दो-बस्तीय उपकर मध्य प्रदेश, बर्मा और आसाम में लगाये गए, पर बाद में उनका स्थान

सामान्य उपकर न ले लिया। १८७१ और १९०५ के बीच कुछ उपकर केन्द्रीय आवश्यकताओं के लिए लगाय गए। अकाल-शीमा-कोष १८७८ में प्रारम्भ हुआ, जिसमें कुछ प्रान्तों में अन्य गाँवों के कर्मचारियों को देने के लिए प्रान्तीय उपकर भी जोड़ दिये गए। भारत सरकार की आर्थिक स्थिति की उन्नति के कारण १९०५-६ में उन उपकरों को छोड़कर, जो स्थानीय आवश्यकताओं के लिए लगाये गए थे, और सब उपकर हटा दिये गए। इस सुधार का प्रभाव किसी-किसी स्थान पर आरोपित उपकरों की मात्रा में कमी करने का नहीं था, वरन् धन-राशि का प्रान्तों से स्थानीय आवश्यकताओं के लिए स्थानान्तरित करना था। प्रान्तीय सरकारों का यह घाटा केन्द्रीय सरकार न पूरा किया। हाल में कुछ प्रान्तों में उपकरों की दर में वृद्धि करने अथवा जैमा मद्राम ने किया है विशेष कार्यों, जैसे प्रारम्भिक शिक्षा आदि, के लिए नये अतिरिक्त उपकर लगाने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है। भूमि पर लगाये हुए इन स्थानीय उपकरों का आधार मालगुजारी की प्रथा के अनुसार बदलता रहता है। भूमि पर उपकर यद्यपि कर देने की शक्ति के अनुपात में नहीं लगाया गया है, क्योंकि इसका आरोप समान रूप से एक ही दर पर होता है, फिर भी प्रत्येक स्थान पर इसे उचित कर मानते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग सम्पत्ति के लाभ के लिए किया जाता है, जिन्हें स्थानीय बोर्डों के कार्यों से लाभ पहुँचता है।

४०. नगरपालिका-वित्त—नगरपालिकाओं की आय के मुख्य स्रोत कर और शुल्क हैं, जिनसे लगभग $\frac{2}{3}$ आय प्राप्त होती है। बची हुई $\frac{1}{3}$ आय नगरपालिका की सम्पत्ति और प्रान्तीय सरकारों की आय के अशदान तथा अन्य साधनों से प्राप्त होती है। स्थानीय अधिकारियों द्वारा आरोपित कर चार वर्गों में बाँट जा सकते हैं—

(१) व्यापार पर कर, जैसे चुगी, सीमा-मार्ग शुल्क, (२) सम्पत्ति पर कर, जैसे घरो तथा उनकी स्थिति पर कर, (गाँवों में भूमि पर उपकर), (३) व्यक्तियों पर कर, जैसे परिस्थिति, व्यवसाय, व्यापार, पेशा, धार्मिक यात्री, घरेलू नौकर-चाकर आदि, (४) फीस और लाइसेंस। फीस म्युनिसिपैलिटी द्वारा की गई किसी विशेष सेवा, जैसे सफाई, के लिए वसूल की जाती है अथवा विलासिता पर कर के रूप में वसूल की जाती है, या कभी-कभी नियमित करने के लिए भी लगाई जाती है, जैसे गाने पर लाइसेंस, गाड़ियों पर, कुत्तों और अन्य पशुओं पर। अप्रिय और खतरनाक व्यापारों पर भी लाइसेंस फीस लगाई जाती है। टेक्सेजन इन्व्वायरी कमेटी ने इस बात का संकेत किया था कि परोक्ष-करों के सम्बन्ध में विशेष रूप से जागरूक रहने की आवश्यकता है, जैसे व्यापार पर कर, जो चुगी का रूप धारण करता है और सीमा-मार्ग शुल्क जिससे अन्तर्प्रान्तीय आवागमन में अनावश्यक बाधा पड़ती है। चुगी और मार्ग शुल्क पर, जो कि करारोप के सभी सिद्धान्तों के विरुद्ध है, विशेष आपत्ति की गई थी और उनके स्थान पर फुटकर बिक्री अथवा पसों पर कर लगाए जाने की राय दी गई थी। कमेटी ने दूसरा महत्त्वपूर्ण सुभाव नगर की सम्पत्ति पर जेबो दर स कर लगाने का दिया, क्योंकि उन्हें नगरपालिका के कार्यों से विशेष लाभ पहुँचता है। जो-कुछ भी हो, कर निर्धारित करने और वसूल करने के यत्न को आज की

अपेक्षा और अधिक कुशल होने की आवश्यकता है। सबसे अधिक व्यय लोक स्वास्थ्य सुविधा तथा लोक-निर्माण और शिक्षा पर है। नगरपालिकाएँ प्रायः अपनी साधारण आय से अपना व्यय पूरा नहीं कर पाती और उन्हें प्रायः सरकार अथवा जनता से ऋण उधार लेना पड़ता है, विशेषकर अपनी ऐसी बड़ी-बड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए, जैसे पानी का प्रवन्ध और गन्दे पानी के बहने का प्रवन्ध आदि।

४१ स्थानीय संस्थाओं के अर्थात् साधन—अधिकारों के धीरे-धीरे स्थानीय संस्थाओं के प्रति हुए अवक्रमण और विस्तृत कार्य, जो लाईं भेगों के समय से और विशेषकर स्थानीय स्वशासन के जुने हुए मन्त्रियों के हाथ में आने के बाद से नगरपालिकाओं, ग्राम-बोर्डों और पंचायतों को दिये गए हैं, जैसे लोक-स्वास्थ्य और शिक्षा आदि को विचाराधीन रखते हुए यह कहा जा सकता है कि इन संस्थाओं के आय के स्रोत नितान्त अर्थात् है। उनके लिए आधुनिक प्रशासन प्रणाली का प्रचलन उस समय तक असम्भव है जब तक कि उनकी आय की वृद्धि का उपाय न किया जाए। १९१६ और १९३५ के विधान के अन्तर्गत स्थानीय संस्थाओं से यह आशा की जाती है कि वे उन सेवाओं का खर्च उठावेंगी जो पहले विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों द्वारा निःशुल्क प्राप्त होती थी। आरम्भ के उत्साह में स्थानीय संस्थाएँ यह भूल गईं कि “सारे कार्य धन के ऊपर निर्भर हैं” और उन्होंने बड़ी महँगी शिक्षा, उपचार आदि की योजनाएँ आरम्भ कर दीं जो उनकी शक्ति के बाहर थीं। इस प्रकार उत्पन्न आर्थिक कठिनाई बाद में व्यय में कमी करके, प्रतिरिक्त कर का आरोप करके और अधिक विचारपूर्ण ढंग से साधनों का बटवारा करके दूर की गई। फिर भी यह कहा जा सकता है कि मूलतः स्थानीय संस्थाओं की आर्थिक स्थिति बहुत ही अधिक असन्तोषजनक है। उनकी कठिनाइयाँ हाल में व्यय में वृद्धि के कारण और भी अधिक बढ़ गई हैं, जो कि भ्रम और पूँजी के मूल्य के बढ़ जाने, वेतन के पुनरीक्षण और महँगाई भत्ता देने के कारण हुई हैं, जबकि उनके आय के साधन कम और लोचनीय ही बने रहे हैं।^१

४२ साधनों के अर्थात् होने का कारण—दम्बई की स्थानीय स्वशासन कमेटी (१९४०) ने कहा था कि “प्रान्तीय सरकारों और स्थानीय बोर्डों के बीच आय के साधनों का बटवारा स्पष्ट रूप से नहीं हुआ है और प्रान्तीय सरकार अच्छे आय के साधनों से लाभ उठाती रही है,” जो कि औचित्य के दृष्टिकोण से स्थानीय बोर्डों को मिलने चाहिए थे। स्थानीय और प्रान्तीय आय-प्राप्ति के क्षेत्रों का स्पष्ट बटवारा अत्यन्त आवश्यक है। भारत में स्थानीय संस्थाओं की निर्धनता का एक कारण यह भी रहा है कि उनका विकास धनी, अर्द्ध-स्वतन्त्र और छोटी-छोटी इकाइयों में बड़े राजनीतिक मण्डल के रूप में व्यवस्थित होने के बजाय अधिकारों के अवक्रमण से हुआ है। दूसरा कारण यह भी है कि स्थानीय बोर्डों का अधिकार-

१. बेल्सियर, रिपोर्ट ऑफ दि पब्लिकिस्टिक इन्क्वायरी कमेटी, दम्बई १९४८, पृष्ठ १६६।

क्षेत्र प्रायः इतना विस्तृत होता है कि उनका करदाताओं से कोई प्रभावशाली सम्बन्ध ही नहीं रह पाता। यदि ऐसा न हुआ होता तो गाँवों, घरों और व्यक्तियों पर स्थानीय वार्डों द्वारा कर आरोप बड़ा सरल होता। इस दृष्टिकोण से गाँव-नचायतों के प्रभाव को फिर से स्थापित करना तथा वर्तमान स्थानीय वार्डों के कर्तव्यों को सीमित कर देना वाञ्छनीय होगा।

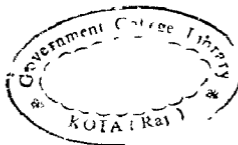
४३ साधनों की उन्नति—यद्यपि विवेन्डीकरण आयोग के प्रस्तावों तथा १९१६ के सुधारों के प्रचलित होने से स्थानीय अधिकारियों को बहुत अधिक आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई है, फिर भी जहाँ तक आरोपित करों की प्रकृति से सम्बन्ध है, इसके सिवाय और कुछ नहीं हुआ है कि वे कर, जो बिना भारत सरकार की आज्ञा लिये हुए आरोपित किये जा सकते हैं, उनका स्पष्टीकरण परिगणित कर नियमों में कर दिया गया है। टेबलेशन इन्क्वायरी कमेटी ने निम्न प्रस्ताव स्थानीय सस्थाओं के आय-साधनों की वृद्धि के दृष्टिकोण से किये हैं—(१) मालगुजारी का नीची दर पर प्रामाणिक कर देना, ताकि स्थानीय कर आरोप का अधिक अवसर प्राप्त हो सके, (२) प्रान्तीय सरकारों द्वारा नगरों से भूमि के बसूल किये हुए किराये और कृषि के अतिरिक्त आय काम में आने वाली भूमि पर बसूल किये हुए शुल्क का एक अंश स्थानीय सस्थाओं को देना, (३) नगरपालिकाओं को विज्ञापन पर कर लगाने का अधिकार देना, (४) मनोरजन तथा जुए पर कर-आरोप के क्षेत्र को बढाना और स्थानीय सस्थाओं को इस प्रकार प्राप्त हुई आय का पर्याप्त अंश देना, (५) परिस्थिति और सम्पत्ति तथा पेशों पर कर लगाने की व्यवस्था को अधिक उन्नत तथा विस्तृत करना, (६) मोटरगाड़ियों पर आयात-कर घटाना और प्रान्तीय सरकारों को इस योग्य बनाना कि वे एक प्रान्तीय कर मार्ग-शुल्क के स्थान पर लगा सकें जो कि स्थानीय सस्थाओं को दिया जा सके, (७) चुने हुए क्षेत्रों में स्थानीय सस्थाओं को विवाहों के रजिस्ट्रेशन पर फीस लगाने का अधिकार देना, और (८) स्थानीय सस्थाओं के साधनों को आर्थिक सहायता द्वारा बढाना, जो कि साधारणतया राष्ट्रीय महत्ता की सेवाओं तक सीमित होनी चाहिए और इस प्रकार दी जानी चाहिए कि प्रान्तीय सरकार कुशलता पर जोर दे सके।^१ बम्बई की स्थानीय स्वशासन कमेटी ने इनमें से अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार किया और स्थानीय सस्थाओं के साधनों को बढाने के लिए निम्न सुझाव दिए। नगरपालिकाओं के आय के साधन निम्न प्रकार बढाए जा सकते हैं—(१) स्थायी सम्पत्ति के स्थानान्तरण पर कर लगाकर, (२) नगरपालिकाओं के अन्दर भवनो व निर्माण किये जाने वाले भूमि के टुकड़ों पर लगाये हुए कर का एक अंश देकर, (३) विवाह, गोद लेन तथा दावतों पर कर लगाकर और (४) मनोरजन कर के एक अंश को देकर तथा विजली के अधिकार से प्राप्त आय का ५०% देकर। गाँव की स्थानीय सस्थाओं के लिए कमेटी ने निम्न सिफारिशों की थी—(१) स्थानीय पनराशि पर उपकर १ आने का स्थान पर १½ अथवा २ आने

१. देखिए, 'टेबलेशन इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट', पृष्ठ १६४-६६।

करना, (२) जंगल की प्रमुख उत्पत्ति से प्राप्त आय पर ११ आने का उपकर लगाना और (३) मालगुजारी के १०% का हस्ताकन करना। कमेटी ने ठीक ही कहा था कि स्थानीय सस्थाओं के लिए सबसे उपयुक्त ढंग करो और उपकरो को व्यक्तियों के प्रति की गई निश्चित सेवाओं पर लगाना होना चाहिए, जैसे अनिवार्य शिक्षा पर उपकर।^१

१९४९ में नियुक्त स्थानीय वित्त जांच समिति ने सिफारिश की थी कि सधीय सूची के ८९वें मद में दर्ज रेल, हवाई या पानी से जाने वाले सामान और सवारी पर लगा टर्मिनल टैक्स तथा रेल के किराये और भाडे पर लगे कर को स्थानीय सस्थाओं के लिए सुरक्षित कर देना चाहिए। इसके अलावा राज्यीय सूची की सातवीं अनुसूची में दर्ज टाल टैक्स तथा अन्य कर, जैसे अलवारी विज्ञापन के अलावा अन्य विज्ञापन पर कर, विद्युत् के उपयोग और विक्रय पर कर आदि, को स्थानीय सस्थाओं के उपयोग के लिए सुरक्षित कर देने की सिफारिश की। १९५३ में नियुक्त कर जांच आयोग ने यह मत व्यक्त किया कि स्थानीय वित्त का ठोस आधार स्थानीय प्रत्यक्ष करारोपण ही हो सकता है। आयोग ने स्थानीय सस्थाओं को कर लगाने के सम्बन्ध में अधिकार प्रदान करने के लिए दो कसौटियाँ रखीं। (१) कर का स्थायित्व तथा (२) करारोपण और प्रशासन की क्षमता। आयोग ने राज्य सरकारों द्वारा ऋण और आर्थिक सहायता देने की भी सिफारिश की।

पश्चिमी देशों में नगरपालिकाओं के क्षेत्र के विस्तार—भूमि की स्थायी सम्पत्ति तथा औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र—में वृद्धि हो रही है और म्युनिसिपैलिटियाँ ट्राम्वे, पानी के कारखाने, गैस और बिजली के कारखाने, कब्रिस्तान, स्नानागार, मछली मारने के स्थान, जहाजों के ठहरने के स्थान, रोटी बनाने के स्थान, रंगमंच, सराय, जलपान-गृह, कारखाने, चक्की और दुग्धशालाएँ इत्यादि चला रही हैं। ये सब आर्थिक कार्य प्रभावशाली रूप से केवल सेवा ही नहीं हैं वरन् आय के अच्छे साधन भी हैं। भारत में स्थानीय वित्त के इस अंग पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है और यदि स्थानीय सस्थाएँ इन साधनों के प्रयोग की सम्भावनाओं पर अपनी छोटी आय को बढ़ाने तथा नागरिक जीवन की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ध्यान दें तो बहुत अच्छा हो।



१. देखिए, 'बम्बई स्वशासन कमेटी की रिपोर्ट' (१९४०)।

अध्याय २६

बेरोज़गारी

१. ग्रह्ययन का क्षेत्र—पाश्चात्य देशों में होने वाली औद्योगिक क्रान्ति के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न आर्थिक योजना में यत्किञ्चित् बेरोज़गारी (वृत्तिहीनता) अनिवार्य है। १९१४-१८ के युद्ध के उपरान्त वाली मन्दी से वृत्तिहीनता की एक अभूतपूर्व परिस्थिति उत्पन्न हो गई। तत्कालीन परिस्थिति की भयकरता और अभूतपूर्वता के बावजूद यह स्वीकार करना पड़ेगा कि पाश्चात्य देशों में इस प्रकार की परिस्थिति (औद्योगिक वृत्तिहीनता) बिलकुल नई नहीं थी।

भारतवर्ष में बेरोज़गारी से उत्पन्न समस्याओं के कुछ ऐसे पहलू हैं जो पाश्चात्य देशों के लिए बिलकुल नये प्रतीत होंगे। प्रथमतः देश की जनता का अधिकांश अपनी रोज़ी के लिए कृषि पर निर्भर है। हम पहले ही देख चुके हैं कि शिथिल मौसमों में ५ से लेकर ६ महीने तक बेकारी रहती है। इस प्रकार की अनिवार्य बेकारी के लिए पूरक उद्योगों की चर्चा हो चुकी है। किन्तु बेकारी का एक और भयकर पक्ष भी है। यह परिस्थिति पूर्णतः या आंशिक रूप से मानसून की विफलता का परिणाम होनी है, जिससे दुर्भिक्ष उत्पन्न हो जाता है। एक विस्तृत क्षेत्र में कृषिकार्य बन्द हो जाने से कृषि तथा उससे सम्बद्ध पूरक उद्योगों में लगे हुए श्रमिक बेकार हो जाते हैं। यह भारत में होने वाली बेकारी का सबसे भयकर पक्ष है।

उद्योगों तथा अन्य पेशों की ओर दृष्टिपात करने पर हम देखते हैं कि श्रमिक दो वर्गों में विभाजित हैं—एक तो हाथ से काम करने वाले श्रमिक, दूसरे मस्तिष्क से काम करने वाले बाबू लोग, अर्थात् तथाकथित पढ़े-लिखे मध्यवर्गीय लोग। जहाँ तक प्रथम वर्ग का प्रश्न है हमारी समस्या उतनी ही जटिल नहीं है। कारखानों के बन्द होने या उनके मजदूरों की छटनी (रिट्रैचमेंट) के कारण कितने ही साधारण और कुशल श्रमिक बेकार हो गए। किन्तु साधारण परिस्थितियों में यहाँ कुशल श्रमिकों की अधिकांशता और तज्जन्य बेकारी न होकर 'औद्योगिक श्रम' की कमी का ही अनुभव किया जाता है। इसके अनिरीक्त यदि यहाँ वृत्तिहीनता आनी भी है तो उसका रूप उतना भयकर नहीं होता जितना की पाश्चात्य देशों में। कारण यह है कि बहुत-से औद्योगिक श्रमिक खेती से भी सम्बद्ध होते हैं। प्रायः कारखानों का काम केवल सहायक स्थान का अधिकारी माना जाता है, जो धनुष की दूसरी प्रत्यक्षा की तरह कृषि के बेकार और शिथिल मौसम में काम देता है। अनएव भारत की वृत्तिहीनता पाश्चात्य वृत्तिहीनता से न केवल आकार में भिन्न होती है वरन् सरकार के लिए तज्जन्य समस्याओं का रूप भी भिन्न होता है।

संगठित उद्योगों की वृत्तिहीनता से भिन्न यत्किंचित् बेकारी कुटीर-श्रमिकों में भी पाई जाती है। भारत में 'आर्थिक-संक्रमण' वाले अध्याय तथा कुटीर-उद्योगों की स्थिति के विवरण में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार भिन्न-भिन्न वर्ग के लोग आर्थिक संक्रमण से प्रभावित हुए। इस विवरण में ही हमें अपनी रोजी खो देने और कोई उपयुक्त रोजी न मिलने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों और दुखों का भी कुछ अनुमान मिल गया था।

एक और प्रकार की वृत्तिहीनता अभी हाल में ही विकसित होने लगी है। यह है मध्यवर्गीयों की वृत्तिहीनता। इससे वे लोग प्रभावित होते हैं जो कि एक स्तर तक शिक्षा पा चुके हैं और अपनी जीविका के लिए बाबूगोरी या क्लर्कों पर निर्भर रहते हैं। हाल में यह समस्या प्रधान स्थान ग्रहण करने लगी थी।

ग्रामीण वृत्तिहीनता : दुर्भिक्ष का वर्तमान रूप और उसका उपचार

२. दुर्भिक्ष का उत्तरदायित्व—देश की राजनीतिक जाति के साथ-साथ बार-बार दुर्भिक्षों के पड़ने के कारण इन दैवी आपत्तियों को एक प्रकार की प्रमुखता मिल गई जो कि अन्यथा अप्राप्य होती।

१८६७ के विशेष आयोग ने दुर्भिक्ष की परिभाषा करते हुए बतलाया कि जनता के बड़े समूह का भूख की यातना सहना दुर्भिक्ष है। लेकिन भारत के इतिहास का अध्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि दो प्रधान कारणों में शब्द के इस अर्थ में परिवर्तन हो गया है। एक तो यातायात एवं परिवहन के साधनों में सुधार होने के कारण एक भाग के दुर्भिक्ष को दूसरे भाग की बहुलता से सहायता पहुँचाई जा सकती है। दूसरे, प्रशासन में भी दुर्भिक्षों का सामना करने की पद्धति में प्रगति हुई है। अतः-एव वर्तमान दुर्भिक्ष खाद्य दुर्भिक्ष न होकर द्रव्य-दुर्भिक्ष है। सरकार के सामने समस्या है कि समुचित रूप में मजदूरी और काम की व्यवस्था करे।

द्रव्य दुर्भिक्ष या वृत्ति-विस्थापन के मुख्य कारण जब तक दूर नहीं किये जायेंगे, ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हो सकेगी। ये कारण हैं—(१) जनता का कृषि पर अत्यधिक अवलम्बन—कृषि एक ऐसा पेशा है जो अनिश्चित वृष्टि पर निर्भर है, (२) पुराने उद्योगों का विनाश तथा कितने ही उद्योगों की अनुपस्थिति; (३) जनता का ऋण में डूबा होना आदि। भारतीय जनता किसी प्रकार अपनी आजीविका प्राप्त करती है और उसके पास कोई सुरक्षित धनराशि नहीं रहती जिस पर वह कमी और अकाल के समय आश्रित रह सके। जनता की आर्थिक शक्ति को सुदृढ़ करने के तरीकों में अनेक बातें शामिल हैं, जैसे जनता के जीवन स्तर को बढ़ाना और उसकी शक्ति को कायम रखना, सुरक्षा-कार्य—मिर्चाई की नहरें, सड़कों का निर्माण, कुओं की भरभरत इत्यादि; साधारण प्रशासन में सुधार, विशेष रूप से माल-प्रशासन के स्थगन और छूट की व्यवस्था; सुविचारित और उदार बन-नीति;

१. देखिए, खण्ड १, अध्याय ५।

२. देखिए, अध्याय २, तैवरान ३६-४६।

कृषि-महाविद्यालय, अनुसन्धान तथा प्रयोग-केन्द्रों द्वारा सुधार; सरकारी आन्दोलन का पूरा-पूरा उपयोग, बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास और छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन, संक्षेप में, सब पहलुओं में आर्थिक आयोजन।

हर्ष का विषय है कि देश में आर्थिक आयोजन १९५१-५२ से चल रहा है और उसके द्वारा वृत्तिहीनता की समस्या को हल करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। द्वितीय कृषि श्रम जांच (१९५६-५७) के अनुसार १९५०-५१ में ग्रामीण बेकारों की संख्या २८ लाख थी। योजना आयोग के अनुसार १९५६ में ५३ लाख ग्रामीण बेकार थे। कार्याङ्कन समूह (प्रोग्राम एवेल्यूएशन आर्गनाइजेशन) की प्राथमिकतम रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण ३० प्रतिशत मानव दिन (मैन डे) बेकार रहते हैं। अतएव तृतीय योजना में इस समस्या को हल करने के लिए पांच प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तावित किये गए हैं :

(१) अकुशल तथा अर्धकुशल श्रम की अपेक्षा रखने वाली राज्‍यिय तथा स्थानीय संस्थाओं की योजनाएँ,

(२) विधान द्वारा निर्धारित ढग से जाति या समूह द्वारा लिये गए कार्य,

(३) वे विकास-कार्य जिनमें स्थानीय जनता श्रम देती है तथा सरकार कुछ सहायता देती है,

(४) वे योजनाएँ जो गाँवों की प्रतिफलान्तरक सम्पत्ति के निर्माण में सहायक हों, तथा

(५) जिन क्षेत्रों में बेकारी अत्यधिक हो वहाँ पूरक योजनाएँ चालू की जाएँ।

इन योजनाओं में से ऐसा अनुमान है, योजना के प्रथम वर्ष में १ लाख व्यक्तियों को, द्वितीय वर्ष में ४-५ लाख व्यक्तियों को, तृतीय वर्ष में १० लाख व्यक्तियों को तथा अन्तिम वर्ष में २५ लाख व्यक्तियों को रोज़ी मिलेगी। उपर्युक्त आधार पर ग्रामीण जन शक्ति के उपयोग के लिए ३ / अग्रगामी योजनाएँ प्रारम्भ की गई हैं। मार्च १९६२ तक प्रत्येक योजना के लिए २ लाख रु० निर्धारित किया गया है। प्रारम्भ की गई अग्रगामी योजनाओं में विचार, वनरोपण, सघार-सुधार आदि हैं।

मध्यवर्गीय बेरोजगारी

३. समस्या का विस्तार क्षेत्र—यद्यपि सभी साधारण तौर पर 'शिक्षित' और मध्यवर्गीय शब्द का प्रयोग करते हैं, किन्तु शिक्षित और अशिक्षित के बीच कोई निश्चिन्त रेखा नहीं खींची जा सकती, न तो मध्यवर्ग के उच्चतर और निम्नतर स्तरों को ही अलग किया जा सकता है। साधारणतया 'शिक्षित मध्यवर्ग' में ऐसे लोग आते हैं जो इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति में नहीं हैं कि अपनी आय में अच्छी तरह अपना जीवन बिता सकें, जो कि शारीरिक श्रम नहीं करते तथा जिन्हें किसी-न किसी रूप में माध्यमिक या उच्चतर शिक्षा मिली होती है। कमी-कमी वनविद्युलर और एग्लो वनविद्युलर कोर्स पूरा करने वाले लोगों को भी इसमें शामिल किया जाता है।

४ मध्यवर्गीय बेरोजगारी की समस्या की गम्भीरता और प्रसार—मध्यवर्गीय वृत्ति-हीनता ने इधर हाल में भयकर आकार ग्रहण कर लिया है।^१ कुछ समय से जनता का ध्यान इस ओर गया है। सरकारी तथा गैर-सरकारी और अर्द्ध-सरकारी सस्थाओं, जैसे विश्वविद्यालयों, ने इसमें रुचि प्रदर्शित की है।^२ १९२४ और २८ के बीच विशिष्ट रूप से आयुक्त समितियों द्वारा कितनी ही गवेषणाएँ की गई हैं। ये गवेषणाएँ एव प्रयोग बंगाल, मद्रास, पंजाब और बम्बई-जैसे प्रान्तों एव ट्रावनकोर-जैसी रियासतों में किये गए हैं। सबसे हाल में नियुक्त होने वाली समितियों में युक्त प्रान्त (सर तेजबहादुर सप्रू की अध्यक्षता में) की और बिहार की समितियों का नाम लिया जा सकता है।^३

इन समितियों की रिपोर्टें से यह स्पष्ट हो गया है कि मध्यवर्गीय वृत्तिहीनता अखिल-भारतीय प्रकार की है।^४ मद्रास समिति ने बताया कि रोजी खोजने वाले शिक्षित व्यक्तियों और रोजगार का अनुपात २ : १ है। स्कूल और कॉलेजों की वार्षिक उत्पत्ति और वर्ष में होने वाली रथान रिक्तता की गणना के अनुसार वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वृत्तिहीनता की सख्या वस्तुतः दुखद थी। १९२७ की पंजाब समिति भी इसी प्रकार की गणना के उपरान्त इस नतीजे पर पहुँची। जबकि अंग्रेजी वनविद्यालय स्कूलों की उत्पत्ति या उत्पादन ५ वर्ष में (१९२२-२७) बढ़कर दूना हो गया है, इसके विपरीत रोजगार में ऐसी कोई वृद्धि नहीं हुई है—न तो सरकारी नौकरी में और न व्यावसायिक क्षेत्र में ही।

इस प्रकार की वृत्तिहीनता की भयकरता को हम पूर्णतया समझ नहीं पाते। इससे वृत्तिहीन व्यक्ति का कष्ट तो पहुँचता ही है, साथ ही एक प्रकार का नैतिक पतन होता है जो साधारण रूप से समाज को ग्रस्त कर लेता है और पीढ़ी दर-पीढ़ी बढ़ता ही जाता है। इस प्रकार के असन्तुष्ट नवयुवकों का अधिक सख्या में बेकार होना देश की राजनीतिक स्थिरता के लिए भी हानिकारक और भयकर है। क्रान्तिकारी समाजवाद या साम्यवाद उन युवकों में बड़ी ही शीघ्रता से जड़ जमा लेता है, जिनके दिल में वस्तुस्थिति के खिलाफ एक प्रकार का विरोधी भाव पहले से ही घर कर चुका होता है।

५ विशेष रूप से प्रभावित वर्ग—शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षितों में अप्रशिक्षितों की अपेक्षा कम बेकारी थी। कानूनी पेशे में बहुमत इस पक्ष में था कि यह जरूरत से ज्यादा

१. द्वितीय महायुद्ध ने वृत्ति के अनेक द्वार खोल दिए और कुछ समय के लिए भारत वृत्तिहीनता समाप्त प्राय हो गई। भारत सरकार के ४८ मन्त्रालय के वृत्ति विनिर्देश, जोकि पहले पुराने नौकरी वालों और छूटे लोगों को अमरीकानों के लिए काम करते थे, अब सबके लिए खोल दिये गए हैं।

२. १९३० में हुए विश्वविद्यालय सम्मेलन ने इस प्रश्न पर विचार किया, लेकिन वे इसके आगे कोई सुझाव नहीं रख सके कि विश्वविद्यालय अपने स्नातकों की वृत्तिहीनता का पता लगायें।

३. बम्बई के अमालय ने १९३८ में विश्वविद्यालय के स्नातकों की वृत्तिहीनता की जाँच फिर से प्रारम्भ की।

४. १९३७ की नवें उद्योग सम्मेलन की बुलेटिनों में भारत के विभिन्न प्रान्तों और रियासतों की मध्यवर्गीय वृत्तिहीनता की परिस्थिति की समीक्षा और उसे दूर करने के लिए काम में लाये गए या विचारत व्यक्तियों का विवरण प्राप्त होगा। 'बुलेटिन ऑफ इन्डियन इण्डस्ट्रीज एण्ड लेबर', न० ६५।

भर चुका है। इसी प्रकार औपघि पेशे के लोग बाजारो, विशेषकर बड़े शहरो, में लो भरे पडे हैं, जबकि छोटे-छोटे गाँवो में इनकी सख्या अत्यन्त कम है, क्योंकि यहाँ पर जीवन की सुविधाएँ अपेक्षाकृत बहुत कम हैं और लोग औपघियो के लिए नियमित रूप से नकद फीस देने के आशी नहीं हैं। इन्जीनियरो की दशा कुछ ही अच्छी थी। रेलवे में रोजी खोजने वाले काफी बडी सख्या में थे, लेकिन प्रशिक्षित न होने के कारण नौकरी न पा सके। जहाँ तक बैंकिंग का प्रश्न है, जो लोग इस विषय में शिक्षा प्राप्त कर चुके थे वे बेदार न रहे, लेकिन जिन्हें प्रशिक्षा न प्राप्त थी वे नौकरी न पा सके।

वृत्ति विनिमयालय के सचालकालय के जन शक्ति विभाग ने १५ मई १९५७ को स्नातकीय बेकारो के सम्बन्ध में यह पाया कि इन प्रकार की बेकारी ग्रन्थ राज्यों की अपशा पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, बम्बई तथा दिल्ली में अधिक है। स्त्री-स्नातको में सबसे अधिक बेकारी केरल में थी। काम ढूँढने वाले बेवार स्नातको में ६३% पुरुष तथा ७% स्त्रियाँ थी। कला और विज्ञान की तुलना में वाणिज्य के स्नातको में बेकारी अधिक थी।

६ वृत्तिहीनता के कारण^१—(१) युद्धोत्तर आर्थिक मन्दी और छटनी—ग्रन्थ देशो की भाँति भारत में भी युद्धोत्तर आर्थिक मन्दी का प्रभाव पडा। बाबूगोरो और युद्ध के ग्रन्थ विभागो में वृत्ति प्राप्त लोग बडी सख्या में बाहर निकाल दिये गए। छटनी की कुल्हाडी के प्रहार सब दिशाओ में हुए और पुराने सस्थापन की यथास्थिति न रही। मध्यवर्ग बडो ही कठोर अग्निपरीक्षा से होकर निकला।

(२) शिक्षा-पद्धति के दोष—वृत्तिहीनता का दूसरा तथाकथित कारण देश की औद्योगिक प्रगति और देश में प्रचलित शिक्षा में सन्तुलन का अभाव है। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली केवल बलर्षी करने योग्य नवयुवक तैयार कर रही है और यह सरकारी नौकरी पान का केवल एक द्वार मात्र है। पजाब समिति के लिए प्रस्तुत की गई अपनी सूची में सर एण्डरसन ने यह स्वीकार किया कि प्रारम्भ से ही (वर्तमान शिक्षा-पद्धति) लडको को विदेशी परीक्षाओ के लिए तैयार करने के लिए बनाई गई थी, जिनका पास करना बहुते के लिए एक प्रकार का भ्रमजाल था। इसका उद्देश्य लडको को बाबूगोरो की शिक्षा देना था। अब बाबूगोरो का पेशा जन-सकुल हो उठा है। इसमें अब नौकरी खोजने वालो की भीड के लिए बहुत ही कम स्थान रह गया है। उन्होने मैट्रिकुलेट की परिभाषा, जिसे वह वृत्ति समस्या का मूल मानते थे, इस प्रकार की—“एक भ्रमणार्थी, जो विश्व में टहलता है, जिसे नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि वह नौकरी देने योग्य नहीं है।” भारत का साधारण शिक्षित व्यक्ति सर्वप्रथम जीविका के लिए सरकारी नौकरी की ओर झुकता है। उसके न

१. बंगाल समिति ने वृत्तिहीनता का एक प्रकार का वर्गीकरण करने का सुझाव रखा—ऐसे लोग, जो अपने किसी अपराध या दोष के बिना ही नौकरी न पाने वाले हों, ऐसे व्यक्ति जोकि ऐसी रोजी चाह रहे हैं जिसके लिए अनुपयुक्त है, उसका कारण बुधा वस्त्र के बाहर की बात मले हो हो। दक्षिण ‘बंगाल वृत्तिहीनता समिति की रिपोर्ट’, पैरा २।

मिलने पर अर्द्ध-सरकारी प्रकार की बलर्की, जैसे रेलवे, म्युनिसिपल बोर्ड और अन्य स्थानीय संस्थाएँ, जैसे पोर्ट-ट्रस्ट इत्यादि, की बलर्की बूढ़ता है। शिक्षा-पद्धति के विरुद्ध यह भी आरोप है कि यह लड़कों को अपने पतृक पेशों के लिए भी बेकार बना देती है, क्योंकि वे एक क्षण के लिए हाथ से काम करके अपनी जीविका कमाने की बात नहीं सोच सकते। वे पंचम श्रेणी का बलर्क होना पसन्द करेंगे, चाहे उन्हें उससे हाथ का काम करने से कम की ही आमदनी क्यों न हो। वे कृषि को भी हेय दृष्टि से देखने लगते हैं। इस प्रकार हाथ से काम न करने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। इसका कारण वर्तमान शिक्षा-प्रणाली का दूषित होना ही है जोकि अनुत्पादक होने के अतिरिक्त देश की मानसिक शक्ति को नष्ट कर देती है। किसान, हस्तकार्य करने वाले तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोग भी अपने बच्चों को सरकारी नौकरी के सालच में पढ़कर, स्कूलों और कॉलेजों में भेजने लगे हैं। इस प्रकार वे सामाजिक सीढ़ी के ऊँचे वाले डबों पर चढ़ रहे हैं। साहित्यिक एवं अर्द्ध साहित्यिक पेशों का यह आवर्षण, जोकि अपनी परिधि में उन वर्गों को भी सम्मिलित कर रहा है जिनके पास कोई भी विद्या की पृष्ठभूमि नहीं है, तथा इनसे प्रचलित वृत्तिहीनता और भी बढ़ रही है।

(३) सामाजिक कारण—कुछ सामाजिक कारण, जैसे जाति-प्रथा, शीघ्र विवाह, संयुक्त परिवार और सामुदायिक असमानताएँ, सब शान्त किन्तु सशक्त रूप से नवयुवकों की आर्थिक महत्त्वाकांक्षाओं और भाग्य को निर्धारित करने में क्रियाशील हैं।^१ उदाहरण के लिए जाति-प्रथा युवकों को कितने ही ऐसे घन्धे करने से रोक देती है, जोकि लाभदायक हैं किन्तु जो सामाजिक दृष्टि से निम्न स्तर के माने जाते हैं। शीघ्र विवाह के परिणामस्वरूप नवयुवकों पर शीघ्र ही जिम्मेदारी पड़ जाती है और प्रशिक्षण भी अवरूढ़ हो जाती है। संयुक्त परिवार प्रथा इस प्रकार के उत्तरदायित्व का भार हलवा कर देती है और कमजोर तथा असहाय को सहायता और सुरक्षा देकर आर्थिक पराश्रयता को जन्म देती है और वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा तथा प्रतिभा को समाप्त कर देती है। शिक्षित वर्ग में वृत्तिहीनता का एक कारण नवयुवकों में अपने घरदार से दूर जाकर अपने भाग्य-निर्माण की अनिच्छा भी है, जोकि संयुक्त परिवार-प्रथा की देन है। इसके विपरीत मद्रास समिति के मत में इस प्रकार की गतिहीनता अब धीरे-धीरे घट रही है और इसका वृत्तिहीनता पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वृत्तिहीनता मूलतः माँग से पूर्ति का अधिक होना ही है।^२

(४) आर्थिक पिछड़ापन—देश के आर्थिक अविश्वसनीयता का कारण औद्योगिक दृष्टि से देश का पिछड़ा होना है, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षित नवयुवकों को वृत्ति के मार्ग नहीं मिलते। क्लायत में सेना, नौसेना और सिविल सर्विसेज की छोड़कर इस समय देश में कुल १६,००० पेशे हैं। भारत में कुल मिलाकर ४० से भी कम हैं।^३ यह याद रखना चाहिए कि केवल व्यावहारिक शिक्षा देने और उसकी सुविधाएँ करने

१. देखिए, मद्रास की रिपोर्ट, पृ० १८, खण्ड १, अध्याय ४ में देखिए।

२. मद्रास रिपोर्ट, पृ० १८ और २७।

३. देखिए, ब्रावनकोर रिपोर्ट, पैरा ५८।

से ही परिस्थिति पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सकता। यह असदिग्ध है कि इससे देश की औद्योगिक प्रगति तीव्रतर हो जाएगी, लेकिन इससे औद्योगिक प्रगति का जन्म नहीं होगा, जब तक कि शिक्षित और प्रशिक्षित लोगों को खपा लेने वाले उद्योगों का विकास और प्रोत्साहन नहीं किया जाता। जैसा कि बंगाल-समिति का मत है—
“एक आदर्श सुसंतुलित विकास में आर्थिक प्रगति और टेकनिकल प्रशिक्षण का साथ-साथ विकास होगा, और एक-दूसरे को प्रोत्साहन देंगे। जब एक पीछे रहेगी तो दूसरी को भी रोकेगी और जब एक बढ़ेगी तो दूसरी को भी बढ़ाएगी।”

७ वृत्तिहीनता को दूर करने के उपचार : वृत्ति-भूरो—वृत्तिहीनता के अनेक कारण हैं इसलिए इसकी कोई एक रामबाण-औषधि नहीं हो सकती। पहले तो जो उपचार सामने रखे गए हैं उनके ऊपर दृष्टिपात कर लेना चाहिए। सरकार, यूनिवर्सिटी और वैयक्तिक संस्थाओं द्वारा चलाये गए वृत्ति-भूरो का मुभाव सामने रखा गया है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में नौकरी चाहने वालों और नौकरी देने वालों को एक-दूसरे के सम्पर्क में लाने के लिए वृत्ति बोर्ड स्थापित किये गए। इनसे अत्यन्त ही महत्वपूर्ण और लाभदायक काम होगा। यदि कुशलता से इनका प्रबन्ध किया गया तो जनता में एक प्रकार के विश्वास का संचार होगा।

जन-प्रवास (माइग्रेशन) भी वृत्तिहीनता को दूर करने का एक साधन माना गया है, किन्तु मध्यवर्गीय वृत्तिहीनता एक अखिल भारतीय प्रकार की है। इससे देश के अन्दर स्थानान्तरण सम्भव न होगा, इससे समस्या की सघनता का देश के सब भागों में समान रूप से वितरण हो जाएगा, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं। एक देश से दूसरे देश में जाने से भी समस्या का स्थायी निराकरण न हो सकेगा।^१

८. वृत्ति विनिमयालय (एम्प्लायमेंट एक्सचेंज)—द्वितीय विश्वयुद्ध में युद्ध की आवश्यकताओं हेतु अधिकारियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्र सेवा श्रमिक न्यायालय (नेशनल सर्विस लेबर ट्रिब्यूनल) स्थापित किये गए। तब से ये सघ सगठन दान्तिकाल में भी कुशल और अर्द्ध-कुशल व्यक्तियों की रजिस्ट्री और स्वेच्छा-स्थानान्तरणकाल के लिए प्रसारित और अनुकूल बनाये गए। १९४५ में युद्ध से निकाले गए श्रमिकों और सिपाहियों तथा विस्थापित और छुड़ाये गए पूर्व-सेवकों (एक्स-सर्विसमें) के पुनर्स्थापन और वृत्ति-दान के लिए वृत्ति पुनर्स्थापन के सामान्य सचालकालय (डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ रिसेटलमेण्ट एण्ड एम्प्लायमेण्ट) की स्थापना की गई। इधर हाल में वृत्ति विनिमयालयों का कार्यक्षेत्र सरणाधिकारों और साधारण रूप से औद्योगिक श्रमिकों से सम्बन्धित वृत्ति और पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त विकसित कर दिया गया है। सम्पूर्ण सगठन सचालक (डायरेक्ट्रेट-जनरल) की अधीनता में है, जिसमें तीन सचालनालय (डायरेक्ट्रेट) हैं—(१) वृत्ति-विनिमयालयों का सचालकालय, (२) प्रशिक्षण सचालकालय और (३) प्रसार सचालकालय। देश का विभाजन आठ भागों में किया गया है और जिनमें से प्रत्येक विभाग एक सचालक के अधीन है। देश में ५४ वृत्ति विनिमयालय

और २३ जिला वृत्ति कार्यालय हैं। केन्द्रीय वृत्ति विनियमालय का काम एक अन्तर्प्रान्तीय विकास गृह (विलियरिंग हाउस) का है। यह विभिन्न भागो के थ्रम की मांग और पूर्ति को व्यवस्थित करता है।

६ अन्य उपचार—जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि हर प्रकार और श्रेणी की वृत्ति-हीनता अन्तिम व्याख्या मे देश के आर्थिक अर्थविकास और पिछड़ेपन का प्रतिबिम्ब-मात्र है। अतएव जिस किसी भी साधन से देश का आर्थिक विकास होगा उससे देश की वृत्तिहीनता की समस्या का समाधान होगा। भौतिक समृद्धि से न केवल वृत्ति के नवीन पथों का उद्घाटन होगा, वरन् देश की समृद्धि के स्तर के उठ जाने से बकीलो, डॉक्टरो, अध्यापको इत्यादि की भी आवश्यकता बढ जाएगी। इसी प्रकार समृद्धि-तल के उठ जाने से प्रशासकीय सेवाओ मे भी प्रसार होगा और अन्त मे, सरकार द्वारा देश के आर्थिक पुनरुद्धार के किसी भी कार्य मे शिक्षित वर्ग मे से व्यक्ति अवश्य लिये जाएंगे।

मद्रास समिति का 'क्षेत्र-उपनिवेश' (फार्म कॉलोनीज) स्थापित करने का प्रस्ताव काफी आकर्षक था, किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से उसकी उपयोगिता सीमित थी। पहले तो पजाब और आसाम-जैसे प्रान्तो को छोडकर शिक्षित वृत्तिहीनो को देने के लिए काफी भूमि नहीं पाई जा सकती, चाहे इसके लिए ग्रामीण समाज और दलित-वर्ग के दावे को थोडी देर के लिए भुला भी दिया जाए। दूसरे, यदि यह पता चल गया कि सरकार शिक्षित वृत्तिहीनो के लिए भूमि देगी तो मध्य वर्ग के लोगो का अपने पुत्रो को स्कूल और कॉलिजो मे भेजने का आकर्षण अधिक बढ जाएगा।

पता ब वृत्तिहीनता जाँच समिति ने बहुमत ने यह सुझाव रखा कि वृत्तिहीनता को कम करने का एक तरीका यह होगा कि उच्चतर शिक्षा के लिए केवल पर्याप्त योग्यता और तीक्ष्ण बुद्धि वाले छात्रो को ही भेजा जाए। वे यदि गरीब हैं तो उन्हें सरकारी सहायता भी दी जाए या उन लोगो को भेजा जाए जो इसकी पूरी कीमत दे सकें (पैरा १६)। हम यह ठीक नहीं समझते कि उच्चशिक्षा को खरचीली बनाने के लिए कुछ भी किया जाए या इसका क्षेत्र सकुचित किया जाए, हाँकि हम यह स्वीकार करते हैं कि छात्रो के अभिभावको को इस बात का पता लग जाए कि वर्तमान काल मे सरकारी नौकरियो के लिए व्यक्तियो की मांग की अपेक्षा पूर्ति बहुत ही अधिक है, और यह कि उन्हें अपने बच्चो के लिए अन्य प्रकार के पेशो की बात सोचनी चाहिए। सभू समिति भी किसी भी कृत्रिम नियम द्वारा विश्वविद्यालयो मे प्रवेश को बाधित करने के खिलाफ थी। ट्रावनकोर समिति के इस कथन मे अधिक सार है कि हर प्रकार की सरकारी नौकरी को प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होना चाहिए। परीक्षाओ को कठोर कर देने और मानदण्ड को ऊँचा उठा देने से कितने ही उम्मीदवार, जो अयोग्य होंगे, छँट जाएँगे और इस प्रकार की शिक्षा मे होने वाली शक्ति तथा धन का अपव्यय भी न होगा। जो प्रतियोगिता-परीक्षा मे फेल होंगे वे जान जाएँगे कि उनके लिए सरकारी नौकरी मिलना सम्भव नहीं और वे अनिश्चित काल तक इस आशा मे तो नहीं रहेंगे कि शायद कभी उन्हें सरकारी नौकरी मिल ही जाए। इससे

शिक्षा का स्तर भी ऊँचा उठेगा और सेवा के लिए अधिक उपयुक्त व्यक्ति मिलेंगे ।

१०. सप्रू (वृत्तिहीनता) समिति—यहाँ हम सप्रू-समिति के कुछ महत्वपूर्ण सुभावों की ओर संकेत करना चाहेंगे । यह समिति युक्तप्रान्त की वृत्तिहीनता की जाँच के लिए नियुक्त की गई थी, किन्तु इसके सुभावों को समस्त भारत पर लागू किया जा सकता है । इन्हें हम इस प्रकार विभाजित करते हैं—(क) वे, जो कि शिक्षित व्यक्तियों की माँग बढ़ाने से सम्बन्ध रखते हैं, (ख) वे, जो पूँति की अधिकता को कम करने से सम्बन्ध रखते हैं; (ग) वे, जिनका उद्देश्य वास्तविक माँग और पूँति का समुचित सन्तुलन स्थापित करना है ।

(१) जिला और नगरपालिकाओं को बाध्य करना चाहिए कि वे सड़कों और इमारतों को अपनी स्थिति में रखने के लिए कुशल और योग्य इंजीनियर तथा निरीक्षकों को नियुक्त करें । यदि सरकार चाहे तो जन-श्रीपथि-सहायता के प्रसार द्वारा सुयोग्य व्यक्तियों को रोजी दे सकती है । जनता के अस्पतालों में अधिक डॉक्टरों की नियुक्ति—देशी दवाओं और जड़ी-बूटियों की प्रभविष्णुता की छानबीन के लिए भी डॉक्टरों की नियुक्ति कर सकती है । नगरपालिकाओं तथा जिला-बोर्डों को चाहिए कि वे जनता के स्वास्थ्य और स्वच्छता की देख-रेख के लिए योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करें । कानून के पेशे में होने वाली भीड़ का निराकरण करने के लिए यह आवश्यक होगा कि लोग कानून की विशेष शाखाओं में विशिष्टता प्राप्त करे । उदाहरण के लिए, कुछ लोग केवल दस्तावेज की रूपरेखा तैयार करने में विशेष योग्यता प्राप्त करें और कुछ मुकदमों की बहस में, इत्यादि । ५५ साल पर सेवा से विरत करने के नियम का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए, ताकि नवयुवकों को तुरन्त अवसर प्राप्त हो सके । बड़े और छोटे पैमाने के उद्योगों को साथ-ही-साथ प्रेरणा देनी चाहिए, ताकि वे बड़ी सहायता में नवयुवकों को खपा सकें । प्रतिवार्य-प्रारम्भिक-शिक्षा प्रचलित करने का जोर-शोर से प्रयास किया जाना चाहिए ।

(२) हाई स्कूल-परीक्षा में दो प्रकार के प्रमाण-पत्र प्राप्त होने चाहिए । एक तो शिक्षा की समाप्ति का होना चाहिए और उन छात्रों को सहायक सरकारी नौकरियों में स्थान मिलने की योग्यता के प्रमाण-पत्रस्वरूप होना चाहिए, जिससे अवसर पड़ने पर औद्योगिक, कृषि और अन्य व्यावसायिक स्कूलों में भी प्रवेश पा सकें । दूसरा प्रमाण-पत्र कला और विज्ञान के महाविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए होना चाहिए ।

(३) व्यावहारिक शिक्षा के लिए मिलने वाली सुविधाएँ भी बढ़ानी चाहिए । समग्र रूप से और विशेष रूप से प्रारम्भिक कक्षाओं में—शिक्षा की प्रवृत्ति व्यावहारिक और ग्रामीण होनी चाहिए । दवा-दारु की शिक्षा प्राप्त करने और डॉक्टरों को पेशा अस्तित्व करने वालों को चाहिए कि सरकार उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में बसने की सुविधा और सहायता दे । इस प्रकार बड़े नगरों से डॉक्टरों की भीड़ भी कम हो जाएगी । फार्मसी, डेंटिस्ट्री (दान की विद्या), हिसाब-किताब, निर्माण और वास्तु-कला, पुस्तकालय की शिक्षा, बीमा-कार्य और अखबारनवीसी-जैसे पेशे का विकास करना चाहिए । ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि डिप्लोमा-प्राप्त व्यक्ति तथा कृषि-स्नातक

वैज्ञानिक कृषि की जीविका के साधन के रूप में अपनाएँ। उनके लिए वैज्ञानिक पशु-पालन में भी खपत होगी। यह भी कोशिश करनी चाहिए कि योग्य शिक्षित व्यक्ति नौकरी के लिए व्यवसाय गृहों के सम्पर्क में आ सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न खण्डों में पेशों की रहनुमाई के लिए प्राधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि समन्वित जीवन-पथों की सूचना दिया करें और इस प्रकार की व्यवस्था संगठित करके अभिभावकों को उनके लड़कों की मानसिक और शारीरिक कुशलता की परीक्षा करके उनके आगे की गति के विषय में सलाह दें। माध्यमिक पाठशालाओं को चाहिए कि वे अध्ययन के और भी अधिक विविध पाठ्य क्रम निर्धारित करें। विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक और पेशों की शिक्षा पर अधिक जोर दें। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के नियुक्ति सच (अपॉइन्टमेन्ट्स बोर्ड्स) के ढंग का नियुक्ति सच यहाँ भी बनाया जाना चाहिए, जिसमें यूनिवर्सिटी के उप-कुलपति, कुछ विभागाध्यक्ष (उदाहरण के लिए शिक्षा, उद्योग और कृषि) तथा कुछ जनता के व्यक्ति और कुछ यूरोपीय तथा भारतीय व्यापारी हों। इसी प्रकार माध्यमिक पाठशालाओं के उत्पादनों की समस्या को सुलभाने के लिए भी सचों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इन बोर्डों को चाहिए कि वे विश्वविद्यालयों के स्नातक तथा स्कूल और कॉलेजों के छात्रों की वृत्ति की समस्या सुलभाएँ।

तृतीय योजना में मध्यवर्गीय बेकारी दूर करने के सम्बन्ध में कहा गया है कि उद्योगीकरण, विकास की योजनाओं तथा ग्रामीण जन-शक्ति के उपयोग के लिए प्रारम्भिक कार्यक्रम स्वतः शिक्षितों को रोजगार देंगे। वृत्ति विनिमयालय में दर्ज व्यक्तियों के सम्बन्ध में यह अनुमान कर लेने पर कि इनका प्रतिशत निश्चित रहा है, यह कहा जा सकता है कि १० लाख शिक्षित बेकार योजना के प्रारम्भ में होंगे और ३५ लाख नए शिक्षित बेकार योजना प्रवृत्ति में काम ढँढेंगे। अतएव यह सुभाव रखा गया है कि शिक्षा में इस प्रकार के परिवर्तन किए जाएँ ताकि भविष्य के उपलब्ध कामों के लिए व्यक्ति मिल सकें। प्राविधिक शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है तथा नई शिक्षा-संस्थाएँ खोली जा रही हैं। पेशों के सम्बन्ध में पथ-प्रदर्शन (वोकेशनल गाइड्स) करने की योजनाएँ भी पिछले पाँच वर्षों में विकसित की गई हैं। निम्न भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीण कार्यक्रमों में ही शिक्षितों को रोजगार मिलने की सम्भावना है। अतएव यह सुभाव रखा गया है कि शिक्षितों को विशेष कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाए। इस दिशा में शिक्षा-पद्धति का पुनर्गठन तथा पेशेवर और प्राविधिक शिक्षा की सुविधाओं का विकास सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात है।

बेरोजगारी की समस्या पर उचित ढंग से विचार करने के लिए सभी प्रकार की बेरोजगारी पर दीर्घकालिक दृष्टि से विचार करना आवश्यक है। आगामी १५ वर्षों में श्रम शक्ति की वृद्धि ७०० लाख के लगभग होगी—तृतीय योजना में १७० लाख, चतुर्थ योजना में २३० लाख तथा पाँचवी योजना में ३०० लाख। पिछली दो योजनाओं का अनुभव यह है कि रोजगार के अवसर अधिकांशतः गैर कृषीय क्षेत्रों में बढ़ेंगे। इस अनुमान पर कि यह प्रवृत्ति भविष्य में बनी रहेगी तथा आगामी १५ वर्षों में ३

श्रम शक्ति कृषि के बाहर काम पाएगी, यह सम्भव हो सकेगा कि १९७६ तक कृषि पर निर्भर श्रम-शक्ति का अनुमान घटकर ६० प्रतिशत हो जाए।

११ बेरोजगारी तथा योजनाएँ—(क) पहली पंचवर्षीय योजना—यह योजना एमे समय म बनी थी जबकि विभाजन तथा युद्ध के पश्चात् स्थिति के कारण बेरोजगारी के बारे में ठीक प्रकार से कुछ नहीं कहा जा सकता था। इसलिए पहली योजना में बेरोजगारी का अघ्याय एक प्रकार से व्यर्थ-सा था। यह ठीक है कि बाद में १९५३ के अन्न तक योजना आयोग ने बेरोजगारी बचकर की उन्नति के लिए ११ शाखाओं वाना प्रोग्राम बनाया। इनके बाद भी पहली योजना में कुछ अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई और प्रत्यक्ष बेरोजगारी कुल ४५ मिलियन तक ही रह गई।

(ख) दूसरी योजना—इस योजना के आरम्भ में अपूर्ण बेरोजगारी ५३ मिलियन लोगों में थी और यह आशा प्रकट की गई कि योजना के दौरान में १० मिलियन और लोगों की सामर्थ्य-शक्ति और बढ़ जाएगी। दूसरी योजना में बेरोजगारी का लक्ष्य १० मिलियन रखा गया और यह सोचा गया कि ५३ मिलियन लोगों की सामर्थ्य अगली योजनाओं में ठीक की जाएगी। परन्तु दुर्भाग्य से दूसरी योजना में बेरोजगारी (खेती को छोड़कर) कुल ६५ मिलियन लोगों में बढ़ी। इस प्रकार बेरोजगारी की सामर्थ्य तीसरी योजना के आरम्भ होने के समय ६ मिलियन के लगभग थी। इससे यह प्रतीत होता है कि देश में बेरोजगार लोगों के बढ़ने के साथ-साथ बेरोजगार तथा बेरोजगारी ढूँढने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती रही है।

(ग) तीसरी योजना—योजना आयोग के हिसाब के अनुसार तीसरी योजना में नये बेरोजगार ढूँढने वालों की संख्या १७ मिलियन और हो जाएगी और पिछले ६ मिलियन बेरोजगारों को मिलाकर कुल बेरोजगारों की संख्या इस प्रकार बढ़कर २६ मिलियन हो जाएगी। परन्तु तीसरी योजना में निवेश तथा इसके स्तर को देखते हुए १४ मिलियन लोगों को नौकरियाँ मिलने की सम्भावना थी (३५ मिलियन खेती में, १०५ मिलियन बाकी क्षेत्रों में)। दुर्भाग्य से तीसरी योजना के मध्य मूल्यांकन अनुसार खेती के बाहर ५ मिलियन ४७ प्रतिशत लोगों को नौकरियाँ मिलीं।

(घ) चौथी योजना—वर्तमान स्थिति को देखते हुए चौथी पंचवर्षीय योजना में नौकरियाँ ढूँढने वालों की संख्या ३५ मिलियन तक बढ़ जाएगी, जिसमें २३ मिलियन नई नौकरियाँ ढूँढने वाले होंगे और १२ मिलियन पुराने ही जो तीसरी योजना में प्राप्त न कर पाए। परन्तु चौथी योजना में २१,५००—२२,५०० करोड़ रुपया खर्च करके अधिक से अधिक १५-१६ मिलियन लोगों को और नौकरियाँ (खेती से बाहर) मिल सकती हैं। इससे यह स्पष्ट है कि अगर चौथी योजना में कम से-कम २५ मिलियन लोगों को नौकरियाँ न मिली तो पाँचवी तथा अन्य योजनाओं में बेरोजगारी की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। ऐसे संकटकाल को दूर रखने के लिए सरकार को अपनी बेरोजगारी, उत्पादन तथा राजकोषीय नीतियों में परिवर्तन लाने होंगे।

भारतीय पंचवर्षीय योजनाएँ

१. भूमिका—हम आज उस युग में से गुजर रहे हैं जबकि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सभी दिशाओं से राष्ट्र की आर्थिक उन्नति के लिए योजनाओं का वर्णन हो रहा है। विशेष रूप से जब से रूस ने योजना के पथ पर अग्रसर होकर अपने-आपको विश्व के बड़े देशों में ऊँचा स्थान प्राप्त कर लिया है, तब से योजना के मार्ग को और भी उन्नत स्थान मिला है। वैसे तो भारत में काफी समय से योजना की आवश्यकता को महसूस किया गया था। १९३१ में सर आर्थर साह्लर और बाद में १९३५ में डा० बाऊले तथा प्रोफेसर डी० एच० रॉबर्टसन ने योजना आरम्भ करने का विचार रखा। देश के एक सर्वश्रेष्ठ इञ्जीनियर सर विश्वेश्वरैया ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था 'प्लैंड इकॉनमी ऑफ इण्डिया' (Planned Economy of India)। उसके पश्चात् १९३८ में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने, जोकि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 'राष्ट्र योजना समिति' देश की आर्थिक उन्नति के लिए बनाई। परन्तु दूसरे महायुद्ध के छिड़ जाने तथा कांग्रेसी नेताओं के जेलों में भेज देने के कारण इस बमेटी के कार्य में विघ्न पड़ गया।

वैसे तो कई कागजी योजनाएँ बनी, उदाहरणतया 'बॉम्बे प्लॉन' (Bombay Plan), 'पीपल्स प्लॉन' (Peoples Plan), गांधियन प्लॉन (Gandhian Plan), तथा पोस्ट वार रिकन्सट्रक्शन एण्ड प्लॉनिंग (Post-war Reconstruction and Planning)। परन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात् सुचारु रूप से योजना के महत्त्व को समझते हुए भारत सरकार ने मार्च १९५० में (राष्ट्र के सभी स्रोतों के ठीक उपयोग और उसके उत्पादन के समतुलित वितरण के लिए) योजना आयोग बनाया। काफी सोच-विचार के बाद पहली पंचवर्षीय योजना सदन के सम्मुख दिसम्बर, १९५२ में रखी गई। वैसे तो पहली योजना को १९५१ से ही चालू समझा गया।

२. योजनाओं के लक्ष्य—भारतीय योजनाओं के कई लक्ष्य हैं। पहली योजना में विशेष लक्ष्य को सामने रखते हुए, इसके अन्तर्गत वह एक नया उन्नति का मार्ग बनायेगी, जिससे जनता का रहन सहन ऊँचा हो सकेगा और अपने जीवन को उज्ज्वल बनाने के लिए अच्छे अवसर मिलेंगे। योजना का मतलब न केवल साधनों को उन्नत करना होगा, बल्कि मानवता की कार्य-शक्ति और सस्था के ढाँचे में परिवर्तन लाया जाएगा। दूसरा, लम्बे समय के लक्ष्य थे कि राष्ट्रीय आय तथा प्रतिव्यक्ति आय को दुगुना किया जाए। यह आशा प्रकट की गई कि १९७५-७६ तक ६ प्रतिशत के लगभग वृद्धि की दर हो ताकि राष्ट्रीय आय (१९६०-६१ की कीमतों को सामने रखते हुए) १९६०-६१ में

१५,५०० करोड़ से बढ़कर राष्ट्रीय आय १९७५-७६ में ३४,००० करोड़ रुपये हो जाए और प्रति व्यक्ति आय इस समय में ३१ प्रतिशत बढ़कर ३३० रुपये में ५३० रुपये हो जाए। तीसरा, ४६ करोड़ लोगों के लिए रोजगार (खेती को छोड़कर) पैदा किये जाएँ, जिससे जनसंख्या का दबाव खेती पर ७० प्रतिशत से घटकर ६० प्रतिशत हो जाए। चौथा, चौदह वर्ष तक के बालकों को विधान के अनुसार व्यापक शिक्षा दी जाए। पाँचवाँ, कुल निवेश दर दूसरी योजना के अन्त तक ११ से १४ प्रतिशत तीसरी में और १८ प्रतिशत चौथी योजना के सम्पूर्ण होने तक। कुल निवेश का बड़ा भाग घरेलू जमा से वित्त का रूप ले और इस प्रकार शुद्ध जमा—आय अनुपात १९६०-६१ में ८.५ प्रतिशत से बढ़कर ११.५ प्रतिशत १९६६ में और १६ प्रतिशत १९७१ के अन्त तक हो जाए। छठा लक्ष्य यह है कि १० वर्षों में हम विदेशी सहायता को काफी हद तक कम कर लें और यह कार्य निर्यात की अच्छी नीतियों द्वारा ही हो सकता है।

३. पहली दो योजनाएँ—पहली योजना (१९५१-५६) न खेती, सिंचाई, शक्ति और यातायात के साधनों पर जोर देते हुए भविष्य में आर्थिक एवं औद्योगिक उन्नति का आधार बनाने की चेष्टा की और कुछ बुनियादी नीतियों में परिवर्तन किये। दूसरी योजना (१९५६-६१) में इन नीतियों को और अच्छा रूप दिया गया और राष्ट्र को समाजवादी आधार पर रखने की चेष्टा की गई। इस योजना में मौलिक तथा बड़े उद्योगों पर जोर दिया गया और यह आशा की गई कि राष्ट्र की आर्थिक उन्नति के लिए सरकारी क्षेत्र का बहुत महत्त्व होगा।

पहली दो योजनाओं में कुल निवेश १०,११० करोड़ रुपया—५२१० करोड़ रुपया सरकारी क्षेत्र में और ४९ करोड़ रुपया निजी क्षेत्र में था। इस प्रकार वार्षिक निवेश दर १०० करोड़ रुपये १९५१ से बढ़कर १६०० करोड़ रुपये १९६१ तक हो गई। पहली दो योजनाओं में खेती तथा सिंचाई पर २१ तथा २० प्रतिशत खर्च किया गया। दूसरी योजना में औद्योगिक उन्नति पर जोर देने के कारण उद्योग तथा खनिज पर ४ प्रतिशत प्रथम योजना से बढ़ाकर दूसरी योजना में २० प्रतिशत कर दिया। पहली तथा दूसरी योजना में शक्ति की उन्नति पर १२ तथा १० प्रतिशत दूसरी योजना में खर्चना निर्धारित हुआ। दोनों योजनाओं में ट्रांसपोर्ट और संचार पर एक ही जैसा जोर देते हुए लगभग २८ प्रतिशत धन व्यय हुआ। सेवा समितियों इत्यादि पर पहली पंचवर्षीय योजना में २३ प्रतिशत तथा दूसरी में १८ प्रतिशत धन व्यय हुआ। प्रथम योजना में कुल सरकारी व्यय (Public Sector) का ६० प्रतिशत भाग घरेलू साधनों से प्राप्त हुआ और दूसरी योजना में ४,६०० करोड़ का ७६ प्रतिशत घरेलू साधनों से तथा शेष विदेशों से प्राप्त हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना में विशेष तौर पर टैक्सों पर जोर दिया गया और कई नये प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर लगाये गए और जा रिक्त साधनों में मिला उसे या ता घाटे के वजह (Deficit Financing) से या विदेशी सहायता से पूर्ण किया गया। दूसरी योजना में घाट का बजट ६४८ करोड़ रुपये था।

पहली दो योजनाओं में राष्ट्रीय आय ४२ प्रतिशत बढ़ी, परन्तु प्रति व्यक्ति आय तेजी से जनसंख्या के बढ़ने के कारण केवल १६ प्रतिशत ही बढ़ सकी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस समय में औद्योगिक उत्पादन ६२ प्रतिशत बढ़ गया और विशेषतया दूसरी योजना में कई क्षेत्रों में उन्नति हुई और एक प्रकार का देश में औद्योगिक आन्दोलन चालू हो गया। औद्योगिक उन्नति और राष्ट्रीय आय के अधिक न बढ़ने के ये निम्नलिखित कारण हैं—

(१) खेती-उत्पादन दर न केवल अस्थायी रही बल्कि इसके साथ-साथ औद्योगिक और निर्यात को बढ़ाने में असफल थी।

(२) विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण कई शक्ति-साधनों को बढ़ाने वाले प्रोजेक्टों और रासायनिक प्रोजेक्टों को चलाने में बड़ी देर लगी।

(३) इन दस वर्षों में निर्यात स्थिर रहा और उतना न बढ़ पाया जितनी आशा थी।

(४) औद्योगिक तथा खेती के क्षेत्रों में प्रशासन के ठीक न होने और योजना के कार्यों को ठीक प्रकार से कार्यान्वित न होने के कारण बहुत बाधाएँ पड़ीं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि दूसरी योजना का समय बहुत सकटपूर्ण था। इन रुकावटों को दूर करने के लिए और योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए तीसरी योजना में विशेष रूप से जोर दिया।

४. तीसरी पंचवर्षीय योजना—(क) लक्ष्य—तीसरी पंचवर्षीय योजना (१९६१-६६) में लम्बे समय के उद्देश्यों को सामने रखते हुए ये लक्ष्य रखे गए—

(१) राष्ट्रीय आय में लगभग ५ प्रतिशत की बढ़ोतरी हो और इस प्रकार का निवेश का आधार बने जिससे कि आत्म-निर्भरता की स्थिति बन सके।

(२) खेती की उन्नति इस प्रकार से हो कि खाद्य-पदार्थों में आत्म-निर्भरता हो, उद्योग तथा निर्यात की आवश्यकताएँ पूरी हो सकें।

(३) बुनियादी उद्योग-घन्धे, इस्पात, रासायनिक, इंजन-शक्ति आदि, मशीन बया यन्त्र इस प्रकार से बढ़ें कि १० वर्ष के समय में और औद्योगिक उन्नति स्वदेशी साधनों से पूरी हो सके।

(४) बहुबल साधनों का अधिक-से-अधिक उपयोग हो और राष्ट्र में रोजगारी के अवसर बढ़ सकें।

(५) आयों में अन्तर तथा आर्थिक साधनों के अकेन्द्रीकरण का कार्य पूरा करना।

(ख) व्यय तथा धन-विभाजन—तीसरी योजना में भौतिक उत्पादन के लिए ५,००० करोड़ रुपया सरकारी क्षेत्र में, ४,१०० करोड़ रुपया निजी क्षेत्र में निर्धारित हुआ। परन्तु सरकारी क्षेत्र में वित्त साधन ७,५०० करोड़ रुपया ही मिलने की आशा की गई।

निम्नलिखित तालिका में दूसरी योजना के असली खर्चों के साथ तीसरी योजना के सम्भावित खर्चें विभिन्न क्षेत्रों में दिखाये गए हैं—

	दूसरी योजना		तीसरी योजना	
	कुल खर्च (करोड़ों में)	प्रतिशत	कुल निर्धारित	प्रतिशत
कृषि तथा बहुमुखी योजनाएँ	५३०	११	१,०६८	१४
बड़ी तथा छोटी सिंचाई के साधन	४२०	९	६५०	९
शक्ति	४४५	१०	१,०१२	१३
ग्राम तथा लघु उद्योग	१७५	४	२६४	४
संगठित उद्योग तथा खनिज	६००	२०	१,५२०	२०
यातायात तथा संचार	१,३००	२८	१,४८६	२०
ध्रम दान तथा अन्य विशेष	८३०	१८	१,३००	१७
पदार्थ (Inventories)	—	—	२००	३

सरकारी क्षेत्र में ७,५०० करोड़ रुपये में से असल निवेश ६,३०० करोड़ रुपया होगा और बाकी का १२०० करोड़ रुपया चालू खाते पर व्यय होगा। इस योजना में निजी क्षेत्र में ४,१०० करोड़ रुपये का निवेश होगा। इस प्रकार कुल निवेश (शुद्ध निवेश) १०,४०० करोड़ होगा। जबकि दूसरी योजना में ६,६५० करोड़ रुपया और पहली योजना में ३,३६० करोड़ रुपया हुआ था।

योजना की पूर्ति के लिए धन इन साधनों से प्राप्त होने की सम्भावना थी जो कि निम्नलिखित तालिका से पता लगता है—

तालिका

(करोड़ रुपये में)

	दूसरी योजना	तीसरी योजना
१. कोष चालू बिल (वर्तमान दर अनुसार)	५०	५५०
२. रेलवे का अनुदान	१५०	१००
३. सरकारी उद्यम का अनुदान	—	४५०
४. लोक उधार	७८०	८००
५. छोटी बचत	४००	६००
६. कोष इत्यादि	२३०	५४०
७. नये कर इत्यादि	१,०५२	१,७१०
८. विदेशी सहायता (बजट-प्राप्ति-पत्र)	१,०६६	२,२००
९. घाटे का बजट (Deficit Financing)	९४८	५५०
कुल	४,७०६	७,५००

५. तीसरी योजना और रोजगारी—दूसरी योजना में बेरोजगारी ठीक प्रकार से दूर न हो सकी और इसके साथ-साथ बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बेरोजगारी जितनी सोची थी उससे अधिक बढ़ गई, जिससे तीसरी योजना में लगभग २६ मिलियन लोगों के लिए रोजगार ढूँढ़ने की समस्या बनी। इसका किसी हद तक हल ढूँढ़ने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक समझा गया—

(१) बेरोजगारी का पहले के अन्तर में तेजी और अच्छी तरह से हल ढूँढ़ना होगा।

(२) ग्रामीण उद्योगों को उन्नत किया जाए तथा मानव-शक्ति और विजली का अंश बढ़ाया जाए।

(३) ग्रामीण कार्यों को इस प्रकार से चालू किया जाए कि कम से-कम २५ लाख मनुष्यों के लिए वर्ष में १०० दिन का काम निकल आए।

परन्तु मध्यकालीन मूल्यांक अनुसार 'वृषि योजना के पहले दो वर्षों में रोजगारी केवल गैर-वृषि क्षेत्र में ३२ लाख अधिक लोगों को मिल सकी। जैसा कि पहले बताया गया है कि तीसरी योजना के बेरोजगारी के लक्ष्य को पूरा नहीं किया गया।

६ तीसरी योजना का मूल्यांक—तीसरी योजना के मध्य मूल्यांक अनुसार यह पता चलता है कि आर्थिक उन्नति की दर तथा रोजगारी के अवसर पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किये गए। यह ठीक है कि कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि धातायात, शक्ति की प्रगति निर्धारित रूप से हो पाई है। परन्तु बहुत-से क्षेत्रों में—मशीन, यन्त्र, अलमूनियम, कपड़ा, इस्पात तथा कच्चा लोहा, सीमेंट, रासायनिक खाद, सिंचाई, कपास, तेल निकालने के बीज और खाद्य पदार्थों में उत्पादन के लक्ष्य बिल्कुल पूरे न हो सके। इसलिए नेशनल प्रगति कौंसिल (National Development Council) ने इस बात का निर्णय किया कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें उन सभी क्रियाओं को दूर करके योजना के लक्ष्यों को पूरा करें। इस विषय में यह कहना उचित होगा कि योजना के पहले तीन वर्षों में राष्ट्रीय आय केवल ६ प्रतिशत बढ़ी, जबकि बढ़ने का लक्ष्य ५ प्रतिशत प्रति-वर्ष था और प्रति व्यक्ति आय २६३२ रुपये से (१९६१) बढ़कर केवल २६६८ तक (१९६४) बढ़ सकी। इसी प्रकार खेती का उत्पादन भी लगभग स्थिर रहा और राष्ट्र की आर्थिक स्थिति संकट में रही।

इस दशा के उपचार के लिए खेती के कार्यक्रम को श्रेष्ठ स्थान दिया गया। खेती पर पैसे का खर्चा १९६१-६२ में ७२६ करोड़ से बढ़ाकर १९६४-६५ में १४६७ करोड़ कर दिया। इसके अतिरिक्त २१.५ करोड़ रुपया छोटी सिंचाई के साधनों तथा उपजाऊपन के संरक्षण के लिए और ७ करोड़ रुपया डेरी, मछली उद्योग, उद्यान-विकास इत्यादि के लिए, जो खेती तथा इन उद्योगों के उत्पादन को जल्दी बढ़ा सकें। इस प्रकार बढ़ी सिंचाई की योजनाओं पर भी अधिक धन व्यय किया गया जिससे कार्य जल्दी सम्पन्न किया जा सके। इस प्रकार १९६४-६५ में खेती पर व्यय ९५५ करोड़ रुपये हुआ जबकि पहले ५५ करोड़ रुपया टोन की सम्भावना थी।

औद्योगिक क्षेत्रों में प्रगति इतनी सराब न थी जिनकी नि वृषि क्षेत्र में। १९६१-६२ में औद्योगिक उत्पादन ६६ प्रतिशत से बढ़ा। अगले दो वर्षों में यह

६ प्रतिशत तक पहुँचा और योजना के अन्तिम वर्ष में ११ प्रतिशत पहुँचने की सम्भावना है। इस मध्यम प्रगति की दर के कारण विशेषतया कुल उत्पादन का गिर जाना और इस्पात, अलमूनियम, सीमेंट, जूट, पटसन उद्योग में उत्पादन की दर का इतनी तेजी से न बढ़ना था। इस प्रकार विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण शक्ति स्कीम बहुत कम उन्नत हो गई और देश के विभिन्न भागों में शक्ति के साधनों की कमी को महसूस किया गया। इसकी रोकथाम के लिए तीसरी योजना में कई कदम उठाये गए और प्रयत्न किया गया कि राष्ट्र में शक्ति के साधनों की स्थापना ५६ लाख किलोवाट (Kwt) (१९६०-६१) से बढ़कर ८८ लाख Kwt (१९६४-६५) में हो गई। इसी प्रकार तीसरी योजना में रेलों तथा सबको इत्यादि तथा सामान लादने की शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की गई और यह आशा प्रकट की जाती है कि तीसरी योजना के २४५ करोड़ टन के लक्ष्य से भी अधिक १५ करोड़ टन लादने की शक्ति बढ़ सकेगी। परन्तु चीनी आक्रमण (अक्टूबर १९६२) और हाल ही में पाकिस्तान के आक्रमण के कारण बहुत-से समाज-कल्याण के कार्यों को बहुत धक्का पहुँचा, क्योंकि बहुत-सा पैसा सुरक्षा के कार्यों के लिए लगाना पड़ रहा है। यह ठीक है कि सरकार सुरक्षा तथा विकास दोनों पर जोर दे रही है, परन्तु ऐसा देखा गया है कि जब देश को सुरक्षा, लड़ाई इत्यादि पर अधिक धन व्यय करना पड़ता है तो आर्थिक विकास में विघ्न पड़ जाता है।

१९६१ से ६४-६५ तक तीसरी योजना में विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिदिन व्यय बढ़ता ही चला गया, जैसा कि निम्नलिखित तालिका से प्रतीत होता है—

तालिका
तीसरी योजना में व्यय तथा लक्ष्यों की रूपरेखा

बड़े कार्य	केन्द्रीय तथा राज्य सम्मिलित	
	१९६१-६२ वित्तसंग्रह	१९६१-६५ कुल व्यय
कृषि तथा बहुमुखी उद्योग	१,०६८	८१५
सिंचाई के बड़े तथा छोटे साधन तथा बाढ़ से बचाव	६५०	४६३
शक्ति	१,०१२	८६१
उद्योग तथा खनिज	१,५२०	१,२३४
ग्राम तथा लघु उद्योग	२६४	१७३
संचार तथा यातायात	१,४८६	१,५६३
सामाजिक सेवा कार्य	१,३००	१,०५०
पदार्थ	२००	—
कुल	७,२००	६,२४६

मातायात पर दूसरे क्षेत्रों के अन्तर में न केवल अधिक धन खर्च हुआ बल्कि १०७ करोड़ रुपया योजना के निर्धारित धन से किया गया। इसी प्रकार खेती, उद्योग, शक्ति, साधन इत्यादि पर भी धन वर्ष-प्रतिवर्ष बढ़ता ही चला गया। तीसरी योजना के पहले चार वर्षों में करो से प्राप्त काफी रही। केन्द्रीय सरकार ने और अधिक करो से १९६१-६२ में १५ करोड़ से १९६५-६६ में २१३ करोड़ रुपया इकट्ठा किया। इसी प्रकार सरकारी उद्यम से भी धन की वेशी १९६१-६२ में २९ करोड़ से बढ़कर १९६४-६५ में १३० करोड़ हो गई। इसी प्रकार सार्वजनिक कर्जा और छोटी जमा १९६१-६२ में १४८ करोड़ तथा ६२ करोड़ से बढ़कर २१४ करोड़ तथा २०१ करोड़ हो गई। विदेशी सहायता योजना के प्रथम चार वर्षों में १७२३ करोड़ रुपये रही, जबकि योजना में २,२०० करोड़ रुपया इसके अन्तर्गत मिलने की सम्भावना थी। घाटे का बजट इन वर्षों में ६८६ करोड़ रुपये रहा, जबकि योजना में ५ वर्षों के लिए केवल ५५० करोड़ रुपया होना निश्चित था।

इस प्रकार यह देखा जाता है कि इन पहली तीन योजनाओं के कारण राष्ट्र की आर्थिक अवस्था में काफी उन्नति हुई। १९५१-६१ में राष्ट्रीय आय ४४ प्रतिशत और प्रति व्यक्ति आय १८५ प्रतिशत बढ़ी। परन्तु तीसरी योजना में राष्ट्रीय आय-दर तथा प्रति व्यक्ति आय-दर इतनी नहीं बढ़ी जितनी कि योजना के अन्तर्गत निर्धारित थी। इससे अधिक दुःख की बात तो कीमतों का दिन-प्रतिदिन बढ़ना और अदायगी शेष विदेशी सहायता के मिलने के पश्चात् भी खराब होते चले जाना ही है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में यो प्रतीत होता है कि योजना से कोई सुदृढ सफलता प्राप्त नहीं हुई।

७ चौथी पंचवर्षीय योजना—अक्तूबर १९५४ में स्मृतिपत्र में चौथी पंचवर्षीय योजना का १९६३-६४ की कीमतों को देखते हुए ढाँचा तैयार किया गया। चौथी योजना की विशेष समस्या यह है कि राष्ट्रीय उत्पादन-शक्ति को इस प्रकार बढ़ाया जाए कि सामाजिक स्थिति को कोई हानि न पहुँचे। विशेषतया मौलिक वस्तुएँ प्रत्येक व्यक्ति के उपभोग के लिए आवश्यक हैं, इनका उत्पादन बढ़े। मानव-जाति तथा आर्थिक साधनों पर निवेश बढ़े और राष्ट्र शीघ्रातिशीघ्र विदेशी सहायता से मुक्त हो सके। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य अपूर्ण रहे उनके कारणों तथा कीमतों के बढ़ने से जो स्थिति बनी है, इसे देखते हुए चौथी योजना के लक्ष्य तथा रचना इस प्रकार से हो कि मुद्रास्फीति को दूर रखा जा सके, जनता के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा किया जा सके और धन का वितरण ठीक प्रकार से हो सके, मानव-साधनों वा तेजी से विकास और उपयोग हो सके और राष्ट्र आत्म-निर्भर हो सके। इस प्रकार स्मृति-पत्र में पारिभाषिक लक्ष्य निम्नलिखित रखे गए हैं—

(१) कृषि-क्षेत्र में कम से-कम ५ प्रतिशत, अगर हो सके तो इससे अधिक वार्षिक दर ऊँची हो।

(२) इसकी पूर्ति के लिए रासायनिक खाद, कृषि-यन्त्रो तथा कीडो के विनाश की दवाइयो को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए ।

(३) आवश्यक उपभोग को वस्तुएँ, जैसे कि कपडा, चीनी, दवाइयाँ, मिट्टी का तेल, कागज इत्यादि के उत्पादन को तेजी से बढ़ाया जाए ।

(४) सीमेंट तथा भवन बनाने की सामग्री की वृद्धि की जाए ।

(५) खनिज पदार्थों, रासायनिक पदार्थों, भवन-निर्माण की मशीनों, खानों, विद्युत् शक्ति तथा यातायात के उद्योगो की चालू स्कीमो को पूर्ण किया जाए और नई स्कीमो को जल्दी चालू किया जाए ।

(६) अधिक-से अधिक सामाजिक उन्नति के लिए सहायता के साधनो की पूर्ति हो, जिससे वे उत्पादन की शक्ति को बढ़ाने मे सहायक हो सकें ।

(७) इन सभी शाखाओ मे विकास के लिए अधिक रोजगारी के अवसर बढ़ाए जाएँ और सामाजिक न्याय प्रदान किया जाए ।

८ इस योजना मे व्यय—मौलिक आगणन के अनुसार २१,५०० करोड रुपये के लगभग चौथी योजना की पूर्ति के लिए धन प्राप्त होगा, जिसमे से ७,००० करोड रुपया निजी क्षेत्र मे से प्राप्त होगा । सरकारी क्षेत्र मे धन इकट्ठा करने के लिए इस यात का प्रयत्न किया जाएगा कि अनियोजित खर्चा कम-से-कम हो और वर्तमान करो के अनुसार अधिक-से अधिक धन इकट्ठा हो । यह आशा की जाती है कि २५०० करोड रुपया बजट के प्राप्त पत्रो से मिलेगा और २५०० से होकर ३,००० करोड रुपये तक करो को बढ़ाने तथा करो के उपवचन को कम करके और सरकारी क्षेत्र के उत्पन्न की कीमतो मे कमीवैशी करके इकट्ठा किया जाएगा । चौथी योजना मे ३,२०० करोड रुपया विदेशी सहायता के रूप मे लिया जाएगा ।

इस प्रकार चौथी योजना मे विशेष क्षेत्रो के धन का वितरण निम्नलिखित तालिका से प्रतीत होता है । साथ ही मे तीसरी योजना का खर्चा भी दिया गया है, ताकि इससे वितरण का ठीक अनुमान लगाया जा सके—

तालिका

(करोड़ों में)

बड़े उद्योग	अनुमानित व्यय तीसरी योजना में	चौथी योजना में वितरण तथा उनके स्थान
कृषि	१,०६०	२,४००
सिंचाई	६४६	१,०००
	१,७०६	३,४००
शक्ति	१,१८७	१,६५०
छोटे उद्योग	२३३	४५०
संगठित उद्योग	१,६६२	३,२००
यातायात तथा संचार	१,६४०	३,०००
	५,०२२	८,६००
शिक्षा	५५७	१,४००
वैज्ञानिक अनुसन्धान	७२	१७५
स्वास्थ्य	३४५	१,०६०
भवन तथा निर्माण	११२	४००
पिछड़ी जातियों की सहायता	१०४	२०५
शिल्पकारी ट्रेनिंग तथा मजदूरों की सहायता		६५
लोक कल्याण	२५०	१४५
ग्रामीण कार्य		१५
फिर से बसाना		२५
आवश्यक		५०
पदार्थ		५०
कुल	८,२००	१५,६२०

६. विशेष उद्देश्य—योजना के उद्देश्यों का निर्धारण इस विचार को देखते हुए रखा गया कि २२,५०० करोड़ रुपये का व्यय होगा और राष्ट्र की तकनीकी तथा प्रशासन-शक्ति इस प्रकार से होगी कि यह निम्न लक्ष्यों की पूर्ति हो सके।

खाद्य-पदार्थों का उत्पादन ६.२ करोड़ टन १९६५-६६ से बढ़कर १२ करोड़ टन १९७०-७१ में हो जाए। कपास की गांठें ६३ लाख से ८५ लाख तक बढ़ जाएंगी। गन्ने का उत्पादन १.१० करोड़ से बढ़कर १.३५

करोड़ हो जाए। सिचाई छोटी तथा मध्यम साधनों से १४० करोड़ एकड़ और भूमि को लाभ हो। स्थिर शक्ति उत्पादन ११७ लाख किलोवाट से बढ़कर २२० लाख किलोवाट हो जाए। औद्योगिक उन्नति, विशेष रूप से खनिज पदार्थ, रासायनिक, कृषि-यन्त्रों, उपभोग-सामग्री तथा पेट्रोल साफ करने की शक्ति बहुत बढ़ा दी जाए। यह आशा प्रकट की जाती है कि कच्चा इस्पात का उत्पादन १६६६-६७ में ८६ लाख टन से बढ़कर १६५ लाख टन १६७०-७१ तक हो जाए। कच्चे लोहे का उत्पादन १२ लाख टन से बढ़कर ४० लाख टन तथा अलमूनियम का ६८,००० से २४ लाख टन हो जाए। इस प्रकार रासायनिक खाद का उत्पादन चार गुना तथा घसवारी कागज ५ गुना, मीमेन्ट दुगुना। १६७०-७१ तक १६६५-६६ के अन्तर में ५० प्रतिशत और वजन उठाने योग्य हो जाएगी। वाणिज्य-सम्बन्धी गाड़ियों की संख्या दुगुनी हो जाएगी। संचार के क्षेत्र में ७ लाख और टेलीफोन के सम्बन्ध मिलेंगे, शिक्षा के कार्यों को बढ़ाया जाएगा और प्रवेश की मात्रा इंजीनियरिंग तथा तकनीकी धाराओं में द्विती स्तर तक बढ़ाई जाएगी। १६७०-७१ तक ६८,६०० विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा सकेगी। इस प्रकार परिवार-नियोजन तथा डॉक्टरों आदि की शिक्षा का विकास भी होगा।

१० भारतीय योजनाओं में कमी—कुछ ऐसे आलोचक हैं जिन्हें भारतीय योजनाओं की आलोचना किये बिना चैन ही नहीं। ऐसे आलोचकों की हम अपेक्षा कर सकते हैं। परन्तु कुछ ऐसी आदर्श विभूतियाँ हैं जिनकी योजनाओं की विवेचना को हम रद्द नहीं कर सकते। १२ अगस्त १६६५ के 'इण्डियन एक्सप्रेस' समाचार-पत्र के सम्पादकीय में योजनाओं के बारे में यह कहा गया कि "पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं की प्रगति से यह स्पष्ट है कि कल्पना तथा अनुभव में बहुत अन्तर है। योजनाओं में अधिक जोर कार्यान्वित करने पर दिया जाना चाहिये था और अगर देश की आर्थिक दशा को ठीक प्रकार से सुधारना है तो इस बात की सोच करनी थी कि किनको प्रधानता देनी है।" क्योंकि ऐसा नहीं किया गया, इसलिए चारों तरफ से योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो रही। जो योजना की असफलता पर निराश हैं उनका कहना है कि योजना से कुछ समय के लिए धक्काश मिलना चाहिए। योजना प्रायोग की नीति ऐसी ही है जैसे उल्टे बाँस बरेली भेजना। इस योजना ने वे लक्ष्य रखे हैं जो किसी प्रकार से थोड़े समय में पूर्ण नहीं हो सकते। आज योजना की दशा ऐसी है कि धन तो व्यय किया जा रहा है परन्तु उसकी प्राप्ति नहीं हो रही और इस प्रकार धन व्यर्थ जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही विचारों को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के श्री चबन सरकार ने सम्पादकीय में व्यक्त किया था।

परिशिष्ट

रुपये का अवमूल्यन

मूमिका—भारत सरकार ने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय किये हैं। आशा की जाती है कि उनका हमारी आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय, जो भारत सरकार ने किया, वह ५ जून १९६६ को रुपये का विनिमय मूल्य १०० रुपये के लिए १८ ६६ ग्राम सोने से गिराकर ११ ८५ ग्राम कर देना है। इस प्रकार रुपये का बाहरी मूल्य ३६ ५ प्रतिशत घटा दिया गया, जिसका अर्थ यह हुआ कि अमरीका को एक डालर के बदले ४ ७६ रुपये के स्थान पर ७ ५ रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार पौड स्टलिंग के बदले १३ ३३ रुपये की जगह पर २१ रुपये मिलेंगे।

अवमूल्यन का अर्थ—रुपये के विनिमय मूल्य का अर्थ है कि विदेशी विनिमय मूल्य के दाम में कमी। इसका मतलब यह हुआ कि रिज़र्व में जो विदेशी मुद्रा दी जाए उसके बदले में किस हिसाब से रुपया मिले और उससे जो विदेशी मुद्रा ली जाये उसके बदले में किस हिसाब से रुपया लें। इस प्रकार हम देखते हैं कि और चीजों के दाम की तरह स्वदेशी मुद्रा का दाम भी होता है। यह कोई ऐसी घटना या मसला नहीं जिसके कारण देश के सम्मान को कोई ठेस पहुँचे। अन्य प्रकार के माल की तरह विदेशी मुद्रा के दाम तय करने के लिए केवल आर्थिक बातों का ध्यान रखा जाये और सब चीजें आर्थिक वास्तविकता के अनुसार हों।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—इसमें कोई शक नहीं कि जो पिछले दस वर्षों में रुपये का मूल्य था वह आज नहीं। आज दाम ८० प्रतिशत पहले से अधिक है। परन्तु १९४६ के बाद रुपये के सरकारी विनिमय मूल्य में कोई तबदीली नहीं हुई। ससार के और बड़े राष्ट्रों में, जिनके साथ हमारा आर्थिक व्यापार है, वहाँ की चीजों के दाम अधिक नहीं बढ़े। इसका नतीजा यह हुआ कि और देशों के मुकाबले में वहाँ की मण्डियों में हमारा माल महँगा मिलता है। इसके साथ साथ हमें अपने निर्यात बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा को और बचाने की आवश्यकता तेज़ी से बढ़ती रही है। निर्यात को बढ़ाने के लिए पिछले वर्षों में औरों के मुकाबले में अपने माल को सस्ता करने के लिए हमने कई तरीकें अपनाये हैं। उदाहरणतया निर्यात को सहारा देना तथा ऋणपत्रों की सुविधा, परन्तु इन उपायों का कोई खास असर न हुआ। हो सकता है कि अगर हमारी कठिनाइयाँ अस्थायी होती तो शायद इनसे लाभ होता। परन्तु हमारी कठिनाइयाँ बहुत गहरी हैं जिनको दूर करने के लिए उपाय भी गहरे होने आवश्यक थे।

अवमूल्यन के प्रभाव—अवमूल्यन का दरअसल मतलब ही यह था कि देश के

निर्यात को बढ़ाने के लिए अच्छे तथा मजबूत उपाय किये जाएँ। अगर एक निर्यात करने वाला १०० डालर का माल निर्यात करता है तो ४७३ रुपये के स्थान पर ७५० रुपये कमायेगा। इससे निर्यात को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, न केवल हमारा माल सस्ता होगा बल्कि निर्यात के उद्योग धन्धों का निवेश और बढ़ायेंगे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारी कुछ पुरानी निर्यात की चीजों को इस प्रकार की सहायता की जरूरत नहीं। इसी प्रकार अवमूल्यन से आयात की बहुत-सी चीजों को देश में ही बनाने की वृद्धि होगी। आयात की चीजों का मूल्य बढ़ जाएगा जिससे इनको देश में बनाने की कोशिश की जाएगी। यह बात खेती पर भी उसी प्रकार लागू होती है जिस प्रकार उद्योग के लिए। कृषि-उन्नति से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

इस विनिमय-दर का न केवल निर्यात और आयात पर ही प्रभाव पड़ेगा बल्कि देश से बाहर जाने वाले तथा बाहर से आने वाले भुगतान (Invisibles) पर भी गहरा असर पड़ेगा जिससे देश से भेजने में प्रोत्साहन मिलेगा, परन्तु देश में आने पर कुछ रोक-टोक हो जाएगी। इस प्रकार विदेशी मुद्रा का बोझ पूँजी, मुनाफा, धन आदि को बाहर भेजने से होता है, उसकी छीजन अब कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जो नये लोग विदेशी पूँजी अब हमारे देश में लगायेंगे उन्हें और अधिक रुपया मिलेगा और इस प्रकार नये क्षेत्रों में तथा विदेशी यात्रियों (Tourists) को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ-साथ रुपये की ऋण शक्ति में कमी आने के कारण जो बहुत-सी बुराइयाँ पैदा हो गई हैं, जैसे कि नियातकर्ता माल के बिल को कम बनाता, सोना, विदेशी मुद्रा, घडियाँ, कंमरे तथा ट्रांजिस्टर्स की चोरबाजारी में कमी होगी। यह कहना गलत होगा कि अवमूल्यन के कारण, विकास-कार्यों के लिए ऋण लेने का बोझ बढ़ जाएगा। विदेशी मुद्रा के हाथ में न तो रुपये की कुल रकम तथा इसकी वापिस अदायगी की राशि में कोई विशेष वृद्धि होगी यद्यपि रुपये के रूप में ऋण की अदायगी का बोझ जरूर बढ़ेगा। सरकारी आयात तथा दूसरे विदेशी खर्चों का परिणाम भी रुपये के रूप में बढ़ जाएगा। परन्तु जैसा कि वित्तमन्त्री सचीन चौधरी ने अवमूल्यन की घोषणा करते हुए बताया है कि सरकार के बजट में कई प्रकार से लाभ होगा, अगर आयात के बारे में उदार नीति को हम ठीक तरह से चला सकें।

कीमतें तथा उत्पादन—इसमें कोई सन्देह नहीं कि अवमूल्यन से आयात की वस्तुओं की लागत में वृद्धि होगी। इस प्रकार आयात की चीजों को देश में बनाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। आजकल इन चीजों का मूल्य उनके वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक है, इसलिए अब उपभोक्ता को आयात की हुई चीजों की कीमत जो देनी पड़ेगी वह वर्तमान दामों से ज्यादा अधिक नहीं होगी। इसके साथ-साथ अवमूल्यन करते हुए सरकार ने इस बात का प्रबन्ध किया है कि उर्वरक, मिट्टी तथा डीजल तेल की कीमत बढ़ने नहीं दी जाएगी और विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा।

असली बात तो यह है कि उत्पादन के बढ़ने से दामों में स्थिरता आ सकती है। सरकार कृषि-उत्पादन तथा उद्योग को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है। हमारी

तीनों योजनाओं के अन्तर्गत जो कारखाने खुले वे अधिकतर बाहर से कच्चे माल तथा कलपुर्जों के प्राप्त न होने से पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर सके। इससे न केवल उत्पादन-शक्ति को घबका पहुँचा है बल्कि साथ साथ चीजों की लागत को कम करने में भी कठिनाई पैदा हो गई है। इस प्रकार उत्पादन को बढ़ाने के लिए अवमूल्यन के साथ-साथ कई और तरीके अपनाने होंगे जिनसे निर्यात बढे और आयात के तरीके सरल हो जायें।

अवमूल्यन से देश क विदेशी व्यापार, आयात-निर्यात और विदेशी मुद्रा मूल्य पर क्या असर पड़ेगा ? आयात का विदेशी मुद्रा मूल्य बढ़ने का कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार निर्यात में भी हमारी इन चीजों का, जो कि कुल विश्व-व्यापार का बहुत छोटा हिस्सा है, विदेशी मुद्रा मूल्य में बढ़ावा नहीं होगा, लेकिन चाय, पटसन, जैसी कुछ चीजें हैं जिनका विश्व-व्यापार में काफी बड़ा हिस्सा है और जिनकी माँग भी घटती बढ़ती रहती है, इनके दामों में कमी को रोकने के लिए सरकार को अवमूल्यन के बाद कुछ न-कुछ करना पड़ेगा।

अवमूल्यन तथा आर्थिक विकास—रक्षामन्त्री श्री बह्मण ने अपने ८ जून १९६६ के रेडियो भाषण में इस बात पर जोर दिया कि “अवमूल्यन विकास के लिए जरूरी है। मुख्य रूप से विकास का अर्थ है कि राष्ट्र अपनी आवश्यकता का सामान तथा मशीनें आदि स्वयं बनाये। अपने देश की जनता के सुख सुविधा और भलाई के साधनों को बढ़ा सके। इस प्रकार आत्म-निर्भरता देश के विकास-कार्यों का सबसे मुख्य लक्ष्य है। विकास-कार्यों में देश का रुपया तथा विदेशी मुद्रा लगाई जाती है। विदेशी मुद्रा विदेशों से ऋण तथा निर्यात करने से प्राप्त होती है। इनमें से निर्यात से मुद्रा कमाना कही अच्छा है। इससे वर्तमान तथा भविष्य दोनों को लाभ पहुँचना है और यह विदेशी ऋणों के मुकाबले में अधिक स्थिर होती है। इसलिए जितना निर्यात बढ़ता है उतना ही हमारी आत्म-निर्भरता भी। इस प्रकार निर्यात को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। निर्यात को बढ़ाने के लिए अवमूल्यन करना बहुत आवश्यक तथा लाभप्रद दिखाई पड़ता था। अवमूल्यन से अधिक विदेशी सहायता प्राप्त करने में भी मदद मिलती है, जोकि खेती तथा उद्योग दोनों बढ़ायेगी। आशा की जाती है वह दिन दूर नहीं जब विदेशी सहायता लेने की जरूरत ही न होगी। यदि देश का उत्पादन तथा ऋण चुकाने की क्षमता बढ़ाने के लिए विदेशी सहायता लेनी पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं। स्मरण रहे कि देश में रुपये के मूल्य में कोई खास परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हाँ, बाहर से आने वाली चीजों के दाम बढ जाएँगे, लेकिन अगर विदेशी सामान से देश में जो माल बने उसमें उत्पादन हो तो जरूरी ही आयातित भोग की वस्तुएँ शनै-शनै कम हो जाएँगी। अवमूल्यन के बाद जो चीजें साधारण जनता के प्रतिदिन व्यवहार में आती हैं उनके दाम को न बढ़ने दिया जाए। जो चीजें आयातित मशीनों के प्रयोग से बनती हैं और जिनका उपयोग धनी लोग करते हैं, उदाहरणतया विलासिता उपभोग की वस्तुएँ, उनकी बात अलग है। अवमूल्यन के बाद व्यापारियों के जो ऊँचे लाभ हैं उनमें अत्यधिक कमी होगी। इसके साथ-साथ बाहर से आने वाली

चीजों के दाम बढ़ने के कारण उन उद्योगों को संरक्षण मिलेगा जो भारत में पहली बार व्यापार करने तथा उत्पादन करने की कोशिश में जुटे हैं।”

अवमूल्यन क्यों ?—देश में अवमूल्यन करने का यह पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार अवमूल्यन की समस्या देश के सामने आई जैसे कि १९२६ के आर्थिक संकट के समय, १९३६ में जब यूरोप के कुछ देशों ने अवमूल्यन किया, १९३७ में, उसके पश्चात् १८ सितम्बर १९४६ को जब ब्रिटेन की सरकार ने अपनी मुद्रा के अवमूल्यन की घोषणा की। भारत सरकार ने भी अपनी मुद्रा को उसी प्रकार ३०.५ प्रतिशत गिरा दिया। इस बार भी सरकार ने बहुत महत्त्वपूर्ण निर्णय किया जब अवमूल्यन की घोषणा की गई। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने एक बहुत बड़ा अपराध किया है जिससे राष्ट्र के सम्मान को बहुत बड़ा धक्का पहुँचा है। यह भी कहा जाता है कि अवमूल्यन करने से पूर्व लोगों को इसकी खबर न दी गई। लोगों को पहले से बता देना बहुत खतरनाक होता जिससे करोड़ों रुपये का सट्टा तथा हानि हो सकती थी। बाकी रही देश की सम्मान की बात, यह तो वही बात हुई कि ऑपरेशन करने से एक रोगी की प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचना। मूल्यों में लगातार वृद्धि होने के साथ, विदेशों में भारतीय रुपये का मूल्य बहुत अधिक गिर गया था। एक अमरीकी डालर का काला बाजार में मूल्य १०-१२ रुपये के बीच था, जबकि विनिमय की सरकारी दर इसी आधार पर ४.७५ पैसे थी, जिससे अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ रहा था। इससे निर्यात करना हानिकारक और आयात करना लाभप्रद सिद्ध हो रहा था। सरकार ने आयात शुल्क लगाया तथा निर्यात मूल्य में सहायता देने का प्रयत्न किया, परन्तु यह जल्दी सिद्ध हुआ कि ये उपाय एक तरफ पेचीदा थे बल्कि अपूर्ण तथा एकतरफा थे। इनसे न तो निर्यात में वृद्धि हुई और न ही आयात के ढाँचे में कोई परिवर्तन हुआ। इसके अतिरिक्त कई और प्रतिकूल परिणाम देखने में आये। भुगतान संतुलन की स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होने के कारण देश के उद्योगों के लिए न तो कच्चा माल और न ही कलपुर्जों ही मिल रहे थे जिससे कई कारखाने बन्द हो गए और कुछ में काम कम हो गया, जिससे देश में बेरोजगारी, छूटनी, उत्पादन की कमी, वस्तुओं का अभाव और ऊँची कीमतों का सामना करना पड़ा।

व्यापारिक तथा औद्योगिक उन्नति—अवमूल्यन कर देना पर्याप्त नहीं, जैसा कि श्री एस्.के. पाटिल रेलवे मन्त्री ने ६ जून १९६६ को अपने रेडियो भाषण में कहा कि “अवमूल्यन के साथ-साथ उत्पादन, निर्यात, आयातित वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया जाए और सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था को ठीक रूप से रखा जाए जिससे भारतीयों की आवश्यकता पूरी होगी, मूल्यों को ठीक स्तर पर रखा जा सकेगा और राष्ट्र आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकेगा। यह आशा प्रकट की गई है कि दम घर्षों में हम अपने निर्यात में तिगुनी वृद्धि करके ८०० करोड़ से बढ़ाकर २४०० करोड़ तक पहुँचा देंगे। अवमूल्यन से निर्यात उद्योगों में विनियोग की प्राथमिकता मिलेगी। नई वस्तुओं का व्यापार स्थापित हो सकेगा। परन्तु इस बात का ध्यान रखना होगा कि अवमूल्यन केवल हमारे ही देश की स्थिति को मजबूत बनाने में सफल

नहीं होगा जब तक हम अन्य उपायों पर ध्यान नहीं देंगे, जैसे कि कठिन परिश्रम, सामाजिक तथा आर्थिक समय, उत्तम प्रबन्ध-व्यवस्था, लागत में कमी करने की प्रबल इच्छा, अधिक उत्पादन, वस्तुओं को बर्बाद न होने देना और सचिवालय तथा सां-जतिक क्षेत्र, दोनों की देख-रेख में कुशलता आदि। इस प्रकार अधिक-से-अधिक निर्यात तथा आत्म-निर्भरता तथा कम-से-कम लागत में वस्तुएँ बनाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए।”

अवमूल्यन पर वाद-विवाद—अवमूल्यन की घोषणा के पश्चात् देश में इसके बारे में प्रत्येक नागरिक ने अपना ही नवीन मत दिया। जैसे कि सी० जी० के० रेड्डी तथा श्रीमती के अनुसार अवमूल्यन के पश्चात् समाचार-पत्रों को बहुत भारी आर्थिक संकट देखना होगा। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के उप-कुलपतियों की नैनीताल की गोष्ठी में कहा गया कि विश्वविद्यालयों के बजट को बहुत भारी घबका पहुँचा है। दिल्ली के एक रिपोर्टर ने समाचार-पत्र में यह लिखा कि अवमूल्यन से पुस्तकें पढ़ने की आदत बहुत महँगी पड़ेगी क्योंकि बाहरी देशों से आने वाली पुस्तकों की कीमतों में बहुत वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार श्री एस० एम० जोशी, अध्यक्ष संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ने कहा कि अवमूल्यन ग्राम जनता के लिए एक बहुत बड़ी घटना है।

निष्कर्ष—भारत की प्रधान-मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने १२ जून १९६६ के रेडियो भाषण में कहा कि अवमूल्यन कोई जादू नहीं है, किन्तु यह देश की अर्थव्यवस्था में आई हुई मौजूदा गिरावटों में कुछ शीघ्रता से सुधार कर सकता है। सरकार को भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ते हुए अन्तर के कारण यह कदम उठाना पड़ा। इसका महत्त्व और उद्देश्य यह है कि देश के निर्यात लाभप्रद हों, और जिन वस्तुओं का आयात होता है उनका स्थान स्वदेशी माल ले सके, जिससे सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में पूंजी लगाने के लिए अनुकूल वातावरण बन सके।

परन्तु अवमूल्यन का उद्देश्य पूरा होगा कि नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि अवमूल्यन के बाद सरकार बाकी कदम क्या उठाती है। अवमूल्यन कोई एक अपने-आपमें ही अन्त नहीं है, बल्कि एक आर्थिक स्थिति को उन्नत बनाने का रास्ता है। सरकार को उन तमाम प्रतिबन्धों से मुक्त कर देना चाहिए जो उत्पादन के मार्ग में विघ्न डालते हैं। बैंकों को औद्योगिक उन्नति के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सरकार को नये क्षेत्र न खोलकर कृषि, औद्योगिक तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रों में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, जिससे निर्धारित लक्ष्य पूर्ण हो सकें। ऐसा करने से देश के कर के बोझ में काफी कमी हो सकेगी, जिससे निजी क्षेत्र में उपनिवेश होगा और उत्पादन अच्छी मात्रा में बढ़ेगा, इससे मुद्रास्फीति पर काबू पा लिया जा सकेगा।